

एक उदारवादी स्वर

चेस्टर वौल्स

संकलित लेख और भाषण

संपादक

हेनरी स्टील कोमागर
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, ऐमहर्स्ट कॉलेज . .

अनुवादक

ओमप्रकाश 'दीपक'

1965

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

EK UDARVADI SWAR

(Hindi Version of 'The Conscience of a Liberal')

by

CHESTER BOWLES

Translated

by

OM PRAKASH 'DIPAK'

Rs. 5.00

"A Close Look at Mainland China"

© 1959, The Curtis Publishing Company

"What Negroes Can Learn from Gandhi"

© 1958, The Curtis Publishing Company

Material used by the kind permission of Foreign Affairs © 1954, 1960
1962 by Council on Foreign Relations, Inc., New York

© 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960,
1961, 1962 by Chester Bowles

प्रकारक

रामबाल पुरी, संचालक

भारतमाराम एण्ड संस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

हौद खाम, नई दिल्ली

17-अशोक मार्ग, इन्दरतगंज, लखनऊ

बोहा रास्ता, धामानी मार्केट, जयपुर

विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़

मूल्य : पाँच रुपए

प्रथम संस्करण : 1965

मुद्रक

सुगन्धर प्रेम,

दिल्ली-6

लेखक परिचय

चेस्टर बौल्स व्यापारी, लेखक, सार्वजनिक प्रशासक, कांग्रेस-सदस्य और राजदूत रह चुके हैं। अमरीका के सार्वजनिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का अनुभव उनसे अधिक व्यापक नहीं रहा।

श्री बौल्स का जन्म 1901 में, स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में हुआ, और उन्होंने अपना कार्य-जीवन एक व्यापारिक अधिकारी के रूप में आरम्भ किया। दूसरा महा-युद्ध आरम्भ होने पर उन्होंने व्यापार छोड़कर पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अधीन संघीय मूल्य प्रशासक के रूप में, और फिर राष्ट्रपति ट्रूमन के अधीन आर्थिक स्थिरीकरण के निदेशक के रूप में काम किया।

युद्ध के बाद, श्री बौल्स संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ट्राइग्वे सी के विशेष सहायक रहे। 1948 में वे कॉनेक्टिकट के गवर्नर चुने गए, और 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमन ने उन्हें भारत और नेपाल में अमरीकी राजदूत नियुक्त किया।

1953 से 1958 तक का काल उन्होंने मुख्यतः विश्व-भ्रमण में और वंदेशिक मामलों पर लिखने और बोलने में बिताया। उन्होंने अधिकांश प्रमुख अमरीकी विश्व-विद्यालयों में भाषण किए हैं। उन्होंने सात पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से पांच इसी अवधि में लिखी गईं।

1958 में कॉनेक्टिकट से कांग्रेस-सदस्य चुने जाकर श्री बौल्स फिर से एक सार्व-जनिक पद पर आए। 1960 के राष्ट्रपति चुनाव-अभियान में श्री बौल्स डेमॉक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन की मंच (घोषणा-पत्र) समिति के अध्यक्ष, और सीनेटर केनेडी के विदेश-नीति सम्बन्धी सलाहकार रहे। दिसम्बर, 1960 में वे विदेशी विभाग के अवर सचिव नियुक्त किये गए, और बाद में राष्ट्रपति केनेडी के अफ्रीकी, एशियाई और सातिन अमरीकी मामलों के सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि रहे। जुलाई, 1963 में वे पुनः राजदूत के रूप में भारत आए।

राजदूत और श्रीमती बौल्स इस समय नई दिल्ली में निवाम करते हैं। उनका स्थायी निवास-स्थान एसेबम, कॉनेक्टिकट में है। उनके पांच बच्चे हैं।

डी० एस० बी० को

मेरा देश जागे

जहाँ चित्त निर्भय हो और सिर ऊँचा हो;

जहाँ ज्ञान उन्मुक्त हो;

जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारो ने जगत को खण्डित न कर दिया हो,

जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हों;

जहाँ अविरत प्रयास पूर्णता की ओर बढ़ता हो;

जहाँ विवेक की निर्मल धारा जड़ रुढ़ि की सूखी रेती में लुप्त न हो गई हो;

जहाँ विचार और कर्म आपकी प्रेरणा से नित्य अधिक व्यापक हों;

ओ पिता, स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में मेरा देश जागे ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(‘गीतांजलि’ के अंग्रेजी संस्करण से)

अनुक्रम

परिचयात्मक भूमिका—हेनरी स्टील कोमागर ... (क)

पहला खण्ड : संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व क्रान्ति

पहले खंड पर एक निजी टिप्पणी—चेस्टर बोल्स	...	3
पहला भाग—विश्व में हमारे लक्ष्य		
1. धारा की मोड़ने का अवसर	...	7
भाषण, फ्रीडम हाउस, न्यूयार्क सिटी, 17 जनवरी, 1947		
2. विधि और निषेध, दोनों के कार्यक्रम की आवश्यकता	...	10
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 18 अप्रैल, 1948		
3. एक और महान् वहस चले	...	14
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 28 फ़रवरी, 1954		
4. क्या आशा का कोई मार्ग नहीं ?	...	20
न्यू सीडर, 26 जुलाई, 1954		
5. लोगों और विचारों की शक्ति	...	24
भाषण, नौसैनिक युद्ध कालेज, 7 जून, 1956		
6. -हम किनने वस्तुनिष्ठ रहे हैं ?	...	29
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 20 मई, 1956		
7. यूरोप में हमारे और रूस के लक्ष्य	...	32
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 12 मई, 1957		
8. यूरोप के प्रति एक नई नीति	...	35
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 20 दिसम्बर, 1959		
9. फिर से पहल करने का समय	...	44
भाषण, मिनेसोटा विदेश-नीति संघ, मिनीआपोलिस, 20 अक्टूबर, 1960		
10. हमारी शताब्दी का भाग्य-निर्णय करने वाले पांच फँसले	...	48
भाषण, अमरीकी पुस्तक-विक्रेता संघ, वाशिंगटन, डी० सी०, 12 जून, 1961		

- | | | | |
|-----|--|-----|----|
| 11. | संपुत्रा राष्ट्र गंग की मरुतनाएँ
भागग, मगुत्रा राष्ट्र गंग दिगग भोज गान्निगटन,
डी० सी०, 24 फरवरी, 1961 | ... | 56 |
| 12. | नए धनगायशरी
भागण राष्ट्रीय प्रीइ शिक्षा सम्मेलन, गान्निगटन,
डी० सी०, 5 नवम्बर, 1961 | ... | 61 |
| 13. | सारी मानवता के लिए शान्ति
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 10 दिगम्बर, 1961 | ... | 65 |
| 14. | एक नई गूटनीति की ओर
फॉरेन एफेयर्स, जनवरी, 1962 | ... | 71 |

दूसरा भाग—भाषिक सहायता के रूप

- | | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 15. | भूरी दुनिया में धमरीही भोजन
भागण, गुनरमार्टट सम्मेलन, गिरागो, 25 मई, 1947 | ... | 91 |
| 16. | शाशाहीन बच्चों के लिए नई धाना
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 1 फरवरी, 1948 | ... | 82 |
| 17. | चतु मूभी कार्यक्रम में एशिया में एक नई शानि का धारम्भ
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 16 नवम्बर, 1952 | ... | 84 |
| 18. | विश्व के भाषिक विकास में गाभीशर
ग्रटलांटिक मन्वली, दिगम्बर, 1954 | ... | 87 |
| 19. | विदेशी सहायता के प्रति नया दृष्टिकोण
प्रतिनिधि सभा की वैदेशिक मामलों की समिति के
समक्ष वक्तव्य, 27 नवम्बर, 1956 | ... | 93 |
| 20. | विदेशी सहायता के वितरण में प्रतिमानों की धावधरता
प्रतिनिधि-सभा में भाषण, 20 फर्रैल, 1958 | ... | 100 |
| 21. | विदेशी में भोजन बँकों की स्थापना का प्रस्ताव
सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति के समक्ष वक्तव्य,
8 जुलाई, 1959 | ... | 109 |
| 22. | लोकतांत्रिक विकास का मर्म : ग्राम विकास
भागण, भूमि-रक्षण सम्बन्धी व्हाइट हाउस सम्मेलन,
24 मई, 1962 | ... | 112 |

तीसरा भाग—विकासशील महाद्वीप

एशिया

- | | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 23. | एक साम्यवादी सहायत्री को उत्तर
ब्लिट्ज, 19 जुलाई, 1952 | ... | 121 |
|-----|---|-----|-----|

24.	एशिया और अमरीकी सपना भाषण, कम्युनिटी चर्च, न्यूयार्क सिटी, 28 मई, 1953	126
25.	एशिया के लिए एक 'मासॉल योजना' भाषण, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एण्ड सायन्सेज, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क सिटी, 19 अक्टूबर, 1953	...	129
26.	ब्रह्मा और विएतनाम : अन्तर और नतीजे न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 13 जून, 1954	...	132
27.	'भूरे व्यक्ति के भार' का विश्लेषण न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 5 सितम्बर, 1954	...	138
28.	स्वतंत्र एशिया का भविष्य ? फ़ॉरेन एफ़ेयर्स, अक्टूबर, 1954	...	143
29.	एशियावासी कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं पॉकेट मैगज़ीन, नवम्बर, 1954	...	148
30.	तटस्थ राष्ट्र और भारतीय सफलता की कहानी दिस मंथ, जुलाई, 1962	...	155
31.	मध्य-पूर्व में नई प्रवृत्तियाँ भाषण, अमरीकी यहूदी कांग्रेस, न्यूयार्क सिटी, 12 अप्रैल, 1962	...	159
अफ्रीका			
32.	अफ्रीका में एक यात्री 1955 में अफ्रीका की यात्रा करते समय श्री वॉल्स द्वारा अपने परिवार को लिखे गए पत्रों के उद्धरण	...	164
33.	अफ्रीका में अमरीका की भूमिका कोलियर्स, 10 जून, 1955	...	172
34.	संयुक्त राष्ट्रों को अफ्रीका की चुनौती न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 21 अगस्त, 1960	...	176
35.	अफ्रीका में आशा की लहर भाषण, अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक कमीशन, अदिस अबाबा, इथियोपिया, 21 फरवरी, 1962	...	169
लातिन अमरीका			
36.	लातिन अमरीका में जमीन की भूख न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 22 नवम्बर, 1959	...	183

37. 'प्रगति के लिए मित्रता' क्या है ? ... 188
भाषण, मेक्सिको उत्तर अमरीकी सांस्कृतिक संस्थान, मेक्सिको सिटी, 19 अक्टूबर, 1961

चौथा भाग—साम्यवादी चुनौती

38. अगर मानस वापस आ सकते ... 195
भाषण, पोलिटिकल सायन्स सोसायटी, दिल्ली कॉलेज, नई दिल्ली, भारत, 15 अक्टूबर, 1952
39. सोवियत संघ को सबसे अधिक किसका भय है ... 199
भाषण, वाई. एम. सी. ए., हार्टफोर्ड, कॉनेक्टिकट, 21 अक्टूबर, 1953
40. संकट प्रतीक्षा नहीं करेगा ... 202
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 27 नवम्बर, 1955
41. एक प्रतियोगिता जिसमें हम हार नहीं सकते ... 205
सैंटरडे रिव्यू, 24 अगस्त, 1957
42. चीनी मुख्य भूमि पर एक दृष्टि ... 209
सैंटरडे इवनिंग पोस्ट, 4 अप्रैल, 1959
43. 'चीन की समस्या' पर पुनर्विचार ... 213
फॉरेन एफेयर्स, अप्रैल, 1960
44. रुस निरस्त्रीकरण क्यों नहीं करता ... 222
न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 19 अप्रैल, 1959
45. प्रतिरक्षा, निरस्त्रीकरण, और शांति ... 227
भाषण, मॉडर्न फोरम, सॉस ऐन्जेलस, कैलिफोर्निया, 11 मार्च, 1960
46. सोवियत भ्रजेयता की मिथ्या धारणा ... 234
भाषण, अमरीकी विदेश विभाग क्षेत्रीय सूचना सम्मेलन, डालास, टेक्सास, 27 अक्टूबर, 1961
47. साम्यवादी विचार-दर्शन की क्षीणता ... 239
फॉरेन एफेयर्स, जुलाई, 1962
48. साम्यवादी जगत को हमसे भ्रमण करने वाली तीन सोनाएँ ... 245
भाषण, अमरीकी विदेश विभाग क्षेत्रीय सूचना सम्मेलन, नेत्रास्वा विश्वविद्यालय, लिन्कन, 12 जून, 1962

दूसरा खण्ड—अमरीकी सपने की उपलब्धि

दूसरे खंड पर एक निजी टिप्पणी—वेस्टर वोल्स ... 257

पहला भाग—अधिक समृद्ध समाज की ओर

1. शांति और सबको काम ... 261
पूर्ण रोजगार अधिनियम, 1945, के समर्थन में वक्तव्य
2. बदलते हुए अमरीका के नकशे ... 264
सेबिंग अमेरिकन कैपिटलिज्म, संपादक-सीमूर ई. हैरिस
3. आर्थिक विकास पर एक नई दृष्टि ... 273
प्रतिनिधि सभा में भाषण, 29 जून, 1959
4. इस्पात के मूल्य और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ... 279
राष्ट्रपति आइजनह्वर को पत्र, 4 अगस्त, 1959
5. सातवें दशक का नया मोड़ ... 282
भाषण, गेल लॉ फोरम, न्यूहैवेन, कॉनेक्टिकट,
21 नवम्बर, 1961

दूसरा भाग—जिम्मेदार राज्य शासन : विकेंद्रीकरण की कुंजी

6. गवर्नर का कार्य, एक गवर्नर की दृष्टि में ... 289
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 24 जुलाई, 1949
7. हमारे स्कूलों की चुनौती ... 293
कॉनेक्टिकट राज्य विधान-मंडल को विशेष सदेश
9 नवम्बर, 1949
8. कॉनेक्टिकट में मकानों के अभाव की पूर्ति ... 298
'द्वयडेंस ऑफ ए नेशन', परिचर्चा, 30 नवम्बर, 1950
9. एक प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ... 302
रेडियो भाषण, 28 अगस्त, 1950
10. राज्य शासन का आधुनिकीकरण ... 304
कॉनेक्टिकट राज्य विधान-मंडल को विशेष
सदेश, अप्रैल 1950

तीसरा भाग—स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र मन

11. स्वतन्त्रता की अन्तहीन खोज ... 315
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 28 मई, 1950

12.	नई आप्रवास नीति की आवश्यकता सर्वे पत्रिका, नवम्बर, 1951	...	320
13.	एक अमरीकी बस्वे का चित्र—एसेक्स, कॉनेक्टिकट भापण, नई दिल्ली समाज कल्याण सम्मेलन, नई दिल्ली, भारत, 1952	...	325
14.	नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख सकते हैं सैंटरडे इवनिंग पोस्ट, 1 मार्च, 1958	...	329
15.	नीग्रो अधिकार—कार्यवाही का समय अभी है न्यू रिपब्लिक 6 जुलाई, 1959 और न्यूयार्क टाइम्स सप्लिमेण्ट, 17 जनवरी, 1 60	...	336
16.	नैतिक खाई समारम्भ भापण, स्मिथ कालेज, 5 जून 1960 पुनश्च	...	341 345

परिचयात्मक भूमिका

आज हमारी धाँखों के सामने एक ऐसी क्रांति हो रही है, जिसकी तुलना पुनर्जागरण काल में, और पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में अमरीका की खोज के फल-स्वरूप हुई क्रांति से की जा सकती है—इतनी असाधारण क्रांति कि सारी दुनिया उससे प्रभावित प्रतीत होती है। इतिहास के दृष्टिज पर पचास से अधिक नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है। करोड़ों स्त्री-पुरुष, जो लम्बे असें तक उपेक्षित और दबे हुए रहे, आज स्वतंत्रता की साँस ले रहे हैं, नई उमंगों के साथ सिर उठाकर चल रहे हैं, और प्रतिष्ठा की माँग कर रहे हैं।

पश्चिम में शक्ति के पुराने केन्द्रों को चुनीती देने वाले नए और विशाल शक्ति-केन्द्र उभर रहे हैं—चीन, हिन्दुस्तान, लातिन अमरीका, अरब देश और निकट भविष्य में ही अफ्रीका। इस सबका मतलब है कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर की ओर, उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यूरोपीय से गैर-यूरोपीय जगत की ओर, इतिहास के केन्द्र का व्यापक स्थानान्तरण हो रहा है।

तीन-चौथाई दुनिया आज यूरोपीय चौथाई से विद्रोह कर रही है—और हम अमरीकी निश्चय ही यूरोपीय चौथाई के अंग हैं। लेकिन इस व्यापक विद्रोह पर विचार करें, तो इसके चरित्र में तत्काल एक अन्तर्विरोध नजर आता है। पिछली पाँच शताब्दियों में पश्चिम ने जो औजार, संस्थाएँ और विचार निमित्त किए हैं, उन्हीं के द्वारा पश्चिम के विरुद्ध यह विद्रोह चलाया जा रहा है। विज्ञान और यान्त्रिकी इसके उपकरण हैं। प्रगति और परिवर्तन के पश्चिमी विचार इसके प्रेरक हैं। पश्चिम की असाधारण खोज, राष्ट्रीयता, इसका माध्यम है।

यहाँ एक और बड़ा अन्तर्विरोध है। विज्ञान और यान्त्रिकी के जो उपकरण आज गैर-यूरोपीय जगत का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वे बहुदेशीय हैं, बल्कि सार्वभौमिक हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीयता का राजनीतिक उपकरण क्षेत्रीय और वैशिष्ट्यवादी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्रांति के सभी उपकरण एकता लाने वाले हैं, जबकि राजनीतिक क्रांति की सारी शक्तियाँ विभाजक हैं।

एक महान् क्रांति से गुजरता हुआ यह गैर-यूरोपीय जगत, एक अवरदस्त छल्लांग के द्वारा यूरोपीय जगत के समकक्ष आने का प्रयास कर रहा है। इतने दिनों से यूरोपीय जगत जिस जीवन स्तर का उपभोग करता रहा है, उसमें और एशिया, अफ्रीका तथा

अधिकांश सातित अमरीका के चीन सदियों की सार्ई को यह एक ही पीढ़ी में पाटने का प्रयास कर रहा है।

क्या नए राष्ट्र बिना जातीय, धार्मिक, और बंधारिक संघर्ष की ज्वालाएँ उत्पन्न किए, स्वतन्त्रता और गुणार के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ? जाने-अनजाने हम सभी लोग एक कठिन दौड़ में लगे हुए हैं—एकता, समृद्धि और प्रगति की आशाप्रद और हितकारी शक्तियों, तथा दूट, युद्ध और विध्वंस की दुःखद और दुष्ट शक्तियों के बीच हो रही दौड़ में।

क्या अन्ततोगत्वा पश्चिम से स्वतन्त्र होने की माँग, पश्चिम की सहायता प्राप्त करने की माँग से अधिक समल प्रमाणित होगी ? क्या राजनीतिक अलगाव की लहर, सहयोग और संयुक्ति की लहर से अधिक सशक्त प्रमाणित होगी ? क्या हिंसक क्रान्ति के द्वारा कार्य करने वाली भयानक शक्तियाँ, विकास द्वारा प्रगति की लम्बी प्रक्रियाओं में बाधा डाल कर उन्हें कुठित कर देंगी ?

ये भयावह प्रश्न ससार के हर देश में राजनेताओं को बार-बार परेशान करते हैं।

इनमें से अधिकांश समस्याओं के लिए पश्चिम स्वयं ही जिम्मेदार है, उनसे अच्छी तरह परिचित है, और उनसे निपटना पश्चिम के लिए जरूरी है। इतिहास के इस सकट में पश्चिम की बुद्धिमत्ता, कल्पना, और उदारता पर ही भविष्य का रूप निर्भर है।

इस प्रसंग में अमरीका की स्थिति सर्वाधिक अनुकूल है। जबकि यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्य बनाए, और स्वयं अपने लाभ के लिए इन महाद्वीपों के लोगों का दोपण किया, यह अमरीका का महान् सौभाग्य था कि कम से कम अमरीकी महाद्वीप के बाहर, वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों से बचा रहा।

अतः जिन्हें 'अंधेरे' महाद्वीप कहा जाता था, उनके लोगों के सामने अमरीकी लोग बिना किसी दोष-भाव का से ग्रस्त हुए जा सकते हैं। यही नहीं, अन्य किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा, स्वशासन की, स्वतन्त्रता की, और सामान्य सार्वजनिक प्रबुद्धता की अमरीकी परम्पराएँ ज्यादा दीर्घकालीन हैं, और यही बातें हैं, जो आज एशिया और अफ्रीका के लोगों में आशा उत्पन्न करती, और उत्साह जगाती हैं।

हमारा धन, बुद्धि और कौशल के हमारे साधन, स्वशासन का हमारा अनुभव, सद्भावना की हमारी पूँजी, और इतिहास की अधिकांश दुःखद शक्तियों से हमारा बचाव, इन सबके कारण, अन्य लोगों भी पश्चिमी राष्ट्र की अपेक्षा, नए राष्ट्रों की सहायता करने के लिए हम ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं।

निर्दय ही हममें बटिनाइयाँ हैं, और हमें उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मिसाल के लिए, अलग्गार को नीति ने यूँ-जिम्मेदारी की एक परम्परा का पोषण किया। साम्राज्यवाद की रूढ़ अभिव्यक्तियों से हमारे बचाव ने हमें अधिकतम प्रबुद्ध

उपनिवेशवाद के भी विरुद्ध कर दिया, और अपने बहुतेरे यूरोपीय सहयोगियों की चट्टनाइयों को समझना हमारे लिए कठिन बना दिया। इसके साथ ही, कभी-कभी हम लोगों ने अति-शुद्धतावादी रीति से साम्राज्यवाद का विरोध किया, जिसने हम स्वयं आदिवासी और नीचो लोगों के प्रति अपने व्यवहार में पागड़ के आरोप का लक्ष्य बने। हमारी समृद्धि भी कभी-कभी बाधा बन जाती है। इससे न केवल कम सीभाग्यशाली राष्ट्रों में ईर्ष्या और सन्देह जन्म लेते हैं, बल्कि हममें भी यह विश्वास करने की प्रवृत्ति आती है कि ऐसा कुछ नहीं जो दकिन की सामर्थ्य के बाहर हो, या जिसे घन से खरीदा न जा सकता हो।

फिर भी, अमरीका की स्पष्टतः एक केन्द्रीय स्थिति है, और युद्धोत्तर-कालीन विश्व में उसकी एक निर्णायक भूमिका है। इसलिए, कि बड़े राष्ट्रों में अकेला अमरीका ही युद्ध के बाद धनी और सशक्त था, उसके साधन, कौशल, और राजनीतिक तथा प्रशासकीय संगठन को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची थी, और केवल वही इस स्थिति में था कि इतिहास के एक संकटपूर्ण क्षण में नेतृत्व ग्रहण कर सके।

अब यह कल्पना आदमी को गंभिरता से सोचने को मजबूर कर देती है, कि अगर नयी दुनिया बर्चिल के शब्दों में, 'पुरानी की रक्षा और मुक्ति के लिए आगे' न आती तो पश्चिमी जगत का—बल्कि समूचे विश्व का ही—क्या बनता। अगर अमरीका 'मानंत योजना' बनाकर उसके अन्तर्गत सहायता न देता; अगर पश्चिमी यूरोप के युद्ध-पीडित राष्ट्रों के स्वयं अपने पैरो पर खड़े होने तक वह उनके पुनर्वास में सहायता न करता; अगर वह (रुस द्वारा स्थल-मार्ग बन्द किए जाने पर) बलिन से हवाई यातायात की व्यवस्था करके उसे न चलाता—जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पिछले दिनों के इतिहास में एक मोड़ लाने वाली घटना थी; अगर वह निकट पूर्व में इंगलिस्तान द्वारा छोड़े गए धूम्र को भरने के लिए तैयार न होता; अगर कोरिया के संकट की उस पर चीन और निर्णायक प्रतिक्रिया न होती; अगर वह छठे दशक में सारी दुनिया ही में सकटापन्न लोगों की रक्षा करने के योग्य न होता और उसके लिए तत्पर न होता, तो इतिहास का जो क्रम हम आज देखते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न होता।

अमरीका का भविष्य चाहे जो भी हो, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि इतिहास की लगभग एक दशक की इस संकटपूर्ण अवधि में उसने घटनाओं की चुनौती का सामना किया, और अपनी बुद्धिमत्ता, अपने साधनों और अपने साहस से यह सब बनवाया कि पश्चिमी जगत अपनी रक्षा करे और भविष्य के कार्यों के लिए शक्ति एकत्रित करे।

विश्व शक्ति होने की आवश्यकताएँ पूरी करना सीखने में इंगलिस्तान को एक सौ साल लगे, और शायद पुरानी दुनिया का कोई अन्य राष्ट्र—स्पेन या फ्रान्स या जर्मनी या रुस, या जापान भी—सीख ही नहीं सका। यह आश्चर्यजनक बात है कि अमरीका ने अपने अन्दर गुना दिमाग रखने की एक विशाल क्षमता और एक विशाल साधन-सम्पन्नता और उन साधनों का उपयोग करने की योग्यता खोज ली।

बोस वर्षों से भी कम समय में उसने जितना कुछ सीखा लिया है, इस पर गौर करें !

उसने सीख लिया है कि विश्व सचमुच एक विश्व है, कोई राष्ट्र अपने-आप में एक अलग टापू नहीं है, और यह कि हर राष्ट्र के दुर्भाग्यों, असफलताओं, सबटों और बर्ह्याण की जिम्मेदारी में कुछ हद तक हमारा भी हिस्सा है ।

कि, दैवी विधान में यूरोपीय जगत, गैरे जगत, ईसाई जगत का कोई विशेषाधिकारपूर्ण स्थान नहीं है ।

कि विश्व को साफ-साफ हमारे और रही, इन दो विरोधी श्रेणियों में नहीं बाँटा जा सकता, बल्कि विश्व सचमुच कई शक्ति-केन्द्रों में बँटा हुआ है, और दो विश्वों की धारणा पर आधारित किसी भी रणनीति की असफलता अनिवार्य है ।

कि हम दूसरे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा नहीं लाद सकते, जो दुर्बल हैं, उन पर भी नहीं, और यह कि हम दूसरे लोगों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपनी नीति या राजनीति की हमारी अपनी धारणाओं को अपना लें या उनसे सहमत भी हों ।

कि हम तटस्थ (राष्ट्रों) पर पक्ष लेने के लिए दबाव डालने का प्रयास न करें, बल्कि तटस्थता को स्वीकार करें और समझें ।

कि सहायता और पुनर्वास के महत्वपूर्ण कार्यों में हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से काम करें और अन्य राष्ट्रों के साथ—प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों के साथ भी—सहयोग करें ।

कि लगभग हर स्थिति में सैनिक सहायता की अपेक्षा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहायता कहीं अधिक प्रभावकारी होती है ।

कि शक्ति की, अणुशक्ति की भी, सीमाएँ होती हैं, और यह कि अधिकांश में सैनिक शक्ति की सीमाएँ स्वयं उसमें ही अन्तर्निहित होती हैं ।

कि हम सभी विदेश-नीति से सम्बद्ध हैं, और वह कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी सम्बद्धता पूर्ण सम्बद्धता है । कि हमारे काल में शान्ति नहीं है, भगड़े और सकट ही सामान्य हैं; कि जिन सकटों से दुनिया के लोग इतने दिनों से पीड़ित होते रहे हैं, अमरीका उनसे बचा नहीं रह सकता ।

इनमें से अधिकांश बातों को आज हम मानकर चलते हैं, किन्तु हमारे वैदेशिक सम्बन्धों के समूचे इतिहास में, शायद हमारे सारे इतिहास में ही, ज्ञानार्जन में हुई यह सर्वप्रमुख प्रगति है ।

×

×

×

इस नए उद्यम की, जिससे हम सब इतने अविच्छिन्न रूप में सम्बद्ध हैं, एक रोचक विशेषता है एक नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी का जन्म—अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिकारी जो आज़ादी से महाद्वीपों में घूमता है, जो हिन्दुस्तान, बोलिविया, काँगो और तैवान की समस्याओं से उसी तरह परिचित है जैसे पूर्व कालिक राजनेता मैसाचुसेट्स, मलाबामा, मिनेसोटा और ऑरिगोन की समस्याओं से हुमा करते थे; जो

अपने आप को किसी विशेष हित, या अर्थतंत्र, या राजनीतिक व्यवस्था का प्रवक्ता नहीं समझता, वरन् मनुष्य के हितों का प्रवक्ता समझता है।

निश्चय ही, इसके पूर्व-उदाहरण मिलते हैं, विशेषतः अठारहवीं शताब्दी में। बेन्जामिन फ्रॉमसन, जो लंदन के रॉयल इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष रूप में और बर्लिन के प्रधान मंत्री के रूप में एक समान प्रभावी थे, या ऐण्ड्रीज बर्नस्टॉर्फ, जो जर्मन राज्यों के दरबारों से बड़ी आसानी के साथ डेनमार्क के दरबार में चले गए। वॉल्टेयर, कॉण्टॉसैंट, फ्रैकतिन, थॉमस पेन—विशाल आत्माएँ, जो अपने को मानवता के सेवक मानती थीं। किन्तु विश्व के अधिकांश भागों में आधुनिक राष्ट्रीयता ने इस सब का अन्त कर दिया।

अब अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनेता, जो दूसरों की सेवा के द्वारा अपने देश की सेवा करता है, एक बार फिर आगे आ रहा है। नार्वे मेनान्सेन, डेल्जियम में स्नाक, फ्रांस में जॉर्ज मॉने, इंग्लिस्तान में चर्चिल, हैमर-शिल्ड, मिर्डल, बॉयड और, ऊ थाण्ट, श्रीमती पंडित, चार्ल्स मलिक, एलीनर रूजवेल्ट, स्टीवेन्सन—हमारी आँखों के सामने बन रहे नए विश्व के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले स्त्री-पुरुषों की यह नयी घंटी है।

इस नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी की विशेषताएँ क्या हैं ?

प्रथम, वह अपने आप को क्षेत्रीय राष्ट्रीयता की पूर्व-धारणाओं और सीमाओं से मुक्त कर पाता है, और दूसरे राष्ट्रों और लोगों के मनों को सहानुभूतिपूर्वक समझ पाता है। सभी राष्ट्रों और जातियों की समानता को केवल बौद्धिक रूप में नहीं वरन् स्वतःस्फूर्त रीति से स्वीकार कर लेता है। जिनके बीच उसका पालन-पोषण हुआ था, उनसे बिलकुल भिन्न हितों, आदतों, प्रतिमानों, और संस्कृतियों को सहानुभूतिपूर्वक समझ सकता है।

दूसरे, वह स्वयं अपने अतीत, या अपने वर्तमान के साथ भी अपनी सम्बद्धता से सीमित नहीं होता, वरन् इतिहास और विज्ञान की उन महान् धाराओं को समझ सकता है, जो इतनी अटल रीति से विश्व का पुनर्निर्माण कर रही हैं। वह उन धाराओं के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के, और एक जाति और महाद्वीप द्वारा दूसरी जाति और महाद्वीप के शोषण के अन्तिम अवशेषों को बहाए ले जा रही हैं। सारी दुनिया में ही, तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ जो नई सकल उभर रही है, उसमें स्वयं राष्ट्र के स्थान को वह वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देख सकता है, यद्यपि वह कभी उसके प्रति उदासीन नहीं रहता।

तीसरे, वह इस बात को समझता है कि इतिहास और राजनीति का एक अविच्छिन्न ताना-बाना है, जिसके धागे हर गाँव, कस्बे, और शहर से हर अन्य गाँव, कस्बे और शहर तक, देश से देश तक और महाद्वीप से महाद्वीप तक फैले हैं। वह जानता है कि आर्थिक और राजनीतिक अलगाव के साथ-साथ बौद्धिक और नैतिक अलगाव का वक्त बीत गया—कि ब्रह्मा या कांगों में जो कुछ होता है, उसका सम्बन्ध

दोस वर्षों से भी कम समय में उसने कितना कुछ सीख लिया है, इस पर गौर करे !

उसने सीख लिया है कि विश्व सचमुच एक विश्व है, कोई राष्ट्र अपने-प्राप में एक अलग टापू नहीं है, और यह कि हर राष्ट्र के दुर्भाग्यों, असफलताओं, संकटों और कल्याण की जिम्मेदारी में कुछ हद तक हमारा भी हिस्सा है ।

कि, दैवी विधान में यूरोपीय जगत, गोरे जगत, ईसाई जगत का कोई विशेषाधिकारपूर्ण स्थान नहीं है ।

कि विश्व को साफ-साफ हमारे और हूँ, इन दो विरोधी खेमों में नहीं बाँटा जा सकता, बल्कि विश्व सचमुच कई दक्षिण-वेन्द्रों में बाँटा हुआ है, और दो विश्वों की धारणा पर आधारित किसी भी रणनीति की असफलता अनिवार्य है ।

कि हम दूसरे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा नहीं लाद सकते, जो दुर्बल हैं, उन पर भी नहीं, और यह कि हम दूसरे लोगों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अर्थनीति या राजनीति की हमारी अपनी धारणाओं को अपना लें या उनसे सहमत भी हो ।

कि हम तटस्थ (राष्ट्रों) पर दबाव डालने का प्रयास न करें, बल्कि तटस्थता को स्वीकार करें और समझे ।

कि सहायता और पुनर्वास के महत्त्वपूर्ण कार्यों में हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से काम करें और अन्य राष्ट्रों के साथ—प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों के साथ भी—सहयोग करें ।

कि लगभग हर स्थिति में सैनिक सहायता की अपेक्षा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहायता कहीं अधिक प्रभावकारी होती है ।

कि शक्ति की, अणुशक्ति की भी, सीमाएँ होती हैं, और यह कि अधिकांश में सैनिक शक्ति की सीमाएँ स्वयं उसमें ही अन्तर्निहित होती हैं ।

कि हम सभी विदेश-नीति से सम्बद्ध हैं, और वह कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी सम्बद्धता पूर्ण सम्बद्धता है । कि हमारे काल में शान्ति नहीं है, भगड़े और सकट ही सामान्य हैं; कि जिन संकटों से दुनिया के लोग इतने दिनों से पीड़ित होते रहे हैं, अमरीका उनसे बचा नहीं रह सकता ।

इनमें से अधिकांश बातों को आज हम मानकर चलते हैं, किन्तु हमारे वैदेशिक सम्बन्धों के समूचे इतिहास में, शायद हमारे सारे इतिहास में ही, ज्ञानार्जन में हुई यह सर्वप्रमुख प्रगति है ।

×

×

×

इस नए उद्यम की, जिससे हम सब इतने अविच्छिन्न रूप में सम्बद्ध हैं, एक रोचक विशेषता है एक नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी का जन्म—अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिकारी जो आजादी से महाद्वीपों में घूमता है, जो हिन्दुस्तान, बोलिविया, कांगो और तैवान की समस्याओं से उसी तरह परिचित है जैसे पूर्व कालिक राजनेता मैसाचुसेट्स, अलाबामा, मिनेसोटा और मॉरिंगोन की समस्याओं से हुआ करते थे; जो

अपने आप को किसी विशेष हित, या अर्चनार्थ, या राजनीतिक व्यवस्था का प्रवक्ता नहीं समझता, वरन् मनुष्य के हितों का प्रवक्ता समझता है।

निश्चय ही, इसके पूर्व-उदाहरण मिलते हैं, विशेषतः अठारहवीं शताब्दी में। बेन्जामिन फ्रॉमसन, जो लंदन के रॉयल इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष रूप में और ववैरिया के प्रधान मंत्री के रूप में एक समान प्रभावी थे, या ऐण्ड्रीज बनेस्टॉफ, जो जर्मन राज्यों के दरबारों से बड़ी आसानी के साथ डेनमार्क के दरबार में चले गए। वॉल्टेयर, कॉण्टॉसैंट, फ्रैंकलिन, थॉमस पैन—विशाल आत्माएँ, जो अपने को मानवता के सेवक मानती थीं। किन्तु विश्व के अधिकांश भागों में आधुनिक राष्ट्रीयता ने इस सत्र का अन्त कर दिया।

अब अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनेता, जो दूसरी की सेवा के द्वारा अपने देश की सेवा करता है, एक बार फिर आगे आ रहा है। नावें मे नान्सेन, बेल्जियम में स्नाक, फ्रांस में जॉर्ज मॉन, इंगलिस्तान में चर्चिल, हैमर-सोल्ड, मिडन, बॉयड और, ऊ थाण्ट, श्रीमती पडित, चार्ल्स मलिक, एलीनर रुजवेल्ट, स्टीवेन्सन—हमारी आँखों के सामने बन रहे नए विश्व के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले स्त्री-पुरुषों की यह नयी श्रेणी है।

इस नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी की विशेषताएँ क्या हैं ?

प्रथम, वह अपने आप को क्षेत्रीय राष्ट्रीयता की पूर्व-धारणाओं और सीमाओं से मुक्त कर पाता है, और दूसरे राष्ट्रों और लोगों के मनों को सहानुभूतिपूर्वक समझ पाता है। सभी राष्ट्रों और जातियों की समानता को केवल बौद्धिक रूप में नहीं वरन् स्वतःस्फूर्त रीति से स्वीकार कर लेता है। जिनके बीच उसका पालन-पोषण हुआ था, उनसे बिलकुल भिन्न हितों, आदतों, प्रतिमानों, और संस्कृतियों को सहानुभूतिपूर्वक समझ सकता है।

दूसरे, वह स्वयं अपने अतीत, या अपने वर्तमान के साथ भी अपनी सम्बद्धता से सीमित नहीं होता, वरन् इतिहास और विज्ञान की उन महान् धाराओं को समझ सकता है, जो इतनी अदृश्य रीति से विश्व का पुनर्निर्माण कर रही हैं। वह उन धाराओं के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के, और एक जाति और महाद्वीप द्वारा दूसरी जाति और महाद्वीप के शोषण के अन्तिम अवशेषों को बहाए ले जा रही हैं। सारी दुनिया में ही, तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ जो नई शक्ति उभर रही है, उसमें स्वयं राष्ट्र के स्थान को वह वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देना सकता है, यद्यपि वह कभी उसके प्रति उदासीन नहीं रहता।

तीसरे, वह इस बात को समझता है कि इतिहास और राजनीति का एक अविच्छिन्न ताना-बाना है, जिसके भागे हर गाँव, कस्बे, और शहर से हर अन्य गाँव, कस्बे और शहर तक, देश से देश तक और महाद्वीप से महाद्वीप तक फैले हैं। वह जानता है कि धार्मिक और राजनीतिक भ्रमण के साथ-साथ बौद्धिक और नैतिक भ्रमण का वक्त बीत गया—कि ब्रह्मा या कांगों में जो कुछ होता है, उसका सम्बन्ध

कॉन्वेंटिकट अथवा यॉर्कसायर के नागरिक से भी है। कि जिन लोगों के लिए भोजन, दवा-इए, झोझार, मशीनों, स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय आदि की व्यवस्था नहीं है, उन्हें ये सारी वस्तुएँ प्रदान करने के महान् उद्यम से हम सभी लोग सम्बद्ध हैं। वह जानता है कि स्वतंत्रता का भी एक अविच्छिन्न ताना-बाना है, कि अपने बीच छोटे-से-छोटे आदमी के साथ हम जो बुद्ध करते हैं, वह सारी मानवजाति के साथ करते हैं, और यह कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की कसौटी, विदेशों में उसका समर्थन करने के साथ-साथ, देश में उसे अमनी रूप देने की तत्परता भी है।

चौथे, अपने सारे आदर्शवाद के बावजूद, वह एक दुनियादार आदमी होता है— एक व्यवहार कुशल प्रशासक, ठिकाऊ दिमाग वाला और कठोर स्थितियों का सामना कर सकने वाला। और जिन्दा रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आलोचनाओं से जल्दी प्रभावित न हो। उसके लिए प्रशासन की नित्य प्रति की समस्याओं का अनुभव आवश्यक है, यह समझना आवश्यक है कि काम करते जाना और नतीज निकालना, भाषण कला और उदारतापूर्ण मुद्राओं से ज्यादा ज़हरी है।

इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कामचारी की चेस्टर बील्स से ज्यादा अच्छी मिसाल और कोई नहीं है।

श्री बील्स ने लिखा है, “1924 में जब मैं कातेज का एक वरिष्ठ छात्र था, मैंने अपना जीवन शासन में लगाने का निश्चय किया।” वे हमें यह भी बताते हैं—और उनका कथन बड़ा अर्थगम्य है—कि 1924 में येल में उनकी कक्षा में उनके अतिरिक्त तीन या चार ही छात्र थे, जिनकी रूचि सार्वजनिक जीवन को अपने नाम में थी। परिस्थितियों ने उनकी इस प्रारम्भिक महत्वाकांक्षा में बाधा डाली, किन्तु उसे नष्ट नहीं किया। जब 1941 में अमरीका युद्ध में फँसा, तो वे बड़ी तत्परता से निजी उद्यम को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम में आ गए, और पिछले दो दशकों में उन्होंने अपनी शक्ति और प्रतिभा सार्वजनिक उद्यम में ही लगाई है।

श्री बील्स के कार्य-जीवन में चार बड़े मोड़ नज़र आते हैं। पहला मोड़ युद्ध-काल में सार्वजनिक सेवा की माँग के समय आया। पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अधीन मूल्य प्रशासक के रूप में, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में ट्राइब्यूनली के विशेष गृहयुक्त के रूप में श्री बील्स ने राजनीति और प्रशासन के कुछ कठिन पाठ सीखे, और विद्वत् की वे यात्राएँ कीं, जिन्होंने उन्हें हर महाद्वीप में, और लगभग हर देश में, एक परिचित व्यक्ति बना दिया है, और जिनसे वह मानसिक आधार-भूमि तैयार हुई, जिसके फल-स्वरूप 1947 के आरंभ में उन्होंने अपना वह असाधारण निवृत्त तैयार किया, जिसमें ‘मातृ संयोजना’ की पूर्ण कल्पना थी। वह निवृत्त इस अग्रह में सज्जित है।

दूसरा मोड़ या कॉन्वेंटिकट के गवर्नर के रूप में उनका चुनाव। इस पद पर कार्य करते हुए, जनसामान्य पर आधारित लोकतंत्र और जनसामान्य पर आधारित उदारवाद का महत्त्व, नित्यप्रति वे, और सुपरिचित रूप में उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ। इसने स्थानीय प्रश्नों का राष्ट्रीय और विद्वत् प्रश्नों के साथ भी सम्बन्ध स्पष्ट रूप में

सामने आया। इससे उनमें खेत और गाँव, तथा कारखाने और दफ्तर के लोगों को सम्बोधित करने की आदत भी आई, जिसके फलस्वरूप वे कई देशों में बड़े विविध प्रकार के श्रोताओं के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए हैं।

तीसरा मोड़ आया जब वे हिन्दुस्तान में राजदूत नियुक्त हुए। इससे उन्हें एक अन्य सम्यक्ता और एक अन्य संसार का परिचय मिला, और एक अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कर्मचारी के रूप में उनकी शिक्षा इससे पूर्ण हो गई। श्री वॉल्स के लचीलेपन का यह प्रमाण है कि वे असाधारण कौशल के साथ अपने को इस स्थिति के, और हिन्दुस्तान के बौद्धिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल बना सके, और वह स्वर निर्धारित कर सके, जिसे उनके कार्यकाल के बाद नई दिल्ली में अमरीकी प्रवक्ताओं ने बड़ी सफलता के साथ कायम रखा है।

इसने उन्हें अमरीकी सार्वजनिक जीवन में हिन्दुस्तान और उसके पड़ोसियों के बारे में सबसे अधिक जानकारी व्यक्ति भी बनाया—उन्होंने अमरीका और हिन्दुस्तान के बीच ऐसे समय मध्यस्थता की, जब हिन्दुस्तान बड़कर विश्व घनितियों की पहली श्रेणी में आ रहा था, और निश्चय ही एशिया की स्वतन्त्र शक्तियों में प्रथम था।

चौथा मोड़ 1960 में आया, जब कॉन्क्रेट से कांग्रेस के सदस्य के रूप में, अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में वे पहले सीनेटर केनेडी के विदेश-नीति सम्बन्धी सलाहकार चुने गए, और फिर डेमॉक्रेटिक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन की मंच समिति (नीति वक्तव्य तैयार करने वाली समिति) के अध्यक्ष चुने गए।

इन अनुकूल स्थिति में उन्होंने डेमॉक्रेटिक चुनाव-वक्तव्य के अधिकांश विदेश सम्बन्धी अंश, नागरिक अधिकार सम्बन्धी अंश, और आर्थिक नीति सम्बन्धी अंश के भी काफी हिस्से का मसौदा तैयार किया। इस वक्तव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं—प्रथम, परेजू नीति और विश्वव्यापी प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से, डेमॉक्रेटिक दल द्वारा स्वीकृत वक्तव्यों में यह सबसे अधिक उदार है। दूसरे, इसे सम्मेलन ने न्यूनतम विवाद के साथ, सामान्य उल्लाह के बीच स्वीकार किया।

इस उपलब्धि का श्रेय बहुत कुछ श्री वॉल्स को है। और यह श्री वॉल्स का सौभाग्य था कि मतदाताओं ने वक्तव्य की इन नीतियों का समर्थन किया, और नये प्रशासन ने सार रूप में उन्हें स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने पहले अवर विदेश सचिव के रूप में कार्य किया, और अर अफ्रीका, एशिया, और लातिन अमरीका सम्बन्धी मामलों में राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका कार्यक्षेत्र काफी बड़ा है, और सद्बुद्धि, सद्भाव, विनोदप्रियता और सत्-परिणामों सहित वे उसका संचालन करते हैं।

सार्वजनिक सेवा के बीस वर्षों में श्री वॉल्स निरन्तर अपना मत व्यक्त करते रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने परेजू, और विशेष रूप में, विदेश-नीति सम्बन्धी अपना मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए सान पुस्तकें लिखी हैं। अमरीकी सार्वजनिक जीवन में शायद कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसने पिछले दशक में अमरीकी लोगों

के समक्ष विदेश-नीति सम्बन्धी बातें करते हुए उनसे अधिक समय और सजिद गवाही हो । इकतालीस राज्यों में, धीसियों विश्व-विद्यालयों में, डेमाक्रैटिक और रिपब्लिकन दोनों प्रकार के श्रोताओं के तीन गमान एवं से, उन्होंने अपनी धार गोंगों तर पढ़ेंवा सकने की प्रसाधारण क्षमता प्रदर्शित की ? ।

फलस्वरूप, उनके अनन्तर रिमाण में लोगों और भावनों की एक धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही है । उनमें से कुछ निश्चिन्तापूर्ण परिणामों के लिए लिगे गए लेख हैं, कुछ काग्रत के सदस्यों अथवा विदेश-नीति निर्धारित करने वालों की सम्बोधित किमे गए प्रभावशाली तर्क हैं, कुछ अग्र-सरकारी प्रतिवेदन हैं, कुछ सामान्य या विशिष्ट अवसरों पर दिये गए भाषण हैं, और कुछ बिना किसी सहायक सामग्री के सभागत दिये गए वक्तव्य हैं ।

हम यहाँ उनके लेखों और भाषणों का एक प्रतिनिधि गकलन प्रस्तुत करने हैं, जो इसके पहले पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हुए ।

पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं 1943 में गधोय मूल्य प्रशासक के रूप में, सार्वजनिक सेवा में श्री वोलस के प्रवेश से आरम्भ करूँ, जब उन्होंने एक विशाल और अव्यवस्थाग्रस्त अभिकरण को अपने हाथ में लिया, प्रशासकीय शल्य-क्रिया का एक चमत्कार कर दिखाया और मूल्य प्रशासन के कार्यालय को मंहगार्द और मुद्रा-स्फीति के विरुद्ध एक तेजी से काम करने वाला, कुशल और सुगठित मीडार बना दिया ।

किन्तु इस युद्धकालीन सामग्री पर नजर डालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उसमें युद्धोत्तर-काल की चेतना और दृष्टि निरन्तर मौजूद होने पर भी, उसकी अधिकांश अन्तर्बन्धु काल सीमित है । फलस्वरूप मैंने इस पुस्तक को दान्ति स्थापना के बाद से, और युद्धोत्तर काल में श्री वोलस के लेखन से आरम्भ करने का निश्चय किया ।

मैंने इन सामग्री की दो व्यापक समूहों में विभाजित किया है—एक, ऐसी सामग्री जिसमें वैदेशिक मामलों के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया गया है, और दूसरे, ऐसी सामग्री जिसका सम्बन्ध, मुख्यतः देश की आन्तरिक स्थिति से है ।

पिछले दिनों, श्री वोलस का योग विदेश-नीति के क्षेत्र में रहा है । अतः यह उचित ही है कि पुस्तक की अधिकांश सामग्री इसी कोटि की ही । विदेश-नीति सम्बन्धी सामग्री की फिर उपयुक्त उप-खंडों में विभाजित किया गया है, जिनका सम्बन्ध सामान्य प्रश्नों से, आर्थिक विकास के प्रश्नों से, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के 'नए' राष्ट्रों की समस्याओं से, और हठीली समस्याओं से है, जो पृथ्वी के हर कोने में हमारे सामने आती हैं ।

यह विभाजन हितों की असम्बद्धता का सूचक न होकर, केवल सुविधा की दृष्टि से किया गया है । जिस क्रम में इसे छापा गया है, उस क्रम से पढ़ने पर वह दार्शनिक एरुमूर्तता और सगति हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, जो श्री वोलस की सार्वजनिक

जीवन में उनके प्रवेश के समय से ही अनुप्राणित करती रही है ।

इस सामग्री को संकलित करने में, कुछ रचनाओं को संपादित और संक्षिप्त करने की अनुमति मुझे श्री बोल्स ने दी थी । इस अधिकार का मैंने पूरा उपयोग किया है । किन्तु, ऐसा करते हुए मैंने कुछ मुख्य विषयों को रेखांकित करने का प्रयत्न किया है, जिनका प्रतिपादन श्री बोल्स ने इस अर्थ में किया है, और जिनकी चर्चा उन्होंने विभिन्न सन्दर्भों में की है ।

पिछले दो दशकों में श्री बोल्स के विचारों का कुछ अंश अब राष्ट्रीय नीतियों और विधियों का अंश बन गया है । उनका ज्यादा बड़ा हिस्सा आज हमारी राष्ट्रीय बहम के केन्द्र में है । और कुछ हिस्सा ऐसे निर्णयों की ओर भी संकेत करता है जिन का सामना हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए जिनका सामना हमें करना पड़ेगा ।

इस प्रकार अपनी सम्पूर्णता में, यह पुस्तक विचार और क्रिया के पारस्परिक सम्बन्ध को, एक क्रान्तिकारी जगत में विचारों की अदम्य शक्ति की नाटकीय रीति से प्रस्तुत करती है ।

समय बीतने के साथ, चेस्टर बोल्स स्थानीय से राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय से विश्व व्यक्तित्व बन गए हैं । इन सारे वर्षों में वे राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने और राष्ट्रीय अन्तरात्मा को रूपायित करने के लिए सोल्साह और निस्वार्थ रीति से काम करते रहे हैं । और आपने देशवासियों को निरन्तर याद दिलाते रहे हैं कि महानता का यही समय है । और वे स्वयं उन लोगों में से रहे हैं, जिन पर पेरिक्लिस के ये स्मरणीय शब्द लागू होते हैं कि "यह जानते हुए कि स्वतन्त्रता सुख का रहस्य है, और स्वतन्त्रता का रहस्य वीर हृदय है, शत्रु के आक्रमण के समय वह चुपचाप अलग नहीं खड़ा रहा ।"

—हेनरी स्टील कोमागर

एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स

15 जून, 1962

पहला खण्ड

संयुक्त राज्य अमरीका और
विश्व-क्रान्ति

पहले खण्ड पर एक निजी टिप्पणी

युद्ध के बाद के मेरे लेखों और भाषणों का यह संकलन तैयार करने के लिए मैं प्रोफ़ेसर कोमागर का आभारी हूँ।

अमरीका के जागतिक लक्ष्यों को मैं जिस रूप में देखता हूँ और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कुछ मैं आवश्यक समझता हूँ उससे सम्बन्धित सामग्री पहले खंड में है। एक श्रेणी के रूप में, यह सामग्री विदेश-नीति के बहुतेरे निर्णायक प्रश्नों पर एक राष्ट्रीय द्विदलीय सहमति की ओर धीरे-धीरे हुई अमरीका की प्रगति को रेखांकित करती है।

इस सहमति में शस्त्रीकरण की निरन्तर चल रही होड़ के प्रति एक गम्भीर राष्ट्रीय चिन्ता के साथ-साथ, प्रत्यक्ष और परोक्ष आक्रमण का विरोध करने की और प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं सहित पर्याप्त प्रतिरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता की स्वीकृति शामिल है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्त्व की स्वीकृति, विश्व व्यापार के विस्तार के लिए हमारी प्रतिबद्धता, और एशिया, अफ्रीका तथा लातिन अमरीका के महत्त्व की जहाँ मानव-जाति का बहुतांश निवास करता है, बड़ी देर से की गई स्वीकृति भी शामिल है।

किन्तु इन पृष्ठों को पुनः पढ़ते हुए मुझे विकासशील राष्ट्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों और प्राथमिकताओं सम्बन्धी बहुतेरे अमरीकियों में अब तक चली आ रही गभीर असह-मतियों की और अपनी राष्ट्रीय सहमति को नयी स्थितियों पर लागू करने में हमारे ढीलेपन की भी याद आती है।

उदाहरण के लिए, प्रगति के लिए मिनता की योजना ने अपने लातिन अमरीकी पड़ोसियों के प्रति हमारी बीस वर्षों की उदासीनता का स्थान बड़ी देर से लिया है।

देस में मिथ्या धारणाओं के संचय से और विदेशों में घमास्थिति के साथ हमारी प्रतिबद्धताओं से; एशिया में कार्य करने की हमारी स्वतन्त्रता में अब भी बाधाएँ आती हैं।

अब भी हर सात अमरीका की कांग्रेस में बहुमत की यह गमभाने के लिए अना-धारण प्रयत्न करने पड़ते हैं कि तयारकथित सोवियत सट्टान को शाय करने, और स्वतं-त्रता के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, स्वतंत्र राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास सर्वाधिक आशाएद मार्ग है।

इसमें कोई शक नहीं कि सड़क बना और समतल की सड़कों से हम समतली सेन बड़ी सेना से और बहुत दूर निकल पाएँ। लेकिन क्या हम अपने सगापारण सड़कीन सड़कों का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं ?

और सबसे अधिक शक्ति प्रदा है—क्या हम सड़क सेना सड़क और मोनाम्पनी सड़क सड़क और सभी सड़कों के लिए अधिकतम शक्ति पर सगापारण सड़क के लिए हैं रहे सड़ककारी सड़क से अधिकतम सड़कीनी हो सकता है ?

सड़कीनी सड़कीनी के सड़क से सड़क से समतलीनी सड़क इन सड़कों के सड़क उतार देने हैं, इससे, सड़क सड़क सड़क से, सड़कीनी के सड़क से हमारे सड़क का सड़क निर्धारित होगा ।

—चेस्टर बील्स

पहला भाग

विश्व में हमारे लक्ष्य

हम में से जो लोग कम भीरु है, वे कम से कम इतना कर सकते हैं कि वर्त्तमान पीढ़ी के सामने जाएँ, और अपने काल के कुछ मूल सत्यों के लिए आग्रह करें—कि पृथ्वी पर मनुष्य के भविष्य का नष्ट होना आवश्यक नहीं; कि संकट आएगा ही, इसे स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं; कि हमारा राजनीतिक कौशल अब भी हमें विनाश से बचा सकता है; कि हमारे नैतिक प्रतिमान आज भी मौजूद हैं; कि युद्ध और अन्याय जैसी कुछ वस्तुएँ अन्तहीन प्रतीत हो सकती हैं, किन्तु ये वस्तुएँ हमेशा गलत होती हैं, उनसे हमेशा लड़ना होगा, और किसी दिन इन पर विजय पानी होगी।

26 जुलाई, 1954

धारा को मोड़ने का अवसर

अल्प-विकसित राष्ट्रों को दीर्घकालीन आर्थिक और प्राविधिक सहायता देने, तथा एक नए समेकित यूरोप के निर्माण के लिए सर्व प्रथम प्रस्तुत प्रस्तावों में से एक श्री बौल्स ने फ्रीडम हाउस, विल्की मेमोरियल बिल्डिंग, न्यू यॉर्क में, 17 जनवरी, 1947 को दिये गए एक भाषण में प्रस्तुत किया।

अगर अमरीकी लोग अगले बीस वर्षों तक, कम भाग्यशाली देशों के विकास के लिए हमारी कुल आय का दो प्रतिशत प्रति वर्ष लगाने का समर्थन करे, तो हम इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं।

विदेशों में खगाई गई निजी पूंजी के अतिरिक्त, इस घन से पृथ्वी की महान् नदियों में संकड़ियों की शक्ति का उपयोग करने में, बाढ़ों को खतम करने में, विशाल विजली-घरों के निर्माण में, और करोड़ों व्यक्तियों के लाभ के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। समूचे पूर्व में, दक्षिण अमरीका में, और यूरोप में आधुनिक परिवहन व्यवस्थाओं के निर्माण में इससे बड़ी मदद मिलेगी।

यह धन लगाकर अमरीकी लोग दुनिया के कई हिस्सों में शान्तिपूर्ण उद्योगों को आधुनिक बनाने में सहायता कर सकते हैं, जिससे फिर यूरोप, एशिया, हिन्दुस्तान, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका में जीवन-स्तर काफी बढ़ जाएगा, और असंख्य लोगों में एक-दूसरे के, और अमरीकी उद्यम के उत्पादनों को खरीदने की क्षमता आएगी।

हमारी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत—चार अरब डालर—प्रतिरक्षा सम्बन्धी हमारे वर्तमान खर्च का केवल एक तिहाई है। नाज़ियों और फ़ासिस्टों के विरुद्ध युद्ध करने में प्रति मास हमारा जो खर्च हुआ था, यह रकम उसकी केवल आधी है। फिर भी, यह निश्चित है कि बहूतेरे लोग इसे अपव्ययपूर्ण फिज़ूल खर्चों कहेंगे, 'साम चाचा' के 'बुढ़ू चाचा' बनने का एक और उदाहरण बताएँगे।

इन आलोचकों का दृष्टिकोण गलत है, और मैं आशा करता हूँ कि उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा खर्च अमरीकी लोगों द्वारा अपनी पूंजी का अधिकतम बुद्धि-पूर्ण उपयोग होगा। इसने सारी दुनिया में करोड़ों मनुष्यों को असीमित आर्थिक लाभ होगा। यह इस बात का जीवन्त प्रमाण होगा कि हमारी अमरीकी व्यवस्था न केवल हम अमरीकियों को एक ऊँचा जीवन-स्तर प्रदान कर सकती है, वरन् अधिक आत्म-

सम्मान के साथ, अधिक समृद्ध जीवन की ओर प्रागे बढ़ने में दूसरों की भी सहायता कर सकती है। शान्ति की रक्षा के लिए, यह हमारी सबसे सस्ती गारंटी होगी।

यह धन किन्हीं शक्तों के साथ, या सकुचित राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के देशों, तथा यूरोप के अन्य देशों के साथ-साथ पोलैण्ड, जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, और पूर्वी यूरोप के युद्ध से विनष्ट राष्ट्रों को भी कर्ज देने का समर्थन करना चाहिए।

किन्तु हमें यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि इस धन का यथासंभव प्रभावकारी उपयोग किया जाय। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय सीमाओं से बंधे हुए नहीं होंते। अतः प्राकृतिक साधनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए, जो जीवन-स्तर को उठाने के लिए अनिवार्य है, सारी दुनिया में ही अधिकाधिक क्षेत्रीय आधार पर नियोजन करना आवश्यक है।

अमरीका में सीमाव्यवस्था हमारे पास इतना काफी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, कि यहाँ उच्च औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक व्यापक बाजारों का विकास किया जा सकता है। इसी कारण, सोवियत रूस में भी ऐसा ही हो सकता है। अगर व्यवस्थित आर्थिक विकास और राजनीतिक अभिवृद्धि के आधार पर शान्ति कायम रखनी है, तो बाकी दुनिया को भी अधिकाधिक ऐसा ही अवसर मिलना चाहिए।

यूरोप ऐसे आर्थिक एकीकरण की, सभावनाओं का एक अच्छा उदाहरण है। यूरोप के विकास, और अतः राजनीतिक विकास में सहायता देने के लिए हमारे खर्चों से एकीकरण को प्रोत्साहन मिले, इसलिए ये खर्च किसी प्रकार के यूरोपीय आर्थिक अधिकरण के माध्यम से होने चाहिए। यह अधिकरण यूरोपीय महाद्वीप के लिए एक व्यापक योजना तैयार करे, साधनों का बँटवारा करे, और उसकी देर-रेल में योजना पर अमल हो।

इसमें एक यूरोपीय बिजली व्यवस्था, यूरोपीय संचार व्यवस्था, यूरोपीय परिवहन व्यवस्था और यूरोपीय खेती व इस्पात के उत्पादन का समन्वय करना शामिल हो।

अमरीका इस यूरोपीय आर्थिक अधिकरण की उदारतापूर्वक सहायता करे, वशतः कि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच आपस में, और हमारे अपने राष्ट्र व यूरोप के बीच खुली खतम कर दी जाय या बहुत कम कर दी जाय, ताकि माल फिर आसानी से उधर-उधर भेजा जा सके। धन का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रों सहित यूरोपीय क्षेत्र के सारे ही तीस करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का स्तर स्थिर पति से ऊँचा उठे। किन्तु, इस अधिकरण का गठन इस प्रकार किया जाय कि जर्मनी को सभाव्य सैनिक शक्ति हमेशा के लिए दब जाय।

अमरीकी आर्थिक सहायता के एक आधार के रूप में, दक्षिणी अमरीका और अमरीका के कुछ हिस्सों के लिए, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए, और निकट पूर्व के लिए, ऐसे ही व्यापक आर्थिक अधिकरणों की योजनाएँ बनाई जाएँ।

स्वायत्त विश्व-शान्ति के लिए हमारे प्रयास के पहले कदम में, क्षेत्रीय नियोजन

के आघार पर अमरीकी प्रविधियों और औद्योगिक उपकरणों का निर्यात अवश्य शामिल होना चाहिए, जिससे कि दूसरे देशों का जीवन-स्तर धीरे-धीरे उठाया जा सके।

अगले दस वर्षों में, या अगली पीढ़ी में विश्व सद्भावना के नवयुग की आशा करना नासमझी होगी। लेकिन विश्व-शान्ति की स्थापना, और मानवी स्वतन्त्रता की उपलब्धि के एकमात्र संभव मार्ग पर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने में देर करना, और भी बड़ी नासमझी होगी।

विधि और निषेध, दोनों के कार्यक्रम की आवश्यकता

श्री वील्स ने, क्रान्तिमारी विश्व में अमरीकी विदेश-नीति के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर आग्रह करने की अपील करते हैं।
 न्यूयार्क टाइम्स मंगलदिन, 18 अप्रैल, 1948।

हम केवल साठे चौदह करोड़ हैं, और हम दो प्रखर लोगों के एक क्रान्तिकारी विश्व में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में, स्थायी शान्ति के आधार का निर्माण करने में हमारी सफलता बहुत कुछ हमारे विचारों की शक्ति पर और अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्धों पर निर्भर होगी।

हमारी सैन्य-शक्ति जितनी है, उसकी दुगुनी होने पर भी, हम बल-प्रयोग से, या बल-प्रयोग की धमकी के द्वारा अपना नेतृत्व दूसरों पर नहीं लाद सकते थे। भविष्य के सप्ताहों में हम सभी प्रभावित कर सकते हैं, जब दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, और दूसरे लोग हम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, जब तक उन्हें भरोसा न हो कि हम उनके सच्चे मित्र और समर्थक हैं।

उनका आदर प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम पहले उन्हें समझें—और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी मात्रा में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने की उनकी भावना को समझें।

अगर हम लोगों के बजाए शान्ति की ही दृष्टि से सोचते हैं, और लोगों को प्रभावित करने वाले विचारों और धारणाओं के बजाए, मुख्यतः रणनीति के आधार पर फैसले करते हैं, तो हम सफट में पड़ सकते हैं।

श्रीमत् अमरीकी न केवल राजनीतिक लोकतंत्र में, बरन् आर्थिक लोकतंत्र में भी विश्वास करता है। हमारे लक्ष्य इतिहास में उभरे लगातार निहित आर्थिक हितों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, अपने संघर्ष में उभरे अनाधारण सफलता भी मिली है। भूमि का व्यापक स्वाभित्त्व, न्यूनतम वेतन कानून, श्रम संगठन, सहकारिता, सामाजिक सुरक्षा, आद-कर, बाल-श्रम कानून, मातृ-शैक्षणिक स्कूल, रोजगार सम्बन्धी आचार-नियम, और अन्य संकेतों तरीकों में हम उस आदर्श की ओर बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिसे राष्ट्र-पति रूजवेल्ट के आर्थिक अधिकार-यंत्र में प्रस्तुत किया गया था।

विधि और निषेध, दोनों के कार्यक्रम की आवश्यकता

फिर भी, जब हम अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में 'लोकतंत्र' की बात करते हैं, तो हमारा विचार राजनीतिक लोकतंत्र तक ही सीमित प्रतीत होता है। हमने आर्थिक लोकतंत्र पर जोर नहीं दिया—अमीन की मिल्कियत का किसान का अधिकार, भोजन और आवास में उचित हिस्सा पाने का शहरी मजदूर का अधिकार, और हर जगह शिक्षा और स्वास्थ्य की एक उचित न्यूनतम मात्रा प्राप्त करने का सभी लोगों का अधिकार।

साम्यवादियों ने इस कमी का लाभ उठाकर, करोड़ों गरीबी से पीड़ित लोगों के हितों की ओर ध्यान देने वाली एकमात्र बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहा है। साम्यवादी नेता ट्रेप दृष्टि के साथ लेकिन बड़ी प्रभावकारी रीति से कहते हैं—“साम्यवाद आर्थिक लोकतंत्र का समर्थक है, जिसका अर्थ है राजकीय नियोजन के द्वारा जीवन-स्तर में सुधार। अमरीका राजनीतिक लोकतंत्र का समर्थक है, जिसे आप ख़ा नहीं सकते हैं, और जो कठिनाई के समय आपकी रक्षा नहीं करेगा।”

उनके इरादों में चाहे जितनी भी बेईमानी हो, साम्यवादी लोग राजकीय नियोजन, राजकीय स्वामित्व, और भूमि सुधारों के द्वारा जिन आर्थिक लोकतंत्र का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे करोड़ों व्यक्तियों के लिए उसमें एक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक आकर्षण है, जिन्होंने गरीबी और अन्याय के सिवाय कभी और कुछ नहीं जाना।

हम लोग, जो पश्चिम के राजनीतिक लोकतंत्र में पले हैं, साम्यवाद के अत्याचार-पूर्ण पक्षों को बड़ा ही अप्रिय पाते हैं, किन्तु एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमरीका के अधिकांश लोगों की दृष्टि में वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिनका सीधा-सा कारण है कि किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक अन्याय हमेशा ही उनके जीवन का न्यूनाधिक स्वीकृत अंग रहा है।

साम्यवाद ने पिछले दो वर्षों में कई मौकों पर विजय प्राप्त की है। जो शक्तिशाली प्राज इतिहास का निर्माण कर रही हैं, अगर हमारी नीतियाँ उनके प्रति अधिक प्रहणशील नहीं बनती, तो आने वाले वर्षों में और भी मौकों पर उसे विजय मिलेगी।

ग्राम तौर पर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और लतिन अमरीका में दो शक्तियाँ ऐसी हैं, जो विश्व साम्यवाद की अभिवृद्धि के विरुद्ध हैं। पहली शक्ति सामन्ती भूस्वामियों की, अर्द्ध-फामिस्ट उद्योगपतियों की, और पुराने अभिजात वर्ग की है—जो साम्यवाद से इस कारण नहीं लड़ते कि वे तानाशाही के विरुद्ध हैं, बल्कि इस कारण कि साम्यवादी तानाशाही से उनकी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की खतरा है। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ उदार और लोकतांत्रिक हैं, जो साम्यवाद से इस कारण लड़ती हैं कि वे पुलिन-राज के अत्याचारों को स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं करेगी।

साम्यवाद के प्रति व्यापक जन-विरोध उत्पन्न करने की एक मात्र आशा उन

सोवतांत्रिक समूहों का निरन्तर समर्थन करने में है, जो मानवी स्वतंत्रता सम्बन्धी हमारी धारणा में सहयोगी हैं। हमने बहुधा ऐसा नहीं किया है—कभी-कभी इन कारणों कि ये समूह दुर्बल थे, कभी इन कारणों कि 'समाजवाद की घोर भुत्ताव' होने के कारण हम उनके आर्थिक विचारों के विरुद्ध थे, और कभी संन्य-नीति दशाव के कारण।

कभी-कभी हमने केवल इस कारण प्रतिक्रियावादियों का समर्थन किया है, कि उन्हें साम्यवाद उतना ही नापसन्द है, जितना हमें, और वे उसके विरुद्ध बल-प्रयोग करने की स्थिति में हैं। इसके फलस्वरूप, साम्यवादी प्रचार की कुशल सहायता में, करोड़ों लोगों के मन में हम ऐसी दार्शनियों के साथ जुड़ गए हैं जिन्हें वे अपने सुरक्षा-पूर्ण भविष्य के मार्ग में प्रमुख बाधा समझते हैं।

इसका विकल्प क्या है? उन दो अरब लोगों के साथ, जो उत्तरी अमरीका में नहीं रहते, हम अपनी रणनीति सम्बन्धी स्थिति कैसे मजबूत बना सकते हैं? युद्ध से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? और अगर हमारी चेष्टाओं के बावजूद युद्ध होता है, तो हमारे लिए अधिकतम समर्थन प्राप्त करने का सर्वाधिक निश्चित उपाय क्या है? हम जिन्हें कर सकते हैं, ऐसे बहुतेरे उपाय हैं।

सबसे पहले, हम सारी दुनिया में आर्थिक सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए भूगर्भ और दवे हुए लोगों के सघर्ष का स्पष्ट रूप में समर्थन करें।

हम उन्हें विश्वास दिलाएँ कि हम पूरे दिल से आर्थिक और सामाजिक गुधारों के पक्ष में हैं, जिन्हें बहुत पहले ही करना चाहिए था, और यह कि हमारी सहायता में वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अधिक ऊँचे जीवन-स्तर भी प्राप्त कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा हम टेनेसी घाटी अधिकरण के नमूने पर दक्कन, क़रात, और जॉर्डन नदियों पर नदी-घाटी विकास योजनाएँ चला सकते हैं। हम इस क्षेत्र के शासकों पर जीवन यापन, साक्षरता और स्वास्थ्य का स्तर उठाने वाले गुधारों के लिए दबाव डाल सकते हैं, जिनकी ज़रूरत बहुत दिनों में चली आ रही है।

यूरोपीय पुनःनिर्माण कार्यक्रम हमें यूरोप में एक असाधारण अवसर प्रदान करता है। यह एक साहसपूर्ण विचार है, जिनके लिए विदेश सचिव मार्शल प्रसादा के पात्र हैं।

किन्तु, हमारे धन का उपयोग कैसे किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे प्रदान प्रतियोगी राष्ट्रियता की उगी परम्परागत धारणा को बढ़ावा देंगे, जिनमें रोमी गम्यता के मुग में यूरोप को युद्ध का भयावह दत्ता रखा है? या कि हम एक ममेजिन 'मनुज राष्ट्रम यूरोप' की नींव रखने के व्यापारिक तरीके निरालेंगे, जो अमरीका का मित्र हो, और एक साम्निपूर्ण विश्व के निर्माण में हमारे साथ काम करने को तैयार हो?

हम दक्षिणी अमरीका के करोड़ों दबे हुए लोगों का पक्ष भी ले सकते हैं, और विधिपट स्थितियों में उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिए ठोस सहायता प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया, तो न केवल दक्षिणी अमरीका, बल्कि सारी दुनिया में ही हम लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेंगे।

यही दृष्टि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में भी अपनाई जानी चाहिए, कि हम उस समय साम्यवाद के प्रतियोगी न बनें जब वह अपने पाँव जमाने लगे, बल्कि साम्यवाद को मोका मिले, इसके पहले ही काम करें। जिन लोगों को गांधी और नेहरू ने उनकी लम्बी नींद से जगाया है, इन सकट पूर्ण प्रारम्भिक वर्षों में भौतिक सहायता की एक उचित मात्रा, अमरीकी कारीगरी की मदद से, उनके जीवन-स्तर को उठाने में सहायक हो सकती है।

किन्तु भौतिक सहायता के प्रस्ताव ही काफी नहीं होंगे। इसके साथ दूरदर्शी नेतृत्व की भी जरूरत होगी। अगर सफलतापूर्वक साम्यवाद का मुकाबला करना है, और स्थायी शान्ति की नींव रखनी है, तो हम अकुशलता और भ्रष्टाचार, प्रतिगामिता या फासिज्म के साथ समझौता नहीं कर सकते।

हम यह प्रदर्शित करें कि हम अमरीकी लोग न केवल हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध हैं, बल्कि उन व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुधारों के भी समर्थक हैं, जिनकी जरूरत बहुत दिनों से है, और जिनका अभाव आज साम्यवाद को बड़े अनुकूल अवसर प्रदान करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, महान् राष्ट्रों ने नेतृत्व का अपना स्थान इस कारण खोया है कि समृद्ध होने पर उन्होंने एक जगह टिकना चाहा, और इस कारण निरन्तर आगे बढ़ती हुई दुनिया से कट गए। कट जाने पर, अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में उनका भय बढ़ा, और भय बढ़ने पर और भी अधिक अनुदारता आई, जिसने धीरे-धीरे पूर्णतः प्रतिगामिता का रूप ले लिया।

आज हम अमरीकी लोग इतिहास के मंच पर केन्द्र में हैं। अगर हमें एक महान् राष्ट्र बने रहना है, तो हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के एक साहसपूर्ण विश्व-व्यापी कार्यक्रम का समर्थन करना होगा, जो कुशलतापूर्वक बनाया और दृढ़तापूर्वक चलाया जाय।

ऐसा करके ही हमारा देश दो अरब लोगों की दुनिया में आशा का प्रतीक बना रह सकता है, जिनका दृढ़ निश्चय है कि वे पीछे नहीं जाएँगे।

एक और महान् बहस चले

अमरीकी विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा जोरदार प्रत्युत्तर की नयी नीति की प्रतिद्ध घोषणा ने उसके सफल संडन में एक चुनौती भरे लेल को प्रेरित किया। न्यूयार्क टाइम्स मंगलान, 28 फरवरी, 1954।

दूसरे महायुद्ध के बाद, हमारी विदेश-नीति के सम्बन्ध में हुई महान् बहसों की सूची, उन ऐतिहासिक कदमों की सूची है, जो अपने ऊपर आई हुई विश्व सम्बन्धी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में अमरीका ने उठाए हैं। ट्रूमन सिद्धान्त, मार्शल योजना, उत्तरी अटलांटिक सन्धि, यूरोप में सेनाएँ भेजना, चीन पर हमला करके कोरिया युद्ध को विस्तार देने से इन्कार करना, ये सभी आधारभूत निर्णय थे, और पूरी तरह सशक्त सार्वजनिक बहस के बाद किये गए थे।

मैं समझता हूँ कि अब एक और महान् बहस होनी चाहिए। 'तात्कालिक प्रत्युत्तर' के सिद्धान्त—संघातित डलेस सिद्धान्त—पर बहस करने की तीव्र आवश्यकता है।

वैदेशिक सम्बन्ध परिषद् के समक्ष अपने भाषण में, 12 जनवरी को विदेश सचिव डलेस ने हमारी विश्व रणनीति सम्बन्धी 'नयी दृष्टि' की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इसमें उन्होंने जो कुछ कहा, वह हमारी विदेश-नीति में किया गया एक दूरगामी परिवर्तन प्रतीत होता है। श्री डलेस का ठीक-ठीक मतलब क्या था ?

अपने भाषण के कुछ हिस्सों में, ऐसे हिस्सों में जिन पर वे बहुत जोर देते हैं, वे स्थानीय प्रतिरोध की, सीमित-युद्ध की धारणा के लगभग पूर्ण परित्याग वा प्रस्ताव करते प्रतीत होते हैं। वे 'स्थानीय प्रतिरक्षात्मक शक्ति पर कम निर्भर रहने, और निरोधक शक्ति पर ब्यापक निर्भरता द्वारा निरोध' पर जोर देते हैं।

वे कहते हैं कि पहले "हमें जरूरत थी कि आर्कंटिक क्षेत्र और जल्प्य क्षेत्रों में, एशिया, निम्न पूर्व और यूरोप में, समुद्र, स्थल, और वायु में, पुराने हथियारों से और नये हथियारों से लड़ने को तैयार रहें।" अब कहा जाता है कि "तत्काल, अपनी पनन्द के माधनों से, अपनी पनन्द के स्थानों पर प्रत्युत्तर देने की विशाल क्षमता पर मुख्यतः निर्भर रहने के.....(एक नए) मूल निर्णय" से यह जरूरत बदल गई है। 'तत्काल प्रत्युत्तर' को हमें आधिकारिक बमबारी के रणनीतिक प्रयोग से जोड़ा जाता रहा है। 'अपनी पनन्द के स्थानों' पर प्रत्युत्तर देने में धारण के क्षेत्र के

एक और महान् बहस चल

बाहर के स्थान भी आते हैं, क्योंकि आक्रमण का क्षेत्र तो शत्रु की पसन्द का होता है।

मव मिलाकर, प्रशासन यह कहता प्रतीत होता है कि भविष्य में रूस या चीन द्वारा दुनिया में कहीं भी गैर-कॉम्युनिस्ट क्षेत्र पर किये गए आक्रमण से निपटने में उसका इरादा मुख्यतः साम्यवादी देशों के प्रमुख नगरों पर रणनीतिक वायुसेना द्वारा आण्विक आक्रमण पर निर्भर रहने का है। उच्च शासकीय सूत्रों के इस सम्बन्धित वक्तव्य से भी इस व्याख्या को पुष्टि होती है कि "यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषण है, जो श्री डलेस ने कभी भी किया है, या कभी भी करने की संभावना है।"

अगर नयी नीति यही है, तो आक्रमण को निरत्साहित करने में, और आक्रमण होने पर उसे रोकने में इस नीति के सकल होने की संभावनाएँ क्या हैं? जैसा श्री डलेस कहते हैं, क्या सचमुच हमसे हमें 'कम कीमत पर अधिक सुरक्षा' प्राप्त होगी?

पहले, हम यह मान लें कि पश्चिमी यूरोप के लिए यह नीति नयी या अपरीक्षित नहीं है। निस्सन्देह, रूस बहुत पहले से जानता है कि यूरोप पर आक्रमण को हम अपने ऊपर दुष्प्रा आक्रमण समझेंगे। और ऐसे आक्रमण के उत्तर में हम उसके विरुद्ध अणु-बम का प्रयोग करेंगे; यद्यपि इसके बाद होने वाले सामान्य युद्ध में संभवतः हमारे अपने देश में व्यापक आण्विक विध्वंस होगा।

लेकिन क्या अमरीका इसके लिए तैयार होगा कि एशिया में हुए स्थानीय आक्रमण का सामना करने में भी वही भयानक सतरे उठाए—मिसाल के लिए अफगानिस्तान, ब्रह्मा, ईरान या इण्डोनेशिया में? कोरिया युद्ध की हमारे ऊपर जो गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी, और हिन्द-चीन में उससे भी अधिक सीमित रूप में फँसने की सम्भावना की जो प्रतिक्रिया हुई, उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे।

द्विती भी मूरत में, विशाल, विकेन्द्रित चीन पर हमारे आण्विक आक्रमण का कितना प्रभाव पड़ सकता है? सोवियत रूस के विपरीत, चीन में कोई बड़े औद्योगिक केन्द्र नहीं हैं। मंचूरिया में इस्पात का कुल उत्पादन डेनावेयर में 'यूनाइटेड स्टेट्स स्टील' कारखाने के उत्पादन का आधा भी नहीं है।

चीनी अर्थतंत्र परिवहन और संचार की अत्यधिक विकसित व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं है। चीनी सेनाएँ गतिशील हैं, छापामार युद्ध में और सम्बन्धित इलाके से ही रसद प्राप्त करने में शिक्षित हैं, और पश्चिमी सेनाओं में संभरण और समर्थन की जो विल्टन व्याख्या होती है, उसके बिना भी काम कर सकती हैं।

हम इसकी धाशा नहीं कर सकते कि चीनी नगरों के आण्विक विध्वंस का कोई और नतीजा निकलेगा, सिवाय एक लम्बे, फँसे हुए, अनिर्णायक संघर्ष के, जिसमें संभव है चीन अपने मुख्य साधन, जनशक्ति, से अधिकांश एशिया महाद्वीप पर अधि-पार कर ले।

धीरे धीरे इस नीति में एक अधिक व्यापक प्रश्न, यानुसार: एक आधारभूत नैतिक प्रश्न निहित नहीं है, कि हमें सामंजस्य में हमें पुरी तरह समझ-भूक कर निर्णय करना चाहिए? हम एक धार्मिक राष्ट्र हैं, हमारा विश्वास है कि ईश्वर के सपत्त मनुष्य पवित्र हैं। हम मनुष्य में परम गुण के सम्बन्ध में अपने तोतागतिक विश्वास पर गर्व करते हैं। मही किशोर? जो हमारी जीवन विधि को साम्यवादियों की जीवन-विधि में भिन्न बनाने हैं।

हिन्दु, अगर हम चीन के नगरों पर हमबारी करने की धमकी देने हैं, तो मही प्रतीत होगा कि तोषित रूप के नगरों के विपरीत, हम ऐसे बड़े नगरों में एकत्रित करोड़ों स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को नष्ट करना चाहते हैं, जिनका सैनिक या औद्योगिक केन्द्रों के रूप में, लगभग कुछ भी महत्त्व नहीं है। क्या हम उन लोगों पर नियंत्रण करने वाले दासकों को सजा देने के लिए, असाहाय लोगों की ऐसी भयानक बलि के लिए तैयार हैं?

साम्यवादी प्रचार ने पहले ही करोड़ों एशियावासियों को यह विश्वास दिला दिया है कि हमने जर्मनी पर अणुबम न गिराकर जापान पर गिराया, क्योंकि हम एशियावासियों को नीची कोटिका मानते हैं। रूसी नगरों के झूठे रहने पर, अरक्षित चीनी नगरों का आश्विक विध्वंस क्या सारे एशिया को हमारा कटु और कठोर राष्ट्र नहीं बना देगा?

यूरोप की स्थिति क्या है? यूरोप में हमारी सबसे नाजुक कूटनीतिक समस्या यूरोपीय राष्ट्रों की एकता को सुरक्षित और सशक्त बनाए रखने की है। क्या श्री डलेस की नयी नीति इस समस्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है? श्री डलेस द्वारा घोषित नई नीति के फलस्वरूप, हमारे यूरोपीय मित्र हमारे साथ सम्बन्ध रखने में अधिक उत्साहित होंगे, या कम?

हम अमरीकी लोग तीसरे महायुद्ध में सब कुछ दाँव पर लगा देने का खतरा उठाने को तैयार हो सकते हैं, जो 'आश्विक प्रत्युत्तर' की नई नीति में निहित है। किन्तु आश्विक प्रत्याक्रमण होने पर हमसे भी कहीं अधिक क्षति रूसी भ्रष्टों से कुछ सौ मील की ही दूरी पर स्थित हमारे यूरोपीय मित्रों की होगी, जो पहले ही युद्धों से चके हुए हैं। ऐसा सन्देह होने पर कि हमारी नई नीति तीसरे महायुद्ध का अनावश्यक खतरा उठाती है, यूरोपीय प्रतिरक्षा के आवश्यक कार्य के प्रति उनका उत्साह बिलकुल बीसा पड़ जा सकता है।

एक और आधारभूत प्रश्न है—अन्तर्राष्ट्रीय आश्विक नियंत्रण की जो कुछ आशा सभी भी शेष है, उस पर नयी नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा?

अपने लक्ष्यों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमने जो सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनमें एक यह भी है कि हमने पूरे दिल से और दूरदर्शिता के साथ सयुक्त राष्ट्र सच के अधीन आश्विक हमियारों के व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण का समर्थन किया है।

एक धीरे महान् बहस चले

अगर हम शान्ति रक्षा के लिए लगभग पूरी तरह अणु-बमों पर निर्भर रहने की ओर बढ़ते हैं, तो संभव है कि इससे आण्विक निरस्त्रीकरण की वह संभावना नष्ट हो जाय, जिसकी इच्छा अधिकांश मनुष्यों में अणु-युग के आरम्भ से ही रही है। और इसके लिए हम दुनिया के सामने पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

मैं समझता हूँ कि एक अन्य प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार होना चाहिए, जिसका सम्बन्ध हमारे शासन के मूल ढाँचे से है। मंत्रिषान के अन्तर्गत, कांग्रेस को और केवल कांग्रेस को ही, युद्ध घोषित करने का अधिकार है।

अगर, मिसाल के लिए चीनी सेनाएँ इण्डोनीशिया पर आक्रमण करती हैं, तो क्या राष्ट्रपति स्वयं चीन के विरुद्ध आण्विक प्रत्याक्रमण आरम्भ करने के पहले कांग्रेस से स्वीकृति माँगेगे? अगर हाँ, तो प्रत्याक्रमण 'तात्कालिक' कैसे हो सकता है, और क्या इसका खतरा न होगा कि इधर कांग्रेस विचार करती रहे, उधर रूस पूर्वानुमान के आधार पर, अमरीकी नगरों पर अपनी ओर से भीषण आण्विक हमले कर दे?

या कि ऐसी संभावना को देखते हुए, राष्ट्रपति स्वयं अपने अधिकार से रणनीतिक वायु-सेना के बमबारों को हमले का आदेश देगा, और कांग्रेस को अपने सर्वधानिक अधिकार के उपयोग का मौका दिए बगैर ही तीसरे महायुद्ध को न्योता देगा, या उसे शुरू कर देगा?

एक अन्य प्रश्न—हमारे सामने जो स्थिति है, उसे लगभग पूरी तरह सैन्य-शक्ति के सन्दर्भ में देखकर, और वह भी केवल एक प्रकार की सैन्य-शक्ति के सन्दर्भ में देख कर, क्या नई नीति साम्यवादी खतरे के चरित्र और व्यापकता का अनुमान वास्तविकता से कम नहीं लगा रही?

शीत-युद्ध की सर्वप्रमुख विशेषताओं में से एक यह भी है कि साम्यवादियों ने कहीं भी रूसी सेनाओं द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की है। वास्तव में, बाहरी सैनिक आक्रमण के द्वारा लौह आवरण की सीमाओं को बदलने का प्रयास भी केवल कोरिया में ही किया गया।

इसके बजाए, हमारे सामने प्रभावकारी सोवियत कार्यपद्धतियों के कई विभिन्न रूप आए हैं। ईरान में 1946 में रूसियों ने उत्तरी प्रान्तों में एक ऐसे विद्रोह का समर्थन किया, जो स्पष्टतः मास्को के आदेश पर ईरानी साम्यवादी दल द्वारा आरम्भ किया गया था।

यूनान, प्रव्हा, मलय, हिन्दचीन, इण्डोनीशिया, फ़िलीपीन और स्वयं चीन में, सुमगठित और भली भाँति प्रशिक्षित स्थानीय सेनाओं या छापामार दस्तों के द्वारा सड़ाई सलाई गई है, जिन्हें बहुधा रूसी हथियार और रूसी विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध रही है।

हर उम्र देश में, जहाँ शासन अपने देश के लोगों के स्पष्ट बहुमत की निष्ठा प्राप्त करने में सफल रहा है, इन साम्यवादी हमलों को सफलतापूर्वक रोकने और पराजित

किया गया है। किन्तु जहाँ प्रोपनिवेशिक शक्ति हटपूर्वक बनी रही है, या जहाँ साम्यवाद के विरोध का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में रहा है जिन पर लोगो को विश्वास नहीं रहा, वहाँ बड़े पैमाने पर पश्चिमी सैनिक और आर्थिक सहायता, यहाँ तक कि पश्चिमी सेनाओं का हस्तक्षेप भी निर्णायक नहीं सिद्ध हुआ।

अन्य मामलो में, विशेषतः जेकोस्लोवाकिया में, सोवियत रूस ने स्थानीय साम्यवादी दलों के सुसंगठित विध्वंसार्थक प्रयासों का सहारा लिया है। इस प्रकार विद्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा में, रूस ने हमेशा बड़ी ही लचीली रणनीति अपनाई है।

साम्यवादी खतरे के यही रूप हमारे सामने सबसे अधिक धाते हैं, जो बाह्य आक्रमण का रूप नहीं ग्रहण करते। नई नीति इन खतरों का सामना किस प्रकार करती है ?

इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि रूस कुछ नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। मिसाल के लिए, इस बात के सभी संकेत मिलते हैं कि रूस का इरादा अपने तेजी से बढ़ते हुए उत्पादन का उपयोग एक जोरदार व्यापारिक प्रयास में करने का है, जिसका उद्देश्य न केवल रूसी अर्थतंत्र की सहायता करना होगा, बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों में नई फूट पैदा करना और एशिया की नई सरकारों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना भी होगा।

इसके भी संकेत मिल रहे हैं कि रूस आगे चलकर एक चतुःसूत्री सहायता कार्यक्रम चलाए। राजनीतिक, आर्थिक और अर्थ-सैनिक उपायों से प्रस्तुत रूस की बहुमुखी चुनौती के समक्ष, केवल अणु-बमों का सहारा लेने से क्या हमारा काम चल सकता है ?

उदाहरण के लिए, क्या एशिया में ऐसे गतिशील और स्वतंत्र राष्ट्रों के विकास की आशा, और उसके लिए काम करना हमने बन्द कर दिया है, जो हमारे लिए नहीं बरन् स्वतंत्र रहने के, स्वयं अपने अधिकार के लिए लड़ने को तत्पर हों ?

हमारे अपने पिछड़े रहे चतुःसूत्री सहायता कार्यक्रम के बारे में क्या नीति है, जिसका थो डलेस ने केवल जिक्र भर किया ?

हमारे प्रतिरक्षा प्रयास और खर्च के बोझ में कोई बड़ी कटौती तभी हो सकती है, जब दुनिया के उन हिस्सों में स्थानीय शक्ति का विकास हो, जहाँ साम्यवादी आक्रमण या विध्वंसक कार्यवाही का खतरा है। यह स्थानीय शक्ति केवल वास्तव में स्वतंत्र शासनों, और स्वयं, बढ़ते हुए आर्थिक ढाँचों के विकास से ही उत्पन्न हो सकती है।

हम आशा कर सकते हैं कि ये सरकारें हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करेंगी, किन्तु हमारे साथ हुए रोज व रोज के समझौते से कहीं अधिक महत्त्व इस बात का है कि वे स्वयं अपनी एक गतिशील आस्था विकसित करें, जिसके लिए वे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आक्रान्ता से लड़ने को तैयार हों।

आन्विक प्रहार शक्ति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और निरन्तर बना रहने वाला

स्थान है। किन्तु यह मान लेना मूर्खतापूर्ण होगा कि एशिया के ललचाने वाले शक्ति-धूम्रों में यह शक्ति साम्यवादी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। विध्वंसक कार्यवाहियों और आन्तरिक क्रान्तियों के सम्बन्ध में ऐसा मानना और भी मूर्खतापूर्ण होगा।

उदाहरण के लिए, जब हम दुनिया के सामने घोषणा करते हैं कि हम हिन्दचीन में सीधे कभी नहीं फँसेंगे, तो कोरिया से भी बड़ी अधिक, हम हिन्दचीन में साम्यवादियों को न्योता देते हैं।

बड़े पैमाने पर आण्विक प्रत्याक्रमण की घमकियों की अपेक्षा, जिनके बारे में लौह आवरण के दोनों ओर हर जानकार व्यक्ति को पता है कि जब तक हमारे यूरोपीय मित्रों पर प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं होगा, तबतक इन घमकियों पर अमल होने की संभावना नहीं है, लचीले, गतिशील सैनिक दस्तों इन स्थितियों में आक्रमण को निरन्तरमाहित करने में अधिक उपयोगी हो सकते हैं, जिन के बारे में सारी दुनिया को मालूम है कि संकट के अवसरों पर हम उनका उपयोग करने को तैयार हैं।

हमारी कूटनीति को दृढ़ होने के साथ-साथ दुनिया की उन क्रान्तिकारी शक्तियों के प्रति भी पूरी तरह जागरूक होना चाहिए, जो भविष्य का निर्माण कर रही हैं। उसे इतना चुस्त होना चाहिए कि दूर तक फैले साम्यवादी जगत के अन्तर्विरोधों को देखकर उनका उपयोग कर सके।

उसे साम्यवादी राष्ट्रों की कार्यवाहियों के फलस्वरूप, सम्मोहन में पड़कर नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेने के खतरे से बचना चाहिए। उसे व्यावहारिकता की अन्तिम सीमा तक, सभी लोगों की स्वतंत्र होने की आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहिए।

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह उस दृष्टिकोण को बनाए रखे, जिसे हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र में 'मानव-जाति के मतों का उचित आदर' कहा था।

इन निर्णायक प्रश्नों पर एक 'महान् बहस' से हम ऐसे सन्तुलित हल खोज सकते हैं, जो हमें चुनौती का सामना करने के योग्य बनाएँ। ऐसी बहस ही, जिसमें कांग्रेस, और देश के लोग भाग लें, लोकतंत्र में विदेश-नीति के विकास की एकमात्र उचित और टिकाऊ रीति है।

क्या आशा का कोई मार्ग नहीं ?

1954 में, जब दुनिया ने हाइड्रोजन बम की संभावनाओं को पहली बार समझा श्री बौल्स ने कुछ आशाप्रद विकल्प सुभाए, और कहा कि सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व के अन्तगत ये मार्ग खुले हैं। न्यूल्कीडर में प्रकाशित एक लेख से 26 जुलाई 1954।

एडमण्ड बर्क ने एक बार इंगलिस्तान की ससद में अपने सहयोगियों को सलाह दी थी कि जब बुरे लोग आपस में मिल जाएँ, तो अच्छे लोगों को भी साहचर्य स्थापित करना चाहिए। अन्यथा वे एक-एक करके नष्ट हो जाएँगे, एक तिरस्करणीय संघर्ष में ऐसा बलिदान, जिस पर किसी को दया नहीं आएगी।

आज जिस संघर्ष का खतरा सामने है, वह आण्विक और पूर्ण हो सकता है, किन्तु इस कारण कम तिरस्करणीय नहीं हो जाता। इससे बचने के लिए अच्छे लोग किस प्रकार साहचर्य स्थापित करें ? कौन-से विकल्प हमारे सामने हैं, जिनमें से हम चुनाव कर सकते हैं ?

पिछले अठारह महीनों में हमारे सामने असम्भव विकल्प रखे गए हैं। इनमें से बहुतों ने तो नारेबाजी का ऐसा रूप ले लिया है, कि उनका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हम से कहा गया है कि हमें 'निवारक युद्ध' और 'तुष्टीकरण' के बीच, 'विरोध नीति' और 'मुक्ति' के बीच 'सँराती कार्यक्रमों' और शुल्क-बोझिल 'सहायता नहीं व्यापार' प्रस्ताव के बीच, 'अपने साधनों के अन्दर घरेलू अर्थनीति और 'लगभग दीवालियापन' के बीच चुनाव करना है।

ऐसा कहना असहनीय पराजयवाद है कि हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से वापसी का कोई मार्ग नहीं है, और सारे ही वांछनीय मार्ग बन्द हो गए हैं। जब तक बम गिरने न लगे, तब तक सदबुद्धि वाले व्यक्ति एक-दूसरे के सामने भी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति घा गई है।

अगर हम खुद पल्ला झाडकर दूसरों पर जिम्मेदारी ढाल देते हैं, तो हमसे कोई भी एक ऐतिहासिक द्रोह की व्यक्तिगत, नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता हाइड्रोजन-बम से प्रस्त भविष्य की अपेक्षा अधिक आशाप्रद विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, ऐसे विकल्प जो हमारी परम्पराओं और हमारे सिद्धान्तों के अधिक अनुकूल हैं।

ये विकल्प नये नहीं हैं। हमें केवल पुराने और साविक धृनों के कुछ परिवर्तित

क्या प्रशासक का कोई मार्ग नहीं ?

रूपों को लेकर ही काम करना है। नए भयावह हाइड्रोजन बमों ने केवल कुछ पुरानी मानवीय द्विविधाओं को नाटकीय रूप देकर तत्काल उन पर ध्यान केन्द्रित कर दिया है। और इन द्विविधाओं में निहित भूल नैतिकता से बचा नहीं जा सकता।

जब हमारे बजट में कटौती करने वाले चतुःसूत्री कार्यक्रम का गला घोटते हैं, तो वे कहते हैं कि उनका निर्णय आर्थिक है लेकिन वह एक नैतिक निर्णय भी है।

जब आपराकालीन शरणार्थी कार्यक्रम पर ऐसे प्रशासकों और विनियमों का बोझ लाद दिया जाता है, जो कानून की भावना के अनुकूल नहीं हैं, तो यह केवल प्रशासकीय मामला ही नहीं है नैतिक मामला भी है।

जब हम अल्पसंख्यक समूहों के साथ भेदभाव बरतते हैं, तो हम न केवल ऐसे परमाधिकार का प्रयोग करते हैं जिसकी प्रवृत्ति गुजाइश नहीं रही, बरन् अपने जैसे एक मनुष्य की हीनता का नैतिक आकलन भी करते हैं।

जब स्थानीय देशभक्त समुक्त राष्ट्र संघ को लेकर होश-हवास खो बैठते हैं, तो वे केवल सनक भरी प्रान्तीयता का ही प्रदर्शन नहीं करते, नैतिक सन्तुलन का अभाव भी प्रदर्शित करते हैं।

हमें ऐसे प्रेतों के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, जिनका हमारी स्वतन्त्रता या सुरक्षा में कभी कोई योग नहीं हो सकता, और उसके बजाए अपने समय और अपनी प्रतिभा का उपयोग महत्वपूर्ण मानवी समस्याओं का हल करने की चेष्टा में करना चाहिए, जो बहुत दिनों से उपेक्षित चली आ रही हैं।

हाइड्रोजन बम ऐसे समय में आया है, जबकि दुनिया के बड़े हिस्से में यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह की लहर उठ रही है। यह विद्रोह कई रूप लेता है—एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीयता, और उपनिवेशवाद का विरोध, यूरोप में शीत युद्ध के सघर्ष से गहरी निराशा, अमरीका में दूसरे दर्जे की नागरिकता के विरुद्ध नीचो लोगो का सघर्ष, सभी अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में खेती सम्बन्धी सुधारों और औद्योगिकीकरण का सघर्ष।

साम्यवादियों ने ये समस्याएँ उत्पन्न नहीं की। वे केवल इनका उपयोग करते हैं।

हमारी यह दृष्टिकोण बिलकुल सही और अपने आप में जरूरी है, कि 'प्रत्यक्ष आक्रमण' का सामना हम सैनिक कार्यवाही से करेंगे। किन्तु आन्तरिक जन असन्तोष की जिन आकस्मिक स्थितियों को साम्यवादी अपनी चालों से उत्पन्न करते, और अन्ततोगत्वा जिनका वे संचालन करते हैं, उनकी गहरी जड़ें पीडा, दमन, और गरीबी में होती हैं, और उनका सामना करने के लिए यह घोषणा काफी नहीं है। और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पिछले दिनों हमारी असफलता इस मूल तथ्य को रेखांकित करती है।

जब तक विश्व क्रान्ति रूस का लक्ष्य बनी रहती है, तब तक सोवियत गुट के साथ स्थायी समझौते का कोई आधार नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अणु-शक्ति के व्यावहारिक नियन्त्रण, लागू किए जा सकने वाले निरस्त्रीकरण,

और समुन्नत राष्ट्र संघ को अधिक गवल बनाने की योजनाएँ प्रस्तुत करना बन्द कर दें।

ऐसा प्रतीत होता है कि रूस ने हमारे ऊपर एक मानसिक शिकंजा डाल दिया है। हमें उस शिकंजे को काट कर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। रूस क्या कहता या करता है, इसकी चिन्ता किए बगैर, विद्वय के रोग के मर्म में जो आधार-भूत समस्याएँ हैं, हमें उन को हल करने में लगना चाहिए।

ऐसे बहुतेरे रचनात्मक कार्य हैं, जिन पर रूस कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। मिसाल के लिए, समुन्नत-राष्ट्र विद्वय विकास अधिकरण के निर्माण को रूस नहीं रोक सकता। उसी तरह, विद्वय स्वास्थ्य समन्वय, राष्ट्र और गैरी समन्वय, शिक्षा, विज्ञान और सञ्चालन समन्वय, बाल-निधि और स्वयं महागभा जैसी समुन्नत राष्ट्रसंघ की मकल एजेन्सियों के विकास पर रूस कोई रोक नहीं लगा सकता।

जो राष्ट्र रूस को साथ लिए बगैर सहयोग करना चाहे, उनके द्वारा अणुशक्ति के सचय को रूस नहीं रोक सकता।

वार्शिंगटन में प्रबुद्ध नेतृत्व पर, या अमरीकी लोगों के दिलों में सक्रिय सद्भावना पर रूस कोई रोक नहीं लगा सकता।

अमरीका किसी समय इतिहास की आशा या, लेकिन पिछले दिनों दुनिया के दो अरब लोगों के मन और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए बहुत कम सामग्री प्रस्तुत करता रहा है। अमरीकी जिन बातों को कहने के लिए पैदा हुए थे, वे बातें हम लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? पहले मजदुर-वर्ग एशिया में गिराने के बाद, हम फिर नए वर्गों के परीक्षण के लिए वहाँ क्यों गए। आस-पास के निर्दोष जापानी मछुधारों से, मनुष्य-जाति की ओर से सार्वजनिक धमा-याचना करने का काम हमने दूसरों पर क्यों छोड़ दिया?

अपने महानतम सम्भारम्भ के इन शब्दों को उच्चारित करने का काम हमने पिछले दिनों श्री लका सम्मेलन में श्री नेहरू पर क्यों छोड़ दिया—“किस्ती के प्रति भी विद्वेप नहीं, और सबके प्रति उदारता के साथ।” देश में और सारी दुनिया में, लिक्न के देशवासियों के ओठों पर ऐसे शब्द क्यों नहीं हैं?

मास्को के दोष-दृष्टि से अस्त व्यक्त भी अपनी अपील गरीब और बचिबत लोगों को सम्बोधित करते हैं। उन्होंने हमारे नारे चुरा लिए हैं; और हमारे सिद्धान्तों को विकृत करके प्रस्तुत किया है। यह उनकी एक भौंडी चाल है, किन्तु आगे चलकर इस के अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। इस अन्तर्जाति का दावा करने वाली अपील की, वर्गोंबहोन समाज की इस मृग-भरीचका की, भाईचारे के इस खोलले नारे की, न्याय पर आधारित समाज प्रदान करने के इन भूठे दावे की हम उपेक्षा करते रहे, संभव नहीं है।

इस चुनौती से हमें झुटकारा नहीं मिल सकता, मिलना चाहिए भी नहीं। साम्य-वादियों के पाखंड का पर्दाफाश करना हमारे लिए जरूरी है, और उसका एक ही विश्वनीय मार्ग है—हम स्वयं अपने पाखंड को खतम करें।

हम में से जो लोग कम भीरु हैं, वे कम से कम इतना कर सकते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के सामने जाएँ और आपने काल के कुछ मूल सत्यों के लिए आग्रह करें—कि पृथ्वी पर मनुष्य के भविष्य का नष्ट होना आवश्यक नहीं ; कि संकट आएगा ही, इसे स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं ; कि हमारा राजनीतिक कौशल अब भी हमें विनाश से बचा सकता है ; कि हमारे नैतिक प्रतिमान आज भी मौजूद हैं ; कि युद्ध और अन्याय जैसी कुछ वस्तुएँ अन्तहीन प्रतीत हो सकती हैं ; किन्तु ये वस्तुएँ हमेशा गलत होती हैं, इनसे हमेशा लड़ना होगा, और किसी दिन इन पर विजय पानी होगी ।

लोगों और विचारों की शक्ति

नौ सैनिक युद्ध कालेज में दिये गए एक भाषण में श्री बोल्स केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर रहने की परम्परा को चुनौती देते हैं, और परिवर्तन तथा क्रान्ति लाने के लिए विचारों और लोगों की शक्तिमय क्षमता पर जोर देते हैं। न्यूपोर्ट, रोडे आइलैंड, 7 जून 1956।

एक रात वाशिंगटन में भोजन के समय मैंने एक दर्जन मित्रों से 'शक्ति' की परिभाषा पूछी। उनमें सेना के लोग, कांग्रेस-सदस्य और विदेश विभाग के सदस्य थे।

मैंने पूछा कि "जब हम लोग शक्ति की बात करते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है?"

एक-एक करके उन्होंने उन वस्तुओं की सूची गिनाई जो उनके विचार से शक्ति का निर्माण करती हैं। इस मिली-जुली सूची में जल, स्थल और वायु सेनाएँ थीं, इस्पात उत्पादन की क्षमता थी, औद्योगिक उत्पादन-शक्ति थी, भूगोल, विदेश स्थित झड़े, और अन्य ऐसी ही वस्तुएँ थीं।

यह परिभाषा हमारे युग की मूल गत्यात्मकता की उपेक्षा करती है। आठ वर्षों की सक्षिप्त अवधि में, लगभग 120 करोड़ लोगों ने—दुनिया की आधी आबादी ने अपना शासन बदला है, और हमारे द्वारा इस प्रकार संकीर्ण रीति से परिभाषित शक्ति का इसमें बहुत कम योग था।

वस्तुतः हर मामले में शक्ति की परम्परागत धारणा लगभग पूरी तरह यथार्थ्य के पक्ष में थी। बार-बार यह शक्ति अपर्याप्त प्रमाणित हुई, और जो परिवर्तन हुए, उन्होंने इस अपर्याप्तता को रेखांकित किया।

चीन इसका एक उदाहरण है। वहाँ प्रारम्भ में माम्रो-से-तुंग के पास केवल दो सौ राइफिलें, एक हजार व्यक्ति, और साम्यवादी तानाशाही की एक ऐसी धारणा थी, जो पुराने चीनी समाज के सन्दर्भ में प्राकृतिक थी, और इसी से माम्रो ने एक ऐसे जन आन्दोलन का विकास किया, जो बीस वर्ष बाद पूरे राष्ट्र पर विजयी हुआ। यद्यपि चीन की परम्परागत सैनिक और औद्योगिक शक्ति ने ग्राम तौर पर कोमिताग का समर्थन किया था, फिर भी माम्रो और साम्यवादी चीन के मालिक बन गए।

हिन्द-चीन में भी हमने एक विचार की शक्ति को देखा, जो राष्ट्रीयता से जुड़ा

हुआ था। हिन्द-चीन की स्वतन्त्रता की चुनौती का विघ्यात्मक उत्तर देने में फ्रांस असफल रहा, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद और साम्यवाद का एक सशक्त और विस्फोटक मेल हुआ। चीन की ही भाँति, दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी टैकों, हवाई जहाजों और सैन्य-शक्ति के अन्य परम्परागत अंगों ने यथा-स्थिति का साथ दिया। फ्रांसीसियों के पास सशक्त सेना थी—संसार की सर्वोत्तम पेशेवर सेनाओं में से एक और हमने उनकी सहायता करने के लिए तीन अरब डालर का सामान वहाँ पहुँचाया फिर भी फ्रांसीसी हारे, और उनके साथ हम भी हारे।

हिन्दुस्तान में हम एक रचनात्मक लोकतांत्रिक विचार की विजय देखते हैं। अहिंसात्मक कार्यवाही द्वारा स्वतन्त्रता सम्बन्धी गांधी की धारणा हिन्दुस्तानी लोगो की प्रकृति और आकाशवाणी के अनुकूल थी। गांधी ने इस सीधी-सादी कार्य-पद्धति का प्रयोग अपने महान् राजनीतिक कौशल, और प्रशासन तथा संगठन की विशाल क्षमता के साथ किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को अन्ततः हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मा और श्री लंका को छोड़ना पड़ा।

परम्परागत अर्थ में अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति का बाहुल्य था। उस समय भी वे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैनिक शक्ति थे। फिर भी, वे गांधी के विचार की शक्ति का सामना करने में असमर्थ रहे।

फिर, इण्डोनेशिया में डच दासकों के पास शामन टैंक, पी-38 राइफिलें और आधुनिक मशीनगनों थी। लेकिन जीत आखिरकार स्वतन्त्रता के विचार की हुई।

नतीजा साफ होना चाहिए—मघाथं हमें बाध्य करता है कि हम 'शक्ति' को अपनी परिभाषा में लोगों की शक्ति और विचारों की शक्ति को भी शामिल करें। हमारे नए, क्रान्तिकारी जगत में ये निर्णायक बल वाली शक्तियाँ हैं, जिनके माध्यम से अधिक अवसर और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए उत्सुक करोड़ों लोग ऐसे आन्दोलनों में संगठित किए जा सकते हैं जिनमें यथा-स्थिति की सरकारों पर असहनीय दबाव डाल सकने की क्षमता हो।

दुर्भाग्य वश, हमने बहुधा केवल तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अपनी प्रतिष्ठा का समर्पण ऐसे लोगों को दिया है जो अतीत की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि करोड़ों व्यक्तियों के मन में, इसके विपरीत, परिवर्तन की कामना है। फलस्वरूप हम बहुधा हारने वाले पक्ष के साथ नजर आते हैं।

एशिया और अफ्रीका के लोग सचमुच क्या चाहते हैं, मुख्यतः इस सम्बन्ध में स्टालिन के अज्ञान के कारण, सोवियत नीति भी बहुधा असफल रही है। जिस प्रकार हम बहुधा उन आधारभूत शक्तियों को नहीं समझ पाए, जो काम बर रही हैं, उसी प्रकार सोवियत रूस भी उन्हें अच्छी तरह नहीं समझ पाया।

सोवियत रूस की सेनाएँ जितना आगे बढ़ सकी थी मुझे उत्तर काल में प्रचार और विध्वंसक कार्यों द्वारा अपने नारे प्रयत्नों के बावजूद रूस यूरोप में उसके आगे एक

वर्ग मील क्षेत्र भी अपने हाथ में नहीं ले सका। एशिया में भी रूस को वंसी ही असफलता मिली—जो कुछ आश्चर्यजनक है।

चीन के राष्ट्रपति सन-यात-मेन अपनी नई संपर्कित सरकार के लिए अमरीकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टाओं में असफल होने के बाद, 1923 में हताश होकर सहायता के लिए रूस की ओर मुड़े। उन्हें विश्वास था कि वे लेनिन और सोवियत रूस से विचार, कार्य पद्धतियाँ, और पूँजी उधार लेने के बाद भी किसी प्रकार उनके द्वारा आत्मसात किए जाने से बच जाएँगे।

सन-यात-मेन की गलती से चीन को मुख्यतः स्टालिन की गलतियों ने बचाया। चीन सरकार के निमंत्रण पर बोरोडिन के नेतृत्व में एक दल यह प्रदर्शित करने के लिए चीन में आया कि एक आधुनिक अर्द्ध-विकसित राष्ट्र को किस प्रकार संगठित करके बीसवीं सदी के अनुरूप बनाया जा सकता है। नव-स्थापित सोवियत शासन के लिए यह कितना बढ़िया अवसर था।

फिर भी, यह दल अपने कार्य में बुरी तरह असफल रहा। इसके सदस्य मार्क्सवाद की इस स्थापना के आधार पर काम करते रहे कि क्रान्तियाँ शहरी मजदूरों और छात्रों द्वारा की जाती हैं। उन्होंने लेनिन की इस सलाह को पूर्ण उपेक्षा की कि खेतिहर देश में आखिरी निर्यात किसानों के हाथ में होता है।

माओ-त्से-तुंग ने सोवियत-निर्देशित प्रयत्नों की भूल को समझा, और शहरों से मुँह मोड़कर जिन मुगों पुराने अग्याओं से किसान पीड़ित थे, उनके सरल मन्दर्भ में किसानों को संगठित करने के लिए गाँवों में घूमने लगे।

उनका नारा सदावत और आकर्षक था। माओ ने कहा—“जमींदारों और सूदखोरों को नष्ट कर दो, और तुम आजाद हो जाओगे।” बीस वर्षों के अन्दर ही माओ और उनके निष्ठावान साथी सारे चीन में अपने सन्देश का प्रचार करने में सफल हो गए।

किन्तु, स्टालिन ने इस बीच चीन से अपनी असफलता में कुछ भी नहीं सीखा। सारे एशिया में वे अपनी क्रान्ति को और अपने प्रयत्नों को छात्रों पर, और बहुत कुछ अस्तित्वहीन सर्वहारा वर्ग पर आधारित करते रहे, और किसानों की उपेक्षा करते रहे, जो जनसंख्या का 80 प्रतिशत थे, और जिनके हाथ में राजनीति की कुँजी थी।

इन अनुपयुक्त दृष्टिकोण के परिणाम 1949-50 तक भी, हिन्दुस्तान में साम्यवादी प्रयत्नों में साफ देखे जा सकते थे। 1948 के अन्त में हैदराबाद में एक तूफानी किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यह विद्रोह साम्यवादियों के एक 'पयभ्रष्ट' समूह द्वारा संगठित किया गया था, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करके स्टालिनवादी दल नीति की प्रवृत्ति की थी। इसका नतीजा निकला कि वे कई हजार गाँवों पर अधिकार करने में सफल हुए। बड़ी कठिनाई से, और काफी सख्या में लोगों के हताहत होने के बाद, अन्ततः भारतीय सेना इस विद्रोह को दबा सकी।

मास्को के आदेशों, और हिन्दुस्तान में स्वयं अपने साम्यवादी दल की इच्छा के विपरीत, माओ की शिक्षा का अनुसरण करने वाले ये 'पयभ्रष्ट' साम्यवादी, आशंका-जनक बिन्दु तक सफलता के निकट आ गए थे। अगर हिन्दुस्तानी साम्यवादियों ने आम तौर पर उनका सबल समर्थन किया होता तो संभव है कि वे हिन्दुस्तान में अपनी कार्यवाहियों का एक स्थायी अड्डा बनाने में सफल हो जाते। हमारे सौभाग्य से किसानों की निर्णायक राजनीतिक शक्ति को न समझने के कारण, रूस ने उनका समर्थन करने से इन्कार कर दिया।

स्टालिन की मृत्यु के बाद, रूस की कार्यनीति में एक गंभीर परिवर्तन आया है। सारे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के अपने अन्तिम लक्ष्य में कोई परिवर्तन किए बिना, सोवियत रूस अब आर्थिक स्वार्थों के आधार पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका से सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करता प्रतीत होता है।

उसके राजनीतिक लक्ष्य मूलतः अपरिवर्तित होने पर भी, उन्हें अब सावधानी से पृष्ठभूमि में ही रखा जाता है। इसका सार्वजनिक आग्रह अब ऐसे मूल मुद्दों पर है, जिनके बारे में सभी लोग एकमत हैं कि ये मुद्दों जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए। उसका उद्देश्य एशिया को धीरे-धीरे सोवियत क्षेत्र में खींच लेना है।

ये नई कार्यनीतियाँ हमारे हितों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। आज हम अपने औद्योगिक कच्चे माल का लगभग 50 फी सदी एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका से आयात करते हैं। पेली रपट के अनुसार 1965-70 तक यह संख्या बढ़कर संभवतः 70 फी सदी हो जाएगी।

अगर सोवियत रूस की इस नई 'दमधोड़ कार्यवाही' के फलस्वरूप, इन विशाल महाद्वीपों में हमारे प्रवेश का मार्ग बन्द हो जाय, तो हमारी सैन्य शक्ति धीरे-धीरे नष्ट होने लगेगी, और हमारा जीवन-स्तर खतरों में पड़ जाएगा।

यही परिणाम है जो हमेशा रूसियों का लक्ष्य रहा है। अब उनकी चालें अधिकाधिक कौशलपूर्ण हैं।

हमारी अपनी नीतियों का निर्माण करने वालों के लिए उन राष्ट्रों का पक्ष लेना स्वाभाविक और मानवीय है, जो 'हमारे पक्ष' में खड़े होने को, और ऐसा न करने वालों की निन्दा करने को तैयार हो।

किन्तु हम संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति निष्ठा खरीद नहीं सकते। हम एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका वालों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे अमरीका के जीवन-स्तर को उठाने के लिए अपनी जान देंगे। सारी मनुष्य जाति के समान, वे केवल अपने देश के लिए, और जिसे वे अपना हित समझते हैं, उसी के लिए बलिदान करेंगे।

अतः, हम उनके स्वार्थ के साथ अपने स्वार्थ का मेल बिठाना होगा। और यह काम नारों से नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही के द्वारा करना होगा। हमें ऐसे सामान्य लक्ष्यों

की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन्हे वे लोग महत्वपूर्ण समझते हैं।

सौभाग्यवश, इन लक्ष्यों को समझना और स्वीकार करना हम प्रमरीकियों के लिए आसान है—औपनिवेशिक शासन से आजादी, बिना जाति, धर्म, या रंग सम्बन्धी किसी भेदभाव के सभी लोगों की मानवी प्रतिष्ठा, और आर्थिक व्यवस्थाओं का विस्तार।

हम कितने वस्तुनिष्ठ रहे हैं ?

विदेशों में हमारी नीतियों की 'वैचारिक शून्यता' को सशक्त चुनौती देते हुए श्री वॉल्स आग्रह सम्बन्धी एक बड़े परिवर्तन का, अमरीका की महानता के उपयुक्त एक नए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। न्यूयार्क टाइम्स मंगलान 20 मई, 1956।

वर्तमान अमरीकी विदेश-नीति के भावी भालोचक शायद एक ऐसी बात पर ध्यान दें, जिस पर इस समय बहुत कम टीका होती है—उसकी वैचारिक शून्यता, किसी ऐसे उद्देश्य का अभाव जिसमें बहुसंख्यक लोग साभीदार हों।

डेमाक्रेंट लोगों के साथ-साथ बहुतेरे रिपब्लिकन भी हमारी विदेश-नीति के पुनः मूल्यांकन की, कष्टदायक पुनः मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं।

किन्तु अगर यह मांग केवल प्राय-व्यय और कार्यनीतियों पर पुनर्विचार करने तक ही सीमित रहती है, तो यह एक अत्यधिक संकुचित दृष्टिकोण होगा। विदेश-नीति अपने आप में स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक साधन है, जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है।

इससे एक आधारभूत प्रश्न उठता है—अमरीका का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? अमरीका दुनिया से क्या चाहता है? वह अपनी ओर से किस योगदान के लिए तैयार है?

जरूरत इस बात की है कि हम न केवल अपने सैनिक कार्यक्रम का, अपनी मित्रताओं का और अपने विदेशी सहायता कार्यक्रम का पुनः मूल्यांकन करें, बल्कि उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम अन्य मनुष्यों के साथ अपने सम्बन्धों का, विश्व के मामलों में अपनी उचित भूमिका का, और अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं का पुनः मूल्यांकन करें।

विश्व के मामलों में वैचारिक दीवालियेपन का यह एक प्रमाण है कि अमरीकी विदेश-नीति में सिद्धान्तों को उचित स्थान देने का सुभाव देने वाले पर तत्काल वास्तविकता से अपरिचित होने का आरोप लगा दिया जाता है।

वे यह मान लेते हैं कि निजी व्यवहार में सिद्धान्तों का पर्याप्त महत्त्व होता है। लेकिन विदेश-नीति का मामला अधिक जोखिम भरा होता है। उनके कथनानुसार, इसमें हमारा ध्यान मुख्यतः शक्ति की कठोर-बुद्धि समझ पर होना चाहिए।

मैं सोचता हूँ कि शक्ति की यह 'रक्षा-प्राधीर' वाली धारणा ही क्या हमारी वर्तमान विश्व-व्यापी द्विविधा के मर्म में नहीं है, जिसे बहुतेरे लोग अन्तर्राष्ट्रीय 'यथार्थवाद' का परम रूप मान लेते हैं? हम कुछ ऐसे छतरनाक श्वरोधों को देखें, जो इस संकुचित दृष्टिकोण ने अभी भी हमारे सामने उत्पन्न कर दिए हैं।

पाँचवें दशक में हमारा यह मान लेना कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था कि राष्ट्रवादी चीन की संकुचित आधार वाली सरकार, जो सामन्तवादी जमींदारी पर आधारित थी, और जिसके नेतृत्व का चीनी लोगों से सम्पर्क टूट गया था, माओ-त्से-तुंग द्वारा चलाई गई क्रांतिकारी लहर को रोकने में समर्थ हो सकती थी?

हमारा यह मान लेना कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था, कि एक कुशलतम पेशेवर सेना भी हिन्दुचीन में साम्यवादियों को रोक सकती थी, जबकि साम्यवाद-विरोधी प्रयास मृतप्राय फ्रांसीसी उपनिवेशवाद पर आधारित था, जो एक पुरानी पड़ चुकी भूमि-व्यवस्था से बधा हुआ था, और स्थानीय भ्रष्टाचार ने जिसे जकड़ रखा था?

कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सभ की सेनाओं को ऐसा मानकर अड़तीसवें अध्याय के पार ले जाना कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था, कि चीन की चेतावनी केवल गीदड़ भभकी थी, और चीन युद्ध में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता था—जबकि तीन वर्ष बाद हमें उसी रेखा पर युद्ध-विराम स्वीकार करना पड़ा?

हमारा यह मान लेना कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था कि अपने अच्छे मित्र पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके हम इस अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, जबकि दक्षिण एशिया के शक्ति-संतुलन को इस प्रकार परिवर्तित करने के फलस्वरूप, अफगानिस्तान ने भयभीत होकर हसी सहायता स्वीकार कर ली, और हिन्दुस्तान ने अपनी सेना में काफी अधिक वृद्धि की?

अपने पश्चिमी उपनिवेशवादी मित्रों से मतभेद बचाने के लिए, अफ्रीका में राष्ट्रवाद के सशक्त, अनिवार्य की विकास की उपेक्षा करना हमारे लिए कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था?

हमारा यह मान लेना कहीं तक यथार्थ के अनुरूप था कि बिना राजनीतिक या आर्थिक आधारों के, उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि (रूस की) नई कार्य नीतियों से दुर्बल नहीं होगी, और यह कि हमारी अपनी शक्तों के अनुसार जर्मनी का एकीकरण हो सकता है?

ऐसे विचारों में जो सकीर्ण दृष्टि परिलक्षित होती है, उससे संकेत मिलता है कि विश्व क्रांति के युग में हमारे बहुतेरे नीति-निर्माता विचारों और लोगों की शक्ति को नहीं देख पाते।

जब तक मनुष्यों के मन विचारों से प्रभावित होते हैं, जब तक मनुष्य और उनकी आकांक्षाएँ शक्ति का एक मुख्य अंग हैं, तब तक अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार राष्ट्रों में उलट-पलट करते रहेंगे, सेनाओं की शक्ति को झुठलाते रहेंगे, और इतिहास का निर्माण करते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि शक्ति के इस मूल पक्ष की स्वीकृति

नया यथार्थवाद है। विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसे समझते थे। हमारी पीढ़ी के नेताओं ने बहुधा इसकी उपेक्षा की है।

हमें विचारों और प्रति-रक्षा के बीच संतुलन प्राप्त करने की चेष्टा करनी होगी। एक ओर दुनिया के ऐसे सभी लोगों को एक संघर्षरत नई स्वतंत्रता के झंडे के नीचे लड़ना होगा, और आज ऐसे लोगों का विशाल बहुमत है, जिनके लक्ष्य वही हैं जो हमारे—आत्म-निर्णय, मानवी प्रतिष्ठा और बढ़ते हुए अवसर। दूसरी ओर हमें एक विशाल, सक्षम प्रतिरक्षा-क्वच निर्मित करना होगा, जिसके पीछे इन तत्त्वों की प्राप्ति के लिए सशक्त प्रयास किए जा सकें।

अगर हम उस तेजी से बदलते हुए, क्रांतिकारी विश्व के सदस्य में अपने हितों पर विचार करें, जिसमें हम रह रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे हित आश्चर्यजनक सीमा तक दूसरे लोगों के हितों से मिलते हैं।

एक वर्ष पहले एशिया और अफ्रीका के अट्ठाइस राष्ट्रों ने अपने चार प्राथमिक लक्ष्य निरूपित किए—श्रीपनिवेशिक प्रभुत्व से आजादी, जाति, धर्म या रंग के भेद-भाव के बिना व्यक्ति की प्रतिष्ठा आर्थिक अवसरों का विस्तार, और शान्ति।

ये मार्क्सवादी विचार नहीं हैं। ये पश्चिमी और अमरीकी विचार हैं—जिस अर्थ तक चल रही अमरीकी क्रांति के पक्ष में जेफरसन, लिंकन, विल्सन, और रूजवेल्ट इतने प्रभावशाली ढंग से बोलें थे, यह इन दो विशाल महाद्वीपों में उसी क्रांति की छाया है।

अगर इस धरती पर हमारा कोई उद्देश्य है—और मैं गंभीरता से विश्वास करता हूँ कि है तो वह उद्देश्य सारी दुनिया में उदार लोकतंत्र की उस भावना का संरक्षण और अन्ततः विस्तार है, जिसमें मनुष्य की प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा सर्वप्रमुख है।

इसके लिए अन्य लोगों के साथ हमारे सम्बन्धों में अप्रहं सम्बन्धी काफी बड़े परिवर्तन की, और अमरीकी सुरक्षा, विकास और अभिवृद्धि की समस्या के प्रति एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, संयुक्त राज्य अमरीका में अपनी सारी यात्राओं में हर जगह मैंने देखा कि अमरीकी लोग ईमानदारी के साथ अपनी निराशा से छुटकारा पाने की, और एक नया दिशा-बोध प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं।

विश्व में अमरीका की भूमिका के सम्बन्ध में सार्वजनिक दृष्टि अगर कहीं अति संकीर्ण है, तो इस कारण कि दोनों राजनीतिक दलों के नेता वह व्यापक दृष्टि प्रदान करने में असफल रहे हैं, जो इसके पहले हमारे इतिहास की सकटपूर्ण अवधियों में महान् अमरीकियों ने प्रदान की थी।

यूरोप में हमारे और रूस के लक्ष्य

श्री योल्ल का कथन है कि मध्य यूरोप में सैनिक शक्ति को धीरे-धीरे घटाने से दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है। न्यूपाक टाइम्स मंगलोजन 12 मई, 1957 में प्रकाशित इस लेख में उक्त प्रस्ताव पर श्री खुरचोव की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है।

यूरोप में हम अमीकी लोग वस्तुतः चाहते क्या हैं? हमारा पहला सुरक्षा सम्बन्धी लक्ष्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि यूरोप की औद्योगिक और सैनिक शक्ति कभी हमारे विरुद्ध संगठित नहीं होगी।

यूरोप में किसी शक्ति या शक्ति-समूह का प्रभुत्व न होने पाए, इसके लिए दम-लिस्तान ने पाँच बड़े युद्ध लड़े। जब इंगलिस्तान की सैनिक क्षमता दूसरे महायुद्ध के बाद कुछ कमजोर पड़ी तो कुछ दूरदर्शी अमरीकी नेताओं ने उस क्षमता को पूरा करने के निर्णायक महत्त्व को समझा।

इस प्रकार 1947 में भूयध्य सागरीय क्षेत्र पर रूस के दबाव के फलस्वरूप हमने 'ट्रुमन मिद्दान्त' का साहस पूर्ण निर्णय लिया। जब रूस ने मध्य और पूर्वी यूरोप से हटना अस्वीकार किया, तो हमने जर्मनों में काफ़ी मात्रा में सैनिक शक्ति लगाई और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की रक्षा-शक्ति को संगठित और सुसज्जित करने में सहायता की।

यूरोप की समृद्धि और उसकी राजनीतिक स्थिरता के निकट सम्बन्ध को समझने के कारण हमने पहले युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए, और फिर यूरोप के असाधारण युद्धोत्तर कालीन आर्थिक विस्तार की ठोस नींव डालने के लिए अरबों डॉलर लगाए।

किन्तु, अधिकांश अमरीकी यूरोप को राजनीतिक क्रीड़ा क्षेत्र मात्र नहीं समझते। यूरोप के साथ सहकृति, इतिहास, धर्म, और विचार-दर्शन में हमारे निकट सम्बन्ध हैं। वस्तुतः, हममें से 80 प्रतिशत यूरोप के वंशज हैं।

यद्यपि 1944 से पूर्वी यूरोप के राष्ट्र बहुत कुछ सोवियत प्रभुत्व में रहे हैं, किन्तु दम दुस्ती क्षेत्र के लोगों के प्रति, जिनके लाखों मित्र और सम्बन्धी अमरीका में हैं, हमारी विनता अब भी गहरी और सच्ची है।

मोटे तौर पर, हमारा विश्वास है कि यूरोप और अमरीका, दोनों के ही लक्ष्यों की पूर्ति अधिकाधिक समकक्ष और मंघ के द्वारा हो सकती है, जिसमें अन्ततोगत्वा पूर्वी यूरोप के राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं। यूरोप के राष्ट्र जैसे-जैसे इकट्ठा होंगे, यूरोप के लोगों में नया आत्म-विश्वास और सोद्देश्यता आएगी। इंगलिस्तान, फ्रांस और अन्य औपनिवेशिक राष्ट्रों के पास सदियों तक दुनिया के विभिन्न भागों में फैली हुई जो शक्ति थी, उसकी समाप्ति को स्वीकार करना भी ऐसे समेकित यूरोप में उनके लिए ज्यादा आसान होगा।

किन्तु रूस की दृष्टि में स्थिति क्या है? 20 फरवरी को, अपने मास्को दफ्तर में निकिता ख्रुश्चोव ने दो घण्टे की एक चर्चा में रूसी दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया।

1. मध्य यूरोप की वर्तमान 'अस्वाभाविक' स्थिति रूस, अमरीका अथवा यूरोप वालों के हित में नहीं है। यह भी संभव है कि किसी अचानक उठी चिनगारी के फलस्वरूप उत्तरी अटलांटिक संधि और सोवियत रूस की सेनाएँ ऐसे किसी संघर्ष में टकरा जाएँ, जिसे कोई भी न चाहता हो।

2. यद्यपि सोवियत रूस या अमरीका, कोई भी जर्मनी के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता, किन्तु एकीकरण की प्रक्रिया सोपानों में चलनी चाहिए, ताकि पूर्वी जर्मनी में विकसित साम्यवादी 'आर्थिक संस्थाएँ' सुरक्षित रह सकें।

3. रूस सारी रूसी सेनाओं को रूसी सीमा के अन्दर ले जाने को तैयार होगा, बशर्ते कि अमरीकी और इंगलिस्तानी सेनाएँ भी अपनी सीमाओं के अन्दर चली जाएँ। श्री ख्रुश्चोव ने कहा कि तब उत्तरी अटलांटिक सन्धि और वासा सन्धि के सदस्य, राष्ट्रों के बीच एक समझौते के द्वारा, जिसमें अधिक शस्त्रीकरण के विरुद्ध भी व्यवस्था हो, यूरोप में शान्ति सुरक्षित हो सकती है। सोवियत रूस चाहेगा कि दोनों ही संगठन भंग कर दिये जाएँ, और उनके स्थान पर एक ऐसा संगठन आए जिसके सदस्यों में अमरीका और रूस दोनों ही हों। किन्तु वे इस पर आग्रह नहीं करेंगे।

4. श्री ख्रुश्चोव ने कहा कि यद्यपि राष्ट्रपति ब्राइजनहूवर के समक्ष प्रधान मंत्री बुल्गागिन ने धीरे-धीरे सेनाएँ हटाने का प्रस्ताव पूरी सच्चाई से रखा था, किन्तु, उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? 'अरबपति हथियार-निर्माताओं' के दबाव के कारण, जो श्री ख्रुश्चोव के अनुसार 'शीत-युद्ध में कोई हिराई लाने के विरुद्ध हैं।'

अपने उत्तर में मैंने कहा कि एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि दोनों ही दलों के अमरीकी इसके इच्छुक हैं कि यूरोप अपने ढंग से विकसित हो। युद्ध के बाद सोवियत रूस ने लाल सेना को अपनी सीमाओं तक हटा लेने से इन्कार किया, इसीके फलस्वरूप जर्मनी में अमरीकी सेनाएँ मौजूद रही, और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का विकास हुआ।

वर्तमान तनाव भरी स्थिति में सोवियत नेताओं का हमसे यह भाषा करना यथार्थ के अनुकूल नहीं था कि हम तीन हजार मील समुद्र के पार चले जाएँ, जब कि उनकी अपनी सेनाएँ अच्छी सड़कों पर केवल कुछ सौ मील हटकर रूसी सीमाओं के मन्दर जाएँ ।

श्री ख्रुश्चोव हमसे ऐसा करने की भाषा नहीं कर सकते थे जब तक कि हम अपनी सेना और साज-सामान के सारे बड़े भण्डो को अपनी पश्चिमी सीमा से कुछ दूर पूर्व की ओर रखने को तैयार न हो और इस सारे क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को पूर्ण सैनिक निरीक्षण का अधिकार न दे ।

श्री ख्रुश्चोव हमसे यह भाषा भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया के अन्य भागों में हवाई भण्डो की अपनी व्यवस्था को हम खत्म कर देंगे जब तक कि सैनिक प्रविधियों में कोई जबरदस्त परिवर्तन न हो जाय, या साविक निरस्त्रीकरण के लिए कोई समझौता न हो जाय ।

मैंने कहा कि बहुतेरे कारणों से अधिकांश अमरीकियों के लिए यह विस्वास करना कठिन था, कि अन्तिम, निर्णायक फैसले का यत्न भाने पर श्री ख्रुश्चोव और उनके साथी सचमुच रूसी सेनाओं को यूरोप में उनके मौजूदा स्थानों से ऐसी शर्तों के अन्तर्गत पीछे हटाने को तैयार होंगे, जो अमरीका को और उत्तरी अटलांटिक संधि में उसके मित्रों को स्वीकार्य हो ।

पहली बात यह है कि पूर्वी जर्मनी, हंगरी, और पोलैण्ड की घटनाओं से मिले संकेत के अनुसार, पूर्वी यूरोप से सोवियत सेनाओं के हटने पर उस क्षेत्र में रूस के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में तेज़ी से कमी आएगी ।

उदाहरण के लिए, पूर्वी जर्मनी के निवासियों का जीवन-स्तर पश्चिमी जर्मनी के निवासियों से काफी नीचा है । वे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के साथ क्यों बिपके रहेंगे, जो पश्चिमी जर्मनी की अधिक स्वतंत्र व्यवस्था की तुलना में कम उत्पादक साबित हुई है ? एक बार लाल सेना के हट जाने के बाद, श्री ख्रुश्चोव जर्मन लोगों को अपने देश का एकीकरण करके उसे अपने ढंग से विकसित करने से कैसे रोकने की आशा कर सकते थे ?

इसके अतिरिक्त, रूसी सेना के हटने पर, इसकी संभावना थी कि यूरोप का एकीकरण हो और पश्चिमी यूरोप के साथ पूर्वी हिस्सों का निकट सम्बन्ध स्थापित हो ।

श्री ख्रुश्चोव ने उत्तर दिया कि रूसी नेताओं ने इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार किया था । उनकी राय थी कि समेकित यूरोप, अमरीका, इंगलिस्तान या फ्रांस के दीर्घ-कालीन हित के अनुकूल नहीं होगा । उन्होंने कहा कि ऐसे यूरोप पर जर्मनी का प्रभुत्व होगा, जो "शान्ति-काल में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, जिन्हें वह युद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं कर सका ।"

मैंने उनसे पूछा कि जैसा मैंने कहा था, उस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का एकीकरण होने पर, उसे रोकने के लिए क्या रूस युद्ध करेगा । उन्होंने उत्तर दिया,

“अगर हमारे यूरोपीय पड़ोसी युद्ध पर उतारू नहीं हो जाते, तो निश्चय ही नहीं।”

पिछले कुछ हफ्तों में इस वार्ता के सम्बन्ध में मैंने कई लोगों से बातचीत की, जिन्होंने वर्षों तक सोवियत रूस का अध्ययन किया है, और जिनमें से कई लोग रूस के वर्तमान नेताओं को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। उनमें न केवल मास्को स्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ शामिल हैं, वरन् पोलैण्ड और युगोस्लाविया की सरकारों के सदस्य, मास्को, बेलग्रेड, बर्लिन और अन्य स्थानों में स्थित अमरीकी अधिकारी और अमरीका में सोवियत रूस के अध्येता भी शामिल हैं।

इनमें से धिकांश का विचार है कि बुल्गारिन और खुश्चोव की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, किन्तु सबकी राय ऐसी नहीं है।

एक प्रभावशाली विदेशी सैनिक नेता ने, जिन्हें रूसी सरकार के नेताओं को जानने का अवसर मिला था, इसके विपरीत एक रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “मैं नहीं जानता कि श्री खुश्चोव के मन में क्या था, किन्तु मार्शल जुकोव किस तरह सोचते होंगे, इसका अनुमान लगाने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि वे इस प्रकार सोचते होंगे—

“पूर्वी जर्मनी में मेरे पास रूसी सेना के वाइस डिवीजन हैं, जो मध्य यूरोप में केन्द्रित है। उनकी संचार व्यवस्था पोलैण्ड और हंगरी से होकर चलती है। अब हम जानते हैं कि इन तीनों राष्ट्रों के लोग हमारे खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं।

“हम लाल सेना के लोग विशेष रूप में यह जान गए हैं कि पूर्वी यूरोप में हमारी नीतियाँ असफल रही हैं। तेरह वर्ष तक हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस इलाके को सोवियत क्षेत्र में खींच लाने की और वहाँ के लोगों का विश्वास प्राप्त करने की चेष्टा की है। इसमें वे पूरी तरह असफल रहे हैं। उनकी असफलता के फलस्वरूप मुझे सोवियत सैनिकों को बुडापेस्ट की सड़कों पर हंगरी के हजारों नागरिकों को मारने का आदेश देना पड़ा।

“किन्तु हमारी सैनिक कठिनाइयाँ यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पिछले तेरह वर्षों में हमने पूर्वी यूरोप के देशों में साठ से अधिक डिवीजन संगठित किए हैं, और उन्हें आधुनिक रूसी तोपों, टैंकों और हवाई-जहाजों से सज्जित किया है। बुडापेस्ट में हमने जो कुछ देखा और पोलैण्ड तथा पूर्वी जर्मनी में जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, उससे संकेत मिलता है कि युद्ध होने पर यह अनुपेक्षणीय ताकत हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, पूर्वी और मध्य यूरोप की सैनिक शक्ति को कठोरता से सीमित करने वाले किसी समझौते से सोवियत रूस को बड़ा लाभ हो सकता है।

“फिर आर्थिक समस्या भी है। युद्ध के बाद से हमने सोवियत यूनियन को मजबूत बनाने के लिए पूर्वी यूरोप से पूंजी, सामान और कच्चे माल के रूप में प्रति वर्ष अरबों रूबल प्राप्त किये हैं। इस इलाके में भ्रष्ट से बचने के लिए अब हमें पूंजी के प्रवाह को इस दिशा को बदलना होगा। क्या इस धन को एशिया और

मे लगाना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा, जहाँ हम बेदाग हैं, और नए सिरे से काम कर सकते हैं ?

“ निश्चय ही हमारा प्रचार विभाग इतना चतुर होना चाहिए कि जर्मनी से हट जाने के प्रस्ताव का उपयोग हमारे राजनीतिक लाभ के लिए कर सके। क्या वे ऐसा नहीं दिखा सकते कि तनाव कम करने की चेष्टा करने वाले हम लोग ही हैं ? अगर अमरीकी लोग इसे अस्वीकार करते हैं, तो यही प्रतीत होगा कि वे यूरोप को विभाजित रखना चाहते हैं। ”

मार्शल जुकोव के विचारों की संभव रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मेरे यूरोपीय सैनिक मित्र ने चेतावनी भी दी—“निस्सन्देह अन्तिम निर्णय मार्शल जुकोव नहीं, वरन् ख्रुश्चोव और अन्य लोग करेंगे।”

जब तक रूस को आशा रहेगी कि एशिया और अफ्रीका के साथ पहले मास्को के आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के बाद, अन्ततः उन्हें सोवियत क्षेत्र में खींचा जा सकता है, तब तक सोवियत रूस किसी सार्थक, दीर्घकालीन, विश्व-व्यापी समझौते के लिए गम्भीरता से बातचीत करेगा, इसमें मुझे सन्देह है। और एक तटस्थ, असम्बद्ध जर्मनी हमारे हित में भी नहीं होगा।

फिर भी, मध्य यूरोप में ऐसी स्थिति बने रहने में न हमें कोई लाभ है, न रूस को, जिसमें किसी आकस्मिक दुर्घटना से आश्विक युद्ध की ज्वाला फूट सकती है, जिससे दोनों ही पक्ष बचना चाहते हैं।

यूरोप के प्रति एक नई नीति

श्री वॉल्स का कथन है कि यूरोप में एक नया युग आरम्भ हो रहा है। इसमें निहित संभावनाओं का सामना करने के लिए अमरीका को अपने लक्ष्यों और साधनों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। न्यूयार्क टाइम्स मंगलदिन, 20 दिसम्बर, 1959।

राष्ट्रपति आइज़नहॉवर, प्रधान मंत्री मैक्लिफन, राष्ट्रपति दिगाल ग्योर चान्मलर आदिसनवर, शिखर वार्ता के पूर्व पेरिस में बातचीत कर रहे हैं, और इसकी पृष्ठभूमि में यूरोप में अमरीकी नीति के सम्बन्ध में आशंकाएँ हैं।

राष्ट्रपति के सानदार वीरे से हमारे तात्कालिक इरादों के बारे में शंकाओं का समाधान करने में सहायता मिली है। किन्तु, जिसे आम तौर पर यूरोप में एक नया और भिन्न काल माना जाता है, उसके बारे में हमारी समझ, और उसमें आत्मविश्वास के माय, प्रभावकारी रीति से काम करने के बारे में हमारी क्षमता के बारे में अब भी सन्देह बने हुए हैं।

हमारे अल्प-कालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर वस्तुपूर्वक रीति से पुनर्विचार करने की आवश्यकता काफी दिनों से है। हमारी यूरोपीय नीति के मूल में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के साथ निकटतम राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक सम्बन्धों के आधार का बने रहना आवश्यक है। किन्तु, तेजी से सामने आती हुई नयी स्थितियों का प्रभावकारी रीति से सामना करने के लिए, इन नीतियों को नया स्वर, नयी दिशा और नयी शक्ति प्रदान करनी होगी।

शीत-युद्ध की कठोरता के स्थान पर बातचीत और आर्थिक प्रतियोगिता चलाने के प्रस्तावों में श्री खुश्चोव ने काफी बड़ी निजी राजनीतिक पूँजी दाँव पर लगाई है। उनकी मशा चाहे जो भी हो, उनके वादों ने देश और विदेश में कुछ आशाएँ उत्पन्न की हैं—ऐसी आशाएँ, जिन्हें वे या और कोई भी धानानी से या जल्दी समाप्त नहीं कर सकता।

चीन की बढ़ती हुई हठवादिता निश्चय ही रूस के नीति-निर्माण में काफी परेशानी पैदा करती होगी। तनाव बढ़ाने का चीन का प्रकट निश्चय, मास्को के नए दृष्टिकोण के विपरीत है। जहाँ तक देखा जा सकता है, चीन रूस पुरी को कायम रखना दोनों के ही लिए निर्णायक महत्त्व की बात प्रतीत होती है। किन्तु रूस से

तीन गुनी आवादी वाले, अतिसाहसिक और आक्रमण की मनोवृत्ति वाले 'छोटे भाई' की शकल निश्चय ही रूसी नीति निर्माताओं के मन में गम्भीर चिन्ता उत्पन्न करती होगी।

अगर हथियारों की प्रविधि और रणनीति में तेजी से बढ़ती हुई क्रांति बिना किसी नियन्त्रण के चलती रही, तो अगले कुछ वर्षों में विश्व की सभी बड़ी शक्तियों को खर्च, खतरों और तनावों में विशाल वृद्धियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही, फ्रांस और अन्य राष्ट्रों के पास भी आणविक हथियार हो जाने पर, किसी विश्वसनीय नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना के साधन अधिक उलभते जाएंगे।

यूरोप के अन्दर, और यूरोप व अमरीका के बीच आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध भी बदल रहे हैं। 1953 से हमारे आर्थिक विकास की औसत वार्षिक गति 2.5 प्रतिशत रही है, जबकि पश्चिमी यूरोप के बड़े हिस्से की रफ्तार इसकी तीन गुनी है। सापेक्ष दृष्टि से यूरोप के आर्थिक विकास में यह तेजी का काल है जबकि हमारे यहाँ प्रगति धीमी है।

इन सारी बातों को देखते हुए हमारे वर्तमान दृष्टिकोणों और कार्यक्रमों में बहुत कुछ ऐसा है जो समयानुकूल नहीं रह गया। युद्धोत्तर काल का अन्त हो गया है। अब हम पुनः समझन, प्रयोग, व्यावहारिकता और प्रवाह के एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं।

जहाँ तक मैं देख पाता हूँ यूरोप में अमरीकी नीति के तीन लक्ष्य हैं—

1. बर्लिन जैसे दवाव बिन्दुओं के सम्बन्ध में हमें अपनी दृढ़ता के सम्बन्ध में विश्वास को पुनः प्रतिष्ठित करना है।

2. एक स्वतन्त्र यूरोपीय समुदाय की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारा मित्र हो और जिसमें अपने पाँव पर खड़े होने की क्षमता हो।

3. हमें सभी राष्ट्रों के सभी लोगों के मन में एक शान्तिपूर्ण, दीर्घकालीन समझौते की आकांक्षा को स्वीकार करना होगा और ऐसे प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने होंगे जो कभी ऐसे समझौते का आधार बन सकें।

पहली आवश्यकता है कि हम उत्तरी अटलांटिक सन्धि को दुर्बलता और सभ्रम की स्थिति में पड़ने से रोकें। जब तक रूसी सीमा के पश्चिम में रूसी सेना के लगभग तीस डिवीजन मौजूद हैं, तब तक यूरोपीय प्रतिरक्षा की तैयारियों को, जो अभी भी अपर्याप्त हैं, और दुर्बल करना नादाना होगी।

पिछले दिनों सरकारी सूत्रों की ओर से यह बड़ा ही अनुपयुक्त सुझाव रखा गया कि हम निकट भविष्य में यूरोप स्थित अपनी स्थल और वायु सेनाओं में और भी एकतरफा कटौती कर सकते हैं। स्वयं सेनाध्यक्ष (राष्ट्रपति) द्वारा इसका खंडन होना चाहिए। जहाँ तक अब यह संभव हो बर्लिन के सम्बन्ध में दृढ़ता की नीति पुनः अपनाने की दिशा में यह पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

बर्लिन की स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। यह स्थिति हमारे लिए खतरनाक है, रूसियों को परेशान करने वाली है, और अत्यधिक साहसी बर्लिनवासियों के लिए और सबमुच सभी जर्मन लोगों के लिए हताशा उत्पन्न करने वाली है। फिर भी जब तक सारे मध्य यूरोप में वर्तमान स्थिति बनी रहती है, तब तक किसी दबाव के अन्तर्गत बर्लिन की विशिष्ट स्थिति के सम्बन्ध में रूसियों को सन्तुष्ट करने की चेष्टा का केवल यही परिणाम होगा कि हमारे मित्र भयभीत हो जाएँगे और रूस को अपनी माँगों और बढ़ाने के लिए बल मिलेगा।

मिसाल के लिए, मित्र राष्ट्रों के बर्लिन स्थित दस हजार सैनिकों की संख्या में किसी संभव कटौती को लेकर सौदेबाजी करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। सामरिक दृष्टि से उनकी वर्तमान संख्या रूसियों के लिए भी महत्वहीन है और हमारे लिए भी। कोई भी ऐसा नहीं समझता कि रूसी आक्रमण होने पर वे सफलतापूर्वक नगर की रक्षा कर सकते हैं। उनके वहाँ रहने का उद्देश्य यही है कि हम वहाँ रहने के अपने अधिकार का एक ठोस प्रतीक बनाए रखें।

अतः, उनकी संख्या में कमी करने के लिए रूसी दबाव का उद्देश्य केवल ऐसी रियायतें प्राप्त करना है, जिन्हें बर्लिनवासी और आम तौर पर सभी जर्मन लोग अमरीकी धीरज और शक्ति में कमी होने का चिन्ह समझेंगे।

ऐसे प्रश्नों पर अधिक दृढ़ नीति अपनाने के फलस्वरूप अगर रूसी लोग बर्लिन और उसके मार्गों सम्बन्धी अपने अधिकार पूर्वी जर्मनी के अपने एजेण्टों को सौंप देते हैं तो हम पश्चिमी बर्लिन में अपनी सेनाएँ रखने, और कब्जा रखने के अपने वर्तमान कानूनी अधिकार को कायम रखने के अतिरिक्त अपने अन्य सभी अधिकार अपने एजेण्टों के रूप में पश्चिमी जर्मनी को सौंप देने पर विचार करें।

सारभूत प्रश्नों पर दृढ़ता का अर्थ हर छोटे-मोटे सवाल पर श्रांख मूँदकर हठ करना नहीं है। बर्लिन में अपने अधिकारों के सम्बन्ध में दृढ़ रहने का यह नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि पूर्वी जर्मनी और शेष पूर्वी यूरोप के साथ हमारे व्यवहार में आगे-पीछे का कोई व्यवहार न रहे। पोलैण्ड, जोकोस्लोवाकिया, और हंगरी से आए लोगों के मत प्राप्त करने के उद्देश्य से 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को मुक्त कराने का वादा बड़ी गैर-जिम्मेदारी का और छलपूर्ण कार्य था, जिसकी असफलता स्पष्टतः स्वयं उसमें ही निहित थी।

एक ओर रूसी हितों, तथा दूसरी ओर अमरीकी शक्ति की सीमाओं की वस्तुपरक समझ के साथ-साथ अमरीकी नीति के अवसरों का होशियारी से सहयोग करने से कहीं अधिक ठोस परिणाम निकलेंगे। कूटनीति, विचार-विनिमय, परामर्श, आर्थिक सहायता और खेती में हमारे अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग पूर्वी यूरोप की राजनीति और आर्थिक जीवन में विभिन्नता लाने में सहायक हो सकता है—जो इस क्षेत्र में हमारी नीति का मूल लक्ष्य होना चाहिए।

इस विभिन्नता से ऐसी हलचल पैदा हो सकती है, जो इस दुःख पीड़ित क्षेत्र के

लोगों के लिए अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना मभव बनाए। हमारा लक्ष्य हंगरी जैसी अव्यवस्था और सखट नहीं है, वरन् उस प्रकार का राष्ट्रीय पुनः जागरण है, जो पोलैण्ड में रक्तहीन क्रान्ति से विकसित हुआ। पिछले दिनों हुए सरकारी दमन के बावजूद स्टालिन के काल में जितना मभव था, पोलैण्ड में आज उससे कहीं अधिक स्वतन्त्रता है।

दूसरी बात यह है कि यूरोपीय एगता की धारणा के विकास के पक्ष में अमरीकी प्रभाव का उपयोग हर मभव अवसर पर होना चाहिए। संयुक्त यूरोप की उपलब्धि के मार्ग में जो विदाल कठिनाइयाँ हैं, उनके बावजूद यह विचार उन सभी लोगों के सामने बराबर रखा जाता रहे जो अपने को यूरोपीय समझते हैं, इसमें अमरीका का अधिकतम हित है।

इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि कोयला और इस्पात समूह यूरोपीय अणु समझौता, और फ्रान्स, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हालैण्ड, और लक्जेंबर्ग द्वारा मिलकर बनाये गए सामान्य बाजार का निर्णायक महत्त्व है। ये विभिन्न सस्याएँ अब धीरे-धीरे मिलकर काम करने की ओर बढ़ रही हैं। अधिकांश अमरीकी लोग जैसा समझते हैं, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की रफ्तार निश्चय ही उससे कहीं अधिक है।

अगर इन छह राष्ट्रों के साथ इंगलिस्तान भी मिल जाय तो इनकी संभाव्य औद्योगिक शक्ति काफी अधिक होगी, और ये मिलकर एक 'संयुक्त राज्य यूरोप' की नींव डाल सकते हैं। इससे फिर एक ऐसी रचनात्मक और गतिशील शक्ति प्राप्त हो सकती है, जो अन्ततः यूरोप के स्थायी विभाजन को रोके।

अमरीकी मंत्र्य नीति उत्तरी अटलाण्टिक गन्धि के साथ जुड़ी हुई है, और जुड़ी रहनी चाहिए इस कारण ही यह आवश्यक है कि हम एकीकरण के इस आन्दोलन को प्रोत्साहित करें कि वह वास्तविक मागर में वाला मागर तरु फले हुई वर्तमान मैनिक विभाजन को मजबूत बनाने में नहीं वरन् उसे कमजोर करने में सक्रिय आर्थिक और राजनीतिक योग दे। हम इस आशा से कार्य करें कि इस समुदाय का विवास इस प्रकार होगा कि हम के पिछलगू देशोत्थित, मध्य यूरोप की वह यूरोप के एकीकरण में शामिल होने के लिए निरन्तर आकर्षित करता रहेगा, चाहे हम दिशा में पहले बंदम कितने भी प्रयोगात्मक और कमजोर क्यों न हों। मिगाम के लिए सामान्य बाजार में मूलान और तुर्की की मजबूतदस्यता से मभव है कि आगे चलकर मुगोम्लाविद्या भी उममें इहाँ प्रकार मजबूत हो जाय।

दूसरे पक्षों में नया मगटन दीवारें मठी करने वाला न होकर दरवाज खोलने वाला हो—और न केवल मुगोम्लाविद्या, के लिए वरन् पोर्तुगल, इगारी, जेकोम्बो-कारिया रुमानिया और युग्राविद्या के लिए भी। उममें एक ऐसे शान के निर्माण में भी मजबूतता मिल सकती है, जिसके मन्दमें में अन्ततः बर्तन और पूर्वी जर्मनी के बारे में भी कोई निर्णय लिया जा सके।

ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे और रूस के भी तात्कालिक हित जर्मनी के विभाजित रहने में है। निश्चय ही वर्तमान स्थिति में जर्मनी का एकीकरण अनभव है। किन्तु दीर्घकालिक दृष्टि से, जर्मनी का विभाजन यूरोप के विभाजन का तीव्र रूप है, और बर्लिन का विभाजन जर्मनी के विभाजन का तीव्र रूप है। ये विभाजन सभी सम्बन्धित लोगों के लिए खतरनाक हैं।

केवल संयुक्त यूरोप में ही संयुक्त जर्मन बिना किसी खतरे के रह सकता है, और संयुक्त यूरोप तथा संयुक्त जर्मनी में ही एक प्रमुख राज-नगर के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। अतः अगर संयुक्त यूरोप के धीरे-धीरे निर्मित होने का दोस्र प्रमाण सामने आए, तो यह आशा की जा सकती है कि पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की भावनाओं और आशाओं पर भी उमका रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यह आश्चर्य और भी अधिक बढ जाएगा, अगर इस सम्बन्ध में अमरीकी नीति को अधिक स्पष्ट करने की दिशा में चेष्टा की जाय कि प्रतिवन्धहीन यूरोपीय बाजार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के प्रयासों का अमरीका हृदय समर्थन करेगा। अगर यूरोप में स्वतंत्र बाजार का विकास हो, तो हम उसे खतरा न समझकर अपने लिये एक अवसर समझें। उदाहरण के लिए, सामान्य बाजार हमें अवसर देता है कि हम दूध देशों से अलग-अलग समझौते करने के बजाए, एक ही समझौते के द्वारा अमरीकी माल पर लगाये गए आयात प्रतिबन्धों, मात्रा सम्बन्धी सीमाओं और शुल्कों आदि के सम्बन्ध में रियायतें हासिल कर सकें चूंकि व्यापार सम्बन्धी समझौते के प्रसंग में हमारी स्थिति मजबूत है, अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सक्रिय होकर इस स्थिति का उपयोग करना चाहिए।

निश्चय ही, हमें हर उपलब्ध अवसर का उपयोग करना चाहिए कि अर्द्धविकसित देशों की सहायता के संयुक्त प्रयासों में समृद्ध यूरोपीय देशों के अधिक भाग लेने को प्रोत्साहित करें। ऐसी सहायता में न केवल ऐसे अफ्रीकी देश शामिल हों जिनसे विभिन्न यूरोपीय सरकारों के निकट सम्बन्ध हैं, वरन् यह सहायता विशेषतः जर्मन की ओर से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के अन्य ऐसे देशों को भी दी जाय, जहाँ उसकी आवश्यकता है और उपयोगिता भी।

यूरोप में आर्थिक एकीकरण से गरीबी और आर्थिक अन्वय की उन गम्भीर समस्याओं को हल करने की भी सहायता मिल सकती है, जो आज भी मौजूद हैं। वस्तुतः इन आर्थिक अन्वयों को समाप्त करने के लिए जल्दी-जल्दी प्रभावकारी कदम उठाना, विशेषतः दक्षिणी यूरोप में, आवश्यक है।

पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के सभी देशों में, 'आर्थिक पुनःनिर्माण' ने ज्ञानदार मकानों और बरिया दूकानों के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि के सुप्रचारित सूचक-अंकों का एक प्रभावशाली दृश्य खड़ा कर दिया है। किन्तु इनमें से कई देशों में वितरण, सहभाग, और न्याय के और भी महत्वपूर्ण सूचक अंक उतने प्रभावशाली नहीं हैं।

अर्मार और गरीब के बीच सार्द, बनी रहने के कारण राजनीतिक विभाजन भी गहरे चने रहे हैं।

युद्ध समाप्त होने के चौदह वर्ष बाद भी, इटली में 37 प्रतिशत लोगो ने साम्यवादी या उनके सहयोगी उम्मीदवारों को वोट दिया। फ्रांस में साम्यवादी वोट 51 प्रतिशत है। यूनान में गृह-युद्ध और साम्यवादी दल के गैर कानूनी होने के बावजूद, साम्यवा-दियों द्वारा नियन्त्रित 'जनवादी वामपक्षी सभ' को पिछले चुनाव में लगभग 25 प्रति-शत वोट मिले।

इसका यह अर्थ नहीं कि इटली, फ्रांस और यूनान के लगभग एक चौथाई लोग साम्यवाद में विश्वास करते हैं। वामपक्षियों को अब भी भारी गंठ्या में मिलने वाला वोट बहुत-कुछ ऐसी सरकारों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन है, जिन पर यदि उचित ही यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे जन सामान्य के विरुद्ध घनी और दमनशाली लोगो का पक्ष लेती हैं। यह विरोध अब भी इतना बड़ा है, यह तथ्य ऐसे मुयारों की आवश्यकता को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्हें बहुत पट्टे ही हो जाना चाहिए था।

तीसरी और अंतिम बात यह है कि अधिकांश यूरोपीय और अन्य लोग भी समान रूप से अब किसी ऐसे साहसपूर्ण और सच्चे प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, जो रूस द्वारा स्वीकृत हो जाने पर अधिक शान्तिपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। इस प्रस्ताव का तर्कसंगत और विश्वसनीय होना आवश्यक है। यूरोप में रणनीति सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का बलिदान किए बिना, यह प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसे सोवियत रूस समझौता-वार्ता के लिए आधार रूप में स्वीकार कर सके।

क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है, जो इस लक्ष्य के अनुकूल हो, जो विशिष्ट रूप में सम्पूर्ण यूरोप पर लागू हो सके, जिसमें उत्तरी अटलांटिक संधि सम्बन्धी हमारी प्रतिबद्धता कायम रहे, जो 'पीछे हटने' के पुराने प्रस्तावों को जाने-पहचाने खतरों से दूर हो, लेकिन फिर भी जो नई समझौता वार्ता की दिशा में एक रचनात्मक प्रयास हो? कोई अरबित विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद है। याकि ऐसे प्रस्ताव में ठीक ठीक क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन मे समझता हूँ कि पिछले बसन्त में राष्ट्रपति दिगाल और चासलर आदेनावर ने जो सुझाव रखा था, उसे प्रस्थान-बिन्दु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

25 मार्च को दिगाल ने कहा—'अगर पीछे हटने में जो क्षेत्र खाली होता है, वह यूरोप पंचत से भी उतना ही दूर नहीं होता जितना अटलांटिक से, तो कैसे..... हम किसी आक्रमणकारी को एक छलांग या एक उड़ान में जर्मनी के खाली इलाके को पार करने से रोक सकेंगे; निश्चय ही हम युद्ध के सभी हथियारों को नियन्त्रित और सीमित करने के पक्ष में हैं। लेकिन इन उपायों में..... इतना काफी बड़ा क्षेत्र आ जाना चाहिए कि फ्रांस सुरक्षित रहे, अरक्षित नहीं।'

दो सप्ताह बाद चासलर आदेनावर ने बॉन में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा—

"जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, मैं इस स्थिति में हूँ कि आम तौर पर तथाकथित तनाव-रहित क्षेत्र के आकार, फैलाव, और प्रकृति के बारे में जनरल दिगाल ने जो कुछ कहा है, उसका समर्थन करूँ।.....ऐसे क्षेत्र का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब अटलांटिक से यूराल तक समस्त क्षेत्र का निःशस्त्रीकरण हो।"

सम्पूर्ण यूरोप की सुरक्षा को सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने वाले इलाके में सीमित सैनिक क्रियाकलाप का ऐसा व्यापक क्षेत्र, आने बढ़ने के लिए सचमुच एक संभव आधार प्रदान कर सकता है। अगर ध्यानपूर्वक बनाये गए कार्यक्रम के अनुसार आण्विक हथियारों के अड्डों, राकेटों और प्रक्षेपास्त्रों के अड्डों, और परम्परागत सैन्य बल के विशाल केन्द्रों को, पूर्ण निरीक्षण और नियन्त्रण के अन्तर्गत धीरे-धीरे घटाया जाय, तो हमें आक्रमण और प्रतिरक्षा की क्षमताओं में अन्तर करने में सहायता मिलेगी, जो इस समय अधिकाधिक कठिन कार्य होता जा रहा है। यह कार्यक्रम एक विश्व-व्यापी शस्त्र-नियन्त्रण समझौते के एक अंग के रूप में, या एक अधिक सीमित क्षेत्रीय मन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सम्पूर्ण यूरोप में सैन्य बल घटाने का ऐसा कार्यक्रम सोवियत रूस और हमारे द्वारा चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के कठिन प्रश्न को छोड़कर भी अपनाया जा सकता है, जिसके कारण किसी विश्व-व्यापी शस्त्र-नियन्त्रण समझौते की संभावनाएँ कम से कम फिलहाल बहुत कम हैं। इस प्रस्ताव की एक अच्छाई यह भी है कि इसमें सभी विदेशी सेनाओं को यूरोपीय महाद्वीप से हटाने की, या किसी देश अथवा किन्हीं देशों के समूह के 'विसैन्यीकरण' की शर्तें नहीं हैं। इन दोनों प्रस्तावों से जितनी समस्याएँ हल हो सकती हैं, उससे अधिक नई समस्याएँ पैदा होने की संभावना है।

इस प्रस्ताव पर सोवियत रूस की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, अगर हम इसे बराबर प्रस्तुत करते रहें, तो इससे भय के स्थान पर आशा उत्पन्न होगी, और सारा विश्व पुनः आश्वस्त होगा कि अमरीकी वृद्धनीति जागरूक और रचनात्मक है, और शान्ति की ओर प्रगति की किसी भी वास्तविक संभावना का उपयोग करने को पुनः उत्तर है।

फिर से पहल करने का समय

श्री वॉल्स का कथन है कि सब कृच्छ्र भूलकर, रूस आगे बधा करेगा, इसी में दृवे रहना अमरीका की गतिशील परम्पराओं के अनुपयुक्त है। अक्टूबर, 1960 में मिनेसोटा विदेश-नीति-संघ के समक्ष एक भाषण में वे अमरीकी विदेश-नीति के लिए कुछ सशक्त और नई निर्देश रेखाएँ प्रस्तुत करते हैं।

श्री ख्रुश्चोव अब क्या करेगे ?

कितने ही महीनों से उनकी धमकियाँ और लातच भरे प्रस्ताव, उनके पतरे और भाषण हमारे अखबारों और टेलीविजन के परदों पर, हमारे राजनीतिक नेताओं के मन पर, और हमारी विदेश-नीति के निर्धारण पर छाए रहे हैं।

किसी मोटर की चकाचौध करने वाली रोशनी में जकड़े हुए खरगोशों की तरह, हमारा ध्यान सोवियत प्रधान मंत्री की हर मुद्रा पर केन्द्रित रहा है।

इतिहासकार निश्चय ही इसे एक विचित्र बात समझेंगे। वे पूछेंगे कि अपनी जीवन्त जनता, अपनी गतिशील औद्योगिक व्यवस्था, अपने असोमित साधनों, और मानवीय स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी सारी शानदार परम्पराओं के बावजूद, बीसवीं सदी का अमरीका अन्धा होकर रूस के कथनों और कार्यों में कैसे जकड़ गया ?

इस स्थिति में नए चेहरो और नए विचारों की आवश्यकता है। इसमें एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है, जो हमारा ध्यान रूस की ओर से, जिसके बारे में हम आज विद्वेग कुछ नहीं कर सकते, हटाकर उन विशाल सभावनाओं की ओर लगाए, जो हमें बहुत कुछ करने का इस्सारा कर रही हैं।

मैं कुछ ऐसे वर्मक्षेत्र गिनाऊँ, जिनमें एक नया प्रशासन अगली जनवरी में तंजी से आने बढ सकता है, चाहे श्री ख्रुश्चोव कुछ भी कहे या करे।

1. हम अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। हमारी सैन्यशक्ति को सतुलित करना आवश्यक है, जिससे ऐसी आण्विक प्रहार-शक्ति प्राप्त हो जिसे अचानक हमले के द्वारा पगु न किया जा सके। इसके साथ ही हमारी स्थल सेनाओं में अधिक लचीलापन और गतिशीलता आए, ताकि अगर स्थानीय संघर्ष फिर उत्पन्न हो, जैसा कि पहले होता रहा है, तो हम उनका सामना कर सकें। हमारी वर्तमान प्रतिरक्षा नीतियों ने हमें केवल एक ही प्रकार का युद्ध लड़ने के लायक छोड़ा है, जिस

के बारे में हमारा कहना है कि हम वंसा युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे—एक सर्वप्राप्ति आण्विक युद्ध जो हमने ही शुरू किया हो।

2. हम निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण के क्षेत्र में अपने सारे प्रयत्नों को एक साथ और तेजी से बढ़ा सकते हैं। नए प्रशासन में निःशस्त्रीकरण और प्रतिरक्षा को उनके वास्तविक रूप में देखना होगा—असंगत, प्रतियोगी नीतियाँ नहीं, बरन् आने वाले महीनों में विश्व की स्थिरता के लिए समान रूप में आवश्यक।

अपने वक्तव्यों और कार्यों के द्वारा, अगला प्रशासन यह प्रदर्शित कर सकता है कि हम जीवन और मृत्यु के नए तथ्यों को जानते हैं, कि हम आण्विक भय के सन्तुलन पर आधारित शान्ति की दुर्बलता को समझते हैं, और यह कि हम निरन्तर ऐसे नए रास्तों की तलाश के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनसे निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी वर्तमान गति-रोध को अगर समाप्त नहीं तो कम किया जा सके।

इन नए रास्तों में वास्तविक सुरक्षाओं के साथ शस्त्र-नियन्त्रण के, उपयुक्त खोज पर आधारित नए प्रस्ताव भी शामिल करने चाहिए, और धीरज तथा कौशल के साथ उनके बारे में बातचीत चलानी चाहिए।

3. हम अटलांटिक के उस पार रहने वाले, विकसित उद्योग-धन्धों और कौशल वाले चालीस करोड़ लोगों के साथ अधिक प्रभावकारी सहयोग सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। हमारी और उनकी एक सामान्य सांस्कृतिक और राजनीतिक परम्परा है।

इस समय उत्तरी अटलांटिक समझौते को कायम रखने वाला सबसे बड़ा अटलांटिक तत्व शायद यह है कि हम सबको ख़ुश्चोब से भय है। ख़ुश्चोब की कठोर या कोमल मुख मुद्रा के अनुसार उत्तरी अटलांटिक सन्धि भी सबल या दुर्बल होती है।

यह सामान्य भय अपने यूरोपीय मित्रों के साथ हमारे दीर्घकालीन सम्बन्धों को कायम रखने के लिए अपर्याप्त है। हमें फिर से इन सम्बन्धों के मूल में जाना चाहिए, और उन राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाना चाहिए, जो हमें जोड़ते हैं।

अटलांटिक समाज में सहयोग की व्याख्या को सबल बनाना नए प्रशासन का पहला काम होना चाहिए।

4. हम अपने आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का पुनः मूल्यांकन और पुनः संगठन कर सकते हैं।

इन कार्यक्रमों के लिए नई कसौटियाँ बनाने की ज़रूरत है, जिससे उन राष्ट्रों को अधिक सहायता मिले जो उसका अधिक से अधिक प्रभावकारी उपयोग कर सकते हों, और जो तीव्र गति से प्रगति करने के लिए स्वयं भी आवश्यक बलिदान करने को तैयार हों।

ऐसे मामलों में जहाँ समस्या को देखते हुए दीर्घकालीन सहायता का आश्वासन उचित हो, इसकी व्यवस्था करके हम व्यवस्थित और कम खर्च नियोजन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

5. संयुक्त-राष्ट्र संघ में हम शीत-युद्ध की तू-तू में-में में माग सेना कम करके, एशिया और अफ्रीका के व्यवस्थित राजनीतिक और आर्थिक विकास में सहायता देने की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की इन महाद्वीपो में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, और इनमें संघ के कार्यक्षेत्र को अर्सेनिक शासकीय सेवा से लेकर आर्थिक सहायता तक, और शस्त्र-नियंत्रण से लेकर शिक्षा तक, जहाँ भी आवश्यकता हो, बढ़ाना चाहिए ।

6. हम सातित्व अमरीका में सकट उत्पन्न होने पर दबाव के अधीन, समय निकल जाने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की नीति को त्याग सकते हैं । इसके बजाए, हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री रूजवेल्ट की 'अच्छे पड़ोसी' वाली नीति को व्यावहारिक रूप में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं ।

इसमें अमरीकी राज्य संघ को सबल बनाना और बगोटा के नए अधिनियम को लागू करना शामिल है ।

सोवियत रूस और अमरीका के बीच शस्त्र-नियंत्रण में प्रगति न होने पर, हम कम से कम निःशस्त्रीकरण के क्षेत्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं । इसके लिए दक्षिण अमरीका एक उत्तम आरम्भ-स्थल है ।

7. चीन के प्रति हम अधिक बस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने सकते हैं । जब तक पीकिंग की सरकार से एशिया की शान्ति को खतरा है, और वह फारमोसा पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करती रहती है, तब तक उसे मान्यता प्रदान करने का कोई सवाल नहीं उठता ।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व, जापान और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ चीन का व्यापार, चीन-रूस सम्बन्ध और चीन द्वारा अपने चारों ओर खड़े किए आवरण में दरार डालना, ये चीनी समस्या के अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष होंगे जिनका नए प्रशासन को सामना करना पड़ेगा ।

यद्यपि चीन के प्रति कठोर नीति अपनाने के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, किन्तु ब्राइडनहृवर प्रशासन जैसा सोचता प्रतीत होता है, खतरा वास्तव में उससे बड़ा है । वस्तुतः प्रशासन ने लगातार स्थिति के आधारभूत खतरों को असलियत से कम भाँका है ।

चीनी विस्तारवाद का सामना हम प्रभावकारी रीति से तभी कर सकते हैं, जब हम इस बात को समझें कि उसके मूल में केवल चीनी साम्यवाद ही नहीं, बरन् चीन की साम्राज्यवादी परम्परा, और पर्याप्त भूमि, तेल, और अन्य साधनों का अभाव भी है ।

पूर्वी एशिया में यथार्थपरक नीति को अपनाना ध्यान संन्य-क्षेत्र के अलावा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी, वास्तविक शक्ति की स्थितियाँ निर्मित करने पर केन्द्रित करना होगा, जो चीन के पड़ोसियों पर चीनी मुख्य भूमि के 65 करोड़ लोगों के प्रभाव को काट सकें ।

जापान और फारमोसा से लेकर, दक्षिण पूर्वी एशिया होते हुए हिन्दुस्तान और

पाकिस्तान तक, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यवस्थित आर्थिक विकास की नींव डालने में हम जो कुछ सहायता करते हैं या नहीं करते उसका स्वतंत्र एशिया के भविष्य पर निर्णायक प्रभाव होगा।

8. अन्त में अमरीका को नेतृत्व के अधिक उपयुक्त बनाने के लिए, ऐसे बहुसंख्यक कार्य हैं, जो हम स्वयं अपने सम्बन्ध में कर सकते हैं।

हम अपने आर्थिक विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, ताकि अपने विस्फोटक किन्तु असीमित संभावनाओं से भरे विश्व की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक लोग, उत्पादन और मशीनें हमें उपलब्ध हो सकें।

हम आधुनिक स्कूल और विश्वविद्यालय बना सकते हैं, और योग्य अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो इसके लिए आवश्यक है कि हर अमरीकी लड़का या लड़की जितनी शिक्षा उपयोगी रूप में ग्रहण कर सके, उतनी उसे उपलब्ध हो।

हम अपनी गन्दी वस्तियों को साफ करके अपने शहरों को पुनःनिर्मित कर सकते हैं।

हम ज्यादा अच्छे, और आसानी से उपलब्ध अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

हम अपनी रेलों के बहुत उत्पादन का उपयोग सारी दुनिया में अमरीकी विदेश नीति की एक मौलिक उपयोगी वस्तु के रूप में कर सकते हैं।

सारे अमरीका में मनुष्यों की समान प्रतिष्ठा के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करके हम सर्वत्र, सभी मनुष्यों के समक्ष यह प्रमाणित कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता के घोषणापत्र के इन शब्दों में अब भी हमारा विश्वास है कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं।

ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो हमारे सामने हैं, और यह सूची किसी भी तरह से पूर्ण नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में हमें रोकने वाले श्री खूबचोव नहीं हैं, बरन् हमारे शासन के वर्तमान नेतृत्व का निष्क्रियता, संभ्रम और आस्था का अभाव हमें रोके हुए है।

हमारी शताब्दी का भाग्य-निर्णय करने वाले पाँच फ़ैसले

श्री चौल्स का विचार है कि इनमें से दो फ़ैसलों का सामना हमने सफलतापूर्वक किया, दो के सम्बन्ध में असफल रहे और एक अभी अनिर्णीत है। अमरीकी पुस्तक-विक्रेता संघ के वार्षिक सम्मेलन के समक्ष एक भाषण से, वाशिंगटन, 12 जून 1961।

आज मैं बहुत आगे जाकर ऐसे लेखकों की तरफ देखना चाहूँगा—लगभग एक बीबी वाद के इतिहासकार—जो हमारे राष्ट्र, विश्व के साथ उसके सम्बन्ध और दुनिया में अधिक स्थिरता लाने में उसके योगदान के बारे में अपना फ़ैसला लिखेंगे।

मध्य-बीसवीं सदी के घटना-क्रम पर अमरीका के प्रभाव के सम्बन्ध में ये इतिहासकार क्या कहेंगे ?

शान्ति और समृद्धि के पक्ष में अपनी असाधारण नयी भौद्योगिक क्षमता के उपयोग की सफलता या असफलता के बारे में वे क्या कहेंगे ?

बीसवीं सदी के पहले पाँच दशकों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि वे अपना ध्यान निर्णय के कम से कम पाँच क्षेत्रों पर केन्द्रित करेंगे। दो मामलों में वे कह सकते हैं कि हम असफल रहे। अन्य दो के बारे में कह सकते हैं कि हम सफल हुए। पाँचवें मामले का फ़ैसला अभी नहीं हुआ।

हमारी पहली दुःखद असफलता थी कि 1919 में हम 'लीग ऑफ नेशन्स' में शामिल नहीं हुए, और यूरोप में उस समय स्थापित शान्ति को कायम रखने के कार्यक्रम के पीछे हमने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा नहीं लगाई।

दूसरी, उतनी ही बड़ी असफलता यह थी कि 1911 में माजू साम्राज्य का पतन होने पर हमने चीन की क्रान्तिकारी उपन-पुथल को, और भविष्य में हमारी सुरक्षा के साथ उसके सम्बन्ध को नहीं समझा।

तीसरी घटना पश्चिमी यूरोप के लिए नाबो खतरे का सामना करने में हमारी सफलता की थी।

चौथा फ़ैसला यूरोप में युद्धोत्तर-कालीन आर्थिक और राजनीतिक अव्यवस्था की चतुर्नीति को दिया गया हमारा धानदार और निर्णायक उत्तर था।

पाँचवाँ, और आखिरी फैसला सातवें दशक में हमारे सामने है, और उसका सम्बन्ध एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लातिन अमरीका में रहने वाले दुनिया के दो-तिहाई लोगों की बढ़ती हुई आशाओं और अपेक्षाओं ने मानव-जाति के लम्बे और घटनापूर्ण इतिहास की सबसे सशक्त और खतरनाक, लेकिन साथ ही सबसे अधिक संभावनापूर्ण क्रान्ति को जन्म दिया है।

इस आखिरी फैसले में न केवल अमरीकी सरकार द्वारा, वरन् अमरीकी लोगों द्वारा भी, एक सर्वथा अभूतपूर्व, बड़ी गम्भीर और दूरगामी परिणामो वाली प्रति-बद्धता शामिल है।

अतः हम निर्णय के पहले चार क्षेत्रों पर संक्षेप में इस आशा से नजर डालें, कि शायद इससे हमें पाँचवें फैसले के सम्बन्ध में कोई नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

1. 'लीग ऑफ नेशन्स' में शामिल न होना

1919 में हमारे 'लीग ऑफ नेशन्स' में न शामिल होने के जो परिणाम हुए, उनकी बेबल एक संक्षिप्त चर्चा काफी होगी।

विल्सन ने हमें बार-बार चेतावनी दी थी कि अगर हमने उनकी दृष्टि का परित्याग किया और नवोदित विश्व-समाज से अलग हो गए, तो इससे न केवल 'विश्व का दिल टूटेगा' बल्कि हमें अपनी असफलता का मूल्य रक्त से चुकाना पड़ेगा।

लेकिन अलगवादी प्रवृत्तियाँ तब तक सबल थीं, और उनके समर्थक चतुर और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने कहा कि 'यूरोप की समस्याओं को हल करने' के लिए अपने नौजवानों और अपने धन को विदेश भेजकर हम काफी उदारता दिखा चुके थे।

और इस कारण युद्धो विल्सन की बात नहीं मानी गई, और उनकी 'लीग ऑफ नेशन्स' का परित्याग किया गया। इस तरह हमारे पितामों की पीढ़ी ने, जो विश्व व्यवस्था के आरम्भ के लिए आवश्यक उत्साह और बल प्रदान कर सकती थी, भविष्य की ओर से मुँह मोड़ लिया। मैं समझता हूँ कि 1919 में विश्व उत्तरदायित्व से अमरीका के पीछे हटने पर सन् 2000 ईस्वी का ऐतिहासिक निर्णय बड़ा कठोर होगा।

2. चीनी क्रान्ति की चुनौती

निर्णय का दूसरा बड़ा क्षेत्र चीनी क्रान्ति की चुनौती से उत्पन्न हुआ। चीनी गणराज्य का जन्म होने पर, नवोदित चीन की भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं को समझने, और उसके आर्थिक विकास पर ठोस और शायद निर्णायक प्रभाव डालने के लिए हमारी स्थिति बड़ी ही अनुकूल थी।

किन्तु, 1920 और 1921 में जब सन-यात-सेन ने चीन के एकीकरण और आर्थिक विकास को धागे बढाने के लिए, काफी मात्रा में कर्ज माँगे, तो हमने फौरन साफ इन्कार कर दिया। यह सवाल उठा था, उस समय हमकी जानकारी भी केवल मुट्ठी भर दूरदर्शी अमरीकियों की थी।

और इस तरह, पश्चिमी यूरोप की राजधानियों में भी ऐसे ही निराग होने के बाद, हताश होकर सन सन उग गहायता के लिए मास्को की नयी साम्यवादी सरकार की ओर मुड़े, जिसे देना अटलांटिक राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया था।

1922 के वाशिंगटन में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में हाईग प्रशासन ने इस अक्षफलता को और भी बढ़ाया। जापान ने अपनी शक्ति पर कुछ सीमाएँ लगाना स्वीकार किया था, इसके बदले में हमने अपनी नयी नीतिना के बड़े हिस्से को सन्तुष्ट कर दिया, पश्चिमी प्रशासन महागणर के क्षेत्र में अपनी शक्ति का परिचय कर दिया, और जापानी आक्रमणों के उग मिलगित के लिए मार्ग खोल दिया जिनकी परिणति उन्नीस वर्ष बाद पूर्ण हायर की घटना में हुई।

किन्तु हमारे सामने और भी अन्तर था, हमने और भी बड़ी गलतियाँ कीं। 1927 में, जब सन-यात-सेन के उत्तराधिकारी, वयाग-वार्ड-शेरु गाम्यवादियों के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने एक आधुनिक, अ-साम्यवादी राज्य स्थापित करने की योजना बनाई, तो हमें एक और मौका मिला कि हम पुरानी गलतियों को सुधार सकें। लेकिन एक बार फिर समृद्ध, सन्तुष्ट, दूरस्थ, गुरभित अमरीका इस चुनौती को समझने में अक्षफल रहा।

1931 में जापानी सेना ने मन्चूरिया में प्रवेश किया। उस समय भी दृढ़ अमरीकी कार्यवाही जापानी आक्रमण को रोक सकती थी, और चीन को एक स्वतंत्र और राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्तपूर्ण राष्ट्र बनने का मौका मिल सकता था। लेकिन 1930 के बाद हम स्वयं अपनी समस्याओं में फँसे हुए थे, और जापानी नौसेना की शक्ति को छोड़ने के लिए, या लड़खड़ाती हुई चीनी सरकार को अति आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थे।

कोई नहीं जानता कि ठीक-ठीक किस समय चीन की घटनाओं को प्रभावित कर सकने की हमारी क्षमता खत्म हो गई।

कुछ प्रेक्षकों का कथन है कि 1941 में भी, अमरीका की ओर से एक व्यापक सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रयास, साम्यवाद का एक प्रभावकारी, लोकतांत्रिक विवलय प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन युद्ध समाप्त होने तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि बड़े पैमाने पर अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप के अलावा और किसी तरह चीन के घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता था।

युद्ध और सकट से जनता की ऊब, और दोनों दलों के राजनीतिक नेताओं द्वारा इस स्वाभाविक मन-स्थिति के अनुकूल चलने के प्रयत्नों के फलस्वरूप, आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में बहस भी नहीं हुई।

इस प्रकार, हम अपनी सदी की विरोध नीति सम्बन्धी दूसरी बड़ी चुनौती का सामना करने में अक्षफल रहे। इस अक्षफलता के परिणाम कई पीढ़ियों तक दुनिया के साथ रहेंगे।

3. नाज़ी जर्मनी का विरोध

तोसरी चुनौती को हमने देर से, लेकिन प्रभावकारी रीति से समझा और उसका सामना किया।

इतिहास सम्बन्धी अपनी सबल दृष्टि के कारण, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने इस बात को समझा कि यूरोप में नाज़ी प्रभुत्व का अर्थ होगा एक ऐसी दुनिया, जिसमें अमरीका की अपनी स्वतंत्रता के लिए आधारभूत खतरा उत्पन्न हो जायगा। 1937 में उन्होंने अमरीकी लोगों में भी यही समझ उत्पन्न करने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्न करना शुरू किया।

हमारी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि रूजवेल्ट की अपील को अस्वीकार करके सबसे अग्रगण्य हो जाएँ। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को सामान भेजने पर रोक लगाने वाला लक्ष्यता अधिनियम हमारी राष्ट्रीय मन:स्थिति को व्यक्त करता था।

फिर भी, आत्म-निर्भरता की पुरानी मिथ्या धारणाएँ कमजोर पड़ने लगी थीं। देर से मही, लेकिन हम राष्ट्रों की परस्पर-निर्भरता को समझने लगे थे, जिसे स्वीकार करने की अपील वुडरो विल्सन ने हमने की थी। और इसलिए, इंग्लिस्तान की कठिनतम और श्रेष्ठतम घड़ी में हमने उसका समर्थन किया।

4. युद्धोत्तर-कालीन पुन:निर्माण की चुनौती

चौथी चुनौती यूरोप में युद्ध समाप्त होने के शीघ्र बाद ही सामने आने लगी।

वर्षों की बमबारी और सड़कों पर हुई लड़ाइयों से यूरोप के नगर खडहर हो गए थे। भोजन, ईंधन, और इमारती सामान नाकाफी था। बढ़ती हुई भँहगाई और मुद्रा-स्फीति से यूरोप की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था टूटने के निकट आ गई थी।

और इस बीच, कुछ सौ मील दूर पूर्वी जर्मनी और पोलैण्ड में सोवियत सेना के दो सौ डिवीजन तैयार खड़े थे, जो चाहने पर लगभग निर्विरोध इंगलिश चैनल तक बढ़ जा सकते थे।

सोवियत रूस ने प्रारम्भ में यूनान और तुर्की पर दबाव डाला। इंगलिस्तान, जिसकी चतुर कूटनीति और सैन्य शक्ति ने दो सदियों से रूस को भूमध्य सागर तक पहुँचने से सफलतापूर्वक रोक रखा था, अब इस चुनौती का सामना करने में समर्थ नहीं था।

इसके साथ ही, सारे पश्चिमी यूरोप में, साम्यवादी दल, जो नाज़ीवाद के विरुद्ध भूमिगत प्रतिरोध के साथ सक्रिय रूप में सम्बद्ध रहे थे, संभ्रम उत्पन्न करने, संयुक्त मोर्चे बनाने और अन्ततः सत्ता हथियाने के लिए जोर-शोर से कार्यवाही कर रहे थे।

हमारा सौभाग्य था कि असाधारण सत्यनिष्ठा और बुद्धि के एक व्यक्ति, जनरल जार्ज मासल इस संकट-काल में हमारे विदेश सचिव थे। हैरी ट्रुमन हमारे राष्ट्रपति थे, जिनका प्रत्यक्ष साहस और सोद्देश्यता की अविचल भावना निश्चय ही हमारे काल के इतिहास में उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करेगी।

इन व्यक्तियों ने संकट का सामना किया, और फलस्वरूप एक शानदार रचना-

त्मक राष्ट्रीय प्रयास ने रूस के सैनिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्तरे को रोका, एक नए स्वतंत्र यूरोप की फिर से नींव डाली, और सगभग निश्चित रूप में हमें एक तीसरे विश्व-युद्ध से बचाया।

यूनान और तुर्की की रक्षा के ट्रूमन सिद्धान्त के बाद, पश्चिमी यूरोप के धार्मिक और राजनीतिक पुनःनिर्माण की मार्शल योजना आई। फिर पश्चिमी यूरोप की सैनिक प्रतिरक्षा के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि सगठन बना, और बर्लिन के साथ हवाई यातायात की नाटकीय घटना हुई, जिसमें हमने यह प्रमाणित कर दिया कि हम अमरीकियों और हमारे मित्रों के पास साधनों के माप-माप सकल्य भी था।

1949 में, जब नए आजाद हुए, बहुत ही गरीब, और अब तक बहुत कुछ अविकसित राष्ट्रों की नई चुनौती सामने आने लगी, तब भी हमने एशिया अफ्रीका और लातिन अमरीका के साथ रचनात्मक साझेदारी के लिए धनु.गुप्ती कार्यक्रम के द्वारा कुछ सर्वथा नए कदम उठाए।

इन वर्षों में हमने एक अभूतपूर्व चुनौती का शानदार, रचनात्मक और दलीय भावना से रहित उत्तर दिया। इन वर्षों में नेताओं ने सचमुच नेतृत्व किया और जागरूक तथा जानकारीपूर्ण अमरीकी लोगों ने उत्तर में ऐसी निष्ठा और बुद्धि का प्रदर्शन किया, जो किसी महान् राष्ट्र की विशिष्टता होती है।

5. अमरीकी नेतृत्व की सातवें दशक की चुनौती

महत्वपूर्ण स्थितियों के इस क्रम में, जिन्होंने इस सदी के पहले साठ वर्षों में अमरीकी लोगों की ऐसी कठिन परीक्षाएँ ली, अब हम पाँचवीं, और सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं।

उन्नीसवीं सदी, और बीसवीं सदी के पहले कुछ वर्षों में, ऐसा कहा जा सकता था कि विश्व-शान्ति लगभग पूरी तरह यूरोप में घबित के सन्तुलन, पर निर्भर थी। दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद से, इस स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हो गया है।

एशिया और अफ्रीका के करोड़ों लोग, जो कभी लंदन, पेरिस, और हाग के आदेशों के अधीन थे, अब स्वतंत्र हो गए हैं। इन नए और अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के उदय ने अनिवार्य ही अमरीकी सरकार, और अमरीकी लोगों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती को जन्म दिया।

यह स्थिति, जिसका प्रभाव-क्षेत्र नया और बहुत अधिक व्यापक है, इस कारण और भी उत्पन्न गई है कि अधिकांश उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में रहने वाली समृद्ध गरीब अल्पसंख्या, और अधिकांश पृथ्वी के दक्षिणी भाग में रहने वाली गरीब रंगीन बहुसंख्या के बीच पहले से ही जो अत्यधिक विस्फोटक अन्तर है, आधुनिक यान्त्रिकी उम्र तेजी से और बढ़ा रही है।

इसी समय, विश्व के मामलों में अग्रपंक्ति की ओर बढ़ता हुआ चीन का नया दंतन है, जो रातोंरात अपना औद्योगिकरण कर लेना चाहता है, जिसमें 65 करोड़

क्रियाशील लोग निवास करते हैं, एक रुढ़िनिष्ठ, आक्रामक नेतृत्व है, अपर्याप्त प्राकृतिक साधन हैं, और जिसके सामने दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसे ललचाने वाला शक्ति का अभाव है, जहाँ तेल और उपजाऊ भूमि की बहुतायत है, जिनकी चीन को बड़ी जरूरत है।

और अन्त में सोवियत रूस है, जिसमें छह करोड़ टन इस्पात उत्पादन की क्षमता है, हमारी अपेक्षा तीन गुनी औद्योगिक विकास की गति है, दुगुनी सख्या में इंजीनियर और वैज्ञानिक प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होते हैं, और आर्थिक हथियारों तथा पारम्परिक सैन्य-बल की विशाल शक्ति है।

पिछले दिनों सोवियत नेताओं ने अल्प-विकसित क्षेत्रों के निर्णायक महत्त्व को नए रूप में समझा है, और उनके साथ अपने व्यवहार में एक नए लचीलेपन, नई चतुराई और नए आर्थिक व राजनीतिक कौशल का विकास किया है।

सब मिलाकर, यह स्थिति अब तक किमी समाज के समक्ष कभी भी आई सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। हमारे मूल्यों, हमारे साहस, और हमारी बुद्धि सबकी परीक्षा है। एक स्वतंत्र समाज के रूप में कार्य करने और समृद्धि प्राप्त करने की हमारी क्षमता की इस अन्तिम परीक्षा के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी ?

हम कुछ अधिक विस्तार से विचार करें कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है।

पहली आवश्यकता है कि हम उन शक्तियों की प्रकृति को समझें, जो पुरानी व्यवस्था को उलट रही हैं, पुराने समाजों को तोड़ रही हैं, नई उमग भरी आशाएँ और अपेक्षाएँ उत्पन्न कर रही हैं, करोड़ों व्यक्तियों के समक्ष ज्यादा अच्छे भविष्य की संभावना प्रस्तुत करते हुए, बहुधा शान्ति के लिए खतरे उत्पन्न कर रही हैं।

इस क्रान्ति के मर्म में मानवी गरिमा के विस्तार की, व्यक्ति के लिए अधिक अवसरों की, अधिक मात्रा में न्याय की सार्विक संभावना है। यद्यपि इसके कार्य बहुधा हिंसापूर्ण, तर्कहीन और विध्वंसात्मक होते हैं, किन्तु यह क्रान्तिकारी संभावना उन्ही मानवी मूल्यों पर आधारित है, जो दुनिया के लगभग हर धर्म में मिल सकते हैं।

सोवियत रूस ने इस क्रान्तिकारी लहर को नहीं उत्पन्न किया, किन्तु वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस लहर को मोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयत्न में, कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से सोवियत रूस की स्थिति बड़ी अनुकूल है।

रूस इन क्रान्तिकारी शक्तियों को समझता है। जातीय संघर्षों से, अथवा दुनिया के रंगीन चमड़ी वाले लोगों के प्रति भेदभाव के इतिहास से उसका चेहरा दूषित नहीं है। अपने तानाशाही शासन के द्वारा वह अपने शैक्षिक, औद्योगिक, आर्थिक या राज-तिक साधनों को इस प्रकार केन्द्रित कर सकता है जिससे वे सोवियत रूस के लक्ष्यों की पूर्ति में सर्वाधिक उपयोगी हों। आम तौर पर इन साधनों को नए राष्ट्र के आन्तरिक गठन के सबसे कमजोर बिन्दु पर केन्द्रित किया जाता है।

फिर भी, रूसी सफलता के मार्ग में कई बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। पहली बात तो यह है कि जो राष्ट्रवाद एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों की और लातिन अमरीका

के नव जाग्रत राष्ट्रों की प्रेरक शक्ति बन गया है, सोवियत रूस के घोषित राष्ट्रीय और सैद्धान्तिक लक्ष्य उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। राष्ट्रवाद के विरुद्ध होने के कारण, सोवियत रूस संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के भी विरुद्ध है, जहाँ नए राष्ट्रों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक विराम-मंच प्राप्त हुआ है। सोवियत रूस औपचारिक धर्म का भी गभीर विरोधी है जिसे वह लोगों के लिए अग्रणीय समझता है। उसका लक्ष्य स्वतंत्रता का विस्तार नहीं है, जिसकी सारी दुनिया को तलाश है, बरन् व्यक्ति को राज्य की सेवा में जोत देना है। अमरीका की शक्ति और दुर्बलताएँ क्या हैं ?

निर्णायक सातवें दशक की चुनौती का सामना करने में, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे प्रतिद्वन्द्वी है। सर्वाधिक हानिप्रद यह तथ्य है कि अमरीकी लोग और उनकी कांग्रेस इस चुनौती की आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं है। वे समस्या के रूप के प्रति निश्चित नहीं हैं, और स्वयं अपने भविष्य के प्रसंग में उसकी तार्किकता के प्रति शकालु हैं।

इसके प्रतिरिक्त, जातीय भेदभाव का लम्बा इतिहास भी हमारी एक कठिनाई है। और अन्त में, हमारी अर्थ-व्यवस्था एक मामूली मदी के प्रभावों से धीरे-धीरे मुक्त तो हो रही है, किन्तु हमारा उत्पादन अभी हमारी पूर्ण क्षमता से बहुत कम है। यद्यपि ये कठिनाइयाँ गभीर हैं, किन्तु हमारी शक्ति भी बहुत अधिक है, और उने कम समझना बहुत बड़ी गलती होगी। हमारे पक्ष में पहली बड़ी बात यह है कि हमारा जन्म एक महान् क्रान्तिकारी नेतृत्व के अन्तर्गत एक क्रान्तिकारी राष्ट्र के रूप में हुआ था। उनसे भी अधिक महत्त्व की बात है कि यह क्रान्ति अब तक चलती आ रही है।

किन्तु हमारे पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है, जिसे हम सबसे कम समझते प्रतीत होते हैं—यह तथ्य कि नए उभरते हुए महाद्वीपों के लोगों के लिए हम ठीक वही कुछ चाहते हैं, जो वे स्वयं अपने लिए चाहते हैं।

हमें विद्यार्थियों की, या हमारी इच्छा के अधीन राष्ट्रों की कोई आकांक्षा नहीं है। टागानोका, बोलिविया, ग्रन्ना, कोरिया और अन्य नए व पुराने राष्ट्रों के लोगों के लिए, हम अधिक धनस्रोतों का विस्तार चाहते हैं, अधिक प्रतिष्ठा और श्वाय, उनके बीमारों की देखभाल के लिए अधिक डाक्टर, बच्चों के लिए अधिक भोजन, और निरक्षरता को दूर करने के लिए अधिक मदद में और ज्यादा अच्छे स्कूल चाहते हैं, संघार के बँहकर माधन चाहते हैं ताकि हम एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें, यात्रा, व्यापार, और स्वतंत्रतापूर्वक माने-जाने का, और स्वयं अपनी शक्ति की सशक्तियों के अन्तर्गत, अपनी इच्छानुसार बोलने, सोचने और उपायाना करने का अधिकार चाहते हैं।

विश्व में एक शान्तिपूर्ण, समृद्ध, अमान्यवादी सामंजस्यकारी का निर्माण करने के प्रयास में, लक्ष्यों की यह एजेंडा समुक्त राज्य के हित में सबसे बड़ी और आधारभूत

शक्ति है। यह तथ्य कि नए राष्ट्रों के लोगों के सोवियत रूस के लक्ष्य, उनके अपने लक्ष्यों के सर्वथा विरुद्ध हैं, सोवियत रूस की आधारभूत दुर्बलता है।'

फिर भी, मुख्य प्रश्न रह जाता है—क्या हम चुनौति का सामना करने के लिए आवश्यक समझ प्राप्त कर सकते हैं, और सफलतापूर्वक उससे निपटने के लिए अपनी शक्तियों को सगठित कर सकते हैं ?

अगर हम अपने उत्तराधिकार के प्रति सच्चे हैं, तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है।

हम ऐसा करें कि सन् 2000 ईस्वी के इतिहासकार यह लिख सकें कि हमारी सदी के पाँच महान् निर्णयों में से पाँचवें और सबसे कठिन प्रश्न का अमरीका ने आत्मविश्वास, साहस और सहानुभूति के साथ उत्तर दिया—ऐसा उत्तर जो हमेशा के लिए सही था।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएँ

संयुक्त राष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में हुए भोज में श्री बोलस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग का मूल्यांकन करते हैं। चासिंग-टन, 24 अक्टूबर 1961।

हमारे सामने दो विशाल प्रतियोगी ज्वार विपरीत दिशाओं में उठ रहे हैं। कभी-कभी ये दोनों ज्वार परस्पर इतने विरोधी प्रतीत होते हैं, कि एक को यथार्थ और दूसरे को भ्रम मान लेने का लोभ होता है।

एक ओर शीत युद्ध के सघर्ष की विशाल धारा है। यह कंट्रीने तारों और पत्थर की दीवारों, अंगल में छिपकर किये गए हमलों और आश्विक विध्वंस के एतारों की दुनिया है, हिंसा, अविश्वास और भय की, धलगाव और टकराव की दुनिया है। स्टालिन ने 1946 में जब पहली बार युवान और तुर्की पर कुट्टिटि डाली, तब ये शीत-युद्ध के सघर्ष का यह मूकानी ज्वार अयबारी की मुठियों पर छाया रहता है।

किन्तु, सश्रीकरण की होड़ के समानांतर, तनाव के साथ-साथ ही चलता हुआ सौगो की जानकारी से बहुत कुछ छिपा हुआ, एक ओर भी ज्वार स्वतंत्रता और धारा की ओर, राष्ट्रीय और मनुष्यों के बीच अधिक सद्भावना और ग्याय की ओर बढ़ता रहा है।

मानवी प्रयाय की इस कम नाटकीय, किन्तु दायद निर्णायक धारा के तत्व क्या हैं? पहला तत्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मान्देलन है, जिसके द्वारा एतिया और अफीका के 10 करोड़ सौगो ने पुखने यूरोपीय और व्यापारिक साम्राज्यों का युवा उतारकर, पन्द्रह वर्षों के अन्दर बालीय नए देशों का निर्माण किया है। इतिहास के पृष्ठों में सम्भवतः शीत-युद्ध की अर्पशा मुक्ति की इस महर को अधिक स्थान मिले।

इस आशाजनक ज्वार का दूसरा तत्व है उग भूग, बीमारी और निराशा के विरुद्ध अभियान का विश्व-स्वाधी निरूपण, जो सदियों से दुनिया के अलग-विगत भागों के लोगों के विशाल बहुमत का भाग्य रहा है।

इस समस्या को हल करने में नए राष्ट्रीय ने बानी सख्ती सुदधान की है। यद्यपि कई इलाकों में प्रगति धीमी है, किन्तु अल्प संकों में हम नियोजन की, सुधार की, और आन्तरिक सघर्षों की मण्डित करने की समाधारण साम्या देखते हैं।

कुछ समय पहले तक केवल कुछ मुठ्ठी भर ऐसे राष्ट्र थे जो उपनिवेशवादी नहीं थे, और जो आवश्यक पूँजी और प्राविधिक समर्थन देने के योग्य थे, और इसके लिए तैयार थे, जिनमें अमरीका भी एक था। अब लगभग पन्द्रह विकसित उद्योग-धन्वों वाले राष्ट्र ऐसे हैं, जो कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति में तेजी लाने के लिए अपनी पूँजी और प्राविधिक कौशल द्वारा सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस सहायता का काफी बड़ा हिस्सा अब क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मार्फत दिया जा रहा है।

यह इस बात का अधिक ठोस प्रमाण है कि आशा की धारा विश्व की समस्याओं के प्रसंग में सबल रूप में प्रवाहित हो रही है।

तीसरी आशाप्रद घटना यह है कि स्वतंत्र राज्यों के नए अन्तर्राष्ट्रीय समूहों का तेजी से उदय हुआ है, जो सुरक्षा और विकास के सामान्य उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र साहचर्य में काम करना सीख रहे हैं। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद, राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलने की, और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रूपों को खोजने की एक विशाल प्रक्रिया चली है, और विश्व समाज में, जो अभी तक अनियोजित और भ्रूण रूप में ही है, अचानक नई संस्थाएँ हमारे सामने आई हैं।

ये तीन तत्व आशा के ज्वार का निर्माण करते हैं।

इन घटनाओं से संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सम्बन्ध है? और संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारा क्या सम्बन्ध है?

हमारे चारों ओर की उलझी हुई और बहुत कुछ अपरिचित दुनिया से अपनी निराशा के फलस्वरूप, सर्वाधिक विचारपूर्ण और जानकर प्रेक्षकों में भी यह प्रवृत्ति होती है कि संभावनाओं को केवल अंधेरे और उजाले के विरोधी सन्दर्भों में देखें। बीच की विभिन्न स्थितियों का सामना करने का कार्य बहुतेरे अमरीकियों के लिए अपरिचित, कष्टप्रद और असन्तोषजनक है।

इस महान् राष्ट्र का निर्माण करने में हमारे अनुभव ने हममें यह सोचने की आदत डाल दी है कि हर प्रश्न के केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक सही और एक गलत। यह भी, कि अगर समस्याएँ हैं, तो हल भी होंगे, अगर खुला सघर्ष होता है, तो एक की पूर्ण विजय होगी, दूसरे की पूर्ण पराजय।

लेकिन जिस नई दुनिया का सामना करना हमारे लिए जरूरी है, वह बहुत ज्यादा उलझी हुई है, और उसमें सीधे-सादे हल शायद ही कभी मिलते हैं। हम मनुष्य-जाति के केवल छह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अपने सारे महान् उद्योगों और सैन्य बल के बावजूद, हम क्या कर सकते हैं, इसकी बड़ी कठोर सीमाएँ हैं।

यह अनिवार्य है कि जो अमरीकी उन उतकणों को नहीं समझ पाते, जिनका सामना संयुक्त राष्ट्र संघ को करना पड़ता है, वे यह आरोप लगाएँगे कि जिस कार्य के लिए हम महान् विश्व संगठन का निर्माण किया गया था, उसे पूरा करने में वह असफल रहा है।

फिर भी, अपने सर्वाधिक सशक्त सदस्यों में से एक के दृढ़ विरोध के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसकी विशेष एजेन्सियों का परिवार, बहुसंख्यक और विभिन्न प्रकार के मोर्चों पर अधिकाधिक शक्ति और दूरदर्शिता के साथ काम करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, विश्व स्वास्थ्य सगठन इस समय मलेरिया की समाप्ति के लिए अभियान चला रहा है—इतिहास में कोई अन्य रोग इतनी अधिक मृत्युओं का, और कार्य में इतनी अधिक शक्ति का कारण नहीं रहा। उसने दुनिया के हर गाँव में साफ पानी पहुँचाने में सहायता देने का अभियान भी शुरू किया है।

पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र वाल निधि ने, जिसमें अठानवें सरकारों ने भाग लिया, साठे पाँच करोड़ गर्भवती स्त्रियों और छोटे बच्चों की माताओं के लिए ज्यादा अच्छी देख-भाल की व्यवस्था की। उमने पन्द्रह सेंट (लगभग बाहर आना) प्रति बच्चे के औसत खर्च पर, नीग्रो बच्चों को होने वाली भूजन की एक व्यापक बीमारी के सिलसिले में साठे सात करोड़ बच्चों का परीक्षण भी किया।

विश्व मौसम सगठन मौसम की सूचना देने के लिए एक विश्वव्यापी व्यवस्था की योजना बना रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार सभ अब सारी दुनिया के लिए रेडियो तरंगों का बँटवारा करता है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय आघार पर आर्थिक और सामाजिक सहयोग के मिल-सिले में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, हर क्षेत्र में द्विराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय सम-भौतों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सभ की सहायत और रचनात्मक एजेन्सियों का भी विकास होता रहा है, जैसे एशिया और सुदूर पूर्व का आर्थिक कमिशन, और लातिन अमरीका का आर्थिक कमिशन।

संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा ने ठोस राजनीतिकी और आर्थिक कार्यवाही की अपनी क्षमता का सानदार प्रदर्शन पिछले वर्ष वागो में किया।

वागो में संयुक्त राष्ट्र सभ ने शान्ति और सुरक्षा के अधिक ठोस आघार निमित्त करने की अपनी क्षमता का भी परिचय दिया। बहुत ही कठिन और तात्कालिक परिस्थितियों में, घट्टादस देनों के लगभग बीस हजार व्यक्तियों की आपाकालीन सेना एनफित करने का जो अमाधारण कार्य संयुक्त राष्ट्र सभ ने किया, वह निश्चिंतता में हम क्षमता का एक नाटकीय उदाहरण है। सभ ने बहुत थोड़े समय में एक बड़ी शान्ति-रक्षक सेना को सगठित करने, नियत स्थानों पर ले जाने, उसे रसद पहुँचाने और मर्यादित करने की जो योग्यता प्रदर्शित की, वह लगभग सभी लोगों की धारणा से अधिक थी। ईरान, यूगान, फिलिस्तीन, स्वेज और कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा शान्ति रक्षण के कार्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिए।

अन्त में, शान्ति रक्षा और आर्थिक व सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र सभ एक अन्तर्राष्ट्रीय सभ के रूप में भी काफी प्रभावशाली रहा है, जहाँ लोग अपने भ्रमों से बच सकते हैं। सभ के अलावक दुग कार्य को किसी आर-विवाद समाज का कार्य बटने हैं, किन्तु सभ में होने वाली बटमें अत्यधिक महत्व

पूण हैं, यद्यपि उनमें हमें बहुधा कटुता और घाटम्बर दिखाई देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो प्रश्न आते हैं, वे इतिहास के सबसे पुराने और कठिन प्रश्न हैं, जिन्हें किसी अन्य मंच पर प्रभावकारी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

तो फिर, 1961 के यथार्थ जगत में हम संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं ?

स्पष्टतः, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उमने युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया है, या कि विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच असहमति की खाई को कम किया है। फिर भी, उसके कार्य कई रूपों में आसाधारण रहे हैं।

गभीर स्थानों पर स्वतन्त्र मनुष्यों की अनन्यक शक्तियाँ जिस विशाल वैचारिक संघर्ष में लगी हुई हैं, उसके कारण बड़ी बाधाएँ आने पर भी, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी प्रकार आशा की सशक्त धाराओं के साथ अपने को अधिकाधिक प्रभावकारी रूप में सम्बद्ध करके बढ़ा और विकसित हुआ है।

जहाँ न्याय के महान् प्रश्न उठे हैं, वहाँ संघ ने सारी मानवता के मत की अभिव्यक्ति के लिए मंच का काम किया है।

जहाँ हिंसा का खतरा उत्पन्न हुआ है, वहाँ संघ ने धार-धार धारा को मोड़ने और शान्ति कायम रखने की अपनी बढ़ती हुई क्षमता प्रमाणित की है।

जहाँ लोग गरीबी के अत्याचार से मुक्ति पाने की चेष्टा करते रहे हैं, वहाँ मानवी पीड़ा के विरुद्ध संघर्ष में अनिवार्य सहयोग के लिए उसने नए मार्ग खोले हैं।

हम एक शोर भरे वैचैन और अव्यवस्थित संसार में रहते हैं, जिसमें भय के एक समाज के साथ-साथ आशा का भी एक समाज है। शीत-युद्ध के समानान्तर, एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका के लोगों के साथ संयुक्त राज्य अमरीका की बढ़ती हुई सामेदारी है। यह विकासशील जगत ही संयुक्त राष्ट्र संघ को रूपायित करने में सहायक होता है, और उसके स्वयं भी अधिकाधिक संघ द्वारा रूपायित होने की संभावना है।

एक अन्तिम बात। हम सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बनाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारी पीढी के अन्य किसी भी व्यक्ति से अधिक जो व्यक्ति सहायक हुआ है, उसे श्रद्धाजलि अर्पित किए बिना मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता।

वे जिस संगठन की धारणी और अन्तरात्मा बन गए थे, उसके समक्ष अपने अतिम अतिवेदन में डॉंग हैमरशोल्ड ने यह गम्भीर चेतावनी दी थी।

“संघ के माध्यम से एक ऐसा मार्ग पाने की चेष्टा, जिसके द्वारा विश्व समाज धीरे-धीरे संघ के घोषणापत्र के अन्तर्गत संगठित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का रूप ले सके, या तो आगे बढ़ेगी, या पीछे हटेगी। संघ के कार्यों के प्रति जिनकी प्रतिक्रियाएँ उसके विकास में बाधा डालती हैं, या उसके द्वारा प्रभावी कार्य की संभावनाओं को कम

करती है, उन पर एक ऐसी स्थिति के पुनः उत्पन्न होने की जिम्मेदारी आ सकती है, जिसे पहले ही सरकारों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक खतरनाक पाया था।" डॉंग हैमरसोल्ड में व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ की सामान्य बुद्धि के साथ एक प्रेरणाप्रद आदर्शवाद का मिश्रण था। 1961 का यथार्थ जगत ही था जिससे वे सम्बद्ध थे, और इसी जगत में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सच को अधिकाधिक प्रभावी रूप में कार्य करने के योग्य बनाया।

हम लोग, जो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते कि उनके द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलते रहे। हमें उस दृष्टि को बनाए रखना होगा, जो हमेशा संयुक्त राष्ट्र सच का लक्ष्य रही है। ऐसा करके ही हम संयुक्त राष्ट्र सच को आशा के विश्व-व्यापी समाज का वह उपकरण बना सकते हैं, जो सच के संस्थापक उसे बनाना चाहते थे।

विदेशी मामलों में सुप्रचारित अति दक्षिण-पक्षीय दृष्टिकोण, और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए उसमें निहित खतरों का यह विश्लेषण राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन के समक्ष एक भाषण में किया गया था।
वाशिंगटन, 5 नवम्बर, 1961।

जिस नए विश्व का उदय हो रहा है, वह न केवल उलझा हुआ है, बल्कि विशाल भी है, और हम अमरीकी मनुष्य जाति में केवल एक छोटा-सा अल्पसंख्यक समूह हैं। बुद्धिपूर्ण और साहसपूर्ण नीतियों के द्वारा हम विश्व के मामलों पर सबल प्रभाव डाल सकते हैं, किन्तु हम अब यह समझने लगे हैं कि हम उनका नियन्त्रण नहीं कर सकते। हम में से बहुतों के लिए यह एक नया अनुभव है।

इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि नई समस्याओं और नई शक्तियों से निराशा और परेशानी होने के फलस्वरूप, हमारे कुछ सर्वाधिक समाहत नागरिक छोटे और जल्दी के रास्ते खोजने लगे हैं।

आज अमरीका में कम से कम तीन प्रकार के नए अलगाव-समर्थक विचार हैं, जिनमें यह निराशा परिलक्षित होती है।

प्रथम वे लोग हैं, जो यह मानने लगे हैं कि जल्दी या देर से, युद्ध संभवतः अनिवार्य है। यह सबसे खतरनाक किस्म का पराजयवाद है।

निस्संदेह, हम युद्ध की संभावना से मुंह चूरा कर शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक नियन्त्रित निःशस्त्रीकरण, और क्लानून के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के सम्बन्ध में पूर्ण सहमति नहीं हो जाती, तब तक हमारी सैन्य शक्ति न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से लिए आवश्यक है, वरन् मनुष्य जाति के विशाल बहुमत के लिए भी आवश्यक है, जो कम्युनिस्ट जगत में रहने के कदापि इच्छुक नहीं है।

हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को इस समय सबल बनाने का अर्थ यह नहीं है कि युद्ध अनिवार्य है। इसके विपरीत, यह एक आवश्यक रक्षा-कवच है, जिसके पीछे रचनात्मक शक्तियाँ एक तर्क संगत विश्व समाज की नींव डालने के लिए कार्य कर सकती हैं।

आजकल के अलगाववादी विचारों का दूसरा रूप यह है कि बहुतेरे अमरीकी विदेशों की वही अधिक बढ़ी चुनौती को भूलकर मुट्ठी भर स्थानीय साम्यवादियों की

कार्यवाहियों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखते हैं।

हर बुद्धिपूर्ण व्यक्ति जानता है कि एक विश्व-व्यापी साम्यवादी पड़यंत्र चल रहा है, और दुनिया के लगभग हर राष्ट्रों में, जिनमें अमरीका भी है, सोवियत साम्राज्य के एजेण्ट हैं।

लेकिन आन्तरिक विध्वंस के प्रति अपनी चिन्ता में इस बात का ध्यान रहे कि हम कहीं गलत लक्ष्य पर वार न कर दें। कुछ निराश अमरीकी ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि साम्यवाद का उदय समाजवाद से होता है, समाजवाद का उदारवाद से, और उदारवाद का जन्म उन लोकतांत्रिक विचारों से होता है जिन्हें यॉमस जेफरसन ने हमारे स्वतंत्रता के घोषणापत्र में समाविष्ट किया। यह धारणा सर्वथा असंगत है। साम्यवादी चुनौती का एक मात्र यथार्थनिष्ठ उत्तर यही है कि न केवल अमरीका में, बल्कि दुनिया में हर जगह लोकतंत्र और प्रगतिशीलता कम न होकर अधिक हो। अलगवावादियों का तीसरा और दायद सबसे ज्यादा परेशान समूह उन लोगों का है, जो व्यवहार में ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि, 'दुनिया को रोको, मैं इससे निकलना चाहता हूँ।' अगर उनका बश चलता तो वे दुनिया के मामलों से अलग होकर भविष्य का बोझ दूसरों पर छोड़ देते, यह मानकर कि हम मानवी घटनाओं के प्रवाह से अपने को काटकर अलग कर सकते हैं।

क्या किसी विचारशील व्यक्ति को ऐसी किसी नीति के परिणाम के बारे में कोई सदेह हो सकता है? वास्तव में, प्रथम महायुद्ध के बाद क्या हमने लगभग पूर्णतः यही नीति नहीं अपनाई थी, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए? मुझे बार-बार यह प्रश्न चिन्तित करता है कि क्या हमने पूरी तरह और आतिथी तौर पर सबक सीखा लिया है?

फिर, हम कुछ ईमानदार लेकिन दिग्भ्रमित लोगों की आवाज सुनते हैं, जो यह मानते हैं कि हम इतिहास के परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं, समुक्त राष्ट्र संधि के मामिक महत्त्व की ओर से झूल मूंद सकते हैं, बिना समझे-बूझे अपने मुल्क बढ़ा सकते हैं, विदेशी सहायता बन्द कर सकते हैं, अपने मित्रों का साथ छोड़ सकते हैं, जो राष्ट्र हमें अच्छा न लगे उस पर आक्रमण कर सकते हैं, और किसी प्रकार इन कार्यों के परिणामों से बच सकते हैं।

मैं उनकी ईमानदारी का आदर करता हूँ, और सीधे-सादे उत्तरों के लिए उनकी सच्ची इच्छा को समझता हूँ। लेकिन उनकी बुद्धिहीन सलाह को मान लेने पर जो विपत्ति निश्चय ही आएगी, उनकी अनदिग्ग देशभक्ति और सद्विश्वास क्या उगम रतीं भर भी बनी कर सकेंगी?

विश्व की अप्रभूतपूर्व चुनौती जो आज हमारे सामने है, वह विदेशी सहायता या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, या संयुक्त राष्ट्र संघ की बहनों के उतार-चढ़ाव या हमने अत्यन्त पड़ोसियों के दृष्टिकोण से नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि आज की दुनिया की भूत-पूर्व आतिथीय शक्तियों से उत्पन्न हुई है।

इन सबल शक्तियों का प्रभावकारी रीति से सामना करने के लिए विशाल शक्ति, धीरज और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा बहुतत्ववादी समाज उपकरणों की जो व्यापक विभिन्नता प्रस्तुत कर सकता है, उस सब की आवश्यकता पड़ेगी—कूटनीति का कौशल, निजी सम्बन्धों की गरमाहट, आर्थिक और प्राविधिक सहायता का सहयोगी हाथ, और सैन्य शक्ति का रक्षा-कवच।

फिर भी, एक आवश्यक शर्त के साथ, मुझे विश्वास है कि हम सफलतापूर्वक चुनौती का सामना कर सकते हैं। शर्त सीधे-सादे रूप में यह है—क्या हम संघर्ष की प्रकृति को साफ-साफ समझते हैं? इतिहास की इस निर्णायक घड़ी में, हम अमरीकी लोग वस्तुतः चाहते क्या हैं?

कुछ लोग उत्तर देंगे कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है—अमरीकी जीवन-पद्धति का संरक्षण। लेकिन आज की निकट पारस्परिक सम्बन्धों वाली दुनिया में, क्या यह उत्तर अब भी पर्याप्त है?

एक क्षण के लिए कल्पना करें कि आप विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक युवा भारतीय अध्यापक मोहन चौधरी से बात कर रहे हैं। वह पूछ सकता है “साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम हिन्दुस्तानी लोग अमरीकियों का साथ क्यों दें?”

और मान लीजिए कि आप उत्तर देते हैं, “इसलिए कि अमरीकी जीवन-पद्धति की रक्षा करने में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है।” क्या आप पूर्ण विभ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रतिक्रिया की आशा कर सकते हैं?

बारह हजार मील दूर दुनिया के सबसे धनी लोग आगे भी अपनी धाराम की जिन्दगी बनाए रखें, इसके लिए एक सामान्य भारतीय अध्यापक मोहन चौधरी अपने जीवन को खतरे में डालना क्यों स्वीकार करे?

कुछ अन्य लोग कह सकते हैं कि अमरीका के राष्ट्रीय उद्देश्य को अधिक व्यापक सन्दर्भ में व्यक्त करना चाहिए। वे पूछ सकते हैं, “हमारा सच्चा लक्ष्य क्या यह नहीं है कि हम आर्थिक सहायता और कुशल कूटनीति या प्रयोग अन्य राष्ट्रों को अमरीकी नेतृत्व के पीछे लाने के लिए करें।”

लेकिन क्या हमसे सर्वाधिक स्वार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति भी गंभीरता से यह विश्वास कर सकता है कि सम्पूर्ण राष्ट्रों की निष्ठा को खरीदना संभव है?

अधिकतर मनुष्य जाति को ऐसे तर्क विलकुल खोखले लगते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए संबंधा अनुपयुक्त हैं। फिर, अमरीका के सच्चे उद्देश्य क्या हैं, और हम उन्हें दुनिया के समने ऐसे रूप में किम प्रकार रख सकते हैं कि उन्हें समझा जा सके?

निश्चय ही, वर्तमान चुनौती केवल मनुष्यों की उम विरोधाधिकारयुक्त अल्पसंख्या के लिए नहीं है, जिनकी सर्वाधिक भौतिक हानि होने की आशंका है। यह चुनौती सभी ऐसे मनुष्यों के लिए है जिन्हें स्वतंत्रता से और स्वयं अपने ढंग से अपने भाग्य का निर्माण करने के अधिकार से प्रेम है।

हम फिर कल्पना करें कि हम ब्रह्मपुत्र के किनारे एक गाँव में हैं, और मोहन

चोपरी हमसे फिर यह निर्णायक प्रश्न पूछता है, 'साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम हिन्दुस्तानी लोग अमरीकियों का साथ क्यों दें ?'

और मान लीजिए कि आप उत्तर देते हैं, " भौतिक दृष्टि से आप और हम हजारों मील दूर हैं, लेकिन बुद्ध सायंभौतिक विश्वासों में हम हिस्सेदार हैं, जिनके लिए हमारे पुराने पीढ़ियों तक लड़ें, जिनकी रक्षा करने के लिए हम आज तैयार हैं, और जिनके लिए आपके अपने महान् यात्री ने अपनी जान दी।

" इसलिए हम आपसे और इन विश्वासों में हिस्सेदार अन्य सभी लोगों से कहते हैं—हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें, जिसमें मनुष्य ऐसी तानाशाही के बग़र पास से अपने को मुक्त कर सकें, जो इन मूलभूत मानवी मूल्यों से इन्कार करती है। "

जब हम ऐसे सार्विक शब्दों में बोलना सीख लेंगे, तो सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के करोड़ों लोगों के चेहरे एक नई समझ और नए आत्मविश्वास से चमक उठेंगे।

एक राष्ट्र के रूप में हमारी ऐतिहासिक भूमिका हमेशा स्पष्ट रही है। आज उसे देश और विदेश में फिर से दुहराने का समय है।

सारी मानवता के लिए क्रान्ति

क्या हमारे जैसा अभावहीन, समृद्ध राष्ट्र, विक्रमशील राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण परिवर्तन की एक विश्व-व्यापी क्रान्ति [को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है ? श्री वॉल्स का विश्वास है कि ऐसा हो सकता है—वर्शतक हम स्वयं अपनी क्रान्तिकारी परम्पराओं के प्रति सच्चे रहें। न्यूयार्क टाइम्स मंगलान में प्रकाशित एक लेख से, 10 दिसम्बर, 1961।

क्या हमारे जैसा अभावहीन और सुविधायुक्त राष्ट्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की एक विश्व-व्यापी क्रान्ति में एक नेता और सहयोगी के रूप में भाग ले सकता है ? या कि स्वयं अपनी आशाकांक्षों और कूटनीतियों के फलस्वरूप, उसका यही भाग्य है कि वह यथास्थिति के साथ जुड़ा रहे, जिसका विनाश निश्चित है, या अधिक से अधिक, किनारे पर खड़ा आशका भरी दृष्टि से देखता रहे ?

ये प्रश्न उस चुनौती के केन्द्र में हैं, जो अमरीकी विदेश-नीति के सामने है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में जहाँ भी मैंने यात्रा की हमारी द्विविधा के मर्म में वही बात मिली—क्या हम समझेंगे, क्या हम अपने को आवश्यकतानुसार ढाल सकते हैं, क्या हम प्रभावी रीति से कार्य कर सकते हैं ?

पिछले चार महीनों में, हमारे विदेशस्थित कूटनीतिक कार्यालयों के पुनः संगठन के सिलसिले में, और मलाया में कोलम्बो योजना की वार्षिक बैठक में भाग लेने के फलस्वरूप मैंने यूरोप के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों की यात्रा की। और हर जगह ये प्रश्न बार-बार दुहराये गए—नए अफ्रीकी राष्ट्रों में हमारे राजदूतों द्वारा उठाई गई समस्याओं में, लैटिन अमरीका में हमारे आर्थिक सहायता प्रशासकों के सामने आने वाली कठिनाइयों में, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों में हमारे आलोचकों और शुभचिन्तकों के सन्देशों और आशाओं में।

हम निस्सन्देह एक विश्व क्रान्ति के मध्य खड़े हैं। क्या विशाल समृद्धि और भौतिक सुविधाओं वाला कोई राष्ट्र कभी कमर कस कर ऐसी किसी क्रान्ति में सक्रिय योग देने वाला हिस्सेदार बना है ? मैंने इतिहास को जितना पढ़ा है, उसमें ऐसा कोई राष्ट्र नहीं मिलता।

तब, क्या अमरीका इतिहास का पहला अपवाद बन सकता है ? लगभग निश्चित

रूप में, इस प्रश्न का हमारा उत्तर न केवल भविष्य का रूप निर्धारित करेगा, बरन् माने वाली कई पीढ़ियों के लिए सभ्यता की दिशा भी निर्धारित करेगा।

एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका में करोड़ों लोगों अधीर होकर पुरानी संस्थापित व्यवस्था को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं—जमींदार और किसान की पुरानी अर्थ-व्यवस्था को, मालिक और नौकर की पुरानी समाज-व्यवस्था को, शासक और शासित की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को।

इन सभी विकासशील महाद्वीपों में, सबसे खतरनाक खाई भव भी अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन लोगों के बीच की खाई है। इस पृष्ठभूमि में अमरीकी लोगों की स्थिति सम्पन्नता के सर्वाधिक मुखर अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरण की है। और हमारा काम इस कारण और भी कठिन हो जाता है कि हमारा राष्ट्र मुख्यतः गीरे लोगों का है, जबकि दुनिया के दो तिहाई लोग रंगीन चमड़ी वाले हैं।

विश्व व्यापी क्रान्ति के मार्ग-दर्शन में सहायक होने की बात तो छोड़ें, ऐसा राष्ट्र उस क्रान्ति से जुड़ भी कैसे सकता है? दो मोटरें रखने वाला आदमी, उस आदमी से कैसे बात कर सकता है, जो अपनी पहली साइकिल का सपना देख रहा है? मोटापे से चिन्तित स्त्री, किसी ऐसी स्त्री से क्या कह सकती है जिसके बच्चे भूखे हैं?

यद्यपि हमारी सफलता के मार्ग में बाधाएँ बहुत बड़ी हैं, किन्तु चुनौती का सामना करने में, कुछ बातें हमारे पक्ष में भी हैं। पहली बात हमारी अपनी अमरीकी क्रान्ति-कारी परम्परा है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा जन्म एक सकल्प के साथ हुआ था, पहले तो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने का, और फिर हमारी सारी जनता की अधिकाधिक न्याय और अधिक तथा सामाजिक भ्रवसर उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का।

हमारा क्रान्तिकारी उत्साह हमारे अपने महाद्वीप तक सीमित भी नहीं रहा। प्रारम्भ से ही हमारे संस्थापकों ने अपनी दृष्टि अधिक व्यापक क्षितिज पर रखी थी। जेफरसन ने कहा था, "अमरीकी क्रान्ति सारी मनुष्य जाति के लिए है।" और मनुष्यों की बहुसंख्या, उन्होंने आगे कहा, "का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि कुछ विशेष कृपापात्र लोग ईश्वर के अनुग्रह से उनकी पीठ पर सवारी करें।"

लौकतांत्रिक क्रान्ति सम्बन्धी जेफरसन की दृष्टि, कि उसके लाभ में सभी मनुष्यों को हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे सारे इतिहास में हमारे साथ रही है। एक के बाद एक हमारे राष्ट्रपतियों ने ऐसे प्रेरणादायक शब्द और कार्य कहे और किए हैं, जिन्होंने मनुष्य की आत्माओं को जगाया है।

लिकन ने कहा, "क्रान्ति का अधिकार, एक अधिकतम पवित्र अधिकार है। ऐसा अधिकार जो हम समझते हैं कि विश्व को मुक्त करने का है।" 1817 में विल्सन के चौदह सूत्रों में हर जगह पराधीन लोगों के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया था, और इन प्रस्तावों की जड़ें अमरीकी परम्परा में बहुत गहरी थीं।

फ्रैन्क्लिन डी० रूजवेल्ट की चार स्वतंत्रताओं के साथ भी ऐसा ही था—भाषण

श्रीर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वयं अपनी रीति से ईश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता, अभाव से मुक्ति, श्रीर भय से मुक्ति—श्रीर इनमें से हर एक विशिष्ट रूप में 'दुनिया में हर जगह' के लोगों के लिए थी।

अतः हमारे नैतिक और वैचारिक साधनों में सर्वप्रथम हमारी अपनी क्रान्तिकारी परम्परा का आदर्शवाद है। दूसरा उपकरण उस परम्परा की आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक अन्तर्वस्तु है। एक राष्ट्र के रूप में हमने केवल क्रान्ति को मौखिक श्रद्धांजलि ही नहीं अर्पित की, बरन् हमने क्रान्ति को कानून का रूप दिया। आज की दुनिया के सन्दर्भ में, बहुतेरे आर्थिक और सामाजिक कानून और कार्यक्रम, जिन्हे हम अमरीकी लोग जीवन का सामान्य अंग मानकर चलते हैं, वैचारिक दृष्टि से आमूल परिवर्तन लाने वाले और परिणाम की दृष्टि से क्रान्तिकारी है।

उदाहरण के लिए, एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका के बहुतेरे नेता अभी भी क्रमशः बढ़ते हुए आर्थिक को एक गम्भीर परिवर्तन लाने वाला सिद्धान्त मानते हैं, जबकि हम अमरीकियों ने इसे पचास वर्ष पहले ही स्वीकार कर लिया था। अधिकांश अमरीकियों ने, चाहे वे किसी भी दल में हों, बहुत पहले से ही इस पद्धति को स्वीकार कर लिया है, जिससे न केवल राजस्व की प्राप्ति होती है, बरन् धन का पुनर्विभाजन करके जो अमीर और गरीब के फर्क को बहुत अधिक घटा देती है।

इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक आवास, उपयोगी सेवाओं और परिवहन का नियमन, और काफी भारी निगम कर जैसी धारणाएँ, जो अब हमारी अर्थ-व्यवस्था का सामान्य अंग हैं, दुनिया के बड़े हिस्से में अब भी 'आमूल परिवर्तन' की धारणा से जुड़ी हुई हैं।

एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका में इस समय जो क्रान्तियाँ हो रही हैं, वे जीवन स्तरों को उठाने, राष्ट्रीय सम्पत्ति का वितरण और स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। ये ऐसे लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त करने की चेष्टा हम करते रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं।

आज की विश्व-व्यापी क्रान्ति से हमें सम्बद्ध करने वाला तीसरा मूल तत्व हमारे इस गंभीर विद्वाम से उत्पन्न होता है, कि हर ग्रामीण परिवार को स्वयं अपनी भूमि का मालिक होने का अवसर मिलना चाहिए। और आज तीन महाद्वीपों में उठ रही क्रान्ति की लहर में और कोई तत्व ऐसे भूस्वामित्व के लिए भूमिहीनों और कास्त-कारों की आकांक्षा से अधिक मौलिक नहीं है।

औपनिवेशिक काल से ही, भूस्वामी किसानों, और देशभक्त सेनाओं के सदस्यों के रूप में, हमने दूरगामी प्रभाव डालने वाले कानूनों के द्वारा हर प्रकार की ग्रामीण सामन्तशाही का विरोध किया है। सौ वर्ष पहले हमने अपने विद्वानों को 'होमस्टेड अधिनियम' का रूप दिया, जिसके अनुसार हर ऐसा परिवार जो खेती कर सकता था और करना चाहता था, 160 एकड़ भूमि ले सकता था। बाद में ग्रामीण कर्जों, सहाकारिता, और कृषि-सुधार की एजेंसियों के द्वारा स्वतंत्र भूस्वामित्व की इस

धारणा को हमने सबल बनाया ।

ये तीन बड़े अमरीकी प्रसाधन—हमारी उपनिवेश-विरोधी क्रान्तिकारी परम्परा, आर्थिक और सामाजिक सुधारों का समर्थन, और भूमि के निजी स्वामित्व के प्रति हमारी निष्ठा—आज के क्रान्तिकारी जगत द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कमीटी का सामना करने में हमारी बहुत अधिक सहायता कर सकते हैं ।

लेकिन आज बहुतेरे एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका वासी ऐसा अनुभव करते हैं कि अपनी परम्पराओं से हमारा सम्बन्ध टूट गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि आधुनिक क्रान्तिकारी विश्व के सम्दर्भ में हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करें और उन्हें साफ-साफ परिभाषित करें । विश्व के साथ अपने सम्बन्धों में हम वस्तुतः चाहते क्या हैं ? हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम क्या हैं ? हम दूसरे राष्ट्रों की सद्भावना और समर्थन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ?

इन प्रश्नों पर नागरिकों और मतदाताओं के रूप में हमें नितन्तर विचार करना होगा । ये प्रश्न हैं, जिन पर हमारे नीति-निर्माता और दूतावासों के अधिकारी पिछले कई महीनों से पुनर्विचार करते रहे हैं । कारण, कि विदेशों में हमारी सारी कार्य-वाहियों के मर्म में यही प्रश्न हैं ।

उदाहारण के लिए, हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या केवल साम्यवाद का प्रतिहार करना है ? साम्यवाद हर जगह स्वतंत्र सस्थाओं के लिए एक अबरदस्त चुनौती है, और साम्यवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई, हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध हमारे संघर्ष का एक अंग है ।

किन्तु, मात्र साम्यवाद के विरोध को जेफरसन और लिंकन के राष्ट्र का एकमात्र राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं माना जा सकता । वस्तुतः जब हम अपने सारे कार्यों को किसी राष्ट्र में साम्यवादी खतरे की उपस्थिति या अनुपस्थिति से जोड़ देते हैं, तो हम उस राष्ट्र में साम्यवाद को घुरे-निषेध या मिट्टी के तेल की भाँति एक प्राकृतिक साधन का सा रूप देने लगते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसके बदले में अमरीकी राजकोष से ढाँवर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

या, जैसा हमसे बहुधा कहा जाता है, क्या हमारा उद्देश्य 'लोगों के मन पर अधि-कार करना' है ? विश्लेषण करने पर, यह लक्ष्य भी, व्यावहारिक यथार्थ और हमारे लोकतांत्रिक विश्वास, दोनों ही दृष्टियों से अनुपपुक्त सिद्ध होता है । क्या जेफरसन ने हमारे प्रश्नों को मनुष्यों के मन की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था, और क्या यह लक्ष्य हमारे सारे इतिहास में परिलक्षित नहीं होता ?

अन्त में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक स्वामित्व की मुलना में निजी स्वामित्व की उत्कृष्टता प्रदर्शित करना है । पूँजीवाद ने हमारे अपने देश में आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी वह बड़े कार्य कर सकता है । लेकिन पूँजीवाद की सार्वभौमिक स्वीकृति अमरीका का अन्तिम राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं है । पूँजीवाद लक्ष्य-प्राप्ति का एक साधन है, स्वयं लक्ष्य

नहीं है।

हमारा सच्चा राष्ट्रीय उद्देश्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कहीं अधिक सरल, कहीं अधिक सार्वभौमिक, और कहीं अधिक प्रभावकारी है। यह उद्देश्य है साम्यवादी राष्ट्रों के माथ मिलकर, एक ऐसे विश्व-समाज के निर्माण के प्रति हमारी निष्ठा, जिसमें वरण की स्वतन्त्रता संभव हो, जिसमें लोग अधिकाधिक मात्रा में आर्थिक अवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त करते हुए स्वयं अपनी मर्जी का जीवन बिता सकें, और जिसमें राष्ट्र स्वयं अपनी संस्कृतियों और परम्पराओं के अन्तर्गत स्वयं स्वतन्त्र निर्माण कर सकें।

अपने पक्ष के तत्वों को समझना, और अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना एक बात है। विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा अपनी नई चेतना के अनुरूप कार्य करना विलकुल अलग बात है।

अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को इस क्रान्तिकारी विश्व के लिए बुद्धिपूर्ण और रचनात्मक कार्यक्रमों का रूप देने के तरीके की खोज में जो उत्तर हमारे सामने आए हैं, उन पर पुनर्विचार करना उपयोगी हो सकता है।

सर्व प्रथम, यह बात विलकुल साफ है कि सभी कार्यवाहियों की पूर्व-आवश्यकता के रूप में, अपनी सैन्य शक्ति को कायम रखना हमारे लिए उस समय तक आवश्यक है, जब तक संभाव्य आक्रान्ता शक्तियाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही, हमारी प्रतिरक्षा नीति हमेशा स्पष्ट सयम की रहनी चाहिए, कभी भी उत्तेजित करने की नहीं।

दूसरे, यह बात भी उतनी ही साफ है कि आण्विक हथियारों की बतड़ी हुई होड़ के जबरदस्त खतरे को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभावकारी और सुरक्षा-पूर्ण निःशस्त्रीकरण योजनाओं की तलाश में हमारा धोरण अनन्त होना चाहिए।

तीसरे, हमें अहंकार और निराशा का परित्याग करके, हमेशा के लिए यह निर्णय करने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, वे निश्चय ही हमारे विरुद्ध होंगे।

हम यह न भूलें कि जार्ज वाशिंगटन से लेकर, बुडरो विल्सन तक, यूरोप के 'अनन्त भगड़ों' के प्रति 'तटस्थता', हमारी विदेश नीति का मुख्य अंग थी। कि दुनिया के नए राष्ट्र, जो हाल ही में यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों का जुआ उतार फेंकने में सफल हुए हैं, अपनी तात्कालिक समस्याओं में उन्नी तरह फँसे हुए हैं, जैसे अपने विकास के बँधे ही काल में हम फँसे हुए थे। और यह कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये राष्ट्र आगे भी साम्यवादी चुनौती को पूरी तरह नहीं समझेंगे, जिसकी हमें उचित ही चिन्ता है।

अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को कार्यान्वित करने में चौथा और निष्पक्ष महत्त्व का प्रदान विदेशों में आर्थिक और प्राविधिक सहायता का हमारा कार्यक्रम है।

विदेशों में हमारे सूचना कार्यक्रम पाँचवाँ और अन्तिम तत्व हैं। इन कार्यक्रमों में हमारा वास्तविक रूप प्रस्तुत होना चाहिए—सौभाग्यशाली लेकिन आत्मतुष्ट नहीं;

एक राष्ट्र जो अथ भी शिक्षा, आवास, और जातीय सम्बन्धों की समस्याओं में जूझ रहा है; एक राष्ट्र जो अथ भी अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक समाज की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें उन लक्ष्यों की चर्चा करना चाहिए, जिन्हें प्राप्त करने की हम अथ भी चेष्टा कर रहे हैं, और जिन्हें हम विदेशों में दूसरों के साथ मिलकर प्राप्त करना चाहते हैं।

अपनी सारी शक्तियों और विघ्न सहित, एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका में मानवी स्वतन्त्रता की वर्तमान लहर में मूलतः उन सार्विक लक्ष्यों का गद्य हो चला आ रहा है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने स्वतन्त्रता के घोषणापत्र में स्वयं-निर्दिष्ट घोषित किया था।

अगर हमारी पीढ़ी के अमरीकी अच्छी तरह इन चुनौतियों को समझकर उगका सामना कर सके, तो किसी के भी लिए इस तरह अथ का कारण बहुत कम है कि विकासशील नए राष्ट्र साम्यवादी प्रति क्रान्ति के चाँभवन, कटुता, और झूठे मूल्यों के शिकार हो जाएँगे।

एक नयी कूटनीति की ओर

विदेशी सहायता, शान्ति सेना, शान्ति के लिए भोजन, और विदेशों में अन्य विकास कार्यक्रमों ने मध्य-बीसवीं सदी की कूटनीति के बदले हुए कार्यक्षेत्र को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। 1962 के प्रारम्भ में फरिन एफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में श्री वॉल्स बताते हैं कि इस चुनौती का सामना करने के लिए, नए प्रशासन ने अपने विदेश-स्थित कार्यालयों का संगठन किम प्रकार किया है।

पिछले महायुद्ध के पूर्व, अमरीकी विदेश-नीति के कार्य अपेक्षतया सुनिश्चित थे। विदेश सचिव फॉर्डेल हन के पाम वाशिंगटन में एक हजार से कम कर्मचारी थे, और वे सारी दुनिया में फैले हुए हमारे कूटनीतिक कार्यालयों का संचालन एक ऐसी इमारत से करते थे, जिसमें युद्ध और नौसेना विभागों के दफ्तर भी थे।

विदेश स्थित अठहत्तर राजदूतों का कार्य अधिकांश यही था कि घटनाक्रमों की सूचना दें और उनका विश्लेषण करें, और समझौता-वार्ताओं तथा मनारोहों में राष्ट्र-पति का प्रतिनिधित्व करें।

बीस निर्णायक वर्षों ने इस परम्परागत रूप को नाटकीय रीति से बदल दिया है। विश्व-क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ-साथ, हमारी कूटनीति का कार्य अधिक पेचीदा हो गया, और उसके उपकरण भी तदनुसार बहुगुणित हो गए।

राजदूतों के लिए, इस परिवर्तन के फलस्वरूप, चुपचाप देखने की अपेक्षा सक्रिय रूप में काम करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आय-उपय और प्रशासन की दृष्टि से, इस परिवर्तन के फलस्वरूप विदेशी विभाग में अब 38,000 कर्मचारी हैं, जिनमें वैदेशिक सेवा और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (जिसमें 17,600 कर्मचारी हैं) के सदस्य भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एक शान्ति सेना है, एक 'शान्ति के लिए भोजन' कार्यक्रम है, एक संयुक्त राज्य एजेंसी है, एक केन्द्रीय गुप्त-सूचना एजेंसी है, विभिन्न प्रकार के सैन्य कार्यक्रम हैं, और धर्म, व्यापार, खेती, तथा राजकीय विभागों के फैले हुए विदेश स्थित कार्यक्रम हैं।

इसके अतिरिक्त, अब मौ से अधिक देशों में हमारे कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं और

166 कोमंग कापांग घोर कोमंग-जनरल कापांग इनसे घलग है। इनमें से कई रणानों पर मुख्य अधिकारी के भींच एक मन्त्रि-परिषद् जैसी होती है। उदाहरण के लिए, दूगरा महापुत्र धारम्भ होने के समय, हमारे पेरिम स्थित दूगावात में घटहत्तर स्थित काम करने थे, जिनमें चार अन्य एजेंटियो के कर्मचारी भी थे। अब वही सात सौ स्थित हैं, जिनमें घट्टास्य अन्य एजेंटियो के कर्मचारी भी हैं।

कापांगलाघ घोर एजेंटियो में हुई इस घगाधारण वृद्धि में धाधुनिक विश्व की पेशीदगी घोर परस्पर-निर्भरता ध्यात होती है। इसका यड़ा हिसासा ऐसा है जो सोवियत चुनौती के न होने पर भी मागने घाता। फिर भी, हमारे समाजों के बीच, मानवी विकास के प्रति सोवियत दृष्टिकोण, घोर उदार-लोनतात्रिक दृष्टिकोण के बीच बढ़ती हुई प्रतियोगिता के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, घोर हम यह जानते हैं कि भविष्य में भी, जहाँ तक देला जा सकता है, यह प्रतियोगिता जारी रहेगी।

हमारे नए युग की चुनौती को प्रारम्भ में हमारे शासन की कार्यकारी घोर विधाधिका, दोनों शाखाओं ने मुख्यतः नीति-निर्माण की चुनौती समझा—घोर उनका यह सोचना प्रकारण भी नहीं था। किन्तु प्रभावकारी विदेश नीति का विकास केवल पहला कदम है। हमें उन नीतियों पर धमल करने के लिए प्रभावकारी उपाय भी निकालने होंगे। घोर हमारी नीति के उपकरणों के लिए, देश घोर विदेश में हमारे प्रयत्नों के सगठन, प्रशासन, घोर कापांग्वधन के लिए इस चुनौती को पिछले कुछ दिनी से ही समझा जाने लगा है, घोर तदनुसार कार्य होने लगा है।

चुनौती घोर विकास की इस पृष्ठभूमि में प्रशासन विदेशों में अपने कार्यकलाप को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उन्हें समन्वित करने की चेष्टा करता रहा है। इस चेष्टा के तीन रूप हैं। (1) हमारे राजदूतों में क्या विशेष गुण होने चाहिए, इस प्रश्न पर आलोचनात्मक पुनर्विचार, (2) जिस देश में उसकी नियुक्त होती है, उसमें राजदूत की बहुत अधिक बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का राष्ट्रपति द्वारा स्पष्टीकरण, (3) जहाँ भी हमारे कूटनीतिक या कौन्सल कार्यालय हैं, वहाँ धापने फले हुए क्रिया-कलाप को समन्वित करने का कार्यक्रम।

कूटनीति की बदली हुई आवश्यकताओं ने स्पष्टतः उन गुणों को भी बदल दिया है, जिनका हमारे राजदूतों में होना आवश्यक है। यद्यपि मोहक व्यवितव्य, भावपंक पत्नी, राजनीतिक प्रहसालता, घोर विश्लेषण-क्षमता अब भी अत्यधिक उपयोगी है, किन्तु अब ये गुण पर्याप्त नहीं हैं।

धाधुनिक राजदूत के लिए प्रशासक होना भी आवश्यक है, जो विविध प्रकार के कार्यों की देख-रेख कर सके। उसमें रचनात्मक नेतृत्व का गुण होना चाहिए, जिसमें वह किसी काम में पहल कर सके, अपने अधीनस्थ लोगों को प्रेरणा दे सके, घोर विस्तार की उसझनों में न फँसकर दूसरों को अधिचार सौंप सके। उसे एक कुशल घोर दूररों को प्रभावित कर सकने वाला कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, जो कठोरता घोर समय को मिथित कर सके।

इन परिस्थितियों में, प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा कि चुनाव अभियान में चन्दा देने वाले कुछ धनी व्यक्तियों को राजदूत बनाकर भेजने की पुरानी परम्परा अब नहीं चलाई जा सकती। फलस्वरूप, 1961 में वैदेशिक सेवा के सदस्यों में से नियुक्त किए गए राजदूतों का अनुयात हमारे इतिहास में सबसे अधिक था। इसके अतिरिक्त, वैदेशिक सेवा के ऐसे प्रभावशाली युवा सदस्यों को जल्दी उच्च पदों पर लाने के लिए विशेष प्रयास किया गया, जिनके बारे में समझा गया कि युवा और हाथ ही में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों की विशेष समस्याओं को वे अच्छी तरह समझ कर, आवश्यक तनीलेपन से उनका सामना कर सकेंगे। वैदेशिक सेवा से अलग जो लगभग बीस नए राजदूत नियुक्त किये गए वे लगभग निरपवाद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विदेश-नीति सम्बन्धी व्यापक अनुभव था। उनमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों से और सार्वजनिक संस्थाओं से लिये गए थे। कुछ को छोड़कर, अब सारे ही राजदूत उत देश की राजवाज की भाषा बोल लेते हैं, जिसमें उनकी नियुक्ति होती है।

इसकी भी चेष्टा की गई कि हर राजदूत को ऐसा कार्य सौंपा जाय जिसके बारे में वह स्वयं अनुभव करता हो कि वह उस की भलीभाँति कर सकता है। 'उनके चरित्र को सबल बनाने' के लिए, वैदेशिक सेवा के अधिकारी जहाँ न जाना चाहते हों उन्हें वही भेजने की अग्नि परीक्षा वाली परम्परा छोड़ दी गई। एक पद पर राजदूत और उसके प्रमुख सहयोगियों के सामान्य कार्यकाल की अवधि को बढ़ाकर चार साल कर दिया गया। राजदूत और उसकी पत्नी को एक जोड़ी के रूप में देखा गया। अपने सहायकों और सहयोगियों का चुनाव करने में राजदूत के अधिकार भी बढ़ाये गए।

अधिक उपयुक्त कर्मचारियों का चुनाव पहला आवश्यक कदम था। अगला कदम था राजदूत के अधिकारों का स्पष्टीकरण।

तदनुसार, 29 मई, 1961 को राष्ट्रपति केनेडी ने हर अमरीकी राजदूत को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के निजी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत की भूमिका को पुनः पुष्ट किया, जिसे अपनी नियुक्ति के देश में अमरीकी शासन की सभी कार्य-वाहियों और कर्मचारियों पर निर्वाह अधिकार था। राष्ट्रपति ने लिखा, "मैं आप पर भरोसा करूँगा कि संयुक्त राज्य शासन के सारे ही क्रियाकलाप पर आप नज़र रखेंगे और उसे समन्वित करेंगे।" "संयुक्त राज्य का सम्पूर्ण बूटनीतिक कार्यालय आपके जिम्मे है, और मैं आशा करूँगा कि आप उसके सारे कार्यों की देख-रेख करेंगे।" राष्ट्रपति के पत्र ने जिम्मेदारियों के बँटवारे से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को हमेशा के लिए खतम करने की चेष्टा की। राजदूत को स्पष्टतः राष्ट्रपति के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया।

अमरीकी बूटनीतिक आचरण के आधुनिकीकरण, और उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करने की दिशा में अगला कदम था यह क्षेत्रीय सम्मेलनों का सिलसिला, जिसमें न केवल राजदूतों को बरन् उनकी पत्नियों, उनके प्रशासकीय अधिकारियों, उनके मुख्य सूचना, महायता और सैन्य सलाहकारों को भी निमंत्रित किया गया।

यद्यपि राजदूतों को नए अधिकार प्रदान कर दिये गए थे, किन्तु उनमें से बहूनों को अब भी सन्देह था कि नए आदेश वहाँ तक प्रमल में जाएं जाने वाले थे। इनके प्रतिरिक्त, कार्यपद्धति बहुत-बुद्धि भ्रष्टी, पहले जैसी ही थी, और वाणिज्य के साथ विभिन्न दूतावासी के आदान-प्रदान में बहुतेरे कार्य सम्बन्धी प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। सेना के मुख्य कार्यालय, नए महामता प्रशासन, सूचना एजेंसी, शान्ति सेना, शान्ति के लिए भोजन, केन्द्रीय गुप्त-सूचना एजेंसी, भाष्य-व्यय दूर, और व्यापार तथा श्रम जैसे विभागों के प्रतिनिधियों को राजदूतों और उनके अधिकारियों के साथ कार्य, जिम्मेदारी और सहयोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं की चर्चा करने का अवसर भी नहीं मिला था। इन सम्मेलनों में दस्ता प्रसर मिला। बहुतेरे मामलों में, बहूत दिनों से अनिर्णीत पड़े हुए प्रश्नों पर तत्काल निर्णय ले लिए गए।

इन क्षेत्रीय सम्मेलनों में जो नर्द वाले थे, उनमें राजदूतों की पत्नियों की उपस्थिति भी एक थी। जैसा कि वैदेशिक सेवा का हर अधिकारी जानता है, ऐसी पत्नी जो स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझती हो, और उन्हें क्रियान्वित करने में सहायक होना चाहती हो, किसी भी दूतावास के लिए बहुमूल्य होता है। इसी प्रकार, अगर किसी पत्नी में इन गुणों का अभाव हो, तो उससे बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। अच्छी या बुरी जैसी भी हो, राजदूत की पत्नी ही भोजों और सरकारी समारोहों में दासता के उच्चतम अधिकारियों के साथ बैठती है।

हर सम्मेलन में, केवल कुछ विशिष्ट बैठकों को छोड़कर, पत्नियों अपने पतियों के साथ रही, ताकि उनकी जानकारी और समझ बढ़े।

इन सम्मेलनों में अकेले विदेश विभाग में ही प्रशासकीय सुधारों के लगभग दो सौ प्रस्ताव सामने आए, जिनमें से आधे से अधिक पर प्रमल भी हो चुका है। इन प्रस्तावों में छोटी सरकारी मोटरें रखने की वाछनीयता से लेकर कार्यालय बर्तमानियों और अफसरों के लिए अधिक सघन भाषा प्रशिक्षण तक के सुझाव शामिल थे। दफ्तरी कार्यवाहियों में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए, वाणिज्य और विदेशस्थित कार्यालयों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में लगने वाले समय को घटाने के लिए, और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के कार्यों को समन्वित करने के लिए बहुतेरे रचनात्मक सुझाव सामने आए।

यह स्वीकार करना ही होगा कि पूर्ण कूटनीति के इस युग में जिन उपकरणों के द्वारा अमरीकी कूटनीति को प्रभावी बनाया जा सकता है, उनके आवश्यक पुनर्निर्माण और सुगठन की दिशा में अभी केवल शुरुआत ही हुई है। अमरीकी लोगों को, और कुछ अधिकारियों को भी, यह समझाने के लिए अधिक सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता होगी, कि लगभग हर काम जो हम करते हैं, चाहे उसका सम्बन्ध श्रम, नागरिक अधिकार, अतिरिक्त भोजन-सामग्री, व्यापार, विज्ञान, या पर्यटन, किसी से भी हो। अब किसी अंश तक उसका सम्बन्ध हमारी विदेश-नीति से होता है। अपने वैदेशिक

कार्यकलाप के इन बहुतेरे पक्षों के परस्पर सम्बन्ध को एक बार समझ लेने पर, समस्या यह सीखने की होती है कि उनका प्रशासन किस प्रकार अधिकाधिक कौशल से और प्रभावी रीति से किया जाय ।

इस प्रसंग में यह हमारा सौभाग्य है कि इस समय राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दृष्टि जागतिक है, जो वैदेशिक मामलों को और एक सुगठित विदेश-नीति को क्रियान्वित करने में अपने विभागों की भूमिका को समझते हैं । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजदूतों के नेतृत्व में अपने विदेश स्थित कार्यालयों के क्रियाकलापों को समन्वित करने में जो प्रगति हमने की है, उसे वार्शिंगटन में विदेश-नीति के वैसे ही बेहतर नियन्त्रण और समन्वय के द्वारा पुष्ट करना आवश्यक है ।

विदेश विभाग के क्षेत्रीय सहायक सचिव इस समन्वय के स्वाभाविक केन्द्र हैं । इन अधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि करके हम उन्हें उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्रों में अपने सारे विविध प्रकार के कार्यों में वास्तविक समन्वय लाने का काम सौंप सकते हैं । यह उन बहुतेरे आवश्यक नए सुझावों में से एक है, जिनका विरोध होने की संभावना है ।

किन्तु जो काम हमारे सामने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए नए दृष्टिकोण, अधिक कल्पनाशील पद्धतियाँ, और कठोरमना प्रशासन आवश्यक हैं, अन्यथा हमारी विदेश-नीति के उपकरण उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में पिछड़ जाएंगे । यद्यपि शुरुआत अच्छी हुई है, किन्तु अभी बहुत-कुछ करना बाक़ी है ।

दूसरा भाग

आर्थिक सहायता के रूप

हमारे सहायता कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य स्पष्ट, तात्कालिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण है—स्वतंत्र विद्व के राष्ट्रों में स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विकास, ताकि वे अमरीका के नहीं, वरन् अपने हित साधन के लिए जीवित रह सकें।

जैसे-जैसे वे अपनी जनता की ज़रूरतें पूरी करने में सफल होंगे, लोकतांत्रिक पद्धतियों में उनका विश्वास बढ़ेगा, और उसके साथ ही, अन्दर या बाहर के सभी शत्रुओं के विरुद्ध अपनी उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए उनकी दृढता भी बढ़ेगी।

ऐसे राष्ट्रों के साथ अमरीका एक स्वतंत्र और गतिशील सम्बन्धों का निर्माण कर सकता है, जो आने वाले वर्षों में साम्यवादी आक्रमण के खतरे को कम करेगी और धीरे-धीरे शान्ति की नींव रखेगी।

दिसम्बर, 1954

भूखी दुनिया में अमरीकी भोजन

युद्ध-काल में अमरीका की खेतिहर उत्पादन सम्बन्धी आश्चर्यजनक सफलताओं ने श्री वॉलस को प्रेरित किया कि वे भूख को खतम करने के लिए एक विश्व-व्यापी खेतिहर क्रान्ति में अमरीकी नेतृत्व का सुझाव दें। सुपरमार्केट इन्स्टीट्यूट के ग्यारहवें वार्षिक सम्मेलन में दिया गया भाषण, 25 मई, 1947।

सुदूर भविष्य तक, न केवल स्वयं अपने लोगों के लिए, वरन् सारी दुनिया में करोड़ों भूखे लोगों के लिए भोजन के उत्पादन, और वितरण में अमरीका को बहुत बड़ा काम करना है।

1939 में दुनिया के तीन चौथाई लोग भोजन पैदा करने, तैयार करने, और वितरित करने में लगे हुए थे। फिर भी, जिसे हम युद्ध-पूर्व की सामान्य स्थिति कहा करते थे, उसमें मनुष्य जाति के दो तिहाई हिस्से को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था।

हमसे से कोई भी, भूखे असुरक्षित लोगों की बस्ती में धनी और विशेषशाधिकार-युक्त व्यक्ति बनकर रहना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन ठीक ऐसी ही स्थिति आज हम अमरीकियों के सामने है। व्यवहार में, हमने दुनिया की गंदी बस्ती के बीच 'संयुक्त राज्य अमरीका' नाम का एक ऐश्वर्यपूर्ण महल सजा कर लिया है।

जब तक विश्व समाज के अन्य सदस्य ज्यादा अच्युत जिन्दगी बिताने के काविल नहीं होते, तब तक हमारे और हमारे बच्चों के लिए कोई शान्ति और सुरक्षा नहीं हो सकती। और भोजन उस बेहतर जिन्दगी का आधार है।

यद्यपि भोजन का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में जीवन स्तरों को ऊँचा उठाने की प्रक्रिया को सिद्धान्त रूप में निरूपित करना आसान है, किन्तु उस पर अमल करना बड़ा ही दुरूह कार्य होगा। भोजन के उत्पादन के सम्बन्ध में यहाँ अमरीका में पिछले 150 वर्षों में हमने जो कुछ किया है, उसी से मकेत मिलता है कि अगली पीढ़ी के अन्दर हमें किस सक्षम की उपलब्धि में सहायता करनी होगी।

अमरीका में 1795 में 90 प्रतिशत लोग अपना भोजन स्वयं पैदा करते थे, और इतना काफी प्रतिरिक्त भोजन जो उन शेष 10 प्रतिशत लोगों के लिए पर्याप्त हो, जो खेतों से सम्बद्ध नहीं थे।

भूखी दुनिया में अमरीकी भोजन

युद्ध-काल में अमरीका की सेतिहर उत्पादन सम्बन्धी आश्चर्यजनक सफलताओं ने श्री वील्स को प्रेरित किया कि वे भूख को खतम करने के लिए एक विश्व-व्यापी सेतिहर क्रान्ति में अमरीकी नेतृत्व का सुझाव दें। सुपरमार्केट इन्स्टीट्यूट के ग्यारहवें वार्षिक सम्मेलन में दिया गया भाषण, 25 मई, 1947।

सुदूर भविष्य तक, न केवल स्वयं अपने लोगों के लिए, बल्कि सारी दुनिया में करोड़ों भूखे लोगों के लिए भोजन के उत्पादन, और वितरण में अमरीका को बहुत बड़ा काम करना है।

1939 में दुनिया के तीन चौथाई लोग भोजन पैदा करने, तैयार करने, और वितरित करने में लगे हुए थे। फिर भी, जिसे हम युद्ध-पूर्व की सामान्य स्थिति कहा करते थे, उसमें मनुष्य जाति के दो तिहाई हिस्से को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था।

हमसे कोई भी, भूखे असुरक्षित लोगों की बस्ती में घनी और विशेषाधिकार-युक्त व्यक्ति बनकर रहना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन ठीक ऐसी ही स्थिति आज हम अमरीकियों के सामने है। व्यवहार में, हमने दुनिया की गंदी बस्ती के बीच 'संयुक्त राज्य अमरीका' नाम का एक ऐश्वर्यपूर्ण महल खड़ा कर लिया है।

जब तक विश्व समाज के अन्य सदस्य ज्यादा अच्छी जिन्दगी बिताने के काबिल नहीं होते, तब तक हमारे और हमारे बच्चों के लिए कोई शान्ति और सुरक्षा नहीं हो सकती। और भोजन उस बेहतर जिन्दगी का आधार है।

यद्यपि भोजन का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में जीवन स्तरों को ऊँचा उठाने की प्रक्रिया को सिद्धान्त रूप में निरूपित करना आसान है, किन्तु उस पर अमल करना बड़ा ही दुर्लभ कार्य होगा। भोजन के उत्पादन के सम्बन्ध में यहाँ अमरीका में पिछले 150 वर्षों में हमने जो कुछ किया है, उसी से मकेत मिलता है कि अगली पीढ़ी के अन्दर हमें किस लक्ष्य की उपलब्धि में सहायता करनी होगी।

अमरीका में 1795 में 90 प्रतिशत लोग अपना भोजन स्वयं पैदा करते थे, और इतना काफी अतिरिक्त भोजन जो उन शेष 10 प्रतिशत लोगों के लिए पर्याप्त हो, जो खेतों से सम्बद्ध नहीं थे।

भारत अमरीका में, प्राधुनिक औद्योगिक और गरीबी की गुफरी हुई पट्टियों के पतन-स्वरूप, लगभग 20 प्रतिशत लोग न बिकने भोजन के लिए भोजन पंजा करते हैं, बल्कि नगरी और कस्बों में रहने वाले लोग अमीरी प्रतिशत लोगों के लिए भी, और जारी बड़ी मात्रा उनके बाद निर्धारित के लिए बच जानी है।

बहुत कुछ इसी परिवर्तन के पतनस्वरूप सामान्य बुद्धिमान अमरीकी हमारे बड़े-बड़े विद्यालय उत्पादन वाले उद्योगों के निर्माण के लिए उपलब्ध हो गये, और हमारे जीवन-स्तर दुनिया के सबसे ऊँचे स्तरों पर उठ सके।

अब हमारे लिए आवश्यक है कि अमरीका और अष्टमहासागर रीति में हम दूसरों की सहायता करें ताकि गरीबी दुनिया में पैदा हो विकास हो। हमें ऐसे सामान प्राप्त करने होंगे जिनसे दुनिया में उपलब्ध भोजन की मात्रा जारी बड़ाई जा सके। कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि उसे एक पीढ़ी के अन्दर दुगुना करना आवश्यक है। इस बीच हमारी अपनी 'बचनों' के द्वारा अमीरी की पूर्ति करने में सहायता करनी होगी।

दुनिया की गरीबी में अत्यन्त अग्रगण्य करने की जरूरत होगी। एशिया, दक्षिण अमरीका और अफ्रीका की महान् नदियों के लिए टेनेसी पाटी अधिस्तरण के समूहों पर नदी पाटी विकास कार्यक्रमों के व्यापक नियोजन की आवश्यकता होगी।

हमें ऐसी के प्राधुनिक औद्योगिक की उत्पादन-शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। विद्यालय शिक्षा योजनाओं और बड़े-बड़े नए उद्योगों की जरूरत होगी।

सबसे अधिक, कई देशों में हमें भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रोत्साहित करना होगा, ताकि बँटकर खाने वाले भूस्वामियों के बजाए, जमीन को जोतने वाले ही उनके मालिक हों।

इसके लिए व्यापक और कल्याणशील नियोजन की आवश्यकता होगी। पुरानी ग्रामीण निषिद्धियों, पूर्वाग्रहों, और परम्पराओं को तोड़ना होगा। उनके लिए जरूरी होगा कि समुक्त राष्ट्र सभ की अधिक सफल बनाया जाय, और सभी राष्ट्र—हमारा-राष्ट्र भी—प्रत्यक्ष, एक तरफा कार्यवाही करने के बजाय समुक्त राष्ट्र सभ के माध्यम से काम करें। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

समुक्त राष्ट्र सभ के भोजन और ऐसी समूहों में, महासभा में, और आर्थिक तथा सुरक्षा परिषदों में, हम अमरीकीयों को पहल करनी चाहिए।

सारी दुनिया में ऐसी के पुनःसंगठन के ऐसे कार्यक्रमों में जो साहसपूर्वक बनाये जाएँ और सशक्त रीति से अमल में लाये जाएँ, हमें अपने सर्वोत्तम कौशल और साधनों के उपयोग के लिए असीमित प्रेरणा और अवसर मिलेंगे। मानवी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार की नीति सही है। हमारी अपनी अर्थनीति और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह नीति सही है।

जब तक विश्व-शांति अक्षय्य रहती है, तब तक हम न केवल सावधान रहें, बल्कि पूरी तरह तैयार रहें। लेकिन हम इस बात को कभी न भूलें कि भविष्य को

रॉकेटों, टैंकों और दूरमारक बमवारों से नहीं जीता जा सकता ।

अगर सभ्यता को सार्यक होना है, तो लोकतंत्रवादी लोगों को उसकी रक्षा करनी होगी और सबल बनाना होगा—ऐसे लोगों को, जिनके विचार गतिशील हों और जिनमें उन विचारों को अमल में लाने का कौशल और साहस हो । सारी मनुष्य जाति का भविष्य उस चुनौती को स्वीकार करने में हमारी तत्परता पर निर्भर हो सकता है, जो भूखा और अव्यवस्थित विश्व हमारे सामने रखता है ।

भाज अमरीका में, आधुनिक औजारों और मशीनों की सुधारी हुई पद्धतियों के फल-स्वरूप, लगभग 20 प्रतिशत लोग न सिर्फ खाने लिए भोजन पैदा करते हैं, बल्कि नगरीय और कस्बों में रहने वाले लोग असी प्रतिशत लोगों के लिए भी, और काफी बड़ी मात्रा उसके बाद निर्यात के लिए बन जाती है।

बहुत कुछ इसी परिवर्तन के फलस्वरूप साधो कुशल समंभारी हमारे बड़े-बड़े विशाल उत्पादन वाले उद्योगों के निर्माण के लिए उपलब्ध हो गये, और हमारे जीवन-स्तर दुनिया के सबसे ऊँचे स्तरों तक उठ सके।

अब हमारे लिए आवश्यक है कि अमनाप्य और कष्टगाप्य रीति से हम दूसरों की सहायता करें ताकि सारी दुनिया में ऐगा ही विकास हो। हम ऐगे साधन प्राप्त करने होंगे जिनसे दुनिया में उपलब्ध भोजन की मात्रा काफी बड़ाई जा सके। कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि उसे एक पीढ़ी के अन्दर दुगुना करना आवश्यक है। इस बीच हमारी अपनी 'बचतों' के द्वारा कमी की पूर्ति करने में सहायता करनी होगी।

दुनिया की मशीनों में सचमुच क्रान्ति करने की जरूरत होगी। एशिया, दक्षिण अमरीका और अफ्रीका की महान् नदियों के लिए टेनेसी घाटी अधिकरण के नमूने पर नदी घाटी विकास कार्यक्रमों के व्यापक निमोजन की आवश्यकता होगी।

हमें खेती के आधुनिक औजारों की उत्पादन-शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। विशाल मिचाई योजनाओं और बड़े-बड़े नए उर्वरक कारखानों की जरूरत होगी।

सबसे अधिक, कई देशों में हमें भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि बँटकर खाने वाले भूस्वामियों के बजाए, जमीन को जोतने वाले ही उसके मालिक हों।

इसके लिए व्यापक और कल्पनाशील नियोजन की आवश्यकता होगी। पुरानी ग्रामीण निपिद्धियों, पूर्वाग्रहों, और परम्पराओं को तोड़ना होगा। उसके लिए जरूरी होगा कि समुक्त राष्ट्र सघ को अधिक सबल बनाया जाय, और सभी राष्ट्र—हमारा-राष्ट्र भी—प्रत्यक्ष, एक तरफा कार्यवाही करने के बजाय समुक्त राष्ट्र सघ के माध्यम से काम करें। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

समुक्त राष्ट्र सघ के भोजन और खेती सगठन में, महासभा में, और आर्थिक तथा सुरक्षा परिषदों में, हम अमरीकियों को पहल करनी चाहिए।

सारी दुनिया में खेती के पुनःसगठन के ऐसे कार्यक्रमों में जो साहसपूर्वक बनाये जाएँ और सशक्त रीति से अमल में लाये जाएँ, हमें अपने सर्वोत्तम कौशल और साधनों के उपयोग के लिए असीमित प्रेरणा और अवसर मिलेंगे। मानवी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार की नीति सही है। हमारी अपनी अर्थनीति और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह नीति सही है।

जब तक विश्व-शान्ति अरक्षित रहती है, तब तक हम न केवल सावधान रहें, बल्कि पूरी तरह तैयार रहे। लेकिन हम इस बात को कभी न भूलें कि भविष्य को

पेरिस के निकट एक औद्योगिक वस्ती में एक कमरे की एक झोंपड़ी में, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, ग्यारह साल की एक लड़की अपने से द्योटे तीन बच्चों के साथ-साथ अपने पिता की भी देखभाल कर रही थी जिसकी टांगे काट दी गई थी, और जिसे नकली टांगों के लिए अभी कई सप्ताह और प्रतीक्षा करनी थी।

उसकी माँ परिवार को जीवित और एक साथ रखने के लिए पर्याप्त धन कमाने की चेष्टा में पचास रुपए प्रति सप्ताह वेतन का एक काम कर रही थी। झोंपड़ी साफ-सुथरी थी, और बच्चे भी। और सबसे अधिक अचरज की बात थी कि ग्यारह साल की वह बच्ची गा रही थी।

वार्सा में वम से ध्वस्त एक मकान के तहखाने के दस फुट चौड़े चौदह फुट लम्बे कोने में मार्शी परिवार के बच्चे हुए सदस्य रहते थे—सात वर्ष का एक लड़का उसकी दस वर्षीय बहन और उनकी दादी। पिता, माँ, एक गोद का बच्चा, और एक लड़की जो अब पन्द्रह साल की होती, 1944 में हुए वार्सा विद्रोह में मारे गए थे।

दादी ने बच्चों को सड़कों पर भटकते हुए पाया, और उन्हें तहखाने में अपने घर ले आई। उन्हें पालने के लिए, वह हाथ से मलवा हटाकर कुछ पैसे प्रति घंटा कमाती है। इसके अलावा, कल्याण विभाग की ओर से उसे लगभग दस रुपए प्रति मास मिलते हैं। बच्चे वारी-वारी से स्कूल जाते हैं, क्योंकि कपड़े इतने नहीं हैं जो दोनों के लिए काफी हों।

वे कुछ उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें सरकार की ओर से चिकनाई लगी हुई रोटी मिलती है, और साथ में संयुक्त राष्ट्र वाल निधि की ओर से कुछ दूध।

जिन देशों में मैं गया, उनमें लाखों बच्चे ऐसी ही हालत में हैं। लेकिन मुझे केवल तकलीफ भूख और गन्दगी ही याद नहीं रहेगी। वार्सा और बुडास्पेट के अनाथालयों में बच्चियों के बालों में सफाई से बांधे गए फ्रीटे इटली और जेकोस्लोवाकिया में किसानों के झोंपड़ों में सजावट करने की कोशिशें, पोलैण्ड के ध्वस्त स्कूलों में प्रसन्न शिशुओं के समूह, स्विट्जरलैण्ड से प्राप्त अस्पतालों के नए सामान के लिए हंगरी और फ्रांस के डाक्टरों की कृतज्ञता भी मुझे याद रहेगी। और साथ ही, सभी देशों में शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों और डाक्टरों की शान्त, निरुद्विग्न, उत्फुल्ल हड़ता, जो युद्धकाल में उत्पन्न एक नयी पीढ़ी की समस्याओं का अल्प साधनों से मुकाबला कर रहे हैं।

यूरोप और एशिया के बच्चे, हमारी पीढ़ी द्वारा उत्पन्न कष्टों की दुनिया में रह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके पिताओं की पीढ़ी ने जिस दुनिया को नष्ट करने में योग दिया था, उससे कहीं ज्यादा अच्छी दुनिया का निर्माण करने का अवसर उन्हें मिले।

आशाहीन बच्चों के लिए नई आशा

बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्रों की अपील के अग्र्यत्त के रूप में युद्ध से ध्वस्त यूरोप की यात्रा करने के बाद श्री बील्म यूरोप की 'नई पीढी' के लिए सहायता और भोजन की अपील करते हैं। न्यूपाक टाइम्स मंगलीन में प्रकाशित एक लेख से, 1 फ़रवरी, 1958।

मैं यूरोप की पांच सप्ताह की सघन यात्रा से अभी-अभी वापस आया हूँ। संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रधान सचिव ट्राइवे ली ने मुझे वहाँ भेजा था कि बच्चों पर युद्ध के प्रभाव का अध्ययन करूँ, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करूँ।

अधिकांश अमरीकियों की भांति, यूरोप में युद्धोत्तर कालीन पुनर्निर्माण की विद्याल कठिनाइयों की जानकारी मुझे भी थी, कि यूरोपीय लोग स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हैं, और विदेशों से उन्हें क्या सहायता मिल रही है।

लेकिन मैंने ऐसी बहुतेरी चीजें देखी, जिनके लिए मैं बिलकुल भी तैयार नहीं था—वार्सा का ध्वस, लिटाइस में मारे गए लोगों के सम्बन्ध में जेक लोगों की कटुता, फ्रांस और हंगरी के बच्चों में क्षयरोग का व्यापक प्रसार, अग्रजों का मौन धीरज।

सबसे अधिक प्रभाव मुझ पर उस साहस और तीव्रता का पडा, जिसके साथ सब लोग अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और उस कड़ी मेहनत का, जो पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे सभी कर रहे हैं, यद्यपि उनमें से बहुतेरे पर्याप्त पौष्टिक भोजन के अभाव में दुर्बल हो गए हैं।

बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्रों की अपील का उन्होंने जो स्वागत किया है, वह भी उतना ही प्रेरणाप्रद है—ऐसे देशों में भी, जिनकी स्वयं भयकर क्षति हुई है। यूरोप के लोगों के लिए इस अपील का अर्थ केवल भोजन ही नहीं है। इसका अर्थ है स्थायी शान्ति की आशा और एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष सहयोग का अवसर। इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ वे अपनी सरकारों से आगे हैं।

इस सक्षिप्त यात्रा में कुछ प्रभाव जो मेरे मन पर अंकित हो गए हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द और सख्याएँ पर्याप्त नहीं हैं। मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर दूँ जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता।

पेरिस के निकट एक औद्योगिक बस्ती में एक कमरे की एक झोंपड़ी में, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, ग्यारह साल की एक लड़की अपने से छोटे तीन बच्चों के साथ-साथ अपने पिता की भी देखभाल कर रही थी जिसकी टांगे काट दी गई थीं, और जिसे नकली टांगों के लिए अभी कई सप्ताह और प्रतीक्षा करनी थी।

उसकी मां परिवार को जीवित और एक साथ रखने के लिए पर्याप्त धन कमाने की चेष्टा में पचास रुपए प्रति सप्ताह वेतन का एक काम कर रही थी। झोंपड़ी साफ-सुथरी थी, और बच्चे भी। और सबसे अधिक अचरज की बात थी कि ग्यारह साल की वह बच्ची गा रही थी।

वार्सा में बम से ध्वस्त एक मकान के तहखाने के दस फुट चौड़े चौदह फुट लम्बे कोने में मार्शी परिवार के बच्चे हुए सदस्य रहते थे—सात वर्ष का एक लड़का उसकी दस वर्षीय बहन और उनकी दादी। पिता, मां, एक गोद का बच्चा, और एक लड़की जो अब पन्द्रह साल की होती, 1944 में हुए वार्सा विद्रोह में मारे गए थे।

दादी ने बच्चों को सड़कों पर भटकते हुए पाया, और उन्हें तहखाने में अपने घर ले आई। उन्हें पालने के लिए, वह हाथ से मलवा हटाकर कुछ पैसे प्रति घंटा कमाती है। इसके अलावा, कल्याण विभाग की ओर से उसे लगभग दस रुपए प्रति मास मिलते हैं। बच्चे धारी-धारी से स्कूल जाते हैं, क्योंकि कपड़े इतने नहीं हैं जो दोनों के लिए काफी हों।

वे कुछ उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें सरकार की ओर से चिकनाई लगी हुई रोटी मिलती है, और साथ में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि की ओर से कुछ दूध।

जिन देशों में मैं गया, उनमें लाखों बच्चे ऐसी ही हालत में हैं। लेकिन मुझे केवल तकलीफ भूख और गन्दगी ही याद नहीं रहेगी। वार्सा और बुडापेस्ट के अनायालयों में बच्चियों के बालों में सफाई से बांधे गए फ्रीते इटली और जेकोस्लोवाकिया में किसानों के झोपड़ों में सजावट करने की कोशिशें, पोलैण्ड के ध्वस्त स्कूलों में प्रसन्न शिशुओं के समूह, स्विट्जरलैण्ड से प्राप्त अस्पतालों के नए सामान के लिए हंगरी और फ्रांस के डाक्टरों की कृतज्ञता भी मुझे याद रहेगी। और साथ ही, सभी देशों में शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों और डाक्टरों की शान्त, निरुद्विग्न, उत्फुल्ल दृढ़ता, जो युद्धकाल में उत्पन्न एक नयी पीढ़ी की समस्याओं का अल्प साधनों से मुकाबला कर रहे हैं।

यूरोप और एशिया के बच्चे, हमारी पीढ़ी द्वारा उत्पन्न कष्टों की दुनिया में रह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके पिताओं की पीढ़ी ने जिस दुनिया को नष्ट करने में योग दिया था, उससे कहीं ज्यादा अच्छी दुनिया का निर्माण करने का अवसर उन्हें मिले।

चतुःसूत्री कार्यक्रम से एशिया में एक क्रान्ति का आरम्भ

1951-52 में अमरीका के प्राविधिक और आर्थिक सहायता के नए चतुःसूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारत ने सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके लिए सभ्यता वार्त्ता राजदूत यौल्स ने की थी। यहाँ श्री यौल्स कार्यक्रम की संभावनाओं पर विचार करते हैं। न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन, 16 नवम्बर, 1952।

एशिया में कोई भी व्यक्ति जो चतुःसूत्री कार्यक्रम पर धमल होते देखता है, उसके ध्यान में शीघ्र ही एक चुनौती भरा तथ्य आता है। चतुःसूत्री सहायता केवल एक साहसपूर्ण और नया कार्यक्रम ही नहीं है। अपनी सभावनाओं में, यह एक क्रान्तिकारी विचार है।

अगर हम इसको समझें और इसका पोषण करें तो इतिहास में चतुःसूत्री कार्यक्रम हमारी पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण विचार बन जा सकता है—ऐसा प्रतिक्रान्तिकारी आन्दोलन जिसका सामना करने में विश्व साम्यवाद समर्थ न हो।

अर्नोल्ड टायनबी ने हाल ही में कहा कि हमारा युग 'अपने भयंकर अपराधों या अपने आश्चर्यजनक आविष्कारों के लिए नहीं' याद रिया जाएगा बल्कि इस कारण याद किया जाएगा कि 'इतिहास में यह पहला युग है, जब मनुष्य-जाति ने इस विश्वास को व्यावहारिक मानने का साहस किया है, कि सम्यता के लाभ सारी मानव-जाति को उपलब्ध हो सकते हैं।'

अधिकार विचारशील लोग, जिन्होंने एशिया में रहकर काम किया है, उनसे सहमत होंगे। यहाँ लम्बे अरसे से दबे हुए करोड़ों व्यक्तियों के लिए इस नए उभरते हुए विश्वास का गभीर क्रान्तिकारी महत्त्व है, कि ज्यादा अच्छी ज़िन्दगी हासिल करना किसी तरह संभव है। यही वह हलचल है, और वह चालक शक्ति है, जो एशिया का रूप बदल रही है, और आने वाले वर्षों में और भी अधिक बदल सकती है।

एशिया की प्रभावी, प्रगतिशील सरकारों के सहयोग से, चतुःसूत्री कार्यक्रम इन करोड़ों व्यक्तियों को ज्यादा अच्छी ज़िन्दगी की आशा, और उसे प्राप्त करने का उत्साह और उपकरण प्रदान कर सकता है। यह उनकी शक्तियों को विस्फोटक निराशा के मार्ग से हटाकर, विकास के ठोस अवसरों की दिशा में लगा सकता है—

ज्यादा अच्छी फ़सलें, अधिक स्कूल, साक्षरता, नलकूप, ज्यादा अच्छे हल, अधिक स्वस्थ बच्चे, और चैचक तथा मलेरिया से राहत ।

दूसरे शब्दों में, चतुःसूत्री कार्यक्रम में अगर पर्याप्त धन लगाया जाय, और बुद्धिमत्ता पूर्वक अगर उसे चलाया जाय तो वह गरीबी, भूख, रोग और अज्ञान के विरुद्ध एक गतिशील, रक्तहीन, अ-साम्यवादी क्रान्ति में सहायक हो सकता है । कोई आश्चर्य नहीं कि साम्यवादी आन्दोलनकर्ता इस कार्यक्रम की तीव्र भर्त्सना करते हैं, क्योंकि हममें से बहुतेरे लोगो की अपेक्षा वे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य-जाति की समस्याओं के प्रति इस यथार्थवादी, हल-बैल से जुड़े हुए दृष्टिकोण की संभावनाएँ लगभग असीमित हैं ।

चतुःसूत्री कार्यक्रम एक जबरदस्त चुनौती है । यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है ।

हमें समझना चाहिए कि इस गतिशील विचार को अपने साथ काम करने वाली स्थानीय शक्तियों के साथ और मनुष्य की बेहदरी की उस जागरण धारा की साथ किस प्रकार मिलना होगा, जो अर्द्ध-विकसित कहे जाने वाले क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों को तेजी से जगा रही है ।

कई बातें हैं, जिन्हें दुहराना उचित होगा ।

प्रथम, चतुःसूत्री कार्यक्रम कोई बना-बनाया इलाज नहीं है, जिसे तैयार माल की तरह इन सुरक्षा के साथ भेजा जा सके कि इससे अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक रोग दूर हो जाएंगे । चतुःसूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य सीधे-सादे शब्दों में ये हैं—आधुनिक औजारों और प्राविधिक सहायता के लोकतांत्रिक उपयोग के द्वारा गरीबी, रोग और अज्ञान पर विजय पाना ।

इन व्यापक नदियों को हर देश के विशिष्ट सन्दर्भ में अलग-अलग निरूपित करना होगा । और विशिष्ट कार्यक्रम को सम्बन्धित देश की अर्थ-व्यवस्था, उसके रीति-रिवाज उनकी संस्कृति और उसके शासन के अन्तरूप बनाना होगा ।

दूसरे, चतुःसूत्री कार्यक्रम कोई दान-खाता नहीं है, बरन् अपनी सहायता आप करने के सामाजिक कार्य सम्बन्धी आधुनिकतम सिद्धान्त पर आधारित, मनुष्य की जिन्दगी को बेहतर बनाने का एक ढंग है । यह ढंग, कभी-कभी धीमा और निराशाजनक होने पर भी, एकमात्र स्थायी ढंग है ।

अगर लोग स्वयं भाग नहीं लेते, अगर वे यह नहीं देखते कि वे स्वयं अपने प्रयत्नों से, धन और सामान की थोड़ी-सी बाहरी मदद पाकर, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, तो कबो तौर पर हुए लाभो की जड़ें नहीं जमेंगी, और अन्ततः उदासीनता उन्हें नष्ट कर देगी ।

तीसरे, हर देश में चतुःसूत्री कार्यक्रम को मानवी समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापकतम कार्यवाही को प्रोत्साहित करना चाहिए । चतुःसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, कुछ थोड़े-से विकास कार्यों को पूर्णता के उच्च-स्तर तक ले जाने की अपेक्षा, ऐसे बहुसंख्यक कार्य कही अधिक लाभकारी होंगे, जो अधिक लोगों को प्रभावित करें, उन्हें स्वयं

अपने हित में सक्रिय होने को प्रेरित करें, और प्रगति की सार्विक भावना में रचनात्मक सहायता पहुँचाएँ ।

भादर्श अस्पतालों, भादर्श स्कूलों, और भादर्श गैरों की आवश्यकता उतनी नहीं है, जितनी व्यापक आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, साक्षरता, और रोती की समस्याओं को हल करने के लिए कार्यवाही करने की और स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करने की, जिसके पीछे अधिकतम सभ्य संस्था में स्वयं जनता के सक्रिय भाग लेने का ठोस आधार हो ।

चौथे, चतु मंत्री कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुए हमें यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि इससे हम लाभ उठाने वाले देश में अपना कोई हित साधन कर सकेंगे, या कि उनकी कृतज्ञता प्राप्त कर सकेंगे वस्तुतः कुछ अर्द्धविकसित देश मुख्यतः हमी भय के कारण अमरीकी सहायता स्वीकार करने से हिचकते हैं कि हम शायद उनकी नयी-नयी प्राप्त हुई आजादी को सीमित करने की, या उनकी राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करें ।

केवल एक ही आधार है जिस पर अमरीका और अर्द्ध-विकसित देश परस्पर अधिक निकट आ सकते हैं, और वह है अधिक सुरक्षित और अधिक स्वतंत्र विश्व का निर्माण करने की सामान्य इच्छा । अगर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, जापान, इण्डो-नीशिया, इण्डोपिया, लाइबेरिया, मिस्र, ब्राजील, वेनेजुआ और एशिया, अफ्रीका, व दक्षिण अमरीका के अन्य देशों में लोकतंत्र सफल होता है, तो हर अमरीकी के लिए यह आशा करने के कारण अधिक होंगे कि उसकी और उसके बच्चों की जिन्दगी ज्यादा अच्छी होगी ।

अगर हम इस सीधे-सादे लक्ष्य में सन्तुष्ट नहीं हो सकते, तो हमारे प्रयत्नों की असफलता अनिवार्य है । हम न केवल एशिया और अफ्रीका के करोड़ों ऐसे लोगों के साथ सहकार का भवसर खो देंगे, जो हमारे मित्र बनना चाहते थे, बल्कि उस रक्तहीन, लोकतांत्रिक क्रान्ति की आशा भी नष्ट हो जाएगी, केवल जिसके द्वारा ही विश्व-शांति और मनुष्य की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की नींव डाली जा सकती है ।

विश्व के आर्थिक विकास में साझीदार

श्री बील्स का कथन है कि स्वयं अपने उद्देश्य के लिए चढ़ती हुई आशाओं की क्रान्ति को नष्ट करने के चतुर साम्यवादी प्रयासों को रोकने के लिए केवल सैन्य सहायता ही पर्याप्त नहीं है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे उन्होंने भटलॉटिक मंचली के दिसम्बर, 1954 के अंक में प्रकाशित इस लेख में प्रस्तुत किया है।

रूटालिन की मृत्यु के बाद से, सोवियत रूस निरन्तर कूटनीतिक पहल अपने हाथ में लेने और स्वतंत्र विश्व को विभाजित करने के लिए प्रयास करता रहा है। रोज ब रोज वह यूरोप, एशिया और और दक्षिण अमरीका के करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहा है, कि साम्यवादी राष्ट्र शान्ति के सच्चे समर्थक हैं, और यह कि अमरीका जिसकी ओर 1945 में दुनिया इतनी उत्साहभरी दृष्टि से देख रही थी, एक शक्ति का भूखा, आक्रांता देश है।

हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या है, इसका कुछ संकेत इस बात से मिलता है, कि इस अविश्वसनीय रूप में विकृत चित्र को बहुत-से लोग सच समझते हैं। अगर हमें इस तस्वीर को बदलना है, तो अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में हमें एक नई दृष्टि अपनानी होगी, क्रान्तिकारी जगत में शक्ति के स्वरूप के बारे में नई समझ प्राप्त करनी होगी, और उस समझ के अगुरु एक नयी साहसपूर्ण कार्य-नीति पर चलना होगा।

यूरोप में हम क्या करते हैं या नहीं करते, इसका निर्णायक महत्त्व है। किन्तु एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में हम क्या करते हैं, यह भी कम से कम उतना ही महत्त्वपूर्ण है। इन अल्प-विकसित क्षेत्रों में हमारा ध्यान सैनिक हलों पर केन्द्रित रहने से, और आर्थिक तथा राजनीतिक तत्वां के प्रति हमारी उदासीनता से विशेष हानि हुई है।

अगर विश्व का साम्यवादी आन्दोलन कल खतम हो जाय, तो भी हर अमरीकी के लिए अल्प विकसित क्षेत्रों का गम्भीर महत्त्व होगा। यद्यपि हम दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं, किन्तु हमारी आबादी दुनिया की आबादी का केवल छह प्रतिशत है। जैसे-जैसे हमारी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं

घनुमों के विरुद्ध अपनी उत्तमियों की रक्षा करने के लिए उनकी हड़ता भी चढ़ेगी।

ऐसे राष्ट्रों के साथ घमरीका एक स्वतंत्र और गतिमान गाम्भारी का निर्माण कर सकता है, जो घाने घाने घनों में गाम्भारी का उद्भव के पहले की कम बनेगी, और धीरे-धीरे ग्यामी गाम्भारी की नींव रखेगी।

इस कारण, निम्नी भी प्रभावी कार्यक्रम का उद्भव के लिए घरीधी को कम करना न होकर, अधिक व्यापक होना चाहिए। गैर-जानकार लोग हमसे बड़े हैं कि निम्नी 'मनुष्य का पेट भरा होगा, वह कभी भी गाम्भारी नहीं बनेगा' यह वन इतिहास के प्रमाणित नहीं होनी। कानियों का नेतृत्व भूखे विमान नहीं करने घरन् मन्वय घरीध, कुठित और सामान्यतः भरणे घाने घाने मुठिमीवी करने हैं।

×

×

×

घ-गाम्भारी राष्ट्रों के लिए हमारे गहारा कार्यक्रमों को राजनीतिक घनों में मुख होना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक है कि शीर्षकानीन गाम्भारी नियोजन, भूमि-गुणार, कर-व्यवस्था में गुणार और घनियों के लिए विनाम गाम्भारी गरीधने के लिए विदेशी मुद्रा के उपयोग पर रोक लगाने की व्यावहारिक घनों लगाई जाएं।

घान बहूतेरे अल्पविकसित देशों में घमरीकी गहायता का प्रभाव इन गुणारों में तेजी घाने के बजाए, उन्हें स्वगित करने के घन में होता है। घमर हम इन गघान से बतराते हैं, तो हमारी गहायता का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ जागा, और हम पर सामन्ती अर्थ-व्यवस्थाओं को गहायता देने का घारोप लगेगा, जो बहुगत्या के बजाय, कुछ घोडे-से लोनों के हित में चलती हैं।

अन्त में, हमें कितनी सरल, चतुराई भरे, और सर्व-व्यापी गूण की तलाश छोडनी होगी। गाम्भारी विनाम की गीमाओं में घमीगित उलभनें हैं, और ये उलभनें हमारे द्वारा इन समस्याओं को हल करने के प्रयासों में भी परिलक्षित होगी।

उदाहरण के लिए, घपने यहाँ घुल्क घटाकर, और व्यापार को बढाकर, ग्राव-व्ययक गहायता की मात्रा को बहुत घटाया जा सकता है। अल्प-विकसित राष्ट्र गघा-सभव अपनी प्रगति का मूल्य देने की तैयार हैं, और इनके घ्रच्छुक हैं। किन्तु उनके सामने डालर प्राप्त करने के दो ही गाने हैं। या तो ये हमारी ग्रावश्यकता की बस्तुएँ हमारे हाथ वेचकर डालर प्राप्त करें, या फिर घमरीकी कर्जों और घनुदानों के रूप में उन्हें डालर मिलें।

हम इन राष्ट्रों के लिए अपनी पैदावार घमरीका के हाथ वेचना जितना गगान बनाएँगे, उन्हें हमसे उतनी ही कम गहायता लेनी पड़ेगी। हमके अतिरिक्त, उनके जीवन-स्तर जितने ऊँचे उठेंगे, घमरीकी विनिर्माताओं से वे उतना ही अधिक सामान खरीद सकेंगे।

अल्प-विकसित देशों में हम जो कच्चा काल खरीदते हैं, उनके मूल्यों में अधिक स्थिरता लाने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मलाया के तीन-चौथाई परि-

चारों की आमदनी अमरीका में खड़ के मूल्य के साथ बधी रहती है। चाय, कहवा, कोको, टीन और तेल का उत्पादन करने वाले बहुतेरे राष्ट्रों में भी लगभग इतना ही निकट सम्बन्ध है।

निश्चय ही, हममे इतनी काफी बुद्धि है कि हम न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की कोई ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसमे बाजार भाव में असामान्य उतार-चढ़ाव न आए, जिसे बड़ी मुसीबत और कटुता उत्पन्न होती है, और केवल सट्टेबाजों को लाभ होता है। सामान्य परिवर्तनों के लिए, न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के साथ एक मूल्य-क्षेत्र बाधा जा सकता है, जिसे हम सामान्यतः अपने भंडारों को बढ़ा या घटाकर नियंत्रित कर सकते हैं।

अगर उत्पादन इतना अधिक होता रहता है कि बाजार में उसे खपाने की क्षमता न हो, तो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों की ओर व्यवस्थित और नियोजित ढंग से मुड़ने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि इस तरह का कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है, या कि इस पर जल्दी सह-मति प्राप्त की जा सकती है। किन्तु इसकी चेष्टा करने का समय अभी ही है, जब इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की हमारे पास काफी गुंजाइश है।

व्यापार अधिक मुक्त हो, और कच्चे माल के लिए स्थिर मूल्यों पर निश्चित बाजार उपलब्ध हो, तो अल्प-विकसित राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाओं को बल मिलेगा, और वे स्वयं अपनी सहायता ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे। किन्तु प्रत्यक्ष सहायता के काफी बड़े कार्यक्रम की भी तीव्र आवश्यकता है। यह कार्यक्रम उतना ही साहसपूर्ण और कल्पनाशील होना चाहिए जितनी मार्शल योजना थी, जिसने पश्चिमी यूरोप की अर्थ-व्यवस्थाओं को 1947 और 1951 के बीच अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी।

अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों से आने वाली पूँजी केवल एक सीमित अंश तक ही पूँजी की इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। युद्ध के बाद से, अमरीका में निजी पूँजी के विनियोग का औसत प्रति वर्ष 46 अरब डालर रहा है। इस अवधि में हमने विदेशों में कुल दस अरब डालर की पूँजी लगाई है। इसका अधिकांश यूरोप और कनाडा में लगा है, और उसका भी बड़ा भाग इन देशों में अमरीकी निगमों द्वारा अर्जित मुनाफों से प्राप्त हुआ था। अगर हम दक्षिण अमरीका में अमरीकी तेल उद्योग के फैलाव को छोड़ दें, तो अल्प-विकसित क्षेत्रों में युद्ध के बाद लगी निजी अमरीकी पूँजी का कुल योग मुश्किल से एक अरब डालर होगा। हिन्दुस्तान में इस अवधि में लगे ऐसी पूँजी 10 करोड़ डालर से कम है।

पूँजी का यह प्रवाह इतना कम होने के उचित और समझ आने वाले कारण हैं। अधिकांश अल्प-विकसित देशों में स्थिति अनिश्चित है। बहुधा, औपनिवेशिक अनुभवों के फलस्वरूप, विदेशी पूँजी लगाने वालों के विरुद्ध अकारण विद्रोह रहा है। कुछ मामलों में, कर सम्बन्धी कानून ऐसे हैं कि अर्जित मुनाफे के एक उचित भाग

को बाहर निकालना कठिन होता है। बहुधा काम करने में नौकरसाही के कारण परेशान करने वाली कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

किन्तु आदर्श स्थितियों में भी यह सोचना भूल होगी कि अल्प-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के आवश्यक आधार निजी पूँजी के द्वारा निर्मित हो सकते हैं। आवश्यक पूँजी की मात्रा बहुत अधिक है, और मुनाफा कमाने के अवसर बहुत सीमित और अनिश्चित हैं।

अधिक मात्रा में विजली, बन्दरगाहों की पर्याप्त सुविधाएँ, अधिक कुशल रेलें, और सुधरी हुई संचार व्यवस्थाएँ, इस तरह की मूल प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांश सरकारी धन से ही हो सकती है। इन आधारों के निर्मित हो जाने के बाद, और औपनिवेशिक आशंकाओं के दूर हो जाने के बाद ही, निजी पूँजी के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। अतः अधिकांश अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में काफी बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष शासकीय कर्ज और अनुदान पर्याप्त प्रगति के लिए आवश्यक है।

एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के बड़े हिस्से में जो गरीबी फैली हुई है, वही साम्यवाद को ऐसी भूमि प्रदान करती है, जिसमें उसके बढ़ने की अधिक संभावना है। जब हम अल्प-विकसित राष्ट्रों की सहायता करने की अपनी इच्छा को इस आधार पर सीमित करते हैं कि हम प्रतिरक्षा और आर्थिक विकास, दोनों के खर्च एक साथ नहीं उठा सकते तो हम केवल रूसियों को शस्त्रों की वर्तमान होड़ को बनाये रखने का एक और कारण प्रदान करते हैं।

रूसियों के भय के भूत से हम अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा सकते? हम ऐसे उपाय क्यों नहीं करते, जो स्पष्टतः हमारी अमरीकी परम्परा के अनुरूप हैं, और जिनसे अन्य मनुष्यों की सर्वाधिक आवश्यक मांगें पूरी होने की शुरुआत होगी?

अब दोनों राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए समय आ गया है कि भविष्य के लिए कार्य के नए प्रतिमान स्थापित करें। अमरीका को अब उधेड़-बुन छोड़कर, साहसपूर्वक एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के स्वतंत्र, अल्प-विकसित, और अजुड़ राष्ट्रों को, उनकी आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए अपने साथ साभेदारों की दावत देनी चाहिए।

विदेशी सहायता के प्रति नया दृष्टिकोण

अल्पविकसित राष्ट्रों की द्विविधा का हल करने के लिए, कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के साथ-साथ ही जीवन स्तरों को कैसे उठाएँ, हमारी वैदेशिक सहायता में अधिक यथार्थ परक दृष्टि की आवश्यकता है, जैसा प्रतिनिधि सभा की वैदेशिक मामलों की समिति के समस्त नवम्बर, 1956 में प्रस्तुत श्री बौल्स की साक्षी से प्रकट है।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के अल्प विकसित, और अधिकांश अजुड़ क्षेत्रों में हमारा प्रभाव घटने के कई कारण बताये गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह है कि नयी सोवियत कार्यनीतियों के फलस्वरूप विद्व की अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते हुए मकट का मुकाबला करने में हम असफल रहे हैं।

अ-साम्यवादी एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नए नेताओं ने पश्चिम में शिक्षा पाई है, और वे आमतौर पर लोकतांत्रिक लक्ष्यों को, तथा विभिन्न अंशों तक लोक-तांत्रिक पद्धतियों को स्वीकार करते हैं। किन्तु उन्हें नीचे जीवन स्तरों द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व आन्तरिक दबावों का भी सामना करना पड़ता है। लोगों में आधुनिक प्रविधियों की संभावनाओं की नई समझ आ जाने के कारण ये दबाव और भी विस्फोटक हो गए हैं।

फलस्वरूप उनके सामने बहुत बड़ी द्विविधा आ जाती है।

औद्योगिकरण चूँकि राष्ट्रीय उद्देश्यों और शक्ति का पर्याचिवाची बन गया है, और नई यांत्रिक प्रविधियों के बारे में लोगों की जानकारी चूँकि व्यापक है, अतः अत्यधिक तीव्र गति से विकास के लिए राजनीतिक दबाव अब एशिया और अफ्रीका में, हमारे अपने औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवधि की अपेक्षा बहुत अधिक है।

इसके साथ ही जिन राष्ट्रों का भुकाव लोकतंत्र को और है, वहाँ लोगों का ध्यान भारी उद्योगों के आवश्यक आधार का निर्माण करने पर नहीं, बल्कि जीवन-स्तरों में सत्काल सुधार करने पर केन्द्रित हो गया है।

अपने प्रतियोगी राजनीतिक नेताओं के वादों, संयुक्त राष्ट्र संघ और चतु सूत्री कार्यक्रम के सर्वेक्षणों, और साम्यवादी प्रचार के फलस्वरूप, लोगों की दृष्टि ऐसी बन गई है, कि वे अपने शासन की प्रभावकारिता को बहुत-कुछ इस आधार पर आँकते

हैं कि वह किस हद तक उन्हें तत्काल अधिक भोजन, वस्त्र, और शिक्षा प्रदान कर सकती है, रोग कम कर सकती है, और कल्याण-सेवाओं को सुधार सकती है।

इस प्रकार, जो राष्ट्र लोकतांत्रिक रीतियों से अपने साधनों का विकास करने का निर्णय करता है, उसे अपने करों को स्वीकार्य सीमाओं के अन्दर ही रखना पड़ता है। उसे अपनी उत्पादन क्षमता का इतना काफी हिस्सा उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं में लगाना पड़ता है, जिससे जीवन-स्तरों में प्रत्यक्ष सुधार की सार्वजनिक माँग को सन्तुष्ट किया जा सके। इसके साथ ही, उसके लिए उचित सीमाओं के अन्दर, मुलनीय साम्यवादी राष्ट्रों की सुप्रचारित दौद्योगिक उपलब्धियों का मुकाबला करना भी आवश्यक होता है।

किन्तु किसी साम्यवादी देश का शासन, पुलिस राज के तरीकों का इस्तेमाल करके, अपनी जनता से कहीं अधिक कर वसूल कर सकता है, बलात् को गई अपनी लगभग सारी ही बचत को भारी उद्योगों और सैन्य प्रतिरक्षा में लग सकता है, और जीवन स्तरों में किसी ठोस सुधार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है।

कार्यरूप में दोनों वैकल्पिक व्यवस्थाओं के व्यावहारिक प्रभावों के विशिष्ट उदाहरण चीन की तानाशाही और हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में देखे जा सकते हैं। चीन अपने कुल वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादन का 22 प्रतिशत विस्तार कार्यों में लगा रहा है, विशेषतः भारी उद्योग, परिवहन, और बिजली के उत्पादन में। हिन्दुस्तान के शासक यद्यपि बड़े ही योग्य और बड़े राजनीतिक साहस वाले व्यक्ति हैं, फिर भी हिन्दुस्तान ऐसे ही विकासों के लिए उपलब्ध बचतों की वार्षिक दर को केवल 8 या 9 प्रतिशत तक ले जा सका है।

इस सक्षिप्त विश्लेषण से यह बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि एशिया और अफ्रीका के उन नए राष्ट्रों के लिए, जो तानाशाही से बचना चाहते हैं, एक बुद्धि-पूर्ण अमरीकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम का निर्णायक महत्त्व है। यह महत्त्व इसमें है कि उन आन्तरिक बलिदानों और दबावों को, जो तीव्र गति से आर्थिक विकास होने पर अनिवार्य ही उत्पन्न होते हैं, स्वतंत्र लोगों द्वारा स्वीकार्य सीमाओं के अन्दर रखा जा सके, और लोकतांत्रिक शासनों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे पुलिस राज के तरीकों से बचते हुए, आर्थिक विकास की साम्यवादी गति का अगर मुकाबला न कर सकें, तो कम से कम उसके निकट पहुँच सकें।

अधिकांश अल्प-विकसित और लोकतंत्र की ओर झुकाव रखने वाले राष्ट्रों को न केवल प्राविधिक सहायता की आवश्यकता है, वरन् आन्तरिक करों के बोझ को सहनीय सीमाओं के अन्दर ही रखते हुए, वे उद्योग-धन्धों, परिवहन, और बिजली के विकास के साथ-साथ उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं में प्रत्यक्ष वृद्धि की वित्तीय व्यवस्था कर सकें, इससे लिए काफी बड़ी मात्रा में पूँजी की भी आवश्यकता है।

विकसित राष्ट्रों से अल्प-विकसित राष्ट्रों की ओर पूँजी के प्रवाह का परम्परागत साधन निजी वित्त-व्यवस्था रही है। किन्तु बड़ी हद तक, यह साधन अब इतने काफ़ी

विदेशी सहायता के प्रति नया दृष्टिकोण

बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है, कि अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सके।

जिन राष्ट्रों में राजनीतिक अशांति व्याप्त है, उनमें प्रत्यक्ष अमरीकी निजी पूँजी का विनियोजन भी उस समय तक सीमित रहेगा जब तक मुनाफों के ऊँचे स्तर राजनीतिक दृष्टि से इस राष्ट्र को अस्वीकार्य रहते हैं, क्योंकि ऊँचे मुनाफे ही ऐसे विनियोजन का प्रीचर्य होते हैं। तेल और खनिज उद्योगों को छोड़कर, 1948 से अब तक एशिया और अफ्रीका में 20 करोड़ डालर से भी कम निजी अमरीकी पूँजी लगी है।

विदेशों में निजी पूँजी के विनियोजन को, अब तक की अपेक्षा काफी अधिक कौशल के साथ प्रोत्साहित करना होगा। आधुनिक परिवहन, पर्याप्त बिजली, और भारी उद्योग के औद्योगिक आधार का विकास आरम्भ होने के साथ, एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक स्थिरता बढ़ने की संभावना है, और तब निजी पूँजी का एक अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान होगा।

इस बीच, अन्य साधनों के अभाव में, एशिया और अफ्रीका के नए अ-साम्यवादी राष्ट्रों में, काफ़ी मात्रा में पूँजी विनियोजन का साधन अमरीकी सरकार होगी। केवल प्रत्यक्ष शासकीय कार्यवाही से ही अमरीकी पूँजी और यांत्रिक प्रविधि, वर्तमान एशिया और अफ्रीका में टिकाऊ लोकतांत्रिक शासन के अनुकूल न्यूनतम विकास लक्ष्यों और उपलब्ध स्थानीय साधनों के बीच की खाई को पाटने के योग्य बन सकती है।

अगले कुछ वर्षों के अन्दर, घटनाओं के दबाव के फलस्वरूप, लगभग निश्चित रूप में, अर्थनीति के प्रति एक नया विश्व दृष्टिकोण विकसित होगा। यह नया दृष्टिकोण हमारी वर्तमान दृष्टि से उतना ही भिन्न हो सकता है, जितना रूजवेल्ट का आन्तरिक आर्थिक कार्यक्रम, काल्विन कूलिज के कार्यक्रम से भिन्न था।

चूँकि भविष्य में हमारी सुरक्षा के लिए इसके निर्णायक महत्त्व को समझने का कोई गंभीर प्रयत्न अब तक नहीं किया गया है, अतः अधिकांश अमरीकी अब भी अर्सेनिक आर्थिक सहायता को एक अल्पकालीन, भलाई करने की योजना समझते हैं, जिसका मूल्य सन्देहास्पद है।

फलस्वरूप, सैन्य प्रतिरक्षा में हमने जितना धन लगाया है, उसका एक प्रतिशत से भी कम इस कार्यक्रम को मिला है। इसके अतिरिक्त, अर्सेनिक सहायता के लिए कांग्रेस ने जिस धन की व्यवस्था की है, उसे बहुधा गलत योजनाओं में, गलत स्थानों पर और गलत कारणों से खर्च किया गया है।

एशिया के देशों में हम देखते हैं कि अमरीकी सहायता के द्वारा उत्पादन में काफी वृद्धि होने पर भी, बहुधा राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि ही वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण यह है कि हमारे सहायता कार्यक्रमों ने बहुत अधिक अवसरों पर पुरानी जीवन विधियों को सुरक्षा प्रदान की है, जिससे बड़े हुए उत्पादन स्तरों पर भी, पुरानी व्यवस्थाओं में निहित विपमताएँ कायम रही हैं।

अधिक धनोत्पादन के अतिरिक्त, हमारे सहायता कार्यक्रम को मजदूरों और

बिसालों के बीच अपनी राष्ट्रीय सरकारों को अपने समाजों के प्रति एक स्वस्थ सहयोगी दृष्टिकोण का विकास करने पर विशेष जोर देना चाहिए।

इसके लिए आवश्यक है कि तीन आधारभूत लक्ष्यों की ओर निरन्तर प्रगति हो, जिसके बिना एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका में राजनीतिक स्थायित्व का विकास लगभग असंभव होगा :

1. आर्थिक उत्पादन में प्रत्यक्ष वृद्धि।
2. यह वृद्धि लाने में निजी सहकार की व्यापक भावना।
3. यह सार्वजनिक विश्वास कि वृद्धि के फलों का समुचित वंटवारा हो रहा है, और धन्याय निरन्तर कम हो रहे हैं।

चूँकि एशिया और अफ्रीका में हमने अपने प्रयासों को अधिकांश पहले लक्ष्य-मात्र उत्पादन वृद्धियों—पर ही केन्द्रित किया है, और चूँकि कई क्षेत्रों में हमारी सहायता से उत्पन्न नए धन का बहुत बड़ा हुआ हिस्सा अल्पसंख्यक शासन वर्ग के हाथ में चला गया है, अतः दुनिया के बहुतेरे हिस्सों में हम अपने को तिरस्कृत यथास्थिति के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं।

मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया के कुछ देशों के अमरीका में शिक्षित छात्र बहुधा एक दुःखद किन्तु सुपरिचित कहानी सुनाते हैं। वे अमरीका में अध्ययन करने के बाद स्वयं अपने देश में लोकतांत्रिक विकास और अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक होकर लौटते हैं। किन्तु स्वदेश पहुँचकर वे देखते हैं कि अमरीकी सहायता ने अर्द्ध-सामन्ती शासन को बल दे रखा है, या सत्ताहूक कर रखा है।

वे अपने यहाँ ऐसे शासन पाते हैं, जो धनिकों पर अमरीका की तुलना में भी बहुत कम कर लगाते हैं। वे देखते हैं कि उनके यहाँ निगम-कर बहुत ही कम हैं, और अल्प-विदेशी मुद्रा को आवश्यक वस्तुओं पर नहीं, बल्कि अधिकांश विलास-सामग्री मंगाने पर संच किया जाता है।

दूसरे शब्दों में, वे बहुधा देखते हैं कि हमारी आर्थिक सहायता का उपयोग मुधारों में तेजी लाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकता की स्थिति करने के लिए और इस प्रकार अलोकतांत्रिक, दक्षिण-पथी मसूहों की शक्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए होता है, जो अतीत के साथ तुरी तरह चिपके हुए हैं।

ऐसे संकीर्ण साधनों के द्वारा 'साम्यवाद को रोकने' के उद्देश्य से दिये गए आर्थिक सहायता अनुदानों का अन्ततः अग्रफल होना अनिवार्य है। अलोकप्रिय, सामन्ती यथास्थिति की सुरक्षा प्रदान करके, जिनके स्वयं अपने माधनों से जीवित रहने की कल्पना नहीं की जा सकती, यह भी संभव है कि अमरीकी सहायता कार्यक्रम बहुत अधिक लोगों को हमारे विरुद्ध कर दे, और अन्ततः एक अमहनीय स्थिति को बदलने के एक मात्र उपाय के रूप में, साम्यवाद को उनके लिए स्वीकार्य बना दें।

×

×

×

में मंत्रों में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करेंगे, जिनके बारे में मुझे लगता है कि

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता के क्षेत्र में किसी ठोस कार्य-योजना के मर्म में इन बातों को होना चाहिए ।

1. हमें आर्थिक सहायता के उद्देश्य को साफ़ तौर पर परिभाषित करना चाहिए । हमें जानना चाहिए कि उसके द्वारा क्या किया जा सकता है । साथ ही, यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता ।

मनुष्य होने के कारण, हम आशा कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमें पसन्द करेंगे और हमारे विचारों का समर्थन करेंगे । लेकिन मित्रों, सहयोगियों और समर्थन की इच्छा, सहायता देने के पीछे हमारी मुख्य प्रेरणा नहीं होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि साम्यवादी चुनौती के नतीजे साफ़ हैं, किन्तु आर्थिक सहायता को 'साम्यवादी खतरे की अवधि' से बाँध देने वाले तक उन समस्याओं को खतरनाक रीति से अति-सरल रूप प्रदान करते हैं, जो आज हमारे सामने हैं । जिस हद तक किसी देश में साम्यवादी खतरा मौजूद हो, उसी अनुपात में हम उस देश को सहायता प्रदान करें, ऐसे प्रस्तावों का भी यही नतीजा निकलता है ।

हमारा लक्ष्य विश्व में किसी अल्प-कालीन लोकप्रियता की होड़ को जीतना नहीं है, वरन् आन्तरिक स्थिरता प्राप्त करने में अन्य राष्ट्रों की सहायता करना है, जिससे वे स्वयं अपने घरों के स्वतंत्र मालिक बने रहें, और सभी बाहरी अतिक्रमणों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ हों ।

2 विदेशी आर्थिक सहायता एक दीर्घ-कालीन योजना है । इसके नतीजे तात्कालिक नहीं हो सकते, और उचित समय के पहले ही आशाएँ करने पर हम केवल निराशा और कटुता का ही अनुभव होगा ।

हम एक ऐसी अवधि में प्रवेग कर रहे हैं, जिसमें यांत्रिक प्रविधि और संचार साधनों की नई उपलब्धियों पर आधारित, तीव्र गति से अन्तर्राष्ट्रीय विकास होने की संभावनाएँ बहुत हैं । फिर भी, ऐसे समाजों का निर्माण आसानी से, या अल्प मूल्य से नहीं होगा, जिनमें आर्थिक अभिवृद्धि, और मानवी अधिकारों में गभीर आस्था का विकास, राजनीतिक स्थायित्व के लिए आवश्यक सन्तुलन के अन्तर्गत साथ-साथ हो ।

निस्सन्देह, समय का यह प्रश्न एक व्यावहारिक विधायक समस्या उत्पन्न करता है । कांग्रेस एक विस्तृत पंच वर्षीय कार्यक्रम तैयार करके पहले ही से अपने-आपको बाँध नहीं सकती । फिर भी, मार्शल योजना, संयुक्त राष्ट्र संघ, आयात-निर्यात बैंक, कृषि समर्थक मूल्य कार्यक्रम, वस्तु ऋण प्रशासन, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि को प्रदान किये गए दीर्घ-कालीन समर्थन में हमें कुछ व्यावहारिक पूर्व-दृष्टान्त मिलते हैं ।

किसी विशेष वर्ष में कार्यक्रम विनियोजन को अस्वीकार कर सकती है । किन्तु एक बार किसी दीर्घ-कालीन कार्यक्रम की सामान्य रूपरेखा पर सहमति हो जाने के बाद, जब तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई बड़ा परिवर्तन न हो, तब तक ऐसी अस्वीकृति की संभावना बहुत ही कम होगी ।

3. हमारी सहायता की मात्रा नयी विद्व स्थिति की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सर्वाधिक तात्कालिक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना धन वास्तव में आवश्यक है, अपने वादों को उममें कम करना बहुत बड़ी भूल होगी।

हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि लोकतंत्र की और भुजाव रखने वाले अधिकांश नए राष्ट्र आन्तरिक विकास के लिए जितनी बचत और खर्च कर सकते हैं, और साम्यवादी राष्ट्र जितना बचा और खर्च कर सकते हैं, उमके बीच काफी बड़ी और सततनाक रूप में विस्फोटक खाई है, और घागे भी रहेगी।

हमारी कुछ सहायता निस्सन्देह प्राविधिक सहायता, वस्तु अनुदान, और वस्तु ऋणों के रूप में होगी, जिनका स्वरूप अलग-अलग राष्ट्रों में बहुत-बहुत भिन्न होगा। भोजन और वस्त्र की मांग करने वाली दुनिया में हमारी रेशों के अतिरिक्त उत्पादन को भी आर्थिक हित का एक बड़ा तत्व बनाया जा सकता है, और बनाना चाहिए। शायद एक विश्व वस्तु बैंक अन्ततः ऐसी व्यवस्था प्रदान करे, जिसमें उसके पूर्ण उपयोग की सुविधा हो।

4. कर्ज पाने वाले राष्ट्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इन कर्जों के एक हिस्से को प्रबन्ध-प्रशिक्षण पर खर्च करें। अनुबन्ध करने वाला संस्थान कारखाने को नियोजित और निर्मित करने की, उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और उस समय तक उसे चलाने की जिम्मेदारी ले, जब तक कि उसके स्थानीय प्रबन्धक उसे अपने हाथ में लेने के योग्य न हो जाएँ।

ऐसे विदेशी विकास कार्यक्रम में अमरीकी व्यापार की मुख्य भूमिका का जल्दी से जल्दी अध्ययन होना चाहिए। अधिक सहायता की एक प्रमुख पद्धति यह होनी चाहिए कि प्रथम कोटि का अमरीकी और पश्चिम यूरोपीय प्राविधिक और प्रबन्धज्ञान एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में पहुँचाया जाय। इससे अमरीकी व्यापार पर अनिवार्य ही एक जिम्मेदारी आती है।

अमरीकी संस्थानों को ऐसी शर्तों पर इस जिम्मेदारी के लिए राजी करना आसान नहीं होगा, जो सामान्यतः उनके सामने रखी जाएँगी। किन्तु अमरीकी उद्योग में ऐसे बहुतेरे नेता हैं, जो आज के लाभार्थ से घागे, कल की जीवन-रक्षा के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं।

5. हमें निरन्तर उन आधारभूत आर्थिक सुधारों से अपने को सम्बद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए, जो ऐसे स्वतंत्र समाज के निर्माण की पूर्व-आवश्यकता हैं, जिस में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएँ पनप सकें। अगर हम इसमें सफल होते हैं, तो अल्पविकसित महाद्वीपों में हम अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को निरन्तर बढ़ता हुआ पाएँगे।

कार्य के लिए सटीक नियम असंभव है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हर राष्ट्र को अपने अपने होने वाले राष्ट्रों

की भूमि के समान पुनः वितरण, आर्थिक अन्यायों की समाप्ति, अधिक तोकतांत्रिक कर-व्यवस्था, और ऐसे ही अन्य कार्यों की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ने की प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं फिर इस बात पर जोर दूँगा कि आवश्यक मानवीय प्रगति के अभाव में, केवल उत्पादन साधों से जितनी समस्याएँ हल होंगी, लगभग निश्चय ही, उमसे अधिक राजनीतिक परेशानियाँ उत्पन्न होंगी।

6. अन्त में, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता का प्रश्न रह जाता है। इसके पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिये गए हैं कि हमें अपनी आर्थिक सहायता का बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वितरित करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी स्थापित करके, ऐसी विकासनिधियों के लिए एक प्रभावकारी माध्यम की व्यवस्था कर सकता है। कोलम्बो योजना संगठन, एक अन्य संभाव्य वितरण एजेंसी है।

एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के लिए एक सुसम्बद्ध और व्यापक आर्थिक विकास कार्यक्रम बनाने पर हमें विचार और क्रिया के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। कार्यकारी स्तर पर यह हमारे शासन से गतिशील नेतृत्व की माँग करेगा। लोगों को शिक्षित करने का ऐसा व्यापक कार्यक्रम आवश्यक होगा, जिसे कांग्रेस के द्विदलीय समर्थन से केवल राष्ट्रपति ही चला सकता है।

विदेशी सहायता के वितरण में प्रतिमानों की आवश्यकता

पूर्वी कॉनेक्टिकट के नवनिर्वाचित कांग्रेस-सदस्य के रूप में श्री वॉल्स प्रतिनिधि-सभा में अपने सर्वप्रथम भाषणों में से एक में (20 अप्रैल, 1958) हमारे सैन्य सहायता कार्यक्रमों के पुनः परीक्षण की माँग करते हैं, और आर्थिक सहायता के प्रशासन के लिए नए और अब स्वीकृत, प्रतिमान प्रस्तावित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अमरीकी लोगों के मन में, और कांग्रेस की कार्यसूची में, विदेशी सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषय कम हों हैं। और शायद किसी भी विषय के सम्बन्ध में इतनी असहमति, भ्रान्तियाँ और निराशा नहीं है।

विदेशी सहायता के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने में इस समय हमारे सामने गंभीर कठिनाइयाँ हैं। इसके प्रमुख कारणों में से एक यह भी है कि प्रशासन ईमानदारी और सफाई के साथ यह बलाने में अग्रपंक्त रहा है कि इस धन की इतनी तीव्र आवश्यकता क्यों है।

हमारी राष्ट्रीय बुद्धि के लिए इससे अधिक प्रशमनीय वान में और कोई नहीं जानता, कि जनमत के सर्वेक्षणों में गत-प्रतिशत अमरीकियों ने विदेशी सहायता कार्यक्रम के लिए सबत समर्थन व्यक्त किया है, यद्यपि शायद उसके सच्चे, दीर्घ-कालीन लक्ष्यों को निरूपित करने में असफल रहा है।

विदेशी सहायता के जो अधिकृत उद्देश्य सबसे अधिक अवसरों पर बताए जाते हैं, वे कई कारणों से अपर्याप्त हैं।

वे विश्व सम्बन्धों में अमरीका के वास्तविक लक्ष्यों के माय न्याय नहीं करते।

वे मनुष्य की प्रतिष्ठा के प्रति उस सामान्य रुचि को अपील नहीं करते, जिसमें हम सम्पूर्ण अ-साम्यवादी दुनिया के लोगों के सहयोगी हैं।

और वे स्वयं अमरीकी लोगों की बुद्धि और अच्युतई को ध्यान में नहीं रखते।

पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम की भूमिका में अब ऐसा प्रतीत होता है कि 'समुक्त राज्य अमरीका की नीति' सहायता कार्यक्रम को केवल 'तभी तक जारी रखने की है जब तक (साम्यवादी) खतरा.....क्रायम है।

शीत-युद्ध के बाजार में, स्वयं हमारी कांग्रेस द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार, शोरभरी साम्यवादी अल्पसंख्या का मूल्य अमरीकी डालरों के बराबर हो गया है।

विदेशी सहायता कार्यक्रम के पक्ष में, गुप्तचुप, अनौपचारिक वार्ताओं में शासन की ओर से दिया जाने वाला एक अन्य मिथ्या तर्क, संयुक्त राष्ट्र महा सभा में हमारी नीतियों के पक्ष में बहुमत का समर्थन खरीदने में इस कार्यक्रम की कथित उपयोगिता का है।

किन्तु, अध्यक्ष महोदय, क्या यह दूसरा तर्क पहले से अधिक बंध है? मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति किसी सामान्य अमरीकी वस्ती में आकर रहता है, और वस्ती में कुछ सुधारों के लिए धन देकर चाहता है कि बदले में लोग उसके राजनीतिक मतों को स्वीकार कर लें। क्या अधिकांश सच्चे और नागरिक-भावना रखने वाले लोग उससे यह नहीं कहेंगे कि वह अपने परोपकार को अपने साथ ले जाय, और अन्यत्र कही जाकर रहे?

क्या हम आशा कर सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के गर्विले नए राष्ट्रों की, और यूरोप व अमरीका के अधिक पुराने राष्ट्रों की प्रतिक्रिया इससे भिन्न होगी?

विदेशी सहायता के लिए तीसरा भ्रान्त तर्क यह है कि साम्यवाद केवल भूखे लोगों को आकर्षित करता है। हम कभी-कभी सुनते हैं कि, "हर किसी का पेट चावल से भर दो, इसीसे अल्प-विकसित विश्व में साम्यवाद का अन्त हो जाएगा।"

यह दृष्टिकोण साम्यवाद के आकर्षण, और वस्तुतः मानव प्रकृति की समझ का जबरदस्त अभाव प्रदर्शित करता है। अन्याय से और अपनेपन की भावना के अभाव से जो निराशा उत्पन्न होती है, वह मात्र भूख की अपेक्षा साम्यवाद की ओर खींचने वाली नहीं सबल प्रेरक शक्ति होती है।

अमरीकी सहायता के उद्देश्य हमेशा ऐसे नकारात्मक चर्चों में ही नहीं व्यक्त किये गए। उदाहरण के लिए, 1948 के विदेशी सहायता अधिनियम में, जो मार्शल योजना का आधार बना था, 80वीं कांग्रेस ने कहा था कि ऐसे कदम उठाये जाएँ, जो 'व्यवितगत स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों को, स्वतन्त्र संस्थाओं को, और सच्ची स्वतन्त्रता को' बल प्रदान करें 'जिसका आधार उत्पादन के लिए सबल प्रयत्न, विदेशी व्यापार का विस्तार, भ्रान्तरिक वित्तीय स्थिरता उत्पन्न करना और कायम रखना, तथा आर्थिक सहयोग का विकास हो।'

अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, 1954 का उद्देश्य वक्तव्य, जो इस वर्ष के विधेयक में भी कायम रखा गया है, हमारे योग्य नहीं प्रतीत होता। इसमें निहित उद्देश्य नकारात्मक, तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित, और यथार्थ की अपेक्षा करने वाले हैं।

मेरा विश्वास है कि इतिहास को इस संकटमय अवधि में अमरीकी लोगों का मूल्यांकन वास्तविकता से कम करना हमें बन्द कर देना चाहिए। अब समय है कि हम-

व्यापारिक लटको को छोड़ कर, जो कुछ आवश्यक है उसे सही वारण समझ कर करें।

अमरीका सचमुच क्या चाहता है ? एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के राष्ट्रों या साधनों पर नियंत्रण करने की हमें कोई इच्छा नहीं है। हमें पिछलग्गुओं की तलाश नहीं। अपने ढंग दूसरों पर लादने की हमें कोई इच्छा नहीं।

वस्तुतः, हमारे अपने राष्ट्र का जन्म क्रान्ति में हुआ था, और आरम्भ से ही हमने हर जगह अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने और कायम रखने के लिए, और स्वयं अपने ढंग से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए लोगों के प्रयत्नों के साथ अपने को सम्बद्ध किया है।

विश्व में हमारे लक्ष्य आज भी वही हैं जो जेफरसन के समय थे—एक शान्तिपूर्ण सत्तार; जिसमें सभी लोगों को स्वयं अपनी सस्कृतियों, धर्मों और राष्ट्रीय क्षमताओं के अनुसार मुक्त और स्वतन्त्र रूप में अपना विकास करने का अवसर मिले।

अब अमरीकी लोगों और दुनिया के सामने इसका प्रत्यक्ष संकेत प्रस्तुत करने का समय है कि हमारे पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक विश्वासों और हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं के उपयुक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव है कि हम इन लक्ष्यों को स्पष्ट निरूपित करें।

अब मैं दूसरे सशोधन के अपने प्रस्ताव को सूँगा। हमारी सैन्य सहायता के कुछ हिस्से के बटवारे की वर्तमान अपव्ययपूर्ण और बहुधा प्रभावहीन रीतियों से मैं ऊब गया हूँ, और मैं समझता हूँ, यहाँ और लोग भी ऊब गए हैं। कई मामलों में हमने अनजाने ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की हैं, जिनसे साम्यवादियों को लाभ हुआ है, और उनका प्रभाव बड़ा है।

निस्सन्देह, मैं इस बात को समझता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ साम्यवादी आक्रमण का स्पष्ट खतरा है, स्थिति के सैनिक पहलुओं को, कम से कम कुछ समय तक, प्राथमिकता देनी होगी। पश्चिमी यूरोप, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया, कोरिया, फारमोसा, और विएतनाम, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं। यहाँ काफी बड़ी मात्रा में अमरीकी सैन्य सहायता परम आवश्यक है।

लेकिन दो सम्पूर्ण महाद्वीपों, दक्षिण अमरीका और अफ्रीका में और एशिया के लेबनान से मनीला तक फैले क्षेत्र के बड़े हिस्से में, विश्व शान्ति को बड़ा खतरा सोवियत टैंको और वायुयानों से नहीं, वरन् आर्थिक क्षय, अन्याय और मानवीय निराशा से है।

इन क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से अमरीकी सैन्य उपकरणों का भेजना, कम ही अवसरों पर हमारे अपने दीर्घ-कालीन सुरक्षा हितों के पक्ष में होता है, और सम्बन्धित देशों के लोगों के हितों के साथ तो उसका मेल और भी कम होता है।

तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर दी गई ऐसी सैन्य सहायता, लगभग

निरपवाद ही व्यर्थ होती है। इसमें आन्तरिक आर्थिक बोझ बढ़ता है। यह आन्तरिक प्रयत्नों को रचनात्मक विकास की दिशा से दूर हटाती है। कुछ मामलों में, वह हमारी प्रतिष्ठा और हमारे प्रभाव को ऐसी तानाशाहियों के साथ बांध देती है, जिनकी जीवनावधि सन्देहास्पद होती है, और जल्दी या देर से जिनका विनाश निश्चित होता है।

इन उठते हुए महाद्वीपों में भौतिक सहायता अगर क्षेत्रीय राजनीतिक तत्वों की ओर उचित ध्यान दिये बिना दी गई, तो विशेषतः हानिप्रद हो सकती है। मनमाने ढंग में भेजे गए हथियार लाभान्वित होने वाले राष्ट्र और उसके अ-साम्यवादी पड़ोसियों के बीच दक्षिण के नाजुक सन्तुलन को बिगाड़ कर, सम्पूर्ण क्षेत्र की सैनिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल देते हैं।

इन सभी कारणों से, मैं समझता हूँ कि एक-एक देश को लेकर हमारे संन्य सहायता कार्यक्रम की प्रभावकारिता पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।

मैं यह नहीं कहता कि हम बिना समझे-बुझे पुरानी व्यवस्थाओं को खतम कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आग्रह करना चाहिए कि उन्हें नए लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाय, और यह कि कोई ऐसे नए समझौते न किये जाएँ जो इन प्रतिमानों के अनुरूप न हों।

×

×

×

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सहायता के वितरण के सम्बन्ध में, एक अधिक यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर हम विचार करें।

ऐसा क्यों है कि कोई बाँध किसी एक देश में बड़ी सफलता से बनाया और चलाया जा सकता है, जबकि एक अन्य देश में वैसे ही बाँध धुरी तरह असफल होता है? ऐसा क्यों है कि आधुनिक उपकरण कुछ देशों में खेती और कारखानों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं, जबकि अन्य देशों को भेजी गई वैसे ही मशीनें बन्दरगाहों में पड़ी सड़ती रहती हैं?

अधिकांश मामलों में, इस स्थिति, में मन्वन्धिन देशों और शासनों का मौलिक अन्तर परिलक्षित होता है—ऐसे अन्तर जिन्हें ध्यान में रखने में हम बहुधा छेदजनक रूप में असफल रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि हर देश की हमारी दीर्घ-कालीन आर्थिक विकास सहायता का उपयोग करने की क्षमता को परखने के लिए, निम्नलिखित पाँच कसौटियाँ रखी जाएँ:

1. अमरीकी आर्थिक बजट और अन्य सहायता देने की सबसे बड़ी बसोटी आत्म-बलिदान की होनी चाहिए।

बड़ी मात्रा में दीर्घ-कालीन सहायता का पात्र उही राष्ट्र को मानना चाहिए, जो यह प्रदर्शित करे कि स्वयं अपने साधनों से अपने राष्ट्रीय विकास के लिए धन की व्यवस्था करने का वह पर्याप्त प्रयास कर रहा है।

व्यापारिक लटको को छोड़ कर, जो कुछ आवश्यक है उसे सही कारण समझ कर करें।

अमरीका सचमुच क्या चाहता है ? एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के राष्ट्रों या साधनों पर नियंत्रण करने की हमें कोई इच्छा नहीं है। हमें पिछलग्गुओं की तलाश नहीं। अपने ढंग दूसरों पर लादने की हमें कोई इच्छा नहीं।

वस्तुतः, हमारे अपने राष्ट्र का जन्म क्रान्ति में हुआ था, और आरम्भ से ही हमने हर जगह अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने और कायम रखने के लिए, और स्वयं अपने ढंग से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए लोगों के प्रयत्नों के साथ अपने को सम्बद्ध किया है।

विश्व में हमारे लक्ष्य आज भी वही हैं जो जेफरसन के समय थे—एक शान्तिपूर्ण सप्ताह, जिसमें सभी लोगों को स्वयं अपनी सस्कृतियों, धर्मों और राष्ट्रीय क्षमताओं के अनुसार मुक्त और स्वतन्त्र रूप में अपना विकास करने का अवसर मिले।

अब अमरीकी लोगों और दुनिया के सामने इसका प्रत्यक्ष संकेत प्रस्तुत करने का समय है कि हमारे पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक विश्वासों और हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं के उपयुक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव है कि हम इन लक्ष्यों को स्पष्ट निरूपित करें।

अब मैं दूसरे संशोधन के अपने प्रस्ताव को सूँगा। हमारी सैन्य सहायता के कुछ हिस्से के बटवारे की वर्तमान अपव्ययपूर्ण और बहुधा प्रभावहीन रीतियों से मैं ऊब गया हूँ, और मैं समझता हूँ, यहाँ और लोग भी ऊब गए हैं। कई मामलों में हमने अनजाने ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की हैं, जिनसे साम्यवादियों को लाभ हुआ है, और उनका प्रभाव बढ़ा है।

निस्सन्देह, मैं इस बात को समझता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ साम्यवादी आक्रमण का स्पष्ट खतरा है, स्थिति के सैनिक पहलुओं को, कम से कम कुछ समय तक, प्राथमिकता देनी होगी। पश्चिमी यूरोप, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया, कोरिया, फारमोसा, और विएतनाम, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं। यहाँ काफी बड़ी मात्रा में अमरीकी सैन्य सहायता परम आवश्यक है।

लेकिन दो सम्पूर्ण महाद्वीपों, दक्षिण अमरीका और अफ्रीका में और एशिया के लेबनान से मनीला तक फैले क्षेत्र के बड़े हिस्से में, विश्व शान्ति को बड़ा खतरा सोवियत टैंको और वायुयानों से नहीं, धरन् आर्थिक क्षय, अन्याय और मानवीय निराशा से है।

इन क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से अमरीकी सैन्य उपकरणों का भेजना, कम ही अवसरों पर हमारे अपने दीर्घ-कालीन सुरक्षा हितों के पक्ष में होता है, और सम्बन्धित देशों के लोगों के हितों के साथ तो उसका मेल और भी कम होता है।

तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर दी गई ऐसी सैन्य सहायता, लगभग

निरपवाद ही व्यर्थ होती है। इसमें आन्तरिक आर्थिक बोझ बढ़ता है। यह आन्तरिक प्रयत्नों को रचनात्मक विकास की दिशा से दूर हटाती है। कुछ मामलों में, वह हमारी प्रतिष्ठा और हमारे प्रभाव को ऐसी तानाशाहियों के माथ धाँध देती है, जिनकी जीवनावधि सन्देहास्पद होती है, और जल्दी या देर से जिनका विनाश निश्चित होता है।

इन उठते हुए महाद्वीपों में सैनिक सहायता अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक तत्वों की ओर उचित ध्यान दिये बिना दी गई, तो विशेषतः हानिप्रद हो सकती है। मनमाने ढंग से भेजे गए हथियार लाभान्वित होने वाले राष्ट्र और उसके अ-नाम्यवादी पड़ोसियों के बीच शक्ति के नाजूक सन्तुलन को बिगाड़ कर, सम्पूर्ण क्षेत्र की सैनिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरों में डाल देते हैं।

इन सभी कारणों से, मैं ममझता हूँ कि एक-एक देश को लेकर हमारे सैन्य सहायता कार्यक्रम की प्रभावकारिता पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।

मैं यह नहीं कहता कि हम बिना समझे-बूझे पुरानी व्यवस्थाओं को खतम कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आग्रह करना चाहिए कि उन्हें नए सद्यों के अनुरूप बनाया जाय, और यह कि कोई ऐसे नए समझौते न किये जाएँ जो इन प्रतिमानों के अनुरूप न हों।

×

×

×

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सहायता के वितरण के सम्बन्ध में, एक अधिक यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर हम विचार करें।

ऐसा क्यों है कि कोई वीथ किसी एक देश में बड़ी सफलता से बनाया और चलाया जा सकता है, जबकि एक अन्य देश में वैसे ही वीथ धुरी तरह असफल होता है? ऐसा क्यों है कि आधुनिक उपकरण कुछ देशों में खेती और कारखानों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं, जबकि अन्य देशों को भेजी गई वैसे ही मशीनें बन्दरगाहों में पड़ी सड़ती रहती हैं?

अधिकांश मामलों में, इस स्थिति, में सम्बन्धित देशों और शासनों का मौलिक अन्तर परिलक्षित होना है—ऐसे अन्तर जिन्हें ध्यान में रखने में हम बहुधा खेदजनक रूप में असफल रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि हर देश की हमारी दीर्घ-कालीन आर्थिक विकास सहायता का उपयोग करने की क्षमता को परखने के लिए, निम्नलिखित पाँच कसौटियाँ रखी जाएँ:

1. अमरीकी आर्थिक बर्ज और अन्य सहायता देने की सबसे बड़ी कसौटी आत्म-वलिदान की होनी चाहिए।

बड़ी मात्रा में दीर्घ-कालीन सहायता का पात्र उची राष्ट्र को मानना चाहिए, जो यह प्रदर्शित करे कि स्वयं अपने साधनों से अपने राष्ट्रीय विकास के लिए धन की व्यवस्था करने का वह पर्याप्त प्रयास कर रहा है।

ऐसे प्रमाण में राष्ट्रीय बरादान का एक उचित सीमा तक प्रभारी कार्यक्रम भी शामिल हो, जो व्यक्ति की जरूरतें देने की क्षमता पर आधारित हो। जिनमें अल्पसंख्यक विदेशी मुद्रा का लेवी से छूट हो जाएगा, ऐसी अनायास्य और शिवाय की सम्पत्तियों के अभाव पर नियंत्रण, और अधिकतम गत्या में विगत परिवारों को उनको भूमि का स्वाभिव्यक्ति दिलाने के लिए हड़ और निरन्तर प्रयत्न भी इन प्रमाणों में शामिल हो।

2. बड़ी मात्रा में अमरीकी पूँजी सहायता प्राप्त करने के लिए, सम्बन्धित अल्पसंख्यक राष्ट्र को चाहिए कि आर्थिक सहायता की एक व्यापक और व्यापक शून्य के साथ, उन सहायता की प्राप्ति के लिए सभी उपलब्ध साधनों के ब्यवहार का ब्योरा तैयार करे।

इससे यह निश्चित हो जाता है कि महत्त्वपूर्ण बावों को प्राथमिकता मिलेगी, कि विकास कार्यक्रम का निजी और सार्वजनिक भाग के साथ प्राप्तिकता का सम्बन्ध होगा, और यह कि अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की प्रायदयता अधिक सही-मती प्रांकी

अगर एक महत्त्वपूर्ण निजी व्यापार क्षेत्र पहले से ही मौजूद है, तो ऐसी योजना में राष्ट्रीय विकास का कार्यक्रम निरूपित करते समय, सेती, बिजली, और परिवहन की सरकारी योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाय।

3. सहायता के लिए उपयुक्त देश में काफी बड़ी, सक्षम, और अष्टाचार-मुक्त नागरिक सेवा होनी चाहिए। बिना योग्य द्रव्यनिधियों, कलक्टरों, और प्रशासकों के, पूँजी विनियोजन की बड़ी रकमों का उपयोग आर्थिक दृष्टि में लाभप्रद रूप में नहीं किया जा सकता।

4. दीर्घ-कालीन पूँजी सहायता के उपयुक्त होने के लिए, किसी देश में अक्षयता टिकाऊ शासन भी होना चाहिए, जिसकी जड़ें जनता में हों।

हमारी लोकतांत्रिक परम्परा के फलस्वरूप, अधिकतम अमरीकियों को किसी भी विचारधारा को तानाशाही सरकारों से कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए। किन्तु, अल्पसंख्यक महोदय, इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी सहायता उन्हीं देशों तक सीमित रहे, जिनमें पश्चिमी नमूने पर ससदीय लोकतंत्र कायम हो।

वस्तुतः, हमें इस तथ्य का सामना करना होगा कि एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्र, लम्बे अर्थ में, शायद हमारी सहायता को अपने लिए अनुपयुक्त समझें। हम केवल एक ही बात को पक्की मान सकते हैं—उन सरकारों के सफल होने की संभावना सबसे कम है, जिनकी शक्ति सामन्ती भूस्वामियों और सूदखोर महाजनों की बदलती हुई निष्ठा पर आधारित है।

मध्यम-वर्गीय मध्य-पक्ष और अ-साम्यवादी वामपक्ष, दोनों के ही समर्थन का परित्याग करके ऐसी सरकारें साम्यवादियों को पूरा मौका देती हैं कि वे सुधारकों का रूप धरकर समुक्त मोर्चों के लिए कोशिश करें। जब हम ऐसी सरकारों का समर्थन करते हैं, और उनका पतन हो जाता है, तो हमारी प्रतिष्ठा और प्रभाव का भी उनके

माय नष्ट हो जाना संभव है।

सगभग एक पीढ़ी तक तुर्की पर शासन करने वाले अतानुर्क, अ-साम्यवादी वाम-पक्ष के एक तानाशाह थे। हम हमेशा उनके तरीकों का समर्थन नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनके शासन की जड़ें जनता के समर्थन में थीं, अतः वे अति आवश्यक सुधार कर सके, और बढ़ते हुए लोकतंत्र की नींव डाल कर, उसमें भाग लेने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर सके। ऐसा शासन हमारी सहायता का पात्र है।

अन्त में, आर्थिक सहायता प्रदान करते समय, सम्बन्धित देश के राजनीतिक महत्त्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। जनसंख्या, भूमिक्षेत्र, साधन, प्रभाव, और स्थिति इन महत्त्व को आंकने के पैमाने होंगे।

जो देश इन न्यूनतम विकास प्रतिमानों की पूर्ति नहीं करते, उन्हें बुद्धिवादान के साथ यह समझा देना चाहिए कि वे उस समय तक हमसे पूंजी सहायता की आशा नहीं कर सकते, जब तक कि वे सफल विकास के लिए स्वयं अपना आन्तरिक आधार निर्मित नहीं कर लेते।

इसका विलम्ब भी यह अर्थ नहीं है कि हम उनकी ओर से मुंह मोड़ लें। इसके विपरीत, उनकी सहायता के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम करते रहना चाहिए।

हमें एक व्यापक आर्थिक विकास योजना बनाने में उनकी सहायता करने का प्रस्ताव रखना चाहिए, जिससे वे स्वयं अपने साधनों का अधिकतम लाभप्रद रीति से उपयोग कर सकें।

हमें प्रशान्त का एक कार्यात्मक आधार निर्मित करने के लिए कर-विशेषज्ञों, इंजीनियरों के सर्वेक्षण दलों, और अन्य प्राविधिक कर्मियों के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए।

हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने घनी उच्चवर्ग के लिए खरीदी गई विलास सामग्री के आयात पर नियन्त्रण लगाएँ ताकि अल्प विदेशी मुद्रा का उपयोग लोगों की जरूरी आवश्यकताओं के लिए हो सके।

हमें उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वे भूमि सुधार आरम्भ करें, और उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों के उपयोग का सुझाव देना चाहिए। जापान और फारमोसा में अमरीकी सरकारी विशेषज्ञों ने निजी भूस्वामित्व के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पहल की, जिसने इन दोनों देशों में किसानों को कृषि-उत्पादकता के नए उच्च स्तर कायम करने में, और ग्रामीण लोकतंत्र के विस्तार में सहायता पहुँचाई है।

अधिक विशिष्ट और तात्कालिक रूप में, हम ऐसी विशिष्ट योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने में इन राष्ट्रों की सहायता कर सकते हैं, जो अपने-आप में लाभप्रद हो, जो सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर न हों, और जो स्पष्टतः जनता के हित में हों।

राष्ट्रीय राजधानी में एक प्राधुनिक अस्तित्व इगना एक उदाहरण हो सकता है जिसमें डाक्टरों और नर्सों के लिए प्रतिक्षण की सुविधाएँ हों, और गाँवों के लिए बिना भरती किए उपचार की व्यवस्था हो। या किसी विश्वविद्यालय का डिग्री और सुधार या कोई कृषि प्रयोग विद्यालय भी हो सकता है।

इस तथ्य की स्वीकार करता हूँ कि किसी प्रकार की प्राथिक सहायता—जिसे सरकारी तौर पर 'प्रतिरक्षा समर्पण' या 'विशेष सहायता' कहा जाता है—प्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, विशेष प्राथिक कारणों से, सैन्य सहायता की पुष्टि के रूप में, या किसी सैनिक अड्डे के उपयोग के बदले में दिये गए किराए के रूप में, आवश्यक होती है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी सहायता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी गई है।

पारस्परिक सुरक्षा में साझेदारी निहित है। प्रभावी होने ले लिए, इनमें दोनरणा सम्बन्ध होना चाहिए। विदेश स्थित अमरीकी प्रतिनिधियों को इनके लिए अधिक हट प्रयत्न करना चाहिए कि सैन्य क्षेत्र में पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी हमारे प्रयत्न सचमुच साझेदारी के आधार पर चलें।

X

हमारे कई विदेशी सहायता कार्यक्रमों के नियोजन और प्रशासन के सम्बन्ध में मेरी आलोचनाएँ सैन्य सहायता और प्राथिक सहायता, दोनों के बारे में हैं। इराक एक उदाहरण है। वहाँ के घटनाक्रम के संक्षिप्त पुनरावलोकन से ऐसी दृष्टिकोण की आवश्यकता प्रकट हो जाती है जो सैन्य-अभिमुख कम हो, और यथार्थ के अधिक अनुकूल हो।

X

X

1953 और 1954 में मित्र ने कई अवसरों पर अमरीका से हथियार देने का अनुरोध किया। ये अनुरोध बुद्धिमत्तापूर्वक अस्वीकार कर दिये गए। इसका मुख्य कारण था कि यह सहायता मित्र और इजराएल के बीच शक्ति-संतुलन को बिगाड़ देती, और इन पड़ोसी देशों के बीच सघर्ष का खतरा बढ़ जाता।

किन्तु 1954 की वसन्त में प्रशासन ने ईराक को सैन्य सहायता देना स्वीकार कर लिया, जिससे न केवल इजराएल के अस्तित्व को खतरा था, वरन् जो अरब देशों के नेतृत्व के लिए मित्र का प्रत्यक्ष विरोधी था।

मित्र ने इस आधार पर विरोध किया कि इस सहायता के द्वारा अमरीका जान-बूझ कर अरब जगत को विभाजित करते का प्रयत्न कर रहा था, और उसने मित्र के हितों की उपेक्षा की थी। इस विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

फरवरी 1955 में तुर्की के साथ ईराक, ईरान और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को जोड़ने के लिए बगदाद संधि की स्थापना की गई। ईरान की खाड़ी की ओर रूस के सैनिक अतिक्रमण को रोकना इसका घोषित उद्देश्य था।

काहिरा में अन्य अरब नेताओं ने इस बात को समझा कि बगदाद संधि के फल-स्वरूप ईराक को कहीं अधिक मात्रा में अमरीकी हथियार दिये जाएंगे। इसके सम्बन्ध

मे नासिर के विरोधों के फिर अस्वीकार किए जाने के बाद, नासिर ने नवम्बर में घोषणा की कि मिस्र ने सोवियत रूस के साथ सैन्य समझौता कर लिया है।

इस कारण-कार्य सम्बन्ध में, निश्चय ही मात्र यही तत्त्व नहीं थे। किन्तु ये घटनाएँ एक घटनाक्रम का अंग थी, जिसका अन्त मिस्र पर इंगलिस्तान-फ्रांस-इजराएल के आक्रमण से हुआ।

इस अवधि में, ईराक को काफी बड़ी मात्रा में आर्थिक और प्राविधिक सहायता भी दी जाती रही। इस कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन्होंने कांग्रेस को सूचित किया कि ईराकी सरकार को तेल से होने वाली आय के साथ यह सहायता प्राप्त हो जाने से ईराक की आर्थिक सफलता निश्चित प्रतीत होती थी।

किन्तु इस बात की कोशिश बहुत कम की गई कि हमारे संयुक्त प्रयत्नों से ईराक के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो। इस प्रकार, नए सिंचाई कार्यक्रमों से भूस्वामियों की आमदनी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन किसानों को बहुत कम लाभ हुआ।

ईराक का कुल राष्ट्रीय उत्पादन तेजी से बढ़ा। लेकिन विलास-सामग्री के आयात पर रोक नहीं लगाई गई, प्रगतिशील कराधान व्यवस्थाएँ आरम्भ नहीं की गई, और भूमि-सुधार स्थगित कर दिये गए। फलस्वरूप आय में वृद्धि होने से केवल अमीर और गरीब के बीच की विस्फोटक खाई और भी अधिक बढ़ गई। जैसी हमने से वहुतों ने भविष्यवाणी की थी, 1958 की गर्मियों में विस्फोट हुआ, और कर्नल कासिम की सरकार सत्ताह्वृष्ट हुई तथा साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा।

अस्पष्ट सैनिक सुरक्षा की तलाश में जब हम राजनीतिक, आर्थिक और स्थानीय यथार्थों की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे हितों का क्या हाल होता है, इसका यह एक उदाहरण है।

ईराक के उदाहरण और अन्य उदाहरणों से एक और भी सवाल उठता है। जो प्रतिमान मीने सुझाए हैं, उनका प्रभाव ऐसे देशों के नेताओं पर क्या पड़ेगा, जो अभी उनके अनुरूप तैयार नहीं हैं, किन्तु जिनको सद्भावना हमारे लिए आवश्यक है? जो राष्ट्र उपयुक्त नहीं सिद्ध होते, क्या वे मेरे द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप मानकर उससे दृष्ट होंगे?

अगर हम अपनी सहायता का उपयोग इन राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिए करेंगे, कि वे शीत-युद्ध में हमारा अनुसरण करें, तो अनिवाय ही रोष उत्पन्न होगा। लेकिन स्वयं भारी कर अदा करने वाले अमरीकी लोगों की यह माँग क्या अनुचित है कि उनकी सहायता का ईमानदारी और कौशल के साथ उपयोग किया जाय?

एशिया और अफ्रीका में स्वयं अपने व्यावहारिक अनुभव के फलस्वरूप मेरा विश्वास है कि जो सिद्धान्त मीने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सरलता से स्वीकार कर लिया जाएगा, अगर उन्हें कुशल अमरीकी वाक्ताकार प्रस्तुत करें, और उनके पीछे कांग्रेस के दृढ़ आदेश का बल हो।

राष्ट्रीय राजधानी में एक प्राधुनिक अस्तित्व इगरा एक उदाहरण हो सकता है जिसमें डाक्टरों और नर्सों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ हों, और गाँवों के लिए बिना भरती किए उपचार की व्यवस्था हो। या किसी विदेशविद्यालय का विस्तार और सुधार या कोई कृषि प्रयोग विद्यालय भी हो सकता है।

मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि किसी प्रभार की प्राथिक गढ़ायता— जिसे सरकारी तौर पर 'प्रतिरक्षा समर्पण' या 'विशेष सहायता' कहा जाता है— प्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, विशेष प्राथिक कारणों में, सैन्य सहायता की पुष्टि के रूप में, या किसी सैनिक षड्युक्त के उपयोग के बदले में दिये गए किराए के रूप में, आवश्यक होती है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी सहायता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी गई है।

पारस्परिक सुरक्षा में साझेदारी निहित है। प्रभावी होने के लिए, इनमें दोनरफा सम्बन्ध होना चाहिए। विदेश स्थित अमरीकी प्रतिनिधियों को इनके लिए अधिक दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए कि सैन्य क्षेत्र में पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धी हमारे प्रयत्न सचमुच साझेदारी के आधार पर चलें।

X

हमारे कई विदेशी सहायता कार्यक्रमों के नियोजन और प्रशासन के सम्बन्ध में मेरी आलोचनाएँ सैन्य सहायता और प्राथिक सहायता, दोनों के बारे में हैं। इराक एक उदाहरण है। वहाँ के घटनाक्रम के संक्षिप्त पुनरावलोकन से ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता प्रवृत्त हो जाती है जो सैन्य-अभियुक्त कम हो, और यथार्थ के अधिक अनुकूल हो।

X

X

1953 और 1954 में मित्र ने कई अवसरों पर अमरीका से हथियार देने का अनुरोध किया। ये अनुरोध बुद्धिमत्तापूर्वक अस्वीकार कर दिये गए। इसका मुख्य कारण था कि यह सहायता मित्र और इजराएल के बीच शक्ति-सन्तुलन को बिगाड़ देती, और इन पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ जाता।

किन्तु 1954 की वसन्त में प्रशासन ने इराक को सैन्य सहायता देना स्वीकार कर लिया, जिससे न केवल इजराएल के अस्तित्व को खतरा था, वरन् जो अरब देशों के नेतृत्व के लिए मित्र का प्रत्यक्ष विरोधी था।

मित्र ने इस आधार पर विरोध किया कि इस सहायता के द्वारा अमरीका जान-बूझ कर अरब जगत को विभाजित करते का प्रयत्न कर रहा था, और उसने मित्र के हितों की उपेक्षा की थी। इस विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

फरवरी 1955 में तुर्की के साथ इराक, ईरान और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को जोड़ने के लिए बगदाद संधि की स्थापना की गई। ईरान की खाड़ी की ओर रूस के सैनिक प्रतिक्रमण को रोकना इसका घोषित उद्देश्य था।

काहिरा में अरब अरब नेताओं ने इस बात को समझा कि बगदाद संधि के फल-स्वरूप इराक को कहीं अधिक मात्रा में अमरीकी हथियार दिये जाएँगे। इसके सम्बन्ध

विदेशी सहायता के वितरण में प्रतिमानों की आवश्यकता

में नासिर के विरोधों के फिर अस्वीकार किए जाने के बाद, नासिर ने नवम्बर में घोषणा की कि मिस्र ने सोवियत हस के साथ सैन्य समझौता कर लिया है।

इस कारण-कार्य सम्बन्ध में, निश्चय ही मात्र यही तत्त्व नहीं थे। किन्तु ये घटनाएँ एक घटनाक्रम का भग थी, जिसका अन्त मिस्र पर इगलिस्तान-फ्रांस-इजराएल के आक्रमण से हुआ।

इस अवधि में, ईराक को काफी बड़ी मात्रा में आर्थिक और प्राविधिक सहायता भी दी जाती रही। इस कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन्होंने कांग्रेस को सूचित किया कि ईराकी सरकार को तेल से होने वाली आय के साथ यह सहायता प्राप्त हो जाने से ईराक की आर्थिक सफलता निश्चित प्रतीत होती थी।

किन्तु इस बात की कोशिश बहुत कम की गई कि हमारे संयुक्त प्रयत्नों से ईराक के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ ही। इस प्रकार, नए सिंचाई कार्यक्रमों से भूस्वामियों की आमदनी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन किसानों को बहुत कम लाभ हुआ।

ईराक का कुल राष्ट्रीय उत्पादन तेजी से बढ़ा। लेकिन विलास-सामग्री के आयात पर रोक नहीं लगाई गई, प्रगतिशील कराधान व्यवस्थाएँ आरम्भ नहीं की गईं, और भूमि-सुधार स्थगित कर दिये गए। फलस्वरूप आय में वृद्धि होने से केवल अमीर और गरीब के बीच की विस्फोटक खाई और भी अधिक बढ़ गई। जैसी हममें से बहुतों ने भविष्यवाणी की थी, 1958 की गर्मियों में विस्फोट हुआ, और कर्नेल कासिम की सरकार सत्ताह्व हई तथा साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा।

अस्पष्ट सैनिक सुरक्षा की तलाश में जब हम राजनीतिक, आर्थिक और स्थानीय यथार्थों की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे हितों का क्या हाल होता है, इसका यह एक उदाहरण है।

ईराक के उदाहरण और अन्य उदाहरणों से एक और भी सवाल उठता है। जो प्रतिमान मैंने सुझाए हैं, उनका प्रभाव ऐसे देशों के नेताओं पर क्या पड़ेगा, जो अभी उनके अनुरूप तैयार नहीं हैं, किन्तु जिनको सद्भावना हमारे लिए आवश्यक है? जो राष्ट्र उपयुक्त नहीं सिद्ध होते, क्या वे मेरे द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप मानकर उससे घृणित होंगे?

भगर हम अपनी सहायता का उपयोग इन राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिए करेंगे, कि वे शीत-युद्ध में हमारा अनुसरण करें, तो अनिवार्य ही रोप उत्पन्न होगा। लेकिन स्वयं भारी कर अदा करने वाले अमरीकी लोगों की यह भाँग क्या अनुचित है कि उनकी सहायता का ईमानदारी और कौशल के साथ उपयोग किया जाय?

एशिया और अफ्रीका में स्वयं अपने व्यावहारिक अनुभव के फलस्वरूप मेरा विद्वान्त है कि जो सिद्धान्त मैंने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सरलता से स्वीकार कर लिया जाएगा, भगर उन्हें कुशल अमरीकी वार्ताकार प्रस्तुत करें, और उनके पीछे कांग्रेस के हड़ घोषित का बल हो।

मस्तुन., मुझे विश्वास है कि अधिकांश सरकारों को यह बात समझाई जा सकती है कि वे कमोदिमी समय उनके दीर्घ-कालीन हित में धारदारक है। उनमें में कई सरकारों ऐसे प्रतिमानों का स्थापन करती है, क्योंकि वे समय आने देग में प्रतिक्रिया-यारी तयों को सम्भालने के लिए उनका उपयोग कर सकती हैं, कि वे रचनात्मक सुधारों में बाधाएं डालना बन्द करें।

अतः, मेरा सुझाव है कि अपनी प्राथमिक महत्त्वता और विनाश कर्तों को हम जिन आधार पर गिराए करना चाहते हैं, उसे पारम्परिक सुरक्षा विधेयक में स्पष्ट निम्नित किया जाय।

जो नई दिशा और धारद्व मीने प्रस्तुत किया है, बांधेग अगल उसे स्वीकार कर लेती है, तो हम दुनिया को दिगा देगे कि हमारा पारम्परिक सुरक्षा कार्यक्रम केवल शीत-युद्ध को एक अस्थायी बाल नहीं है, और यह कि हमने एक हड़, दीर्घ-कालीन कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को सर्वत्र, बढ़ती हुई समृद्धि और शान्ति की दुनिया में, स्वयं अपनी चुनी हुई सरकारों के अन्तर्गत रहने का अवसर प्रदान करना है।

विदेशों में भोजन बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव

सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति की एक सुनवाई का विषय यह था कि अमरीकी खेती के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग दुनिया के भूखे लोगों को भोजन देने के लिए कैसे किया जा सकता है। 8 जुलाई, 1959 को श्री वॉल्स ने उसमें यह सुझाव रखा कि विकासशील राष्ट्रों में बहुसंख्यक 'भोजन बैंक' स्थापित किये जाएँ।

भविष्य के इतिहासकार जब मुड़कर हमारी पीढ़ी पर नज़र डालेंगे तों उन्हें बहुतेरे आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई देंगे, किन्तु इससे अधिक विरोधाभासपूर्ण बात कोई और नहीं होगी कि संयुक्त राज्य अमरीका के पास तयाकथित 'फालतू' कृषि उत्पादनों का विशाल भंडार है, जिसका मूल्य लगभग दस अरब डालर है, जबकि दुनिया में भूख और राजनीतिक संकट व्याप्त है, और शान्ति के लिए ठीक प्रयत्न करने की बड़ी ज़रूरत है।

मध्य बीसवी सदी के इस विन्दु पर, हममें अपनी निधियों को 'बोझ' कहने की प्रवृत्ति है, जबकि दुनिया के अधिकांश मनुष्यों के पास भोजन की कमी है, और लगभग हर देश को या तो आयात करने पड़ते हैं, या भूखे रहना पड़ता है।

भोजन और वस्त्र, सोवियत रूस की सबसे बड़ी अकेली आर्थिक समस्या रही है। आज जो समस्या घायद चीन के साम्यवादी शासन को तोड़ सकती है, वह भोजन की समस्या है—प्रति परिवार के लिए 1'7 एकड़ भूमि के आधार पर वे अपनी आबादी को भोजन प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हैं कि अपनी विशाल क्षमता को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर अपने सारे भोजन का करें क्या ?

एक अर्थ में आज हमारे सामने विश्व स्तर पर बहुत कुछ वही स्थिति है जो 1933 के अमरीका में थी, जब एक करोड़ साठ लाख बेकार मजदूर जिनमें से बहुतेरे भोजन के अभाव से पीड़ित थे, रोड़ ऐसी दूकानों के सामने से गुजरते थे, जिनमें भोजन सामग्री भरी हुई सड़ रही थी, लेकिन वे उस सामग्री को खा नहीं सकते थे, क्योंकि, अर्थशास्त्रियों के शब्दों में, 'अर्थशास्त्र के लौह नियम' इसमें बाधक थे।

अन्ततः, हमने एक ऐसा शासन चुना जिसने इस स्थिति की अनैतिकता, और अर्थयार्थता को समझा। बिना सचमुच यह जाने हुए कि क्या करना चाहिए, कल्पना-

शील रीति से हलों की तलाश करते हुए, कभी एक और कभी दूसरा कदम उठाकर हमने प्रयोग करना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे हमने 'अर्थशास्त्र के लोह-नियमों' को पुनः निरूपित करना, और बाहुल्य के साथ आवश्यकता का मेघ विठाना सीख लिया।

आज हमारे सामने दुनिया के पैमाने पर वैसी ही समस्या है, जिसमें दो तिहाई मानव-जाति के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, जबकि हम भोजन के भंडारों को लेकर चिन्तित हैं, जिनके लिए 'कोई बाजार नहीं' है। फिर भी मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में शायद हम विभ्रम की इस स्थिति की ओर वैसी ही आश्चर्य भरी दृष्टि से देखें, जैसे आज हम 1933 की स्थिति की ओर से देखते हैं, जब बहुलता के बीच अमरीकी लोग भूखे रहते थे।

किसी भी दशा में, अब समय आ गया है कि हम अपने कथित दोषों को अपने लिए हितकारी बनाना प्रारम्भ करें। आपकी समिति के समक्ष जो विधेयक है, उसका यही गुण है कि हमें ऐसा करने के योग्य बनाने में यह बड़ा सहायक होगा।

विधेयक¹ के शीर्षक S की रचनात्मक, निर्माणात्मक सभावनाओं ने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय 'भोजन बैंक' का यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

विभिन्न देशों में भोजन के आरक्षित भंडार बनाने के विचार पर कई वर्षों से हमारे अपने शासन में संयुक्त राष्ट्रों में और अन्यत्र चर्चा होती रही है। किन्तु वाफ़ी बड़े पैमाने पर अभी तक इस समस्या का सामना नहीं किया गया है।

आज हम जानते हैं कि न केवल नैतिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी, हमारे पास समय सीमित है। हमारी संचित वस्तुओं का अंगर उपयोग नहीं होता तो वे व्यर्थ जाती हैं। वस्तुएँ खराब न होने पाएँ, यह एक स्थायी और बढ़ती हुई समस्या है। इस वर्ष भी फसल अच्छी होने की संभावना से, दीर्घ ही हमारे सामने भण्डार करने की नई समस्या खड़ी होगी।

नाटकीय स्थितियों में नाटकीय हलों की आवश्यकता पड़ती है। अब कार्यवाही करने का समय आ गया है।

मेरा सुझाव है कि हम अपने सारे फ़ालतू अनाज का आधा भाग लेकर उसे विदेशों में पूर्वनिश्चित भंडारों में रख दें। करोड़ों लोगों के लिए यह अकाल और रोग के विरुद्ध प्रत्यक्ष और विश्वसनीय सुरक्षा होगी और हमारे इस दुःखनिश्चय का गभीर प्रदर्शन होगा कि जब हमारे पास इतना फ़ालतू भोजन है, तो कोई व्यक्ति भूखा न मरे।

ऐसे तीस या चालीस भंडार अकेले भारत में ही रने जा सकते हैं, और दस अन्य पाकिस्तान में। अन्य भंडार मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, इंडोनीशिया, और दक्षिण अमरीका के कुछ हिस्सों में रने जा सकते हैं।

1. 1959 का इन्दी अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए भोजन विधेयक।

हमारी ओर से ऐसे रचनात्मक प्रयत्न से हमें धन की भी वचत हो सकती है। जो सारे आंकड़े मिला देखे हैं, उसके अनुसार फालतू वस्तुओं को किसी भी मात्रा में विदेश भेजने पर जो खर्च आएगा, वह उन वस्तुओं को इस देश में तीन वर्ष तक संचित करके रखने के खर्च से काफी कम होगा। इस पद्धति से होने वाली वचत, दूसरे वर्ष के बाद बहुगुणित होने लगेगी।

अतः हम अपना आधा अनाज इन विदेशस्थित 'भोजन बैंकों' में रख दें। हम इस बात का ध्यान रखें कि ये बैंक अच्छी तरह निर्मित किए जाते हैं, ताकि अनाज खराब न होने पाए जैसे वह इस देश में सुरक्षित रखा जाता है। फिर हम सम्बन्धित सरकारों के साथ समझौते करें जिसमें दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार स्थानीय उपयोग के लिए यह अनाज निकाला जा सके।

फसल का सचमुच खराब हो जाना, एक स्वाभाविक शर्त होगी। दूसरी शर्त होनी चाहिए अभाव के फलस्वरूप भोजन के मूल्यों का बहुत बढ़ जाना, जिसके फल स्वरूप भोजन के सम्बन्ध में संकटपूर्ण महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाय। तीसरी एक शर्त अपर्याप्त पोषण की विशिष्ट मात्राओं से सम्बन्धित हो सकती है।

सारी दुनिया में स्थापित, अमरीका द्वारा चलाये गए 'भोजन बैंकों' की पूरी शृंखला, वस्तुतः अमरीका के विशाल भोजन भंडारों को भूखे लोगों तक पहुँचाने वाली धारा बन जाएगी। अगर इस भंडार को उन तक पहुँचाने के लिए, अधिक अमरीकी जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो अभी बेकार पड़े हैं, तो हमें इस अवसर का स्वागत करना चाहिए।

इस विधेयक के शीर्षक 5 में प्रस्तुत विचार का उपयोग करके और भेरे प्रस्ताव के अनुसार उसका विस्तार करके, हम करोड़ों व्यक्तियों को यह ठोस आश्वासन प्रदान करेंगे कि वे और उनके बच्चे भुखमरी, अकाल, और रोग के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, जिससे मनुष्य इतिहास के आरम्भ से अब तक हमेशा ग्रस्त होते रहे हैं।

हमारे लिए संभव ऐसे कार्य बहुत कम हैं, जो अमरीकी विदेश-नीति को एक नया विध्यात्मक रूप प्रदान करने में इससे अधिक उपयोगी हों।

लोकतांत्रिक विकास का मर्म : ग्राम विकास

श्री बौलस का कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली मनुष्य जाति की गरीब और उपेक्षित बहुसंख्या तक र्धसर्धी सदी के लाभों को पहुँचाना आर्थिक विकास सहायता का एक प्राथमिक लक्ष्य बन जाना चाहिए। भूमि रक्षण सम्बन्धी व्हाइट हाउस सम्मेलन के समक्ष एक भाषण से, वार्शिंगटन, 24 मई, 1962।

अमरीकी इतिहास के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में से दो को सातान्द्री इस वर्ष पटती है, ऐसे दस्तावेज जिनके फनस्वरूप यह निश्चित हो गया कि अमरीकी भूमि का उपयोग सामान्य भलाई के लिए होगा—20 मई, 1862 का होमस्टेड अधिनियम, और 2 जुलाई, 1862 का मॉरिल लैण्ड ग्राण्ट कालेज अधिनियम।

यद्यपि भौतिक प्रगति के सन्दर्भ में, हमारे राष्ट्रीय विकास में इन कानूनो का नाटकीय महत्त्व है, किन्तु इनका सर्वाधिक महत्त्व शायद इसमें है कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया, और ध्यनित की गरिमा में हमारे विद्वानों को गभीरता प्रदान की।

स्वयं अपनी भूमि का स्वामी होने का मनुष्य का अधिकार, और अपने नागरिकों को उपयोगी और उत्पादक मनुष्यों के रूप में शिक्षित करने की शासन की जिम्मेदारी, अमरीका की सुदीर्घ परम्परा का अंग रहे हैं।

परिवार का अपना खेत, काउण्टी का एजेण्ट, गाँव का स्कूल, अपनी सहायता-आप का सामुदायिक सगठन, अधिकतम सत्ता की अधिकतम भलाई के लिए साधनों का उपयोग, और लोगों की सेवा करने वाले विश्वविद्यालय, इन सबका जन्म ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों से हुआ है, जिनकी जड़ें बड़ी गहरी और व्यापक हैं, और जो कई अर्थों में औपनिवेशिक काल से हमारे बीच रहे हैं।

जिसे वे उचित समझते हैं, उसके लिए लड़ने में अमरीकी किसानों ने कभी हिचक भी नहीं दिखाई। शासन के अग्र्याय, अथवा बैंकरो या रेलों के शोषण में विरोध की एक मौलिक धारा हमेशा हमारी ग्रामीण परम्परा की एक विशेषता रही है।

सौ वर्ष पहले हमारे राष्ट्रीय कानूनो में, और अग्र्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में अमरीकी किसान की तत्परता में जिन सिद्धान्तों को अभिव्यक्ति मिली थी, क्या

एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के अधीर, विकासशील राष्ट्रों के लिए भी उनकी कोई सार्थकता है ?

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी सार्थकता है। सचमुच, मैं सतभ्रता हूँ कि एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका में सफल अमरीकी नीति की कुंजी शायद उन्हीं में हो। इस पृष्ठभूमि में हम उम चुनौती पर नजर डालें जो हमारे सामने है।

अधिकांश अमरीकियों के लिए, असममित, चिल्लाते हुए छात्रों और विरोध प्रकट करते हुए औद्योगिक मजदूरों के चित्र, एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका की अशांति को व्यक्त करने वाले प्रतीक होते हैं। लेकिन इन विकासशील महाद्वीपों के भविष्य का निर्णय, दूरस्थ, मिट्टी के बने गाँवों में होने की सम्भावना अधिक है, जहाँ 80 प्रतिशत लोग रहते हैं।

एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका की किसान बहुसंख्या दो कारणों से महत्वपूर्ण है—प्रथम, अपनी संभाव्य राजनीतिक दक्ति के कारण, और दूसरे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अपनी आर्थिक भूमिका के कारण।

जब तक किसी विकासशील देश में तीन चौथाई जनसंख्या को राजनीति में कोई सक्रिय भाग लेने से, और निजी प्रवृत्ति से वंचित रखा जाता है, तब तक वे विध्वंसक कार्यवाही और अशांति के लिए उर्वर भूमि बने रहेगे। जब तक उनमें मात्र अति आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त, और कुछ भी खरीदने की क्षमता का अभाव रहेगा, तब तक सहरी केन्द्रों में औद्योगिक उत्पादन के स्वस्थ विकास की आशा भी नहीं की जा सकती।

बहुतेरे नए उठते हुए देशों में ग्रामीण क्षेत्रों पर सदियों से जमींदारों और महाजनों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व रहा है। अब भी भूमि के लगान में फसल का तीन बटा पाँच (३/५) हिस्सा तक चला जाता है। कर्जों पर सूद बहुधा 30 प्रतिशत वार्षिक से अधिक होता है।

किन्तु अब हर जगह इन स्थितियों को सबल चुनौतियाँ दी जा रही हैं। यह बात फल रही है कि गरीबी और निरक्षरता, अभागे लोगों के लिए ईश्वर का विधान नहीं है, बल्कि ऐसी बुराइयाँ हैं जिनका सामना करके उन्हें समाप्त करना है।

किन्तु प्रगति की रफ्तार को और कम करने में, तथा चुनौती का प्रत्यक्ष सामना करने से नए शासनों को रोकने में, कई तत्व मिल जाते हैं। इनमें तेजी से औद्योगीकरण करने के पक्ष में असंतुलित आग्रह, और लोगों तथा उनकी संस्थाओं का पर्याप्त ध्यान न रखना भी एक है।

निस्सन्देह, आधुनिक समाजों के विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है, और ऐसे विकास को आगे बढ़ाना हमारे आर्थिक सहायता कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारे अपने इतिहास पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाएगा कि औद्योगिक विकास अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। राजनीतिक स्थायित्व वाले समाज के लिए एक ठोस ग्रामीण आधार की आवश्यकता होती है, जो

किसान बहुसंख्या को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा का भंग बनाता है।

अतः हमारे सहायता कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण और ग्रामीण विकास के बीच एक प्रभावी कार्य-सन्तुलन की स्थापना करना है। अन्यथा औद्योगिकीकरण, बिजलीघर, बन्दरगाह और सड़कों पर चाहे जितने अरब डालर खर्च किये जाएँ, हम अपने लक्ष्य में असफल रहेंगे।

यद्यपि विकास की विभिन्न स्थितियों वाले राष्ट्रों की विशिष्ट समस्याओं के बारे में कोई सामान्य निरूपण करना उतरनाक होता है, फिर भी, हमारे अनुभव के अलावा जापान और अन्य देशों के अनुभव से सन्तुलित ग्रामीण विकास के बारे में कुछ नतीजे निकाले जा सकते हैं। इन नतीजों को सात शीपों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :

1. किसी पुराने समाज का आधुनिकीकरण, सर्वोत्तम रूप में भी, एक सीढ़ने वाली प्रक्रिया होती है। अतः तेजी से औद्योगिक विकास करने पर इरु-तुलित आग्रह से ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही राजनीतिक अशांति के घटने के बजाए बढ़ने की संभावना अधिक होती है।

सचमुच, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से अपने-आप राजनीतिक स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। लातिन अमरीका में हमें इसका नाटकीय प्रमाण मिलता है। वहाँ प्रति व्यक्ति कुछ राष्ट्रीय उत्पादन, ब्रेनेजुला में 1000 डालर के उच्च स्तर से लेकर बोलिविया में 55 डालर के निम्न स्तर तक है। किन्तु इन पराकाष्ठाओं के बीच राजनीतिक स्थायित्व का कोई रूप सामने नहीं आता वैंटिस्टा के अधीन क्यूबा में प्रति व्यक्ति औसत आय लातिन अमरीका में दूसरे नम्बर पर थी।

नतीजा साफ है—व्यवस्थित राजनीतिक विकास के लिए केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति और राजनीतिक सुधार भी आवश्यक हैं।

2. अतः भूमि सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम, एक राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकता है। जो किसान स्वयं अपनी भूमि के मालिक नहीं होते, उनके सामने कोई प्रेरणा नहीं होती कि वे बुद्धिमत्तापूर्वक किसानी करें, और अधिक समय तक बकड़ी मेहनत करें, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला ग्रामतीर पर अस्थिर और उदासीन रहता है, बिना भविष्य का विचार किए अपनी जमीन का उपयोग करता है, और जमीन की संभावनाओं को व्यर्थ जाने देता है। उसका अविश्वास और असन्तोष आमतौर पर आसानी से प्रकट हो जाते हैं।

अतः जहाँ अब भी विशाल सामन्ती भूमिपतिरियाँ हैं, वहाँ उनको समाप्त करना होगा, और पुराने मालिकों को मुआवजा देते हुए जमीन का, उसे जोतने वालों के बीच, बँटवारा करना होगा।

3. यद्यपि भूमि के स्वामित्व का बहुत-से लोगों में फैला होना, ग्रामीण समाज में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक है, किन्तु यह उस प्रक्रिया का केवल एक भंग

है। सामुदायिक विकास की एक व्यापक योजना का भी वैसे ही प्राथमिक स्थान है। इसमें एक कृषि विस्तार सेवा भी शामिल होनी चाहिए, जो सुघरे हुए बीज, औजार, उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाएँ आदि का प्रयोग आरम्भ करने में, और सिंचाई के जल का अधिक प्रभावकारी उपयोग कराने में सहायक हो।

अगर भूमि सुधार के साथ-साथ इस प्रकार का सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, तो लगभग निश्चित रूप में उत्पादन का स्तर गिरेगा। ऐसा कार्यक्रम चलाने पर, जापान की भाँति, प्रति एकड़ उत्पादन लगभग निश्चित ही बढ़ेगा।

बिना मूल्य दिये गए स्थानीय श्रम की सहायता से सड़कों और स्कूलों का निर्माण करने के लिए, स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए, और गाँव स्वशासन को विकसित करने के लिए आगे बढ़ने में सामुदायिक विकास प्रयत्नों में स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, वास्तविक विकास की अपेक्षा उसकी उपलब्धि के साधन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वयं गाँव वालों द्वारा बनाई गई स्कूल की फर्ची इमारत, या स्थानीय सड़क, हर सम्बन्धित व्यक्ति को समुदाय के निर्माण में भाग लेने की एक नई प्रेरणाप्रद भावना प्रदान करती है। हमारे अपने ग्रामीण विकास की भी यही परम्परा है।

अतः, बिना स्थानीय सहयोग के सरकार द्वारा बनाई गई सड़क या स्कूल में ज्यादा अच्छे होने पर भी, उनकी अपेक्षा गाँव के व्यवस्थित राजनीतिक विकास में ऐसी स्थानीय योजनाओं का योग कहीं अधिक होगा।

4. ग्रामीण सामुदायिक विकास में व्याज की नीची दरों वाली ग्रामीण ऋण व्यवस्था एक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसके फलस्वरूप किसान सूदखोर महाजनों से पीछा छुड़ा सकते हैं, और ऊर्वरक या खेती के मामूली औजार खरीदने के लिए उचित शर्तों पर धन प्राप्त कर सकते हैं।

5. लोकतांत्रिक आधार पर क्रय-विक्रय सहकारिताओं का भी संगठन होना चाहिए। ऐसी सहकारिताएँ बिचबूँदों के मुनाफों को कम करने में सहायक होंगी, और उपभोक्ता मूल्य का ज्यादा बड़ा हिस्सा किसान-उत्पादक को मिल सकेगा। जापान में ऐसी उन्निस हज़ार सहकारी संस्थाएँ संगठित की गई हैं।

6. विकासशील देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे हमारे संयुक्तराज्य सेना इंजीनियर दल के नमूने पर इंजीनियरों के दस्ते संगठित करने में अपने सैन्य बजट का कुछ हिस्सा लगायें।

ये दस्ते पुलों, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में महत्वपूर्ण विकास कार्य कर सकते हैं, और साथ ही उन ग्रामीणों के साथ निकट सम्बन्ध भी स्थापित कर सकते हैं, जिनकी स्वाधीनता की वे रक्षा करना चाहते हैं।

7. स्वस्थ ग्राम समाजों का निर्माण करने में विकासशील राष्ट्रों की सहायता

करते हुए हम धमकीयों को माद रखा था। भावित कि मेरी मादरभी हमारे मादरे ही सारा अनुभव उनके लिए साधक गरी है।

उदाहरण के लिए, अधिकांश धमकीयों में गरी दृष्टि कीमती और बेनीस मशीनों का उद्वेग मुद्रण भव की साधन प्रदान है, यदि एक उदाहरण को बहाल गरी।

संशयका कम साधनी मादरे देनी में, कि सार-सहित-सहित और सरोर के कुल गुरु सार, मेरी की मशीनों का योग मद्रसूचक होगा। वेकिट विन्मुद्रा, सति-गत श्री मंका, और अधिकांश अन्य विद्यमानों सार में, गरी साधनी भव की साधन सादर-सहा में अधिक है, मेरी का काम मादरे को-सारी में, और वेन का भवे की मद्र में, उदाहरण कम सारी के साधन विद्यता का गवता है।

मेरी, सार, और सति-सहित का अधिकांश उदाहरण उदाहरण और सित के और या सार एक-एक के सारी में होगा है, गरी हर गीसा सैमे ही उदाहरण का है सैमे सितो निरी मशीन में।

^

x

x

सदरि हमने मुद्रण सारी की है, विन्मु और भी बहूत कुल करता है। एविता, धमकीका और साधन धमकीका के साधनी सारी में परिचालन की साधन साधनी है, और उममे उदाहरण गरी विद्यता का गवता।

यह गिनविहर विचारणीय धमकीयों के सामने एक निर्मादक प्रश्न रगनी है—कदा हम साने मुद्र के साधनीयं साधनीयारी परिचालनों में सधनामक साधनीयं सन साने हैं, सैमे परिचालन जिनका अधिकांश विशेषाधिकार मुद्रण गीव भरण विरोध करेगे, सतिन जो अधिकांश मनुष्य-जाति को कुल अधिक भोजन, कुल अधिक सार, बीमार सन्धे के लिए डाक्टर, और निरी प्रविष्टा की भावना की साधनी प्रदान करेगे हैं?

सारी दुनिया में जागते हुए विचारनों की मना-सिधति, बहूत पहले गिरी गई एक-विन साधनी हैम की एक सतिता में सारा दृष्टि है, जो उद्वेगने सित के प्रसिद्ध गिन 'कुदाय लिए मनुष्य' को देगकर सितो सौ।

“सदियों के सोक से दवा यह भुचता है

“सपने कुदाय पर और देगता है भूमि की,

“गुगो का सून्य उसके चेहरे पर,

“और उसकी पीठ पर दुनिया का सोक।

“सिसने उसे सानन्द और निरासा के प्रति जड बनाया,

“जो सोक नहीं करता और कभी सासा नहीं...?”

“सो, सभी देशों के मालिको, स्वामियो और सामको,

“भविय्य इस सतिता का सामना सैमे करेगा?

“उस सही इसके निर्मम प्रश्न का उत्तर सैमे देगा

“जब विद्रोह की साधियाँ सभी देशो को हिला देंगी?

“तब राज्यों और राजाओं का क्या होगा—

“उनका जिन्होंने उसे आज जैसा बनाया है—

“जब उसका मौन आतंक दुनिया का फँगला करने को उठेगा

“सदियों की खामोशी के बाद ?”

हम भर-पेट खाने वाले अमरीकियों को इस मनुष्य से क्या कहना है ? क्या हमसे उसे समझने की, और उसकी चुनौती का प्रभावशाली उत्तर देने की क्षमता है ? हमारी शताब्दी के अगले दशक का रूप बहुत कुछ इन प्रश्नों की दिये गए हमारे उत्तरों से निर्मित हो सकता है ।

तीसरा भाग

विकासशील महाद्वीप

एशिया और अफ्रीका की भांति, लातिन अमरीका में असली चुनाव नागरिकता और दासता के बीच, आशा और निराशा के बीच, व्यवस्थित राजनीतिक विकास और रक्तमय उथल-पुथल के बीच है। इस चुनाव को समझने में, या नेतृत्व स्थापित करने की चेष्टा कर रहे सशक्त नए तत्वों का समर्थन करने में हमारी असफलता के परिणाम भयंकर होंगे।

22 नवम्बर, 1959

तेइस

एक साम्यवादी सह-यात्री को उत्तर

जुलाई, 1952 में हिन्दुस्तान के वामपक्षी साप्ताहिक 'विलटूज' को दी गई एक अनोखी भेंट में राजदूत वॉल्स ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिनमें तात्कालिक अमरीका-विरोधी साम्यवादी दल-नीति, और अमरीकी 'हस्तक्षेप' के सम्बन्ध में एशिया की कुछ गंभीरतम आशंकाएँ परिलक्षित होती हैं।

विलटूज सवादाता : भारत के लिए जो अमरीकी आर्थिक सहायता आपने आरम्भ कराई है, उसका उद्देश्य क्या है ? क्या यह परोपकार है, या कि इसका उद्देश्य अमरीकी विदेश-नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है ?

श्री वॉल्स : आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक बात कह दूँ : अगर हिन्दुस्तान का हर साम्यवादी कल अपनी सदस्यता छोड़ दे, तो भी हिन्दुस्तान की समस्याएँ बनी रहेंगी। साम्यवादियों ने इन समस्याओं को जन्म नहीं दिया, यद्यपि वे अब उनसे लाभ उठाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं।

यहाँ या अन्यत्र कहीं भी साम्यवाद का सवाल उठने के बहुत पहले से अमरीकी लोग चर्चों, धर्मादा संस्थाओं और अन्य निजी साधनों से हिन्दुस्तान को सहायता भेजते रहे हैं। अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने के लिए, और हिन्दुस्तानी लोगों के लिए भोजन और दवाओं का मूल्य चुकाने के लिए, करोड़ों डालर यहाँ अमरीकियों द्वारा निजी तौर पर भेंट के रूप में यहाँ भेजे गए हैं।

लगभग दस लाख डालर मूल्य का भोजन और दवाएँ इस वर्ष भेंट के रूप में आई हैं। निजी साधनों से, हिन्दुस्तानी अस्पतालों के लिए भेंट के रूप में सत्रह अस्पतालों का निर्माण भेजा गया है। इनके बारे में कोई दिखावा या प्रचार नहीं किया गया, और सहायता करने के अतिरिक्त इनके पीछे कोई मंशा नहीं रही।

जहाँ तक अमरीकी सरकार की सहायता का सम्बन्ध है, हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दुस्तान अगले कुछ वर्षों में एक ऐसी बात प्रमाणित कर सकेगा जो अभी तक कभी भी साफ तौर पर प्रमाणित नहीं हुई—कि एक अल्पविकसित देश में लोकतांत्रिक शासन न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र चोट का अधिकार, बोली की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकता है, वरन् जीवन-

स्तरों को, और खेती के उत्पादन को बड़ा भी सकता है, और इस्पात, बिजली रसायन, और अन्य उद्योगों के विस्तार को नीव भी रख सकता है।

अगर एशिया में लोकतंत्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता, तो अन्ततः एशिया में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। परीक्षण का मुख्य स्थान यहाँ हिन्दुस्तान में है। अतः अगर हिन्दुस्तानी लोगों के महान् प्रयत्नों की सफलता के लिए हम अमरीकी लोग कुछ कर सकते हैं, तो उसे आवश्यक करेंगे यही हमारा उद्देश्य है।

ब्लिट्ज सवाददाता : क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि प्राविधिक सहयोग प्रशासन और चतुःसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अत्यल्प रकमें प्रदान की गई हैं, उनसे भारत के आर्थिक विकास को कोई सारभूत सहायता मिलेगी? क्या यह कहना प्रतीत होगा कि यह थोड़ी-सी आर्थिक सहायता अधिक से अधिक एक प्रचार सूत्र है?

श्री वॉलन : इस पिछले वर्ष जनवरी से 30 जून तक के बीच में खर्च करने के लिए पिछले जनवरी में हमने जो रकम स्वीकार की थी, वह अत्यल्प नहीं है—यह रकम 5 करोड़ 40 लाख डालर है। इस धन से अब एक लाख टन उर्वरक की व्यवस्था हो रही है, इसकी सहायता से 2,200 नलकूप खोदे जा रहे हैं, जिनसे लगभग आठ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, जो इतिहास में नलकूपों का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और इसके द्वारा हिन्दुस्तान में मलेरिया को खत्म करने की और बड़ा कदम उठाने के लिए डी० टी० टी० की व्यवस्था हो रही है।

हमारा अमरीकी सहायता कार्यक्रम छोटे औजारों के विनिर्माण के लिए लगभग चालीस-पचास हजार टन इस्पात की भी व्यवस्था करेगा। यह हिन्दुस्तान में मछली पकड़ने के फन्धे का आधुनिकीकरण करने में सहायता के लिए काफी बड़ी गुरुप्राप्त करेगा। यह आपकी पहली बड़ी नदी घाटी विनास योजनाओं के लिए मिट्टी हटाने के औजारों और बुनडोत्रर प्रदान करेगा, और अन्य कई योजनाओं में सहायक होगा।

कुछ उर्वरक आ गया है, डी० टी० टी० आ गया है, भारतीय ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए जीप गाड़ियाँ इंग्लैण्ड में आने लगेंगी। इन सभी योजनाओं में, निस्सन्देह, हमारे धन के मुद्दाबत्ते पर हमें निया गया आश्वासन अपना खर्च भी है। विदेश में यारोशी गई वस्तुओं की अभावगी हम आपकों में करते हैं। आप स्थानीय सामग्री, श्रम, आदि की व्यवस्था करते हैं।

नती, मैं इसे 'आयल्प' प्रयोग नहीं कह सकता, और यह समाचार कि हिन्दुस्तान सोवियत-विश्व युद्ध में, गणक और गनिमीय रीति में अपनी जनता की सम्म्याएँ हल करने के लिए कदम उठा रहा है, प्रचार नहीं है। यह एक बठोर तथ्य है, त्रिगे साम्प्रदायी मित्र नहीं करने।

ब्लिट्ज सवाददाता : क्या आपको है कि अमरीकी सहायता कार्यक्रम का सारा आच्छ एक लेनिन्टर देश के रूप में हिन्दुस्तान के विकास पर है? भारत के औद्योगिक विकास पर और क्यों नहीं दिया जा रहा?

श्री वील्स : यह एक उचित प्रश्न है। अमरीका में मेरे बहुतेरे मित्र भी यही सवाल उठाते हैं। स्थिति यह है।

1947 में विभाजन के फलस्वरूप, भोजन और कपास पैदा करने वाली कुछ सर्वोत्तम भूमि हिन्दुस्तान से छिन गई। फलस्वरूप, अब उसे लोगों को पर्याप्त भोजन देने के लिए प्रति वर्ष तीस से पचास लाख टन तक अनाज खरीदना पड़ता है, और अपनी कपास मिलों की उरुरत पूरी करने के लिए प्रति वर्ष पन्द्रह लाख से अधिक कपास की गाँठें खरीदनी पड़ती हैं।

हिन्दुस्तान का योजना कमीशन, जिसने पंच वर्षीय योजना तैयार की है, अनुभव करता है कि गेहूँ, अन्य भोजन सामग्री, और कपास में आत्म निर्भर होना हिन्दुस्तान की पहली समस्या है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के अन्य अध्येता भी इससे सहमत हैं।

पिछले वर्ष केवल अमरीका से ही तीस लाख टन अनाज आया था। इस अनाज का मूल्य चुकाने के लिए हिन्दुस्तान को 60 करोड़ डालर के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इस बड़ी रकम का लगभग एक तिहाई हिन्दुस्तान को अमरीका से कर्ज लेना पड़ा, जिसकी अदायगी 1957 से आरम्भ करके तीस वर्षों में करनी होगी।

इस प्रकार, रेलों, इस्पात के कारखानों, रसायन उद्योगों का निर्माण करने में खर्च होने के बजाए, भारत को विदेशी मुद्रा के बड़े भाग को भोजन का आयात करने के लिए खर्च करना पड़ता है, जो लोगों को जीवित रखने के लिए, और वह भी अपेक्षितानिम्न स्तरों पर जीवित रखने के लिए आवश्यक है। अगर हिन्दुस्तान अगले कुछ वर्षों में पर्याप्त भोजन और कपास पैदा कर सके, तो इस विदेशी मुद्रा का उपयोग इस्पात के कारखाने, छोटे विद्युत-पंथों के कारखाने, और नई परिवहन व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए, और देश की अन्य मौलिक विकास आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

यही कारण है कि आपके भारतीय आर्थिक नियोजन करने वालों का विश्वास है कि खेती में मुद्धार पहला आवश्यक कदम है, और यह कि औद्योगिक विकास दूसरा कदम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वे सही हैं।

ब्लिट्ज संवाददाता : क्या ऐसा हो सकता है कि हिन्दुस्तान की सहायता के लिए ज्यादा बड़ी रकमें स्वीकार हो सकें, इसके पहले अमरीकी कांग्रेस इस बात का अधिक स्पष्ट प्रमाण चाहती है कि जल्दी या देर से हिन्दुस्तान अमरीकी विदेश-नीति को आशाएँ पूरी करेगा ?

श्री वील्स : अगर हम कोशिश करें, तो भी हिन्दुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश को खरीद नहीं सकते, और हमें इसकी कोशिश भी नहीं करनी। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में हिन्दुस्तान की सहायता करना चाहते हैं। इसके बदले में हम हिन्दुस्तान से यह नहीं कहते हैं कि वह हमसे सहमत हो या हमारे साथ मतदान करे। कभी वह करेगा, कभी नहीं करेगा।

मतभेद होंगे, और इनमें से कुछ मतभेद हम दोनों के लिए अच्छे भी हो सकते

है। हमारी मुख्य रुचि इसमें है कि भारतीय लोग एक ऐसे समाज में विकास और समृद्धि प्राप्त करें, जिसमें व्यक्तिगत और मानवी स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहे। हमारा विचार है कि हिन्दुस्तान इसमें सफल होगा।

विन्ट्रुज सवाददाता : आपने पिछले वर्षों में एशिया में घरबों डालर लगाए हैं। फिर भी, सारे एशिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें अमरीका के प्रति कृतज्ञता की भावना हो। इस अन्तर्विरोध, या उलटे घरर का क्या कारण है ?

श्री बोल्स . मैं फिर कह दूँ कि हम हिन्दुस्तान में या अन्यत्र कहीं कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं करते। किन्तु, अगर आपका मतलब यह है कि एशिया के लोग सामान्यतः अमरीका के प्रति मित्रता का भाव नहीं रखते, तो आपको अपनी सूचना का क्षेत्र अधिक व्यापक बनाना चाहिए। मैंने भारतीय लोगों को भावपूर्ण, मिलनसार और मित्रतापूर्ण पाया है। मैंने हर जगह इस मित्रता का अनुभव किया है, जिसमें वे तीस विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, जहाँ मैं बोला हूँ।

मैं दूर-दूर के इलाकों में, ग्रामीणों के घरों में भी बातचीत करने और चाय पीने के लिए गया हूँ, जहाँ कम ही विदेशी जाते हैं। हर जगह लोगों ने मेरा अधिकतम भावपूर्ण और हादिक स्वागत किया। इनमें से कुछ लोग शिक्षित थे, लेकिन अधिकांश लोग नहीं, और वे हिन्दुस्तान के लिए, और अपने लिए ठीक वही कुछ चाहते हैं, जो अमरीका में हम लोग अपने लिए चाहते हैं—एक तर्क संगत, सान्त्वितपूर्ण विश्व, जिसमें लोग आत्म-सम्मानपूर्वक मिलकर काम करें।

हम इस बात को समझते हैं कि कितनी ही पीढ़ियों तक पश्चिम ने पुराने औप-निवेशिक एशिया के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। अगर मैं एशियावासी होना तो जिन औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन अधिकांश एशियावासियों को रहना और काम करना पड़ा था, उस पर मुझे रोष होता। लेकिन वह दृष्टिकोण अब हमारे वर्तमान सम्बन्धों पर लागू नहीं होता। कभी मेरे साथ यात्रा कीजिए तो आप स्वयं ही देखलेंगे।

विन्ट्रुज सवाददाता : क्या आप बता सकते हैं कि अमरीका को निरपवाद बाधों का डर अंतो सर्वथा असोक्तप्रिय प्रतिश्रियावादीयों में ही अपने मित्र वर्षों मिलते हैं, जिनकी स्वयं अपने लोगों के बीच कोई जड़ नहीं होती ? क्या आप सहमत नहीं हैं, कि एशिया में अमरीकी असोक्तप्रियता का यही मूल कारण रहा है ?

श्री बोल्स . हम दूसरे देशों के नेताओं को नहीं चुनते। वे कई रीतियों से चुने जाते हैं, कुछ अश्लील, कुछ सुरी, कुछ लोकतांत्रिक, और कुछ बिलकुल आलोचनात्मक।

लेकिन मैं इसका और कह दूँ—मैं नहीं समझता कि जिन क्रानिकारी विश्व में हम रह रहे हैं, उसमें प्रतिश्रियावादी अपने को आगम रण मानते हैं, चाहे वे फासिस्ट दक्षिणपक्ष के हों, या मार्क्सवादी वामपक्ष के। दक्षिणपक्षी प्रतिश्रिया का विनाश निश्चित है, और यह उचित हो है। वामपक्ष की मार्क्सवादी प्रतिश्रिया या तो अपनी नीतियों को मशीनित करेगी, या बच्चे भी मरने बोझ में और अपने अन्तर्विरोधों के अन्तर्विरोध टट जायेगी।

कभी-कभी शीत युद्ध के दस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष के कारण हम अपने को कठिन स्थितियों में पाते हैं, जिनमें ऐसे समझौते की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें पसन्द नहीं होते किन्तु दीर्घ कालीन दृष्टि से हम जिन बातों में विश्वास करते हैं उनका जीवित रहना एक गतिशील उदारवादी आन्दोलन में ही संभव है, जो वाम और दक्षिण दोनों प्रकार के प्रतिक्रियावादियों को अस्वीकार करे, और जो भूमि सुधार, न्यूनतम वेतन, अधिक ऊँचे जीवन स्तर अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा, और अधिक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति, और बिना जाति, धर्म, वर्ण या रंग का भेदभाव किए, सभी लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने के प्रति समर्पित हो।

यही उस प्रकार का राजनीतिक आन्दोलन है, जिसमें अधिकांश अमरीकी गभीरता से विश्वास करते हैं, और जिसका हम यहाँ हिन्दुस्तान में, और सारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में समर्थन करेंगे। और अन्ततः इसकी जीत होगी।

हिन्दुस्तान में अमरीकी राजदूत के रूप में काम करने के बाद 1953 के आरम्भ में पापल लौटकर श्री योल्म में इकतान्तीय राज्यों में एक नई अमरीकी नीति के पक्ष में भाषण दिए, जो कि नए जागते हुए एशिया की नई आदर्शरचनाओं के अनुकूल हो। यहाँ न्यूयार्क के कम्युनिटी चर्च में मई, 1953 में दिये गए भाषण में वे एक अधिक रचनात्मक एशिया नीति के आठमूल सूत्र प्रस्तुत करते हैं।

पिछले दशक में, हमने मेहनत के साथ यूरोप के लिए एक अमरीकी नीति निर्मित की है, एक सार्वभूमिक, व्यावहारिक नीति जिगरी मात्र हमारी विशाल बहुगुण्य समर्थन करती है। यह नीति उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के राष्ट्रों के निश्चय सम्बन्ध को, और इस तथ्य को स्वीकार करती है, कि हम सिंगी याहरी सक्ति को यूरोप पर अधिकार या नियन्त्रण नहीं करने दे सकते।

लेकिन हम इस कठोर तथ्य को स्वीकार करें कि युद्ध के आठ वर्ष बाद भी एशिया में अमरीका की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस पर बहस करना बपर्य है कि इसमें दोष किसका है। ऐसा बहुतेरा दोष है जो दोनों राजनीतिक दलों पर व्यापक रूप में आरोपित किया जा सकता है। अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में हम करने क्या जा रहे हैं।

मैं आठ मूल सूत्र निरूपित करता चाहूंगा, जिन पर मैं समझता हूँ अमरीका की एक रचनात्मक एशिया नीति आधारित होनी चाहिए।

प्रथम, हमें यह समझना होगा कि एक एशियाई दृष्टिकोण है।

मैंने इस दृष्टिकोण को लेबनान, श्रीलंका, भारत, ब्रह्मा, इण्डोनीशिया, विएतनाम, फिलीपीन, और जापान में, ऐसे व्यक्तियों को व्यक्त करते सुना, जो भिन्न भाषाएँ बोलते हैं और एक-दूसरे से हजारों मील दूर रहते हैं।

इसमें कोई 'अग्रम' बात नहीं है। एशिया के सन्दर्भ में यह एक सरल साफ और समझ में आने वाली बात है।

दूसरे, एशिया के भविष्य का निर्णय अन्ततः एशियावासियों द्वारा होगा।

हम विध्यात्मक तत्वों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और नकारात्मक तथा विध्वंसक तत्वों को निरुत्साहित कर सकते हैं, और यह महत्त्वपूर्ण है। लेकिन अन्धता या बुरा, एशिया के भविष्य का निर्णय वांशगत में अमरीकियों द्वारा नहीं, बरन् लोकियों

की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने में बहुत अधिक बार जनत न साबित हुआ हो। विनम्रता की भावना रखने वाला कोई व्यक्ति इन सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करेगा कि आज ने इन वर्षों बाद एशिया में या अन्यत्र कहीं क्या स्थिति होगी।

फिर भी, कुछ तथ्य अभी भी स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, हमें इन तथ्यों की स्वीकार करना चाहिए कि सोवियत रूस के सामने जो घनेगी सबसे बड़ी विपत्ति या समस्या है, वह एक अधिक स्वतंत्र चीन का विकास है। आज चीन सोवियत रूस के साथ प्रति निकट से बंधा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जो अमरीकी विदेश नीति यह मान लेती है कि ऐसे सम्बन्ध स्थायी हैं, वह लगभग निश्चय ही गलत साबित होगी।

सातवें, संयुक्त राष्ट्र तय की सहमति और अस्पष्टता दोनों के बीच के रूप में कायम रखना चाहिए।

अतः हम उसे गोरे, पश्चिमी देशों का एक बन्ध बना देने का सोच का संवरण करें। जेफरसन की परम्परा में, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्षों को उपनिवेशवाद, प्राथिक शोषण, और जाति धर्म या रंग पर आधारित विभी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध स्पष्ट अमरीकी वक्तव्यों से गुंजाएँ।

आठवें, हम विदेशों में लोकतंत्र को सकलतापूर्वक आगे बढ़ा नहीं सकते, जब तक कि हम देश में अधिक पूर्ण रूप में उस पर अमल न करें।

इतिहास की इस निर्णायक घड़ी में अपनी सैन्य प्रतिरक्षा को कमजोर करना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। दुर्बल अमरीका, अधिकतम प्रतिकूल स्थितियों में होने वाले तीसरे महायुद्ध को पूर्णतः निश्चित बना देगा।

लेकिन हमारे सामने केवल एक सैनिक खतरा ही नहीं है, बरन् निर्भय, साहसी और दृढ़ व्यक्तियों के हाथ में एक विस्फोटक, गतिशील विचार का भी खतरा है। ऐसे विचारों को बमों से नष्ट नहीं किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की बाँध धारणाओं का मुकाबला, व्यक्तिगत अधिकारों, लोकतंत्र, और व्यक्ति मनुष्य में गतिशील आस्था की विपरीत धारणा से करके उन पर विजय पानी होगी।

स्वतंत्रता की घोषणा के एक सौ सत्तर वर्षों बाद भी, अमरीकी सपना दुनिया का सबसे सशक्त विचार है। केवल हम ही उस विचार को नष्ट कर सकते हैं, और केवल हम ही उसे क्रियान्वित कर सकते हैं।

एशिया के लिए एक 'मार्शल योजना'

विदेशी सहायता देने के प्रभावकारी साधनों की खोज के फलस्वरूप, अक्टूबर, 1953 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में एशिया के लिए एक 'मार्शल योजना' का यह विचारोत्तेजक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

ऐसा कहना बिल्कुल गलत और बहुत ही अपमानजनक है कि एशियावासी एक कटोरा चावन के लिए अपनी आत्मा बेच देंगे। औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता के लिए वे बीरतापूर्वक लड़ें हैं, और अपनी सीमाओं के अन्दर साम्यवादी आक्रमणों के विरुद्ध उन स्वतंत्रता की उन्हीं सफलतापूर्वक रक्षा की है।

अब वे रोटी और आजादी दोनों के ही लिए आग्रह कर रहे हैं। एशिया में तुरु-स्तन की प्रमाणित करना होगा कि वह दोनों प्रदान कर सकता है, अन्यथा एशिया में लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा।

मुख्यतः इस निर्णायक प्रयत्न के लिए नेतृत्व और साधन एशियावासियों को ही प्रदान करने होंगे, एशिया की स्वतंत्र सरकारों को भूमि सुधार करने होंगे, कराधान की उचित व्यवस्थाएँ करनी होंगी, और सभी उपन्यध साधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय योजनाएँ बनानी होंगी। इस समय जहाँ भी वे ऐसा कर रही हैं, तोग उत्साह-पूर्वक एकजुट हो रहे हैं।

लोकतान्त्रिक एशिया तानाशाही निर्ममता के साथ अपने लोगों को दया नहीं सकता। अतः उसे सहायता के लिए पश्चिम की ओर देखना पड़ेगा। अतः सूची कार्यक्रम सही दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन हमारी सहायता में प्राविधिक गृह्यता के साथ-साथ पूंजी भी शामिल होनी चाहिए, और समस्या का मामला दुबडो में करने के बजाए, यूरोप की भाँति क्षेत्रीय आधार पर करना चाहिए। इनका सर्वोत्तम तरीका यही होगा कि एक संयुक्त योजना के द्वारा सारे स्वतंत्र एशियाई क्षेत्र के साधन इसमें लगाये जाएँ।

एशिया के स्वतंत्र देश कई तरीकों से एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जापान, जहाँ चावल का प्रति एकड़ उत्पादन अमरीका से काफी अधिक है, और भारत का चार गुना है, सघन खेती के लिए प्राविधिक सहायता प्रदान कर सकता है।

इण्डोनीशिया भी, जिसने घान की सिचाई के पानी में बड़ी मात्रा में मछलियाँ

पैदा करने की पद्धति का सकल प्रयोग किया है, एशिया के धान उगाने वाले राष्ट्रों को कुछ दे सकता है। हिन्दुस्तान को मलेरिया नियंत्रण का अनुभव है, और वह एण्डोनीशिया जैसे मलेरिया प्रस्त देशों को कार्यकर्ताओं के दल भेज सकता है। शम विवास और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भी, हिन्दुस्तान अपने बहुल और गहन अनुभव से बहुत कुछ दे सकता है।

इसी प्रकार, एशिया के राष्ट्रों में पारस्परिक व्यापार उन सभी की अर्थ-व्यवस्थाओं को बल दे सकता है। दक्षिण एशिया जापान के लिए एक बड़ा बाजार, और कुछ ऐसे कच्चे माल का स्रोत बन सकता है, जो पहले कभी जापान को चीन से प्राप्त होता था। जापान के छोटे उद्योग दक्षिण एशिया में विकेंद्रित उद्योग के लिए नमूने का काम दे सकते हैं।

एक समेकित क्षेत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से चलाए जाने पर, हमारे अपने सहायता कार्यक्रम अधिक प्रभावकारी होंगे। इस समय अमरीकी शासन का चतुःसूत्री कार्यक्रम है, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की कोलम्बो योजना है, संयुक्त राष्ट्रों को प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, भोजन तथा शैती संगठन, और बात-निधि जैसी आधा दर्जन अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम हैं; नार्व, स्विट्जरलैंड और स्वीडेन की, तथा निजी संस्थाओं और धार्मिक समूहों की सहायता योजनाएँ हैं। इन सभी के द्वारा महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम हो रहा है। लेकिन उनमें समन्वय अधिक होने से सभी को लाभ होगा।

शायद एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्रों का आर्थिक कमिशन ऐसे क्षेत्रीय प्रयास के लिए नाभि-केन्द्र का काम कर सकता है। अगर कोई व्यावहारिक, व्यापक योजना विकसित हो, तो उसे अपना विश्वास और समर्थन देने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए।

बया अब समय नहीं है कि अमरीका स्वतन्त्र एशियाई राष्ट्रों को ऐसी पहल करने के लिए निमन्त्रित करे, जैसे विदेश सचिव मार्शल ने 1947 में यूरोपीय लोगों को प्रोत्साहित किया था। शेष एशिया को साम्यवादी चीन के रास्ते पर जाने से रोकने में सहायक होने का यह भी एक मार्ग है।

अगर हम समय रहते कल्पनापूर्ण रीति से पर्याप्त कार्यवाही नहीं करते, तो सारे दक्षिण एशिया में हमारी असफलता के सम्मुख चीन में हमारी असफलता गौण हो जायेगी। ब्यागकाई-शेक के चीन को हमने जितनी सहायता दी थी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, एण्डोनीशिया और ब्रह्मा को मिलाकर, जिनकी आबादी मनुष्य जाति की लगभग एक चौथाई है, अब तक हमने उसकी आधी से भी कम सहायता दी है। इन देशों को सब मिलाकर हमने जितनी सहायता दी है, उससे अधिक सहायता हमने अकेले यूनान को दी थी।

सदियों से पश्चिमी जगत एशिया से लाभ उठाता रहा है। अपने एशियाई और

अफ्रीकी उपनिवेशों से यूरोपीय राष्ट्रों ने वह धन प्राप्त किया, जिसने पश्चिमी औद्योगीकरण को आसान बनाया ।

अग्ने खुले सीमान्त के फलस्वरूप, अमरीका एशियाई उपनिवेशों पर निर्भर नहीं रहा, लेकिन पहले महायुद्ध के पूर्व हमें काफी बड़ी मात्रा में अंग्रेजी पूँजी की आवश्यकता पड़ती थी—जो आंशिक रूप में एशिया और अफ्रीका में लगी औपनिवेशिक पूँजी से अर्जित की गई थी ।

वस्तुतः, येल विश्वविद्यालय को, जिसका मैं स्नातक हूँ, पहला बड़ा दान ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रान्त के अंग्रेज गवर्नर एलियू येल ने कपड़ों से लदे हुए पाँच जहाजों के रूप में दिया था । इन शानदार वस्त्रों को बनाने में जो शक्तिहीन भारतीय स्त्री-पुरुष लगाये गए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने में समृद्ध अमरीकी परिवारों के पुत्रों की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से अपना वक्त और अपनी मेहनत लगाई होगी, इसमें मुझे सन्देह है ।

इतिहास का यह कैसा आश्चर्यजनक और शानदार मोड़ होगा, अगर पश्चिम ने एशिया में जो धन प्राप्त किया है, उसका कुछ हिस्सा अब वह ढंराज सहित वापस करे, ताकि एशिया का विकास कुछ अधिक आसान हो सके, और एशिया की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो सके । हम अमरीकियों से अब इतिहास की माँग है कि हम एक नए प्रकार की दुनिया में कल्पना और संवेदनशीलता के साथ काम करें ।

ब्रह्मा और वियतनाम : अन्तर और नतीजे

दक्षिण-पूर्वी एशिया सम्बन्धी इस लेख में, जिसकी भविष्यवाणियाँ सच निकली हैं, श्री बौलम का कथन है कि पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रों से ही यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा सफलतापूर्वक कर सकेंगे। यह लेख 13 जून, 1954 को न्यूयार्क टाइम्स मंगलदिन में प्रकाशित हुआ था।

1946 के दिग्गमर मास के आरम्भ में, एशिया में औपनिवेशिक नीति के सम्बन्ध में मेरे एक प्रदन के उत्तर में, ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के एक सदस्य ने भविष्यवाणी की थी - "यावत् धमरीकियों ने फिलीपीन को पहले ही स्वतन्त्र कर दिया है। एक वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मा, हिन्द चीन, मलय, और इंडोनेशिया भी स्वतन्त्र हो जाएंगे।

लेकिन यह नई स्वतन्त्रता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। नई सरकारें कमजोर और अक्षुण्ण होंगी। उनकी सैन्य शक्ति लगभग शून्य होगी। बिना पश्चिमी निर्देशन के, उनकी शासकीय सेवाएँ शीघ्र ही बिखर जाएंगी। अतः, और दो या तीन वर्षों के अन्दर, साम्यवादी चीन पर अधिकार कर लेंगे, और यह एशिया में स्वतन्त्रता का अन्त और पश्चिम के शक्ति का वृद्धि होगी।"

इस गम्भीर भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच निकला है। 1949 में साम्यवादी चीन ने गाने चीन में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में अमेरिकी पार्लियामेण्ट का यह सदस्य गलती पर था। 1947 और 1948 में अमेरिकी ने हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, और श्रीलंका को छोड़ दिया था, और हालैण्ड वाले इंडोनेशिया को छोड़ने लगे थे।

नजर डालें, तो मैं समझता हूँ कि हम देख लेंगे कि यह मात्र संयोग क्यों नहीं है। पिछले दिनों ब्रह्मा और विएतनाम के इतिहास से कुछ विशेषण प्रांशिक नतीजे निकलते हैं।

ऊपरी दृष्टि से, दक्षिण-पूर्व एशिया के इन दो देशों में बड़ी समानता है। दोनों ही प्राकृतिक साधनों में समृद्ध हैं, खूब वर्षा होती है, जमीन अच्छी है, और निर्यात के लिए चावल खूब होता है। दोनों ही देशों में आवादी बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रह्मा का क्षेत्र फ्रान्स, बेल्जियम, और हालैण्ड के मिले-जुले क्षेत्र में अधिक है, और उसकी आवादी एक करोड़ नब्बे लाख है। विएतनाम का क्षेत्र लगभग इटली के बराबर है, और आवादी दो करोड़ चालीस लाख।

लेकिन समानताएँ केवल भौतिक ही नहीं हैं। दोनों देशों का औपनिवेशिक शासन का लम्बा इतिहास है। मध्य उन्नीसवीं सदी में विएतनाम में फ्रांस की सत्ता पूरी तरह स्थापित हो गई थी। ब्रह्मा में स्वतन्त्रता के अन्तिम अवरोध अंग्रेजों ने 1886 में समाप्त कर दिए। इनके महायुद्ध के समय, दोनों देशों पर जापानियों का अधिभार रहा।

युद्ध-काल में, दोनों ही देशों में अंग्रेज और अमरीकी समर्थन से छापामार आन्दोलन विकसित हुए। छापामारों में साम्यवादी नेता प्रमुख थे। जब जापानियों को अन्ततः हरा दिया गया, तो दोनों ही देशों में पूर्ण स्वतन्त्रता की एक जैसी और व्यापक माँग उठी। 1946 में, जब अंग्रेज वाइसराय लार्ड लुई माउण्टबैटन हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के बारे में गांधी और नेहरू से वार्ता कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा के वर्तमान प्रधान मंत्री ऊ नू भी अंग्रेजों के साथ वैसी ही वार्ता चला रहे थे, और विएतनामी नेता फासीसियों में बातचीत कर रहे थे।

लेकिन यहाँ दोनों देशों के बीच समानताएँ अचानक समाप्त हो जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, और श्रीलंका की भाँति ब्रह्मा में भी अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार कर ली। विएतनाम, और कम्बोडिया तथा लाओस के दो सम्बद्ध राज्यों में, फ्रांसीसी हिचकते और टालमटोल करते रहे। फल हुआ है एक अतिनासक आठ वर्षीय गृह युद्ध।

आज फ्रांस की एक लाख चालीस हजार सेना बुरी तरह फँसी हुई है, और उसके साथ फ्रान्स द्वारा प्रशिक्षित और सज्जित, और फ्रांसीसी अफसरों के नीचे लड़ने वाले डेढ़ लाख विएतनामी सैनिक हैं। फ्रांसीसी सेना के 38,000 व्यक्ति मारे गए हैं, जिनमें 11,000 फ्रांसीसी सैनिक भी थे, जिनमें अनुभवी युवा अफसरों की संख्या काफी बड़ी थी।

इस फ्रांसीसी प्रयास के समर्थन में अमरीकी सैन्य सहायता अब दो अरब डॉलर के निक्कट पहुँच गई है—पिछले पाँच वर्षों में सारी दुनिया में चतुस्रुनी विज्ञान कार्यक्रम के कुल खर्च का दो या तीन गुना। स्वयं फ्रान्स को पूरी मार्शल योजना में अमरीका से जितना धन मिला था, उसमें अधिक वह हिन्द चीन के युद्ध पर खर्च

चुना है। फिर भी, इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय, इसमें गंभीर सन्देह है कि उत्तरी विएतनाम में लाल नदी के मुहाने के समृद्ध इलाके में फ्रांसीसी सेनाएँ अपने पाँव टिकाए भी रख सकती हैं या नहीं।

यह सैनिक पराजय इस कारण हुई है कि फ्रांस और अमरीका दोनों ने ही उपनिवेशवाद के विरुद्ध एशिया की क्रांति की वास्तविकता को समझने से लगातार इन्कार किया है। दूसरे महायुद्ध में पराजित, और अपने भविष्य के बारे में शकालु फ्रांस को भय रहा है कि एशिया में औपनिवेशिक वापसी में मोरक्को, ट्यूनिशिया और अफ्रीका के अन्य फ्रांसीसी क्षेत्रों में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। अमरीकी लोग यूरोप में फ्रांस के सैन्य समर्थन की आवश्यकता को जानते हैं, और इस कारण विएतनाम, कम्बोडिया और लाओस को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए दबाव डालने से हिचकते रहे हैं, जो साम्यवाद-विरोधी कार्यवाही के लिए प्रभावकारी आधार निर्मित करने का एकमात्र ढंग था।

फनस्वरूप, एक घोषित साम्यवादी, हो-ची-मिन विएतनामी राष्ट्रवाद के देशभक्त नेता होने का दम भर सके हैं, जबकि विएतनाम के साम्यवाद-विरोधी नेता, जिनमें कई योग्य और निष्ठावान व्यक्ति हैं, अपने देशवासियों को फ्रांस के एजेंट प्रतीत होते रहे हैं।

यद्यपि फ्रांस ने विएतनाम को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने की दिशा में, विशेषतः पिछले कुछ महीनों में, काफी बड़ी रिमापत्ते दी है, लेकिन ये रिमापत्तें निरपवाद ही फ्रांसीसी सेनाओं पर साम्यवादियों की विजयों के बाद दी गई हैं, और इस कारण नया समर्थन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य में असफल रही हैं।

जन-समर्थन प्राप्त करने में फ्रांसीसियों की असफलता का एक और कारण यह है कि वे गाँवों में मामूली से मामूली सुधारों का भी समर्थन करने से हिचकते रहे हैं। 1952 में विएतनाम के साम्यवाद-विरोधी प्रजातन्त्री बान ताम ने मुझसे बताया कि जब साम्यवादी किसी गाँव पर अधिकार करते हैं तो वे घोषणा करते हैं कि मारे वज्रें रह कर दिये गए, और अब सारी जमीन जोतने वाली बनी होगी।

जब फ्रांसीसी सेनाएँ उन क्षेत्र पर फिर से अधिकार करती, तो जमींदारों और महाजनों की पुरानी शक्ति को तत्काल पुनः प्रतिष्ठित कर देती। 'ऐसी लड़ाई में हम साम्यवादियों को कैसे हरा सकते हैं?' उन्होंने चके हुए स्वर में पूछा।

सब महीने बाद सीओए में अपने दफ्तर में बान ताम ने मुझे बताया कि इस बीच 'बड़ी रूढ़ि' हुई है। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, "अब फ्रांसीसी जब किसी गाँव पर फिर से अधिकार करते हैं, तो जमीन किसानों के पास ही रहने देते हैं। इसलिए अब किसान आशा करता है कि साम्यवादी उनके यहाँ अधिकार करेंगे और उन्हें जमीन देंगे, और तब वह प्रायः ना करता है कि फ्रांसीसी मात्र उन्हें मुक्त करेंगे, ताकि जमीन उनके पास बनी रहे।"

नाममभी और गलतफ़हमी की, और स्वतन्त्र होने की एगिजावातियों में बढ़ती

हुई हठ आकांक्षा की, हठपूर्ण उपेक्षा की, यह दुबद विएतनामी कहानी, ब्रह्मा के युद्धोत्तर कालीन इतिहास के विलकुल विपरीत है।

जब 1946 में हिन्दी चीन में फ्रांसीसियों का सशस्त्र विरोध आरम्भ हो रहा था, उस समय ब्रह्मा भी गृह-युद्ध के निकट था, और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाहियाँ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन हिन्दचीन के विपरीत, 1947 में ब्रह्मा स्वतन्त्र हो गया।

साम्यवादियों को निराशा हुई कि अंग्रेजों के चने जाने से वे 'उपनिवेशवाद का नाश हो' के नारे से वचन हो गए, जो फ्रांसीसियों ने विएतनाम में उन्हें प्रदान किया था, और 1948 में उन्होंने नई सरकार के विरुद्ध युवा, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। 1949 में पूर्वी ब्रह्मा के कठोर, युद्ध-प्रिय करेन लोगों ने भी, जो एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, ऐसा ही किया। 1951 तक लड़ाई सारे ब्रह्मा में फैल गई, और इस गणतंत्र का भविष्य निश्चय ही अधकारमय प्रतीत होता था।

1951 का वर्ष समाप्त होते-होते, अमरीकी सरकार ने लगभग तय कर लिया था कि ब्रह्मा की नई सरकार का विनाश निश्चित था। इसी समय, चीन की साम्यवादी सरकार ने, एशिया में शक्ति के वास्तविक स्रोतों को ज्यादा अच्युत तरह समझते हुए, ब्रह्मा के साम्यवादियों में आशा छोड़ दी थी।

इस समय विएतनाम में साम्यवादी सेनाओं को चीनी सहायता तेजी से बढ़ाई जा रही थी। लेकिन ब्रह्मा के नए गणराज्य की दुर्बल स्थिति के बावजूद, जहाँ तक ज्ञात है, ब्रह्मा के साम्यवादियों की सहायता के लिए कोई चीनी हथियार या लड़ाई का सामान नहीं भेजा गया। पीकिंग की सरकार जानती थी कि ऐसा हस्तक्षेप होने पर स्वतन्त्र ब्रह्मा यह दावा कर सकेगा कि साम्यवादी विद्रोहियों को चीन से धन मिल रहा था, और इस प्रकार विदेशी प्रभुत्व की पुरानी आशंकाओं को उनके विरुद्ध जगा सकेगा।

धीरे-धीरे प्रधान मन्त्री ऊ नू और उनके महयोगियों को मारे ब्रह्मा में अपेक्षितया ठोस आधार पर शासन स्थापित करने में सफलता मिली। साम्यवाद और सच्चे आर्थिक और राजनीतिक सुधारों का समर्थन करके उन्होंने साम्यवादियों के समर्थन का आधार ही खतम कर दिया। इस वर्ष अगस्त के आरम्भ में आत्म-समर्पण करने वाले अन्तिम साम्यवादी नेता ने शिकायत भरे स्वर में कहा, "लोगों से हम साम्यवादी जिम्मा बादा करते रहे थे, उन गाँव-कार्यक्रम को ऊ नू ने वापस ले लिया, और हमारे पाग लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं रहा।"

यद्यपि उसकी निष्ठा स्पष्टतः लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में है, किन्तु हिन्दुस्तान की भाँति ब्रह्मा ने भी दुनिया के मामलों में हठतापूर्वक 'तटस्थता' की नीति अपनाई है। जनवरी, 1950 में, साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करने वाला पहला असाम्यवादी राष्ट्र ब्रह्मा था। 1953 में, जब शासन को यह विश्वास हो गया कि उत्तर ब्रह्मा में चीनी राष्ट्रवादी सेनाओं को फारमोसा ने अमरीका की जानकारी और सहमति में हथियार और सामान पहुँचाया है, तो उसने शिष्टता से किन्तु कुछ हठता के साथ, यह

अभी भी बन्दूकों और बमों से या संयुक्त राष्ट्र संघ के मतदानों से भी कहीं अधिक उलझी हुई है। फ्रांसीसियों ने कटिन मार्ग से हिन्दचीन में यह सबक सीखा है, रूस ने पूर्वो जर्मनी, पोलैण्ड और बाल्कन प्रदेश में, और चीनियों ने कोरिया में।

निश्चय ही शक्ति के कई पैमाने होते हैं। लेकिन लोग, और उन्हें प्रभावित करने वाले विचार ही आखिरी पैमाना होते हैं।

‘भूरे व्यक्ति के भार’ का विश्लेषण

नए राष्ट्रीय राष्ट्रों, और पश्चिम के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना का निर्माण महत्त्व होने पर, श्री योल्म ने एशिया और अफ्रीका के लोगों से जाग्रत किया कि वे पश्चिम-निर्गमियों द्वारा पूर्वमांगताओं के सम्बन्ध में अपना दिमाग साफ करें। म्यून्खेन 5 मिन्यूट, 1954।

‘गौर व्यक्ति का भार’ सम्बन्धी पुरानी पारम्परिक वाक्य-प्रयोग एशियावासी बल्कि अधिकांश विचारशील पश्चिमी लोग भी समझते हैं। लेकिन जब पश्चिम बड़ी दर में महयोग के एक नए साधारण की सामान्य में निरन्तर है तो उसके सामने एक गौर बाधा सा रही है—एक एशियाई मन स्थिति जिसे ‘भूरे व्यक्ति का भार’ कहा जा सकता है।

एशिया के नए राष्ट्रों की उपनिवेशों के प्रति गौर मन में प्रकृत का गर्भर भाव है। एशिया के प्रति सामान्य पश्चिमी दृष्टिकोण से गौर प्रतिक्रिया गुणित है। किन्तु जो एशियावासी दर समय पश्चिम की आलोचना करने रहते हैं उनमें भी कहना चाहेंगा कि उनकी अपनी स्थिति भी गौर दोषरहित नहीं है। सामान्य एशिया की दुर्लभताओं पर मिश्रतापूर्ण दृष्टि डालने में हम उचित परिदृश्य की प्राप्ति में कुछ सहायता मिले, जिसकी वही आवश्यकता है।

हम सर्वाधिक मूल प्रश्न, उपनिवेशवाद, से प्रारम्भ करें। पिछले दिनों पश्चिमी उपनिवेशवाद का जो बटु अनुभव एशिया की दुःसा है, उसके फलस्वरूप एशिया में एशियावासियों का साम्राज्यवाद बहुधा विस्मृत हो जाता है जिसका साधुनिक उदाहरण हमें 1931 और 1945 के बीच किये गए जापानी आक्रमणों में मिलता है।

स्वयं अपने इतिहास का सावधानी से पुनरावलोकन करने पर वस्तुनिष्ठ एशियावासियों को और भी प्रमाण मिलेंगे कि उपनिवेशवाद केवल एक पश्चिमी रोग नहीं है, बरन किसी भी मनुष्यीय समाज के विकास में एक सम्भव स्थिति है, चाहे उसका निवार होने वालों के लिए यह स्थिति कितनी भी दुःसा क्यों न हो।

उदाहरण के लिए, हिन्दुस्तान को केवल अपनी प्राचीनता पर गर्व है, बल्कि वह दक्षिण एशिया में अपने प्राचीन उपनिवेशों पर भी खुल कर गर्व करता है। अशोक के काल से लेकर पश्चिमी खोजियों के पूर्वी समुद्रों में आने तक, हिन्दुस्तान संस्कृति,

व्यापार और विजय अभियानों का प्रसारण केन्द्र था।

नई दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में मेरे बच्चों ने इतिहास की जो पुस्तक पढ़ी उसका एक अध्याय था ‘महत्तर भारत’। उसके नक्शों में थी लका, ब्रह्मा, मलय, जावा मुमात्रा, धोर्नियो, वाली और कम्बोदिया के हिन्दू उपनिवेश दिवाये गए थे। लेखकों का कथन है कि “इस उपनिवेशीकरण का उद्देश्य शोषण करना, या केवल फैलते हुए व्यापार के लिए बाजार प्राप्त करना ही नहीं था।”

इसके विपरीत, हिन्दुस्तान के स्कूलों को सिखाया जाता है कि हिन्दू उपनिवेशवादी अधिक पिड़डे हुए इलाकों में सम्पत्ता की ज्योति को, और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को, ले गए। यह सब सच ही सकता है, लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवाद के पुराने समर्थक रुडयार्ड किपलिंग क्या इससे ज्यादा अच्छे ढंग में अपनी बात कह सकते थे ?

अपनी पुस्तक ‘भारत की खोज’ में नेहरू ने भारत की इस ऐतिहासिक भूमिका-की स्पष्टतः उपनिवेशवाद के यथार्थवादी सन्दर्भ में रखा है। वे लिखते हैं कि श्री लका, दक्षिण ब्रह्मा, और इण्डोनीशिया के कुछ हिस्सों को दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य ने जीत कर अपने में मिला लिया था। वे कहते हैं कि उस समय भी, चीन की खानें मलय में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा लाभ थी।

आज भी पड़ोस की राजधानियों में, विशेषतः नेपाल और श्रीलंका में, नए भारतीय ‘सामाज्यवाद’ का भय है। हिन्दुस्तानियों को ये भय उतने ही निराधार प्रतीत होते हैं, जितने अमरीका के पड़ोसियों के सम्बन्ध में उसकी महत्त्वाकांक्षामो के आरोप हमें निराधार प्रतीत होते हैं। लेकिन ये आरोप बहुधा लगाए जाते हैं, और बहुत-से लोग उन पर विश्वास करते हैं, इस तथ्य से संकेत मिलता है कि हिन्दुस्तान की शक्ति और प्रभाव बढ़ने के साथ-साथ, वह अधिकाधिक सन्देह और आलोचना का शय्य भी बनेगा।

नेपाल के साथ, जो उसकी उत्तरी सीमा पर पांच सौ मील तक फैला है, भारतीय सम्बन्धों के उतार-चढ़ाव, अपने कुछ मित्रों और गृहयोगियों के साथ अमरीका के अनुभव में बहुत कुछ मिलते हैं।

जब 1951 में लान चीन तिब्बत में सड़कें बनाने लगा, तो हिन्दुस्तान ने चिन्तित होकर अपनी उत्तरी सीमाओं को देखा। 1952 में नेपाली सेना का पुनः संगठन और आधुनिकीकरण आरम्भ करने के लिए एक भारतीय सैन्य दल नेपाल की राजधानी काठमांडू को भेजा गया। नेपाल-तिब्बत सीमा के साथ हिमालय के दरों में गश्त करने के लिए नेपाली गुरखा दस्तों के साथ-साथ भारतीय सेना की टुकड़ियाँ भी लगाई गईं।

शीघ्र बाद ही नेपाल सरकार को आर्थिक विकास के लिए एक फाफो बड़ा कर्ज दिया गया। फिर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के एक सिलसिले की सिफारिश की गई, और उसके साथ ही, नेपाल की कर व्यवस्था को आधुनिक बनाने, सड़कें

काश्मीर की तात्कालिक, साहसपूर्वक, सैन्यरक्षा से गांधी के लाखों हिंसा से घृणा करने वाले समर्थकों को प्रसन्नता हुई थी, और महात्मा गांधी ने स्वयं भी उदास होकर उनके लिए सशर्त अनुमति प्रदान कर दी थी।

अतः बुद्ध, अशोक और गांधी की मिसालों के बाद भी, हिंसा और युद्ध के मार्ग का परित्याग करने की अममर्यता में एशिया बहुत कुछ बाकी दुनिया जैसा ही है। जब पाकिस्तान अपने सीमा-रक्षकों की सच्चा बड़ाता है, तो हिन्दुस्तान को बदले में अपनी सीमा-रक्षा मजबूत करने के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझता। हिन्दुस्तान के कार्य की ऐसी ही प्रतिक्रिया पाकिस्तान पर होती है। भय से उत्पन्न भय के फलस्वरूप चलने वाली शस्त्रीकरण की होड़, किसी भी समय केवल पश्चिम की ही विशेषता नहीं रही।

भौतिक प्रगति के लिए विकासशील नए एशिया की स्पष्ट भूख भी हर जगह दिखाई देती है। साम्यवादी चीन में मानवी ऊर्जा के विशाल भंडारों को हिंसा, बला, और क्रूरता भरे उपायों से सगठित किया जा रहा है। लोकतांत्रिक भारत के नेता, जिन्होंने अहिंसक उपायों से अपने 36 करोड़ लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की, अपनी शक्तियों को एक पंचवर्षीय विकास योजना में लगा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि बिना तानाशाही के गरीबी को मिटाया जा सकता है।

अच्छा हो या बुरा, और अपनी अध्यात्मिक परम्पराओं के बावजूद, एशिया के लोग आज जन्दी में हैं। पश्चिमी विधियों के अध्यात्मिक परित्याग से कहीं अधिक यह जल्दी भौतिक विकास के लिए है। जो अब लोगों और उनकी संसदों की सामान्य रुचि का विषय बन गया प्रतीत होता है।

एक अन्य प्रश्न जो पश्चिम के बहुतेरे लोगों को सचमुच परेशान करता है, उस दोहरी नीति से उत्पन्न होता है, जो स्वतंत्र एशिया के प्रवक्ता बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में अपनाते प्रतीत होते हैं। आरम्भ से ही, एशिया के महान् धार्मिक नेताओं ने बहुत ध्यान देकर यह सिखाया है कि अधिकतम प्रशसनीय लक्ष्यों के लिए भी बुरे साधनों का प्रयोग उचित नहीं है। गांधी की शिक्षा का यही मर्म है।

किन्तु स्वतंत्र एशिया के नेता बहुधा बुरे साधनों की निन्दा करने में चुनाब करते प्रतीत होते हैं। पश्चिम को उसकी हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, वे बहुधा साम्यवादी देशों में सुलेग्राम बेईमानी और क्रूरता के प्रति उदासीन प्रतीत होते रहे हैं।

एशियावासियों को पश्चिमी लोगों से यह कहने का अधिकार है, कि वे अपने पुराने ग्रहकार को छोड़ें, दूसरों के विचारों का आश्रय करें, और राजनीतिक शक्तों के बिना ही सहायता प्रदान करें। एशियावासियों को पश्चिम में यह मार्ग करने का भी अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वह नैतिक व्यवहार का अधिक ऊँचा स्तर अपनाएँ, समझौता-वार्ताओं में अधिक लचीलापन दिखाएँ, बलों और बल पर कम जोर दें, और उन राजनीतिक व धार्मिक शक्तियों को अधिक गंभीरता से समझे,

जो इतिहास की दिशा निर्धारित कर रही है।
 लेकिन घमरीजियों और घम्य पश्चिमी लोगों को भी एशिया के घ-साम्यवादियों से यह आशा करने का उतना ही अधिकार है कि वे हमारी कठिनाइयों को कुछ ज्यादा अच्छी तरह समझें, इस बात को समझ कि नाति एक दुर्गरण सम्बन्ध है, और जब तक साम्यवादी लोग विश्व प्रभुत्व के अपने बहुधा घोषित लक्ष्य का परिष्कार नहीं करते, तब तक नाति स्थिति नहीं ठीक करनी।
 'गोरे व्यक्ति के भार' के बाग में, सारे पागल के बावजूद, बड़े-बड़े पश्चिमी लोगों ने न्यूनाधिक गफनता के साथ अपनी गन्धता के सर्वोत्तम अंश को एशिया तक पहुँचाने की चेष्टा की थी। आज जब भूरा व्यक्ति दुनिया में अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ छोड़ रहा है, तो पश्चिम के लिए, जिगने अपने गवक नीत लिए हैं, मायद यह उचित होगा कि वह एशिया से पश्चिम की गलतियों न दोहराने का अनुरोप करे।
 एशिया की भूमिना विभ्रमपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में केवल भगने और विवाद के बुद्ध और कारण जोड़ने की ही नहीं है। हम आशा करते हैं कि वह दुनिया को अपने सर्वोत्तम अंश प्रदान करेगा, जिसे शक्ति और आशा की बड़ी जरूरत है।
 मैं समझता हूँ यही अर्थ है: "सारी दुनिया के लिए एशिया के पाम एक सन्देश है।.....लेकिन एशिया केवल एशिया के लिए न होकर सारी दुनिया के लिए हो, इसके लिए उसे बुद्ध के सन्देश को फिर से खोल कर सारी दुनिया में पहुँचाना होगा।"

स्वतंत्र एशिया का भविष्य ?

एशिया नीति के सम्बन्ध में नए विचारों और प्रस्तावों की आवश्यकता को समझ कर, श्री वॉल्स एशिया में कार्यरत क्रान्तिकारी शक्तियों पर एक पेंनी और दूरगामी दृष्टि डालते हैं, और एक एशियाई मुनरो सिद्धान्त की संभावना का सुझान रखते हैं। कारेन एकेयर्स, अक्टूबर, 1954।

ऐतिहासिक तुलनाओं के आधार बहुधा बड़े दुबल होते हैं। किन्तु 'तटस्थ' एशिया के वर्तमान दृष्टिकोण, और पिछली शताब्दी में हमारी विदेश-नीति का निर्धारण करने वाले दृष्टिकोणों की समानता तत्काल ध्यान खींचती है।

एशिया के नए स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति अमरीका का भी जन्म क्रान्तिकारी उथल-पुथल के युग में हुआ था, जब फ्रांस की राज्य-क्रान्ति और नेपोलियन-कालीन युद्ध पूरी तेजी पर थे। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तटस्थता और गतिशील स्वतंत्रता की अमरीकी नीति का सुझाव रखा था।

वाटरलू में नेपोलियन की सेनाओं की पराजय के बाद, 1814 में अमरीकी नीति-निर्धारकों के सामने एक बिलकुल नयी और अप्रत्याशित समस्या आ खड़ी हुई। इस समय अमरीका के पास सबल सेना का अभाव था, और उसकी नौसेना बहुत छोटी थी। किन्तु सारी दुनिया में उसका नैतिक प्रभाव बहुत था, कुछ बँसे ही जैसे आज हिन्दुस्तान का है। और जैसे शीत-युद्ध में दोनों गुट आज हिन्दुस्तान की मित्रता चाहते हैं, उन्ही प्रकार 1820-23 में रूस के नेतृत्व में बना हुआ 'पवित्र-संध' और अंग्रेजी सरकार, दोनों ही अमरीका की सहमति और समर्थन चाहते थे।

किन्तु लोकतंत्र के अमरीकी समर्थकों को 1823 में जॉर्ज की सरकार उतनी ही अप्रिय थी, जितना उसका उत्तराधिकारी साम्यवादी शासन आज अधिकाँश स्वतंत्र एशिया को अप्रिय है। उसका प्रस्ताव शिष्टतापूर्वक, लेकिन हड़ता से अस्वीकार कर दिया गया, जैसे एशिया के स्वतंत्र राष्ट्रों ने अब तक साम्यवाद के साथ जुड़ना स्वीकार नहीं करने को गृह्य करने, ते०

स्तान और एशिया के अन्य स्वतंत्र मीधे प्रयास किए कि दक्षिण अमरीका में 'पवित्र' संध को ठीक करने का अवसर मिल जाए, ~~करने।~~
 वे एकरूपीय घोषणा करने

का निर्णय किया। 2 दिसम्बर, 1823 को, कांग्रेस के नाम अपने सानवें वार्षिक सम्मेलन के एक अंग के रूप में मुन्रो ने अपना प्रसिद्ध मिद्दान्त प्रस्तुत किया।

इस प्रकार, अपने इतिहास के प्रारम्भ में अमरीका ने विश्व राजनीति के एक मूल-सूत्र के अनुसार कार्य किया, जिसकी वाद में हमने बहुधा उपेक्षा की—कि तटस्थता और गम्बद्धता इच्छा करने मात्र में ही प्राप्त नहीं होते। और यह कि समय रहते थोड़ी-थी, रचनात्मक, शान्तिपूर्ण कार्यवाही के द्वारा घाद में कई गुनी, दुःख और रक्त-मय कार्यवाही की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति और 1823 में अमरीका की स्थिति में बहुतेरे स्पष्ट अन्तर हैं। साथ ही, बहुतेरी महत्त्वपूर्ण समानताएँ भी हैं।

जैसा आज मध्य-पूर्व में और दक्षिण-पूर्व एशिया में है, उसी तरह 1823 में दक्षिण अमरीका में एक शक्ति-शून्य था, जो चुम्बक की भाँति शक्तियों की महत्त्वकांक्षाओं को आकर्षित करता था। हिन्दुस्तान और स्वतंत्र एशिया के लिए आज मूल प्रश्न यही है, जो 1823 में अमरीका के लिए था—शक्ति-संघर्ष को अपने पड़ोस में ही विश्व युद्ध का रूप लेने से कैसे रोके, जिसमें शामिल होना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है।

जैसा 1823 में अमरीका के साथ था, आज हिन्दुस्तान अपने को भौगोलिक दृष्टि से, संघर्ष के मुख्य केन्द्रों से दूर समझता है, और उसे अपनी विशाल आर्थिक समस्याओं की, तथा विकास और प्रगति के स्वयं अपने अवसरों की गंभीर चिन्ता है।

अपनिवेशवाद के प्रति वह अधिकतम सकारण है, और उन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का समर्थन करने को उत्सुह है, जो औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते हैं। उसे विश्वास है कि शक्ति और बढ़ती हुई समृद्धि की सर्वोत्तम आशा इसी में है कि सभी शक्तियों के साथ उचित सम्बन्ध बनाए रखे, और अपनी जनता को भावनात्मक दृष्टि से वर्तमान संघर्षों में फँस जाने से बचाए।

यह तुलना कहाँ तक चल सकती है? 1823 में अमरीका की भाँति, क्या आज के हिन्दुस्तान में यह चेतना है कि स्वयं-तः स्थिति को ठाम, कल्पनापूर्ण कार्यवाही के द्वारा, और कुछ स्पष्ट जिम्मेदारियाँ उठाकर ही कायम रखा जा सकता है?

अब तक मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में वर्तमान शक्ति घुंम बने रहते हैं, साम्प्रवाद को उनमें प्रवेश करने का लोभ होता रहेगा, और मास्को-पीकिंग गुट द्वारा किसी भी प्रयत्न से अधिक आक्रमण का अमरीका सीधे मुकाबला करेगा, चाहे उसमें तीसरा महायुद्ध शुरू होने का भी खतरा हो।

क्या हिन्दुस्तान समझता है कि ऐसे संघर्ष में, जिनमें उसके आवश्यक सामुद्रिक संचार साधन हूट जाँगे, और जो उसकी सीमाओं के बहुत निकट होंगे, इसके लिए अपनी तटस्थता को, जो उसकी विदेश नीति का आधार है, एतम्भव होगा?

एशिया में ऐसी कोई प्रतिरक्षा व्यवस्था
स्तान, ब्रह्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया

के-
सा

वाली ही होगी, और उससे होने वाली राजनीतिक हानियाँ स्पष्ट हैं।

अने वाले वर्षों में, पाँचों कोलम्बो शक्तियों के सामने एक ऐसा विकल्प है जो वर्तमान उनमें हुई स्थिति में एशिया को स्थायित्व की सम्भावना सर्वाधिक व्यावहारिक रूप में प्रदान करता है, और जो अमभव नहीं है।

पश्चिम-मार्गीयत मैन्य मंडि में शामिल होने से इन्कार करते हुए, वे चीनी दवाव की भाँधी सम्भावना को समझ सकते हैं, और अपने इन दृढ़ निश्चय की घोषणा कर सकते हैं कि भविष्य में दक्षिण एशिया पर किसी भी ओर से आक्रमण होने पर वे उसका सबल विरोध करेंगे।

उन प्रसंग में, मैं समझता हूँ कि नई दिल्ली में हुए भारत-चीन समझौते को पूरी तरह साम्यवाद की जीत मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी। जुलाई में प्रकाशित चाउ-एन-लाई-नेहरू वक्तव्य में कहा गया है कि तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन संधि को सारे एशिया के लिए एक नमूना समझा जाय। इस संधि की भूमिका में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के लिए पाँच सिद्धान्त निरूपित किये गए हैं—एक दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुता का पारस्परिक आदर, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

हिन्दुस्तानी लोग इस बात को अवश्य ही समझते होंगे कि 1951 में तिब्बत पर अधिकार करके चीन ने इन पाँचों सिद्धान्तों का उलघन किया था। किसी ने अब तक ऐसा नहीं कहा कि चीन के प्रति अपने व्यवहार में हिन्दुस्तान ने कभी उनका पालन नहीं किया। अब चाउ और नेहरू द्वारा इन सिद्धान्तों के दोहराए जाने का यही अर्थ है कि चीनियों ने उन आदर्शों के अनुसार आचरण धारण करने का वादा किया है, जिनका उन्होंने हाल ही में और खुले आम उलघन किया था।

जाहिर है कि हिन्दुस्तानी लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमने युद्ध के बाद के वर्षों में व्यर्थ ही आशा की थी, कि भूख मिट जाने पर साम्यवादी शेर शांति और समरसता का जीवन स्वीकार कर लेगा।

शंकालु एशियावासियों को समझाने में, कि वे असंभव की प्राप्ति की आशा कर रहे हैं, पश्चिमी दलीलों का असर कम ही होगा, चाहे ये दलीलें कितनी भी तर्कसंगत क्यों न हों। साम्यवादियों द्वारा वादे तोड़ने का कठोर, कटु अनुभव ही संभवतः उनका भ्रम निवारण कर सकेगा।

इस कारण नेहरू और चाउ-एन-लाई के समझौते से भारत और चीन में अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित होने के बजाए, शायद उल्टा ही परिणाम निकले। किसी भी दशा में चीनी इरादों को परखने के लिए एक पक्की कसौटी मिल जानी है। अगर चीन 1920 के बाद दो दशकों तक की रूसी नीति का अनुसरण करता है, और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने, तथा अपने दवाव को ढीला करने का निर्णय करता है, तो हिन्दुस्तान और एशिया के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक ध्वज-स्थापणें ठीक करने का अवसर मिल जाएगा, जिसकी उन्हें बड़ी जरूरत है।

अगर चीन अपने नए वादों को उपेक्षा करता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में और अधिक विस्तार के लिए कार्यवाही करता है, जिसकी संभावना अधिक है, तो चीनी साम्यवाद का असली स्वरूप बहुतेरे एशियावासियों के लिए पहली बार स्पष्ट हो जाएगा।

नई दिल्ली और रंगून में चाउ द्वारा हाल ही में किये गए वादों के बाद ऐसा होने पर स्वतन्त्र एशिया को शायद वैसे ही प्रारम्भिक, मानसिक धक्का लगे, जैसा जंबोस्तोवाक्रिया पर साम्यवादियों के बलात् अधिकार और जान मसार्किक की मृत्यु से 1948 में पश्चिम को लगा था।

इस स्थिति में हिन्दुस्तान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एशिया में साम्यवादी चीन के प्रसारवाद का विरोध करने में हिन्दुस्तान सचमुच किस हद तक जाएगा? आज जैसी स्थिति है, उसमें कोई भी इसे नहीं जानता, शायद स्वयं हिन्दुस्तानी लोग भी नहीं। हिन्दुस्तान और उसके पड़ोसियों द्वारा एशिया के लिए एक मुनरो सिद्धान्त की घोषणा सार्यक हो, इसके लिए इस सन्देह को दूर करना जरूरी होगा।

अप्रैल, 1954 के श्रीलंका सम्मेलन से एक बात साफ हो गई। राष्ट्रपति मुनरो एकपक्षीय कार्यवाही कर सकते थे, और दक्षिण अमरीका के अपने दुर्बल पड़ोसियों की भावनाओं के बारे में उन्हें विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नेहरू किन्ती एकपक्षीय 'नेहरू सिद्धान्त' की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में उनके गर्वभरे पड़ोसियों के नाराज हो जाने का खतरा है। एशिया के स्थानीय मुनरो सिद्धान्त के प्रभावकारी होने के लिए, उसे बहुपक्षीय आधार पर निरूपित करना होगा, और इसके साथ अन्य कई प्रश्न भी जुड़े हुए हैं।

हमारा अंतिम लक्ष्य भूमध्य सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्वतंत्र, आत्म-विश्वासपूर्ण, और गतिशील नए राष्ट्रों का विकास है। स्वतंत्र, एशिया के बहुतेरे नेता जैसा सोचते प्रतीत होते हैं, उसके बावजूद, साम्यवादी कार्यक्रम ऐसे विकास का मौका देगा या नहीं, इसमें सन्देह है।

लेकिन एशिया में, या अन्यत्र कहीं, समुक्त राज्य ऐसी स्थितियाँ नहीं उत्पन्न कर सकता। इनका विकास अपने आप, स्वयं अपने प्रयास से ही हो सकता है। हम अधिक इतना ही कर सकते हैं कि मित्रतापूर्ण और हस्तक्षेपरहित प्रोत्साहन और समर्थन के द्वारा उनके विकास में सहायक हों।

एशियावासी कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं

एशियाई आलोचकों के साथ असंख्य अवसरों पर हुई बातचीत से, श्री बौल्स के दिमाग में दुतरफा वार्त्तालाप प्रस्तुत करने की बात आई। यहाँ वे एशिया के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में महा के एक प्रोफेसर के साथ एक अमरीकी राजदूत की वहीत प्रस्तुत करते हैं।
पॉकेट मैगज़ीन, नवम्बर, 1954।

अगर हमे एशियावासियों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध का कोई पुल बनाना है, तो हमें बात कम करनी चाहिए, और सुनना अधिक चाहिए। कभी-कभी जो कुछ हम सुनेगे, वह हमे अप्रिय लगेगा। फिर भी हमे सुनना होगा।

ग्रहों में विज्ञान के एक तीक्ष्णबुद्धि और लगन पूर्ण प्रोफेसर से हाल ही में हुई एक भेंट (जो उतने ही साम्यवाद-विरोधी थे, जितने वे अतर्क-संगत रूप में अमरीका-विरोध प्रतीत होते हैं) निम्नलिखित वार्त्तालाप का आधार है। इसमें स्वतंत्र पश्चिम और स्वतंत्र एशिया के महत्त्वपूर्ण और असंतोषप्रद सम्बन्ध में निहित कुछ कटु आवेग सामने आते हैं।

बर्मा प्रोफेसर : आप अमरीकियों ने एशिया में जो गलतियाँ की हैं, उन्हें देखकर दुःख होता है। जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, तो हमे आपसे बड़ी आशाएँ थी। लेकिन अब हम निराश और निरुत्साहित हो गए हैं।

अमरीकी बूटनीतिज्ञ : शायद आप बहुत अधिक आशा रखते थे। आतिरकार, हम भी आपकी तरह मनुष्य हैं, और हमारी बहुतेरी सीमाएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना हमारा स्वभाव नहीं है। 1941 तक हम दूसरे महायुद्ध से बचते रहे, जब पर्ल हार्बर के विस्फोट ने हमे अपने अकेलेपन से बाहर निकाला। युद्ध समाप्त होते ही हमने अपनी सेना विघटित कर दी, लेकिन देखा की सोवियत सभ ने अपनी सेना कायम रखी और उसके आधुनिकीकरण में अरबों खर्च किए।

हमारी धाज जो स्थिति है, उसके लिए हमने स्वयं चेष्टा नहीं की, और हम अपने निधे किसी प्रकार का लाभ नहीं चाहते। न हम एतान्तवादी हैं न साम्राज्यवादी। हम गचमुच केवल शान्ति और सुरक्षा के लिए और किसी उपाय से साम्यवाद को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

बर्मा प्रोफेसर : साम्यवाद मुझे उतना ही अप्रिय है जितना आपकी। वस्तुतः,

मेरे भतीजे को साम्यवादी छापामारो ने अगस्त, 1951 में मार डाला। हमारी सरकार सालों से साम्यवादियों से लड़ती रही है, और पिछले दिनों ही अन्ततः उन्हें परास्त करने में सफल हुई है। लेकिन आप अमरीकी लोग साम्यवाद के भय से इस तरह प्रस्त हो गए हैं कि एशिया के यथार्थों से आपका सम्पर्क नहीं रहा।

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : हम उससे अत्यधिक प्रस्त कैसे हो सकते हैं ? आप भूलते हैं कि साम्यवादी सारी दुनिया पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेनिन ने तीस वर्ष पहले साम्यवादी दल के लक्ष्य निर्धारित कर दिये थे, और उसके बाद हर महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता ने उन्हें दोहराया है।

बर्मा प्रोफेसर : यह सच है। लेकिन आप अमरीकी लोग ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि आप साम्यवाद पर बम गिराने उसे रोक सकते हैं। साम्यवाद केवल कोई सगा या स्थान नहीं है। यह एक विचार है।

हम हमेशा मानते रहे हैं कि आप अमरीकियों के पास उससे ज्यादा अच्युत विचार है। हम शिक्षित एशियावासियों में से अधिकांश ने आपका स्वतन्त्रता का घोषणापत्र पढ़ा है। हमसे कुछ को वह कष्टग्रह है। एशिया में हम जो लोकतंत्र निर्मित करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए आपका सविधान एक आदर्श रहा है।

हमें चिन्ता इस बात से है कि आप अमरीकी लोग अब स्वयं अपनी स्वतन्त्रता की लम्बी परम्परा से, और मानवता में अपने विश्वास से मूँह मोड़ते प्रतीत होते हैं। स्वयं अपने देश में साम्यवाद का विनाश करने की चेष्टा में आप साम्यवाद के तरीकों को अपनाते के लिए तैयार प्रतीत होते हैं।

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अपनी लोकतांत्रिक परम्परा को छोड़ दिया है ? दूसरे महायुद्ध के बाद एशिया में हमारे कार्यों को देखिए। युद्धकाल में कई लाख युवा अमरीकी एशिया को जापानी साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के लिए मारे गए।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आग्रह किया कि नए सयुक्त राष्ट्र सभ में चीन को पांच बड़ी शक्तियों में से एक के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाय। जैसा हमने कहा था, युद्ध समाप्त होते ही हमने फिलीपीन को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी।

हमने भारत और इंडोनेशिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया, और हमने जापान को जिनकी सहायता और प्रोत्साहन दिया, उनका किसी विजेता ने कभी भी अपने पुराने शत्रु को नहीं दिया।

बर्मा प्रोफेसर : मैं जानता हूँ। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि आप पश्चिम के ही अंग हैं, जो अपने नगरों, विश्वविद्यालयों, और ऊँचे जीवन-स्तरों का निर्माण करने के लिए प्रति वर्ष एशिया में करोड़ों डालर का धन पीड़ियों तक ले जाता रहा, और जिन्होंने हमें गरीबी, अशिक्षित, और भुखमरी के निकट लाकर छोड़ा।

एशिया से पश्चिम जो धन ले गया, उससे भी बुरा वह अपना था, जिसका हमें अनुभव कराया गया। चूँकि हमारी चमड़ी रंगीन है, इसलिए हमारे साथ दूसरे दर्जे

के मनुष्यों जैसा व्यवहार किया गया।

अमरीकी कूटनीतिज्ञ . लेकिन मैं फिर पूछता हूँ कि आप इसमें अमरीकियों को क्यों शामिल करते हैं ? हमारी एशिया में ऐसी औपनिवेशिक स्थिति कभी नहीं रही। और हमारा देश स्वयं यूरोप के औपनिवेशिक प्रभुत्व से लड़ करके स्वतंत्र होने वाला पहला राष्ट्र था।

बर्मा प्रोफेसर . लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप क्या करते रहे हैं ? एक तो आप करोड़ों डालर को सैन्य सामग्री के द्वारा हिन्दचीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को पुष्ट करते रहे हैं। अगर 1946 में आपने सशक्त नीति अनाई होती, तो फ्रांसीसी भी छोड़कर चले जाते, जैसा अंग्रेजों ने भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा और थी लका में किया, और विएतनाम, कम्बोडिया और लाओस भी बिना किसी रक्तपात के स्वतंत्र हो जाते।

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : हाँ, लेकिन हो-ची-मिन साम्यवादी थे, और वे बंदल इन तीनों देशों को साम्यवादी चीन को सौंप देते।

बर्मा प्रोफेसर : मैं स्वीकार करता हूँ कि हो-ची-मिन साम्यवादी हैं। लेकिन अगर वे विएतनाम की नई प्राप्त स्वतंत्रता को साम्यवादी चीन या रूस या अन्य किसी विदेशी शक्ति के हाथ देचने की कोशिश करते, तो उनके देश के लोग, जो हमेशा चीनियों को शका की दृष्टि से देखते रहे हैं, उन्हें हटा देते।

फ्रांसीसियों ने मूलतःपूर्वक उन्हें सैन्य शक्ति के द्वारा नष्ट करने की चेष्टा की। आपने कितने ही जहाज भरकर मशीनगनों, टैंकों, वायुयानों और अन्य सामान से उनका समर्थन किया। अतः आप ईमानदारी के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपने एशिया में साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया ?

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : यूरोपीय उपनिवेशवाद आपकी तरह हमें भी अप्रिय है, और हम भी मानते हैं कि हिन्दचीन में फ्रांसीसियों ने गलतिर्मा की हैं। लेकिन जिस तरह के उपनिवेशवाद की बात आप कर रहे हैं, एशिया में वह तो लगभग समाप्त हो चुका है।

आप नए साम्यवादी साम्राज्यवाद की उपेक्षा करते प्रतीत होते हैं, जिसके पीछे रूस और चीन का समर्थन है, और जो कहीं अधिक खतरनाक है। आप एशियावासी यूरोप के जीर्ण उपनिवेशवाद की बात करते रहेंगे, और बीमवी राक्षी वा नया साम्यवादी उपनिवेशवाद आरको टा जाएगा।

बर्मा प्रोफेसर . अगर आप हमें अकेला छोड़ दें, तो हम एशियावासी साम्यवाद के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, आप जैसा सोनते हैं उनमें कहीं ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। आप जरा घटनाओं की देखिए। चीन के युद्ध के अलावा, दूसरे महायुद्ध के बाद में एशिया में दृढ़ गृह-युद्ध हुए हैं, और सभी साम्यवादियों ने मर्गटिल करके चलाए।

इनमें से चार ऐसे देशों में हुए जिन्होंने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की थी—फिलीपीन, इंडोनेशिया, ब्रह्मा, और हिन्दुस्तान—और इन चारों ही देशों में, किसी

एशिया:वासी कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं

बाहरी सहायता के साम्यवादियों को दवा दिया गया। दो अन्य देशों—मलय और हिन्दचीन—में साम्यवादियों को बड़े पैमाने पर भगड़े उत्पन्न करने में सफलता मिली। हिन्दचीन में फ्रांस और अमरीका के समुच्चय संघ प्रयासों के बावजूद, उन्हें उबरदस्त सफलता मिली है।

क्यों ? केवल इसलिए कि हिन्दचीन और मलय में वे लोगों से बह सके कि वे विदेशी गोरे उपनिवेशवादियों को बाहर निकालने के लिए साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध चला रहे हैं। लेकिन जहाँ भी उन्हें एशियाई राष्ट्रवाद का सामना करना पड़ा, वहाँ उन्हें असफलता मिली।

इसके अलावा, आप अमरीकियों ने केवल एशिया में ही उपनिवेशवाद का समर्थन किया हो, ऐसा नहीं है। अफ्रीका में भी आपके काम लगभग उतने ही गलत रहे हैं। सभी लोगों के स्वतंत्र होने के अधिकार के बारे में जो बढ़िया बातें आप लोग करते हैं, उसके बावजूद समुच्चय राष्ट्र संघ में आपने लगातार ट्यूनीसिया और मोरक्को के स्वाधीनता आन्दोलनों के विरुद्ध मतदान किया है।

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : फ्रांसीसी अफ्रीका के बारे में हमें समझौता करना पड़ा क्योंकि यूरोप की प्रतिरक्षा के लिए फ्रांसीसी सेना आवश्यक है। अतः हमें फ्रांसीसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पड़े, जो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, और मोरक्को की स्वतंत्रता के सख्त खिलाफ थे। इससे कभी-कभी हमें अपने मन के विरुद्ध मतदान करना पड़ा।

बर्नो प्रोफेसर : लेकिन ऐसे समझौते से आपको लाभ क्या होता है ? आपने न केवल एशिया के अधिकांश लोगों का, बल्कि सारे अफ्रीका के लोगों का विश्वास खो दिया।

आप अमरीकियों के साथ दिक्कत यह है कि आप हर चीज को सैन्य शक्ति के सन्दर्भ में देखते हैं, जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि दुनिया के बड़े हिस्से में सैन्य शक्ति निर्णायक तत्व नहीं है।

ग्रंथों ने हिन्दुस्तान क्यों छोड़ा ? क्या इसलिए कि उनमें सैन्य शक्ति की कमी थी ? नहीं। उनकी सैन्य शक्ति दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी थी। लेकिन गांधी के नेतृत्व में जनता के संयुक्त संकल्प के विरुद्ध वे कुछ ही वर्षों तक हिन्दुस्तान की अपने अधिकार में रक्त सक्त थे। अब हिन्दचीन में फ्रांसीसियों ने वही सबक कहीं अधिक-मूल्य देकर सीखा है।

आप अमरीकी लोग कब सीखेंगे कि एशिया की समस्याएँ मूलतः राजनीतिक और भाषिक हैं, और सैन्य आवश्यकताएँ अपेक्षितमा गौण हैं ?

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : लेकिन हमने तो इसे मान लिया है। अपने चतुःसूत्री कार्यक्रम के द्वारा हमने एशियाई राष्ट्रों की सहायता करनी चाही है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और गरीबी, रोग और निरक्षरता को कम कर सकें।

बर्नो प्रोफेसर : मैं स्वीकार करता हूँ कि चतुःसूत्री कार्यक्रम दुनिया के अधिकतम

वादों चीन द्वारा भारे जाने के बाद हम उसे मान्यता कैसे दे सकते हैं ? अथ जल्दी है कि आप तय्यों को देखें । साम्यवादी चीन एक आक्रान्ता राष्ट्र है ।

बर्मा प्रोफेसर : लेकिन आप रुसियों को भी आक्रान्ता कहते हैं, और रुसी कम से कम उतने ही साम्यवादी है, जितने चीनी । फिर भी आपने साम्यवादी रुस को बीस वर्ष पहले मान्यता दे दी थी, और युद्धकाल में आप मित्रों के रूप में उनके साथ कन्या मिलाकर लड़े भी थे ।

हमसे से बहुतेरे एशियावासियों को यह विश्वास हो गया है कि आप चीन को इस कारण मान्यता नहीं देते कि चीनी रंगीन हैं, और आप लोग गोरे हैं । क्या आप अमरीकी लोग स्वयं अपने देश में भी रंगीन लोगों को हमारे दर्जे का नागरिक नहीं मानते ? अगर आप रंगीन लोगों को गोरे के समान ही समझते हैं, तो आप ने हमारे महायुद्ध में अणुबम जापानियों पर ही क्यों गिराया, जर्मनों पर क्यों नहीं ?

अमरीकी कूटनीतिज्ञ : यह बिलकुल फिजूल बात है । जर्मनों के साथ युद्ध समाप्त होने तक अणु बम तैयार भी नहीं हुआ था ।

बर्मा प्रोफेसर : कोई एशियावासी बड़ी मुश्किल में ही आपकी इस बात पर विश्वास कर सकेगा ।

(रात में देर तक इसी तरह बातचीत चलती रही ।)

×

×

×

यह रोपपूर्ण एशियावासी ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है, जिन पर तेहरान और तोक्वो के बीच रहने वाले करोड़ों अन्य एशियावासी विश्वास करते हैं ।

साम्यवाद में उसे कोई रुचि नहीं । वह सचमुच चाहता है कि लोकतंत्र चले । वह अमरीका में विद्वास करना चाहता है । वह चाहता है कि उसका देश स्थायित्व, समृद्धि और शांति के नए क्षितिजों की ओर बढ़े और विकसित हो ।

लेकिन उसे ऐसे अमरीका से चिंता होती है, जो विभ्रमित, और दुनिया के ऐसे लोगों से बटा हुआ प्रतीत होता है, जिन्हें उसका मित्र होना चाहिए । वह उद्दिग्ध और उसे बड़ा डर भी है ।

उसके गंभीर और बहुधा पक्षपातपूर्ण विश्वासों का इतिहास में बड़ा महत्त्व होगा, और उनके सामने युद्ध के हमारे हथियारों का पल्ला भी किमी दिन शायद हल्का पड़ जाय । हमें उसकी बात सुननी होगी । जब हम समझें कि वह गन्ती पर है तो उससे असहमति व्यक्त करें, लेकिन सुनें जरूर ।

तटस्थ राष्ट्र और भारतीय सफलता की कहानी

क्या हम अपने यूरोपीय मित्रों के मूल्य पर, विकासशील राष्ट्रों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देते रहे हैं ? श्री बौल्स का मत इसके विपरीत है, और वे उन सभी राष्ट्रों की सहायता करने का आग्रह करते हैं, जो हमारी सहायता का उचित उपयोग करें, चाहे वे मित्र हों या तटस्थ ।
दिस मध पत्रिका, जुलाई, 1962 ।

कथित अफ्रो-एशियाई गुट की ओर अधिकांश अमरीकियों का ध्यान अभी हाल ही में गया है । यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिन अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों का आज विश्व में प्रमुख स्थान है, उनमें से कइयों को पिछले कुछ वर्षों में ही स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है ।

संयुक्त राष्ट्र मध में इस समय जो 104 राष्ट्र हैं, उनमें से आधे एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र हैं । इन नए राष्ट्रों को विश्व संगठन में अभिव्यक्ति का एक अन्तर्राष्ट्रीय मध मिला है, और उन्होंने उसका पूरा उपयोग किया है ।

संयुक्त राष्ट्र मध में अफ्रीका और एशिया के देशों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण, सोवियत रूस की नीति की अपेक्षा अमरीकी नीति से कहीं अधिक अवसरों पर मेल खाते हैं । फिर भी, इतने काफी मतभेद बने हुए हैं, कि बहुतेरे अमरीकियों को चिंता होती है ।

पिछले कुछ महीनों में ये मतभेद और भी अधिक गभीर प्रतीत हुए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण अफ्रीकी और एशियाई नेताओं ने, रूस के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की कोशिश करते हुए, अमरीका की तीखी आलोचना की है ।

इसके साथ ही, भौतिक मामलों की बढ़ती हुई पेचीदगी, उलझे हुए प्रश्नों के शीघ्र और सरल उत्तरों का अभाव, और अणुशक्ति के बारे में कोई गलती हो जाने के निरन्तर बने हुए खतरे के फलस्वरूप बहुतेरे अमरीकियों में निराशा और विभ्रम की भावना धा गई है ।

यह निराशा बहुधा तटस्थ या अशुद्ध राष्ट्रों की धैर्यहीन आलोचना में व्यक्त होती है । हमारे कुछ अधिकांश परराष्ट्रवादी आलोचकों का आरोप है कि अमरीका अफ्रोएशियाई राष्ट्रों की ओर उचित से अधिक ध्यान देना रहा है, हम उनकी अनावश्यक 'मुत्तामद' करते हैं, और हमारी नीतियाँ 'व्यापहारिक' नहीं हैं ।

बहुधा ये मन ऐसे लोगों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, जो अपने को 'कठोर दयार्थ-

वादी' कहते हैं। जिन लोगों का दृष्टिकोण दुनिया के मामलों में अधिक संयमपूर्ण है, उन्हें ये लोग 'कल्पनाशील अ.दसंवादी' कहते हैं।

अपने को यथार्थवादी कहने वाले ये लोग, विदेश-नीति के निर्धारण में एक पुरानी और सुपरिचित विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। मैं समझता हूँ कि तथ्यों से यह पता चल जाएगा कि विश्व शक्तियों के प्रति अपनी जड़ता और वैयंहातता में वे गत ही अधिक होते हैं, सही कम।

उदाहरण के लिए, पहले महायुद्ध के तत्काल बाद, युद्धोद्विग्न और 'लोग ऑफ़ नेदान्स' की उनकी 'कल्पनाशील' धारणा के विरुद्ध इन 'यथार्थवादियों' के आक्रमणों के फलस्वरूप हम एक पीढ़ी तक दुनिया से कटे रहे, और दुनिया को 'युद्धों का अन्त करने वाले युद्ध' का भयंकर अनुभव फिर से करना पड़ा।

एशियाई और अफ्रीकी प्रश्नों के प्रति उनमें दृष्टि का जो अभाव रहा है, उसकी कीमत भी बहुत अधिक देनी पड़ी है। विश्व के मामलों में 'कठोर यथार्थवादी' विचारधारा के श्रेष्ठ समर्थकों को विश्वास था कि एक बार हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ब्रह्मा से उनके हट जाने के बाद, और अपना काम खुद चलाने का भार 'गैर जिम्मेदार देशों' लोगों के हाथ में आ जाने पर, ये देश शीघ्र ही टूट जाएंगे। और हाल में, उनका कहना था कि उन्हें सिलखाने वाले 'अनुभवी यूरोपीय' लोगों के बिना, मित्रों लोगों के लिए स्वयं नहर को चलाना सम्भव नहीं होगा।

लेकिन नतीजे बिल्कुल भिन्न निकले। ग्राम तौर पर ये राष्ट्र अपना शासन करने में बहुत ही सश्रम प्रमाणित हुए हैं, और वे दुबता के साथ अपनी विशाल समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

दूसरे महायुद्ध के बाद, 'कठोर यथार्थवादी' सेना के फ्रांसीसी दस्ते ने हिन्द चीन में एक अति भ्रूषतापूर्ण नीति अपनाएने के लिए फ्रांस की सरकार को राजी कर लिया। असंभव भौगोलिक-राजनीतिक स्थितियों में, एशिया में एक औपनिवेशिक चौकी कायम रखने का प्रयत्न करके उन्होंने उपनिवेशवाद के सभी एशियाई विरोधियों को राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों को, फ्रांस के विरुद्ध 'राष्ट्रीय मुक्ति' का एक सफल युद्ध चलाने के लिए हो-ची-मिन के अधीन एक संयुक्त मोर्चे में ढकेल दिया।

किन्तु हिन्द-चीन के विनाशकारी अनुभव से भी 'यथार्थवादियों' ने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने ही कई वर्षों तक इस बात को अस्मंभव बना रखा कि फ्रांस की सरकार अल-जीरिया वासियों के साथ कोई उचित समझौता करे। अभी पिछले दिनों ही, 'कठोर' विचारक अल-जीरिया के निराश औपनिवेशिकों को फिर ऐसे रास्ते पर ले जाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी ही हो सकता है।

'हम एशिया और अफ्रीका की चिन्ता न करें,' इस नीति के वर्तमान जड़ और बहुधा भयंकर गलतियाँ करने वाले समर्थकों में से बहुतेरे जाने-अनजाने, एक लम्बी और अहंकारपूर्ण परम्परा के अधिकृत सदस्य हैं, जो गोरों को दुनिया की जातियों में श्रेष्ठ मानती है। कुछ पीढ़ियाँ पहले उनके वैचारिक पूर्वज, कहीं भी 'देशी' लोगों के

नियंत्रण के बाहर जाते प्रतीत होने पर, 'घोटी गोनाबारी' की माँग किया करते थे।

अगर उन दिनों धर्म और दूरदर्शिता कुछ अधिक रही होती, और 'कठोर यथार्थ-वाद' कुछ कम रहा होता, तो आज एशिया और अफ्रीका की नई सरकारों के सामने जो दुर्गम बटिनाइयाँ हैं, उनकी कठोरता कुछ कम होती। इस युग में, जब अभिजात वर्ग तेजी से समाप्त हो रहा है, मोरो की भ्रष्टता की यह धारणा घातक हो सकती है।

पिछले सोलह वर्षों में, पुराने यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों में से चौपचासीस नए देशों का निर्माण हुआ है, जिनकी आवादी दुनिया की आवादी की तुलना एक तिहाई है। चूँकि ये नये देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के बारे में बड़े सावधान हैं, अतः वे ऐसी किन्हीं भी नीतियों पर नहीं चतना चाहते, चाहे वे अपने-आप में कितनी भी बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों न हों, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उन पर विदेशियों द्वारा लादी जा रही हैं। रूस और अमरीका दोनों के साथ इनके व्यवहार में यह दृष्टिकोण एक मीन बल के साथ लागू होता है।

अतः हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में आश्वस्त होना कि इन नए देशों में से हर एक, अपने सांस्कृतिक सन्दर्भ के अन्दर, स्वयं अपनी रीति से अपने भविष्य का निर्माण कर सकने की स्थिति में हो।

साम्यवाद को रोकने की क्षमता इस पर निर्भर नहीं है कि नए राष्ट्रों में अमरीकी तरीकों को अपनाने की तत्परता कितनी है, या उनके नागरिकों में अमरीकी बन्दूकें चलाने की योग्यता कितनी है। यह हर नए राष्ट्र की योग्यता पर निर्भर है कि वह अपने प्राकृतिक और मानवी साधनों का विकास कहाँ तक करता है, और अपनी शासकीय संस्थाओं को कहाँ तक राष्ट्रीय उद्देश्य की अपनी भावना के अनुरूप बनाता है।

अमरीका के वर्तमान रूप के निर्माण में कई पीढ़ियाँ लगी थीं, बड़ी मेहनत, बड़े बलिदान और काफी मात्रा में पूँजी की महायत्ना की आवश्यकता पड़ी थी। रूसी लोगो ने भी तीन या चार दशकों में एक आधुनिक औद्योगिक राज्य का निर्माण कर लिया, लेकिन उनके तरीके स्वतन्त्रता की हमारी धारणाओं के बिलकुल विपरीत हैं।

अब मध्य के मध्य में एशिया और अफ्रीका के अल्प-विकसित राष्ट्र हैं। यहाँ हम अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये करोड़ों व्यक्तियों में एक जबरदस्त दृढ़ता देखते हैं। पीढ़ियों की गरीबी और उपनिवेशवाद ने उन्हें तात्कालिकता की एक जबरदस्त भावना, और स्वतन्त्र रहने की दृढ़ता प्रदान की है।

फिर भी, स्वतन्त्रता के द्वारा समृद्धि का लक्ष्य एशिया और अफ्रीका उसी हालत में प्राप्त कर सकते हैं, जब अधिक सुविधा प्राप्त स्वतन्त्र राष्ट्र ईंगलिस्तान, अमरीका फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें।

अगर हम यह सहायता नहीं प्रदान करते, तो हम पूर्ण विश्वास रखें कि ये नए

राष्ट्र धृती की निष्क्रियता और निराशा में चुपचाप वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को देखा है, और किसी न किसी प्रकार उनमें अपना हिस्सा प्राप्त करने को वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

इस स्थिति में घन के साथ-साथ बड़े धैर्य और साहस की, विवेक, समझ और मवे-दनशीलता की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम एशिया और अफ्रीका में हो रही जड़दंस्त राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को आत्म-विकास की शान्तिपूर्ण धाराओं में संगठित कर सकें, तो इसमें हमको और नए राष्ट्रों को मचमुच बड़ा लाभ होगा।

दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि हम छोड़े-छोड़े अल्प-बड़े राष्ट्रों को लाल चीन के रास्ते पर जाते हुए देखें, जिनमें शायद उतनी ही भूख रहेगी लेकिन जो उतने ही स्पष्ट रूप में हमारे विनाश को अपना लक्ष्य बनाएंगे।

क्या यह लक्ष्य हमारी पहुँच के बाहर है? मैं ऐसा नहीं समझता। प्रमाण के रूप में, हम देखें कि एक ही अल्प-विकसित देश में एक पीढ़ी से कम समय के अन्दर क्या कुछ हुआ है।

हिन्दुस्तान पैंतालीस करोड़ लोगों का राष्ट्र है, लगभग उतने ही जितनी अफ्रीका और लातिन अमरीका की कुल आबादी है। 15 अगस्त, 1962 को स्वतंत्र, आधुनिक हिन्दुस्तान अपने पन्द्रह वर्ष पूरे करेगा। गांधी की प्रतिभा और अंग्रेजों की असाधारण समझदारी के फलस्वरूप, हिन्दुस्तान अपनी स्वतंत्रता का उत्सव अपने पुराने औप-निवेशिक शासकों के प्रति बड़ी सद्भावना के साथ मनाता है।

पिछले दस वर्षों में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय 42 प्रतिशत बढ़ी है, और अनाज की पैदावार 52 प्रतिशत बढ़ी है। 1947 में अनुमान था कि प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित होते थे। अब यह क्षीण करने वाला रोग लगभग लुप्त हो गया है। औसत जीवनावधि हिन्दुस्तान में 1947 में सत्ताइस वर्ष थी, अब बया-लिस वर्ष है।

ऐसे देश में जहाँ दस वर्ष पहले केवल 10 प्रतिशत लोग साक्षर थे, आज 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 60 प्रतिशत स्कूल जाते हैं। हिन्दुस्तान में औद्योगिक उत्पादन प्रति वर्ष 14 प्रतिशत बढ़ रहा है। यह रफ्तार दुनिया की सबसे ऊँची रफ्तारों में से एक है।

स्वतंत्रता के पहले वर्षों में हिन्दुस्तान ने एक संविधान बनाया, जिसमें अमरीका और दंगलिस्तान दोनों देशों के शासनों की विशेषताएँ हैं। तब से वह तीन राष्ट्रीय चुनाव करा चुका है, जो दुनिया में लोकतांत्रिक अधिकार का सबसे विशाल प्रयोग होता है, और उनमें मतदान का अनुपात अमरीका से अधिक था।

हिन्दुस्तान में भाषण की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतन्त्रता है, अखबारों की स्वतंत्रता है, और निजी उद्यम में सरकारी 'हस्तक्षेप' शायद हमारे समाज से भी कम है।

हिन्दुस्तान की सफलता बहुत कुछ स्वयं उसके अपने प्रयत्नों का फल है। हिन्दु-स्तानी लोगों ने बड़ी मेहनत की है, योग्य नेतृत्व का विकास किया है, अपने को

शिक्षित विया है, और ठोस अग्रजी प्रशिक्षण पर आधारित एक स्वस्थ शासकीय सेवा निमित्त की है। लेकिन अमरीका की उदार सहायता के बिना भारतीय लोकतंत्र की सफलता की संभावना शायद इतनी अधिक न होती। पिछले पन्द्रह वर्षों में हमने हिन्दुस्तान को आर्थिक सहायता के रूप में 3 अरब 80 करोड़ डॉलर प्रदान किए हैं।

इस सहायता का लगभग 55 प्रतिशत 'अतिरिक्त' वस्तुओं—गेहूँ, कपास, मक्का आदि के रूप में था। अन्य 42 प्रतिशत डॉलरों में सामग्री खरीदने के लिए था—इस्पात, रेलें और मशीनें, अधिकांश अमरीका में, अमरीकी मजदूरों द्वारा बनाई गई। शेष सहायता प्राथमिक परमासं और प्रशिक्षण के लिए थी।

बड़े पैमाने पर हमारी सहायता, और लोकतंत्रिक सिद्धान्तों में हिन्दुस्तान की निष्ठा के बावजूद, हिन्दुस्तान हमेशा हमसे सहमत नहीं होता। इस और चीन की भौगोलिक निकटता, और हिन्दुस्तान का अपना पुराना इतिहास बहूधा दुनिया के मामलों में हिन्दुस्तान को एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, उसी तरह जैसे दो महाभागों के बीच हमारी सुरक्षित स्थिति ने हमें एक शताब्दी से अधिक समय तक तटस्थ और अलगवादी बना रहने दिया, जबकि अग्रजी कूटनीति और अग्रजी नौ सेना शांति कायम रखती थी।

फिर भी, इस एशियाई देश की असाधारण सफलता का हमारी अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर महत्त्व है। बढ़ती हुई शक्ति और विश्वास से पूर्ण हिन्दुस्तान, एशिया में लाल चीन के विरुद्ध सन्तुलन प्रदान करता है, जिसका सर्वाधिक महत्त्व है। हिन्दुस्तान प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र केवल एक सुखद पश्चिमी सिद्धान्त ही नहीं है। व्यवहार में भी वह बड़ी अच्छी तरह काम करता है।

अतः जब हम एशिया और अफ्रीका के प्रवक्ताओं की आलोचनाओं से चिढ़ते और परेशान होते हैं, जो विश्व के मामलों में पूरी तरह हमारा दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते, तो हम इस पर भी विचार करें कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, फिलीपीन, और अन्य नए राष्ट्रों की सफलता से अ-साम्यवादी जगत को कितना बल मिला है, और अगर उनके प्रयत्नों को सफलता न मिलती, तो परिणाम कितना विनाशकारी होता।

दीर्घ कालीन दृष्टि से, हमारा राष्ट्रीय हित ऐसे राज्यों के एक विश्व समुदाय के निर्माण पर निर्भर है, ऐसा समुदाय जो मानवीय समस्याओं के सम्बन्ध में एक अधिकाधिक सामान्य दृष्टिकोण में हिस्सेदार हो। ऐसे विश्व समुदाय का साम्यवाद के पास कोई प्रभावकारी उत्तर नहीं है।

मध्यपूर्व में नई प्रवृत्तियाँ

मध्य-पूर्व के जीवन्त निवासियों का ध्यान अपने राष्ट्रीय साधनों के विकास में केन्द्रित होने पर, क्या इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तनाव कम होंगे ? श्री थौल्म अमरीकी यहूदी कांग्रेस के समक्ष न्यूयार्क में 12 अप्रैल, 1962 को दिये गए भाषण में ज्यादा अच्छे वातावरण के लिए सीमित आशा प्रकट करते हैं ।

मध्य पूर्व के सम्बन्ध में अमरीकी मत विद्ये दशक में ऊँची आशाओं, और पंभीर आशाकाओं के बीच भूलता रहा है । अब, कम से कम फिलहाल, वह बीच के किनी बिन्दु पर रुका हुआ प्रतीत होता है ।

अपने वर्तमान अनुमान में, हम किसी हद तक मान सकते हैं कि इस क्षेत्र के शीघ्र आर्थिक विकास और बढ़ती हुई राजनीतिक एकता के सम्बन्ध में हमारी ऊँची आशाओं में कमी हुई है । एक अन्य अर्थ में, वर्तमान स्थिति में हमारे शासन द्वारा, रूस द्वारा, और स्वयं मध्य पूर्व के राष्ट्रों द्वारा एक बहुत ही उलझी हुई और कठिन स्थिति के प्रति यथार्थवादी समंजन परिलक्षित होता है ।

सैंकड़ों वर्षों तक इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लोग युद्धों की और शोषण की ठोकें खाते रहे । पहले महायुद्ध ने स्वतंत्रता, समृद्धि और बढ़ती हुई एकता की ऊँची आशाएँ उत्पन्न कीं ।

किन्तु तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक शून्य को शीघ्र ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भर दिया, और पुराने संघर्षों के स्थान पर नए संघर्ष आ गए । हमारे महायुद्ध के बाद भरव जगत में यूरोपीय उपनिवेशवाद अन्ततः समाप्त हो गया, और एक स्वतंत्र नए राष्ट्र के रूप में इजराएल की स्थापना हुई ।

तीस बरुगा की इस अवधि में बहूतेरे अमरीकी हठपूर्वक हम आशा की अपनाए रहे कि अन्वत्र की भांति मध्य-पूर्व में भी किसी प्रकार बुद्धिमत्ता से काम लिया जाएगा, तेल से होने वाली तेजी से बढ़ती हुई आय का सारे क्षेत्र में अधिक प्रभावकारी उपयोग किया जाएगा, भरव और इजराएली लोग एक साथ रहता और काम सीखेंगे, और पानी की तथा शरणाधिकियों की सी समस्याओं के सम्बन्ध में सहयोग बढ़ेगा ।

कुछ वर्ष पहले, जब यह बात साक होने लगी कि वे आशाएँ जल्दी २

चाली नहीं, तो हमारा दृष्टिकोण अधिक निराशावादी हो गया। आज जब हम मध्यपूर्व की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट लगता है कि तीन महत्वपूर्ण मामलों में स्थिति सुधरी है, यद्यपि इसका प्रचार नहीं हुआ है।

1. साम्यवाद का आक्रामक धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। जारनाही का एक आधुनिक नस्करण होने के प्रतिरिक्त, सोवियत रूस तेल क्षेत्र में कम कीमत पर विक्री करने वाले एक प्रमुख प्रतियोगी के रूप में भी सामने आ रहा है।
2. मध्य-पूर्व के राष्ट्रों के साथ अमरीका के सम्बन्धों में अब तनाव कम है, और युगो पुराने भगड़ों के तात्कालिक हलौ की आशा अब अमरीका में कम की जाती है।
3. स्वयं मध्य-पूर्व के राष्ट्रों का ध्यान अब पड़ोसियों के साथ अपने भगड़ों पर कम है, और अपने आंतरिक विकास में उनकी रुचि बढ़ रही है।

इन तीन परिवर्तनों से मिलकर एक सामोश राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आई है, और अगर भाग्य ने साथ दिया, तो इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे सभी सम्बन्धित लोगों के बीच तनाव कम हो सकते हैं, और उन्हें विकास के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हमारे सकटग्रस्त विश्व में ऐसी राहें समाचारों में प्रमुख स्थान नहीं पाती, लेकिन इनसे इतिहास का निर्माण हो सकता है।

कुछ वर्ष पहले, बहुतेरे अमरीकियों को चिन्ता थी कि अरब राष्ट्रवाद साम्यवाद के पजे में फस जाएगा। लेकिन पिछले वर्षों में हमने देखा कि ये राजनीतिक दक्षिणों सचमुच एक-दूसरे के कितनी विरुद्ध हैं, और किसी विकासशील नए देश के क्रियाशील प्रयत्न विदेशी घुसपैठ के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा हो सकते हैं।

केवल मिस्र को देखना ही पर्याप्त होगा, जहाँ राष्ट्रपति नासिर असादान बाँध के लिए बड़े पैमाने पर रूसी सहायता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने देश का विकास स्वयं अपनी व्यावहारिक नीतियों के अनुसार कर रहे हैं। समुक्त अरब गणराज्य का नियंत्रण करना तो दूर रहा, खुश्चोव नासिर को स्थानीय साम्यवादी दल की कार्यवाहियों सहन करने के लिए भी राजी नहीं कर सके।

साथ ही, हमारे अपने शासन ने मध्य-पूर्व में हमारे प्रभाव की सीमाओं को समझ लिया है, और प्रयोगों की सफलता असफलता के द्वारा इस विस्फोटक क्षेत्र के बारे में जीवन के कुछ मूल तथ्य सीख लिए हैं। हमने विनये हप में यह भीय लिया है कि मध्य-पूर्व में हम जितना ममभते थे, हमारी आवश्यकताएँ उतने कम हैं, और यह कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अधिकतम सैन्य मुरशा के कार्यक्रम पर जोर देना, आवश्यक रूप में सर्वोत्तम उपाय नहीं है।

हमें सचमुच जल्द ही अपने पर्याप्त सचय की है, कि सीमा-मर्याद और विरोधी महत्वाकांक्षाओं कोई विरव-व्यापी सकट न उत्पन्न करने पाएँ, और इनकी काफी भिन्नता की है, त्रिनमें आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थित रीति से हो मके। मग्ने प्रतिक्र, हम चाहते हैं कि मध्य-पूर्व के राष्ट्रों का विकास एक स्वतंत्र विश्व समाज के स्वाधीन और घातम-सम्मानपूर्ण सदस्यों के रूप में हो, जो स्वयं अपने राष्ट्रीय

आदर्शों के अनुसार अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं और नियतियों का विकास करें।

मध्य-पूर्व में अपनी शिक्षा की प्रकिया में हमने, अत्यन्त की भाँति, तटस्थता के साथ, और विभिन्न प्रकार की सम्बद्धता के साथ रहना सीखा है।

इस क्षेत्र की आवश्यकताएँ बहुत ही अधिक हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, आक्रमण महा-मारियो, हत्याकांडों, और क्रान्तियों ने इस क्षेत्र के मानवी और प्राकृतिक साधनों को नष्ट किया है। अधिकांश रेगिस्तानों में सिंचाई की महान् योजनाओं के लडहर मिलते हैं। जिस भूमि पर से एक वार नमक साफ कर दिया गया, उसे फिर से खराब हो जाने दिया गया। पानी की निकासी के रास्ते भर गए हैं। सिंचाई के लिए बनाई गई सतहें नष्ट हो गई हैं। जहाँ हर चीज प्रकृति से लड कर छीननी पड़ती है, वहाँ अतीत के आर्थिक आधारों को फिर से क्रायम करना भी बहुत बड़ा काम है।

पिछले वर्षों में मध्य-पूर्व के नेताओं की अधिकाधिक सख्या इस बात को समझने लगी है कि उनकी जैसी जबरदस्त आन्तरिक समस्याएँ दब्द्राडम्बर से हल नहीं की जा सकतीं। भूमि का गलत बंटवारा, शिक्षा, और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, और दीर्घकाल से उपेक्षित सामाजिक सुधार, आन्तरिक विकास की ऐसी नित्य प्रति की समस्याओं की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

इस बीच अमरीका ने, जिसे मध्य-पूर्व में बहुत बड़ी सफलताएँ और असफलताएँ मिली, यह सीख लिया है कि वह एक समूचे उप-महाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों का निर्देशन नहीं कर सकता, और यह कि केवल डालरों से कोई समाज सुखी नहीं हो जाता। अधिक विशिष्ट रूप में, हम यह सीख रहे हैं कि अत्यन्त की भाँति मध्य-पूर्व में भी, प्रभावकारी अमरीकी विदेश-नीति की एक अर्थी वार्यँ आवश्यकता यह है कि हम लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हों—जीवन में अधिक सक्रिय भाग लेने की, अपनत्व की भावना में वृद्धि के लिए, और व्यक्तिगत न्याय तथा प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई मात्रा के लिए उनकी तीव्र आकांक्षा को ज्यादा अच्छी तरह समझें।

अनुभव ने हमें सिखाया है कि जब इन मानवीय तत्वों की उपेक्षा की जाती है, तो तेजी से होने वाला आर्थिक विकास बहुधा निराशा का कारण बन जाता है, क्योंकि एक ओर पुराने सामाजिक सम्बन्ध टूट जाते हैं, दूसरी ओर लोग जितना पा सकते हैं, उससे अधिक पाने की आशा हम उनमें जगा देते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को रोक नहीं जा सकता।

चुनौती दोहरी है—आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन खोजना, और यह काम ऐसी रीति से करना जिसमें व्यक्ति को अधिकाधिक मात्रा में निजी सन्तोष प्राप्त हो।

शाम तौर पर, मध्य-पूर्व की वर्तमान मन स्थिति विध्यात्मक है, और कुछ हद तक ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यह मन-स्थिति कायम रहेगी और विकसित होगी। अगर ऐसा हुआ तो विध्वंस, नगरों के विनास, बदलती हुई निष्ठाओं, और गहरे जमे हुए संघर्षों की लम्बी परम्परा टूटेगी, जो इतने लम्बे समय से मध्य-पूर्व की विशेषता रही है। यह एक स्वागत-योग्य घटना होगी।

लेकिन हमे खतरे की निरन्तर चल रही अन्तर्धारा को उपेक्षनीय नहीं समझना चाहिए। कोई एक विस्फोटक दुर्घटना ही इस समय धीरे-धीरे हो रही प्रगति के क्रम को उलट सकती है, और सारे क्षेत्र को रक्तमय अव्यवस्था में डकेल सकती है। इस बीच सबसे बड़ी क्षेत्रीय समस्याएँ बहुत-कुछ अछूती ही बनी रहती हैं, और उनके सरल हलों की आशा करना भूल होगी।

मिसाल के लिए, जार्डन नदी और अरब शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, जिन्होंने मध्य-पूर्व को स्थायी सकट की स्थिति में रखने में योग दिया है, सभी पक्षों की ओर से हार्दिक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी।

अन्ततोगत्वा, संभव है कि मध्य-पूर्व में किसी एक प्रभावी विचार का उदय हो, जिसके लाभ सभी सम्बन्धित पक्षों के लिए इतने महत्वपूर्ण हों कि परम्परागत मत-भेद भुला दिये जाएँ, जैसे यूरोप में उस समय 'सामान्य बाजार' ऐसे ही मतभेदों को मिटा रहा है। जब तक इस आवश्यक नयी मन स्थिति का विकास नहीं होता, तब तक हमें आर्थिक और राजनीतिक समझन की नित्य प्रति की समस्याओं के सम्बन्ध में यथार्थ के अनुरूप व्यवहार करना होगा।

यहाँ इजराएल की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। एक पीढ़ी से कम समय में, इजराएल ने दुनिया में विकास की सर्वाधिक तीव्र गतियों में से एक प्राप्त कर ली है—आठ प्रतिशत वार्षिक। उसका प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन 1,000 डालर प्रति वर्ष से अधिक है, जो उसके मध्य-पूर्वी पड़ोसियों से कहीं ज्यादा है, और हालैण्ड, इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, यूनान, या पुर्तगाल से भी ज्यादा है।

इजराएल की औद्योगिक विकास की गति 1961 में 14 प्रतिशत थी, दुनिया की उच्चतम गतियों में से एक। पिछले वर्ष की अपेक्षा उसका निर्यात 25 प्रतिशत अधिक था, और विदेशी मुद्रा की वृद्धि 65 प्रतिशत अधिक थी।

इसके साथ ही, अरब बहिष्कार ने इजराएल को मध्य-पूर्व के बाहर मित्रों और बाजारों की खोज करने को मजबूर किया। इसका एक फल यह भी हुआ कि इजराएल ने अन्य देशों को प्राविधिक सहायता पहुँचाने का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया, जो इस समय अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के बीस से अधिक राष्ट्रों में चल रहा है। पिछले वर्ष बावन देशों के एक हजार छात्र इजराएल में अध्ययन कर रहे थे, और दो सौ से अधिक इजराइली विशेषज्ञ अलाविकसित देशों में सलाहकारों का काम कर रहे थे।

इजराएल के पड़ोसी अभी इन प्रयत्नों को समझने और उनकी तारीफ करने की मन:स्थिति में नहीं हैं। इजराएल की सफलता ही अभी एक तर्कहीन विरोध-भावना उत्पन्न करती है। लेकिन जब मध्य-पूर्व के राष्ट्र स्वयं अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सफल होंगे, और उनमें नया विश्वास आने से सहिष्णुता और समझ का विकास होगा, तो यह स्थिति भी बदल सकती है।

इस प्रसंग में मध्य-पूर्व के लिए यथार्थ के अनुकूल अमरीकी नीति की मूल आवश्यकताएँ क्या हैं ?

प्रथम, अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने में इस क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की सहायता करने को हमें तैयार रहना चाहिए। इनके लिए, किसी भी श्रेणी से आक्रमण होने पर, पर्याप्त और तत्काल उपलब्ध अमरीकी रोक की आवश्यकता है।

दूसरे, हमें विशिष्ट तनावों को कम करने के लिए, और अरब-इजराएली झगड़े को खुले मध्य का रूप ग्रहण करने से रोकने के लिए, जो तंजो में फैल सकता है, संयुक्त राष्ट्र सभ के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

तीसरे, हमें सभी मध्य-पूर्वी देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने पड़ोसियों के साथ क्रुद्ध प्रचारात्मक बहसों में कम समय लगाएँ, और स्वयं अपने आन्तरिक विकास की समस्याओं को हल करने में ज्यादा। हम उन देशों को विशेष अग्रता-सहायता दे सकते हैं, जो केवल कुछ धनी लोगों की ही नहीं, बल्कि अपने सभी नागरिकों की हालत सुधारने के लिए सचमुच विग्नित हैं।

चौथे, मध्य-पूर्व के पड़ोसी राष्ट्रों के बीच मझुयोग का कोई आधार प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए, चाहे मझुयोग के क्षेत्र कितने भी अस्थायी या सीमित क्यों न हों।

मध्य-पूर्व में या अन्यत्र कहीं, स्थायित्व के लिए कोई मन्त्र नहीं है। अपनी विशाल सैन्य और औद्योगिक शक्ति के बावजूद, अन्यत्र की भाँति वहाँ भी घटनाओं को निर्देशित करने की हमारी क्षमता बिलकुल गौण है।

फिर भी, धैर्यपूर्ण कूटनीति, आक्रमण की धमकियों का सामना करने की दृढ़ सत्परता, हमारे लोगों के उद्देश्यों की सचेतनीय समझ, और प्राथिक विकास में सहायक होने में अपने साधनों का बुद्धिपूर्ण उपयोग, इनसे ही शायद हम अव्यवस्था को रोक कर, राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व में अभिवृद्धि कर सकते हैं।

कम से कम एक बात निश्चित है—केवल व्यापक सन्तुष्टि के निर्माण से ही, जिनके नागरिकों को वास्तविक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, और भौतिक सुविधाएँ प्राप्त हों, स्थायी विश्वशान्ति की स्थापना की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मध्य-पूर्व का भावी घटनाक्रम अनिश्चित है। लेकिन आशाहीन नहीं है।

अफ्रीका में एक यात्री

सहारा के दक्षिण में, श्रीमती चौला के साथ 1955 की सर्दियों में छह सप्ताह की अफ्रीका-यात्रा सम्बन्धी ये टिप्पणियाँ, जिनमें स्टेराक की पेंनी दृष्टि परिलक्षित होती है, अपने परिवार को लिये गए उनके अनौपचारिक पत्रों से ली गई हैं।

अफ्रीका भ्राने के पहले हम से बहुतेरे लोगो ने कहा था कि अफ्रीका एक नहीं है, वरन् उसके कम से कम आधे दर्जन टुक हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में केवल दो सप्ताह के अन्दर ही हमने ऐसा बहुत कुछ देखा है, जो दृग्-पूर्व-मूचना की पुष्टि करता है।

एक पराकाष्ठा पर मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका है, जिसमें लगभग 25 लाख फ्रांसीसी और इतालवी लोग निवास करते हैं। दूगरी पराकाष्ठा पर दक्षिण अफ्रीका है, जहाँ हठी गोरों की उतनी ही बढी सख्या है। पुत्तंगाली पूर्व और पश्चिम अफ्रीका, और अफ्रेजी पूर्व अफ्रीका भी इसी कारण और ऐसे ही विस्फोटक हैं—गोरे औपनिवेशिक, जो आए, देखा, पुता हुए, और जम गए।

अफ्रेजी पश्चिम अफ्रीका इसके विपरीत है, जहाँ यूरोपीय लोग कम हैं, और जहाँ स्वतन्त्रता का, जिम्मेदारी से मुक्त होने की उत्सुक अफ्रेज स्वागत करने। सहारा के दक्षिण में फ्रांसीसी अफ्रीका और बेल्जियन वागो की स्थिति भी भिन्न है, जहाँ ईमानदार औपनिवेशिक प्रशासकों की स्पष्ट योजनाएँ भी इन क्षेत्रों के भविष्य पर लगे हुए विशाल प्रश्न-चिन्ह को नहीं मिटा पायी। और अन्त में स्वतन्त्र अफ्रीका है—लाइबेरिया, इथियोपिया, मिस्र, सीरिया, और शीघ्र ही सूडान—जिनमें से हर एक के सामने अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं, जिनके लिए अब उपनिवेशवाद को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अफ्रीकी दृश्य की इन विभिन्नताओं में से कुछ इन टिप्पणियों में और बाद की टिप्पणियों में व्यक्त होगी। ये टिप्पणियाँ मैंने इच्छानुसार, अनियोजित ढंग से लिख डाली हैं और इनमें उस परिप्रेक्ष्य का अभाव है जो बाद में विमर्श और दूरी शायद प्रदान करें।

×

×

×

अफ्रीका का प्रभाव मुझे पर एक खाली महाद्वीप होने का पडता है। एशिया के बाद इस पर विशेषतः ध्यान जाता है, और दोनों का अन्तर मुझे निरन्तर प्रभावित

करता है। अफ्रीका में लोगों की सापेक्षिक अल्पसंख्या का क्या आर्थिक विकास की समस्या पर जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

मिसाल के लिए, बेल्जियन कांगो प्रशासनो में उतना ही समृद्ध है जितना हिन्दुस्तान, और लगभग उतना ही बड़ा है। लेकिन हिन्दुस्तान के छत्तीस करोड़ लोगों की तुलना में, उसकी आवादी केवल एक करोड़ बीस लाख है। उसके गवर्नर ने मुझे कहा—“अगर हमारी आवादी पांच गुनी होती, तो हमारा विकास दुगुनी तेजी से होता।”

एशिया में सरकारें आधुनिक मशीनों को प्रोत्साहित करने में हिचकती हैं। इतने अधिक लोगो को काम की जरूरत होने के कारण, वेतन और क्रय शक्ति में बड़ी धीमी गति से वृद्धि होती है। अफ्रीका में अभी भी धम की दृष्टि करने वाले हर ढंग का प्रयोग करने की मांग है। अतः अफ्रीका में कौशल का विकास होने पर, कहीं अधिक वेतनों और ऊँचे जीवन-स्तरों के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके राजनीतिक परिणाम उलझे हुए और अप्रत्याशित हो सकते हैं।

आज कांगो के कारखाने हिन्दुस्तान के कारखानों से कहीं ज्यादा आधुनिक हैं। कपड़ा मिल के मजदूर को दो डालर रोज के अलावा एक भूकान, अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा का पूरा खर्च, और भोजन भत्ता मिलता है।

×

×

×

एक अंग्रेज जिला अधिकारी से, जो 1938 में गोल्ड कोस्ट आया था, मैंने उस समय की उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा। उसने कहा, “प्रथम, कानून और व्यवस्था, और फिर संचार सुविधाएँ, और छूत के रोग। (छूत के रोग वे होते हैं, जिनके यूरोपीय लोगों को लगने की संभावना सबसे अधिक होती है।)

मैंने उससे पूछा कि अब उसका काम क्या है। उसके ढंग से ऐसा नहीं लगता था कि जो परिवर्तन हो गया है उसके महत्त्व को वह समझता है, किन्तु उसका उत्तर था, “प्रथम, गाँव की सड़कें और पानी। फिर स्कूल, मलेरिया नियंत्रण, गाँव के अस्पताल, और खेती के उत्पादन में सुधार।”

यह कहना अनुचित न होगा कि औपनिवेशिक सरकारों ने युद्ध के बाद से ही अफ्रीका के लोगों में रुचि लेनी आरम्भ की है। युद्ध के पहले ये सरकारें अफ्रीकियों के प्रति काम करती थीं। अब वे अफ्रीकियों के लिए काम करती हैं। यह ठोस प्रगति है। लेकिन जब तक वे उनके साथ काम नहीं करती, तब तक क्या आवश्यक साम्प्रदायिक बन सकती हैं ?

×

×

×

एक कट्टे अफ्रीकी ने मुझ से आकरा में कहा—“गोरे लोग ईसा के नाम पर अफ्रीका में गुलामी लाए।”

गलतियों में धर्म-प्रचारकों का भी हिस्सा रहा है, लेकिन भाड़ियों के इलाके में सफर करते हुए, मुझे उनकी स्फूर्ति, साहस और उद्देश्य भावना पर लगातार आश्चर्य

होता रहा। इसके प्रतिरिक्त, सामाजिक न्याय के लिए काले मनुष्य की भाँग के सम्बन्ध में धीरज खोने से पहले हम याद कर लें, कि हमारी ईसाई शिक्षाओं में ही उममें उन आकाशवाणी और आस्था का विकास हुआ है, जिन्होंने अब उसका 'उपयोग' कठिन बना दिया है।

×

×

×

गोल्ड कोस्ट में सम्भवतः अग्रज वही असमजित शिक्षा-व्यवस्था निर्मित करने जा रहे हैं, जो हिन्दुस्तान में इतनी अधिक सख्या में हताश बुद्धि-जीवियों को जन्म दे रही है।

जब मैंने एक अत्यन्त बुद्धिपूर्ण अग्रज से यह बात कही, उन्होंने उत्तर दिया, "हिन्दुस्तान में व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर गिर जाने दिया गया। यहाँ गोल्ड कोस्ट में हम ध्यान रखेंगे कि ऑक्सफोर्ड वाला स्तर कायम रहे।"

मैंने कहा, "क्या यह संभव नहीं कि आरगफोर्ड-कैम्ब्रिज या हार्वर्ड-येल वाली शिक्षा सभी योग्य अफ्रीकियों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा न हो, जिनके नए समाज को प्राविधिक कौशल प्राप्त करने की जरूरी है?"

उन्होंने उत्तर दिया, "नहीं, अफ्रीका के लिए आरग का सर्वोत्तम मार्ग आक्सफोर्ड जैसी शिक्षा ही है।" इसमें बहग की कोई गुंजाइश नहीं थी, और हमने बातचीत का विषय बदल दिया।

यद्यपि अफ्रीकी नेताओं के लिए उदार शिक्षा की आवश्यकता को कम समझना भूल होगी, किन्तु मेरा विचार है कि अग्रजों का एकांगी दृष्टिकोण अनुपयुक्त है। इस समय अगर किसी चीज पर बहुत अधिक जोर देने की जरूरत है, तो वह विरोपज्ञों का प्रशिक्षण है।

अफ्रीका को योग्य राजीतिक नेतृत्व के अलावा इमीनियरों, डाक्टरों और कृषि विरोपज्ञों की भी जरूरत है। जिसने भी एशिया और अफ्रीका को देखा है, वह इस सम्बन्ध में विवाद नहीं करेगा कि दोनों को ही वकीलों की जरूरत कम है और खेत में या जंता मशीं कहते हैं, 'भाभी' में काम करने वाले विरोपज्ञों की जरूरत ज्यादा है।

शिक्षा के सम्बन्ध में विरोधी औपनिवेशिक दृष्टिकोण बड़े दिलचस्प हैं। अग्रज लोग विश्वासपूर्वक अच्छी शिक्षा के लामो पर भरोसा करते हैं, विरोपज्ञ: ऑक्सफोर्ड स्तर की शिक्षा पर, और उनका ह्वाला है कि जितने अधिक स्नातक हों, उतना ही अच्छा। गोल्ड कोस्ट के तीन हजार भाबी नागरिक इस समय विदेशों में अग्रजों भायी सख्याओं में शिक्षा पा रहे हैं और एक हजार छात्रों के लिए ऑक्सफोर्ड के नमूने पर एक विश्व-विद्यालय आकरा में बन रहा है।

दूसरी ओर बेल्जियम अधिकांश शिक्षित अफ्रीकी के ह्वाला से ही भडकते हैं। कांगो के ग्यारह लाख इस समय बेल्जियम में पढ रहे हैं। अन्य किसी देश में एक भी नहीं। और लियोपोल्डविले के बाहर जिन विश्वविद्यालयों की अभी गुरुणात भर हुई है, उसके बारे में ह्वाला है कि जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है, उसमें स्नातकों

अफ्रीका में एक यात्री

की संख्या प्रतिवर्ष 'छह या सात से अधिक नहीं' होगी।

फ्रांसीसी लोग इन दोनों पराकाष्ठाओं के बीच कहीं अपना मार्ग तलाश कर रहे हैं। फ्रांसीसी भूमध्य-क्षेत्रीय अफ्रीका के (जिसका क्षेत्र अमरीका का प्राचा है, लेकिन प्राचादो केवल चालीस लाख है) तीन सौ छान फांस में पड़ रहे हैं। उनमें से अधिकांश को उदार कलाओं से दूर, विशेष व्यवसायों की शिक्षा दी जा रही है।

सब मिलाकर शिक्षा की सुविधाएँ सभी औपनिवेशिक देशों में तेजी से बढ़ रही हैं। सामान्य अनुमान है कि छह वर्ष के बच्चों में से आधे स्कूल जाते हैं, जो अगर सही है, तो हिन्दूस्तान से अधिक है।

फ्रांसीसी भूमध्य क्षेत्रीय अफ्रीका और वेल्जियन वागो में सारे समय में केवल चार अफ्रीकियों से मेरा परिचय नाम लेकर कराया गया। वे सभी दब्यु थे, और उन्होंने अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की। फिर भी लियोपोल्डविले में मैंने उनमें से तीन से पूछा "वर्तमान व्यवस्था में आपके लोग सबसे अधिक आलोचना किस बात को करते हैं?" एक क्षण को हिचक के बाद उत्तर मिला, "राजनीतिक भेदभाव की उतनी नहीं जितनी सामाजिक भेदभाव की। एक काला शहर है, और एक गोरा शहर है, और अंधेरा होने के बाद एक का मदभी दूसरे में नहीं जा सकता।"

×

×

×

मध्य अफ्रीका में हमारे अमरीकी सूचना कार्य का लक्ष्य विशाल अफ्रीकी बहुसंख्या नहीं है, जो भविष्य का निर्माण करेगी, वरन् बहुत ही थोड़े-से यूरोपीय लोग हैं। लियोपोल्डविले के हमारे पुस्तकालय में पुस्तकें लेने के लिए 680 लोगों ने नाम दर्ज कराए हैं। उनमें केवल बारह अफ्रीकी हैं।

कुल 4,300 पुस्तकें हैं जिनमें से केवल 280 फ्रांसीसी भाषा में हैं। मैंने पूछा कि लियोपोल्डविले में कितने लोग अंग्रेजी बोल या पढ़ सकते हैं। उत्तर मिला, "शापद अठारह सौ, जिनमें से कुछ को छोड़कर दोष गव वेल्जियन हैं।"

हमारे थोड़े-से घन को अधिक श्रुद्धिपूर्ण रीतियों से खर्च करने के तरीके अवश्य ही होंगे। अगर हम अफ्रीकी बहुसंख्या के समक्ष अपनी बात सफाई से नहीं कह सकते तो हमें अपने प्रयत्नों को कहीं और केन्द्रित करना चाहिए।

यद्यपि लियोपोल्डविले में दो प्रमुख दैनिक पत्र हैं, किन्तु तीन लाख अफ्रीकियों में उनकी केवल 1,600 प्रतिर्या विकती हैं। शंका लु यूरोपीय लोगों को इन अफ्रीकों से बड़ी सात्वना मिलती है, क्योंकि उनसे पता चलता है कि खतरनाक विचारों को कम से कम किया जा सकता है।

×

×

×

उत्तरी रोडेसिया की जिन स्थान में हम गए, वहाँ 9,000 अफ्रीकी खनिक हैं, और 1,500 यूरोपीय हैं। दोनों के अपने अलग सगटन हैं।

यूरोपीय खनिकों का औसत मासिक वेतन 294 डालर है। इसके अलावा उन्हें 60 प्रतिशत 'ताँब बोनस' मिलता है, और मासूनी मासिक चन्दे पर एक प्रति प्राधु-

निक मरान मिलता है, और मामूली मासिक चन्दे पर एक प्रति मास्युनिक बचक की सदस्यता मिलती है। उनका वेतन अमरीकी ताँबा मिनिको से काफी अधिक है, यद्यपि जीवन-निर्वाह का खर्च अमरीका का लगभग आधा है।

जर्मन के नीचे काम करने वाले अमरीकी मिनिक का औसत मासिक वेतन 18 डालर है, जिनके अलावा उसे एक छोटा, लेकिन उगरी ढक्कनों के लिए पर्याप्त मान मिलता है, दैनिक भोजन का राशन मिलता है, और मुफ्त बिजली मिलती है। गभी सुविधाओं को ध्यान में रखे, तो अनुमान लगभग 20 और 1 का है। ये चीजें सप पासन द्वारा प्रकाशित 'मथली डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक' (मासिक मारिपरी मार) के दिगम्बर, 1964 संस्करण में लिये गए हैं।

निस्सन्देह, अफ्रीकियों की अपेक्षा यूरोपीय ऐमा काम अधिर करने हैं जिनमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कामों के लिए जिनकी अमरीकी मान में वेतनों का अनुपात तीन और दो का, या अधिक से अधिक दो और एक का होगा।

दक्षिणी रोडेसिया में औसत वेतन उत्तरी रोडेसिया में लगभग 30 प्रतिशत कम है। कानूनी न्यूनतम वेतन 15 डालर मासिक है, और सत्तर प्रतिशत अफ्रीकी न्यूनतम स्तर पर हैं। मुझे बताया गया कि सारे सप में, कम से कम वेतन पाने वाले यूरोपीय से अधिक वेतन पाने वाले अफ्रीकी 'दो दर्जन से अधिक नहीं' हैं।

मैंने पूछा कि अफ्रीकी दैनिक क्या वेतन मांगते हैं। उत्तर मिला, "अठारह पाउण्ड (48 डालर) मासिक, जो स्पष्टतः राजनीतिक उद्देश्यों से ही गई, उम तत्वों की माँग है।"

X

X

X

मैंने एक उच्च अधिकारी से कहा, "मे कुछ उलभन में हूँ। मुझे बताया गया है कि गोलड कोस्ट के अफ्रीकी, और दक्षिणी रोडेसिया के अफ्रीकी एक ही बान्धु जाति के हैं। लेकिन गोलड कोस्ट के चार हजार द्वाय देश-विदेश के कालेजों में पढ़ने जाते हैं, जब कि यहाँ सारे सप में केवल पचाम अफ्रीकी स्नातक हैं। इसके अतिरिक्त, गोलड कोस्ट के शासन में बहुसंख्यक बड़े ही योग्य अफ्रीकी हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं हैं। इसका कारण क्या है?"

अधिकारी थोड़ा परेशान नजर आया। उन्होंने स्वीकार किया कि बात अजीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी इन पर सचमुच विचार नहीं किया था।

उत्तर सरल है। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन अफ्रीकियों की प्रगतिके लिए हर तरह के प्रयत्न कर रहा है। यहाँ मध्य अफ्रीकी सप में, उपनिवेश विभाग का दखल कम होने के कारण, दो लाख विशेषाधिकारयुक्त यूरोपीय लोग साठ लाख अफ्रीकियों की आशाओं और आकांक्षाओं के मार्ग में चट्टान बनकर अडे हुए हैं। ये टूटी हुई आशाएँ किस दिन फूट पड़ेंगी।

X

X

X

अफ्रीका में एक यानी

पुनरावलोकन करते हुए, मैं कागो के सम्बन्ध में कुछ बातें और जोड़ दूँ। बेल्जियम लोग, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, इस विशाल क्षेत्र के विकास का एक सुनिश्चित, सुसंगठित, और तर्कसंगत कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस कार्यक्रम की दुर्बलता यह प्रतीत होती है कि वे अफ्रीकियों को किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा—प्राविधिक शिक्षा भी—प्राप्त नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि तब अफ्रीकी लोग अपने भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी में अधिकाधिक हिस्से की माँग करने लगेंगे।

खतरा इस सभावना में नहीं है कि बेल्जियन लोग अन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद की शक्ति से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि इसमें है कि जब वे दबाव में आकर समझौता करेंगे, तो अफ्रीकी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगभग पूर्णतः अनुभवहीन होंगे, जिनकी वे निश्चित रूप में माँग करेंगे, और अन्ततः प्राप्त करेंगे।

यद्यपि अंग्रेजी उपनिवेशों में राजनीतिक शान्ति काँगों की तुलना में बहुत कम प्रतीत होती है, किन्तु इसका कारण यह है कि दक्षिणी रोडेशिया के अतिरिक्त, अंग्रेज लोग सचमुच अफ्रीकियों को यथासंभव अधिक से अधिक शासकीय अनुभव प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। फलस्वरूप, जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ वहाँ अन्ततः सत्तासूड होंगी, तो अपेक्षतया शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण की संभावना, वहाँ मुझे अधिक प्रतीत होती है।

×

×

×

दक्षिणी रोडेशिया में जो यूरोपीय लोग हमें मिले, उन्होंने हमारा बड़ा सत्कार किया और बड़ी मित्रता का व्यवहार किया। इस कारण उनकी नीतियों और दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में अपनी परेगानी को कठोरता से व्यक्त करने में मुझे कुछ दुःख होता है। एक अतिम उदाहरण से संकेत मिलेगा कि वे जिन्दगी की असलियतों से कितनी दूर हैं, और वहाँ जातीय भेदभाव से अपेक्षतया मुक्त यूगाण्डा की तुलना में स्थिति कितनी भिन्न है।

सैलिसबरी में हमारे सम्मान में तीन भोज हुए, सभी में औपचारिक पोशाक आवश्यक थी। अन्तिम भोज गवर्नर-जनरल ने दिया, जिसमें हमारे अलावा सोलह व्यक्ति और थे। सोलह में केवल दो ही उपाधिहीन थे—दो युवा सैनिक सहायक, जो हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे थे। दो 'लार्ड' थे, पाँच 'सर' थे, और उनकी पत्नियाँ थीं। इन तीनों ही पार्टियों में किसी 'देशी' यादमी का वैसे ही कोई स्थान नहीं था, जैसे किसी भेड़िए का।

यूगाण्डा में स्थिति प्रसन्नतादायक रूप में भिन्न थी। पहली रात, खूबसूरत विक्टोरिया झील के किनारे गवर्नर के भवन में भोज के समय कम्पाला के भारतीय मेयर उपस्थित थे, कई अफ्रीकी अधिकारी थे, और दो अमरीकी समाज शास्त्री व उनकी पत्नियाँ थीं। दूसरी रात कम्पाला में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें भारतीयों और अफ्रीकियों की संख्या यूरोपीय लोगों से कहीं अधिक थी। एक

निक मकान मिलता है, और मामूली मासिक खर्चे पर एक प्रति मासुनिक खर्च की गहरयता मिलती है। उनका वेतन अमरीकी ताँबा गणियों से काफी अधिक है, यद्यपि जीवन-निर्वाह का खर्च अमरीका का लगभग आधा है।

अमीन के नीचे काम करने वाले अफ्रीकी गणिक या प्रयोग मासिक वेतन 18 डालर है, जिनके अलावा उसे एक छोटा, लेकिन उगरी उम्बरों के लिए पर्वण मकान मिलता है, दैनिक भोजन का राशन मिलता है, और मुग्न विहरणा मिलती है। सभी सुविधाओंको ध्यान में रखें, तो अनुयात लगभग 20 और 1 का है। ये प्राँडे सप शासन द्वारा प्रशासित 'मथनी हाइजेस्ट प्राँक स्टैटिस्टान' (मासिक गारिखी मार) के दिग्ग्यर, 19५4 संस्करण में लिखे गए हैं।

निरम्गदेह, अफ्रीकियों की अघेसा गुरोपीय लेगा काम अधिख करने हैं जिनमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कामों के लिए जिनो अमरीकी मान में वेतनो का अनुयात तीन और दो का, या अधिक से अधिक दो और एक का होगा।

दक्षिणी रोडेसिया में प्रयोग वेतन उत्तरी रोडेसिया में लगभग 30 प्रतिशत कम है। कानूनी न्यूनतम वेतन 15 डालर मासिक है, और सत्तर प्रतिशत अफ्रीकी न्यूनतम स्तर पर हैं। मुझे बताया गया कि सारे सप में, कम से कम वेतन पाने वाले गुरोपीय से अधिक वेतन पाने वाले अफ्रीकी 'दो दर्जन से अधिक नहीं' हैं।

मैंने पूछा कि अफ्रीकी गणिक क्या वेतन माँगते हैं। उत्तर मिला, "अठारह पाउण्ड (48 डालर) मासिक, जो स्पष्टतः राजनीतिक उद्देश्यों से की गई, उस तत्वों की माँग है।"

×

×

×

मैंने एक उच्च अधिकारी से कहा, "मैं कुछ उलभन में हूँ। मुझे बताया गया है कि गोल्ड कोस्ट के अफ्रीकी, और दक्षिणी रोडेसिया के अफ्रीकी एक ही वाग्नू जाति के हैं। लेकिन गोल्ड कोस्ट के चार हजार दान देश-विदेश के कालेजो में पढ़ने जाते हैं, जब कि यहाँ सारे सप में केवल पचास अफ्रीकी स्नातक हैं। इसके अतिरिक्त, गोल्ड कोस्ट के शासन में बहुसंख्यक बड़े ही योग्य अफ्रीकी हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं है। इसका कारण क्या है?"

अधिकारी थोड़ा परेशान नजर आया। उन्होंने स्वीकार किया कि बात अजीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी डम पर सचमुच विचार नहीं किया था।

उत्तर भरत है। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन अफ्रीकियों की प्रगति के लिए हर तरह के प्रयत्न कर रहा है। यहाँ मध्य अफ्रीकी सप में, उपनिवेश विभाग का दखल कम होने के कारण, दो लाख विशेषाधिकारपुक्त गुरोपीय लोग साठ लाख अफ्रीकियों की आशाओं और आकांक्षाओं के मार्ग में चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। ये दूटी हुई आशाएँ किस दिन फूट पड़ेंगी।

×

×

×

पुनरावलोकन करते हुए, मैं वागो के सम्बन्ध में कुछ बातें धीरे जोड़ दूँ। बेल्जियम लोग, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, इन विदाल क्षेत्र के विकास का एक मुनिपोजित, मुसगठित, और तर्कसंगत कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस कार्यक्रम की दुर्बलता यह प्रतीत होती है कि वे अफ्रीकियों को किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा—प्राविधिक शिक्षा भी—प्राप्त नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि तब अफ्रीकी लोग अपने भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी में अधिकाधिक हिस्से की माँग करने लगेंगे।

खतरा इस सभावना में नहीं है कि बेल्जियन लोग अन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद की शक्ति से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि इसमें है कि जब वे दबाव में आकर समझौता करेंगे, तो अफ्रीकी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगभग पूर्णतः अनुभवहीन होंगे, जिनकी वे निश्चित रूप में माँग करेंगे, और अन्ततः प्राप्त करेंगे।

यद्यपि अंग्रेजी उपनिवेशों में राजनीतिक शान्ति काँगों की तुलना में बहुत कम प्रतीत होती है, किन्तु इसका कारण यह है कि दक्षिणी रोडेसिया के अतिरिक्त, अंग्रेज लोग सचमुच अफ्रीकियों को यथासंभव अधिक से अधिक शासकीय अनुभव प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। फलस्वरूप, जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ वहाँ अन्ततः सत्ताह्व होंगी, तो अपेक्षतया शान्तिपूर्ण संक्रमण की संभावना, वहाँ मुझे अधिक प्रतीत होती है।

×

×

×

दक्षिणी रोडेसिया में जो यूरोपीय लोग हमें मिले, उन्होंने हमारा बड़ा मत्कार किया और बड़ी मित्रता का व्यवहार किया। इस कारण उनकी नीतियों और दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में अपनी परेशानी को कठोरता से व्यक्त करने में मुझे कुछ दुःख होता है। एक अतिम उदाहरण से संकेत मिलेगा कि वे जिन्दगी की असुलियतों से कितनी दूर हैं, और वहाँ जातीय भेदभाव से अपेक्षतया मुक्त यूगाण्डा की तुलना में स्थिति कितनी भिन्न है।

सैलिसबरी में हमारे सम्मान में तीन भोज हुए, सभी में औपचारिक पोशाक आवश्यक थी। अन्तिम भोज गवर्नर-जनरल ने दिया, जिसमें हमारे अलावा सोलह व्यक्ति और थे। सोलह में केवल दो ही उपाधिहीन थे—दो युवा सैनिक सहायक, जो हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे थे। दो 'गार्ड' थे, पाँच 'सर' थे, और उनकी पत्नियाँ थीं। इन तीनों ही पार्टियों में किसी 'देशी' आशमी का वैसे ही कोई स्थान नहीं था, जैसे किसी भेड़िए का।

यूगाण्डा में स्थिति प्रसन्नतादायक रूप में भिन्न थी। पहली रात, खूबसूरत विक्टोरिया झील के किनारे गवर्नर के भवन में भोज के समय कम्पाला के भारतीय मेयर उपस्थित थे, कई अफ्रीकी अधिकारी थे, और दो अमरीकी समाज शास्त्री व उनकी पत्नियाँ थीं। दूसरी रात कम्पाला में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें भारतीयों और अफ्रीकियों की संख्या यूरोपीय लोगों से कहीं अधिक थी। एक

निक मकान मिलता है, और मामूली मासिक बन्दे पर एक अति प्राधुनिक पत्र की सदस्यता मिलती है। उनका वेतन अमरीकी तौरा खनिकों से काफी अधिक है, यद्यपि जीवन-निर्वाह का खर्च अमरीका का लगभग आधा है।

जमीन के नीचे काम करने वाले अफ्रीकी खनिक का औसत मासिक वेतन 18 डालर है, जिसके अलावा उसे एक छोटा, लेकिन उमकी जरूरतों के लिए पर्याप्त मकान मिलता है, दैनिक भोजन का राशन मिलता है, और मुफ्त विद्विता मिलती है। मभी सुविधाओं को ध्यान में रखे, तो अनुपात लगभग 20 और 1 का है। ये अंकड़े सभ शासन द्वारा प्रकाशित 'मथली डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स' (मासिक सांख्यिकी सार) के दिसम्बर, 1964 संस्करण से लिये गए हैं।

निस्सन्देह, अफ्रीकियों की अपेक्षा यूरोपीय ऐसा काम अधिक करने हैं जिनमें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कामों के लिए किसी अमरीकी खान में वेतनों का अनुपात तीन और दो का, या अधिक से अधिक दो और एक का होगा।

दक्षिणी रोडेसिया में औसत वेतन उत्तरी रोडेसिया में लगभग 30 प्रतिशत कम है। कानूनी न्यूनतम वेतन 15 डालर मासिक है, और सत्तर प्रतिशत अफ्रीकी न्यूनतम स्तर पर हैं। मुझे बताया गया कि सारे सभ में, कम से कम वेतन पाने वाले यूरोपीय से अधिक वेतन पाने वाले अफ्रीकी 'दो दर्जन से अधिक नहीं' है।

मैंने पूछा कि अफ्रीकी खनिक क्या वेतन मांगते हैं। उत्तर मिला, "अठारह पाउण्ड (48 डालर) मासिक, जो स्पष्टतः राजनीतिक उद्देश्यों से की गई, उग्र तत्वों की मांग है।"

×

×

×

मैंने एक उच्च अधिकारी से कहा, "मैं कुछ उलझन में हूँ। मुझे बताया गया है कि गोल्ड कोस्ट के अफ्रीकी, और दक्षिणी रोडेसिया के अफ्रीकी एक ही बान्दू जाति के हैं। लेकिन गोल्ड कोस्ट के चार हजार छात्र देश-विदेश के कालेजों में पढ़ने जाते हैं, जब कि यहाँ सारे सभ में केवला पचास अफ्रीकी स्नातक हैं। इसके अतिरिक्त, गोल्ड कोस्ट के शासन में बहुसंख्यक बड़े ही योग्य अफ्रीकी हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं है। इसका कारण क्या है?"

अधिकारी थोड़ा परेशान नजर आया। उन्होंने स्वीकार किया कि बात अजीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी इन पर सचमुच विचार नहीं किया था।

उत्तर सरल है। ब्रिटिश पूर्वो अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन अफ्रीकियों की प्रगति के लिए हर तरह के प्रयत्न कर रहा है। यहाँ मध्य अफ्रीकी सभ में, उपनिवेश विभाग का दखल कम होने के कारण, दो लाख विशेषाधिकारमुक्त यूरोपीय लोग साठ लाख अफ्रीकियों की आशाओं और आकांक्षाओं के मार्ग में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। ये टूटी हुई आशाएँ किस दिन फूट पड़ेंगी।

×

×

×

पुनरावलोकन करते हुए, मैं वांगो के सम्बन्ध में कुछ बातें और जोड़ दूँ। वेल्जियम लोग, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, इन विद्यालय क्षेत्र के विकास का एक सुनियोजित, सुसंगठित, और तर्कसंगत कार्यक्रम चला रहे हैं।

इस कार्यक्रम की दुर्बलता यह प्रतीत होती है कि वे अफ्रीकियों को किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा भी—प्राप्त नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि तब अफ्रीकी लोग अपने भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी में अधिकाधिक हिस्से की माँग करने लगेंगे।

खतरा इस सम्भावना में नहीं है कि वेल्जियम लोग अन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद की शक्ति से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि इसमें है कि जब वे दबाव में आकर समझौता करेंगे, तो अफ्रीकी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगभग पूर्णतः अनुभवहीन होंगे, जिनकी वे निश्चित रूप से माँग करेंगे, और अन्ततः प्राप्त करेंगे।

यद्यपि अंग्रेजी उपनिवेशों में राजनीतिक शान्ति काँगों की तुलना में बहुत कम प्रतीत होती है, किन्तु इसका कारण यह है कि दक्षिणी रोडेसिया के अतिरिक्त, अंग्रेज लोग सचमुच अफ्रीकियों को यथासंभव अधिक से अधिक शासकीय अनुभव प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। फलस्वरूप, जब राष्ट्रवादी शक्ति वहाँ अन्ततः सत्ताह्व होगी, तो अपेक्षतया शान्तिपूर्ण संक्रमण की संभावना, वहाँ मुझे अधिक प्रतीत होती है।

×

×

×

दक्षिणी रोडेसिया में जो यूरोपीय लोग हमें मिले, उन्होंने हमारा बड़ा सत्कार किया और बड़ी मित्रता का व्यवहार किया। इस कारण उनकी नीतियों और दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में अपनी परेशानियों को कठोरता से व्यक्त करने में मुझे कुछ दुःख होता है। एक अंतिम उदाहरण से सूक्त मिलेगा कि वे जिन्दगी की असुलियतों से कितनी दूर हैं, और वहाँ जातीय भेदभाव से अपेक्षतया मुक्त यूगाण्डा की तुलना में स्थिति कितनी भिन्न है।

सैलिसवरी में हमारे सम्मान में तीन भोज हुए, सभी में औपचारिक पोशाक आवश्यक थी। अन्तिम भोज गवर्नर-जनरल ने दिया, जिसमें हमारे अलावा मोलह व्यक्ति और थे। मोलह में केवल दो ही उपाधिहीन थे—दो युवा सैनिक सहायक, जो हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे थे। दो 'लार्ड' थे, पाँच 'सर' थे, और उनकी पत्नियाँ थीं। इन तीनों ही पार्टियों में किसी 'देशी' आदमी का बँसे ही कोई स्थान नहीं था, जैसे किसी भेड़िए का।

यूगाण्डा में स्थिति प्रसन्नतादायक रूप में भिन्न थी। पहली रात, मूबमूरत विक्टोरिया झील के किनारे गवर्नर के भवन में भोज के समय कम्पाना के भारतीय मेयर उपस्थित थे, कई अफ्रीकी अधिकारी थे, और दो अमरीकी समाज शास्त्री व उनकी पत्नियाँ थीं। दूसरी रात कम्पाना में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें भारतीयों और अफ्रीकियों की संख्या यूरोपीय लोगों से कहीं अधिक थी। एक

अफ्रीका में अमरीका की भूमिका

श्री वॉल्स का कथन है कि 1955 में अमरीका की कोई अफ्रीकी नीति नहीं थी। वे कुछ मूल सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं, जिन पर एक वस्तुपरक नीति को आधारित होना चाहिए, और जिन्हें अथ व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है। कोलियर्स पत्रिका, 10 जून, 1955।

अपनी अन्य सारी चिन्ताओं का बोझ लिए हुए, अधिकांश अमरीकियों की प्रवृत्ति यह पूछने की है—“मैं आखिर अफ्रीका के बारे में चिन्ता क्यों करूँ? मेरे लिए अफ्रीका का क्या मतलब हो सकता है?”

अफ्रीका उनके लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एशिया के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा है। उसके प्रसाधनों के बारे में पूरी तरह कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम जानते हैं, कि ये प्रसाधन बहुत अधिक हैं।

अभी भी, हम रणनीतिक महत्त्व के यूरेनियम, रबड़, कोबाल्ट, मंगनीज, औद्योगिक हीरे, क्रोमियम, सीसा, जस्ता, कच्चा लोहा, और बाक्साइट के लिए अफ्रीका की ओर देखते हैं—और अफ्रीका की खनिज सम्पत्ति को अभी तो मुश्किल से खरोचा भर गया है। अब अवेले फ्रांसीसी भूमध्य-क्षेत्रीय अफ्रीका में ही सत्तर भूवैज्ञानिक दल काम कर रहे हैं, और बेल्जियम कागो व ब्रिटिश अफ्रीका में भी कम से कम उतना ही व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

लेकिन आज अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण विकास शायद उसके 20 करोड़ या अधिक लोगों का जागरण है। एक लम्बी रात के बाद अफ्रीकी दैत्य अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अपना आलम दूर करके हाथ-पाँव फैला रहा है, जिसमें जीवन के निकट घा रहे कैंगोयों की सारी उत्सुक, अधीर भावनाएँ हैं। अगले कुछ वर्षों में अफ्रीका पर विस्फोटक समस्याएँ, नषर्ष, और समाचार छा जाएँगे। हम अमरीकी लोग चाहें या न चाहें, हमें उनकी चिन्ता करनी पड़ेगी।

इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि नए जागरण का गभीर राजनीतिक महत्त्व है। अफ्रीकियों द्वारा चुपचाप दूमरे दर्जे की नागरिकता स्वीकार कर लेने के दिन तेजी में बीत रहे हैं। हो सकता है कि वे अनिच्छापूर्वक कुछ और विलम्ब स्वीकार

कर लें, लेकिन आघातभूत प्रश्नों पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

हर जगह अफ्रीकी लोग पश्चिम से कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुतेरे प्रश्नों के जातीय लाक्षणिक अर्थ भी हैं—“जब गोरे यूरोपीय लोग अफ्रीका से इतना अधिक धन ले जा रहे हैं, तो हम काले अफ्रीकी लोग इतने गरीब क्यों हैं?” “जब ईसाई धर्म सभी मनुष्यों को भाई मानता है, तो अधिकांश यूरोपीय और अमरीकी लोग अब भी हमारे साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव क्यों बरतते हैं?”

विशेषतः अमरीकियों से अफ्रीकी लोग पूछते हैं—“अपनिवेशवाद का विरोध करने के अपने लम्बे इतिहास के बावजूद, आपका शासन अब अफ्रीकी स्वतंत्रता के प्रश्न पर खामोश क्यों रहता है? संयुक्त राष्ट्र सभ में आप निरन्तर इस समस्या को टालते क्यों हैं?”

हमारी अफ्रीकी नीति क्या है? ऐसा कहना उचित होगा कि इस समय हमारी कोई नीति नहीं है। इसलिए नहीं है, कि वर्षों से हम मानते आए हैं कि अफ्रीका केवल इंगलिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल, और बेल्जियम का एक प्रसार है, और यह कि एक यूरोपीय नीति से अफ्रीका का भी काम चल सकता है। इसी प्रकार के विनाशकारी दृष्टिकोण के फलस्वरूप हमने हिन्दचीन को एशियाई समस्या न मानकर फ्रांसीसी समस्या माना। अफ्रीका में हमें ऐसे दृष्टिकोण की क्रोमत् और भी अधिक देनी पड़ सकती है।

कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि अफ्रीका के सम्बन्ध में तर्कसंगत नीति का विकास कोई आसान काम है। यह एक ऐसा विषय है, जिसपर यूरोपीय जनमत बड़ी आसानी से जागता और प्रभावित होता है। यह बड़ा ही उलझा हुआ प्रश्न है, जिसमें विवेकहीन, जातीय आडम्बर की बड़ी संभावना है। अपने प्रयत्नों के लिए दिशा-संकेत के रूप में मेरे मुझाव निम्नलिखित हैं :

1. हम सबसे पहले यहाँ से प्रस्थान करें कि अफ्रीका पर हमारा नियन्त्रण नहीं है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की हमें कोई इच्छा नहीं है, और जो कुछ हम वहाँ कर सकते हैं, उसकी कठोर सीमाएँ हैं।

2. अपने यूरोपीय मित्रों को औपनिवेशिक नीतियों के सम्बन्ध में दंभपूर्ण उपदेश देने, या अफ्रीकी लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए सस्ती लोक-प्रियता की नीति अपनाएँ के बजाएँ, हम सार्वजनिक रूप में ही नहीं, कमरों में होने वाली बैठकों में भी, स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वाले हर व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रस्ताव का समर्थन करें।

3. अन्ततः स्वयं अफ्रीकी लोग ही स्वतंत्रता की गति निर्धारित करेंगे। किन्तु अगर हम अफ्रीकियों को यह विश्वास दिला सकें कि जितनी जल्दी वे इसकी व्यवस्था कर सकें, उतनी जल्दी उनके स्वतंत्र होने का हम ईमानदारी से समर्थन करते हैं, तो हम इस स्थिति में होंगे कि उन अफ्रीकियों की माँगों को संशोधित कराने में सहायक हों सकें, जो अपनी योग्यता से अधिक अधिकार चाहते हैं। समय के पूर्व स्व-शासन

से केवल असफलताएँ हाथ आएँगी, जिमसे उग्रतावादी लाभ उठाएँगे।

4. अगर हिन्दुस्तान की भाँति गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया, व्यवस्थित, लोकतांत्रिक रीति से, स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विकसित होते हैं, तो उन लोगों को अपनी राय बदलनी पड़ेगी, जो सचमुच ऐसा मानते हैं कि भविष्य में भी जहाँ तक देखा जा सकता है, अफ्रीकी अपना शासन स्वयं नहीं चला सकेंगे।

इन नए उभरते हुए, स्वतंत्र पश्चिम-अफ्रीकी शासनों की सफलता के हित में अमरीका जो भी कुछ कर सकता है, उसे इस रचनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। इसका मतलब केवल हमारे शासन द्वारा आर्थिक सहायता ही नहीं बरन् कर्पादा संस्थाओं और धर्म-संगठनों आदि निजी संस्थाओं द्वारा सक्रिय, कल्पनाशील सहायता कार्य भी है।

5. इसी कारण हमें उदारता से और बुद्धिपूर्वक उन अफ्रीकी राष्ट्रों को भी सहायता करनी चाहिए, जो पहले से ही स्वतंत्र हैं—मिस्र लीबिया, इथियोपिया, लाइबेरिया, और इनमें शीघ्र ही शामिल होने वाला सूडान। उनकी प्रगति, दूसरों की गति निर्धारित करने में सहायक होगी।

6 अफ्रीका में किसी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तैयार होने के पहले, हमें ध्यानपूर्वक उसकी जाँच कर लेनी चाहिए कि वह सभी जातियों के लोगों को पूरा अवसर प्रदान करता है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप में भी, अपने को अफ्रीका में विदेशी प्रभुत्व के जारी रहने के साथ सम्बद्ध कर लेते हैं, तो हमारा प्रभाव प्रष्ट हो जायेगा।

7. विदेश विभाग को अफ्रीका की ओर पहले से कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। आज अफ्रीका में हमारे कूटनीतिक कार्यालय बहुत कम हैं। यद्यपि कर्मचारियों की योग्यता और ईमानदारी ने मुझे सामान्यतः काफी प्रभावित किया, किन्तु उनमें से अधिकांश के पास उचित से बहुत अधिक काम है, और इतने बड़े क्षेत्रों की जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनकी शारीरिक क्षमता से बहुत अधिक हैं।

8. हमें अपने लक्ष्यों को भी अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित करना चाहिए। विदेश विभाग, और अमरीकी सूचना एजेंसी के लोगों को आदेश दे देना चाहिए कि उनके कार्य का प्राथमिक उद्देश्य अफ्रीकियों के साथ कार्यात्मक सम्बन्ध और निवृत्त मद्भावना का विकास करना है, केवल चोटी के मुठ्ठी भर यूरोपीय शासकों के साथ सम्बन्ध बनाना ही नहीं। अफ्रीका में हमारे सूचना कार्यक्रम में काफी अधिक वृद्धि करनी चाहिए, और उसे घोरो के बजाएँ अफ्रीकियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

9. स्वयं अमरीका में अब अफ्रीकियों के वंशज एक करोड़ साठ लाख अमरीकी हैं, जिनमें से बहुतेरे हमारे अपने लोकनिय के विकास में सक्रिय योग दे रहे हैं। निजी और अधिवृत्त, दोनों ही रूपों में, उन अमरीकियों से ज्यादा अच्छे राजदूत अफ्रीका में और नहीं हो सकते, जो स्वयं अफ्रीका के वंशज हैं।

यात्री-अध्यापकों, शिक्षकों, शासकीय कर्मचारियों और धर्म-प्रचारकों के रूप में योग्य अमरीकी नीचो लोगों की अफ्रीका में उरस्थिति मात्र से भी सभी सम्बन्धित लोगों को बड़ा लाभ होगा।

10. अमरीकी विश्व-विद्यालयों में अफ्रीका की ओर पहले से कही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अमरीका में अफ्रीका सम्बन्धी अध्ययन के जो दो केन्द्र इन समय भी चल रहे हैं, इन्हें निजी संस्थाओं और अन्य माधनों की सहायता से पुष्ट करना और उनका विस्तार करना चाहिए, और उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए।

11. कूटनीतिक साधनों से हमें अपने यूरोपीय मित्रों को सुभाव देना चाहिए कि एक अफ्रीका सम्मेलन बुलाया जाय, और एक अफ्रीकी घोषणा-पत्र तैयार किया जाय। यह घोषणा-पत्र स्व-शासन के प्रतिमान निर्धारित कर सकता है, और यूरोपीय शक्तियों के इस इरादे को समस्त रीति से पुनः प्रस्तुत कर सकता है, कि वे निरन्तर और मोह्वेय रीति से स्व-शासन की ओर कदम उठाएँगे।

अगर यूरोप की पूंजी और वैज्ञानिक कौशल, तथा अफ्रीका के मानव और प्राकृतिक साधनों के बीच एक साम्प्रदायी कायम हो सके, तो अफ्रीका और यूरोप दोनों के ही लिए भविष्य अधिक समृद्ध और मन्तोपजनक हो सकता है।

एक अग्रज अधिकारी ने मुझ से कहा—“हमें अफ्रीकियों की माँगों के आगे चलना होगा, अन्यथा हम समाप्त हो जाएँगे। अगर हम बहुत धीरे-धीरे चलते हैं, तो वे इतने जबररस्त विस्फोटक दबाव उत्पन्न करेंगे कि हम अव्यवस्था में फँस जाएँगे। बुद्धिमानी का काम यही है कि हम उनकी माँगों को पहने से ही समझें, और दबाव उत्पन्न होने के पहने ही व्यवस्थित रीति से उन माँगों को स्वीकार कर लें।”

इस स्थिति में अमरीका को एक ऐतिहासिक भूमिका अदा करनी है। कुशल, बुद्धिपूर्ण, और ईमानदार नीतियों के द्वारा हम यूरोप और अफ्रीका के सर्वोत्तम अंशों को प्रीन कर सकते हैं। हम उन भावश्यक साम्प्रदायी की स्थापना में सहायता कर सकते हैं, जो स्वतंत्रता के क्षेत्रों का विस्तार करने में और सभी मनुष्यों की नैतिक प्रगति में सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्रों को अफ्रीका की चुनौती

जब 1960 की गमियों में नए स्वतंत्र कोंगो में विस्फोट हुआ, तो अफ्रीका में एक नए और खतरनाककरणक्षेत्र की संभावना ने इस अपूर्व प्रस्ताव को प्रेरित किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ सभी गैर-अफ्रीकी शक्तियों के लिए एक 'आचार-संहिता' के विकास के लिए कदम उठाए। थ्यू-थार्क टाइम्स मंगलवार, 21 अगस्त, 1960।

अंधेरे आकाश में किसी ज्वाला के चमक उठने की तरह, कांगों में हाल ही में हुआ विस्फोट दिखाता है कि अफ्रीका की समस्याएँ कितनी व्यापक और गहरी हैं, और उस महाद्वीप के साथ नया सम्बन्ध स्थापित करने में साहसपूर्ण अमरीकी नेतृत्व की आवश्यकता कितनी अधिक है।

मैं समझता हूँ कि समस्या की कुंजी इसमें है कि अफ्रीका के आर्थिक और राजनीतिक पुन्य को भरने में नेतृत्व करने की क्षमता संयुक्त राष्ट्र संघ में है, और अधिकांश अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ को इस रूप में स्वीकार करने के लिए असाधारण रूप में उत्तर है।

अतः अफ्रीका में एक विध्यात्मक नई अमरीकी नीति का प्रस्थान-बिन्दु, संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान की एक नाटकीय रूप में विस्तृत धारणा होनी चाहिए—ऐसा योगदान जिसमें न केवल आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा शामिल हो; बल्कि आर्थिक प्रगति और व्यवस्थित राजनीतिक संक्रमण भी शामिल हो।

महासभा के शरदकालीन सत्र में, अफ्रीका में सभी गैर-अफ्रीकी शक्तियों के व्यवहार के सम्बन्ध में एक आचार-संहिता के लिए एक अमरीकी प्रस्ताव पेश करके इस नए दृष्टिकोण की पर्याप्त नाटकीयता प्रदान की जा सकती है।

इस घोषणा-पत्र में, बड़ी शक्तियाँ अफ्रीका में क्या नहीं करने को सहमत हैं, केवल इसका एक नकारात्मक वक्तव्य ही नहीं होना चाहिए। घोषणा-पत्र को प्रस्तावित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य रचनात्मक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यवाही के एक व्यापक कार्यक्रम पर सहमत हों, जो नए अफ्रीकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आश्वासन दे, उनके व्यवस्थित राजनीतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे, और शीत-युद्ध की खीच-तान से उन्हें बड़ी हद तक मुक्त करे।

संयुक्त राष्ट्रों को अफ्रीका की चुनौती

इस प्रकार की प्रतिबद्धता से अधिक विकसित राष्ट्र इस योग्य हो सकेंगे कि शक्ति-गुटों की छतरनाक रूप में स्थिर प्रतिद्वन्द्विता के बजाए, जिम्ने पध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में दुनिया को युद्ध के कगार कर गड़ा कर रखा है, वे संयुक्त राष्ट्र मंच के 'तटस्थ' माध्यम के द्वारा अफ्रीका की विज्ञान और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सकें ।

हम कुछ अधिक विस्तार से विचार करें कि इन प्रतिबद्धताओं में से कुछ क्या हो सकती हैं ।

1. सभी राष्ट्रों द्वारा इस बात की गारंटी कि वे अफ्रीका में आन्दोलनात्मक प्रचार नहीं करेंगे, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विध्वंसात्मक कार्यवाही को समाप्त करेंगे । संयुक्त राष्ट्र सच को अधिकार हो कि उल्लंघन के सभी आरोपों की जांच करे और महासभा को सूचित करे ।

2. अफ्रीका में हथियारों की होड़ को बढ़ावा न देने के लिए, ऐसा ही समझौता वर्तमान परिस्थितियों में नए अफ्रीकी राष्ट्रों की वास्तविक सैन्य आवश्यकताएँ बहुत कम हैं । ये आवश्यकताएँ कम ही रहें, इसमें हमारा भी लाभ है, और अफ्रीकियों का भी ।

3. बड़ी शक्तियों के बीच एक समझौता कि अफ्रीका के लिए अधिकांश आर्थिक, प्राविधिक और शैक्षिक सहायता संयुक्त सच के माध्यम से दी जाय । संयुक्त राष्ट्रों की विशेष एजेन्सियों, प्राविधिक सहायता प्रशासन, विशेषनिधि, विश्व बैंक, और नए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में इस कार्य के लिए आवश्यक प्रशासन-यंत्र पहले से ही मौजूद है ।

अब आवश्यकता है, अनिवार्य ही शीत-युद्ध की प्रतिद्वन्द्विता को प्रविष्ट कराने वाले द्विपक्षीय समझौते के पुराने मार्ग के स्थान पर, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम का उपयोग करने के संकल्प की ।

4. संयुक्त राष्ट्रों की एक नई प्रशासन सेवा संगठित करके, अनुभवी प्रशासकों, इंजीनियरों, प्राविधिक विशेषज्ञों, अध्यापकों, और हर प्रकार के व्यावसायिक लोगों के लिए अफ्रीका की तात्कालिक आवश्यकता को शीत-युद्ध के घेरे के बाहर पूरा करने का एक व्यापक और कल्पनाशील प्रयत्न किया जाय ।

तेजी से अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए, एक पीढ़ी या और अधिक समय तक, अफ्रीकी नीति-निर्माताओं के अजीब गैर-अफ्रीकी प्रशासकीय अधिकारियों की आवश्यकता होगी । मूल प्रश्न यह है—ये गैर अफ्रीकी कहाँ से लिए जाएँगे ? इनकी प्रथम निष्ठा किनके प्रति होगी ? क्या वे शीत-युद्ध को अफ्रीका में लाने के उपकरण बनेंगे ? अथवा, क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन और सद्भावना के उद्देश्य में सहायक होंगे ?

5. कानों में आज जिन प्रकार काण हो रहा है, उनके आधार पर अफ्रीका में और पन्द्रह प्रयोग करने के लिए एक स्थायी पुनित वन की स्थापना । कौनों राष्ट्र

को आन्तरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता की आशा अब मुख्यतः ऐसे बल से ही है । न केवल यूरोपीय नियंत्रण हटने के परिणामस्वरूप, वरन् स्वयं नए अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने पर, अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे तनावों का उत्पन्न होना निश्चित है ।

वर्तमान अफ्रीकी निष्ठाओं के साथ अगर राष्ट्रीय सीमाओं का मेल करना चाहें, तो एक दूसरे को पुष्ट करने और काटने वाले हितों का एक विचित्र नक्शा उभरता है । इस स्थिति में कई सघ प्रस्तावित हुए, घोषित हुए, और खत्म हो गए, जिससे अब तक भी काफी टकराव पैदा हुआ है ।

इन मामलों में परिणाम का नियंत्रण करना, यथास्थिति को बनाए रखना या परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम नहीं है, चाहे इस तरह के काम कितने भी बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों न प्रतीत हों । यह मामला सिर्फ स्वयं अफ्रीकियों के नियंत्रण करने का है ।

लेकिन यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी स्थितियों को हिंसात्मक रूप लेने से रोके, और विशेषतः बड़ी शक्तियों को किसी पक्ष की ओर से हस्तक्षेप करने से रोके । अगर मुख्यतः अफ्रीकी राष्ट्रों द्वारा ही भर्ती किया गया पर्याप्त पुलिस बल मौजूद हो, तो वह बाहर से प्रत्यक्ष, एक पक्षीय, सैन्य हस्तक्षेप के लोभ को संयमित करने में बड़ा उपयोगी हो सकता है ।

6. प्रस्तावित अफ्रीकी घोषणा-पत्र एक विशेष अफ्रीकी न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था कर सकता है जो सम्भवतः विश्व न्यायालय से सम्बद्ध हो, और जिसे विशिष्ट रूप में अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच, और अफ्रीकी राज्यों तथा बाहरी राष्ट्रों के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार हो ।

ऐसा न्यायालय, जिसके मददगार अधिकांश अफ्रीकी राष्ट्रों से लिये गए हों, लेकिन केवल उन्हीं से नहीं, बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध एक अन्य दावा का काम करेगा— बसतें कि अफ्रीकी राज्यों को इसके लिये राजी किया जा सके कि वे बिना बहुसंख्यक शर्तों लगाए, उसके अधिकार-क्षेत्र को स्वीकार कर लें ।

मेरा यह मतलब नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अशान्त नए अफ्रीका की सारी समस्याओं का बोझ सफलतापूर्वक उठा सकता है । किन्तु मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं को शीत-युद्ध के विस्फोटक विरोधों में अलग करके उन्हें हल करने की चेष्टा करने का सबसे प्रभावकारी माध्यम संयुक्त राष्ट्र संघ प्रदान कर सकता है ।

क्या हमारा अपना शासन इसके लिए तैयार है कि अफ्रीका के प्रति हमारे वर्तमान अपर्याप्त और विफल दृष्टिकोण का परिवर्तन करके, वहाँ विध्यात्मक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक नया साहसपूर्ण प्रयत्न आरम्भ करें ?

अगर हम भीरु बनकर दम भवसर का उपयोग नहीं करते, तो एक बात निश्चित है—अफ्रीका तेजी से शीत-युद्ध का एक सतरनाक नया रणक्षेत्र बन जायेगा, और इसके विस्फोटक रूप में अनिश्चित परिणाम होंगे ।

अफ्रीका में आशा की लहर

अदिस अबाबा, इथियोपिया में, अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक वमीशन की एक बैठक में, मुख्यतः अफ्रीकी श्रोताओं के समक्ष फरवरी, 1962 में श्री वॉल्स अफ्रीकी, एशियाई, और लातिन अमरीकी मामलों में राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में, अफ्रीका के प्रति प्रशासन का नया दृष्टि कोण निरूपित करते हैं।

हम यहाँ इस विशाल, गतिशील अफ्रीकी महाद्वीप की तात्कालिक चुनौती पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके 22 करोड़ लोग अपनी भूमि और अपने भविष्य की असंमित संभावनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

आशा की लहर कही भी इतनी तेज या इतनी गहरी नहीं है, जितनी यहाँ अफ्रीका में। कही भी ऐसे आधुनिक समाजों का निर्माण करने के लिए आधुनिक प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करने का दृढ़ निश्चय यहाँ से अधिक नहीं है, जिनमें शरीबी, रोग और दमन का स्थान समृद्धि, प्रगति और न्याय से लेंगे।

पन्द्रह वर्ष पहले कितने लोग कल्पना कर सकते थे कि अट्टाइस स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्रों की यह बैठक अपने लोगों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य पर विचार करने के लिए यहाँ अदिस अबाबा में होगी?

अमरीका अपने को अफ्रीका के साथ, और विशेषतः अफ्रीका के भविष्य के साथ किस रूप में सम्बद्ध करता है? यहाँ हमारे लक्ष्य क्या हैं?

हम विनम्रता की भावना के साथ आरम्भ कर रहे हैं। अफ्रीका के सम्बन्ध में अपने सम्बन्धित ज्ञान पर, और आपके लोगों के साथ अतीत में सम्पर्क के अभाव पर हम बहुत ही लज्जित हैं। इन वर्षों में आपके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करने में हमारी असफलता में, हमारे अपने देश के विकास पर हमारे ध्यान का बहुत अधिक केन्द्रित रहना परिलक्षित होता है।

यह एक विरोधाभास है, कि जिन सक्रियता के साथ हमने स्वयं अपनी समस्याओं का सामना किया, उसके कारण हमें अन्य लोगों के संपर्क का ज्ञान ही बहुत कुछ नहीं हो सका, जो उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए हम अपनी उप-निवेश-विरोधी क्रान्ति में लड़े थे।

जिन जातीय संधियों ने हमारे अपने देश में कठिनाइयाँ उत्पन्न की थीं, उनके कारण भी हम अफ्रीका में विनम्रता की भावना लेकर आते हैं। हमारे लोगो में में 10 प्रतिशत से अधिक के पूर्वज अफ्रीकी थे। सो वर्ष पहले, हमारे महान् गृह-युद्ध में, इंग्लिश गुलामी को अमरीका से रातम करने के लिए दस लाख गोरे अमरीकी मरे थे।

तब से दोनों जातियाँ निरन्तर स्थिर गति से सहयोग और पारस्परिक भादर का आधार निमित्त करती रही हैं। विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में, भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने में बहुत अधिक प्रगति हुई है।

यद्यपि मेरे देश में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने मनुष्य की समानता के महान् नैतिक यथार्थ को अभी भी स्वीकार नहीं किया है, किन्तु भेदभाव की समाप्ति अब स्पष्ट दिखाई दे रही है।

सभी जातियों के विचारशील अमरीकी इस समय अफ्रीका में जो गभीर रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें हम अपने सामान्य संधियों की अभिव्यक्ति देखते हैं। अफ्रीका और अफ्रीकियों के सम्बन्ध में पुस्तकें, फिल्मों, और पत्र-पत्रिकाओं में लेखों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या इस रुचि का प्रमाण है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, हमारे प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह भी है कि शीत युद्ध को अफ्रीका के बाहर रखा जाय। इसमें हमारा भी हित है, और आपका भी, कि इस दुष्ट संधयों की कटुता, विभाजकता, और आर्थिक अर्थव्यय से यथासंभव आप लोगो को मुक्त रखा जाय।

हमारा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की सर्वाधिक भाशा एक सबल संयुक्त राष्ट्र संध में है। यही कारण है कि कागो में संयुक्त राष्ट्रों के खर्च का लगभग 50 प्रतिशत अमरीका वहन करता है, और हर जगह संयुक्त राष्ट्रों के कार्यक्रमों का सक्रिय समर्थन करता है।

आर्थिक क्षेत्र में, अफ्रीका के बहुतेरे नए राष्ट्रों के साथ प्रभावकारी कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जिससे आपके समाजों को सबल बनाने में सहायता मिलेगी, उससे हमारे अपने समाज को भी सबल बनाने में सहायता मिलेगी।

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अफ्रीका अफ्रीकी राष्ट्र जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उससे हमें उत्साह मिला है। नीचे लिखी बातें विशेषतः महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती हैं:

प्रथम, यद्यपि आप औद्योगिक योजनाओं की तीव्र आवश्यकताओं को समझते हैं, किन्तु आपने येनी और ग्राम-विकास के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की है। एशिया और दक्षिण अमरीका की भाँति, आपके तीन-चौथाई लोग गाँवों में रहते हैं। वही लोग भोजन उत्पन्न करते हैं, और अन्ततः नगरों में बनी विनिर्मित वस्तुओं को खरीदने की अधिकतम क्रय-शक्ति भी उन्हीं को प्रदान करनी होगी।

जिना गाँवों में बढ़ती हुई मृष्टि, शिक्षा, और न्याय के, उन ठोस आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक आधारों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिन पर कोई

विवसित अर्थ-व्यवस्था टिकी होती है।

दूसरे, मानव भूत्यों और मानवीय सम्बन्धों के महत्त्व के सम्बन्ध में आपके आग्रह की हम प्रशंसा करते हैं। यद्यपि आर्थिक प्रगति आवश्यक है, किन्तु अगर वह प्रगति व्यक्तियों के रूप में लोगों की प्रतिष्ठा और कल्याण के प्रति आदर रखते हुए नहीं होनी, तो राष्ट्र के राजनीतिक स्थायित्व पर इसका प्रभाव कम ही पड़ता है।

तीसरे, हम शिक्षा के महत्त्व पर आपके आग्रह के प्रशंसक हैं। आपकी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल व्यवस्था के तेजी से विकास में, और दीर्घ-कालीन दृष्टि से उच्च शिक्षा की संस्थाओं के निर्माण में, किसी आधुनिक समाज का निर्माण करने में शिक्षा के प्रमुख योग के प्रति अफ्रीका का आदर और समझ परिलक्षित होती है।

चौथे, हमें खुशी है कि आप में से बहुतों, आसानीय धन के अतिरिक्त निजी पूँजी की ओर ध्यान देने को भी तैयार हो रहे हैं, जो बहुतों अधिक विकसित देशों में उपलब्ध है। हमारे धन का सबसे बड़ा भाग निजी पूँजी के रूप में है, जिसमें हमारे लोगों की संचित वचत लगी हुई है।

किन्तु अमरीकी शासन, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों ही आधारों पर, अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता को निरन्तर बढ़ा रहा है। 1962 में अफ्रीका में हमारे कुल षष्ठों, अनुदानों, प्राविधिक सहायता, शोध-उत्पादन की विक्री और अनुदानों का, और मयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में हमारे योग का जोड़ संभवतः 52 करोड़ डॉलर से अधिक होगा।

गैर-सरकारी स्तर पर जन सहयोग के हमारे कार्यक्रम भी बढ़ रहे हैं। शांति-सेना के माध्यम में, सैकड़ों अमरीकी माध्यमिक स्कूल शिक्षक आपके कई देशों में पढ़ा रहे हैं, और अन्य सैकड़ों आ रहे हैं।

जितना वे सिखाते हैं, इस अनुभव से वे उतना ही सीखेंगे भी। इस समय लगभग तीन हजार अफ्रीकी छात्र अमरीका में पढ़ रहे हैं और सीखने के साथ-साथ सिखा रहे हैं।

हमारे युवा लोग विशेषतः अफ्रीका में एक ऐसा महाद्वीप देखते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी नई बातें हो रही हैं, जहाँ नई आगएँ, नए अवसर और नई सीमाएँ खुल रही हैं। युवा अमरीकियों के इस आकर्षण को मैं प्रत्यक्ष अनुभव से जानता हूँ, क्योंकि पिछले डेढ़ साल से मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधु नाइजीरिया सरकार के कर्मचारियों के रूप में नाइजीरिया के एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने रहे हैं। उनके पत्रों से मुझे भविष्य के युवा अफ्रीकी नेताओं के मन की कुछ झलक मिली है।

शोर मचाने में, अफ्रीका के आर्थिक एकाकरण में आपकी बढ़ती हुई रुचि की मैं प्रशंसा करता हूँ।

एकता के कई भिन्न मार्ग हैं। जो मार्ग आपने सर्वाधिक उपायुक्त लगे, उसे चुनना आपके हाथ में है। किन्तु एक बात साफ है—औद्योगिक दृष्टि से अतीविकसित 'मातृ' देशों, और उनके द्विपक्षीय रीति से कायम रहे गए औद्योगिक-आधारों का युग हमेशा

के लिए खतम हो चुका। इस परिवर्तन ने कुछ बिलकुल नए धार्मिक यथार्थों को जन्म दिया है। क्षेत्रीय धार्मिक समूहों के विकास में ये यथार्थ परिमिश्रित होते हैं।

किन्तु अफ्रीकी क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के मार्ग में भय भी बहुत बढ़ी आधाएँ हैं। उदाहरण के लिए, किसी महाद्वीप में स्वतंत्र प्रभुसत्ताओं की संख्या इनकी अधिक नहीं है, जितनी अफ्रीका में। इनमें से अधिकांश का निर्माण दूरस्थ शोषित-वैशिक राजघानियों से वर्षों पहले विदेशियों में हुए समझौतों के फलस्वरूप हुआ था।

आज ये सामंतीय इकाइयाँ राष्ट्रीय यथार्थ बन गई हैं, जिनमें करोड़ों लोग तेजी से और सगर्व अपने राष्ट्रीय भविष्य का विकास कर रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता का उमड़ता हुआ नया गर्व, और अधिक तेजी से धार्मिक विरासत के लिए आवश्यक क्षेत्रीय सहयोग, इनमें किसी प्रकार समझौता करना होगा। मैं किसी ऐसे अफ्रीकी देश को नहीं जानता जो अगर किसी अधिक बड़े समूह का सक्रिय सदस्य बने, तो उसके विकास की गति तेज न होगी।

एक महान् साहित्यिक कार्य को आपने अर्द्धांतरह शुरू किया है—जो शायद विश्व का सबसे समृद्ध और गभावनाओं से पूर्ण महाद्वीप है, उसका पुनर्जन्म। मैं आपकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

छत्तिस

लातिन अमरीका में ज़मीन की भूख

लातिन अमरीका की यात्रा पर गए एक अमरीकी उप-राष्ट्रपति के अशांतिपूर्ण स्वागत से इस क्षेत्र के सम्बन्ध में अमरीकी नीति के बारे में काफी चिन्ता उत्पन्न हुई। वहाँ जन असंतोष के पीछे जो प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उस समय थीं, और आज भी हैं, नवम्बर 1959 में न्यूयार्क टाइम्स मंगलदिन में प्रकाशित यह लेख उनमें से एक को रेखांकित करता है।

लातिन अमरीका के राष्ट्रवादी नेता, जो अधिकांश साम्यवाद के तीव्र विरोधी हैं, उस गरीबी, प्रतिक्षा, स्थायी कर्जदारी और नव को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, जिन्होंने कुछ मुट्टी भर लोगों को छोड़कर, अन्य सभी को अपने देशों के स्वस्थ विकास में भाग लेने से रोक रखा है।

अनिवार्य ही उनके मुख्य हथियारों में भूमि सुधार भी होगा, ताकि अधिकांश किसान परिवार स्वयं अपनी ज़मीन के मालिक बन सकें। यह भी अनिवार्य है कि लातिन अमरीका के साम्यवादी इस आन्दोलन के साथ अपने को सम्बद्ध करने का अधिकधिक प्रयत्न करेंगे।

भूमि सुधार का साम्यवादी रूप केवल समूहीकरण की व्यवस्था की ओर पहला कदम होता है, जिसमें हर किसान राज्य का कर्दी बन जाता है। फिर भी, भोले-भाले भूमिहीन किसानों के लिए उसमें बड़ा अपर्णण है, जो उसमें केवल स्वतंत्रता की संभावना देघते हैं।

सम्बन्धित प्रश्न क्या हैं? लोकतांत्रिक साधनों से उनको हट करने की संभावनाएँ क्या हैं?

आज लातिन अमरीका में 1.5 प्रतिशत लोग, जिनमें से हर एक के पास पन्द्रह हजार एकड़ या और ज्यादा ज़मीन है, खेती की कुल भूमि में से आधी के मालिक हैं, और सर्वोत्तम भूमि पर उनके अधिकार का अनुपात और भी अधिक है। लातिन अमरीकियों में बड़ा हिस्सा गरीब कास्तकारों का है, जो अपने ज़मींदारों के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं।

यह भूमि व्यवस्था स्पेनी और पुर्तगाली विजेताओं द्वारा बिये गए बन्दोवस्तों के

वक्त से चली आ रही है, जो अपने माय अपनी सामन्ती व्यवस्थाएँ भी लाए थे। जब उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में औपनिवेशिक बन्धन टूटे, तो बड़े जमींदारों का प्रभुत्व आम तौर पर बिना किसी चुनौती के ही स्थापित हो गया।

अगर यह पुरानी व्यवस्था उचित मूल्यों पर भोजन और वस्त्र का उत्पादन करती तो आर्थिक और सामाजिक अन्याय उतने स्पष्ट न होते। किन्तु भूमि का बड़ा हिस्सा कॉफी और चीनी जैसी नरक फसलों के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे बहुत थोड़े लोगों को लाभ होता है, और खेती के तरीके बहुत पुराने हैं। इस कारण अधिकांश लातिन अमरीकियों को अब भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।

इस बीच 2.5 प्रतिशत प्रतिश्वर्ष के हिसाब से बढ़ती हुई जनसंख्या—वृद्धि की यह रफ्तार दुनिया की सबसे तेज रफ्तारों में से है—उपलब्ध भोजन सामग्री पर अधिकाधिक दबाव डालती है, जिसकी मात्रा कम होती जाती है।

सारे लातिन अमरीका में, जो सचमुच लोकतांत्रिक तत्व हैं, वे स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व के लिए भूमि व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है। फिर भी, लोकतांत्रिक साधनों में शांतिपूर्ण संक्रमण हो सके, इसमें किसानों की सहायता करने में स्वयं उनका श्रितना बड़ा हित है, इसे समझने में भूस्वामी वर्ग असमर्थ प्रतीत होते हैं।

एक या दो पीढ़ी पहले मेक्सिको की क्रांति से, या रूस और चीन की क्रांतियों के अधिक भयंकर नतीजों से भी, ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा।

लातिन अमरीकी भूमि विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि जल्दी या राष्ट्रीयकरण, चाहे जितना भी साम्य-नीति पर आधारित हो समस्या के हल का एकमात्र उपाय नहीं है। हर देश की अपनी अलग किस्म की चुनौती है।

किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि लातिन अमरीका की भूमि-व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन अनिवार्य है। केवल एक ही प्रश्न रह जाता है—ये परिवर्तन कैसे होंगे, रक्त-मय क्रांति के द्वारा या दीर्घ-कालीन लोकतांत्रिक नियोजन के द्वारा? हम अतीत के कुछ अनुभवों के नतीजों को देखें।

मेक्सिको में 1916 और 1934 के बीच लगभग दो करोड़ पचास लाख एकड़ सामन्ती भूमि जब्त करके किसानों में बाँट दी गई। व्यवस्था के प्रारम्भिक सोपान में दो लाख से अधिक खेत-मजदूरों को उनके छोटे-छोटे खेत मिले। राष्ट्रपति कार्डेनास के अधीन, जो 1934 में पदासीन हुए, और पाँच करोड़ एकड़ भूमि को जब्त करके अस्सी लाख भूमिहीनों में बाँट दी गई।

मेक्सिको के भूमि मुद्दारे के प्रारम्भिक सोपानों की कुछ कमजोरियाँ बाद में सामने आईं। नए भूस्वामी आदिवासी के पास, काम करने के अपने सारे सशक्त के वावरुद न अच्छे बीज थे, न खेती के पशु और औजार। उन्हें कहीं से कर्ज नहीं मिल सकता था। वह नियोजन पद्धतियों से, और अपनी फसलों को लाभदायक रीति से बेचने के तरीकों से अपरिचित था। फल यह हुआ कि खेती की पैदावार गिरी, और मजदूरी व फसलियाँ

जैसी मेक्सिको की मुख्य फसलों में कमी आई।

उसके बाद से, निजी और सार्वजनिक अमरीकी सहायता की मदद से, मेक्सिको के शासन ने एक ग्राम प्रसार व्यवस्था के द्वारा इन कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा की है, जो खेती के नए तरीकों को सीधे किसानों तक पहुँचाने हैं, और अब उत्पादन स्थिर गति से बढ़ रहा है।

बेनेजुना में, राष्ट्रपति रोमुलो बेटनकोर्ट ने पिछली जुलाई में अपनी कांग्रेस के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें देश की जीर्ण कृषि व्यवस्था की समस्या को सशक्त रीति से हल करने का प्रयास किया गया है। मेक्सिको के जंते अनुभवों से लाभ उठाकर, बेनेजुला का कार्यक्रम मजदूरों, बीज, और उर्वरकों के लिए उदार सरकारी कर्जों की, और नए भूमिधर्मियों को सलाह देने के लिए कि वे क्या, कहाँ, और कब बोएँ, एक कृषि प्रचार सेवा की व्यवस्था करता है।

यह बेटनकोर्ट का दूसरा प्रयास है। 1948 में, बेनेजुला के इतिहास में पहली बार हुए स्वतंत्र चुनावों में उनकी 'एग्रिकल्चर डेमोक्रेटिक पार्टी' पहली बार सत्ता में चढ़ गई थी, और उसने एक कृषि सुधार कानून बनाया था, जिनमें मुभावजा देकर भूमि पर अधिकार करने, और भूमिहीनों में फिर से उसका बँटवारा करने की व्यवस्था थी। छत्तीस दिन बाद, सेना ने सुधारक सरकार का तत्ता पलट दिया।

बोलिविया में, 1952 में क्रांतिकारी शासन के सर्वप्रथम कार्यों में से भूमि सुधार भी एक था। बोलिविया के सामन्त शर्द्ध-दासता की व्यवस्था के लिए बदनाम रहे थे, जो उन्हें खेत-मजदूरों से निजी सेवा लेने का अधिकार देती थी।

क्रान्तिकारी सरकार की योजना हर किसान को, भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर, पचास एकड़ में दो हजार एकड़ तक जमीन देने की थी। लेकिन बोलिविया में कभी कोई भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया था, और उपलब्ध कृषि-भूमि के पर्याप्त नकशे भी नहीं थे।

अन्त में, मशीन-यन लेकर चलने वाले अधीर किसानों ने मामला अपने हाथ में ले लिया। आज भी बोलिविया के भूमि सुधारों में अव्यवस्था व्याप्त है। लेकिन एक बात निश्चित है—बोलिविया का खेत मजदूर अब कभी भी सामन्ती दासता को चुपचाप सहन नहीं करेगा।

यद्यपि सालिन अमरीका के जिम्मेदार नेता इस बात के इच्छुक हैं कि उनके यहाँ लोगों की वर्धनी इस तरह का बिगड़ा हुआ रूप धारण करे, इसके पहले ही वे भूमि के बँटवारे में सुनियोजित कार्यक्रम को कानून द्वारा कार्यान्वित कर दें, किन्तु यथार्थवत्ति के पक्ष में अब भी बड़ी शक्ति है।

इतिहास कब तक प्रतीक्षा करेगा? इस सताब्दी में लोकतान्त्रिक सरकारों द्वारा केवल चार भ्रवसरो पर भूमिसुधार के व्यापक कार्यक्रम अपनाये गए हैं—1926 में जेकोस्लोवाकिया में, क्रांति के बाद मेक्सिको में, हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में, और प्युर्टोरिको में, जिसके लिए सन् 1900 में कांग्रेस ने कानून द्वारा व्यवस्था की थी कि

यहाँ निगमित संस्थाएँ पाँच भी एकड़ से अधिक भूमि पर स्वामित्व नहीं रख सकती।

यह स्थिति सारे लातिन अमरीका में अमरीकी कूटनीति के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र में अमरीकी नागरिकों द्वारा लगाई गई निजी पूँजी की प्रचुरता से अधिक है। यह दुनिया के और किसी भी हिस्से से अधिक है, और इसका एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूर्णतः कानूनी व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं है। यद्यपि इन पूँजी का केवल एक हिस्सा ही भूमि में लगा है, फिर भी, बड़ी भू सम्पत्तियों को तोड़ने के लिए बनाये गए कानूनों से कुछ अमरीकी वित्तीय हितों को निश्चय ही गभीर क्षति होगी।

फलस्वरूप, इसकी संभावना है कि लातिन अमरीका की जीर्ण कृषि-व्यवस्थाओं को सुधारने के किन्हीं भी प्रयत्न को, चाहे वह जितना भी आवश्यक, लोकतांत्रिक या तर्कमग्न बने न हो, गाम्बवादी जल्दी के रूप में बदनाम किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कांग्रेस और विदेश विभाग पर बड़ा दबाव पड़ने की संभावना है। जल्दी या देर से, व्यक्तिगत भूस्वामित्व की लम्बी परम्परा वाले अमरीका को ये दबाव ऐसी स्थिति में ले जा सकते हैं, कि वह एक ऐसे क्षेत्र के विकास को रोकने वाले हितों का समर्थन करे, जिस पर हमारी अपनी सुरक्षा निर्भर है।

प्राथमिक इतिहास में सर्वाधिक उग्र भूमि मुधार, युद्ध के तत्काल बाद अमरीकी तत्वावधान में जनरल डग्लस मैकार्थर द्वारा जापान में किया गया। युद्ध के पहले, दो तिहाई जापानी किसान दूमरों की जमीन पर खेती करते थे। आज 92 प्रतिशत जापानी ग्रामीण परिवारों के पास अपनी जमीन है, और प्रति एकड़ उत्पादन अभूतपूर्व ऊँचे स्तरों पर पहुँच रहा है।

अमरीकी प्रभाव ने तैवान में भूस्वामित्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कार्यान्वित करने में क्याण-गार्ड-रोक की भी सहायता की, जो अगर चीन की मुख्य भूमि पर दस वर्ष पहले लागू की गई होती, तो लगभग निश्चित रूप में किंगानों को उनके पास में कर देती।

क्याण-गार्ड-रोक के कार्यक्रम के अन्तर्गत, कोई किमान दस एकड़ से अधिक भूमि का मालिक नहीं रह सकता, और किन्हीं को ऐसी जमीन का मालिक होने का भी अधिकार नहीं, जिस पर वह स्वयं खेती न करता हो। सरकारी अधिभारियों की राय में तैवान में धारण के प्रति एकड़ उत्पादन में जो अगाधारण वृद्धि हुई है, उसका श्रेय बहुत कुछ इन सुधारों को है।

इन सुदोत्तर एशियाई सुधारों का विरोध करने वालों की ताकत इतनी थी, कि समादेश द्वारा ही उन्हें कार्यान्वित किया जा सका। जनरल मैकार्थर के मध्य शासन ने विशेष रूप में जापानी जमींदारों के विरोध की पूर्ण उपेक्षा की।

क्या अमरीकी कूटनीति इतनी पुरुराई, अनुकूल-वादि, और प्रचार-वादि प्राल्न कर सकती है कि इन क्षेत्र में मानिदुर्ण प्रान्ति करने के लिए वह मानिन अमरीका की मददरत सरकारों के साथ मिलकर काम करे ?

यद्यपि हमारा शासन घटना-क्रम को नियंत्रित नहीं कर सकता, किन्तु यह बहुधा रचनात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के रूप में :

हम भूमि के व्यापक स्वामित्व के लिए, उनित उपायों के अपने परम्परागत समर्थन को पुनः व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने विदेश-व्यापी अनुभव के आधार पर मुआवजे की योजनाएँ तैयार करने में लातिन अमरीकी सरकारों की सहायता कर सकते हैं, जिससे जमींदारों को उचित मूल्य मिल जाए और मालिकों पर अनुचित बोझ भी न पड़े।

हम पहले से ही यह मानकर चल सकते हैं कि हमेशा तक की ही जीत नहीं होगी, लगभग निश्चित रूप में अन्याय होगा, और दीर्घ कालीन स्थापित्व के लिए दिया गया अल्प कालीन मूल्य बहुधा उचित से बहुत अधिक प्रतीत होगा।

सबसे बड़ी बात है कि हम मूल प्रश्न को दृष्टि से ओझल न होने दें। एशिया और अफ्रीका की भाँति लातिन अमरीका में भी असली चुनाव नागरिकता और दासता के बीच, आशा और निराशा के बीच, व्यवस्थित राजनीतिक विकास और रक्तमय जल-पुथल के बीच है। इस चुनाव को समझने में, या नेतृत्व स्थापित करने की चेष्टा कर रहे नए जीवन्त तत्वों का समर्थन करने में हमारी असफलता के भयकर परिणाम होंगे।

‘प्रगति के लिए मित्रता’ क्या है ?

अक्टूबर, 1961 में मेक्सिको सिटी में, मेक्सिको उत्तर अमरीकी सांस्कृतिक संस्थान के समक्ष भाषण देते हुए, अर विदेश सचिव वॉल्टर अमरीकी और लातिन अमरीकी लोगों के इस कार्यक्रम के, जिमकी आवश्यकता बहुत दिनों से थी, ऐतिहासिक महत्त्व की ओर संकेत करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में साहमपूर्ण आन्तरिक सुधारों की आवश्यकता बताते हैं।

‘प्रगति के लिए मित्रता’ का उद्देश्य सारे लातिन अमरीका में गरीबी और अन्वेषण की जड़ों पर प्रहार करना है, और हमारे इसीस राष्ट्रों के लोगों और जासनों को इस योग्य बनाना है, कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक मापनों से अपनी स्वतंत्र भस्वामों को मजबूत बनाएँ।

जब हम इस चुनौती भरी नई साझेदारी की सभावनाओं और धारों पर विचार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ कठोर तथ्यों को सामने रखना चाहिए।

उदाहरण के लिए, हमने अनुभव से सीखा है कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के लिए क्या कर सकता है, इसकी कुछ कठोर सीमाएँ होती हैं, चाहे उसके साधन वित्त भी व्यापक हों, और सद्भावना कितनी भी अधिक हो। कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को न तो समृद्धि दे सकता है, न स्वतंत्रता। इन्हे स्वतः स्फूर्ति, कड़ी मेहनत, और बहुधा बलिदानों के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र समाजों के निर्माण के सामान्य प्रयास में, लातिन अमरीका के विशेषाधिकारयुक्त अल्पसंख्यकों को कुछ तत्कालिक लाभों का परिचय करने में अधिक उत्प्रेरणा दिखानी चाहिए। ऐसे समाजों में ही शांतिपूर्ण मापनों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है।

वहनेरे लातिन अमरीकी राष्ट्रों में महान् मुक्तिदाताओं के हाथों औपनिवेशिक बन्धनों के टूट जाने के बाद, क्रांतिकारी प्रक्रिया मुर्का गई। उन प्रारम्भिक दिनों से ही कई लोकतांत्रिक नेताओं के साहस और निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद जिन आर्थिक और सामाजिक सुधारों के द्वारा ही कोई समाज गभीरता और गरिमा प्राप्त कर सकता है, वे दब गए या भटक गए।

और, आवश्यक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन न होने के कारण, विनाश घन

‘प्रगति के लिए मित्रता’ क्या है ?

का अस्तित्व बहुधा दीन गरीबी के साथ-साथ है ।

‘प्रगति के लिए मित्रता’ राष्ट्रों को एक ऐसी साझेदारी के लिए आयात प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य समूचे अमरीकी महाद्वीप की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति एक नया और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रदान करना है । ऐसी साझेदारी का विकास सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार हो सकता है ? हर साझेदार की भूमिका कैसे समझी और परिभाषित की जाय ?

सितम्बर 1960 में, बोगोटा के अधिनियम ने इस बात पर जोर दिया कि दोतरफा सम्बन्धों के द्वारा ही आर्थिक और सामाजिक विकास सफल हो सकता है ।

उसमें कहा गया, “आर्थिक और सामाजिक प्रगति के सहयोगी कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक होगा कि अमरीकी गणराज्य अपनी सहायता स्वयं करने के अधिकतम प्रयत्न करें, और बहुतेरे मामलों में यह भी जरूरी होगा कि वर्तमान संस्थाओं और चलनों को, विशेषतः कराधान, भूमि के स्वामित्व और उपयोग, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्रों में सुधारा जाय ।”

अगस्त, 1961 में, पुन्टा डेल एस्ते में ‘अमरीकी लोगों की घोषणा’ और भी स्पष्ट थी । इसने ‘भूमि के स्वामित्व और उपयोग के अन्यायपूर्ण ढाँचों और व्यवस्थाओं’ की निन्दा की, और ‘इसलिए कि भूमि, उस पर काम करने वाले के लिए अधिकाधिक कल्याण का आधार बने, और उसकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा बने’—हर देश की विशिष्टताओं के अनुसार, कृषि सुधार के समेकित कार्यक्रमों का सशक्त समर्थन किया ।

घोषणा ने ऐसी कर-व्यवस्था की माँग की ‘जो उन लोगों से अधिक ले, जिनके पास सबसे अधिक है, करों की चोरी को कठोरता से दंडित करे, राष्ट्रीय आय का फिर से इस प्रकार बँटवारा करे कि जिनकी आवश्यकता सबसे अधिक है, उनको लाभ पहुँचे, और इसके साथ ही, बचत को और पूँजी के विनियोजन और पुनर्विनियोजन को प्रोत्साहित करे ।’

घोषणा ने अन्त में यह विश्वास प्रकट किया कि ‘ये गंभीर आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक परिवर्तन केवल हर देश के आत्म-सहायक प्रयत्नों के द्वारा ही फली-भूत हो सकते हैं ।’

सितम्बर के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस ने आर्थिक सहायता सम्बन्धी विधेयक पारित किया, जिसमें इन सिद्धान्तों का समावेश किया गया, और जिस धन की व्यवस्था की गई, उसका बँटवारा करने में राष्ट्रपति केनेडी की जिम्मेदारी निरूपित की गई ।

उपरोक्त के लिए, इस नए कानून में कहा गया है कि विकासशील राष्ट्रों को कर्ज और अनुदान देने समन, राष्ट्रपति ‘ध्यान रखें कि लाभान्वित होने वाला देश किन हद तक अपनी जड़ों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखता है, और किस हद तक स्वयं अपनी सहायता करने के

उपायों को अपनाने की स्पष्ट दृढ़ता प्रदर्शित करता है।”

इस कानून में व्यापक, सुविचारित योजनाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिससे अपव्यय और भ्रष्टाचार को रोका जाय। इसमें समेकित ग्राम समाजों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, ताकि जमीन जोतने वालों को अधिक अवसर और न्याय मिले।

लातिन अमरीका के विशिष्ट सन्दर्भ में, नए आर्थिक सहायता कार्यक्रम में बात पर जोर दिया गया है कि सहायता 'बोगोटा के अधिनियम के सिद्धान्तों के अनुसार' दी जाय।

इस प्रकार, ये हमारे स्पष्टतः निरूपित लक्ष्य हैं। स्वयं कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? यद्यपि पद्धतियाँ, प्रतिमान, और विशिष्ट कार्यक्रम अभी बनाए जा रहे हैं, फिर भी, कुछ सामान्य बातों पर विचार किया जा सकता है।

एक चुनौती, जिस पर हमें विचार करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहाँ इस समय लातिन अमरीका के 70 प्रतिशत लोग रहते हैं।

इस प्रश्न का सामना करते समय, हमें अस्पष्ट रूप में 'भूमि सुधार' का माँग करने वाले लोकप्रिय नारों के आगे जाकर देखना होगा। यद्यपि गतिशील ग्राम समाजों का निर्माण करने के लिए भूमि का व्यक्तिगत अथवा सहकारी स्वामित्व आवश्यक है, किन्तु यह अपने आप पर्याप्त नहीं है।

अगर ग्रामीण परिवारों को अधिकधिक प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने हैं, जिनसे उन्हें इतनी अधिक तलाश है, तो शासकीय प्रसार सेवाओं का निर्माण करना होगा, जो खेती की आधुनिक पद्धतियों को और साधनों के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा दें। ऐसी प्रसार सेवाओं में अस्पताल, स्कूलों, और सड़कों के विचारपूर्वक समेकित कार्यक्रमों को भी शामिल करना चाहिए।

कम ध्याज पर बर्ज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और सहकारिता का विकास होना चाहिए ताकि समूचे समुदाय स्वयं अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने विकास के लिए काम करना सीखें जहाँ संभव हो, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने के लिए नदी-नालों पर बाँध बनाये जाएँ, और नलरूप खोदे जाएँ।

समुदाय के सभी स्वास्थ्य लोगों को इन सुविधाओं का निर्माण करने में अमदान के लिए प्रोत्साहित करके, प्रसार कार्यक्रमों में निजी गवर्नर और सक्रिय सहयोग की भावना को और अधिक बढ़ा सकता है।

ग्रामीण समाजों के साथ काम करने का विद्यमान दिनों हमारा जो अनुभव रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यही निवृत्तता है—जब ग्राम सुधार के कार्यक्रम विचारपूर्वक समेकित होते हैं, सभी मानवीय शक्तियाँ पूर्णतः मुक्त होती हैं।

मैं विशेष ध्यान के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास की भावना रखने वाला कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि वह अपने लोगों को शिक्षा

देने की स्थिति में नहीं है। अपने बच्चों को शिक्षा दिए बिना उसका काम नहीं चल सकता। और न अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा किए बिना चल सकता है।

बोगोटा के अधिनियम, और पुन्टा डेल एस्ते में हाल ही में हुए सम्मेलन, दोनों में ही इस बात पर जोर दिया गया कि आय के साथ बढ़ने वाला आय कर, अपनी सहायता प्राप्त करने का एक आवश्यक रूप है। नए उत्पादक उद्यमों में पूंजी के विनियोजन को गतिशील प्रोत्साहन देते हुए, अनुपयुक्त मुनाफों को समेटने के लिए ऐसी कर-व्यवस्थाएँ आवश्यक होती हैं।

यद्यपि हमारी इच्छा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की बिल्कुल नहीं है, किन्तु हम कठोर अनुभव से जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक और दिखाई पड़ने वाले अन्तरों से उन लोगों में कटु अशांति और निराशा उत्पन्न होती है, जिन्हें कम मुविद्याएँ प्राप्त होती हैं।

देशी पूंजी के विनियोजन को बढ़ाने के लिए, और मफल विकास के लिए एक अन्य आवश्यक शर्त यह है कि विकासशील राष्ट्रों की मुद्रा का, उन देशों की मुद्राओं के साथ तर्क संगत सम्बन्ध हो, जिसके साथ उसके व्यापारिक सम्बन्ध हों।

यह बात साफ कह देना चाहता हूँ कि जो पूंजी किसी देश के बाहर चली जाती है, उसकी जगह भरने के लिए भेरे देश का शासन, या अन्य कोई पूंजी विनियोजन कर्ज या अनुदान क्यों दे, यह भी नहीं समझ पाता, जबकि उस प्रकार की रोकें लगाकर ऐसी पूंजी को देश में रखा जा सकता है, जिनका प्रयोग युद्ध के बाद इंगलिस्तान ने अपनी अर्थ-व्यवस्था को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए किया था।

यह भी नहीं समझ पाता कि ऐसे राष्ट्रों की सहायता करने के लिए अपने ऊपर बर लगाने की उम्मीद हमसे क्यों की जाय, जो स्वयं अपने समृद्ध लोगों पर, उनकी कर देने की क्षमता के अनुसार कर नहीं लगाते, या करों की चोरी की ओर ध्यान नहीं देते। अमरीका में हम लोग पचास साल से आय कर दे रहे हैं।

यह, जो राष्ट्र बोगोटा के अधिनियम की भावना के अनुसार, अपनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए अमरीका वस्तुतः क्या करने को तैयार है ?

हम राष्ट्र अपनी विशेष आवश्यकताएँ और संभावनाएँ प्रस्तुत करेगा। किन्तु विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज और अनुदान देने के लिए, विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों से काफी मात्रा में धन उपलब्ध है। इसके साथ ही नियोजन, अमला कार्य और विकास के लिए प्राविधिक विशेषज्ञ, गेहूँ, मक्का, सूखा दूध और चिकनाई आदि वृषि उत्पादन, और अध्यापन, सर्वेक्षण, और अन्य योजनाओं में सहायता करने के लिए, मुख्यतः हमारे विश्व-विद्यालयों से भर्ती किये गए छात्रों के स्वयंसेवक भी उपलब्ध हैं।

ऐसे सुझावों का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम आशा करते हैं कि ऐसे समझौते हो सकेंगे, जिनसे लातिन अमरीकी देशों की समृद्धि के लिए

अगर मार्क्स वापस आ सकते

1952 में मार्क्सवाद भारतीय विश्वविद्यालयों में अ-साम्यवादी छात्रों के बीच भी, एक व्यापक रूप में स्वीकृत आर्थिक सिद्धान्त था। उस वर्ष अक्टूबर में, नई दिल्ली में राजनीति के भारतीय छात्रों के सम्मेलन, राजदूत ब्रौस ने भारतीय आर्थिक और राजनीतिक विकास सन्दर्भ में, मार्क्स के पुराने पड़ चुके विचारों के मूल तकदोप की ओर संकेत किया।

काल मार्क्स ने जिस काल में अपना जीवन बिताया और लिखा, उसकी पृष्ठ-भूमि में ही उनकी शिक्षाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। 1848 में, जब 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' (साम्यवादी घोषणा-पत्र) लिखा गया था, यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और वहाँ के औसत नागरिक के लिए दुनिया निश्चय ही दुःख भरी थी।

हर तरफ गरीबी थी। घाठ, दस, या बारह बरस के बच्चे, कुछ आने प्रति सप्ताह के लिए कारखानों में बड़ी देर तक काम करते। जो कुछ लोग धनी थे, और निरन्तर अधिक धनी होते जाते थे, जबकि गरीबों को अपनी गरीबी से मुक्ति पाने की कोई आशा दिखाई नहीं देती थी।

युवा किसानों की एक अंतहीन धारा काम की तालाश में शहरों में आती, उससे वेतन और नीचे गिर जाते, और इस प्रकार नई पीढ़ाओं और कटुता का जन्म होता। उपनिवेशों में लोगों का निर्मम शोषण होता था, और कच्चे माल के लिए बड़े यूरोपीय राष्ट्रों के संपर्क बहुतेरे तनावों को जन्म देते थे।

यह एक ऐसी दुनिया थी, जिसमें कुछ थोड़े-से लोगों को लाभ होता था, और अधिकांश लोगों को कष्ट होते थे। उन्नीसवीं सदी के साथ हम जिस कला, संस्कृति और शिक्षा को जोड़ते हैं, वह केवल एक सीमित अल्पसंख्या को उपलब्ध थी।

मध्य-उन्नीसवीं सदी में लोभ और शोषण की इस बड़ी दुःखपूर्ण दुनिया को देख कर, मार्क्स कुछ ऐसे नतीजों पर पहुँचे, जो उन्हें स्पष्ट और अनिवार्य प्रतीत हुए।

उन्होंने सोचा कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्ततः विनाश होगा, 'शासक वर्ग' से सत्ता हिन जायगी, और तब जनता 'सर्वहारा की अधिनायक शाही' संगठित करेगी। मार्क्स के अनुसार, अपना कार्य समाप्त हो जाने पर यह क्रान्तिकारी शासन 'शुक्रनि'

लगेगा, समाज के विभिन्न वर्ग विघटित हो जाएँगे, और दुनिया के लोग, सभी लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता और अधिक भ्रवसरो की फँसती हुई सीमाओं की प्राप्ति कर सकेंगे।

गरीबी और शोषण की जिस पृष्ठभूमि में कार्ल मार्क्स ने लिखा था, उसे देखते हुए इन कठोर निष्कर्षों को समझा जा सकता है। किन्तु मार्क्स अगर आज हमारे भ्रव भी दोषपूर्ण सतार में वापस आ सकते, तो कुछ बातों से उन्हें बड़ा आश्चर्य होता।

उदाहरण के लिए, निजी स्वामित्व की हमारी धमरीकी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी लोगों को जो अधिकाधिक बढ़ने हुए भ्रवसरो प्राप्त हुए हैं, क्रयशक्ति में निरन्तर जो वृद्धि हुई है, और जो औद्योगिक विकास, और गतिमय अभिवृद्धि हुई है, मार्क्स उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। न हमारी धमरीकी शिक्षा व्यवस्था की वे कल्पना कर सकते थे, जो अठारह वषों तक के सभी लड़के-लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देती है, न हमारे उन बानूनों की जो सोलह वषों की आयु के पहले किसी व्यक्ति को कारखानों में काम करने से रोकते हैं, न उत्तराधिकार करो और पैंसठ वषों की आयु के बाद मिलने वाली वृद्धों की पेंशन की, न चिकित्सा-बीमा, बेकारी का बीमा, सार्वजनिक आवास व्यवस्था, और स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की।

ये नई और सचमुच क्रांतिकारी धाराएँ हैं। कोई व्यक्ति उनकी पूर्व-कल्पना नहीं कर सकता था, मार्क्स जैसी बुद्धि का व्यक्ति भी नहीं। एक शताब्दी से अधिक समय तक धमरीकी में एक नए प्रकार की अदृशक क्रांति चलती रही, और भ्रव भी जनसाधारण के लाभ के लिए चल रही है।

इसके प्रतिरिक्त, बीसवीं सदी की यह महान् प्रगति धमरीका तक ही सीमित नहीं रही। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नावों की सहकारी संस्थाओं की कल्पना मानस कैंसे कर सकते थे, जहाँ बड़े-बड़े उद्योगों के उत्पादनों के खरीदार ही सचमुच उन उद्योगों के मालिक हैं? वे उन वितरण-सहकारिताओं की कल्पना कैसे कर सकते थे, जिन्होंने उभोवता के लिए वस्तुओं के मूल्य को और अधिक घटा दिया है।

मार्क्स ऐसे शासकीय स्वामित्व की कल्पना कैसे कर सकते थे, जो निजी स्वामित्व के साथ-साथ, उससे प्रतियोगिता करता हुआ, शान्तिपूर्ण रीति से काम करता है? वे तीन भिन्न प्रकारों की उत्पादन व्यवस्थाओं—सहकारी, निजी पूँजीवाद, और समाजवादी—के मिश्रण की कल्पना कैसे कर सकते थे, जो लगभग एक-दूसरे की प्रतिधोषिता बनकर काम करती हैं, कि कौन व्यवस्था सर्वोत्तम वस्तुएँ सबसे सस्ते मूल्यों पर पैदा कर सकती है, कि कौन मजदूरों को सबसे अच्छा वेतन दे सकती है, कि लोगों को सर्वोत्तम भविष्य प्रदान कर सकती है?

वे इगलितरिजान में मजदूर दल की सरकार की कल्पना कैसे कर सकते थे, जो इस्राइल के कारखानों और कौयले की खानों के सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करने के साथ-साथ, अधिकतम व्यावहारिक सीमा तक निजी स्वामित्व को आयम

रखने के लिए बचनबद्ध हो ?

अगर वे इंग्लिस्तान के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' (लोक सभा) में बैठकर सदस्यों को हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मा, और श्रीलंका के 50 करोड़ लोगों की स्वतंत्रता के लिए मतदान करते देखते, तो क्या सोचते ? गांधी की महान रक्तहीन, अहिंसक क्रान्ति की कल्पना मार्क्स कैसे कर सकते थे ?

और वे इसकी कल्पना कैसे कर सकते थे कि दुनिया के राष्ट्र समुक्त राष्ट्र सच में एकत्रित हो जाएंगे, जो अपनी सारी अपूर्णताओं के बावजूद दुनिया को पहला विश्व-व्यापी मंच प्रदान करेगा ? विश्व स्वास्थ्य सगठन, समुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति सगठन की पूर्व-कल्पना वे कैसे कर सकते थे ?

कार्ल मार्क्स इन घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें विदवास था कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में जो अर्थ-व्यवस्था मजबूती से प्रतिष्ठित प्रतीत होती थी, और जिसकी उन्होंने सर्वथा उचित आलोचना की थी, वह अपने रोग दूर नहीं कर सकेगी, और विश्व में निश्चय ही रक्तमय अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने वाला विस्फोट होगा ।

मार्क्स आर्थिक अनिवार्यता में विश्वास करते थे । मनुष्यों की इस क्षमता को उन्होंने नहीं समझा कि वे लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से कार्य करते हुए अपना जीवन सगठित कर सकते हैं, ताकि आर्थिक शक्तियों का उपयोग सबकी भलाई के लिए किया जा सके ।

माल्थस के सिद्धान्त यांत्रिक प्रविधियों के विकास की कल्पना नहीं कर सके थे । मानस के सिद्धान्तों ने उन मानवीय तत्वों की उपेक्षा की, जिनमें गांधी भी आस्था थी ।

कार्ल मार्क्स के प्रसंग में सोवियत रूस की क्या स्थिति है ? आज विश्व का साम्यवादी आन्दोलन जिस रूप में है, उसकी प्रतिक्रिया मार्क्स पर क्या होती ?

मुझे राक है कि कार्ल मार्क्स अगर इस समय धरती पर वापस आते, तो उन्हें लौह आवरण के पार जाने में भी मफ़तना मिलती या नहीं । लेकिन अगर उन्हें सोवियत रूस और अन्य पिछलग्गू देशों में जाने के लिए पारत्र मिल भी जाते, तो वहाँ की स्थिति देखकर उन्हें निश्चय ही आश्चर्य होता । मार्क्स ने जिस साम्यवाद के लिए काम किया था, और आशा की थी, वह उस साम्यवाद से बहुत भिन्न था, जिसका आजकल बड़ा जोर है ।

सबसे पहले उनका ध्यान निजी स्वतंत्रता के पूर्ण अभाव पर जाता । अपने लेखन के अनुसार वे कहते, "यह साम्यवादी शासन पंतीस वर्षों से सत्ताह्वर रहा है । निश्चय ही अब इसे 'मुर्तना' चाहिए । सबंधारा को अपना कामकाज खुद ही चराना चाहिए जिसमें राजकीय प्रतिबन्ध अधिकाधिक कम हों, और हर व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो ।"

अगर मार्क्स मास्को रेडियो की आवाज़ सुनते, तो कुछ समय के लिए शायद आश्चर्य हो जाते, क्योंकि उन्हें बहुतेरी परिचित शब्दावली सुनने को मिलती । वे

सोवियत नेताओं की भविष्यवाणी सुनते कि 'पूर्जोवाद' आखिरकार अपने-आप नष्ट होने वाला है। वे सुनते कि 'पूर्जोवादी' देश (साम्यवादी शब्दावली में जिसका अर्थ है हर ऐसा देश जो सोवियत प्रसारवाद और आक्रामक नीति के विरुद्ध हो) शीघ्र ही 'पूर्जोवादी जगत' को विभाजित करने वाले एक युद्ध में अपना विनाश कर लेंगे। लेकिन जब मार्क्स कठोर तथ्यों का अध्ययन करते, तो पुरानी परिचित शब्दावली उन्हें खोखली प्रतीत होती।

निश्चय ही, दुनिया उस तरह विभाजित है, जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन वे देखते कि संघर्ष 'पूर्जोवाद' और 'साम्यवाद' के बीच नहीं है, बरन् जो देश स्वतंत्र रहने को दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, चाहे उनके यहाँ किसी भी प्रकार का शासन हो, और जो देश बल प्रयोग द्वारा दूसरों पर आक्रमण करने को तत्पर प्रतीत होते हैं, उनके बीच है।

इस दुसरे आधुनिक संघर्ष में वे देखते कि स्कैंडिनेविया (नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क) और इंग्लिस्तान के लोकतांत्रिक समाजवादों, अमरीकी निजी स्वामित्व की व्यवस्था, और युगोस्लाविया का स्वतंत्र साम्यवादी शासन, ये एक-दूसरे से कब्जा मिलाए लड़े हैं।

काले मार्क्स देखते कि इस आधुनिक जगत में 'पूर्जोवाद' बनाम 'समाजवाद' का पुराना संघर्ष भूटा पड़ चुका है, और असली संघर्ष स्वतंत्रता और स्वाधीनता की शक्तियों तथा दमन और आक्रमण की शक्तियों के बीच है।

सोवियत संघ को सबसे अधिक किसका भय है

1953 में समाप्त होने वाला कोरिया युद्ध अन्य सशस्त्र साम्यवादी आक्रमणों की कटु आशंका छोड़ गया। उसी वर्ष अक्टूबर में हार्ट फोर्ड कानेविटकट में वाइ. एम. सी. ए. में भाषण देते हुए श्री वॉल्स इन आशंकाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने की चेष्टा करते हैं।

एक क्षण के लिए, इस बात को छोड़कर कि हम अमरीकी किस बात से डरते हैं, हम देखें कि जिस क्रांतिकारी विश्व में हम रह रहे हैं, उसमें सोवियत संघ के नेताओं को सबसे अधिक डर किस बात का है।

मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक उन्हें इस बात का डर है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र लोकतंत्र के ऐसे सफल उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और दुनिया की समस्याओं का सामना इतनी सफलता के साथ करेंगे कि लोकतंत्र का विचार, किसी दिन स्वयं सोवियत संघ के अन्दर भी अजेय हो जायगा।

उन्हें डर है कि हमारे ठोस कार्यों से लोकतांत्रिक जगत इतना सबल हो जाएगा कि आंतरिक साम्यवादी क्रान्ति असम्भव हो जाएगी।

उन्हे डर है कि चतुःभुत्री कार्यक्रम को विस्तृत किया जाएगा, और आर्थिक विकास के लिए साहसपूर्वक उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे अमरीकी सहायता के फलस्वरूप एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के स्वतंत्र राष्ट्र बिना तानाशाही की क्रूरता के अपना विकास कर सकेंगे।

उन्हें डर है कि आर्थिक असफलता के फलस्वरूप अव्यवस्था और उसके निकट सम्बन्धी साम्यवाद के आने का इन्तजार करने के बजाए, हम इन राष्ट्रों के लोकतांत्रिक प्रयासों की सफलता के लिए उन्हें कर्ज या अनुदान के रूप में पूंजी और प्राविधिक सहायता प्रदान करेंगे।

उन्हें डर है कि हम इस तथ्य को अच्छी तरह समझ जाएँगे कि एशिया में सर्वाधिक निर्णायक प्रतियोगिता साम्यवादी चीन और लोकतांत्रिक हिन्दुस्तान के बीच है, जो अल्प-विकसित जगत के दो ध्रुव हैं, और यह कि चीन को जितनी सहायता संघ से मिलती है, हम हिन्दुस्तान को उससे अधिक प्रभावकारी समर्थन प्रदान करेंगे।

उन्हें डर है कि हम स्वतंत्र एशियाई देशों के इस निश्चय को स्वीकार कर लेंगे और उसका आदर करेंगे, कि वे सैन्य सन्धियों से असम्बद्ध स्वतंत्र विदेश नीतियाँ अपनाएँगे।

वे जानते हैं कि अगर पश्चिमी देश एशियाई राष्ट्रवाद का इस प्रकार आदर करें, तो केवल साम्यवादी ही 'विदेशी दावित के एजेण्ट' कहे जा सकेंगे।

उन्हें डर है कि हम अपना यह वर्तमान विफल दृष्टिकोण छोड़ देंगे कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, वह हमारे विरुद्ध है, जिसने बहुतेरे गर्धीले और मित्रतापूर्ण राष्ट्रों को हमसे रूठ किया है, और जो उस 'तटस्थता' के विलकुल विपरीत है, जिस पर प्रथम महायुद्ध के पूर्व पूरी एक शताब्दी तक हम स्वयं आग्रह करते रहे थे।

उन्हें डर है कि अफ्रीका में, और एशिया के शेष औपनिवेशिक क्षेत्रों में अमरीकी विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करने लगेगी, जिससे एकमात्र 'साम्राज्यवाद विरोधी' होने के छसी दावों का खोजलापन स्पष्ट हो जाएगा।

उन्हें डर है कि अमरीका अलोकतांत्रिक और अलोकप्रिय सरकारों का समर्थन करना बन्द कर देगा, जो साम्यवादियों को अपने आक्रमणों के लिए बड़े आसान लक्ष्य प्रदान करती है।

उन्हें डर है कि हम ऐसी सरकारों को विशेष समर्थन प्रदान करने लगेगे, जो आवश्यक भूमि सुधारों और सामाजिक सुधारों को कार्यान्वित करती है, और कराधान की उचित व्यवस्था कायम करती है।

उन्हें डर है कि हम ऐसे सुधारों को अपनी आर्थिक सहायता की एक शर्त बना सकते हैं, जिसने दुनिया के लोग यह देख सकेंगे कि हम उनके पक्ष में हैं।

उन्हें डर है कि हम न केवल आक्रमण के सामूहिक प्रतिरोध के लिए, वरन् अधिक मद्दत में विश्व की आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए भी समुचित राष्ट्र सघ को समर्थन और बल प्रदान करेंगे।

उन्हें डर है कि अपने बुद्धि-कौशल और सवेदनशीलता के द्वारा हम समुक्त राष्ट्र सघ को लोकतांत्रिक राष्ट्रों की निष्ठा का केन्द्र बनाने में सहायक हो सकते हैं।

उन्हें डर है कि यहाँ अमरीका में हम अपनी अर्थ-अवस्था को बिना मन्दी के चला सकने में समर्थ होंगे।

उन्हें डर है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के नए कार्यक्रम पूर्ण उत्पादन, और पूर्ण रोजगार के स्तर पर चलने रहेंगे और इस प्रकार उनकी सारी माकर्मवादी भविष्यवाणियों को भूठा सिद्ध करेंगे।

उन्हें डर है कि पिछले बीस वर्षों में जातीय सम्बन्धों में हुई प्रगति को हम न केवल कायम रखेंगे, बल्कि अपने सारे ही नागरिकों की पूर्ण प्रतिष्ठा और ममान अधिकारों की दिशा में नाटकीय नए कदम भी उठाएँगे।

उन्हें डर है कि साम्यवादियों के भय के फास्वरूप बहुतेरे स्कूल व्यवस्था मडलों और बहुतेरे इलाकों में विभाजित होने के बजाए, अमरीकी लोग स्वयं अपने स्वतंत्र सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था में एक हो जाएँगे।

उन्हें डर है कि साम्यवाद से लड़ते हुए भी, हम अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं को पूरी तरह बनाए रखेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति दुनिया के सामने सगर्व एक

उदाहरण ब्रन कर खड़ी रहेगी ।

सक्षेप में, उन्हें डर है कि थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के विचारों के प्रति पुनः समर्पित, जागरूक अमरीका के नेतृत्व में, उन स्थितियों को समाप्त करके, जो साम्यवाद के प्रसार को संभव बनाती हैं, लोकतांत्रिक जगत् साम्यवाद की विश्व विजय की आशाओं को विफल कर देगा ।

संकट प्रतीक्षा नहीं करेगा

1955 में सोवियत रणनीति ने खुले आक्रमण का मार्ग छोड़ कर, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक पैतरेबाजी का रास्ता अपनाया। इसने अमरीका के समक्ष एक नया संकट और नयी चुनौती रखी, जिसका वर्णन श्री वॉल्स ने इस लेख में किया है। न्यूयार्क टाइम्स मंगल, 27 नवम्बर, 1955।

जुलाई, 1955 में हुए शिखर सम्मेलन में, मर्यादों के अनुकूल इस बात पर सहमति हुई कि वर्तमान स्थितियों में आण्विक युद्ध लगभग निश्चित रूप में दोनों ही पक्षों को नष्ट कर देगा, और इस कारण इन प्रकार का युद्ध व्यवहारतः असम्भव हो गया था। किन्तु उसमें इस बात का संकेत नहीं मिला कि सोवियत संघ ने अपने दीर्घकालीन जागतिक लक्ष्यों का परिवर्तन कर दिया है।

ख्रिश्चोव और बुल्गानिन ने इसके पहले एक बात समझ ली थी, जिसकी अधिक मताग्रही स्टालिन ने हठपूर्वक उपेक्षा की थी—कि सैनिक गतिरोध की पृष्ठभूमि में, सैनिक आक्रमण, या आक्रमण की धमकी विश्व साम्यवाद के लिए व्यर्थ हो गई थी।

शिखर सम्मेलन के पहले भी, और उसके बाद बढ़ती हुई गति से साथ, सोवियत नेताओं ने नए आण्विक शक्ति सन्तुलन के नतीजों को साहसपूर्वक स्वीकार किया, और तदनुसार काम करना आरम्भ किया। पिछले कुछ महीनों में वे सोवियत विदेश नीति की मुख्य दिशा को चतुराई के साथ बदल कर उसे संघर्ष के एक बिलगुल नए क्षेत्र में ले गए हैं—राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, और कूटनीतिक पैतरेबाजी का क्षेत्र।

इस बीच अमरीकी नीति उसी रणनीति से बंधी हुई प्रतीत होती है, जो शीत युद्ध के समय भी अत्यधिक संकीर्ण प्रमाणित हुई थी, और जो नए प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता के सन्दर्भ में और भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। दुनिया के बड़े हिस्से में हमारी नीतियाँ अभी भी बहुत कुछ शक्ति की सैन्य-अभिमुख धारणाओं पर आधारित हैं। एशिया के कई हिस्सों में, और अफ्रीका में एक अपरिवर्तनीय कूटनीति ने हमें अब भी

समाप्ति के साथ बांध रखा है, जो अनुयोगी है, तिरस्त्र है, और जिसका विनाश निश्चित है।

अगर हम यह मानें कि अणु-युद्ध की संभावना अधिक है, तो दीर्घ-कालीन आर्थिक, वैचारिक, और राजनीतिक तर्कों का महत्त्व गीत होगा। लेकिन अगर वेनेडा के शिलर सम्मेलन का कोई अर्थ है तो यह कि जब तक हम सैन्य क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक संतुलन को बनाए रखते हैं, तब तक प्रायुक्त हथियारों की भयंकरता ने ही विश्व-युद्ध को बेमनस बना दिया है।

अगर ऐसा है तो एतनीति और कार्यनीति की हर स्थिति में जो विदेश-नीति अपने-आप ही सैनिक तत्वों को अधिक महत्त्व देती है, और उन राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक शक्तियों की ओर बल-से-बल ध्यान देती है, जो हम समय इतिहास का निर्माण कर रही हैं, वह लगभग निश्चित रूप में प्रयोज्य रहेगी।

नई सोवियत कार्यनीतियों से डरने के बजाय हमें उनका स्वागत करना चाहिए। आर्थिक विकास, राजनीति, और विचार, हमारे नौकान्तिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। हमारे विरोधी ने प्रतिद्वन्द्विता के लिए ऐसा प्रस्ताव चुना है, जिसमें हमारा बल प्रमाणित हो चुका है। हम प्रत्य-विस्तार के माध्यम से चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं।

अमरीका के सामने इस समय जो बड़ी आर्थिक चुनौती है, उस पर कांग्रेस का और जनमत का ध्यान केंद्रित करने के लिए, आर्थिक माहसूरुण, और अधिक आत्म-होगी। वर्तमान दिशा को बदलने के लिए 1956 में और उसके बाद जो कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, वे वैचारिक दृष्टि से उन कदमों से कम मौलिक और दूर-दक्षिणा पूर्ण नहीं होंगे, जो इस वर्ष पूर्ण प्रयोग की स्वतंत्र रखने में सहायक होने के लिए दोनों दलों की मिनी चुनौती के लिए उठाए थे।

जिन दिशाओं में प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उनमें से कुछ की सूची बनाने से चुनौती की व्यापकता का कुछ संकेत मिलेगा :

1. एक सैन्य प्रतिरक्षा कार्यक्रम, जो मास्को में आने वाले किसी भी सैन्य सन्धि का सामना करने के लिए पर्याप्त हो।
2. एक आर्थिक विकास कार्यक्रम, जो इतना काफी बड़ा हो कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में बड़ी कृषि कर सके, जो मार्शल योजना के यूरोप के लिए किमा था।

3. एक अर्ध-नीति का विकास, जो वास्तविक समस्या पर ध्यान केंद्रित करे -

4. एक यूरोपीय समुदाय के निर्माण के लिए कौसे राजी हिये, जो उत्तरी अमेरिकी सन्धि के अन्तर्गत टोस आर्थिक और राजनीतिक आधारों को निर्मित करे और यूरोप के लिए के विद्वलनशू राष्ट्रों को बराबर स्थिति की ओर आकर्षित करे।

5. एक औपनिवेशिक नीति, जो हमें अपरिचलनीय रीति से स्वतन्त्रता के पक्ष में खड़ा करवे, एशिया और अफ्रीका में यही मनुष्यजाति की बहुमत्या का विश्वास प्राप्त करे, और इसके साथ ही दोष औपनिवेशिक लोगों द्वारा क्रमिक और जिम्मेदार कार्यवाही को प्रोत्साहित करे ।

6. एक मध्य-पूर्वी नीति जो अपने आवश्यक लक्ष्य के लिए पर्याप्त हो—रचनात्मक स्थानीय शक्तियों को प्रोत्साहन देना, और इस निर्णायक महत्त्व के क्षेत्र में सोवियत प्रवेश को रोकना ।

7. सुदूर पूर्व में वस्तुस्थिति के अनुकूल समझौते के लिए एक नया प्रयाग, जिसमें हिन्द-चीन, या कम से कम सत्रहवें शताब्दी के दक्षिण के भाग की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो, फारमोसा स्वतन्त्र और सुरक्षित हो, जापान आधिक्य दृष्टि से पुष्ट हो, और साम्यवादी चीन के साथ अधिक सामान्य सम्बन्धों की सम्भावना हो ।

8. एशिया में हिन्दुस्तान और जापान के निर्णायक रणनीतिक महत्त्व की स्वीकृति । अगले दस वर्षों में हिन्दुस्तान क्या करता है, या नहीं करता, और जापान में क्या होता है, इसी से सम्भवतः अ-साम्यवादी एशिया के भविष्य का निर्णय होगा । हमें हिन्दुस्तान की तटस्थता के सम्बन्ध में अपनी निराशा का परित्याग करके, एक ठोस, सुविचारित, यथार्थ के अनुरूप कार्यक्रम बनाना चाहिए ।

इनमें से पहली दो बातों का निर्णायक महत्त्व है । हमें अपने सैन्य-शक्ति कायम रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें दूर-दूर तक फैले आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी साम्यवादी कार्यवाही का प्रतिरोध करना चाहिए ।

कुछ लोग अब भी ऐसा कहते हैं कि हम इस नयी आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक प्रतियोगिता की चुनौती का सामना कर सकने की स्थिति में नहीं हैं । लेकिन इसका वास्तविक खर्च चाहे जितना भी हो, अकेले 1955 में ही हमारी कुल राष्ट्रीय आय में हो रही बारह अरब डॉलर की वृद्धि का केवल एक हिस्सा होगा ।

दक्षिण कोरिया से साम्यवादियों को बाहर रखने के लिए अमरीका और उसके मित्र देशों को हजारों लोगों की जिन्दगी और पचास अरब डॉलर के सामान की कीमत देनी पड़ी । अगर हम इस समय हिचकते हैं, तो हमें यूरोप, मध्य-पूर्व, दक्षिण एशिया, और अफ्रीका से उन्हें बाहर रखने के लिए कहीं ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है । नई सोवियत चुनौती के लिए हमारी कार्यवाही का पर्याप्त होना, उस कार्यवाही की कसौटी होनी चाहिए ।

भविष्य के इतिहासकार कही ऐसा न कहें कि दूसरे महायुद्ध के बाद के दूसरे दशक में, अमरीका के नेतृत्व में सारी दुनिया में स्वतन्त्रता, इसलिए समाप्त हो गई कि हम अपने वजट को असंतुलित नहीं करना चाहते थे ।

एक प्रतियोगिता जिसमें हम हार नहीं सकते

1957 में सोवियत रूम की यात्रा करने पर, रूसी युवा लोगों में अमरीका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता ने श्री योल्म को प्रभावित किया। इसका एक परिणाम यह लेख हुआ, जिसमें उन्होंने अमरीकी-रूसी सांस्कृतिक विनिमयों पर रोक लगाने की वर्तमान नीति का विरोध किया है। सेंटरडे रिच्यू, 24 अगस्त, 1957।

हाल ही में सोवियत संघ की एक यात्रा में मैंने रूसी युवा लोगों में नई हलचल के कई चिन्ह देखे। व्यवस्था से विरुद्ध प्रभावी विद्रोह की सभावना का संकेत करने वाली कोई चीज नहीं थी, लेकिन ऐसा बहुत था, जिससे दृष्टिकोण की कठोरता कम होने का, पुराने मतान्तरों के सम्बन्ध में शकाओं का संकेत मिलता था। हर जगह जिज्ञामु, मिश्रतापूर्ण युवा लोगों ने स्नेह, और प्रश्नों के साथ हमारा स्वागत किया।

वापस आने पर, सबसे अधिक मुझे यह प्रश्न उद्दिग्ण करता रहा कि स्टालिन के बाद रूसी शासन की खुले-सम्बन्धी वाली परीक्षणात्मक नीति का क्या हम सही उपयोग कर रहे हैं? या, अधिक व्यापक रूप में, सारे साम्यवादी जगत में परिवर्तन और हलचल की जो नई प्रक्रिया निश्चित रूप में इस समय आरम्भ हो रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, क्या हम अपना काम कर रहे हैं?

सोवियत संघ में मैंने मास्को में होने वाले छठे विश्व युवक समारोह की बड़ी चर्चा सुनी, जिसके लिए सारी दुनिया से हजारों युवा लोगो को निमंत्रित किया गया था। मार्च में यहाँ वापस आने के बाद मैंने सुना कि इस वर्ष के समारोह में अपने गम्भीर रूप में लोकतांत्रिक अमरीकी विचारों को प्रस्तुत करने का एक अवसर देत कर, विदोपतः योग्य अमरीकी युवा छात्रों के कई समूह वहाँ जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। यह खेद की बात है कि अधिकांशों द्वारा उन्हें इसमें निरस्तहित किया गया।

जिन लोगो ने पूछताछ की, उन्हें भेजे गए पत्रों में हमारे शासन की भीड़ स्थिति निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त हुई—आपका शासन आपको पारंप्र देने से इन्कार नहीं करेगा, लेकिन इस मिलसिले की व्यवस्था सोवियत सरकार द्वारा स्वयं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गई है, और उसमें भाग लेने वाले अमरीकी, साम्य-

वादी लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होंगे ।

फलस्वरूप, धमरीकी प्रतिनिधि मंडल की सहायता पर एक ही से भी कम रह गई है । उनमें कई योग्य, सोशलिस्टिक प्रवृत्ति हैं, जो लिगो बहुरंग में अपने पक्ष का भलोभाति समर्थन कर सकते हैं । लेकिन जो लोग धम भी जाने की सोच रहे हैं, उनमें से अधिकांश या तो राजनीतिक दृष्टि से नासमझ हैं, या फिर स्पष्ट रूप से साम्यवादियों के सहयोगी हैं । कुछ थोड़े-से धमवादों को छोड़कर, ऐसे युवा स्त्री और पुरुष, जो सर्वाधिक सक्षम रूप में धमरीकी सोशलिस्टिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उन्होंने सरकारी दोष से डर कर न जाने का फैसला कर लिया ।

समारोह की प्रारम्भिक सूचनाओं से पता चलता है कि धमरी भीरता के कारण हमने व्यक्तिगत सम्पर्कों का, जिनमें युवा धमरीकी अपने सर्वोत्तम रूप को व्यक्त करता है, एक प्रसाधारण अवसर खो दिया । कुल 102 देशों से लगभग 2,20,000 युवा स्त्री-पुरुषों ने समारोह में भाग लिया था । और ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति ऐसे मुखर युवा धमरीकीयों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी, जो स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं ।

अपने पिछले भ्रम में खाइफ पत्रिका ने समाचार दिया है : "समारोह में खुले मेल-जोल की अनुमति ने, रूसियों को भूली हुई स्वतंत्रता के नए अनुभव से चौंका कर छोड़ दिया ।" सरल सामाजिक सम्पर्कों और खुली राजनीतिक बहनों को देखकर, संवाददाता पलोरा ल्यूइस को याद आया कि 1955 में वार्सा समारोह के बाद "वेचनी की दबी हुई चिनगारियाँ साम्यवादी जगत में भड़कने लगी ।" मास्को में एक पोलैण्ड-वासी ने उनसे कहा, "मैं सोचता हूँ कि क्या खुदवोध समझते हैं कि वे कितना बड़ा खतरा उठा रहे हैं ?

यह ऐसी एकमात्र स्थिति नहीं, जिसमें हम व्यक्तिगत सम्पर्कों से पीछे हटे हैं, जिनमें स्वतंत्र लोगों का सर्वोत्तम रूप व्यक्त होता है । मैं जब मास्को में था, तो एक अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता चल रही थी । एक धमरीकी टीम को निमंत्रित किया गया था, लेकिन अन्तिम समय पर वह पीछे हट गई । मास्को विश्वविद्यालय में सोवियत छात्रों ने मुझसे पूछा, "आपकी टीम ने आने का निर्णय क्यों किया ? क्या इसलिए कि विश्व ओलम्पिक में हमने आपको हरा दिया था ?"

मुझे जो अधिदृष्ट कारण बताया गया था, उसे मैंने यथा संभव विश्वसनीय रीति से दुहरा दिया—कि अक्टूबर में हंगरी में हुए विस्फोट के बाद, हम विरोध स्वरूप सोवियत सभ के साथ अपने सांस्कृतिक विनिमयों को समाप्त कर रहे हैं ।

"किस बात के विरोध में ?" रूसियों ने पूछा । इससे कम से कम मुझे हंगरी की क्रांति के सम्बन्ध में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जो अभी तक उनके सामने नहीं आया था । लेकिन 'विरोध' की ऐसी लौह-भावरण के ही दूसरे पक्ष की नीतियाँ, और तो छोड़ें, स्वयं अपने लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं करतीं ।

कोई विरोध तभी प्रभावकारी हो सकता है जब उन लोगों को उसका पता हो

जिनसे विरोध किया जा रहा हो। और रूसियों के लिए अमरीकियों के विचारों को समझने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वे अमरीकियों से मिलें और उनसे बात करें—वही 'सांस्कृतिक सम्पर्क' जिस पर हम भीरुता के साथ प्रतिबन्ध लगाते रहे हैं।

हर योग्य प्रेक्षक इस बात से सहमत है कि इस समय सोवियत रूस के युवा लोगों में एक नया जागरण आ रहा है। उसे आगे बढ़ाने के लिए हम हर उचित अवसर का उपयोग क्यों नहीं करते? हमारे शासन को वास्तव में डर किस बात का है?

श्री ख्रुश्चोव के पिछले बयानों से इसकी कोई आशा नहीं मिलती कि सोवियत शासन की योजना निकट भविष्य में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई ढिलाई लाने की है। लेकिन कम से कम लौह आवरण आंशिक रूप में तो खुला है।

मास्को विश्वविद्यालय में मुझे छात्रों का समाचार-पत्र दिखाया गया, जिसके चालू अंक में इण्डियाना विश्व-विद्यालय के छात्रों का एक पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें छात्रों और सूचनाओं के विनिमय का प्रस्ताव था। रूसियों को इस संभावना ने बड़ा आकर्षित किया।

विश्वविद्यालय के रेडियो पर अमरीकी जाज संगीत बहुधा प्रसारित किया जाता है। वस्तुतः, जब हम प्रसारण कक्ष में गए, तो लुई आर्मस्ट्रॉंग (प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो जाज संगीतज्ञ) का एक गीत प्रसारित किया जा रहा था। जब छात्रों को मालूम हुआ कि हमारे पास भूयाक टाइम्स यूरोपीय सञ्चरण की कुछ हाल की ही प्रतियाँ थी, तो उन्होंने इन प्रतियों को देखने का अनुरोध किया।

हर जगह मुझसे मेरे अपने कालेज जाने वाली आयु के तीन बच्चों के बारे में बहुसंख्यक प्रश्न किये गए। 'वे क्या पढ़ रहे हैं?' स्नातकीय परीक्षा के बाद वे क्या करेंगे?' और बार-बार यह प्रश्न—'क्या आप सोचते हैं कि शांति होनी?' फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम व्यक्तिगत सम्पर्कों से अपने को रोक रहे हैं, जो हर आयु के रूसियों के साथ हमारी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए।

कुछ महीने पहले मुझे बताया गया था कि रूसियों ने कुछ उद्यमी अमरीकी नागरिकों को मास्को में एक कृषि मेला लगाने को अनुमति दे दी थी। हम मेले की जगह पसन्द कर सकते थे, अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ प्रकाशित कर सकते थे, और इतना काफी शुल्क लगा सकते थे कि मेले का खर्च निकल आए। लेकिन हमारे भीरु अधिकारियों ने पहले तो योजना को निजी अमरीकी हाथों से निकाल दिया, फिर छुपचाप उसे छटम कर दिया।

अतएव हम अमरीकियों को दुनिया में डर किस बात का है? साम्यवादी विचारों के बीच एक खुली, स्वतन्त्र-गति से चलने वाली प्रतियोगिता में हमारा क्या नुकसान हो सकता है? निश्चय ही हमें यह डर नहीं हो सकता कि स्वतन्त्रता की परम्परा में पले हुए अमरीकी रूसियों के साथ अपने सम्पर्कों में उनसे अच्छे नहीं साबित होंगे, अतएव अपने अनिहीन और बेकार सिद्ध हो चुके विचार-धरान से ही परिचित हैं।

कटोर सोवियत ध्यास्या को नाम करते हुए देखने के बाद, और उन निष्पक्ष, गतिहीन, मनाघटी दारों को मुनने के बाद, जिनके युवा सोवियन लोगों को नई पीढ़ी स्पष्टतः ऊने लगी है, मेरी भविष्यवाणी इसके विपरीत है।

हम मास्को सरकार से क्यों न कहें कि यह अपने सर्वाधिक विरवनीय छात्रों में से वान लो को चुन कर समरीवा भेजे, और हम पाँच लो को चुन कर रूस भेजें ? इसका परिणाम साम्यवादी मनाघट्ट के लिए बड़ा विनाशकारी ही हो सकता है।

सोवियन छात्र अपने दागन के प्रकार की वेदमानी को समझ कर, और स्वयं मस्याप्रो की मत्पारमक शक्ति के लिए नया धादर लेकर लौटेंगे। समरीवी छात्रों में अन्तर्बन्धेह रूसी लोगों के प्रति मानवीय महानुभूति और निम्नी स्नेह की भावना आएगी। लेकिन इसके साथ, उनमें इग बाग की समझ और गहरी होगी कि ताना-शाही दागन के अधीन जीवन कितना अप्रिय हो सकता है, और हमारी अपनी उपन-स्थिती को तथा हमारी असीमित लोकतांत्रिक मभावनाओं को भी वे ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे।

रूस ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। मुझे इसका विदवास है। लेकिन हम यह प्रस्ताव रखकर दुनिया को यह पता न दिया दें कि युवा समरीवी लोगों द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक विचारों की शक्ति और प्रभावकारिता में हमें पूरा विदवास है ?

किसी सरकार मास्को रेडियो पर अधिक सांस्कृतिक सम्पर्कों की बात बड़े जोर-शोर से करती है। क्या अब हम चुनौती को स्वीकार करने का समय नहीं आ गया है ?

चीनी मुख्यभूमि पर एक दृष्टि

कम्यून व्यवस्था के अन्तर्गत भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन के कठिन संघर्ष में 1959 में परेशानियाँ होने लगी थीं। संटरडे ईवनिंग पोस्ट (4 अप्रैल, 1959) में प्रकाशित अपने इस लेख में श्री वील्स चीन के करोड़ों लोगों को भोजन देने के इस संघर्ष के महत्त्व पर, और उसके दीर्घ-कालीन खतरों पर विचार करते हैं।

दृष्टा साम्यवादी अर्थशास्त्र, जिसने दो पीढ़ियों के अन्दर रूस को बलान् एक आधुनिक औद्योगिक राज्य बना दिया, एशिया में सफल हो सकता है? या, वहाँ की बिलकुल भिन्न स्थितियों के कारण एशियाई साम्यवादी की असफलता अनिवार्य है।

इस प्रश्न पर दोनों दलों के धमरीकी नीति-निर्माताओं को तत्काल गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उनके उत्तरों पर बड़ी हृद तक कल की दुनिया का रूप निर्भर हो सकता है।

चीनी साम्यवादियों के सामने बड़ी जबरदस्त समस्याएँ हैं, जो कठिनतम स्थितियों में उनके राजनीतिक और आर्थिक सिद्धान्तों की परीक्षा ले रही हैं।

अगर पीकिंग सरकार रूस के नमूने पर तेजी से औद्योगीकरण करने की वर्तमान योजना को कार्यान्वित करती है, तो चीन की ग्राम अर्थ-व्यवस्था पर असंभव बोझ पड़ने की संभावना है, जिसके लिए जरूरी होगा कि 65 करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करने के अलावा, 'अतिरिक्त' कृषि उत्पादनों की भी व्यवस्था करे जो अति आवश्यक आयातों के मूल्य की भ्रदायगी में सहायक हों।

अगर वह किसानों को सन्तुष्ट करके भोजन का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है, तो लगभग निश्चित रूप में उसे अपने साम्यवादी राजनीतिक लक्ष्यों का परित्याग करना पड़ेगा। संक्षेप में यही चीन की मूल द्विविधा है।

एक पूरे राष्ट्र को स्वयं कमर कस कर उठने को तैयार करने की व्यवस्था, जो रूस में बड़ी कीमत देकर सफल हुई, शायद चीन में सफल न हो, क्योंकि वहाँ स्थिति लगभग पूरी तरह भिन्न है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ भूमि, भोजन और लोगों से सम्बन्धित हैं।

सोवियत संघ दो महाद्वीपों में लगभग दस हज़ार मील तक फैला है। हमारे

घमरीकी परिचय की भाँति, पूरान पर्वत के पूर्ण का विनाश, मगूड क्षेत्र निम्नने दो सी वर्षों में ही गुला है। यह सब भी बहुत कुछ परिवर्तित है।

साम्यवादियों के सत्तापन्न होने के पहले, रूसियों की भुगतारी का अनुभव शायद ही कभी हुआ था। वस्तुतः पहले महापुत्र के पूर्व, जार के काल में रूस लगभग एक करोड़ टन गेहूँ प्रति वर्ष निर्यात करता था।

गेती में इस बड़े, पूर्व-निर्मित अनुकूल स्थिति के बावजूद, सोवियत प्रयोग 1930 के बाद भोजन की कमी से लगभग टूट गया था। स्टालिन ने देखा कि तेजी में रूस का औद्योगीकरण करने के लिए, भोजन की विनाश मापनों की शहरों की घोर भेजना पड़ेगा, ताकि बढ़ती हुए औद्योगिक आवादी को भोजन दिया जा सके।

हर किसान परिवार के लिए स्वतंत्र भूस्वामित्व और अधिराधिक अवसर सम्पत्ती लेनिन के वादों की सुनेमाम तोड़ कर, स्टालिन ने सारे सामीप्य रूस की कठोरता से बंधे हुए राजनीतिक आचारों पर गगनशित करना आरम्भ किया।

दोम वर्षों से अधिक समय तक रूसी किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह और आतंकिन किया गया। वेत पर कृषि उत्पादनों का मूल्य कम रखा कर, और सरकारी पुटकर दुकानों पर ऊँची कीमतें लेकर, किसानों से बहुत अधिक मुनाफ़ा वसूल किया गया, ताकि उद्योग-धन्धों के तेजी में विज्ञान के लिए अधिराधिक पूँजी प्राप्त हो।

ग्राम विकास में बहुत थोड़ी पूँजी लगाई गई, और उद्योग की वस्तुएँ तो लगभग ही नहीं। सोवियत सभ भोजन के पहले से ही मौजूद उम अतिरिक्त उत्पादन पर कठिनाई से जीवित रहा, जो साम्यवाद ने नहीं, वरन् प्रकृति ने प्रदान किया था।

क्रिन्तु दीर्घ-कालीन परिणामों की दृष्टि से, यह अवदंस जुधा कामयाब हुआ। यद्यपि मानवी पीडा के अर्थ में इसकी कीमत दिल दहना देने वाली थी, लेकिन स्टालिन की दृढ़ता, और रूसी भूमि की लगभग असीमित क्षमता के फलस्वरूप, सोवियत शासन दो पीढ़ी से कम समय में ही एक सशक्त औद्योगिक राज्य का निर्माण कर सका।

इसी स्टालिनी कार्यक्रम को पीकिंग सरकार ने चीन की विकास-योजना के रूप में स्वीकार किया है। चीन की कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों में ऐसा करके उसने शायद इतिहास के सबसे अधिक साहसपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक जुए में दाँव लगाना शुरू किया है।

लेनिन की भाँति माघो ने भी अपनी क्रांति को उस अधिकतम नाटकीय वादे पर आधारित किया था, जो किसी किसान राष्ट्र से किया जा सकता है—“जमींदारों का नाश हो। भूमि जोतने वाले की” लेकिन समय आने पर, स्टालिन की भाँति माघो ने भी बेहिचक इस वादे को तोड़ दिया, और चीन के किसानों को ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के साथ बाँध दिया, जिसमें निजी भूस्वामित्व का कोई स्थान नहीं।

1957 तक, लगभग सारे ही चीनी ग्रामीण परिवार 7,40,000 सामूहिक खेतों में संगठित कर दिये गए थे। अब सार ही सामूहिक खेतों, ग्राम उद्योगों और स्थानीय अर्द्ध-सैनिक दलों को 'कम्यूनो' या समुदायों में समेकित किया जायेगा। यह क्रम इतना अधिक उग्र और क्रूर था कि स्टालिन ने भी इसका प्रयास करने का साहस नहीं किया था।

यद्यपि अब यह स्पष्ट है कि पीकिंग सरकार कठिनाइयों में पड़ गई है, किन्तु यह समझना भूल होगी कि कोई दिशा-परिवर्तन होने वाला है। कम्यून कार्यक्रम के लक्ष्यों पर बार-बार जोर दिया गया है।

साम्यवादी चीन के नेता जानते हैं कि उनके प्रयत्नों की सफलता या असफलता बहुत कुछ गाँवों पर निर्भर होगी। यद्यपि कठिनाइयाँ निस्सन्देह बहुत अधिक हैं, किन्तु वे प्रभावी रीति से यह तर्क दे सकते हैं कि कम से कम इस मामले में वे अपने रूसी सहयोगियों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुभवी हैं।

रूस की क्रांति केवल दो लाख पार्टी सदस्यों द्वारा की गई थी। वे अधिकांश बुद्धिजीवी और मजदूर थे जिनकी जड़ें शहरों में थीं। मास्को और लेनिनग्राड में क्रांतिकारी उद्यम-पुखल के समय लेनिन द्वारा चतुराई से की गई घोषणा से कि 'सारी भूमि जोतने वाले की' उन्हें रूसी किसानों का सहयोग प्राप्त हो गया। लेकिन वे कभी ऐसा अनुभव नहीं कर सके कि वे आन्दोलन के अग्र हैं।

इसके विपरीत, चीन की क्रांति की गहरी जड़ें हमेशा गाँवों में रही। लाल सेनाओं के आगे बढ़ने के पहले गाँवों को संगठित करने वाले पचास लाख पार्टी सदस्यों की संख्या अब बढ़कर एक करोड़ तीस लाख हो गई है, और इनमें से अधिकांश किसान परिवारों के हैं। सभी स्तरों पर इस ग्राम अभिमुख साम्यवादी नेतृत्व के निर्देशन में चीन के दस लाख गाँवों में से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें दो दशकों से विकसित हो रहे अनुशासन का अनुभव है।

साम्यवादी नेताओं का विद्वान है कि इन पद्धतियों से वे एक क्रान्तिकारी उत्साह कायम रख सकते हैं, जो विकास की सतरों से भरी अवधि में चीन को आगे ले जाएगा, और तेजी से औद्योगीकरण के लिए पूँजी का निर्माण करेगा।

निकट पारिवारिक सम्बन्धों और प्राचीन धार्मिक विश्वासों पर आधारित अनिश्चित किन्तु अत्यधिक निजी सुरक्षा के स्थान पर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की है जो केन्द्रीय शासन की इच्छा के प्रति पूर्ण अधीनता के बदले में, रोजमर्रा के एक नीरस जीवन के पोषण की व्यवस्था करती है।

उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि के परम्परागत आर्थिक प्रोत्साहन के स्थान पर वे मेले करते हैं, जिनमें बड़े-बड़े घंटे बजते हैं, पटाखेबाजी होती है, परेड और नाच होते हैं, और 'जनता के दायुगो' की सामूहिक भर्त्सना होती है।

लाघों सरकारी ध्वनि-विस्तारक, और निरन्तर चलने वाली 'अध्ययन गोष्ठियाँ', बहुधा बाह्य संघर्षों की ज्वालाओं को भड़का कर, लोगों को और अधिक प्रयत्न करने के लिए बलकारती हैं। इस प्रक्रिया में अमरीका ऐसे विष-धमन का विशेष लक्ष्य होता

है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय तू-तू में-में के इस युग में भी कोई मुकाबला नहीं।

लेकिन मानवीय शक्तियों के इस लगभग पूर्ण सगठन, और सर्वाधिक अनुकूल मौसम के बाद भी, अन्ध्र के समान, चीन को भोजन के उत्पादन की समस्या में कुछ कठोर यथार्थों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें साम्यवादी नारों से खत्म नहीं किया जा सकता। चीन के प्रयत्नों की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उसकी विशाल जनसंख्या है, जो प्रतिवर्ष एक करोड़ साठ लाख की गति से बढ़ रही है, और उसके विद्यालय, किन्तु सीमित क्षेत्र में भरी हुई है।

वर्तमान औसत प्रति ग्रामीण परिवार के लिए दो एकड़ से भी कम का है। कुछ थोड़े-से परिचामी क्षेत्रों को छोड़कर, चीन की अधिकांश आसानी से सींची जा सकने वाली भूमि पर इस समय सघन खेती हो रही है। वहाँ भी नव तोड़ जमीन को बहुत अधिक खर्च पर ही खेती के लायक बनाया जा सकता है।

चूँकि लोग पहले से ही अधिकांश चावल, गेहूँ और सब्जियाँ खा कर रहते हैं, अतः मासाहार को घटाकर अनाज की बचत करना, जैसा कि स्टालिन ने किया था, यहाँ बहुत दूर तक मुमकिन नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रति एकड़ उत्पादन पहले ही काफी अधिक है। चीन में साम्यवाद की विजय के बहुत पहले से ही, शायद अन्य किसी भी अल्प-विकसित देश से अधिक, चीन के किसान अच्छे बीज, अधिक मात्रा में प्राकृतिक खाद, और बोवाई-कटाई को अधिक कुशल पद्धतियों का प्रयोग कर रहे थे।

यद्यपि जापान में प्रति एकड़ उत्पादन लगभग दुगुना रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा जा सकता है, भविष्य में भी उत्पादन के इन स्तरों को प्राप्त करना चीन के लिए असम्भव प्रतीत होता है।

चीन को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के ये कठोर सामाजिक और आर्थिक तथ्य हैं, जिन पर तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार सम्बन्धी पीकिंग के गर्व भरे दावों के साथ-साथ विचार करना चाहिए।

‘चीन की समस्या’ पर पुनर्विचार

कारेन एफेयर्स के अप्रैल, 1960 के अंक में प्रकाशित, चीन की समस्या, और फारमोसा तथा मुख्यभूमि सम्बन्धी अमरीकी नीति के इस विस्तृत विश्लेषण में, प्रभावकारी नई अमरीकी नीति के लिए श्री यॉल्स कुछ निर्देश रेखाएँ प्रस्तुत करते हैं। इन विचारों की पीकिंग में माओत्से-तुंग और तैवान में राष्ट्रवादी, दोनों ने ही तीव्र आलोचना की है।

क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम ‘चीन की समस्या’ के आधारभूत तथ्यों का सामना करें? जब तक हम ऐसा नहीं करते, सारे एशिया के ही साथ हमारे सम्बन्धों में बड़ी अड़चन आती रहेगी।

वर्तमान स्थिति में, अमरीका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करने की बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर हम कूटनीतिक विनिमय का प्रस्ताव रखें, तो माओत्से-तुंग निश्चय ही पूछेंगे कि हमारी मान्यता में ‘फारमोसा प्रान्त’ पर चीन की प्रभुसत्ता की मान्यता भी शामिल है या नहीं। और जब हम कहेंगे कि नहीं, तो उत्तर में अनिवार्य ही वे हमारे प्रस्ताव को तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार कर देंगे। अगर हम प्रस्ताव रखें कि दोनों चीनों को संयुक्त राष्ट्र मध्य का सदस्य बना लिया जाए, तो भी यही नतीजा निकलेगा। च्यांग-काई-शेक भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। गतिरोध बना रहेगा।

इसका अर्थ है कि जिन दो मूल प्रश्नों को लेकर यहाँ अमरीका में इतना गहरा मतभेद उत्पन्न हुआ है, उन्हें फिलहाल हल नहीं किया जा सकता। बाद में हम ऐसा कोई प्रस्ताव रखकर साम्यवादी चीन के शांतिपूर्ण इरादों को परखना उपयोगी पा सकते हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष एक ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लें, जिसे बिना युद्ध के न हम बदल सकें, न वे। लेकिन तब तक के लिए, हम औपचारिक सम्बन्धों के प्रश्न को छोड़कर, तात्कालिक, और सम्भवतः प्राप्य लक्ष्यों की ओर ध्यान दें।

अगर साम्यवादी चीन के सम्बन्ध में कोई नया परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने का कोई अन्य कारण न भी होता, तो निःशस्त्रीकरण का निष्पत्तिक प्रश्न अपने-आप में ही हमके लिए पर्याप्त था। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता, कि चीन के भाग लिए बिना निःशस्त्रीकरण की किसी योजना का कोई मतलब नहीं हो सकता। उसके पास न केवल दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बल्कि आण्विक हथियारों के निर्माण की

संभाव्य क्षमता भी है। ऐसा मोचने का भी कोई कारण नहीं है कि रंग दग मामले में चीन की जिम्मेदारी ले सकता है। या तो हमें बड़े पैमाने पर विदेश-व्यापारी निरस्त्रीकरण की किसी सुरक्षित व्यवस्था के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने का विचार छोड़ देना चाहिए, या फिर चीनी क्षेत्र में घटनाक्रम को प्रभावित करने के तरीकों की खोज करनी चाहिए।

हो सकता है कि हम साम्यवादी चीन में निश्चिंत भविष्य में होने वाली घटनाओं को विलकुल भी प्रभावित न कर सकते हों लेकिन हमारे मन्दिर चीन की समस्या के अन्य पहलुओं को प्रभावित करने की क्षमता, जितनी हम हमेशा प्रतीत होते हैं, उगने अधिक है।

फारमोसा (तैवान) हमका एक उदाहरण है। यह द्वीप गमूदा है, और इनमें असाधारण आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन न केवल चीनी मुख्य भूमि के सम्बन्ध में, बल्कि भारत से जापान तक फैले हुए सारे ही स्वतंत्र एशिया के मदर्भ में इसकी राजनीतिक स्थिति अभी भी बड़ी अनिश्चित है।

ऐसा इस कारण है कि फारमोसा की राजनीतिक स्थिति इस मिथ्या धारणा पर आधारित है कि च्यांग-काई-शेक, जिन्हें ग्यारह वर्ष पहले मुख्य भूमि से भागना पड़ा था, अब भी 65 करोड़ चीनियों के शासक हैं। इस मिथ्या धारणा के—जिसे अधिकांश एशियावासियों ने, उत्तरी अटलांटिक संधि में हमारे मित्रों ने, हमारे निकटतम मित्र कनाडा ने, और बहुतेरे अमरीकियों ने भी अस्वीकार कर दिया है—केवल वाशिंगटन के भारी दबाव के कारण तीन या चार एशियाई सरकारों का, हमारे विदेश विभाग का, और कांग्रेस के कुछ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इस मिथ्या धारणा को बनाए रखने से फारमोसा ऐसे समय में अधिकाधिक अकेला पड़ता जाएगा, जब उसके नेताओं को स्वतंत्र, अ-साम्यवादी एशिया के विचार और काम की मुख्य धारा के साथ अपने को जोड़ने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए।

अमरीका और राष्ट्रवादी चीन, दोनों को ही अपने मित्रों और साथियों के साथ सहमति के क्षेत्र की तलाश करनी चाहिए, अपनी नीतियों को अधिक तर्कसंगत रूप में उन शक्तियों से सम्बन्धित करने की चेष्टा करनी चाहिए, जो अगले दशक में एशिया में घटनाक्रम का रूप निर्धारित करेंगी। मैं समझता हूँ कि ऐसी नीतियों को निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित किया जा सकता है—

1. पौरुष सरकार के कठिनाइयों से घिरे होने पर भी, चीन की मुख्यभूमि पर उसका दृढ़ नियंत्रण है।
2. साम्यवादी चीन में अपर्याप्त साधनों, बढ़ती हुई आवादी, निर्भय नेतृत्व, और तीव्र राष्ट्रीय भावनाओं के फलस्वरूप, दुर्दम्य प्रसारवादी प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी, जिनका लक्ष्य दक्षिण की ओर के दुर्बल पड़ोसी राज्य होंगे।
3. अमरीकी नीति का एक प्राथमिक लक्ष्य दक्षिणपूर्व एशिया में चीन के सैनिक

प्रभार को रोकना होना चाहिए, जिसकी चेष्टा करने का लोभ चीन के साम्यवादी नेताओं को हो सकता है।

4. निरस्त्रीकरण के किसी भी प्रभावकारी कार्यक्रम में अन्ततः चीन का भाग लेना आवश्यक होगा।

5. वर्तमान परिस्थितियों में, चीन के साथ हमारे मुख्य मतभेदों के बारे में किसी समझौता वार्ता के सफल होने की संभावना नहीं है।

6. फारमोसा में बसे हुए अस्सी लाख फारमोसाई लोगों और चीन की मुख्यभूमि से आये हुए बीस लाख चीनियों को सुरक्षित, स्वतंत्र अस्तित्व का, और साम्यवादी क्षेत्र के बाहर अपने सांस्कृतिक विकास का अधिकार है। फारमोसा का ऐसा विकास अमरीकी लोगों के हित में है।

7. किन्तुहाल, फारमोसा की स्वतन्त्रता अमरीका की सैन्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता पर निर्भर रहेगी।

8. दीर्घ-कालीन दृष्टि से, फारमोसा के लोगों की सुरक्षा और समृद्धि एशिया के अ-साम्यवादी राष्ट्रों, विशेषतः भारत और जापान के व्यवस्थित राजनीतिक विकास पर, और फारमोसा सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण पर निर्भर होगी।

9. अगर कभी यह ध्यावहारिक हुआ, तो मुख्यभूमि पर चीनी लोगों के साथ अपने परम्परागत मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को पुनः स्थापित करना हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल होगा।

अब इन मान्यताओं के सन्दर्भ में हम उन तथ्यों पर विचार करें, जिनका सामना अमरीकी नीति को करना होगा।

×

×

×

फारमोसा में आज राजनीतिक शक्ति एकमात्र जनरलिसिमो च्यांग की सर्वसत्तावादी राष्ट्रवादी सरकार के हाथ में है। मुख्य भूमि से जो बीस लाख व्यक्ति च्यांग के साथ भागकर 1949 में फारमोसा आए थे, अधिकांश सरकारी कर्मचारी उन्हीं में से हैं, और साठ लाख की सेना में भी दो-तिहाई वही लोग हैं। एक दशक तक फारमोसा के सम्बन्ध में अमरीकी नीति मुख्यतः इस राष्ट्रवादी चीनी शासकों की अल्पसंख्या पर केन्द्रित रही। किन्तु दीर्घ-कालीन दृष्टि से, अस्सी लाख फारमोसाई लोग ही द्वीप के भाग्य का निर्णय करेंगे। हम उनकी इच्छाओं, आशाओं, आंशकान्तों के बारे में बहुत कम सुनते हैं। पिछले दिनों फारमोसाई एकेडमी में लिखते हुए एक फारमोसावासी ने (ली तियां होक, ‘चीनी गतिरोध: एक फारमोसाई दृष्टिकोण’ फारमोसा एकेडमी, अप्रैल, 1958।) कहा कि न कोई स्वतन्त्र फारमोसाई समाचारपत्र है, और न कोई मान्यता प्राप्त फारमोसाई राजनीतिक दल है।

1945 के पहले लगभग दो दशकों तक फारमोसा पर जापान का शासन था। यद्यपि उनमें से अधिकांश दक्षिण-पूर्व चीन की फुकीन बोली बोलते हैं, लेकिन उन्हींमें शिक्षा जापानी स्कूलों में पाई। समृद्धि बढ़ने के कारण, उनमें से बहुतेरे अपने को चीन

की अपेक्षा जापान के अधिक निकट अनुभव करने लगे। लेकिन पन्द्रह वर्ष के राष्ट्रवादी शासन के फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समय, सामीप्य, और शिक्षा के फलस्वरूप विशेषतः युवा समूहों में, द्वीप के चीनी और फारमोसाई समुदायों का धीरे-धीरे मिश्रण हो रहा है। संभवतः एक नए राष्ट्रीय व्यक्तित्व का धीरे-धीरे उदय हो रहा है, जिसकी संस्कृति चीनी है और दृष्टिकोण फारमोसाई।

1949 के बाद राष्ट्रवादी सरकार ने कुछ रचनात्मक कार्य किए हैं, जो उसने मुख्यभूमि पर रहने हुए नहीं किए थे। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक यह है कि उसने ग्रामीणों के निर्णायक महत्त्व को स्वीकार कर लिया है, जो सभी एशियाई राष्ट्रों में न केवल बहुमूल्या में है बल्कि भोजन की पूर्ति पर भी जिनका नियंत्रण है, और इस कारण व्यवस्थित विकास को आर्थिक और राजनीतिक कुञ्जी भी जिनके हाथ में है।

च्यांग के निर्देशन में एक भूमि सुधार कार्यक्रम के साथ, जिसमें भू-स्वामित्व को दस एकड़ तक सीमित कर दिया गया है, और लगान भी काफी घटा दिया गया है, एक सक्षम ग्रामीण विस्तार सेवा, आसान बज्रों और उर्वरक उद्योग में वृद्धि की भी व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप, चावल और कपास के प्रति एकड़ उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, और किसानों की जिन्दगी ज्यादा आसान और समृद्ध हुई है। फारमोसा के जीवन स्तर अब जापान के बाद एशिया में सबसे ऊँचे हैं।

ध्वान्तरिक राजनीतिक स्थिति भी सुधरी है। निश्चय ही, राष्ट्रीय सरकार को अब भी लगभग पूरी तरह मुख्यभूमि से द्राये हुए लोग ही चलाते हैं। विधान सभा के 1576 सदस्य हैं, जिसमें केवल 26 फारमोसावासी हैं। लेकिन फारमोसाई लोगों के लोकतांत्रिक सहकार की दिशा में भी कुछ प्रगति हुई है। प्रान्तीय सभाओं और काउन्टी प्रशासनों में, बहुत कुछ स्वतंत्र चुनावों के द्वारा, द्वीपवासियों का काफी बड़ा बहुमत है। अधिकांश नगरों के मेयर स्थानीय फारमोसावासी हैं।

तीस वर्षों में अधिक समय तक, द्वार और जीत हर स्थिति में, च्यांग-काई-शेक ने लगभग अकेले ही कोमिन्तांग (राष्ट्रवादी दल) की एक्ता को बनाए रखा है। लेकिन वे हमेशा शासन चलाते नहीं रह सकते। फारमोसा का भविष्य उम सरकार के स्वामित्व पर निर्भर होगा, जो उनके न रहने पर कायम होगी।

जब तक अमरीका पूर्व एशिया में पर्याप्त मौसना और धायुगेना रक्षता है, और उमका उपयोग करने को तैयार रहना है, तब तक माओत्सेतुंग एक ही तरीके से फारमोसा पर अपनी प्रभुता स्थापित कर सकते हैं, और वह है किमी ऐंगी माजिन की सफलता, जो च्यांग या उनके उत्तराधिकारियों को हटाने द्वीप में ऐंगी सरकार को सत्ता ह्द करे, जो पीकिंग ने समझौता करने को तैयार हो।

मुख्यभूमि पर सशक्त तानाशाही शक्तियाँ (केनिन-मिनि-माओ) के विचार-दर्शन को मनुचित सीमाओं के अन्दर चीनी समाज का पुनः निर्माण कर रही हैं, चीनी विचारों को फिर से दान रही है, और चीनी इतिहास को फिर से लिख रही हैं।

एक स्वतन्त्र चीनी-फारमोसाई राष्ट्र इसके विपरीत एक आधुनिक अ-साम्यवादी चीनी समाज का रूप प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें जनता कठोर बन्धनों से मुक्त हो, अधिकाधिक मात्रा में राजनीतिक स्वतन्त्रता हो, और सभी नागरिकों को अधिकाधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध हो। ऐसे समाज का निर्माण करने में तैवानी और चीनी लोगों की युवा पीढ़ी को एक सामान्य उद्देश्य की भावना प्राप्त हो सकती है, और विदेशों में बसे हुए एक करोड़ तीस लाख चीनियों को एक सांस्कृतिक आधार भी प्राप्त हो सकता है।

×

×

×

ऐसे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपनी नीति को किस प्रकार संशोधित कर सकते हैं।

हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि अमरीकी नीति-निर्माता सद्भावनाओं और डालरों में चाहे जितने सम्पन्न हों, वे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि फारमोसा अ-साम्यवादी एशिया में एक नयी विध्यात्मक भूमिका अपनाए। मुख्यभूमि से भाग्य हुए राष्ट्रवादी धारणार्थी इसे स्वेच्छया फारमोसाई बहुमत पर साद भी नहीं सकते। हमारा कार्य एक सच्चे मित्र का कार्य होना चाहिए। स्थानीय फारमोसावासियों, राष्ट्रवादी चीनियों, और सामान्यतः सारे विश्व को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य मुख्यभूमि पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक घड़डे का निर्माण करना नहीं, बरन् एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना है।

फारमोसा की वर्तमान स्थिति केवल इस मिथ्या धारणा को जीवित रखती है कि मुख्यभूमि पर शीघ्र ही राष्ट्रवादी आक्रमण होने वाला है, जिससे पीकिंग को प्रतिरोधात्मक कार्यबाहियों का आसान बहाना मिल जाता है। उसके विपरीत, हमें चीनी तट से लगे हुए द्वीपों को तटस्थ बनाने की तत्काल प्रोत्साहित करना चाहिए।

दूसरी ओर, हमें अपने इस आश्वासन को अधिक पुष्ट करना चाहिए कि फारमोसा पर साम्यवादी आक्रमण होने पर हम उसका हर तरह से सैन्य प्रतिरोध करेंगे, और इसमें किसी साजिश द्वारा शासन पलटने को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को भी शामिल कर लेना चाहिए। ऐसी किसी साजिश के सफल होने पर, हमें आर्थिक और नौसैनिक घेराबन्दी करनी चाहिए, ताकि पीकिंग सरकार द्वीप पर प्रभावी रूप में अधिकार न कर सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फारमोसा का स्थान स्वीकार किया जाय, इसमें कुछ समय लग सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर विश्वसंगठन की सारी सुरक्षाएँ फारमोसा को सुरक्षा प्रदान करेंगी। इस बीच, द्वीप की रक्षा करने के लिए हमारी सैनिक प्रतिबद्धता असंदिग्ध रहनी चाहिए। जैसे हम पश्चिमी बलिन के लोगों को नहीं छोड़ सकते, उसी तरह फारमोसा के लोगों को भी नहीं छोड़ सकते।

सभी जगहों के अ-साम्यवादी चीनियों के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में फारमोसा के

इस देखते हुए, बहस में जीतने के लिए विदेश विभाग के कुछ प्रवक्ताओं द्वारा पिछले दिनों यह बताने के प्रयास के कि श्री ख़श्चोव 'विद्वे साम्यवादी आन्दोलन के नेता हैं, और 'चीन पर काबू न रखने' के लिए उनका मजाक उड़ाने के प्रयास, नास-ओ भरे श्री वे मतलब हैं। हम इस बात को समझें कि साम्यवादी राष्ट्रों, और साम्यवादी मित्रताओं पर भी अर्थशास्त्र, राष्ट्रीयता, और इतिहास के क्षारक प्रभाव पड़ते ।

1919 से 1933 तक सोवियत संघ के साथ अमरीका का कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं था। फिर भी, इस अवधि में हजारों अमरीकियों ने रूस की यात्रा की, जिससे वहाँ की घटनाओं के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी, और रूसी लोगों ने भी हमको कुछ अधिक जाना और समझा। मुझे ऐसा लगता है कि इन समय हमको चीनी मुख्यभूमि के साथ जनता के स्तर पर अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए सभी उचित उपायों का प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। साम्यवादी चीन के साथ सवाददाताओं के विनिमय के लिए एक नया प्रयास पहले कदम के रूप में उपयोगी हो सकता है। हमें तथ्यों और परिप्रेक्ष्य की बड़ी जरूरत है, जो योग्य अमरीकी सवाददाता हमें प्रदान कर सकते हैं, और चीनी पत्रकार अमरीका में जो कुछ देख सकते हैं, उसमें परेशान होने की हमें कोई जरूरत नहीं।

पीकिंग सरकार और हमारा शासन, दोनों ही अब तक ऐसे दुतरफा विनिमय में बाधक रहे हैं। ऐसा सोचना निस्सन्देह भूल होगी कि चीन के लोगों के साथ पुनः सम्पर्क स्थापित करने की हमारी चेष्टाओं का पीकिंग द्वारा स्वागत किया जायेगा।

कई दृष्टियों में, हमें अपना सार्वजनिक शत्रु बनाए रखने में साम्यवादियों का हित है। किन्तु यह हमारा काम है कि सवाददाताओं की यात्रा के मार्ग में हमारी ओर से जो बाधाएँ अभी तक मौजूद हैं, उन सबको हटा दें, ताकि सम्पर्क के मार्ग में बाधाएँ कायम रखने की जिम्मेदारी साफ़ तौर से पीकिंग पर धा जाय।

लेकिन समाचारों का अधिक स्वतंत्र प्रवाह केवल एक गुरुमान है। हमारे शासन की शिक्षाओं, राजनीतियों और व्यापारियों को—उन सभी अमरीकियों को जो चीनी क्रान्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, और उम्र जानकारी को हममें से नए लोगों तक पहुँचा सकते हैं—चीन की यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए, यदि हमके लिए श्रेयान्वित करना चाहिए।

×

×

×

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के भौतिक और भूमि प्रणालियों पर बनाएँ अधिभार करने के अलावा, चीन के पास एक ही विकल्प है कि अपने व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम अपनाएँ। यदि विश्व-शांति इन पर निर्भर होगी कि चीन अन्तः-कीन-या मार्ग चुनता है, अतः इन प्रश्न पर अमरीकी नीति-निर्माताओं को तरफ़ान अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।

जब हम दो चीजों के मध्य पर आधारित अल्पकालीन नीतियाँ बनाने और

चलाने से आरम्भ करके, पूर्वी एशिया में गतिरोध समाप्त करके आगे बढ़ने लगेंगे, तभी इस आने वाली घटनाओं पर रचनात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। और ऐसा होने पर, क्या यह आना सर्वथा असंगत होगी कि पूर्वी एशिया में युद्ध के खतरे की गंभीरता ही धीरे-धीरे उस क्षेत्र में अमरीका और सीवियत संघ के बीच, किसी हद तक, कम से कम अप्रत्यक्ष सहयोग को जन्म देगी? हमारे गंभीर वैचारिक और राजनीतिक मत-भेदों और लक्ष्यों के बावजूद, एशिया में सैनिक, आर्थिक, और राजनीतिक शक्ति सन्तुलन में अधिक स्थिरता लाना हम दोनों के ही हित में प्रतीत होता है।

जिन नीतियों का मुझको मने दिया है, उनसे फारमोसा के राष्ट्रवादियों में परा-काष्ठावादी तत्व प्रसन्न नहीं होंगे और पीकिंग के साम्यवादी उनकी तीव्र निन्दा करेंगे। देशभक्त, किन्तु यथार्थ से सर्वथा काटे हुए फारमोसाई राष्ट्रवादी भी, जिनकी रांग है कि हम ब्यांग को हटाकर, उनकी सहायता करें कि वे स्वयं अपना शासन स्थापित कर सकें, इन नीतियों को अस्वीकार कर देंगे।

इस समय, हमारी नीति का लक्ष्य होना चाहिए कि निम्नलिखित बातें चीनी साम्यवादी नेताओं के समक्ष स्पष्ट कर दें :

1. उनके दक्षिण-पूर्वी एशिया में बढ़ने का, हम सभी आवश्यक साधनों से विरोध करेंगे।

2. हम उन्हें प्रत्यक्ष आक्रमण या विध्वंसक कार्यवाहियों द्वारा फारमोसा पर अधिकार नहीं करने देंगे।

3. फारमोसा में हमारे सैनिक ब्रह्मों का उद्देश्य मुख्यभूमि पर राष्ट्रवादी आक्रमण में सहायता या सहयोग देना नहीं है।

4. फारमोसा एक स्वतंत्र इकाई बना रहेगा, और उसके शासन के रूप के सम्बन्ध में अन्ततः उसके सभी लोगों की राय ली जायेगी।

अगर हम इन लक्ष्यों को अपना लें, तो संभव है कि फारमोसा की समृद्धि और उसका स्थायित्व स्पष्ट हो जाने पर, पीकिंग सरकार अनिच्छापूर्वक अ-साम्यवादी एशिया के एक तथ्य के रूप में फारमोसा की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर ले।

रूस निरस्त्रीकरण क्यों नहीं करता

न्यूयार्क टाइम्स मंगलान के 19 अप्रैल, 1957 के अंक में श्री बौलस इसका विश्लेषण करते हैं कि रूस शास्त्र-नियंत्रण सम्बन्धी समझौता क्यों नहीं करना चाहता। और साथ ही, प्रभावकारी अमरीकी नीति सम्बन्धी अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

प्रत्यक्ष रूप में गतिरोध देखकर, और निराश होकर, दुनिया सोचती है कि हथियारों की होड़ के दुश्चक्र से बचने के लिए क्या अब भी कोई प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है। देखने में, रूसी दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि रूसी नेता शास्त्र-नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई व्यावहारिक समझौता नहीं करना चाहते।

वे एक व्यापक निरस्त्रीकरण कार्यक्रम का समर्थन क्यों नहीं करते? उन्हें ऐसा करना चाहिए, इसके दो बड़े कारण हैं प्रथम, सोवियत रूस संन्य खर्चों को उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में लगा सकता है, जिससे उसे देश और विदेश में तात्कालिक लाभ होंगे। दूसरे, साम्यवादी रूढ़ियों के अनुसार, पूंजीवाद पश्चिम की निरन्तर समृद्धि बहुत कुछ उसके शास्त्र-उद्योगों पर निर्भर है।

जहाँ तक पहले कारण का सम्बन्ध है, सोवियत सभ की उत्पादन शक्ति का लगभग 22 प्रतिशत इस समय सेना पर लगता है। अर्थात् 190 अरब डालर के कुल वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 40 अरब डालर। सामान्य निरस्त्रीकरण सम्बन्धी समझौता हो जाने पर रूसी नियोजक इस बड़ी रकम के अधिकांश भाग को अन्य कार्यों में लगा सकेंगे, जिससे रूस की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी।

सोवियत सभ के अन्दर मकानों की गभीर कमी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जा सकेगी। दस-पन्द्रह वर्षों के अन्दर, देश के अधिकांश भाग में शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्तियों को साफ किया जा सकेगा। मोटरों और उपभोग की अन्य वस्तुओं के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा।

इसके साथ ही, रूस बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मुक्त निर्धारित कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकेगा, जो अल्पविकसित महाद्वीपों में, और स्वयं यूरोप में भी, पूंजीवादी देशों की व्यापारिक स्थिति को कमजोर करे। टाइपराइटर, मोटरें, ट्रक और अन्य सामान का मूल्य तुलनीय अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, और जर्मन वस्तुओं से 40, और 50 प्रतिशत तक कम रखे जा सकते हैं। श्री ख्रुश्चोव हम से बराबर

कहते रहते हैं कि किसी प्रत्यक्ष शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता में साम्यवाद की विजय निश्चित है।

जहाँ तक सोवियत रूस के निरस्त्रीकरण पर जोर देने के दूसरे कारण का सम्बन्ध है, साम्यवादियों का दावा है कि अमरीकी मैन्य उद्योगों के घन्द होने पर, तेजी से मन्दी फैलेगी, लोग दीवालिया होंगे, तंगी आएगी, और कट्टु राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होंगे, जिसके फलस्वरूप पूँजीवाद का पतन और साम्यवाद की विजय और भी जल्दी होगी।

यद्यपि मार्क्सवादी विश्लेषण हमारी समस्या को बहुत बड़ा-चड़ा कर रखता है, किन्तु हममें से सर्वाधिक दृढ़ पूँजीवादियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हथियारों पर होने वाले खर्च में काफी बड़ी कमी करने पर, अमरीकी उद्योग-वन्धों के समक्ष गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी।

यह सच है कि अगर कांग्रेस बड़े पैमाने पर करों में कटौती कर दे, तो अरबों डालर हथियारों की सरकारी खरीद में लगने के बजाए पारिवारिक खरीद में, या रोजगार देने वाले विस्तार कार्यक्रमों में लगाए जा सकेंगे। देश के अन्दर राष्ट्रीय हित के उपेक्षित क्षेत्रों—मकान, सड़कें, सड़की नवीकरण, अस्पताल, स्कूल आदि—की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी बड़ी रकमें लगाई जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, हम एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में अपने फिलहाल अपर्याप्त आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ा सकेंगे, और इस प्रकार, बढ़ते हुए निर्यात व्यापार को नीव डाल सकेंगे।

किन्तु इन कार्यवाहियों का असर होने के पहले, कठिन समंजन के कई महीने बीत जाएँगे। इस बीच हमारे सोवियत प्रतियोगी, उस तेज रफतार से जो केवल तानाशाही व्यवस्थाओं की ही उपलब्ध होती है, नए बाजारों में प्रवेश करेंगे, पुराने बाजारों से हमें स्थानच्युत करेंगे, और सारी दुनिया के लाखों यात्रियों को साम्यवाद की भौतिक उपलब्धियों से प्रभावित करेंगे।

अतः इन दोनों कारणों से, व्यापक निरस्त्रीकरण सन्धि के लिए काम करना सर्वथा रूस के हित में प्रतीत होता है, भंडे उड़ाए हैं, और शांति-कगोत छोड़े हैं। फिर भी समझौता वार्ताओं में, वे कभी कोई ठोस, व्यावहारिक प्रस्ताव लेकर नहीं आये। क्यों?

एक उत्तर पश्चिमी प्रेक्षकों के एक समूह द्वारा दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर पेरोवर सैनिक हैं (यद्यपि वे मंत्रियों की रायों के प्रतिनिधि नहीं हैं), जो भविष्य में संकट को अनिवार्य मानते हैं। इनकी राय के अनुसार, रूस द्वारा निरस्त्रीकरण की समस्या का ठोस रूप में सामना न करना इस बात का प्रमाण है कि सोवियत संघ का अकेला, अपरिवर्तनीय लक्ष्य विश्व पर बलात् अपना प्रभुत्व स्थापित करना है।

दूसरी पराकाष्ठा पर जो समूह है, वह एक भिन्न उत्तर देता है। हमारी वास्त-

विक कमियो का उन्हें पूरा एहसास है, वे काल्पनिक होने की हद तक धादशवादी है, और सारी मनुष्य जाति से यहाँ तक कि सोवियत नीति के निर्माताओं से भी उच्चतम आशाएँ रखते हैं। उनका कहना है कि मास्को ने निरस्त्रीकरण इस कारण नहीं स्वीकार किया कि हमने पर्याप्त चेष्टा नहीं की।

लेकिन मुझे सन्देह है कि वास्तविक कारण कहीं ज्यादा उलभा हुआ है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान रूसी व्यवहार को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है।

1. जिन शक्तियों को उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया, उनसे सोवियत नेताओं का वास्तविक भय—एक पुन उठता हुआ, सशस्त्र जर्मनी, उत्तरी अटलांटिक संधि, और अमरीकी आण्विक अट्रों की विश्व-व्यापी व्यवस्था।
2. उनके 65 करोड़ गतिशील, जमीन के भूखे चीनी पड़ोसी, जो जल्दी या देर से साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, इसकी सम्भावना है।

3. एक हद तक सोवियत नेता स्वयं गोपनीयता की रूसी परम्परा के शिकार हैं, और हमारे खुले समाज की तुलना में, उनकी गोपनीयता हथियारों की होड़ में सच-मुच उनके लिए अपेक्षतया लाभकारी है।

4. नीति सम्बन्धी हिचक और विरोधी दवाव—उदाहरण के लिए साम्यवादी दल के अन्दर, और दल तथा सेना के बीच मतभेद—जो रूसी सरकार की कार्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता को सीमित कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार के मतभेद हमारी अपनी सरकार के कार्य-स्वातन्त्र्य को सीमित करते हैं।

अंत में, मेरा निजी अनुमान है कि निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में रूसी नेताओं में हिचक उत्पन्न करने वाले मूल तत्वों में से एक वह है, जिसे एक शब्द, 'हंगरी' में व्यक्त किया जा सकता है। जेनेवा में 1955 में 'चार बड़ों' की बैठक के बाद तनाव में कमी होने पर, संभावना की एक लहर समूचे साम्यवादी साम्राज्य में फैल गई, पोलैंड में उयल-पुयल, और हंगरी में विद्रोह।

अतः सोवियत नेताओं के लिए, शीत युद्ध में कोई भी वास्तविक कमी बड़ी भयोलपादक बात होगी, ऐसी जिसके प्रति कोई भी तानाशाही राज्य अत्यधिक शकालु होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा एकता उत्पन्न करने वाले उन भयों का अन्त, जो सोवियत संध की एकता को क्रायम रखने में सहायक रहे हैं।

इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर कठिन है। रूसी इरादों के बारे में हमारी धारणाएँ केवल अनुमान पर आधारित हो सकती हैं, इस कारण हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए हमारी नीति के तीन पक्ष होने चाहिए :

1. हमें बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। वे आशाहीन प्रेक्षक, जिनका कहना है कि निरस्त्रीकरण पर गंभीरता से विचार करने में रूस की प्रतिबद्धता

इस बात का प्रमाण है कि मास्को की योजना अपनी पसन्द के समय और स्थान पर युद्ध करने की है, वस्तुतः सही हो सकते हैं। हम कोई जुधा नहीं खेल सकते।

2. इसके साथ ही, हमें दुनिया के सामने विश्वसनीय रूप में यह प्रमाणित कर देना चाहिए कि हमारे मैन्य कार्यक्रम में हुई वृद्धि केवल रूस द्वारा उत्पन्न किये गए गतिरोध का ही तार्किक परिणाम है, और हम बड़े पैमाने पर निरस्त्रीकरण के लिए समझौता करने को इच्छुक और उत्सुक हैं।

अगर ऐसे निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में हमारे वर्तमान शासन की कोई विश्वसनीय नीति है, जिसके आधार पर समझौता-वार्ता हो सके, तो किसी को उसका ज्ञान नहीं। सोवियत रूस की अनुकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं है, इससे हमारी अपनी असफलता क्षम्य नहीं हो जाती कि हमने कोई यथार्थपरक, सन्तुलित शांति कार्यक्रम विकसित नहीं किया, जिसे हम निरन्तर, रचनात्मक रीति से दुनिया के सामने रख सकें।

3. अन्त में, हमें अच्छी से अच्छी स्थिति के लिए भी—इस संभावना के लिए कि अन्ततः रूस निरस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाएगा—तैयार रहना चाहिए।

इसके लिए आवश्यक होगा कि हम साफगोई से अनुमान लगाएँ कि हथियारों की होड़ में कोई डिलाई आने पर, हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव होगा। ऐसा सर्वोक्षण कांग्रेस की समुक्त आर्थिक समिति द्वारा, या इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई किसी एजेन्सी या समिति द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए उद्योगों, मजदूरी आन्दोलन और विश्वविद्यालयों से आर्थिक विशेषज्ञ लिये जा सकते हैं।

इस अध्ययन में, इस बात पर विचार होना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में, हथियारों के उत्पादन में कटौती होने पर, कितनी बेकारी होगी, निगम करों में किस हद तक, और किस रूप में कमी करना संभव होगा, और इस कमी का निगमित पूँजी के विनियोजन पर, और उभोक्ताओं की खरीदारी पर अनुमानित प्रभाव क्या पड़ेगा।

उसे पता लगाना चाहिए कि शहरी विकास, आवास, अस्पताल, स्कूल, और सड़क-निर्माण के कार्यक्रम, और विदेशों में पूँजी विनियोजन, किस हद तक कमी को पूरा कर सकेंगे और संक्रमण काल में किस प्रकार के, और कितने बेकारी के मुद्दावर्जों की जरूरत होगी।

बहुतेरे अमरीकी निरस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों की खुची बहस से घबड़ा जाएँगे। लेकिन कार्ल मार्क्स के विपरीत, मैं समझता हूँ कि उनकी आसंकाएँ अति-पूर्ण हैं।

युद्ध उत्पादन बोर्ड के एक सदस्य के रूप में 1945 में मैंने युद्ध से शांति की ओर हमारे आर्थिक संक्रमण के नियोजन में भाग लिया था। रोजगार क्षेत्र में एक करोड़ भूतपूर्व सैनिकों के अचानक प्रवेश करने के बावजूद, डेढ़ वर्ष में हम क्रिस्ती बड़ी मन्दी के और बिना गंभीर बेकारी के, अपने लगभग आधे उद्योग-धन्धों को युद्ध-कालीन स्तर से शान्ति कालीन स्तर पर सफलतापूर्वक ले आए थे।

अगर आज फिर वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो जाय, तो मुझे कोई शक नहीं कि हम फिर वैसे ही सफल होंगे। इस समय हमारे प्रयत्नों का कहीं छोटा हिस्सा हथियारों के उत्पादन में लगा है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेशी सहायता और अन्य क्षेत्रों में आवश्यक कार्य विशाल मात्रा में करने को पड़े हैं, जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं।

अमरीकी पहल, और सैनिक, राजनीतिक, व आर्थिक पक्षों को ध्यान में रख कर बनाई गई व्यापक अमरीकी शान्ति नीति का रूस पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो किस हद तक, यह कोई नहीं बता सकता। लेकिन यह तेजी से चलने वाला ढुंग है, और इसकी सभावनाएँ अससीमित हैं। स्टालिन की मृत्यु के बाद, सोवियत संघ में भी काफी बड़े परिवर्तन हुए हैं।

हमारी क्रांतिकारी शताब्दी में नीति निर्माण, अधिक से अधिक, खतरों के ताजुक सन्तुलन का कार्य है। यद्यपि कोई निश्चित, सुरक्षित रास्ता नहीं है, किन्तु हथियारों की होड़ के तेजी से बढ़ते जाने के समय कुछ न करने की नीति सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक स्वस्थ, व्यावहारिक, कल्पनाशील अमरीकी नीति का निर्माण, जिस पर हम सभी चलने को तैयार हों, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिसे उपेक्षित या स्थगित नहीं किया जा सकता।

प्रतिरक्षा, निरस्त्रीकरण और शान्ति

श्री बौल्स बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई सैन्य प्रविधियों, और फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्याप्त सैन्य बल और निरस्त्रीकरण के सच्चे प्रयास के बीच विस्फोटक संकट का सिंहावलोकन करते हैं। लॉस एंजेलिस में 'मॉडर्न फोरम' के समस्त मार्च, 1960 में दिये गए भाषण से।

दुनिया में आज 100 अरब डालर प्रतिवर्ष हथियारों पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा, इस खर्च के परिणाम बड़े भयोत्पादक रूप में अनिर्णायक होते हैं। जो राष्ट्र हथियारों की होड़ में सबसे ज्यादा फँसे हुए हैं, उनके प्रमुख रणनीतिज्ञ वही लोग हैं, जो अधिकाधिक खर्च में सबसे ज्यादा व्यस्त हैं।

हथियारों की होड़ बढ़ने के साथ ही निरस्त्रीकरण की तात्कालिक आवश्यकता का बोद्धिक और नैतिक बोध भी गहरा होता जाता है। लेकिन इस बोध का अभी कोई निर्णायक रूप नहीं है, और व्यवहार में, उसके स्थान पर शीघ्र ही प्रतिरक्षा की अधिक टिकाऊ और अधिक स्वीकार्य स्थिति को फिर से अपनाने की, उतनी ही आसानी से समझी जा सकने वाली आवश्यकता आ जाती है।

बहुतेरे बोधगम्य कारणों से, वाशिंगटन और मास्को में अधिकांश नीति-सचालक निरस्त्रीकरण के बजाय, शस्त्रीकरण के सवाल में व्यस्त हैं। कभी-कभी वे अपने को इस पेचीदा अर्द्ध-सत्य से समझा लेते हैं कि हथियार बढ़ने से निरस्त्रीकरण की उपलब्धि में सहायता मिलेगी क्योंकि, जैसा चर्चिल ने एक बार कहा था, 'हम सम-भोता वार्ता करने के लिए शस्त्रीकरण करते हैं।'

लेकिन शस्त्रीकरण के जो परिणाम होते हैं, वे सब इसकी पुष्टि ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने आप से बराबर यह कहते रहना निरर्थक प्रतीत हो सकता है कि हथियारों की होड़ को बढ़ाना ही शांति की उपलब्धि का सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन इसका विकल्प, कि बढ़ती हुई सोवियत सैन्य क्षमता के विरुद्ध हम प्रभावी प्रतिकारक शक्ति न कायम रखें, और भी निरर्थक है।

स्पष्टतः शान्ति अगर कभी कोई सरल, एकपक्षीय, अकृत्रिम वस्तु थी भी, तो अब नहीं है। यह नैतिक, सैनिक, आर्थिक, और प्राविधिक समस्याओं का एक जबरदस्त जाल है।

आज हमारे सर्वाधिक बुद्धिपूर्ण पर्यवेक्षकों में से बहुतेरे हार मान लेते हैं, और

इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस अव्यवस्था में से किसी प्रकार की व्यवस्थित नीति निकालना असंभव है।

ये निराशावादी आज गलत हो सकते हैं। लेकिन इन सभी तत्वों की पेचीदगी अग्रर यूँही बढ़ती रही, तो कल वे सही होंगे। प्रति वर्ष शांति की समस्या अपने-आप में अधिक कठिन होती जाती है। प्रतिरक्षा और निरस्त्रीकरण की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे यह बात विशेषतः सच है। जितनी देर तक हम समस्याओं को बढ़ने देते हैं, उतनी ही वे काबू के बाहर होती जाती हैं। हम पूछ सकते हैं कि फिर हम दिखाओ का पता कैसे लगाएँ कि किस तरफ जाना है? हम समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं?

जैसा अणु-शक्ति कमीशन के भूतपूर्व कमिश्नर थामस ई० मरे ने कहा है, "एक हद तक अणुशक्ति का विकास स्वयं अपनी दृढ़तात्मकता से हुआ है। ...आरम्भ में हम सामरिक नीति में इस प्रसीमित शक्ति को जोड़ने के अंतिम परिणामों के बारे में सोचते हुए डरते थे, क्योंकि यह नीति पहले से ही असीमित जनसंख्या के विनाश को आधुनिक युद्ध-कला का एक सामान्य अंग समझती थी, लेकिन, जैसे भी हो, हमने उसे जोड़ दिया। एक भुलावे में पड़कर, हमने सैन्य-प्रविधि के द्वारा अपनी रणनीति निर्धारित हो जाने दी। ...अब प्राविधिक विकास हमारे नियंत्रण के बाहर तेजी से हो रहा है, और हम उसके साथ लिचे जा रहे हैं।"

'सुश्रीम सोवियत' (रूस की सर्वोच्च सभा) के समक्ष 14 जनवरी, 1960 को दिये गए ख्रुश्चोव के भाषण से पता चलता है कि रूस में भी यात्रिक प्रविधियाँ हर चीज को अपने साथ खींचे लिए जा रही हैं। प्राणिक अस्त्रों का जो रूप है, और जिस तेजी से उनकी गार हो सकती है, उसके फलस्वरूप अब यह अनिवार्य है कि शीत-युद्ध के दोनों पक्षों में यात्रिक प्रविधियाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक समय और शक्ति लगाएँ। संभव विरोधी के पहले किसी प्राविधिक विकास को प्राप्त करने के अस्थायी लाभ का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जाता है। संभावना इस बात की है कि नए अस्थायी संतुलनों को बिगाड़ने के प्रयत्नों का एक अंतहीन सिलसिला चले, जिसमें खर्च और खतरे बहुगुणित होते जाएँ।

इसके साथ ही, आक्रमण के लाभ और प्रतिरक्षा की हानि का अन्तर बढ़ता जाता है। यह अन्तर अभी भी इतना अधिक हो गया है कि सर्वथा समझदार और गंभीर सोवियत रणनीतिज्ञ शीम्र ही यह अनुभव करने लगे कि अमरीका पर अचानक आण्विक हमला करना, सोवियत रूस के लिए एक तर्क संगत नीति होगी।

सैन्य प्रविधियों के जिस दसक में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें अचानक हमला, रणनाश, घलती, और दुर्घटना के खतरनाक तत्व निहित हैं। और जैसे वे सब काफी न हों, अब हम लोह धारण के दोनों ओर शीत-युद्ध के रणनीतिज्ञों को एक-दूसरे का मनोविश्लेषण करने की चेष्टा करते देख सकते हैं। अस्थिरता के इससे बढ़े किसी नए तत्व की बलना करना कठिन है।

रोज व रोज इस पीढ़ी के अमरीकियों के सापन, शक्तिशाली, जनशक्ति, और

मनोशक्ति, अधिकाधिक इस प्रश्न पर केन्द्रित हो रही है कि आधे-घंटे के प्रलयकारी आण्विक विनाश में अपने-आप को कैसे बचाया जा सकता है। उत्तर-जीवन के साथ हमारी व्यस्तता ने भयंकर सीमा तक अन्य सभी कामों का स्थान ले लिया है। कूट-नीति, विदेशी सहायता और शिक्षा, सब इस मूल रणनीतिक प्रयास के साथ बंध गए हैं।

दोनों ओर से करोड़ों व्यक्तियों के विनाश की धमकियाँ अणु-युग में निरोध और प्रतिरोध की प्रमुख विशेषता बन गई हैं, और हमें सलाह दी जाती है कि अपनी धमकियों को विश्वसनीय बनाने के लिए हमें बराबर नए तरीके निकालने होंगे।

फिर भी, चूंकि यांत्रिक प्रविधियाँ अनियंत्रित गति से बढ़ती जाती हैं, अतः ये धमकियाँ अपनी भयंकरता के कारण ही विश्वसनीयता खो रही हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया अणु बम, दूसरे महायुद्ध में प्रयुक्त बड़े में बड़े साधारण बम से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसके बाद कुछ हाइड्रोजन बम जो हमने बनाए हैं, उनकी शक्ति दूसरे महायुद्ध में गिराये गए सारे बमों की कुल शक्ति से हजार गुना अधिक है।

आण्विक प्रविधियों की होड़ का अंत क्या हो सकता है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। अगर यह होड़ बेरोकटोक चलती रही, तो इसका अंत होगा दुनिया का अंत। किमी ने कहा है कि हमारे आस-पाम के ग्रहों के प्राणीविहीन होने का कारण शायद यह है कि उनके वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिकों से आगे थे।

×

×

×

जब हम आज निरस्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें दूसरे महायुद्ध के पहले की, या अणु-युग, या प्रशोषास्त्रों के युग के भी पहले की आदतों के अनुसार सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए। 1960 की दुनिया इन सभी कालों की दुनिया से भिन्न है, और हमें पुराने निरर्थक मताग्रहों को छोड़कर उसके वास्तविक रूप को देखना चाहिए।

यह व्यंगपूर्ण है कि अपने मताग्रह-रहित, लोभतांत्रिक विरोधियों की अपेक्षा, खुश्चोव कभी-कभी अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने मताग्रहों का परित्याग करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, फरवरी, 1957 में उनके मास्को के दफ्तर में मैंने श्री खुश्चोव से पूछा कि वे क्या वास्तव में अपने मार्क्सवादी विश्वासों से हट नहीं रहे हैं। हम निरस्त्रीकरण की चर्चा कर रहे थे, और निरस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रभावी समझौता करने की उनकी इच्छा को मैंने चुनौती दी थी।

मैंने कहा कि मार्क्सवादी मताग्रह के अनुसार, पूँजीवादी पश्चिम अपनी समृद्धि को कायम रखने के लिए बहुत कुछ अपने शास्त्र उद्योगों पर निर्भर है। इस सिद्धान्त का यह अर्थ प्रतीत होता है कि निरस्त्रीकरण से साम्यवाद की विजय और निकट आ जाएगी। इसके अनुसार सैन्य उद्योगों के बन्द होने पर बेकारी बढ़ेगी, क्रय-शक्ति

पटेगी और बढ़ती हुई मन्दी के फलस्वरूप राजनीतिक उथल-पुथल होगी और पूँजीवाद का विनाश होगा।

फिर, श्री जूडचोव इस मानसवादी सिद्धान्त पर चल कर, निरस्त्रीकरण के व्यावहारिक समझौते के लिए हर संभव प्रयास क्यों नहीं करते, जो पूँजीवाद के विनाश की भूमिका होगी ? क्या इस प्रकार काम करने में उनकी असफलता उन्हें मानसवाद से हटने वाला नहीं बनाती ? क्या उन्हें अपने अधिक मताग्रही साथियों की प्रतिक्रियाओं की चिन्ता नहीं थी ? उनकी मुस्कान भरी प्रतिक्रिया से संकेत मिलता था कि उन्होंने मेरी बात समझ ली है, और उसमें वे परेशान नहीं हुए।

यह एक ऐसा प्रसंग है, जिसमें हम इस बात को ज्यादा पसन्द कर सकते हैं, कि आधुनिक मानसवादी अपने मताग्रह को छोड़ने के बजाए, उसके अनुरूप आचरण करें।

इस बीच, शास्त्र-नियंत्रण के क्षेत्र में हम अमरीकियों के अपने मताग्रह हैं, जिनका हमें परित्याग करना है। कितनी बार हमने सुना है कि सबसे बठिन समस्याएँ, निस्सन्देह, राजनीतिक समस्याएँ हैं—बर्लिन, जर्मनी, मध्य-पूर्व, कोरिया, विएतनाम, और फारमोसा—और कितनी बार हमें समझाया गया है कि इन समस्याओं के हल हो जाने के बाद ही शास्त्र-नियंत्रण संभव होगा ?

यह बार-बार दुहराई गई बात खोखली प्रतीत होती है कि हथियार लक्षण है, रोग का कारण नहीं। शास्त्र-नियंत्रण का अपना एक महत्त्व हो गया है। विशेषतः इस बात को देखते हुए कि विश्व की बहुतेरी बड़ी और ठोस राजनीतिक समस्याओं के बारे में इस समय समझौता होना संभव नहीं है, या सदेहास्पद है, शास्त्र-नियंत्रण का सचमुच प्राथमिक महत्त्व हो जाता है।

इस समस्या के मूल में दो आधारभूत सत्य हैं। पहला यह तथ्य है कि सारे इतिहास में शास्त्रों की होड़ का अन्त आमतौर पर युद्ध में हुआ है। दूसरा यह तथ्य है कि असावधानी और एकपक्षीय या सुरक्षाहीन निरस्त्रीकरण का अन्त हमें राष्ट्रीय सकट में हुआ है।

ये दोनों तथ्य समान रूप से मौलिक हैं, और उन पर साथ-साथ विचार करना चाहिए। हमारी कुछ बड़ी कठिनाइयाँ अपने विचारों में उन्हें अलग-अलग करने के प्रयत्नों से उत्पन्न होती हैं। जिनका मुख्य आग्रह हमारी मैन्य प्रतिरक्षा को हर तरह से पूर्ण बनाने पर है, वे बहुधा शास्त्र-नियंत्रण के समर्थकों को गभीर सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। जिनका आग्रह सुरक्षापूर्ण निरस्त्रीकरण पर है, वे सैन्यबल के लोगों के प्रति उसी प्रकार सकालु हैं।

अगर हम अपने को बचाने की समस्या को प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो समस्या शास्त्रों की होड़ में आगे रहने की है। मानवी दृष्टिकोण से देखें, तो समस्या इस होड़ को बम करने की है।

जनवरी, 1959 के फारेन एफैयर्स में लिखते हुए श्री ऐल्बर्ट वॉल्स्टेटर ने कहा—

“तनाव घटाना, जिसे सब लोग अच्छा समझते हैं, और रक्षा सम्बन्धी सावधानी घटाना, जिसे सब लोग बुरा समझते हैं, इनके बीच अन्तर कर पाना आसान नहीं है।”

प्रतिरक्षा और निरस्त्रीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, निरीक्षण के प्रदन पर मिलते हैं। ज़मीन या पानी के नीचे किये गए परीक्षणों का पता लगाने में, अधिक विश्वसनीय वैज्ञानिक उपलब्धि, बड़े समय, अनिश्चय और परेशानी को बचत कर सकती थी। जिस हृद तक शासनों के अन्दर ऐसी शक्तियाँ हैं, जो परीक्षण करना चाहती हैं, चाहे उनका पता चले या न चले, उस हृद तक पता लगाने की समस्या हल हो जाने पर भी विवाद का अन्त न होता। लेकिन जेनेवा में बड़े विभ्रम और बड़ी बाधा का एक कारण दूर हो जाता।

ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सभी दिशाओं में प्रगति कठिन है, उन क्षेत्रों की अपेक्षा न करना उचित होगा, जहाँ अधिक सही वैज्ञानिक सूचना नीति की समस्याएँ हल कर सकती हैं। ज़मीन के नीचे किये गए परीक्षणों का पता लगाने के विवाद में, वैज्ञानिक समस्या को हल करना स्पष्टतः एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयास करना चाहिए। चूँकि हमने अभी तक इस वैज्ञानिक खाई को पाटने का सशक्त प्रयास नहीं किया है, अतः अब ऐसा करना आवश्यक है।

आण्विक अस्त्रों में दूसरों को हिस्सेदार बनाने का वर्तमान विवाद इसका एक और बड़ा उदाहरण है कि प्रतिरक्षा और निरस्त्रीकरण के भिन्न परिप्रेक्ष्य किस प्रकार नियंत्रणों के वैज्ञानिक और प्राविधिक सद्वर्धन में एक जगह मिलते हैं।

एक दृष्टिकोण के अनुसार हमें अधिक व्यापक रूप में अपने मित्रों को आण्विक अस्त्रों में हिस्सेदार बनाना चाहिए। इनका तर्क है कि हमारे संभाव्य शत्रु के पास जो क्षमता पहले से ही है, उससे अपने मित्रों को बचित रखना इस युग में आत्मघाती कार्य होगा, जिसमें एक क्षण के छोटे से अंश का भी रणनीतिक महत्त्व है।

दूसरा दृष्टिकोण इस उतने ही यथार्थ खतरे पर जोर देता है कि हथियारों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने से इसकी संभावना बढ़ती है कि उन पर कभी भी नियंत्रण न किया जा सके, और इसके साथ, अणु-युद्ध के दुष्घटनावश, या जान-बूझ कर शुरू किए जाने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है।

किन्तु इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की अगर हम निकट परीक्षा करें, तो शायद ये अद्वैत रूप में विरोधी न सिद्ध हों। यहाँ भी, खेल की संभावना जो भी है, वह नियंत्रण व्यवस्थाओं के क्षेत्र में है। यह मभवतः प्रश्नों के इस क्रम के कार्य-पद्धति सम्बन्धी नए उत्तरों पर निर्भर है।

प्रतिरक्षा और निरस्त्रीकरण, दोनों की ही आवश्यकताओं से सगत अगर कोई विशिष्ट कदम है, तो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि में ऐसी नई व्यवस्थाएँ कौन-सी की जा सकती हैं, जो वाह्य आक्रमण के लिए एक साथ ही अधिकतम रोक और न्यूनतम उत्तेजना प्रदान करें? कौन-सी व्यवस्था आण्विक प्रविधियों को

अधिकतम सीमा तक सामान्य उद्देश्यों में लगा सकती है, और वचित होने की उस भावना को अधिक से अधिक घटा सकती है, जो इस समय उन राष्ट्रों को अणु-शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनके पास इस समय अणु-शक्ति नहीं है।

अपने मित्रों को वे समझे-बूझे अणु-शस्त्र प्रदान करने में इस प्रश्न का उत्तर मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह, प्रश्न का उत्तर इस सरल सतोप में भी मिलने की संभावना नहीं है कि हम अणु-अस्त्रों का स्वयं अपना भंडार जमा करते रहे, और हमारी आपत्तियों के बावजूद, तथा हमारी सहायता के बिना ही, अणु-अस्त्रों के फैलाव की बढ़ी ही यथार्थ संभावना पर विचार न करें।

नियंत्रण, देख-रेख, निरीक्षण, और नियोजन सम्बन्धी कार्यों में अगर उत्तरी अटलांटिक संधि के माध्यम से वे सदस्य भी भाग लें जिनके पास अणु-अस्त्र नहीं हैं, तो फ्रांस के समान स्वतंत्र मार्ग पर चलने की कुछ सदस्यों की इच्छा इससे समाप्त हो सकती है। अगर उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा एक विश्वसनीय, और व्यापक प्राण्विक बाधा रणनीति का विकास किया जाय, तो इसी से अलग-अलग प्राण्विक प्रतिकार विकसित करने के कारण घटेंगे, और रूस भी अधिक आश्वस्त हो सकता है। उत्तरी अटलांटिक संधि के अन्तर्गत, समुक्त वैज्ञानिक खोजकार्य का शस्त्र-निर्माण और शस्त्र-नियंत्रण दोनों में ही सम्भाव्य महत्त्व बहुत अधिक हो सकता है।

उत्तरी अटलांटिक संधि के बाहर भी अणु अस्त्रों के फैलने के खतरे के उतने ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, साम्यवादी चीन, या अरातिपूर्ण पूर्वी जर्मनी में स्वतंत्र प्राण्विक क्षमताओं के विकास की संभावना से रूस को वास्तव में कोई सन्तोप नहीं हो सकता। सामान्य खतरे से, सामान्य हित पर आधारित समझौतों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति के लिए तैयार किये गए 'सोवियत संध और पूर्वी यूरोप' सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन में, फोलम्बिया-हार्वर्ड खोज समूह के दिमाग में शायद यही बात रही हो, जब उसने लिखा—“दीर्घ-कालीन दृष्टि से, शस्त्र-नियंत्रण के शुद्ध पक्षों को सीमित करने में सामान्य हित की संभावनाओं की खोज करते हुए, हम रूसियों को शायद अपना सबसे जिम्मेदार और दक्षियानूयी विरोधी पाएँ।” यह बात बट्टेरे अमरीकियों को विचित्र लग सकती है, लेकिन किसी भी तरह अगम्य नहीं है।

×

×

×

गवने प्रतिपक्ष घाटबर्ष की बात यह है कि शस्त्र-नियंत्रण की समस्या को जो प्रायमि-कता मिलनी चाहिए, यह हमने उगे इतने दिनों तक नहीं दी, और अब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए घाघट न किया गया हो। लेकिन अभी अनुसंधान-कार्य कर दिने गए।

इस प्रकार, सिद्धते होने से हम साम पहले, 1 मार्च, 1950 को, कॉन्फिडेंट के इन्डिस्ट्रियल सीनेटर, स्पर्डीन वायन मंजमेहोन ने सीनेट में मापण देने हुए उम प्रचार

की कार्यवाही के लिए अपील की, जो हमने अभी तक नहीं की है। उन्होंने तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया था, और उनके संदेश की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। उनकी भांति, मैं भी अपनी बात इन शब्दों से समाप्त करूँ, जो दस वर्ष पुराने होकर भी सर्वथा नए हैं :

“हर क्षण के साथ सम्पत्ता को बचाने का समय कम होता जाता है। हम इस काम में कब सगेंगे ? निश्चित हमें उदासीनता की भेंट नहीं प्रदान करेंगे। अगर हम कार्यवाही नहीं करते, तो बरवाद धरती के उत्तराधिकारी शायद हमेशा हमारी भत्सना करेंगे।

“हमारी भत्सना मूर्खों के रूप में नहीं की जाएगी—क्योंकि कोई मूर्ख भी किसी बहुत बड़े खतरे को समझ लेता है। हमारी भत्सना कायरों के रूप में की जायगी—जो ठीक ही होगी, क्योंकि जो भयानक तथ्य हमने धीरे-धीरे के साथ काम करने की माँग कर रहे हैं, उनसे कोई कायर ही मुँह चुरा सकता है। महानतम संकट का यह काल महानतम भ्रवसर का भी काल है। आश्विक शान्ति का पुरस्कार, जीतने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है—और वह पुरस्कार है एक आश्चर्यमय नयी दुनिया।”

अधिकतम सीमा तक सामान्य उद्देश्यो मे लगा सकती है, और वचित हं भावना को अधिक से अधिक घटा सकती है, जो इस समय उन राष्ट्रो को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनके पास इस समय अणु-शक्ति न अपना मित्रो को वे समझे-बूझे अणु-शस्त्र प्रदान करने मे इस प्रश्न मिलने की सभावना नही है। इसी तरह, प्रश्न का उत्तर इस सरल स मिलने की सभावना नही है कि हम अणु-अस्त्रो का स्वयं अपना भंडार रहे, और हमारी आपत्तियो के बावजूद, तथा हमारी सहायता के बिना ही, के फैलाव की दृष्टि ही यथार्थ सभावना पर विचार न करे।

नियंत्रण, देख-रेख, निरीक्षण, और नियोजन सम्बन्धी कार्यों मे अष्टलाटिक संधि के माध्यम से वे सदस्य भी भाग लें जिनके पास अणु-अस्त्रो फ्रांस के समान स्वतंत्र मार्ग पर चलने की कुछ सदस्यों की इच्छा इस हो सकती है। अगर उत्तरी अष्टलाटिक संधि के द्वारा एक विश्वसनीय, औष्णिक बाधा रणनीति का विकास किया जाय, तो इसी से अलग-अलग प्रतिकार विकसित करने के कारण घटेंगे, और रूस भी अधिक आश्वस्त हो स उत्तरी अष्टलाटिक संधि के अन्तर्गत, संयुक्त वैज्ञानिक खोजकार्य का शस्त्र और शस्त्र-नियंत्रण दोनो मे ही सम्भाव्य महत्व बहुत अधिक हो सकता है।

उत्तरी अष्टलाटिक संधि के बाहर भी अणु अस्त्रों के फैलने के खतरे के गभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, साम्यवादी चीन, या अर पूर्वी जर्मनी मे स्वतंत्र औष्णिक क्षमताओं के विकास की संभावना से रूस को में कोई सन्तोष नही हो सकता। सामान्य खतरे से, सामान्य हित पर स समझौतों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

सीनेट की बंदेशिक सम्बन्ध समिति के लिए तैयार किये गए 'सोवियत स पूर्वी यूरोप' सम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्ययन मे, कोलम्बिया-हार्वर्ड खोज समूह के मे सायद यही बात रही हो, जब उमने निम्ना—“दीर्घ-कालीन दृष्टि से, शस्त्र न्ण के कुछ पक्षो की सीमित करने मे सामान्य हित की संभावनाओं की खोज हुए, हम ह्मियों को सायद अपना सबसे जिम्मेदार और दक्षियानुशी विरोधो पा, यह बात बहूनेरे अमरीकियों को विचित्र लग सकती है, लेकिन निमी भी स अगमन नहीं है।

×

×

×

सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि शस्त्र-नियंत्रण की समस्या को जो प्राथमि- कता मिलनी चाहिए, वह हमने उमें इतने दिनों तक नहीं दी, और अब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रायश् न किया गया हो। लेकिन अभी अनुरोध पन-मुने कर दिने गए।

इस प्रकार, सिद्धने ह्मने मे दस साल पहले, 1 मार्च, 1950 को, कनिट्टिकट के प्रतिष्ठित सेनेटर, रजर्गन ब्रान्त मैग्नेहोन ने सीनेट में भाषण देने हुए उस प्रकार

की कार्यवाही के लिए अपील की, जो हमने अभी तक नहीं की है। उन्होंने तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया था, और उनके सन्देश की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। उनकी भांति, मैं भी अपनी बात इन शब्दों से समाप्त कहूँ, जो दस वर्ष पुराने होकर भी सर्वथा नए हैं :

“हर क्षण के साथ सम्यता को बचाने का समय कम होता जाता है। हम इस काम में क्या लगे ? नियति हमें उदासीनता की भेंट नहीं प्रदान करेगी। अगर हम कार्यवाही नहीं करते, तो बरबाद धरती के उत्तराधिकारी शायद हमेशा हमारी भर्त्सना करेंगे।

“हमारी भर्त्सना मूर्खों के रूप में नहीं की जाएगी—क्योंकि कोई मूर्ख भी किसी बहुत बड़े खतरे को समझ लेता है। हमारी भर्त्सना कायरों के रूप में की जायगी—जो ठीक ही होगी, क्योंकि जो भयानक तथ्य हमसे धीरज के साथ काम करने की माँग कर रहे हैं, उनसे कोई कायर ही मुँह चुरा सकता है। महानतम संकट का यह काल महानतम अवसर का भी काल है। आण्विक शान्ति का पुरस्कार, जीतने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है—और वह पुरस्कार है एक आश्चर्यमय नयी दुनिया।”

सोवियत अजेयता की मिथ्या धारणा

नए प्रशासन ने 1961 में, चोटी के अमरीकी संपादकों, और जनमत के नेताओं के साथ अमरीकी विदेश-नीति की समस्याओं की चर्चा करने के लिए कई क्षेत्रीय 'मूचना सम्मेलन' किए। अक्टूबर, 1961 में, डालास, टेक्सास में हुए सम्मेलन में अवर विदेश सचिव वॉल्स ने शीत युद्ध में सोवियत पैतृराजकी के सम्बन्ध में एक नया परिप्रेक्ष्य अपनाने का सुझाव रखा।

कोई राष्ट्रीय नीति जो सोवियत शक्ति और संकल्प को ध्यान में नहीं रखती, वह खतरनाक ही नहीं, आत्मघाती होगी। फिर भी, हमें अपनी दृष्टि सन्तुलित रखनी चाहिए। सभी रूसी दस फुट ऊँचे नहीं होते।

हम इस स्पष्ट तथ्य को बहुधा भुला देते हैं, विशेषतः एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के नए राष्ट्रों के साथ अपने व्यवहार में, कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में रूस ने कहीं अधिक, और कहीं ज्यादा गंभीर गलतियाँ की हैं, और उन्हे उतना ही अधिक निराश भी होना पडा है।

स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, हम पिछले पन्द्रह वर्षों को उस रूप में देखें, जिस रूप में रूसी शासन के सदस्य आवेगहीन यथार्थ की दृष्टि से देखने पर इस काल को देख पाते होंगे। ऐसे सिंहावलोकन से हमें स्वयं अपनी शक्तियों को ज्यादा अच्छी तरह समझने में, और समूचे विश्व की स्थितियों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता मिल सकती है।

दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप में एक राजनीतिक और आर्थिक शून्य उत्पन्न हो गया था। अधिकांश उद्योग नष्ट हो गए थे, महगाई और व्यापक बेकारी से हर राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पीड़ित थी।

इन बीच अमरीका में, दोनों दलों के विवेकहीन राजनीतिक नेताओं की प्रेरणा ने इन बातों की होड़ लग गई थी कि हम जल्दी से जल्दी अपनी विजयी सेनाओं को मंग कर दें, और अपने घरों में वापस आ जाएं।

अधिकांश पूर्वी यूरोप पर साल सेनाओं का अधिकार था, और सोवियत सेना के समग्र दो सी युद्ध-परीक्षित डिवीजन अब भी हथियारबन्द थे। घतःस्टालिन को

विश्वास था कि साम्यवाद शीघ्र ही सम्पूर्ण यूरोप के दून्य को भर देगा। यूरोप में साम्यवाद का प्रभुत्व स्थापित करने की स्टालिन की पद्धतियों में संन्य शक्ति, साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित हड़तालों, विभाजक प्रचार, और यूनान तथा अन्य स्थानों में छापामार कार्यवाहियाँ भी शामिल थीं।

फिर भी नतीजा क्या निकला ?

जारो की पुरानी परम्परा में, यूनान और तुर्की के माध्यम से भूमध्य-सागरीय क्षेत्र पर सोवियत दबाव को, ट्रुमन निदान्त के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर अमरीकी संन्य और प्रायिक सहायता की प्रतिरोधात्मक कार्यवाही ने, और स्वतंत्रता के प्रति यूनान की निष्ठा ने विफल बना दिया।

कुछ महीनों के अन्दर ही, पश्चिमी यूरोप की मुद्ध-ध्वस्त अर्थ-व्यवस्थाओं का पुनः निर्माण करने के लिए मार्शल योजना की सहायता प्रदान की गई। इसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि की स्थापना हुई, जिसने हमारे मित्रों और साम्यवादी जगत के बीच एक प्रभावकारी रक्षा-पत्रित प्रदान की

यह भूल जाना आसान है कि पन्द्रह वर्ष पहले ही, बहुतेरे अमरीकी यह गंभीर भविष्यवाणी करते थे कि पश्चिमी यूरोप शीघ्र ही साम्यवादियों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन, जेकोस्लोवाकिया को छोड़कर, सोवियत शक्ति उस इलाके से आगे नहीं बढ़ सकी, जिसे लाल सेना ने जीत कर अपने अधिकार में ले लिया था। तत्काल साहसपूर्ण, संयुक्त कार्यवाही से यूरोप की स्वतंत्रता सुरक्षित हो गई, और आज वह अपने इतिहास के अन्य किसी भी काल से अधिक सबल और समृद्ध है।

सोवियत सच ने 1948 में शीत-युद्ध की एक और चाल चली कि बर्लिन के रास्ते बन्द करके उसका दम घोट दिया जाय। लेकिन इस परीक्षा में भी अमरीकी और अंग्रेज उद्यम और चतुराई को सफलता मिली। बर्लिन के साथ हवाई सम्पर्क की अवि-द्वसनीय शी लगने वाली व्यवस्था से रूसी बार विफल कर दिया गया। और कुल नतीजा यही निकला कि पश्चिम में साम्यवादी खतरे की चेतना अधिक आई।

1948 में ही युगोस्लाविया सोवियत गुट से अलग हो गया। और तेरह वर्ष तक दी गई रूसी धमकियों और लोभों को उसे वापस लाने में सफलता नहीं मिली है। एकात्मक समझे जाने वाले सोवियत साम्राज्य में यह पहली महत्वपूर्ण दरार थी। यद्यपि वे अब भी अपने को साम्यवादी कहते हैं, किन्तु युगोस्लाव लोग आज सोवियत नियंत्रण से मुक्त एक अपेक्षतया समृद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं।

स्टालिन और उनके प्रति-आज्ञावादी समर्थकों के लिए 1948 वस्तुतः बड़ी व्यस्तता का वर्ष था। उसी वर्ष मास्को के आदेश से एशिया में छह नई साम्यवादी क्रातियाँ आरम्भ की गईं—फिलीपीन, इण्डोनेसिया, फ्रांसीसी हिन्दचीन, मलय, ब्रह्मा और भारत में।

इन छह राष्ट्रों में से पाँच नए स्वतंत्र, अपेक्षतया असंगठित राष्ट्र थे, जिन्हें अपेक्षतया दुर्बल और बटा हुआ समझा जाता था। मास्को की नजरों में वे साम्यवादी

क्रांति के लिए—जो सावधानी से संगठित की गई थी, जिसे धन की कमी न थी, और जिसका नेतृत्व स्थानीय था—प्राप्त लक्ष्य प्रतीत हुए होंगे। लेकिन पाँचों में ही ये प्रयास पूर्णतः असफल रहे।

छठे क्षेत्र हिन्द-चीन में, साम्यवादी अपने प्रचार और दबाव को फ्रांस के विरुद्ध केन्द्रित कर सके, जो एक ग़ोरा औपनिवेशिक देश था, और केवल यही उनकी शक्तियों को नाशिक सफलता मिली।

फिर, कुछ ही वर्ष पहले, सभी विचारशील प्रेक्षक मध्य-पूर्व में सोवियत प्रवेश से चिन्तित थे। बहुतों का ख्याल था कि, मिसाल के लिए, मिस्र पर सोवियत नियंत्रण कायम हो जाएगा। किन्तु आज नासिर का राष्ट्रवाद आन्तरिक साम्यवाद के विरुद्ध तेजी से लड़ता है, और सोवियत सघ के साथ उनके सम्बन्धों में घनिष्ठता बराबर कम होती जा रही है। मध्य-पूर्व में स्थिति यद्यपि अभी अस्थिर और अनिश्चित है, किन्तु सोवियत रूस को अभी तक अपनी आशाओं से बहुत कम लाभ हुआ है।

1955 में सोवियत रूस ने हिन्दुस्तान और जापान में ख़ुश्चोव का नया आर्थिक राजनीतिक कार्य-क्रम चलाया। हर तरह के संकेत और वादे किये गए। और एक बार फिर उसके प्रयत्न अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सके।

अपनी सारी समस्याओं सहित, आज हिन्दुस्तान एक तेजी से विकसित होता हुआ अधिकाधिक आत्म-विश्वास पूर्ण, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धोत्तर कालीन जापान धीरे-धीरे अपने आन्तरिक सघर्षों पर काबू पाता जा रहा है, और एक लोकतांत्रिक शासन के अन्तर्गत, असाधारण आर्थिक और राजनीतिक सफलता प्राप्त कर रहा है।

अब हम अफ्रीका पर विचार करें, जो सोवियत महत्त्वकांक्षा के सर्वप्रथम लक्ष्यों में से एक है, और जिस पर उन्होंने बड़ी आशाएँ लगा रखी हैं।

पिछले दस वर्षों में, अफ्रीका में चौबीस नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ है। जब इस विशाल और अव्यवस्थापूर्ण महाद्वीप में साम्यवादियों ने अपने प्रयत्न तेज किए तो अफ्रीका में रूसी 'पिछलगुओं' की अनिवार्यता की बड़ी चर्चा हुई।

यद्यपि अफ्रीकी राजधानियों में कुछ रोप उत्पन्न करने वाले भाषण हुए हैं, और कुछ सम्बन्ध आशंकाजनक सीमा तक दुर्बल हैं, किन्तु अफ्रीकी राष्ट्रवाद ने अभी तक रूसी लालचों में फँसने को अपने से बचाया है।

वांगो में विशेषतः नाटकीय रीति से रूस की पराजय हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं उसका मुख्य विरोधी था। इस पराजय का प्रत्यक्ष परिणाम था कि एक प्रधान-मन्त्री के स्थान पर तीन प्रमुख अधिकारियों द्वारा प्रशासन के 'त्रिमूर्ति' प्रस्ताव के द्वारा रूस ने संयुक्त राष्ट्र सघ की प्रभावकारिता को समाप्त करने की चेष्टा की। सोवियत गुट के बाहर एक भी राष्ट्र ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जो एक और पराजय थी।

मेरा यह मतलब नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सब काम हमारी तबियत के अनु-

सार हो रहा है। लेकिन इस संगठन को नष्ट या दुर्बल करने के सोवियत प्रयास अभी तक असफल रहे हैं।

साम्यवादी चीन में भी, जहाँ साम्यवाद की आश्चर्यजनक जीत पर रूस ने अपने-आपको बघाई दी थी, आज रूस को उलभन में डालने वाले दवावों और अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम विद्वत् साम्यवादी आन्दोलन के नेतृत्व के लिए कटु संधर्ष होता देख रहे हैं, जो पीकिंग और मास्को के बीच बार-बार उठने वाले सैद्धान्तिक विवादों में व्यक्त होता है।

अब हम उन आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों के एक अन्य पक्ष पर विचार करें, जिनकी ओर मास्को को ध्यान देना होगा। पिछले कई वर्षों से रूसी सरकार दो प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच दान्तिपूर्ण प्रतियोगिता की बात करती रही है। किन्तु ऐसी प्रतियोगिता का अनुभव क्या अपने पड़ोस में ही उन्हें नहीं हो चुका ?

पन्द्रह वर्षों से पश्चिमी जर्मनी का विकास एक व्यवस्था के अन्तर्गत हो रहा है, पूर्वी जर्मनी का दूसरी के अन्तर्गत। और नतीजा क्या निकला है ? पश्चिमी जर्मनी में हमें आधुनिक काल की महान् आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सफलता की कहानियाँ में से एक मिलती है—अत्यधिक शक्ति और सम्भावनाओं से युक्त एक स्वतंत्र, समृद्ध, गतिशील समाज।

इसके विपरीत पूर्वी जर्मनी का शासन बुरी तरह असफल है, आर्थिक मंदी है, बौद्धिक विफलता है, और स्वयं उसके नागरिक उसे स्पष्ट तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। वस्तुतः पूर्वी जर्मनी में सोवियत असफलता इतनी बढ़ी रही है कि साम्यवादियों की मशीन-गनों और टैंकों द्वारा रक्षित एक दीवाल बनानी पड़ी ताकि पूर्वी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी के तथाकथित 'साम्यवादी स्वर्ग' से पश्चिमी जर्मनी के 'पूँजीवादी गन्दे नाले' की ओर सामूहिक निष्क्रमण न करें।

इस हताशाजनित कार्य से साम्यवादी नेताओं ने दुनिया को यह बता दिया है कि अपने लोगों को अपने साथ रखने का उनके पास एक ही उपाय है, कि वे उन्हें ताले में बन्द रखें। यद्यपि पूर्वी जर्मनी पश्चिम के लिए नई समस्याएँ उत्पन्न करता है, किन्तु यूरोप में सोवियत नीति की असफलता का यह एक विशाल प्रतीक है।

अपने लोगों का समर्थन प्राप्त करने में साम्यवादियों की असफलता केवल पूर्वी यूरोप में ही नहीं बरन् पोलैण्ड और हंगरी में भी, और वस्तुतः शेष सभी अभाग्य पिछलग्गू राष्ट्रों में भी है। और यह स्थिति तब है जब साम्यवादी स्कूलों, साम्यवादी रेडियो, और साम्यवादी पुस्तकों और समाचार पत्रों के द्वारा समूची युद्धोत्तरकालीन पीढ़ी का पिछले पन्द्रह वर्षों से सुनियोजित, सघन और निरन्तर सैद्धान्तिक प्रशिक्षण किया जा रहा है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय स्वाधीनता की भूख, जो सोवियत तानाशाही का प्रतिरोध करने से भी पीछे नहीं हटी, रूसी असफलता की गंभीरता को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करती है।

पाँच वर्ष पहले, हंगरी के पचीस हजार नौजवानों ने बुडोपेस्ट की सड़कों पर सोवियत टैंको के विरुद्ध सघर्ष में अपनी जान देकर इसे प्रमाणित किया। पूर्वी जर्मनी के लगभग चालीस लाख लोगो ने, जिनमें से अधिकांश की आयु तीस वर्ष से कम है, पश्चिम में सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने घरों को छोड़कर इसका प्रमाण दिया है।

यद्यपि हमें कभी भी सोवियत सघ की भौतिक और सैन्य शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, किन्तु रूस की आर्थिक और राजनीतिक कार्यवाही यूरोप में असफल रही है, सुदूर पूर्व में असफल रही है, मध्य-पूर्व में असफल रही है, और अफ्रीका में असफल रही है। एकमात्र ब्यूवा के अपवाद को छोड़कर यह लातिन अमरीका में भी असफल रही है।

मेरा कहना है कि शीत युद्ध में सोवियत रूस की जीत नहीं, हार होती रही है।

साम्यवादी विचार-दर्शन की क्षीणता

इस विचारोत्तेजक लेख में श्री बौल्ट का कथन है कि राष्ट्रीयता की शक्ति और पश्चिमी समाज की स्पष्ट सफलता के सामने साम्यवादी विचार का आकर्षण पुराना पड़ गया है। फॉरेन एफेयर्स, जुलाई, 1962।

साम्यवाद का अब भी दावा है कि उसकी शक्ति अनिवार्य ही सारे नए और पुराने राष्ट्रों पर छा जाने वाली है। लेकिन क्या इस तथ्याकथित नियति के अनुरूप उसकी शक्ति बढ़ रही है? या कि उसने ऐतिहासिक सत्य और आधुनिक यथार्थ से अपने को असम्बद्ध कर लिया है, और उसकी प्रासंगिकता व गति दोनों ही समाप्त हो रहे हैं।

पिछले दिनों चार महाद्वीपों की यात्रा करने पर मुझे विश्वास हो गया है कि एक विचार-दर्शन के रूप में साम्यवाद की शक्ति घट रही है। साम्यवादी सिद्धान्त और आज के कठोर आर्थिक व राजनीतिक यथार्थ के बीच बढ़ते हुए अन्तर्विरोधों को अब अधिक व्यापक रूप में समझा जा रहा है।

स्वयं सोवियत संघ में भी व्यावहारिक परिवर्तन अब रूढ़ सिद्धान्तों में सार्वजनिक रूप में स्वीकृत परिवर्तनों में परिलक्षित हो रहे हैं। सीधा सा तथ्य है कि साम्यवादी सिद्धान्त ने जैसा कहा था, दुनिया उसके मुताबिक चलने से इन्कार कर रही है।

मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अनुसार, साम्यवाद को एक अन्तर्राष्ट्रीय मसाल बनना चाहिए, जिनके चारों ओर सारी दुनिया के मजदूर वर्ग, राजनीतिक सीमाओं को तोड़ कर, एक निष्ठापूर्ण आन्दोलन में एकतावद्ध हो। अतः लेनिन को आशा थी कि सोवियत क्रांति के फलस्वरूप, पश्चिमी यूरोप के मुख्य देशों में एक के बाद एक, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला सर्वहारा वर्ग सत्ताह्व ह होगा। ऐसा न होने पर उन्हें बड़ी निराशा हुई।

जब स्टालिन ने विश्व क्रांति से ध्यान हटाकर 'एक देश में समाजवाद' पर लगाया, तो वे मुख्यतः एक रक्षात्मक चाल चल रहे थे, ताकि विश्व प्रभुत्व की दिशा में जो भी अगला कदम व्यावहारिक हो, उसकी तैयारी के लिए सोवियत संघ को पर्याप्त समय और साधन मिल सकें।

पाँच वर्ष पहले, हंगरी के पचीस हजार नौजवानों ने बुडोपेस्ट की सड़कों पर सोवियत टैंकों के विरुद्ध संघर्ष में अपनी जान देकर इसे प्रमाणित किया। पूर्वी जर्मनी के लगभग चालीस लाख लोगों ने, जिनमें से अधिकांश की आयु तीस वर्ष से कम है, पश्चिम में सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने घरों को छोड़कर इसका प्रमाण दिया है।

यद्यपि हमें कभी भी सोवियत संघ की भौतिक और सैन्य शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, किन्तु रूस की आर्थिक और राजनीतिक कार्यवाही यूरोप में असफल रही है, सुदूर पूर्व में असफल रही है, मध्य-पूर्व में असफल रही है, और अफ्रीका में असफल रही है। एकमात्र बयूबा के श्रमवाद को छोड़कर यह सातित्त अमरीका में भी असफल रही है।

मेरा कहना है कि शीत युद्ध में सोवियत रूस की जीत नहीं, हार होती रही है।

साम्यवादी विचार-दर्शन की क्षीणता

इस विचारोत्तेजक लेख में श्री यौल्ट का कथन है कि राष्ट्रीयता की शक्ति और पश्चिमी समाज की स्पष्ट सफलता के सामने साम्यवादी विचार का आकर्षण पुराना पड़ गया है। फॉरेन एफेयर्स, जुलाई, 1962।

साम्यवाद का अब भी दावा है कि उसकी शक्ति अनिवार्य ही सारे नए और पुराने राष्ट्रों पर छा जाने वाली है। लेकिन क्या इस तथाकथित नियति के अनुरूप उसकी शक्ति बढ़ रही है? या कि उसने ऐतिहासिक सत्य और आधुनिक यथार्थ से अपने को असम्बद्ध कर लिया है, और उसकी प्रासंगिकता व गति दोनों ही समाप्त हो रहे हैं।

पिछले दिनों चार महाद्वीपों की यात्रा करने पर मुझे विश्वास हो गया है कि एक विचार-दर्शन के रूप में साम्यवाद की शक्ति घट रही है। साम्यवादी सिद्धान्त और आज के कठोर आर्थिक व राजनीतिक यथार्थ के बीच बढ़ते हुए अन्तर्विरोधों को अब अधिक व्यापक रूप में समझा जा रहा है।

स्वयं सोवियत संघ में भी व्यावहारिक परिवर्तन अब रुढ़ सिद्धान्तों में सार्वजनिक रूप में स्वीकृत परिवर्तनों में परिलक्षित हो रहे हैं। सीधा सा तथ्य है कि साम्यवादी सिद्धान्त ने जैसा कहा था, दुनिया उसके मुताबिक चलने से इन्कार कर रही है।

मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अनुसार, साम्यवाद को एक अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चाल बनना चाहिए, जिनके चारों ओर सारी दुनिया के मजदूर वर्ग, राजनीतिक सीमाओं को तोड़ कर, एक निष्ठापूर्ण आन्दोलन में एकताबद्ध हों। अतः लेनिन को आशा थी कि सोवियत क्रांति के फलस्वरूप, पश्चिमी यूरोप के मुख्य देशों में एक के बाद एक, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला सर्वहारा वर्ग सत्ताहृद् होगा। ऐसा न होने पर उन्हें बड़ी निराशा हुई।

जब स्टालिन ने विश्व क्रांति से ध्यान हटाकर 'एक देश में समाजवाद' पर लगाया, तो वे मुख्यतः एक रक्षात्मक चाल चल रहे थे, ताकि विश्व प्रभुत्व की दिशा में जो भी अगला कदम व्यावहारिक हो, उसकी तैयारी के लिए सोवियत संघ को पर्याप्त समय और साधन मिल सकें।

समय आया दूसरे महायुद्ध के बाद, जब साम्य सेनाओं ने पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। साम्यवादी विचार सोवियत संघ में निभा कार्यक्रमों को बढ़ा कर, और औद्योगिक विकास के द्वारा किया गया था। सगभग तदनुसार ही, युद्ध-शीघ्र पश्चिमी यूरोप पर साम्यवादी दबाव का अनुभव किया जाने लगा। यहाँ फिर सोवियत योजनाएँ आगे नहीं बढ़ सकी, इस कारण ही मार्शल योजना की सहायता, और उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा रक्षण, यूरोपीय राष्ट्रों ने सेना से अपना आर्थिक पुनः निर्माण कर लिया।

तब स्टालिन एशिया और अफ्रीका की ओर मुड़े। 1948 में, चीन की ओर बहुत दिनों से विकसित हो रही चीनी साम्यवादी क्रांति के प्रतिरिक्त, छह देशों में साम्यवादी नेतृत्व में क्रांतिवादी आरम्भ की गई। हाल ही में स्वतंत्र हुए भारत, इण्डोनेशिया, ब्रह्मा, मलय और फिलीपीन में ये क्रांतिवादी प्रगमन हुईं। केवल हिन्द-चीन में ही, जहाँ फ्रांसिसियों ने एक असभ्य औपनिवेशिक स्थिति को स्थायमान रखने की चेष्टा की, साम्यवादियों को काफी बड़ी सफलता मिली।

तब से, एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ बहुगुणित हो गई हैं। इसके प्रमाण साम्यवादी प्रचार के अन्तर्विरोधों में, मास्को और बहुतेरे स्थानीय साम्यवादी दलों के बीच मतभेदों में, स्थानीय दलों में पड़ने वाली फूट में, और सन्तोषजनक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा में मास्को की नीतियों में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं।

इस साम्यवादी अभियान का एक विशिष्ट पहलू यह है कि उसके प्रचारक साम्यवाद के कथित सामाजिक या आर्थिक गुणों का सहारा लेने से हिचकते हैं। इसके बजाए, वे साम्यवाद को राष्ट्रवादी शक्तियों के एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

इसके फलस्वरूप काफी सैद्धान्तिक विभ्रम उत्पन्न होता है। एक तो पूर्वी यूरोप के पिछले देशों में सोवियत संघ की राष्ट्रीयता-विरोधी नीतियाँ अब सुविदित हो गई हैं। इसके प्रतिरिक्त, राष्ट्रवाद का मौखिक समर्थन करके सोवियत संघ एक ऐसी शक्ति का समर्थन कर रहा है, जिसका न केवल साम्यवादी सिद्धान्त से बल्कि संसद के अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों से कोई मेल नहीं है।

उदाहरण के लिए, आज दक्षिणी विएतनाम में, साम्यवादी प्रचार मार्क्सवादी शब्दावली में 'सर्वहारा' और 'मेहनतकश जनता' से विद्रोह की अपील करने के बजाए गोरे विदेशियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध चेतावनी देना अधिक प्रभावकारी पाता है।

अन्य देशों में, ऐसा लगता है कि साम्यवाद के गुणों की प्रशंसा करने वाला प्रचार निश्चित रूप से हानिकारक समझा जाता है, और इस कारण, परम्परागत सभी लक्ष्यों की अधिक प्रभावकारी रूप में आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं किया जाता।

उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में कोई साम्यवादी इस्तहार, प्रदर्शन या नारे कोई भी प्रत्यक्ष साम्यवादी प्रचार देखा या सुना नहीं जा सकता। मार्क्सवादी परम्परा

के अनुसार छात्रों, मजदूरों या किसानों को अफगान शाही परिवार के विरुद्ध भडकाने के बजाए, कम से कम फिलहाल, सोवियत नीति शासक और चासित दोनों को यह समझाने की प्रतीति होती है कि अफगानिस्तान को शीघ्रता से बीसवीं सदी में लाने का सर्वोत्तम उपाय पड़ोसी सोवियत संघ से आर्थिक सहायता और प्राविधिक मार्ग-दर्शन प्राप्त करना है—जिसके सैद्धान्तिक प्रभावों से मुक्त होने का दावा किया जाता है।

सोवियत नीति और साम्यवादी सिद्धान्त के बीच पूर्ण विरोध कई अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अल्जीरिया में, केवल रूस के राष्ट्रीय हितों के कारण, सोवियत संघ दिगाल सरकार को खुश रखने को इतना उत्सुक था, कि युद्ध-विराम के बाद तक अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता न देकर उसने एक सुनहरी सैद्धान्तिक अवसर खो दिया।

इसी प्रकार, मध्य-पूर्व के तेल-उत्पादक राज्यों में साम्यवादी आन्दोलन पर इसके विपरीत प्रभाव की ओर ध्यान दिए बिना, सोवियत संघ तेजी के साथ अपने तेल को, जहाँ भी बाजार मिले वहाँ बेच रहा है।

इस बीच, पैतालीस देशों में साम्यवादी दलों को सरकारी आदेश या कानून द्वारा दबा दिया गया है। इसमें अफ्रीका के बहुतेरे नये राष्ट्र नहीं आते, जिनमें साम्यवादी दलों का निर्माण ही नहीं हो सका है। इस समय केवल दो अफ्रीकी राज्यों में साम्यवादी दल कानूनी रीति से काम कर रहा है—द्यूनिसिया, जहाँ वह महत्वहीन है, और मडागास्कर, जहाँ साम्यवादी अपने को 'टीटोवादी' कहते हैं।

साम्यवादियों के बहुतेरे रूपों में से जहाँ किसी रूप को सहन भी किया जाता है, वहाँ उनका प्रभाव आम तौर पर सीमित रहा है। जहाँ वे अन्य दलों में शामिल हो गए हैं, वहाँ उन्होंने अपना व्यक्तित्व खो दिया है। जहाँ शामिल नहीं हुए, वहाँ उन्होंने बहुधा अपने को जेल में पाया है।

अपेक्षतया बर्गविहीन और अत्यधिक राष्ट्रवादी नए अफ्रीकी समाजों में साम्यवादी विचार-दर्शन के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, गिनी उनका एक उदाहरण है। एक दलीय गिनी राज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, साम्यवादियों को अपने हितों को शासन के गतिशील राष्ट्रवादी लक्ष्यों के अधीन रखना पड़ा। पिछले दिसम्बर मास में जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सोवियत राजदूत से कहा गया कि वे देश छोड़ दें।

हिन्दुस्तान में साम्यवादी दल पर कानूनी रोक नहीं है, लेकिन संगठन में फँसी हुई अव्यवस्था में वही द्विविधा परिलक्षित होती है, जो अन्य कई विकासशील राष्ट्रों में साम्यवादियों के सामने आती है। अपनी मतशक्ति को कायम रखने के लिए, साम्यवादियों को अपनी सैद्धान्तिक अपील को गौण स्थान देकर, गोघ्रा और काश्मीर जैसे राष्ट्रवादी लक्ष्यों के समर्थन पर जोर देना पड़ता है। दल के अन्दर भी मास्को-समर्थक और पीकिंग-समर्थक गुट तीव्र और विस्वसात्मक सैद्धान्तिक लड़ाई में लगे हुए हैं।

विकासशील राष्ट्रों में भाज थापद ही कोई ऐसा होगा, जिसमें साम्यवादी

प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप में सोवियत लक्ष्यों के एजेंट का कार्य कर रहा हो। जहाँ इसे दबा नहीं दिया गया है, या जहाँ उसे महत्वहीन मानकर इसकी उमेशा नहीं की गई है, वहाँ यह भटकाव और धारारत के उपेक्षणीय कार्य कर रहा है।

इंडोनीसिया एक महत्वपूर्ण भ्रमवाद है, जहाँ साम्यवादी दल सोवियत गुट के बाहर सबसे बड़ा है। किन्तु वहाँ भी साम्यवादी दल की शक्ति का एक बड़ा कारण यह है कि इंडोनीसियाई राजनीति में बने हुए एकमात्र औपनिवेशिक प्रश्न, परिवर्तन्युगिनी के सवाल पर उसने अपने भाषको राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ सम्बद्ध कर लिया है। अगर इस प्रश्न का हल शांतिपूर्वक किया जा सके, और आर्थिक विघ्न के लिए सघन प्रयास किया जाय, तो भासा की जा सकती है कि इंडोनीसिया में साम्यवाद की शक्ति घटेगी।

X

X

X

जब सोवियत सघ ने देखा कि नए विकासशील राष्ट्रों में साम्यवादो सिद्धान्त का आकर्षण कम होता जा रहा है, तो उसने राजीतिक प्रसार के दो अन्य हथियारों का अधिकाधिक प्रयोग करना आरम्भ किया है—विश्वसक कार्यवाहियों, और विदेशी सहायता।

दक्षिणी विण्टनाम और लाओस में भौगोलिक स्थिति साम्यवादी घुसपैठ और विश्वसक कार्यवाही के लिए सर्वथा अनुकूल थी। लेकिन ऐसी स्थितियों में, जहाँ प्रत्यक्ष साम्यवादी दबाव उस तरह संभव नहीं था, मास्को और पीकिंग दोनों के हो विश्वसक प्रयत्नों ने घाम तौर पर जनता में अरुचि या विरोध उत्पन्न किया है, और कई मामलों में इसके फलस्वरूप प्रभावकारी रीति से सरकारी प्रतिकारात्मक कार्यवाही हुई।

पिछले दिनों लातिन अमरीका की यात्राओं में मैंने विशेष रूप से यह बात देखी। बड़ी रकम खर्च करने, और जासूसी, प्रचार, तथा आन्दोलन करने के बड़े प्रयत्नों के बावजूद, या शायद इसके कारण ही, कास्ट्रो (क्यूबा) के साथ अब तक चौदह लातिन अमरीकी राष्ट्र कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके हैं। कम से कम आंशिक रूप में क्यूबा के बाहर अपनी राजनीतिक गलतियों का प्रतिकार करने के प्रयत्न में उन्होंने पिछले दिनों स्वयं अपने देश में अधिक मताग्रहपूर्ण साम्यवादी तत्वों का परित्याग किया है।

अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के दूसरे साधन के रूप में, साम्यवादी सरकारों ने विदेशी सहायता के कार्यक्रम अधिकाधिक अपनाए हैं। 1955 से 1961 तक रूस-चीन गुट ने, लोह आवरण के बाहर अट्टाइस राष्ट्रों को लगभग चार अरब चालीस करोड़ डालर अधिक अनुदान या कर्ज के रूप में, अधिकांश कर्ज के रूप में, दिए हैं। इसका लगभग तीन-चौथाई सोवियत संघ ने दिया। 1961 के अन्त में, साम्यवादी गुट के लगभग 8,500 वैज्ञानिक विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे।

कई मामलों में यह सहायता ऐसे राष्ट्रों को दी गई है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में

साम्यवाद-विरोधी नीतियाँ अपनाई हैं। अमरीकी और यूरोपीय विदेशी सहायता कार्यक्रमों की काट करने में इस प्रयास का राजनीतिक महत्त्व चाहे जो भी हो, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की धारणाओं से इसका कोई सैद्धान्तिक सम्बन्ध नहीं।

शास्त्र नियंत्रण के निर्णायक प्रश्न पर भी, साम्यवादी सिद्धान्त का रूसी राष्ट्रवाद के स्वीकृत हितों के साथ टकराव हुआ है।

माक्स के अनुसार, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं को युद्ध या युद्ध का खतरा जीवित रखता है। अगर सोवियत नेतृत्व सचमुच अपने इस सिद्धान्त में विश्वास करता, तो वह हथियारों के बोझ को कम करने के लिए एक सशक्त और यथार्थपरक कार्यक्रम चलाता, और उसे यह विश्वास रहता कि अगर अमरीका अपने प्रतिरक्षा बजट में कमी करना स्वीकार कर लेगा तो वहाँ बेकारी कावू से बाहर हो जाएगी, और अगर अस्वीकार करेगा तो सारा विश्व एकमत से उससे रुष्ट हो जाएगा। किन्तु गोपनीयता की परम्परागत रूसी राष्ट्रवादी भावना के कारण, मास्को निरीक्षण के सिद्धान्त के किसी व्यावहारिक रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके द्वारा, कार्ल माक्स के भावजूद, शास्त्र नियंत्रण को वास्तविक बनाया जा सकता है।

मैंने जो उदाहरण दिए हैं, उनसे पता चलता है कि साम्यवादी प्रचार हो या राजनीतिक कार्यवाही, विध्वंसात्मक कार्यवाही हो या विदेशी सहायता, साम्यवादी सिद्धान्त या तो सोवियत विदेश नीति के लिए व्यर्थ रहा है, या उसके कार्य में बाधक। इनसे यह भी देखा जा सकता है कि सोवियत रूस ने जहाँ अपने अनुभव से, व्यावहारिक यथार्थ को देखते हुए, इस या उस चाल या पैतरे को बाँझनीय या आवश्यक पाया है, वहाँ इसके फलस्वरूप, सोवियत सिद्धान्त विकृत या विभ्रमपूर्ण हो गए हैं, या कई मामलों में उनकी पूर्ण उपेक्षा की गई है।

साम्यवादी सिद्धान्त अपने अनुयायी राष्ट्रों को एक सूत्र में बाँधे रखने में भी विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुए। वस्तुतः, ऐसा कहा जा सकता है कि साम्यवादी सिद्धान्त का बड़ा महत्त्व इस समय साम्यवादी गुट के अन्दर चल रहे विवादों में ही है—सबसे अधिक, निस्सन्देह, मास्को और पीकिंग के सैद्धान्तिक विवादों में। ये विवाद, एक अकेली राजनीतिक और आर्थिक रूढ़ि के समूचे मार्क्सवादी विचार को क्षति पहुँचाते हैं, और मास्को द्वारा सोवियत संघ के विशिष्ट अनुभव और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उसकी व्याख्या करने के प्रयत्नों को असफल बनाते हैं।

स्वयं राष्ट्रवाद, वर्गों पर आधारित विश्व की मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारणाओं के विरुद्ध है, क्योंकि इसके अनुसार अर्थ-व्यवस्था और इतिहास के तथाकथित अनिवार्य प्रवाह परिवर्तन का आधार नहीं रह जाते, बरन् परिवर्तन किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, या व्यक्तियों के समूह की व्याख्याओं और आवश्यकताओं पर आधारित हो जाता है। लेकिन मास्को, पीकिंग, बेलग्राड, तिराना, और पूर्वी यूरोप की पिछलग्गू राजधानियों की असहमति में राष्ट्रवाद का तत्व प्रमुख रूप में विद्यमान है।

इतना कुछ दाँव पर लगा होने के बावजूद, साम्यवादी राष्ट्र-एक संयुक्त मोर्चा

बनाकर कायम नहीं रख सकते, यह तथ्य न केवल 'साम्यवादी संघ' के रूप में उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करता है, वरन् इस संघ की तथ्यान्वित अविचल एकता के फलस्वरूप दुनिया में मार्क्सवादी विचारों की जो शक्ति मानी जाती है, उसे भी प्रभावित करता है।

मेरा विचार है कि आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, साम्यवादी सिद्धान्त का ह्रास हो रहा है, और स्वयं साम्यवादियों के लिए, एक राजनीतिक अज्ञान के रूप में, सभी आर्थिक रोगों के इलाज के रूप में, और एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में इसका मूल्य घटता जा रहा है।

यद्यपि आगे चलकर इससे हमें लाभ हो सकता है, लेकिन मैं अधिक से अधिक जोर देकर कहना चाहूँगा कि अमरीकी लोगों और उनके नीति-निर्माताओं के समक्ष सोवियत संघ जो तात्कालिक चुनौती प्रस्तुत करता है, वह इससे किसी प्रकार कम नहीं होती।

स्वयं अपने मताग्रहों से अधिकाधिक मुक्त होने पर, सोवियत नेताओं की प्रेरणा हो सकती है कि अपनी विशाल शक्तियों का प्रयोग अधिक रचनात्मक रीति से करें। अथवा, इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि स्वयं सोवियत संघ के अन्दर आस्था का एक संकट उत्पन्न हो जाय, 'श्रद्धालुओं' और 'अपार्थवादियों', में टकराव हो। इससे साम्यवादी जगत में ऐसी निराशाएँ और विरोध-भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके परिणाम विश्व-शांति के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि साम्यवादी देशों में मताग्रहों कट्टरता के कम होने का, और उसके स्थान पर राष्ट्रवादी लक्ष्यों के आने का यह परिणाम नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत किसी समय इसके फलस्वरूप हमारे साथ और हमारे मित्रों के साथ सफल वार्ता और शांतिपूर्ण समझौते के लिए नए आधार उपलब्ध होंगे।

यह प्रश्न रह जाता है कि स्वयं अमरीका की स्थिति क्या है? अगर यह सच भी है कि एक विश्व सिद्धान्त के रूप में, साम्यवाद का महत्व बहुत-कुछ समाप्त हो रहा है, तो भी हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका महत्व बहुत अधिक नहीं होगा, अगर उस लोकतांत्रिक आस्था को हम भविष्य के लिए अर्थमय नहीं बना पाते, जिस पर आचरण करना हमारा लक्ष्य है।

अगर ऐसा होता है, तो अमरीकी लोगों को एक ऐसी भूमिका अपनानी होगी, जो मनुष्य-जाति के लम्बे इतिहास में अभी तक किसी समृद्ध और सशक्त राष्ट्र ने नहीं अपनायी। अमरीका को उस सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक क्रान्ति से अपने-आप को जोड़ना होगा, जो दुनिया के सभी हिस्सों में अब करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी को बदलने लगी है।

हम ऐसी भूमिका भ्रदा कर सकें, इसके मार्ग में बाधाएँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन हमारे लिए और मनुष्य जाति के लिए उसमें निहित संभावनाएँ लगभग असीमित हैं।

साम्यवादी जगत को हम से अलग करने वाली तीन सीमाएँ

सैन्य सीमाओं को सुरक्षित रखने की अपनी शक्ति को कायम रखते हुए, श्री वील्स आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं में 'अधिकतम कठोरता' के स्थान पर 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति का समर्थन करते हैं। 21 जून, 1962, को नेवास्का विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण।

आज अमरीका में क्या विदेश-नीति सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय सहमति है ? मेरा विश्वास है कि विदेश-नीति के तीन महत्वपूर्ण पक्षों के सम्बन्ध में ऐसी सहमति मौजूद है :

1. सदातक सैन्य बल की आवश्यकता, और आक्रमण का विरोध करने के लिए आवश्यक होने पर उसका प्रयोग करने का संकल्प।

2. यह तथ्य कि अणु-प्रक्षो ने सैन्य स्थिति को एक नया रूप प्रदान किया है, और यह कि युद्ध होने पर वह सीधे ही एक-दूसरे के सम्पूर्ण विनाश का काम बन जा सकता है।

3. उन राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का महत्त्व जिन्होंने बीस वर्षों में भी कम समय में दुनिया के नकशों को इतनी नाटकीय रीति से बदल दिया है, और एशिया अफ्रीका के करोड़ों निवासियों की जिन्दगियाँ बदल दी हैं।

हमारे अन्दर जो मतभेद छेपे रह जाते हैं, वे पडति और प्राथमिकता सम्बन्धी हैं, विशिष्ट रूप में, सटस्थ राष्ट्रों और साम्यवादी राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्धों के प्रयोग में। इन मतभेदों पर तुल्यतर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम अन्तर को मिटा सकें, और राष्ट्रीय सहमति का एक ढाँचा बना सकें, जिसके अन्तर्गत हमारा शासन विश्वास कर सके।

इन प्रश्नों के प्रति अधिराज अमरीकियों के दृष्टिकोण दो समूहों में रखे जा सकते हैं। दोनों ही एक शांतिपूर्ण, अधिक व्यवस्थित विश्व में विश्वास करते हैं, दोनों ही जानते हैं कि कोई सरल उपाय उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमरीकी विदेश-नीति के अर्धनिक पहलुओं के बारे में उनके दृष्टिकोणों में बड़ी भिन्नता है।

उन प्रसंग में ऐसा कहा जा सकता है कि एक समूह 'अधिकतम कठोरता' की नीति का समर्थक है, और दूसरा 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति का।

'अधिकतम कठोरता' का समर्थन करने वाले, सार रूप में, इस पुराने सूत्र को मानते हैं कि जो हमारे साथ नहीं, वह हमारे विरुद्ध है। उनका विश्वास है कि संघर्ष की रेखाएँ हर जगह बहुत साफ़ सीधी जानी चाहिए। उनका मत है कि जो लोग दुनिया की हमारी व्याख्या से सहमत नहीं हैं, उनके साथ सहयोग करने का कोई आधार नहीं है, और अन्ततः दुनिया पर या तो साम्यवादी पक्ष का प्रभुत्व होगा, या लोकतांत्रिक पक्ष का।

विदेश-नीति के विशिष्ट प्रश्नों पर 'अधिकतम कठोरता' के दृष्टिकोण को लागू करने के उदाहरण पिछले दिनों अमरीकी सीनेट की कार्यवाहियों में देसे जा सकते हैं, जब उसने पहले हिन्दुस्तान को दी जाने वाली सहायता घटाने के पक्ष में और फिर पोलैण्ड व यूगोस्लाविया को दी जाने वाली अमरीकी सहायता को समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया। यद्यपि बाद में बातचीत के फलस्वरूप विधेयक से ये व्यवस्थाएँ निकाल दी गईं, किन्तु सीनेट की कार्यवाही से पता चलता है कि यह विचारधारा कितनी व्यापक है।

इसके विरुद्ध 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि साम्यवादी जगत में शक्तियों का सन्तुलन निरन्तर बदल रहा है, और यह परिवर्तन हर देश के अन्दर और एक-दूसरे के साथ उनके सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए अधिकाधिक दबाव उत्पन्न करता है। उनका विश्वास है कि इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना हमारे नीतियों का लक्ष्य होना चाहिए।

कठोर सैन्य आवश्यकताओं को समझते हुए भी, 'शक्ति' की उनकी परिभाषा में सैनिक हथियार और औद्योगिक क्षमता के अलावा, लोग और उनको प्रभावित करने वाले विचार भी शामिल हैं। इस प्रकार, वे न्याय, प्रतिष्ठा, और प्रगति की आकांक्षाओं को विशेष महत्त्व देते हैं, जो विकासशील राष्ट्रों के विचारों और नीतियों को निर्धारित करती हैं।

इस पृष्ठभूमि में हम कठोरता और लचीलेपन के इन दो दृष्टिकोणों की जाँच करें कि साम्यवादी हितों और हमारे हितों के बीच जो तीन सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाएँ हैं, उन्हें ये दृष्टिकोण किस तरह प्रभावित करते हैं।

यद्यपि इन तीन सीमाओं के स्वरूप और महत्त्व में बड़ा अंतर है, किन्तु 'अधिकतम कठोरता' के समर्थक अधिकांश इन अन्तरो की उपेक्षा करते हैं। उनके विचार से हर सीमा एक ऐसी रेखा है जिसे हमको न केवल टैको के विरुद्ध बल्कि व्यापार, सहायता, लोगो और विचारों के विरुद्ध भी कठोरता से कायम रखना है।

इसके विपरीत, 'अधिकतम लचीलेपन' के समर्थकों का विश्वास है कि अणु युग में इन तीन सीमाओं के अन्तरो का एक प्रभावकारी विदेश-नीति में निर्णायक महत्त्व है। ये अन्तर क्या हैं?

सैन्य सीमा बाल्टिक से लेकर लौह आवरण के साथ-साथ बास्फोरस तक जाती है, जहाँ सोवियत संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि की सेनाएँ, टैक और वायुयान,

कंठीले तारों, सन्तरी-चीकियों और सुरंग लगे हुए इलाकों की पंक्ति के आर-पार एक दूसरे के धामने-सामने पड़े हैं।

मध्य-क्षेत्रीय संधि, दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि और अन्य विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सैन्य संधियों से होती हुई यह सीमा न्यूनाधिक प्रभावकारिता के साथ दक्षिण चीन सागर तक फैली है।। सेनाओं और संधियों के इस संगठन के पीछे दोनों विरोधी शक्ति-गुटों की भयंकर आण्विक क्षमता है।

इस सैन्य सीमा के सम्बन्ध में, हमारी विदेश-नीति की राष्ट्रीय सहमति स्पष्टता प्रतिष्ठित है। 'अधिकतम कठोरता' व 'अधिकतम लचीलेपन' दोनों ही धाराएँ इस बात पर सहमत हैं कि सशस्त्र आक्रमण या आक्रमण की धमकी के सामने दुबलता दिखाने से आक्रमण और बढ़ता है, और इस कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन यहाँ आकर सहमति अचानक समाप्त हो जाती है। कठोर दृष्टिकोण के समर्थक आर्थिक सीमा के सम्बन्ध में भी सैन्य सीमा जैसी अपरिवर्तनीयता अपनाना चाहेंगे। वे न केवल सेनाओं के लिए, वरन् व्यापार, वैज्ञानिकों, और पूँजी के लिए भी दीवार खड़ी करना चाहेंगे।

अधिक लचीलेपन के समर्थक इससे सहमत नहीं हैं। वे आर्थिक सीमा को साहस, कौशल और स्फूर्ति के लिए एक अवसर मानते हैं।

युगोस्लाविया को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर दोनों धाराओं के मतभेद से उनके दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाते हैं। कठोर दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि इस सहायता ने केवल एक संभाव्य शत्रु को शक्ति प्रदान की है। अधिकतम लचीलेपन की नीति के समर्थक समझते हैं कि यह सहायता बुद्धिमत्तापूर्ण और फलदायक रही है।

हम 1948 के आरम्भ में जो स्थिति थी, उस पर संक्षेप में विचार करें, जब सर्व-प्रथम युगोस्लाविया के प्रश्न पर चर्चा शुरू हुई।

उस समय यूनान में गृह-युद्ध पूरी रफतार से चल रहा था, और सोवियत-निर्देशित साम्यवादी छापामार दक्षिणी युगोस्लाविया के ग्रहों से यूनानी लोकतंत्र को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे।

इटली में एक कटुतापूर्ण चुनाव अभियान अपने चरम-बिन्दु पर पहुँच रहा था। श्यापक शरीबी, युद्ध की पकान, और राजनीतिक निराशा के फलस्वरूप, बहुतेरे प्रेक्षकों को भय था कि स्वतंत्र चुनावों के इतिहास में साम्यवादियों को शायद अपनी पहली सच्ची सफलता प्राप्त हो। दुनिया के दूसरे कोने में, चीन के गृह-युद्ध में, लगता था कि साम्यवादियों को शीघ्र ही शानदार सफलता मिलेगी।

इस प्रकार, फ्रांस की सीमाओं से लेकर जापान सागर तक फैले हुए एकात्मक साम्यवादी साम्राज्य की संभावना हमारे सामने थी। ऐसा होने पर यूरोप के युद्ध-विनष्ट राष्ट्रों पर, और एशिया के हाल ही में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों पर उसका कल्पना-शील प्रभाव पड़ता।

इस महत्वपूर्ण वर्ष के फरवरी और मार्च महीनों में स्टालिन के साथ टीटो की बहुत दिनों से चली आ रही असहमतियाँ पहली बार व्यक्त हुईं। जून में युगोस्लाविया ने साहसपूर्वक सोवियत नियंत्रण से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और सहायता के लिए हमसे अपील की।

इससे राष्ट्रपति ट्रुमन, और आर्थर वान्डेनबर्ग के नेतृत्व में रिपब्लिकन दल के बहुमत वाली कांग्रेस के सामने ऐतिहासिक महत्त्व की एक द्विविधा आई। युद्ध-काल में युगोस्लाव लोगो ने दृढ़ता के साथ लगभग तीस नाज़ी डिवीजन फँसा रखे थे। किन्तु उसके बाद युगोस्लाविया साम्यवादी गुट के अति पश्चिम-विरोधी सदस्यों में से एक रहा था, और अमरीकी जनमत उसके प्रति अधिकाधिक कटु हो गया था।

लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना के नए प्रयास में टीटो का समर्थन न करते, तो युगोस्लाविया को मजबूरन स्टालिनी गुट में वापस जाना पड़ता, और साम्यवादी साम्राज्य में पड़ी पहली दरार पट जाती।

बड़े विचार-विमर्श के बाद, एक द्विपक्षीय समझौता हो गया कि युगोस्लाव स्वतंत्रता का सक्रिय समर्थन करने में अमरीका का सर्वाधिक हित है। शीघ्र ही काफी मात्रा में सैन्य और आर्थिक सामग्री रवाना कर दी गई। 1952 में अपने चुनावों के बाद, राष्ट्रपति ब्राइडन हूवर ने इस नीति को जारी रखने का इरादा व्यक्त किया। आठ वर्ष बाद राष्ट्रपति केनेडी ने भी ऐसा ही किया।

इस सहायता कार्यक्रम के तात्कालिक परिणाम नाटकीय रूप से अनुकूल सिद्ध हुए। अप्रैल, 1948 में, युगोस्लाविया के अलग होने की अफवाहों से प्रोत्साहित होकर, इटली में लोकतांत्रिक शक्तियों ने चुनावों में निर्णायक विजय प्राप्त की। एक वर्ष बाद, युगोस्लाविया में उनके पुराने अड्डे के सतम हो जाने पर, यूनाइटेड साम्यवादी छापामारो पर काबू पा लिया गया।

तब से, स्वयं युगोस्लाविया के अन्दर काफी बड़े परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए, एनी क्रिस्म के सामूहिक सेनों का ग्राम तौर पर परिचालन कर दिया गया है। दम किसानों में से नौ, अब खुद अपने सेनों के मालिक हैं। औद्योगिक विकास-मंथनी साम्यवादी मनाग्रह को बड़ा हद तक सशोभित किया गया है। अब युगोस्लाविया के वैदेशिक व्यापार का सत्तर प्रतिशत अ-साम्यवादी देशों के साथ है। इसके फलस्वरूप विदेशों में कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कहा कि, "देखल युगोस्लाव और अमरीकी लोग ही अब भी ऐसा समझते हैं कि युगोस्लाविया एक साम्यवादी राज्य है।"

समुक्त राष्ट्र मंच में युगोस्लाविया अब भी बहु-मंथक धवसरो पर सोवियत मंच के साथ मतदान करता है। उसके नेता बहुधा ऐसे दृष्टिकोण धरनाते हैं, जिनमें अधिवांस अमरीकी सर्वपा असहमत होने हैं।

फिर भी, युगोस्लाविया को सोवियत शक्त का निश्चलानू नहीं कहा जा सकता। तथाकथित त्रिमूर्ति योजना के विरुद्ध एक ही प्रधान मंत्री रहने के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर, बाकी के समुक्त राष्ट्रों की योजनाओं के लिए विश्व-व्यवस्था करने के प्रश्न

पर, और पिछले अक्टूबर में रूस द्वारा पचास मेगाटन के डाइड्रोजन बम के त्रिफोट के प्रश्न पर, युगोस्लाव प्रतिनिधियों ने अमरीका का समर्थन और रूस का विरोध किया। युगोस्लाविया ने साम्यवादी चीन का निरन्तर कटु विरोध किया।

युगोस्लाविया की स्वाधीनता का स्वयं साम्यवादी गुट के अन्दर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, बहुतेरे प्रेसकों का विश्वास है कि भूमि के समूहीकरण जैसी बहुतेरे मताग्रही साम्यवादी पद्धतियों का परित्याग करने में पोलैण्ड की युगोस्लाविया से प्रेरणा मिली।

सोवियत रूस और पूर्वी जर्मनी में स्थित लाल सेना दस्तों के बीच फँसा हुआ पोलैण्ड विदेश-नीति के मामलों में बराबर मास्को का समर्थन करता है। फिर भी, सैन्य सीमा के पार, थोड़ी ही मात्रा में अमरीकी आर्थिक सहायता ने पोलैण्ड के लोगों में एक नयी, विश्वास और स्वतंत्रता की, भावना उत्पन्न करने में सहायता पहुँचाई है। अब पोलैण्ड के वैदेशिक व्यापार का चालीस प्रतिशत अ-साम्यवादी देशों के साथ है।

आरम्भ से ही, युगोस्लाविया में हमारे सहायता प्रयास का लक्ष्य यह रहा है कि अपने मूल निर्णय करने में वहाँ का शासन स्वतंत्र हो, और अन्य साम्यवादी राष्ट्रों में भी स्वतंत्रता की ऐसी ही भावना की प्रोत्साहन मिले। मुझे लगता है कि आम तौर पर, हम इस लक्ष्य में सफल रहे हैं।

अब हम आर्थिक सीमा के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से पर विचार करें, जिसके सम्बन्ध में दोनों विचारधाराओं में अब भी बहस चल रही है—अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के नवोदित राष्ट्र।

यहाँ 'अधिकतम कठोरता' के समर्थक उन्हीं लोगों की सहायता करना चाहेंगे, जिनकी सरकारें अमरीकी नीतियों का समर्थन करें। 'अधिकतम लचीलेपन' के समर्थकों का विश्वास है कि 'इधर या उधर' का यह दृष्टिकोण नए विकासशील राष्ट्रों को मजबूर करेगा कि वे या तो मास्को अथवा वॉशिंगटन की अधीनता स्वीकार करें, या फिर अव्यवस्था और बढ़ते हुए कष्टों में पड़े रहें।

विकासशील महाद्वीपों में हमारे सामने क्या स्थिति है, इस पर विचार करने से शायद यह समस्या अधिक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में सामने आए।

एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के उभरते हुए राष्ट्र निरक्षरता, रोग, गरीबी, और अन्याय की भयंकर समस्याओं से लड़ रहे हैं। जब तक इन राष्ट्रों के लोगों को विश्वास नहीं हो जाता कि इन बुराइयों को दूर करने की दिशा में उचित प्रयत्न हो रही है, तब तक व्यवस्थित राजनीतिक विकास असंभव होगा।

इन नये राष्ट्रों की सहायता करने के अमरीकी प्रयत्नों में एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका के बहुतेरे नेताओं के भगड़ालू राजनीतिक दृष्टिकोणों से दिक्कत पैदा होती है, जिन्हें पश्चिम के आर्थिक सुविधा प्राप्त या-कुछ मामलों में जातीय भावना से अस्त पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उनके पुराने अनुभवों के कटु बना दिमा है।

जब ये भ्रष्टो-एशियाई प्रवृत्ता गंगुवा राष्ट्र संघ में घोर भ्रष्टान भ्रमरीकी नीतियों की आलोचना करते हैं, तो सपादकीय लेखक उन्हें 'भ्रष्टान घोर साम्यवादी प्रचार के शिकार' कहते हैं, घोर कांप्रेस के सदस्य गांग करते हैं कि ऐसे 'भ्रष्टानयोगी' राष्ट्रों के साथ हमारे सहायता कार्यक्रम समाप्त कर दिखे जाएं ।

यद्यपि ऐसी प्रतिक्रियाओं को हमारी अपनी परेशानियों घोर निराशा के मन्त्र में समझा जा सकता है, किन्तु इससे हमारी दुनिया की उनही हुई भ्रष्टानियों सतम नहीं हो जाती ।

भ्रष्टान, एशिया घोर लातिन भ्रमरीका के साधनों घोर बाजारों पर नियंत्रण करना, जिन पर पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्र बहुत अधिक निर्भर हैं, साम्यवाद के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है । भ्रमरीकी विदेश-नीति का एक प्राथमिक उद्देश्य इन प्रयत्नों को विकल करना, घोर विकासशील राष्ट्रों की सहायता करना है, जिससे वे अपनी स्वतंत्रता पूर्णतः स्थापित कर सकें, घोर अधिकधिक राजनीतिक स्वामित्व घोर आर्थिक प्रगति प्राप्त करें ।

नए राष्ट्रों को समझना हमारे लिए पाहे जितना भी कठिन प्रतीत हो, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, बेल्जियन, घोर डच शासन के बदले में, जिससे उनमें से कई राष्ट्रों ने हाल ही में मुक्ति पाई है, वे रूस की अधिक क्रूर प्रभुता को स्वीकार कर लें । इसके प्रतिरिक्त, उनकी अपनी संस्कृतियाँ घोर इतिहास एक गहरी जमी हुई विविधता को प्रोत्साहित करते हैं, जो विदेशी दबावों घोर सिद्धान्तों को आमानी से स्वीकार नहीं करती ।

मास्को के रणनीतिक कठोर अनुभवों से यह सीख रहे हैं कि दुनिया में सोवियत प्रभुत्व के लेनिनवादी लक्ष्य के मार्ग में, स्पानीय-विरोधी शक्तियाँ बहुत बड़ी बाधाएँ हैं । 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति के समर्थकों का विश्वास है कि एक लचीला, सु-प्रशासित, सवेदनाशील आर्थिक सहायता कार्यक्रम इन पहले से विद्यमान बाधाओं को घोर सबल बना सकता है । किन्तु वे इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रयास के उद्देश्यों घोर सीमाओं के बारे में हमारे दिमाग में सफाई रहनी चाहिए ।

हमारा लक्ष्य विकासशील राष्ट्रों की बोलियों घोर नीतियों पर नियंत्रण करना, दुनिया में रूस से अधिक लोकप्रिय होना, या सयुक्त राष्ट्र संघ में वोट खरीदना नहीं है ।

भ्रमरीकी डालरों से खरीदे गए शासनों पर हमारे पक्ष में बने रहने का भरोसा उसी तरह नहीं किया जा सकता, जैसे इस तरह खरीदे गए व्यक्तियों पर । हमारे जैसे घनी राष्ट्र इसकी भी आशा नहीं कर सकते कि हमसे अधिक कम भाग्यशाली लोग हमसे प्यार करेंगे । हम अधिक से अधिक उनके आदर को अपेक्षा कर सकते हैं ।

अतः, हमारे वास्तविक लक्ष्य दो होने चाहिए—प्रथम, जो विकासशील राष्ट्र स्वयं अपनी सहायता करने को उत्सुक हैं, उनमें आर्थिक प्रगति को बढ़ाने घोर फैलाने से सहायता करना । घोर दूसरे, इस काम को ऐसी रीति से करना कि उन राष्ट्रों के

लोगों को अधिक व्यापक रूप में सक्रिय भाग लेने का अवसर मिले, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता में हर परिवार का निजी हित बढ़े।

इन दो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, हम कठोरता और लचीलेपन के दो विरोधी दृष्टिकोणों पर भारतीय गणराज्य के प्रसंग में विचार करें, जो नए स्वतंत्र राष्ट्रों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

एक दशक से अधिक समय से, हम दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्रों, चीन और हिन्दुस्तान में एक नाटकीय और संभावनापूर्ण घटनाक्रम देख रहे हैं। इनमें से एक तानाशाही की पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है, और दूसरे ने लोकतन्त्र को स्वीकार किया है।

पिछले एक-दो वर्षों में नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। जबकि हिन्दुस्तान यह प्रमाणित करता रहा है कि एक सक्षम लोकतांत्रिक शासन अधिकाधिक मात्रा में रोटी, आजादी और अवसर प्रदान कर सकता है, साम्यवादी चीन में आंतरिक कठिनाइयों की बाढ़ आ गई है।

फिर भी, आज जब कि इस स्थिति से आगे निकलने वाले नतीजों को समझा जा रहा है, 'अधिकतम कठोरता' की नीति के अमरीकी समर्थक कहते हैं कि भारत को हमारी निर्णायक महत्त्व की सहायता बड़ी हद तक कम कर दी जाय।

अधिकांश अमरीकी लोग भारत सरकार के जिन कार्यों को श्रद्धा समझते हैं, उनसे या दूसरों द्वारा की गई किसी भी आलोचना पर नाराज हो जाने की भारतीय प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली चिड़ के प्रसंग में इस प्रस्ताव को समझा जा सकता है। लेकिन जो लोग हमारे युग का इतिहास लिखेंगे, उन्हें यह बात सर्वथा तर्कहीन लगेगी।

इस प्रकार, साम्यवादी जगत और हमारी अपनी दुनिया के बीच आर्थिक सीमा उलझी हुई है। 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति के अनुसार इस सीमा को खुला रख कर, हम बराबर प्रगति करते रहे हैं।

पूर्व और पश्चिम के बीच तीसरी सीमा, सांस्कृतिक सीमा के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

'अधिकतम कठोरता' की विचारधारा का तर्क है कि रेडियो प्रचार को छोड़कर, आर्थिक सीमा की भाँति सांस्कृतिक सीमा को भी सैन्य सीमा जैसी कठोरता से बन्द रखना चाहिए। 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति यहाँ भी लचीलेपन और स्वतः स्फूर्ति के पक्ष में है। कौन-सा रास्ता अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है ?

1955 में जेनेवा सम्मेलन के बाद सोवियत जगत और पश्चिमी जगत को बाँटने वाली सैन्य सीमा के आर-पार विद्वानों, छात्रों, कलाकारों, संगीतज्ञों, किसानों और वैज्ञानिकों का प्रवाह निरन्तर स्थिर गति से चलता रहा है

'अधिकतम कठोरता' के सिद्धान्त को मानने वालों को यह दुतरफी सांस्कृतिक

विनियम खतरनाक ही नहीं, घर्नातिक भी प्रतीत होगा है। दूसरी ओर, सचीनेशन पर आधारित कार्यक्रम के समर्थकों का कहना है कि यह जन-स्तर पर समझ को बढ़ाने में, और दोनों संघों के नागरिकों को एक-दूसरे के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी प्रदान करने में सहायक हो रहा है।

उनका कहना है कि अगर कभी पूर्व और पश्चिम को भ्रमण करने वाले संघर्ष कम हुए, तो यह उभय समझ का ही फल होगा जिसे संन्य सीमा के दोनों ओर धीरे-धीरे और कष्टप्रद रीति से विकसित किया जा रहा है।

किसी हद तक हम सब रुद्धियों के फंदी हैं। हम एक-दूसरे को विद्वृत और प्रति सरन बिम्बों के सन्दर्भ में देखते हैं। विचारों, कलाओं, और विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा अध्ये सम्पक से इन झूठे चित्रों को सुधारने में सहायता मिल सकती है। और ज्यादा साफ देख पाने पर हम अधिक बुद्धिमत्ता से काम कर सकते हैं।

मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट है कि इन दो विकल्पों में से हमें जिसको चुनना चाहिए। हमें, एक स्वतंत्र राष्ट्र को, विचारों से क्यों भय हो? क्या विचारों से साम्यवादियों को भय नहीं होना चाहिए?

X

X

X

भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं?

यद्यपि आण्विक गतिरोध खतरनाक है, किन्तु संन्य सीमा पर हमारी स्थिति सबल है। रुद्धियों द्वारा घोषित तारीखें धाई और गई, लेकिन स्वतन्त्र मनुष्यों के द्वारा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए हृदय निश्चय के एक ज्वलन्त उदाहरण के रूप में, संन्य सीमा पर हमारी जोकी, पश्चिमी बलिन्, आज भी मौजूद है।

विद्युत् दो वर्षों में, हमारी संन्य शक्ति आम तौर पर अधिक सन्तुलित, अधिक गतिशील, और इस कारण संन्य सीमा की रक्षा करने में अधिक समर्थ हुई है। इस बीच, हमें यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि सोवियत नेता अन्ततः इस बात को समझे कि समूचे इतिहास के दो महानतम भौद्योगिक राष्ट्रों का एक-दूसरे को नष्ट करने की अधिकाधिक क्षमता प्राप्त करने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रतियोगिता मूर्खतापूर्ण है।

आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं पर, निरन्तर प्रगति और परिवर्तन की संभावनाएँ अधिक आशाप्रद प्रतीत होती हैं।

अ-साम्यवादी जगत पहले किसी भी समय से अधिक तेजी से होने वाले आर्थिक विकास के दरवाजे पर खड़ा है। स्वतन्त्र मनुष्यों के अधिक समृद्ध, परस्पर अधिक सम्बद्ध समाज का निर्माण होने पर, सोवियत रुम भी बाध्य हो सकता है कि स्वयं अपनी व्यवस्था की निष्फल कठोरताओं को और अधिक सरोधित करे।

इस बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं के धार-पार व्यापार, पूँजी, कारी-गरी, शांति सेना के स्वयंसेवकों, गेहूँ, कपास, वायु-बन्दी, और विचारों के बढ़ते हुए प्रवाह से दिमाग खुलेंगे, मताग्रह कमजोर पड़ेंगे, और विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा।

हम अमरीकी लोग प्रयोग करने की अपनी तत्परता नई स्थितियों के प्रति अपने अनुकूलन, और नई कार्यविधियाँ निकालने में अपनी कल्पना-शक्ति पर हमेशा गर्व करते रहे हैं। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति अटल निष्ठा के ढाँचे में, हम इसी कारण सबल हुए हैं कि यथास्थिति की कठोरताओं के बजाए, हमने रचनात्मक, जिम्मेदार कार्यशीलता को पसन्द किया है।

तर्क संगत शांति के आधार की खोज करते हुए, हम इस परम्परागत धारणा का परित्याग क्यों करें। दूसरा कोई चाहे ऐसा करे भी, लेकिन हम भला नए, गर्व-भरे विकासशील राष्ट्रों से यह अपेक्षा क्यों करें, कि वे दुनिया को हमारी ही नजर से देखेंगे ? क्या कोई नया राष्ट्र कभी भी जेफरसन, जैक्सन, और लिंकन के युवा अमरीका से अधिक स्पष्टवक्ता, स्वतन्त्र, और अजुड़ था ?

×

×

×

मूल प्रश्न अब भी रह जाता है—क्या कोई लोकतांत्रिक शासन ऐसी विदेशी नीति बना और चला सकता है, जो आज की दुनिया की उलझनों के लिए पर्याप्त हो ?

इसका उत्तर एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति निर्मित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है, जो राष्ट्रपति को एक ठोस आधार प्रदान करे जिससे वे विश्व-नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा सकें।

युद्ध के बाद ऐसी सहमति के निर्माण की दिशा में कई बड़े क़दम उठाए हैं। जो परेशान करने वाले मतभेद अब भी बचे हैं, उनका सम्बन्ध एक घोर पिछलग्गू देशों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से, और दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका नए अजुड़ राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्धों से है।

इस मतभेद से इतिहास की एक निर्णायक घड़ी में अमरीकी विदेश-नीति की प्रभावकारिता कम होने का खतरा है। इसे खुली जिम्मेदारी सार्वजनिक बहस के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। जो मत मीने यहाँ व्यक्त किए हैं, वे उस बहस में एक व्यक्ति का योग हैं।

दूसरा खण्ड

अमरीकी सपने की उपलब्धि

दूसरे खण्ड पर एक निजी टिप्पणी

पहले खण्ड में चर्चित विश्व समस्याओं का सामना हम कितनी सफलता के साथ करते हैं, इसका निर्णय भन्ततः स्वयं भ्रमरीकी समाज के स्वरूप द्वारा होगा। तीन सत्वों द्वारा यह स्वरूप निर्धारित होगा :

—हमारी घरेलू भ्रय-व्यवस्था की शक्ति और गतिशीलता;

—हमारी संघ-राज्य और कार्यकारी-विधायिका-न्यायपालिका पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की ग्रहणशीलता, लचीलापन, और सन्तुलन;

—सभी भ्रमरीकी सह-नागरिकों को पूरी मात्रा में प्रतिष्ठा, भवसर, और न्याय प्रदान करने के लिए हमारी नैतिक प्रतिबद्धता की गंभीरता।

अगर हम इन तीन मामलों में असफल रहते हैं, तो भ्रमरीका के पास विश्व-व्यापी आर्थिक चुनौती का सामना करने के लिए उत्पादन-शक्ति का, विदेशों में राजनीतिक संकटों का सामना करने के लिए लचीलेपन का, और अन्य राष्ट्रों का आदर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय निष्ठा का अभाव रहेगा।

दूसरे खण्ड में, सत्रह वर्ष की अवधि में लिखे गए, इन प्रश्नों से सम्बन्धित लेख और भाषण हैं। इस सामग्री को फिर से पढ़कर मैं देखता हूँ कि उसमें उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में भ्रमरीका में प्रभावशाली प्रगति हुई है, लेकिन अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में इसका चिन्तनीय अभाव है।

बेकारी, जातिभेद, और भ्रष्टाचार, स्कूलों और मकानों की कमी, और गन्दे शहर, राज्य विधायिकाओं में असन्तुलित प्रतिनिधित्व, और वाशिंगटन में शासकीय अड्डचनें इन समस्याओं के अवशेष भ्रमरीका की राष्ट्रीय अन्तरात्मा, विश्वास, और क्षमता पर आग भी एक बोझ हैं।

चदाहरण के लिए, दस वर्ष पहले कानेटिकट राज्य के गवर्नर के रूप में मैंने जिन समस्याओं का सामना किया था, 1962 में राष्ट्रीय विधायक गतिरोध के मर्म में भी वही प्रश्न हैं। राज्यों के अधिकारों का सर्वाधिक सुस्तर समर्थन करने वाले राजनीतिक नेता बहुधा राज्यों की जिम्मेदारियों को अस्वीकार करने वालों में सबसे आगे दिखाई देते हैं।

पहला भाग

अधिक समृद्ध समाज की ओर

मुझे विश्वास है कि इस देश में सच्ची आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने, और अपनी अमरीकी परम्पराओं के अनुसार व्यक्ति के जीवन का विकास करने का एकमात्र उपाय पूर्ण उत्पादन और पूर्ण रोजगार के वातावरण में है, जिसमें व्यापार को अच्छा मुनाफा मिले, मजदूरों को अच्छे काम और स्थिर वेतन मिलें, और किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो। तभी हम भय और असुरक्षा के जाल से निकल सकते हैं, जिसने अतीत में कल्पनाशील और साहसपूर्ण रीति से विचार करने की क्षमता हममें से लाखों व्यक्तियों में नष्ट कर दी है।

1 सितम्बर, 1945

शान्ति और सबको काम

जापान पर विजय प्राप्त होने के तीन सप्ताह बाद सीनेट की बैंक और मुद्रा समिति ने एक 'पूर्ण रोजगार विधेयक' सम्बन्धी सुनवाई आरंभ की, जिसका उद्देश्य शान्ति स्थापना के बाद पुनः परिवर्तन की प्रमुख समस्या को हल करना था—युद्धोत्तर अर्थ-व्यवस्था में सभी लोगों के लिए काम की व्यवस्था करना। श्री वॉल्स ने, जो उस समय मूल्य प्रशासन कार्यालय के अध्यक्ष थे, 1 सितम्बर, 1945 को अपना साक्षी दी।

शान्ति की स्थापना से अमरीकी लोग अब शान्ति, समृद्धि और बाहुमूल्य की एक बिलकुल नई दुनिया के प्रवेश-द्वार पर खड़े हैं।

युद्ध-काल में हमने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे औद्योगिक संयन्त्र में कितने विशाल उत्पादन की क्षमता है। हममें से कम ही लोग होंगे जो ऐसा नहीं सोचते कि युद्ध-उत्पादन से हटाकर इसी औद्योगिक संयन्त्र को शान्ति-कालीन उत्पादन में तगाने पर, यह अब आधुनिक मकानों और ज्यादा अच्छी शिक्षा के द्वारा जीवन के ज्यादा ऊँचे स्तर, और स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अवकाश के कहीं अधिक ऊँचे स्तर प्रदान कर सकता है।

मरे-पैटर्मन विधेयक में, जो इस समय आपकी समिति के सामने है, कहा गया है कि इस प्रकार की समृद्धि प्राप्त करना—स्वतन्त्र उद्यम की व्यवस्था के अन्तर्गत निरन्तर समृद्धि—अमरीकी लोगों की राष्ट्रीय नीति होगी।

ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो इस विधेयक को बड़ी आशका की दृष्टि से देखते हैं।

कुछ लोग इसलिए इसका विरोध करते हैं कि हर प्रकार के शासन को वे अहवि और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, और इस विधेयक में सीमित शासकीय नियोजन की जो व्यवस्था है, उससे डरते हैं।

बया वे सचमुच ऐसा सोचते हैं कि 1932 की मन्दी की तीव्रता के निकट पहुँचने वाली भी किसी और मन्दी का सामना, यहाँ जितना प्रस्तावित है, उससे कहीं अधिक दूरी तक जाने वाले शासकीय नियंत्रणों के बिना हम कर सकते हैं ?

अन्य लोग इसलिए इस विधेयक का विरोध करते हैं कि उन्हें संघ शासन के दीवालिया हो जाने का भय है। लेकिन इस बात को गंभीरता से कौन मान सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अस्थिर होने पर, और लाखों बेकार व्यक्तियों के काम की

बदलते हुए अमरीका के नकशे

एक भूतपूर्व व्यापारी के रूप में, श्री चौल्स अन्य व्यापारियों को चुनौती देते हैं कि वे निजी उद्यम व्यवस्था की कार्यप्रणाली, और युद्धोत्तर-काल में पूर्ण उत्पादन और रोजगार कायम रखने की तीव्र आवश्यकता के प्रति अधिक यथार्थ-परक दृष्टिकोण अपनाएँ। सीमूर ई० हैरिस द्वारा सम्पादित 'सेविंग अमेरिकन कपिटलिज्म' से।

दूसरे महायुद्ध ने विश्व की ऐसी विरासत छोड़ी है, जो लगभग मनुष्य की समझ के परे है। उसने नगर, कारखाने, बाँध, बिजली-घर और रेलें नष्ट कर दी हैं। इससे भी बुरा है कि उसने करोड़ों मनुष्यों की शक्ति, आशाओं, और क्षमताओं को नष्ट कर दिया है, जिन पर विश्व का पुनः निर्माण निर्भर होगा।

विश्व-व्यापी विनाश की इस पृष्ठभूमि में अमरीका एक आर्थिक स्वप्न-देश प्रतीत होता है—वह स्वयं युद्ध के विनाश से अछूता रहा, उसके साधनों को क्षति नहीं पहुँची, और उसके लोग आम तौर पर समृद्ध और एकताबद्ध हैं।

फिर भी, आज सारे अमरीका में हमारे आर्थिक भविष्य के बारे में बेचैनी है। विदेशों में यूरोप और एशिया की अव्यवस्था पर नज़र डाल कर, बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या अभाव की दुनिया में हम बाहुल्य का एक द्वीप बनकर समृद्ध हो सकते हैं।

चौथे दशक में आर्थिक अल्पता के दर्शन ने हमारे आर्थिक विकास में बड़ी बाधा पहुँचाई थी। पल हार्बंद के एक मास बाद, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जब पचास हजार वायुयान और पचास लाख टन भार के जहाजों के वार्षिक उत्पादन की माँग की, तो बहुतेरे अमरीकियों को विश्वास था कि वे एक असंभव माँग कर रहे हैं।

लेकिन भीरु विचारक गलती पर थे। जैसे-जैसे समय बीता, हमारा देश अपनी विशाल औद्योगिक क्षमता की पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हुआ। हमने राष्ट्रपति के पचास हजार वायुयानों के लक्ष्य को पूरा किया, फिर उसे दुगुना कर दिया। प्रति वर्ष पचास लाख टन भार के जहाजों के उनके अनुमान को हमने चार गुना कर दिया। दस प्रतिशत कम मजदूरों के साथ, हमारे किसानों ने खेतिहर उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि की। 1942, 1943, और 1944 में, तथ्यों से पता चलता है कि हमने अपने इतिहास की अन्य किसी भी अवधि से अधिक अमीनिरु वस्तुओं का

बदलते हुए अमरीका के नशरे

उत्पादन किया। और इस सब के ऊपर, युद्ध प्रयत्नों के जित्तर पर, हमने 100 अरब डालर के सैन्य सामान और सेवाओं की वार्षिक उत्पादन गति प्राप्त की।

हमारा औद्योगिक संयन्त्र हमारे लोगों को क्या कुछ प्रदान कर सकता है, युद्ध कालीन उत्पादन की सफलता ने इसमें हमारे विश्वास को फिर से प्रतिष्ठित किया। जब हमने अपने युद्ध कारखानों को दिनरात काम करते देखा; तो हम कुछ समझने लगे कि शांतिकाल में ये कारखाने हम सबके लिए उपभोग की वस्तुओं की कमी बाढ़ ला सकते हैं। और इससे यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमें मन्दियों को अनियमित मान कर स्वीकार नहीं करना चाहिए, पुराने पढ़े भाषिक सिद्धान्तों को हमें छोड़ देना चाहिए, किसी प्रकार, बिना अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोए, हमें अपने छेतों और कारखानों में पूरी तरह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की जारी रखना चाहिए जिनकी हमें, और सचमुच सारी दुनिया को, इतनी जरूरत है।

हम अपनी युद्धकालीन गति को कैसे कायम रख सकते हैं? पूर्ण रोजगार और पूर्ण उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था को जिस सिद्धान्त के आधार पर निर्मित करना होगा, उसे सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक डालर मूल्य के उत्पादन से, एक डालर की संभाव्य क्रय-शक्ति उत्पन्न होती है।

अगर उत्पादन के स्तर को कायम रखना और बढ़ाना है, तो इस सारे धन का व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं द्वारा उसी समय खर्च होना जरूरी है। अन्यथा वस्तुएँ और सेवाएँ बिना खरीदी रह जाएँगी, और हमारा उत्पादन उतना ही घट जाएगा।

इससे नए सामान और नई मशीनों के आदेश रह कर दिए जाएँगे; बेकारी और बेकारों बढ़ेंगे। क्रय शक्ति घटेगी, और हम मन्दी की ओर बढ़ने लगेंगे। बेकारी में होने वाली हर वृद्धि, और क्रय-शक्ति में होने वाली हर कमी अपने-आप को बढ़ाएगी।

तीन समूह हैं, जो मिलकर हमारी कुल क्रयशक्ति के सारे धन को खर्च कर सकने की स्थिति में हैं, और इस प्रकार एक समृद्ध, बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था को कायम रख सकते हैं। इनमें से एक समूह व्यापार है। हर वर्ष यह समूह एक विशाल, लेकिन घटती-बढ़ती रकम औद्योगिक विस्तार, तरह-तरह की वस्तुओं, नए सामान, और इमारतों पर खर्च करता है।

खर्च करने वाले तीन समूहों में दूसरा समूह शासन है—संघ, राज्य, और स्थानीय। प्रतिवर्ष हमारी शासकीय संस्थाएँ स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, सिंचाई योजनाओं, पुलिस और दमकल विभागों, सेना और नौसेना के प्रतिष्ठानों पर विभिन्न रकम खर्च करती हैं।

खर्च करने वालों का तीसरा समूह अक्रोधी लोग स्वयं हैं। हर वर्ष हम अपने वेतनों, पगारों, और लाभांशों की विभिन्न रकमों, उपभोगताओं के रूप में भोजन, वस्त्र, यात्रा, सिनेमा, कपड़ा धोने और सफाई करने की मशीनों, पुस्तकों, मकानों,

श्रीर केश-विन्यास आदि पर खर्च करते हैं ।

यद्यपि इन तीनों समूहों द्वारा किए जाने वाले खर्च का रूप प्रति वर्ष बदलता रहता है, लेकिन तीनों का कुल खर्च मिलाकर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा प्राप्त सभी लोगों की कुल आय के बराबर होना चाहिए—अन्यथा हमें बढ़ती हुई वैजारी का सामना करना पड़ेगा ।

अतः समस्या स्पष्ट है । इन तीनों समूहों में किसी प्रकार सन्तुलन कायम रखना आवश्यक है, ताकि जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करें, उन सभी के लिए बाजार मौजूद रहे, और उत्पादन व रोजगार को एक ऊँचे स्तर पर कायम रखा जा सके, और हमारी उत्पादन शक्ति में वृद्धि होने के साथ-साथ यह स्तर भी उठे ।

हमारे वर्तमान शासकीय बजटों का हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण हमारी कुल क्रय-शक्ति को कायम रखने में शासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसका महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता है, कि हमारी कुल क्रय-शक्ति के शासन द्वारा समर्थित हिस्से को, उचित सीमाओं के अन्दर, हमारी कुल आवश्यकताओं के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है ।

जब हम देखते हैं कि शासन क्या कर सकता है, और उसे क्या करना होगा, तो हमारे सामने बहुतेरे पूर्वाग्रह और कुठारें आ जाती हैं । चालीस वर्ष से अधिक आयु के अमरीकी, ऐसे काल में व्यस्क हुए थे, जब शासन की प्राथमिक जिम्मेदारियाँ आम-तौर पर यही थी कि अपराध को कम करे, सेना और नौसेना के बुनियादी ढाँचे को कायम रखे, सड़कों को चालू रखे, और सीमित सेवाओं के खर्च के लिए न्यूनतम आवश्यक कर लगाए ।

हमसे कहा जाता है कि शासन में कोई भी विस्तार व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करता है, और उसका यथासंभव विरोध करना चाहिए, और यह कि न्यूनतम आवश्यक शासन भी प्रशंसा की नहीं, सहन करने की वस्तु है । हमारे बचपन के व्यंग्य-चित्रों में सार्वजनिक कर्मचारियों को स्थूलकाय राजनीतिज्ञों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिनके मुँह में बढिया सिगा और सिर पर बढिया टोप होते थे, और जेबों में हजार डालर के नोट, जिन पर 'रिश्वत' लिखा रहता था ।

1929 की मन्दी के बाद से इस धिसे-पिटे दृष्टिकोण को स्वीकार करना अधिकाधिक कठिन होता गया है । देश के विकास के साथ, यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती गई है कि हमारे शासन में, बड़ी हुई जिम्मेदारियों के अनुरूप वृद्धि करनी होगी । हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास होने पर, और उसमें नई पेची-दगियाँ आने पर, शासन के प्रति पुराने दृष्टिकोण को संशोधित करना अपरिहार्य हो गया था । ऐसे संशोधन के बिना हम यह आशा कैसे कर सकते थे, कि अपरिहार्य घटनाओं ने शासन पर जो नई जिम्मेदारियाँ डाल दी थी, उन्हें वह कौशल से, पर्याप्त रूप में, और बिना हमारी स्वतन्त्रताओं को नष्ट किए निभा सकेगा ?

एक निर्णायक महत्त्व के प्रश्न की हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते—अगर अमरीकी लोग अभी पर्याप्त शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अन्त में हमें बहुत अधिक शासन स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात विरोधाभासपूर्ण प्रतीत हो सकती है, लेकिन सच है। अगर हम आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए शासन को पर्याप्त अधिकार देने को तैयार नहीं हैं, तो अनुत्तरित समस्याएँ किसी दिन हमको पकड़ रोंगी, और, पहले पर्याप्त कार्यवाही करने के लिये जितना शान्कीय नियंत्रण आवश्यक होता, बाद में उत्पन्न सकट का सामना करने के लिए हमें उससे कहीं अधिक शासकीय नियंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा।

×

×

×

मैं समझता हूँ कि शासन के छह आधारभूत कर्तव्य हैं। उसकी पहली जिम्मेदारी परम्परागत है—एक सक्षम ढाक व्यवस्था को, और अन्य आधारभूत शासकीय सेवाओं को कायम रखना। इस प्रश्न पर मतभेद की गुंजाइश बहुत कम है।

शासन का दूसरा कर्तव्य उन चार समूहों के बीच निर्णायक का काम करना है, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था के मुख्य अंग हैं—व्यापारी, मजदूर, किसान, और उपभोक्ताओं के रूप में हम सभी लोग। हमारे आर्थिक इतिहास के प्रारम्भिक काल में यह भूमिका अपेक्षितया महत्त्वहीन थी।

लेकिन 'बड़े' व्यापार का विकास होने पर, 'बड़ी' खेती और 'बड़े' मजदूर समूहों का भी विकास हुआ। इसके फलस्वरूप हमारा शासन भी 'बड़ा' हुआ, इतना काफी सफल कि 14 करोड़ नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा कर सके, जो अल्पव्यय व्यापारियों, मजदूरों, और किसानों के अत्याधिक सङ्गठित समूहों की दया पर निर्भर होते।

इस क्षेत्र में शासन की एक बड़ी जिम्मेदारी किसी भी दिशा में अधिक एकाधिकार को रोकना है। सीमित औद्योगिक उत्पादन का प्रतिरूप मजदूर आन्दोलन में सुविधाजनक काम लेना, और अनावश्यक काम गढ़ने के अन्य तरीके हैं। ये दोनों ही बुराइयाँ इस धारणा से उत्पन्न होती हैं कि हम अपने सभी साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं है।

शासन की तीसरी जिम्मेदारी ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करना है, जिनकी हम लाभ-हानि के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों से उचित रूप में अपेक्षा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, इसकी अपेक्षा करना उचित न होता कि एक अरब डालर से अधिक पूँजी वाले टेनेसी घाटी अधिकरण की स्थापना निजी पूँजी द्वारा हो सकती थी। न हम इसकी ही अपेक्षा कर सकते हैं कि मिसौरी, आर्कन्सास, कोलम्बिया, सेन्ट लॉरेन्स और अन्य प्रमुख नदियों के जलमार्गों में पानी के प्रवाह का पर्याप्त नियंत्रण निजी धन से किया जा सकता है।

इसी कारण, हम यह आशा भी नहीं कर सकते कि निजी पूँजी लगाने वाले गन्दी चस्त्रियों को समाप्त करने के लिए, और आधुनिक बगीचों, अस्पतालों, और मनोरंजन

क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे। इस व्यापक क्षेत्र में ऐसी बहुतेरी सेवाएँ हैं जो अमरीकी लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो अभी तक उन्हें पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। यह हमारे आधुनिक लोकात्मिक शासन की जिम्मेदारी है कि उनकी व्यवस्था करने के लिए तेजी से काम करे।

हमारी निजी उद्यम व्यवस्था में शासन की चौथी जिम्मेदारी यह है कि बिना जाति, धर्म, या रंग के भेदभाव के, हर नागरिक को उचित रूप में समान अवसर प्राप्त हो। अपने सारे इतिहास में, हमने उन लोगों की प्रीर सगर्व संकेत किया है, जो गरीबी से उठकर शासन, व्यापार, या कानून के क्षेत्रों में जिम्मेदारी के स्थानों पर पहुँचे हैं।

फिर भी, किसी भी निष्पक्ष प्रेक्षक की स्वीकार करना होगा कि हम अभी अपने आदर्श से बहुत दूर हैं। धनी माता-पिता के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, और सामान्य विकास के ऐसे अवसर मिलते हैं, जिनसे कम आय वाले लोगों के बच्चे वंचित रहते हैं।

यह संघ-शासन की जिम्मेदारी है कि अमरीका में हर बच्चे को शिक्षा का एक उच्चतर उपलब्ध हो, चाहे उसके माता-पिता की आय जो भी हो।

हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक न्यूनतम स्तर भी निर्धारित करना चाहिए, प्रीर यह न्यूनतम स्तर ऊँचा होना चाहिए। व्यापक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए, कई हजार अस्पताल बनाने प्रीर दसियों हजार डॉक्टरों, दन्त-चिकित्सकों और नर्सों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। लेकिन हम एक धनी राष्ट्र हैं, प्रीर इस जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते।

सभी लोगों के लिए अच्छे मकानों की व्यवस्था करने के प्रयास में भी हमारे शासन को प्रगुआई करनी होगी। युद्ध के पहले अनुमान लगाया गया था कि एक तिहाई से अधिक अमरीकी परिवारों के निवास-स्थान सर्वथा अपर्याप्त थे। एकाधिकार-प्रस्त आवास उद्योग, जो केवल सुविधाजनक काम ही करता है, प्रीर जिसने निर्माण-काम के सम्बन्ध में राजनीति प्रेरित नियम बना रखे हैं, अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी को निभाने में घुरी तरह असफल रहा है।

हमारे शासन की पाँचवी जिम्मेदारी हमारे आयात-निर्यात कार्यक्रम को इस प्रकार समेकित करना है, जिससे सारी दुनिया में राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके।

दुनिया में एकमात्र हमारा ही प्रमुख राष्ट्र ऐसा है, जो युद्ध से झड़ता रहा है। हम प्राकृतिक साधनों, मानवी कौशल, और उत्पादन क्षमता में समृद्ध हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह बराबर छोटी होती जाती है। हममें से कुछ लोग अब भी कहते हैं कि शेष दुनिया के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं, प्रीर यह कि हमें अपने प्रयत्नों को केवल अपने लोगों के धन में वृद्धि करने पर केन्द्रित करना चाहिए। हमारी प्रीर दुनिया की भलाई के लिए यह जरूरी है कि इस दृष्टिकोण का परिवर्तन किया जाय।

दुनिया की गन्दी वस्ती के बीच हम अमरीकियों के लिए सफलतापूर्वक किसी महल का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक सभी लोगों का जीवन स्तर बराबर नहीं उठता, तब तक हमें या हमारे बच्चों को शांति या सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती।

अगर हम दुनिया की उत्पादन शक्ति को, और उसके साथ दुनिया के लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दुनिया की खेती के आधुनिकीकरण में सहायता करनी होगी। यह अगली पीढ़ी के लिए एक बुनियादी चुनौती है। हमें आधुनिक परिवहन व्यवस्थाओं के, बिजली-घरों के और मूल औद्योगिक कारखानों के निर्माण में भी सहायता करनी होगी। अमरीकी प्रबन्ध-कौशल के लिए लगभग असीमित अवसर हैं।

सोवियत संघ और साम्यवादी दल भूखे लोगों को अधिक ऊँचे जीवन-स्तर और अधिक आर्थिक सुरक्षा की आशा दिलाने हैं। अगर हमें सफलतापूर्वक इस चुनौती का सामना करना है, केवल इतना कहना ही काफी नहीं होगा कि साम्यवाद का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र की समाप्ति होता है, यद्यपि यह बात अपने आप में विलकुल सही है। हमें सारे विश्व के पैमाने पर, न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को बल्कि आर्थिक लोकतंत्र को भी प्रोत्साहित करना होगा।

हमारे शासन की छठी और अन्तिम जिम्मेदारी यह है कि अपनी सारी नीतियों को इस प्रकार समन्वित करें कि हम जो कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध हो।

मेरा तात्पर्य यह है कि शासन इस बात की सुरक्षा प्रदान करे हमारे मजदूर, किसान, और व्यापारी प्रति वर्ष जिन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, उनके लिए हमेशा क्रय-शक्ति मौजूद रहे। अगर हमें पूर्ण उत्पादन और पूर्ण रोजगार को कायम रखना है, तो यह कार्य आवश्यक है। यह सुरक्षा जितनी प्रभावकारी होगी, आर्थिक भविष्य के सम्बन्ध में विश्वास उतना ही अधिक होगा, और दबी हुई माँगें उतने ही अधिक निश्चित रूप में खरीदों का रूप लेंगी। इस बात पर विशेष जोर देने की जरूरत है।

×

×

×

तथाकथित सामान्य कालों में, हर व्यापारी को दो खतरे उठाने पड़ते हैं। पहला, प्रतियोगिता का सामान्य खतरा होता है, इस बात की कसौटी कि उसमें अपने उद्योग के अन्य व्यापारियों के साथ, उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करने में प्रतियोगिता करने की योग्यता है। यह एक उचित जोखिम है, जिसे निजी उद्यम की हमारी व्यवस्था में सचमुच विश्वास करने वाले हर व्यापारी को स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा खतरा इस संभावना का है कि मन्दी कभी भी आ सकती है। मन्दी में कुशल और अकुशल दोनों ही तरह के व्यापारी दीवालिया हो जाते हैं। मन्दी के निरन्तर भय के फलस्वरूप व्यापारी अपना उत्पादन सीमित रखते हैं, विस्तार

क्रमो को रोक देते हैं, और विनाश आरक्षित विधियाँ एनप्रित करते हैं, जिनकी सहायता से वे कठिन समय में अपने को बचा लेने की आशा करते हैं।

कोई आधुनिक अर्थ-व्यवस्था किन तरह काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग जो कुछ जानते हैं, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह दूगरा पतरा अनावश्यक है। युद्धपूर्ण, लोकतांत्रिक कार्यवाही के द्वारा इसे मिटाया जा सकता है, और मिटाना चाहिए।

सबसे पहले, हमारे लिए जरूरी होगा कि सावजनिक निर्माण कार्यों को समन्वित करें, और उन्हें निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाएँ।

हमें अपनी कर नीतियों और वित्तीय नीतियों पर भी सावधानी से विचार करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में हम कर सम्बन्धी जिन त्रानूनों के अधीन काम करते रहे हैं, वे किसी पुराने मकान की तरह बढते रहे हैं, कभी एक कमरा इधर, कभी एक भण्डारघर उधर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कराधान नीति पूर्ण रोजगार और पूर्ण उत्पादन में योग दे, तो हमें उसका नए सिरे से संगठन करना पड़ेगा।

आधुनिक कराधान कार्यक्रम को नए उद्यम के विकास के लिए अधिक प्रोत्साहन भी प्रदान करना होगा। नए उद्योगों को इस बात की अनुमति होनी चाहिए कि प्रारम्भिक वर्षों में होने वाली हानि को अपने पाँव पर खड़े हो जाने के बाद होने वाले लाभों से सतुलित कर सकें।

अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि किमी विशिष्ट अवधि में, मूल कर-व्यवस्था तत्कालीन आर्थिक स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए जिस अवधि में उत्पादन घटने का खतरा हो, उसमें कर घटा देने चाहिए, ताकि क्रम-शक्ति और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बढ़े।

मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया जाय, कि वे अपनी आर्थिक परिपक्व की सलाह से, निश्चित सीमाओं के अन्दर, हमारी अर्थ-व्यवस्था की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार, करों को घटा-बढा सकें। निस्सन्देह, राष्ट्रपति का ऐसा करने का अधिकार, स्पष्टतः निरूपित विधायक सत्ता और प्रतिमानों के अन्तर्गत होना चाहिए। इससे हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के तेजी या मन्दी की ओर बढ़ने पर, तत्परता से अपनी कुल क्रय-शक्ति के प्रवाह को घटा या बढा सकेंगे।

मे समझता हूँ कि हमारे पास इतना काफी आर्थिक ज्ञान है, कि व्यापारिक चक्र की ऊँच-नीच को सम-स्तर पर लाने के लिए, हम इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें।

लेकिन यह मानना भूल होगी कि निजी उद्यम व्यवस्था के अन्तर्गत शासन हमारी सारी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकता है। अगर निजी उद्यम व्यवस्था में व्यापार, मजदूरों और किसानों के नेता अपने उचित आर्थिक कर्तव्यों को पूरा करने में व्यापक रूप में असफल रहते हैं, तो शासकीय खर्च, ध्यानपूर्वक समन्वित होने पर भी, उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी निजी उद्यम व्यवस्था

को कायम रखते हैं,—और उसे छोड़ना निश्चय ही मूर्खतापूर्ण होगा—तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था पर सबसे बड़े प्रभाव वेतनों, मूल्य और मुनाफों को तय करने में, और हमारी औद्योगिक सुविधाओं के विस्तार का नियोजन करने में, व्यक्तियों के रूप में, व्यापारियों, मजदूरों और किसानों के निर्णयों के पड़ेंगे ।

अगर हमें अपने आर्थिक भविष्य का तर्क-संगत हल प्राप्त करना है, तो जिम्मेदार मजदूर नेतृत्व आवश्यक होगा । हमें कम काम करने के चलन को खतम करना होगा, और हर मजदूर को यह निश्चय करना होगा कि पूरे दिन के वेतन के बदले में वह पूरे दिन का काम करेगा ।

लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे व्यापारियों के ऊपर होगी । ऐसा इस कारण है कि निजी उद्यम की अर्थ-व्यवस्था, व्यापारिक अर्थ-व्यवस्था होती है । व्यापारियों से यह आशा करना उचित नहीं होगा कि वे व्यापार में घाटा लाने वाले काम करेंगे । मुनाफे व्यापार का प्राणरजत होते हैं ।

किन्तु अगर हमारे व्यापारियों को अपने प्रति ही नहीं, बल्कि हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो मुनाफा कमाने के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण दीर्घकालीन होना चाहिए ।

तीन ही तरीके हैं, जिनमें वेतन बढ़ाये जा सकते हैं । जिस व्यापार में पर्याप्त से अधिक मुनाफा हो रहा हो, वह वेतन बढ़ाकर, और वर्तमान मूल्य स्तरों को कायम रखकर भी काफी मुनाफा कमा सकता है । जो व्यापार उचित से कम वेतन देकर, केवल सामान्य मुनाफा कमा रहा हो, वह मूल्य बढ़ा कर वेतन बढ़ा सकता है, और उसे ऐसा करना चाहिए । जहाँ वेतन उचित से कम हैं, वहाँ ऐसा करना सर्वथा तर्क-संगत होगा । अगर मालिक लोग न्यूनतम वेतन प्रतिमान को पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें व्यापार में नहीं रहना चाहिए । हमसे से किसी को भी उपभोक्ता के रूप में यह अधिकार नहीं कि उचित से कम वेतनों का लाभ उठाएँ ।

अन्त में, श्रम की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाकर, वेतन बढ़ाये जा सकते हैं, मूल्य स्थिर रखे या कम किये जा सकते हैं, मुनाफे कायम रखे या बढ़ाये जा सकते हैं । अपने जीवन-स्तर में वृद्धि के लिए हमें बहुत कुछ इस आखिरी तरीके पर भी निर्भर रहना होगा । युद्ध के पहले के बीस वर्षों में, प्रति व्यक्ति, प्रति घण्टा श्रम की उत्पादन शक्ति 4 प्रतिशत वार्षिक की रफ्तार से बढ़ती रही थी ।

श्रम की उत्पादन शक्ति अधिकांश मशीनों और सुविधाओं में सुधार होने से बढ़ती है । प्रबन्धकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि वे अपने मुनाफों को अपने कारखानों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में लगाएँ, यह उचित है कि बढ़ी हुई श्रम उत्पादन शक्ति से होने वाली आय के एक हिस्से से उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाने का अधिकार हो । लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि श्रम की उत्पादन शक्ति में वृद्धि के काफी बड़े हिस्से को वेतन वृद्धियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ।

अगर प्रबन्धक इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते, या मजदूर अपनी माँग के-

धोचित्य को प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वस्तुओं के बढ़े हुए उत्पादन को गरीबों के लिये क्रय-शक्ति में आवश्यक वृद्धि नहीं होगी। 1929 की मजदूरों की मन्दी का यही कारण था।

एक उदारवादी स्वर

मूल्य-निर्धारण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसमें निजी उद्यम व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारियों को मुख्य नियंत्रण करने रहते हैं। कुछ मूल्य बढ़ाने अधिक रंगे जाते हैं, क्योंकि मूल्य कम होने पर अधिक मात्रा और अधिक मुनाफों की संभावनाओं की व्यापारी नहीं समझ पाते। अमरीकी व्यापार के हर हिस्से में हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं, जहाँ मूल्य कम होने पर मात्रा में इतनी वृद्धि हुई है कि मुनाफे काफी बढ़ गए। मेरा भाव है कि निजी नियंत्रणों के इस आवश्यक क्षेत्र में उद्यम अधिक हो, मालिक मजदूर सम्बन्धों में अधिक बल्पनाशीलता हो, व्यापार पद्धतियों में सुधार हो, और बड़ी हुई मात्रा पर आधारित मुनाफे की दीर्घ-कालीन संभावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा जाय।

पूर्ण उत्पादन को जिन बाजारों और क्रय-शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें कायम रखने में शासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन मूल्य, मुनाफे और वेतन तय करने में हमारे व्यापारियों, मजदूरों और किसानों की जिम्मेदारी और भी बढ़ी है।

अगर, किसी कारणवश, निजी नियंत्रणों के इस क्षेत्र में हम असफल रहते हैं, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में शासन का महत्व निश्चय ही बढ़ेगा। अगर एकाधिकारवादी मूल्य निर्धारण चलता रहता है, तो शासकीय नियंत्रण की माँग बढ़ेगी। अगर मालिक-मजदूरों के विवाद बढ़ कर हमारे आर्थिक जीवन में व्यापक गड़बड़ी पैदा करते हैं, तो यह माँग और भी अधिक होगी।

और अगर शांति काल में एक बार शासन को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना पडा, जो निजी नियंत्रणों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, तो शासकीय नियंत्रण बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक नियंत्रण से फिर दूसरे नियंत्रणों को जगह मिलती जाती है। हमें इससे बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

आर्थिक विकास पर एक नई दृष्टि

जब अमरीकी अर्थ-व्यवस्था का पिछटना जारी रहा, तो कांग्रेस-सदस्य वॉलस ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख भाषण में अधिक तीव्र गति से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त निजी और सार्वजनिक कार्यवाही के लिए अपील की। 29 जून, 1959।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसे प्रश्न पर बोलने खड़ा हुआ हूँ, जो मेरे विचार में, अमरीकी लोगों के सामने सर्वप्रमुख प्रश्न है। मेरा तात्पर्य इससे है कि पिछले वर्षों में हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, बिना मंहगाई के, और रोजगार का ऊँचा स्तर कायम रखते हुए, निरन्तर विकास की अपनी विशाल क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने में बराबर असफल होती रही है।

इस चुनौती का सामना करने में हमारी सफलता से न केवल आने वाले वर्षों में हमारे अपने समाज का स्वरूप निर्धारित होगा, वरन् क्रान्तिकारी परिवर्तन के विश्व में नेतृत्व की हमारी क्षमता भी निर्धारित होगी।

इस समय हम दस वर्षों में अपनी तीसरी मन्दी से निकल रहे हैं। पहली 1949 में आई, दूसरी 1953-54 में, और तीसरी 1957-58 में।

पिछले वर्षों में उत्पादन में जो क्षति हुई, वह भरी नहीं जा सकती, और उसकी मात्रा काफी है। अगर कोरिया-युद्ध के बाद हमारे विकास की गति दूसरे महायुद्ध के पूर्व की 4 प्रतिशत वार्षिक की गति पर कायम रहती, तो हमने जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है, उससे 170 अरब डालर अधिक मूल्य का करते।

अगर हम 5 प्रतिशत वृद्धि की गति प्राप्त कर लेते, जिसे 1958 में रॉकफेलर प्रतिवेदन ने व्यावहारिक और आवश्यक दोनों ही बताया था, तो कोरिया युद्ध के बाद हमारा अतिरिक्त उत्पादन 400 अरब डालर से अधिक का होता।

यह एक विशाल रकम है। यह लगभग एक पूरे वर्ष की राष्ट्रीय आय के बराबर है। यह हमारे 285 अरब डालर के राष्ट्रीय ऋण की डेढ़ गुनी है।

कोरिया युद्ध के बाद हम अपनी आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धि में असफल क्यों रहे हैं? क्या गड़बड़ी हो गई?

कारण बहते-धरे और उलझे हुए हैं। उनकी प्रकृति और विनाश दोनों के जाने में

ईमानदार व्यक्तियों में मतभेद हो सकता है। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि इतिहासकार हमारे पिछड़ने का कारण बहुत कुछ यह बताएँगे कि जिस निजी उद्यम व्यवस्था को हम इतना मौलिक समर्थन प्रदान करते हैं, उसकी गरयात्मकता को हम नहीं समझ पाए।

हमारी गलतियाँ इस कारण नहीं हैं कि सभ शासन ने हमारी अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। हमारी कठिनाइयाँ इस कारण हैं कि हमने उस शक्ति का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए, गलत कारणों और गलत तरीकों से किया।

अपने शासन की शक्तियों का उपयोग, विकास और रोजगार के ऊँचे स्तर को प्रोत्साहित करने के लिए करने के बजाए, हमने बहुधा उनका उपयोग अनजाने में विकास को कुंठित करने के लिए किया है, क्योंकि हम भूल से यह मान बैठते हैं कि निरन्तर विकास, रोजगार का ऊँचा स्तर, और मूल्यों की स्थिरता, इनमें परस्पर मेल नहीं हो सकता।

यद्यपि हम सब सहमत हैं कि अधिकांश मूल्य बहुत ऊँचे हैं, लेकिन जीवन-निर्वाह के सूचकांक एक वर्ष से अधिक समय से स्थिर रहे हैं। वस्तुतः, श्रम विभाग के अनुसार, पिछले उन्नीस वर्षों में इतने लम्बे समय तक मूल्य पहले कभी निरन्तर स्थिर नहीं रहे।

मूल्य बढे हैं कम्पनियों के सामान्य हिस्सों के, और भू-सम्पत्तियों के। इनमें बीसियों अरब डालर की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अगर यह वृद्धि जारी रहती है, तो जैसा अतीत में हो चुका है, ये मूल्य भूरा पडेंगे। ऐसा होना पर सब से गहरी चोट लाखों छोटे-छोटे पूँजी विनियोजकों को लगेगी, जिनमें से बहुतेरों ने मूल्य बढने की गैर-जिम्मेदार बातों के फलस्वरूप ही बाजार में प्रवेश किया।

हमारी अर्थ-व्यवस्था के निरन्तर तेज रफतार से विकसित न होने का लगभग हर उस प्रश्न पर गभीर प्रभाव पड़ता है, जो इस कांग्रेस में हमारे सामने आता है। अपने प्रति सच्चे रहकर हम इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकते। इसे ध्यान में रख कर, कांग्रेस द्वारा अब तक प्रस्तुत राष्ट्रीय आर्थिक नीति के सर्वाधिक स्पष्ट वक्तव्य पर हम पुनर्विचार करें। मेरा तात्पर्य 1946 के रोजगार अधिनियम से है।

यह कानून यद्योत्तर-कालीन सहयोग और विश्वास की भावना का एक फल था। कांग्रेस में इसे एक द्विपक्षीय समूह ने प्रस्तुत किया था, और दोनों दलों के विशाल बहुमत ने इसका समर्थन किया था।

सामान्य बत्त्याएँ इसका व्यक्त उद्देश्य था। इसमें राष्ट्रपति से कहा गया कि वे कांग्रेस के समक्ष एक 'आर्थिक प्रतिवेदन' प्रस्तुत करें जिसमें 'संयुक्त राज्य अमरीका में रोजगार, उत्पादन, और क्रय-शक्ति के चाबू स्तरों की सूचना के साथ यह भी बताया

जाय कि घोषित नीति को कार्यान्वित करने के लिए किन स्तरों की आवश्यकता है।

पिछली जनवरी में अपने आर्थिक प्रतिवेदन में राष्ट्रपति आइजनह्वर ने इस जिम्मेदारी का जिम्मा किया था। लेकिन पहले के आर्थिक प्रतिवेदनों का उन्होंने कभी अनुमरण नहीं किया, जिनमें राष्ट्रीय लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाते थे, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निरूपित किये जाते थे।

अन्य कई प्रश्नों की भाँति इस प्रश्न पर भी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी गई है। अगर हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने की इस जिम्मेदारी से मुँह मोड़ते हैं तो हम आगे भी अपने अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएँगे।

यह भी आवश्यक है कि अपनी वर्तमान धीमी प्रगति के कारणों के सम्बन्ध में हम इस सदन में किसी प्रकार की सामान्य सहमति पर पहुँचें। एक बार ऐसी सहमति प्राप्त हो जाने पर, हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हम मूल्यों को स्थिर रखते हुए, उत्पादन के ऊँचे स्तरों को कायम रख सकें, और बढ़ा सकें।

इस प्रसंग में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

एक—मैं आशा करता हूँ कि समुक्त आर्थिक समिति के अध्ययनों और प्रतिवेदन में इसका एक आँकड़ो सहित, दस्तावेजी विवरण भी शामिल होगा कि हमारे लोगों, मशीनों, और पूँजी का अधिकतम उपयोग होने पर हमारी निजी और सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति होगी।

दो—मैं आशा करता हूँ कि इस प्रतिवेदन में हमारी वास्तविक संभावनाओं के कुछ विशिष्ट अनुमान भी होंगे कि हमारे उद्योगों को अधिकाधिक व्यापक बाजार प्रदान करने में सहायक होने के लिए कितनी क्रय-शक्ति की आवश्यकता होगी, हमारी औद्योगिक मशीनों के आधुनिकीकरण और विस्तार को जारी रखने के लिए कितनी और किस प्रकार की पूँजी आवश्यक होगी, और हमें, संसार के सबसे धनी राष्ट्र में, कितनी और किस प्रकार की सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

तीन—मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन में इसका भी संकेत होगा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने पर, हमारे संघ, राज्य, और स्थानीय राजस्व में कितनी वृद्धि होगी।

चार—मैं आशा करता हूँ कि 'साधन और पद्धति' समिति हमारी वर्तमान कर-व्यवस्था का विश्लेषण करके सुधारों की सिफारिश करते समय, इस पर भी विचार करेगी कि करो से होने वाली आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा राज्यों और स्थानीय शासन संस्थाओं को कैसे दिया जा सकता है, और औद्योगिक विस्तार तथा विकास के लिए किन विशेष कर प्रोत्साहनों की आवश्यकता हो सकती है।

चूँकी पूँजी के रूप में विनियोजित हर डालर के पीछे कूल राष्ट्रीय उत्पादन में दो डालर वार्षिक की वृद्धि होती है, अतः ऐसा प्रयास हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को उद्दीपित करेगा।

पाँच—मैं आशा करता हूँ कि कर-व्यवस्था की वर्तमान खामियों की ओर जँसे,

व्यापार में खर्च-खाते की जाने वाली बहुत बड़ी कटौतियाँ, गंभीरता से ध्यान दिया जायेगा। कुछ प्रेक्षकों का ख्याल है कि विभिन्न रीतियों से हमें चार अरब डालर वार्षिक की हानि हो रही है।

उह—मैं आशा करता हूँ कि अर्द्ध-एकाधिकारप्रस्त उद्योगों में 'नक्ली' मूल्यों की समस्या के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इन प्रस्तावों को गंभीरता से लेना चाहिये। क्या एकाधिकार सम्बन्धी वर्तमान कानूनों को अधिक व्यापक बनाना चाहिये? एक-एक विशेष 'अतिरिक्त लाभ' कर व्यावहारिक और प्रभावकारी होगा?

सात—इस सम्बन्ध में मैं आशा करता हूँ कि सदन को इस प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर मिलेगा कि हमारी राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए आर्थाङ्गजनक रूप में व्यापक मूल्य या वेतन वृद्धि की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक जाँच की जाय।

आठ—यद्यपि खेती में हमारी प्रमुख समस्या उत्पादन सम्बन्धी नीतियों की है, किन्तु भोजन के उपभोग में काफी बड़ी वृद्धि की सम्भावना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

हमारी खेती का बाहुल्य कम भाग्यशाली देशों में आर्थिक विकास में सहायता देने का, और करोड़ों व्यक्तियों की भूल मिटाने का सशक्त उपकरण हो सकता है। उसे बेकार पड़े रहने देना अशुद्धिमत्तापूर्ण, अनाधिक और अनैतिक है।

हमारे 'अतिरिक्त' भोजन के काफी बड़े हिस्से की यहाँ अमरीका में भी आवश्यकता है। स्कूलों में भोजन देने के कार्यक्रम का विस्तार, और भोजन टिकट योजना अथवा भी हमें दो व्यावहारिक अवसर प्रदान करते हैं कि इस समय खतियों में पड़े हुए नौ—मैं आशा करता हूँ कि सयुक्त आर्थिक समिति के प्रतिवेदन में व्याज की दरों का, और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन, निर्माण, क्रय शक्ति, बेकारी, और सभी स्तरों के सरकारी राजस्व पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।

दस—अन्त में कुछ बातें मैं एक निकट रूप में सम्बन्धित विषय पर कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जल्दी या देर से कांग्रेस को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। वर्षों से साम्यवादी दुनिया को वह यह बजाते आ रहे हैं कि अमरीका को सबसे अधिक भय निरस्तोकरण के आर्थिक परिणामों का है।

मास्को के अनुभार, अंगर सेना के मुख्य कार्यालय से शास्त्रों की माँग आनी बन्द हो जाय, तो अमरीकी उद्योग दीवालिया हो जाएँगे, और अमरीकी मजदूर भूखों मरने लगेँगे। तब पूँजीवाद का पतन और साम्यवाद की विजय अनिवार्य हो जाएगी।

वर्लैं मावर्न के बावजूद, मैं समझता हूँ कि हममें से अधिकांश लोग जैसा मानते हैं, शांति-कालीन अर्थ-व्यवस्था की ओर सन्नमण उससे कहीं अधिक सरल होगा। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के अठारह महीने बाद, हमने 45 प्रतिशत अमरीकी

उद्योगों को युद्ध-कालीन उत्पादन से हटाकर शांति-कालीन उत्पादन में लगा दिया था और सेना से निकले हुए लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को असेनिक अर्थ-व्यवस्था में रखा लिया था ।

निश्चय ही, उस समय हमें यह लाभ था कि मकान, स्कूल, और उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं को युद्ध-काल में संचित मॉर्गों की मात्रा इकट्ठा हो गई थी, जिसकी पूर्ति करनी थी । लेकिन 1945 में हमारी अर्थ-व्यवस्था का जितना हिस्सा प्रतिरक्षा उत्पादन में लगा हुआ था, आज उसका पाँचवाँ भाग ही लगा है । जहाँ तक पुरानी अपूर्ण आवश्यकताओं का सवाल है, हर मेयर, नगर नियोजक, शिक्षक, सड़क इंजीनियर, अस्पताल अध्यक्ष, और समाजशास्त्री जानता है कि उनकी मात्रा विशाल है ।

सिनेटर हम्फ्री की अध्यक्षता में सीनेट की निरस्त्रीकरण समिति ने निरस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सुनवाई की है । मुझे विश्वास है कि इन विषय पर और अधिक अध्ययन से अमरीकी लोग आश्चर्य होंगे और दुनिया को प्रमाण मिलेगा कि शीत युद्ध के तनावों को यथार्थ परक रीति से घटाने के मार्ग में अमरीका नहीं वरन् सोवियत रूस बाधक है ।

अन्त में, हम इस पर विचार करें कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके व्यावहारिक उत्तर प्राप्त करना, व्यविनयो के रूप में, और एक राष्ट्र के रूप में, हमारे लिए बितना महत्त्वपूर्ण है ।

उदाहरण के लिए, अगले वित्तीय वर्ष में रोजगार के ऊँचे स्तर और आर्थिक विकास की तीव्र गति संघीय राजस्व और का संघीय बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अगर 1961 के वित्तीय वर्ष में 4 प्रतिशत विस्तार की गति कायम रहे, तो 1960 में अपेक्षित वृद्धियों के अलावा, 18 से 20 अरब डालर मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन हमें प्राप्त होगा ।

इसमें संघीय कर-अर्थ में कई अरब डालर की वृद्धि होगी । ब्याज की अदामगी में और संघीय सहायता की रकमों में कमी होने से, हमारे पास पर्याप्त धन होगा कि निर्माण कार्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा, और स्वास्थ्य कल्याण और खोज सम्बन्धी अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभा सके, और उसके साथ ही करो में कमी कर सकें, और बजटको सन्तुलित कर सकें ।

अगामी वर्षों में, अगर हम बुद्धिमत्तापूर्ण नीति-निर्देशन कर सकें, जिससे बिना भँहगाई के तीव्र गति से विस्तार हो सके, तो हम करो में और कटौती करने, और राष्ट्रीय ऋण में बहुत दिनों से स्थगित होती आ रही, प्रभावकारी कमी करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ।

अध्यक्ष मरुोदय, यह कोई भेखचिल्ली का सपना नहीं है । यह निरन्तर आर्थिक विकास का बठोर, तथ्यपूर्ण गणित है ।

अपने राष्ट्र की सुरक्षा, और अपने लोगों के कल्याण के लिए जिसकी आवश्यकता

इतनी स्पष्ट है, अलग-अलग रीतियों और कारणों में, उसके लिए प्रयास करने का विरोध करने वाले समूह भी रहेंगे।

वे ऐसा कहकर बांधों, स्कूलों, या मकानों के निर्माण सम्बन्धी हर प्रस्ताव का विरोध करेंगे कि इससे बजट के असन्तुलित हो जाने का, या हानिकारक मॅहगाई आने का भय है। हमारी द्विविधा के मूल कारणों तक पहुँचने के हर प्रयास को वे व्यर्थ या असामयिक घोषित करेंगे।

ऐसा होने देना बड़ी भूल होगी कि अमरीका के भविष्य के बारे में यह भीरु दृष्टि-कोण इस सदन के बहुमत को डर दिखाकर राजनीतिक दृष्टि से निःसक्त बना दे। मेरा निवेदन है कि बिना मॅहगाई लाए, अधिक तीव्र गति से हमारी अमरीकी अर्थ-व्यवस्था का विस्तार इस कांग्रेस को कार्यसूची पर अक्ति पहली चुनौती है।

इस्पात के मूल्य और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था

अगस्त, 1959 की लम्बी इस्पात हड़ताल के चौथे सप्ताह में यह पत्र राष्ट्रपति आइजन हूवर को भेजा गया था। उसमें कांग्रेस-सदस्य वील्स ने सुझाव दिया है कि अर्थ-व्यवस्था और इस्पात उद्योग, दोनों की दीर्घ कालीन मलाई के लिए इस्पात के मूल्य को बढ़ाने के बजाए घटाना चाहिए।

प्रिय श्री राष्ट्रपति,

युद्ध-काल में मूल्य-प्रशासक और आर्थिक स्थिरीकरण के निदेशक के रूप में इस्पात उद्योग में मूल्यों, वेतनों और मुनाफों के उलभे हुए पारस्परिक सम्बन्धों से, हफ्ते-ब-हफ्ते, मेरा निकट सम्बन्ध रहता था। उसके बाद से, इस महत्त्वपूर्ण उद्योग के कार्य-संचालन को देखकर मुझे अधिकधिक परेशानी होती रही है, जिसका हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में रोजगार और विनिर्माण की लागत पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है।

इन चौदह वर्षों में, मालिक-मजदूर मतभेदों के फलस्वरूप, इस्पात उद्योग में छह बार काम बन्द हुआ। एक सौ नब्बे दिनों के उत्पादन की हानि हुई। फलस्वरूप, साढ़े चार करोड़ टन इस्पात का उत्पादन जो हो सकता था, नहीं हुआ, और वेतनों व मुनाफों में करोड़ों डालर की हानि हुई।

वर्तमान गतिरोध का यह चौथा सप्ताह है। अगर जल्दी ही कोई समझौता नहीं हो जाता, तो हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

हम इस समय पिछले दस वर्षों में अपनी तीसरी मन्दी से निकल रहे हैं। स्कावटों के इस सिलसिले के कारण हमारे विकास की औसत वार्षिक गति इतनी कम हो गई है, जितनी पिछले कई दशकों में कभी नहीं रही।

इस्पात के उत्पादन, और इस्पात मजदूर की क्रय-शक्ति में निरन्तर कमी होते रहने से हमारी समृद्धि में और भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त इस्पात का भंडार कम होने पर, अमरीका का लगभग हर उद्योग प्रभावित होगा। मजदूरों और प्रबन्धकों में कट्टा, जो पहले ही चिन्तनीय रूप में अधिक है, और बढ़ जाएगी।

अगर मजदूरों और प्रबन्धकों के समझौते के फलस्वरूप मूल्य बढ़े, तो हमारी अर्थ व्यवस्था पर कुल मिलाकर इसका विपरीत प्रभाव और भी अधिक होगा। 1945 में मूल्य प्रशासन कार्यालय द्वारा नियत सीमा 54 डालर प्रति टन से बढ़कर इम्पात का मूल्य यू० भी 1959 में 155 डालर प्रति टन हो गया है। चौदह वर्षों की इस अवधि में, थोक मूल्यों में हुई वृद्धि की यह वृद्धि चार गुनी है।

1953 से अद्य तक औसत थोक मूल्यों में हुई 9 प्रतिशत वृद्धि में से 7 प्रतिशत इम्पात या इस्पात का प्रयोग करने वाली वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि का फल है। अगर कृषि उत्पादन के थोक मूल्यों में वमी न हुई होती, जो 1953 की तुलना में 9 प्रतिशत गिरे हैं, तो मुख्यतः इम्पात उद्योग द्वारा उत्पन्न की गई मँहगाई की प्रवृत्तियाँ और भी अधिक स्पष्ट होती। इसका अर्थ है कि भोजन के गिरते हुए मूल्य इम्पात के बढ़ते हुए मूल्य को सन्तुलित करते रहे हैं।

वार-वार और व्यापक मूल्य वृद्धियों का कारण पूछे जाने पर, इम्पात उद्योग की ओर से हमेशा कहा जाता है कि प्रति घंटा वेतन की दरें भी तीन गुनी हो गई हैं। वार-वार इस बात के दुहराए जाने के कारण बहुत-से लोग समझने लगे हैं कि ऊँचे मूल्यों के लिए केवल मजदूर ही दोषी है। लेकिन इसमें एक निर्णायक महत्त्व का प्रश्न छूट जाता है—प्रतिघंटा वेतन दरों और श्रम की उत्पादन शक्ति का सम्बन्ध।

निगमों के मुनाफे नई तर्कों द्वारा निर्धारित होते हैं, जहाँतक श्रम की लागत एक तत्व है, महत्त्व श्रम के प्रति घंटा मूल्य का नहीं है, वरन् प्रति दिन इम्पात के उत्पादन में श्रम के मूल्य का है। यद्यपि इसके सही आँकड़े दुनिया के अधिकतम गुप्त भेदों में से हैं, फिर भी बाह्य प्रमाणों से सकेत मिलता है कि वेतन दरों में वृद्धि को बड़ी हद तक श्रम की उत्पादन शक्ति में हुई वृद्धि ने सन्तुलित कर दिया है।

आज हमारे सामने जो स्थिति है, उसमें तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है। अगर हम प्रागे भी इसी तरह दशाहीन चलते रहे, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था की गति और भी धीमी हो जाएगी, और सामान्य पुन-निर्माण के एक निर्णायक बिन्दु पर रोजगार और मुनाफे दोनों के लिए खतरा पंदा हो जाएगा।

इसे केवल प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच एक द्वन्द्व के रूप में देखने पर, यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि पिछले दिनों श्रम की उत्पादन शक्ति में हुई वृद्धि को देखते हुए, बिना मूल्यों में कोई वृद्धि किए, इम्पात उद्योग में वेतनों में वृद्धि होनी चाहिए। उच्च क्षमता स्तर पर काम करते हुए, इम्पात उद्योग तब भी अधिकतम मुनाफे कमा सकता है।

लेकिन मैं समझता हूँ कि जनहित में सर्वोत्तम यह होगा कि वेतन दरों में कोई परिवर्तन किए बिना, इम्पात के मूल्य घटाये जाएँ। इसका प्रमाण स्पष्ट प्रतीत होता है कि इम्पात उद्योग यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाकर अधिकतम मुनाफे कमाता रह सकता है।

स्वभावतः इस प्रस्ताव के प्रति न प्रबन्धकों का दृष्टिकोण उत्साहपूर्ण है, न मजदूरों

का। लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हम सभी को विशेष समूह-हितों के भागे जाकर व्यापक जनहित की दृष्टि से विचार करना चाहिए। मैं गंभीरता से विश्वास करता हूँ कि इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में यह ऐसा ही अवसर है।

इस्पात के मूल्यों में दस डालर प्रति टन की कमी से आगामी शरद ऋतु में मोटरों, कपड़े धोने की मशीनों, रेफ्रिजरेटो, और अन्य घरेलू सामान के मूल्यों में कमी हो सकती है। इससे हमारे सड़क-निर्माण कार्यक्रम, औद्योगिक निर्माण, मशीनी औजारों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत में कमी हो सकती है।

इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को भी वह शक्ति पुनः प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है, जो तभी आ सकती है जब हमारी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा हो, और हमारे लोगो को पूर्णतः रोजगार उपलब्ध हो। स्वयं इस्पात उद्योग में इससे विक्री बढ़ सकती है, ज्यादा लोगों को, ज्यादा टिकाऊ काम मिल सकता है, और इस्पात के आयात में दूसरों का मुकाबला करने में हमारी स्थिति सुधार सकती है।

पिछले कुछ महीनों में हमने मँहगाई के खतरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ आर्थिक विकास के बारे में बहुत कम बात हुई है। मेरा निवेदन है कि दोनों समस्याओं में निकट सम्बन्ध है, और इस्पात मूल्यों को घटाकर आंशिक रूप में दोनों का ही सामना किया जा सकता है।

इस कारण मेरा सादर निवेदन है कि हमारे देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था के दीर्घ-कालीन हित में, आप इस्पात उद्योग से यह साहसपूर्ण, रचनात्मक कार्यवाही करने के लिए कहें।

पुनःनिर्माण करने और शिक्षा को सुधारने के प्रयत्नों की गति धीमी करें, और नीचो भ्रमरीकियों से कहे कि वे कुछ दिन और धीरज रखें ।

व्यवहार में वे कहेंगे—“दुनिया को रोको, हम उतरना चाहते हैं ।” लेकिन दुनिया रुकेगी नहीं, और हमसे सर्वाधिक भय भी उतर नहीं सकते ।

हमारी तेजी से बदलती हुई दुनिया में जितने भयंकर खतरे हैं, उतने इतिहास के किसी अन्य काल में नहीं थे । और न किसी अन्य काल में ऐसे उरसाह्वदंडक अवसर ही प्रदान किए थे कि व्यक्ति का विकास हो, वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा हो, और मानवी शक्तियाँ सामान्य कल्याण के लिए मुक्त हो ।

अतः हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में उदारमना व्यक्ति हमारे और अन्य अ-साम्यवादी राष्ट्रों के बीच अधिक सबल विश्व सहयोग की, अन्य लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण में अधिक रुचि लेने की, और अधिक दृढ़ता की माँग करेंगे, कि हम न केवल सावियत धमकियों का सामना करें, बल्कि देश में भी ज्यादा अच्छा समाज निर्मित करें, जिसमें मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करने को स्वतंत्र हो, चाहे उनकी जाति, धर्म या रंग कुछ भी हो ।

नए सन्दर्भ में लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ की बहस होने पर, नए मतभेदों के प्रकट होने और नए राजनीतिक दृष्टिकोणों के अपनाए जाने पर, हम आशा करते हैं कि उन्हीं का पक्ष सबल रहेगा, जो मनुष्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखते हैं । आज के खतरनाक, उत्तेजक, और सभावनापूर्ण विश्व के सन्दर्भ में, लोक-तान्त्रिक आस्था के संभाव्य फलों को पुनःपरिभाषित करना ऐसे लोगों का कर्त्तव्य है ।

का। लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हम सभी को विशेष समूह-हितों के आगे जाकर व्यापक जनहित की दृष्टि से विचार करना चाहिए। मैं गंभीरता से विश्वास करता हूँ कि इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में यह ऐसा ही अवसर है।

इस्पात के मूल्यों में दस डालर प्रति टन की कमी से आगामी शरद ऋतु में मोटरों, कपड़े धोने की मशीनों, रेफ्रिजरेटरों, और अन्य घरेलू सामान के मूल्यों में कमी हो सकती है। इससे हमारे सड़क-निर्माण कार्यक्रम, औद्योगिक निर्माण, मशीनी औजारों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत में कमी हो सकती है।

इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को भी वह शक्ति पुनः प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है, जो तभी आ सकती है जब हमारी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा हो, और हमारे लोगों को पूर्णतः रोजगार उपलब्ध हो। स्वयं इस्पात उद्योग में इससे विक्री बढ़ सकती है, ज्यादा लोगों को, ज्यादा टिकाऊ काम मिल सकता है, और इस्पात के आयात में दूसरों का मुकाबला करने में हमारी स्थिति सुधार सकती है।

पिछले कुछ महीनों में हमने मँहगाई के खतरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ आर्थिक विकास के बारे में बहुत कम बात हुई है। मेरा निवेदन है कि दोनों समस्याओं में निकट सम्बन्ध है, और इस्पात मूल्यों को घटाकर आंशिक रूप में दोनों का ही सामना किया जा सकता है।

इस कारण मेरा सादर निवेदन है कि हमारे देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था के दीर्घ-कालीन हित में, आप इस्पात उद्योग से यह साहसपूर्ण, रचनात्मक कार्यवाही करने के लिए कहें।

सातवें दशक का नया मोड़

श्री वील्स का कथन है कि युद्धोत्तर काल का अन्त होने के साथ, हमारे समाज में नई शक्तियाँ विकसित हो रही हैं। वे अपील करते हैं कि उनका सामना करने में हम बिसे-पिटे राजनीतिक खेबिलों का परित्याग करें। न्यू हैवेन कॉन्फिटकट में 21 नवम्बर, 1961 को येल लॉफोरम के समक्ष दिया गया भाषण।

दुनिया, अपनी अर्थ-व्यवस्था, और अन्य राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्धों के प्रसंग में, हम एक मोड़ के निकट आ रहे हैं हम युद्धोत्तर काल के अन्त पर पहुँच गए हैं, और अनिश्चयपूर्वक मनुष्य के इतिहास में एक नये युग के प्रवेशद्वार पर खड़े हैं।

मेरा विश्वास है कि हमारे अपने समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विभ्रम दिखाई पड़ते हैं, वे उस हलचल का एक अंग हैं, जो महान् राष्ट्रीय निर्माणों के पहले उत्पन्न होती है।

तीन सशक्त राजनीतिक नीतियाँ हमारे समाज में काम कर रही हैं, जिनमें से किसी के भी बारे में यह संभावना नहीं है कि वह पुराने नारों का शिकार होगी, या परिचित रीतियों से उसका राजनीतिक वर्गीकरण आसानी से हो सकेगा। धीरे-धीरे, हममें से हर एक पर दबाव पड़ रहा है कि हम इन शक्तियों का सामना करें, सार्वजनिक प्रश्नों सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें, निष्फल धारणाओं का परित्याग करें, और नई स्थितियाँ ग्रहण करें।

इनमें से पहली शक्ति युद्धोत्तर कालीन परस्पर सम्यद्ध जगत का हमारे अमरीकी समाज पर पड़ने वाला विशाल प्रभाव है, और उस प्रभाव के अधिक मथाथं परक उत्तर के लिए हमारी सज्ज है।

पिछले पन्द्रह वर्षों से, हममें से बहुतेरे लोग एक-दूसरे को विश्वास दिलाते रहे हैं कि हम जिन विद्वन्-व्यापी दवावों का सामना करने की कोशिश करते रहे हैं, वे अस्थायी हैं, अगर हम बुद्धिमत्ता और साहस से काम करें तो किसी प्रकार दुनिया का संकट समाप्त हो जाएगा, और हम अपनी भौतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए निरद्विग्न और सुखी रह सकेंगे।

यह उत्तरनाक रूप में संकीर्ण दृष्टिकोण कुछ हमारे भ्रमवादी प्रतीत के आकर्षण

के कारण है और कुछ विश्व के मामलों में विकृत दृष्टिकोण के कारण, जो इसलिए उत्पन्न हुआ कि युद्ध के बाद हमने विशेषतः अनुकूल स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना किया था ।

उस समय अमरीकी अर्थ-व्यवस्था ही युद्ध के विनाश से अछूनी थी, युद्धकालीन विशाल पूँजी विनियोजन से सबल हुई थी, और आगे बढ़ने को आतुर थी । अणु-अस्त्रों का एकाधिकार अमरीकी सैन्य शक्ति का दृढ़ आधार था ।

फलस्वरूप, अन्य राष्ट्रों की तुलना में अमरीका की शक्ति बहुत अधिक थी । उस समय दुनिया में शायद ऐसा कुछ भी नहीं था, जो करना चाहने पर नहीं हम नहीं कर सकते थे ।

पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बिलकुल बदल गई है । सातवें दशक के आरम्भ में, एक सशक्त नया यूरोप, रामी भ्रम्यता के बाद पहली बार एक समेकित समाज का निर्माण कर रहा है, सोवियत संघ की औद्योगिक और सैन्य शक्ति केवल हमसे ही कम है, और एक कठोर तथा कट्टु साम्यवादी शासन के अन्तर्गत चीन अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ खतरनाक रूप में प्रभारवादी विचार विकसित कर रहा है ।

साथ ही, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में एक नई चेतना आई है कि निरक्षरता, गरीबी, और बीमारी को खतम किया जा सकता है, और उनके लोगों को नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं ।

फलस्वरूप आज दुनिया में असीमित सभावनाएँ हैं, और गंभीर अनिश्चय हैं । सब, क्या यह आश्चर्य की बात है कि हमसे जो लोग अधिक भीरु हैं, वे उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं, या बौद्धिक घरोंदों में घुन जाना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि वे जब वापस बाहर आएँगे तो दुनिया किसी प्रकार एक पीढ़ी पहले के अधिक व्यथस्थित रूप में वापस आचुकी होगी ?

अतः, हम अब दूसरी शक्ति को देखें, जो मेरे विचार से सातवें दशक में राजनीतिक घटनाक्रम का रूप निर्धारित करने में महायुक्त होगी—हमारी अपनी अर्थ-व्यवस्था में विकसित हो रही शक्तियाँ । इन शक्तियों के दबावों का सामना करने के प्रयास में हम फिर देखते हैं कि बहुतेरी पुरानी धारणाएँ अगर अप्रासंगिक नहीं, तो खोजली प्रतीत होती हैं ।

अपने सर्वोत्तम रूप में काम करते हुए, जिनमें वह सर्वाधिक प्रभावकारी और गतिशील होती है, हमारी पूँजीवादी व्यवस्था योग्य प्रवृत्त, छोटे मुनाफे और अधिकतम संभव मात्रा तक विक्री बढ़ाने के सशक्त प्रयासों पर आधारित रही है, जिसमें मात्रा बढ़ने के साथ मुनाफे भी बढ़ते हैं ।

कुछ उद्योगों में हम अब देखते हैं कि मूल्य और वेतन सम्बन्धी ऐसे हथकण्डों के द्वारा, जिनका प्रायिक लक्ष्य ने शायद ही कोई सम्बन्ध होता है, इस सूत्र का संबंधा परित्याग कर दिया गया है । कुछ उद्योगों में मनमाने मूल्य तय कर दिए जाते हैं, ताकि मुनाफे ज्यादा हों, जबकि 25 प्रतिशत या उससे अधिक उत्पादन क्षमता लेकर पड़ी...

राजनीतिक पुनःस्थापन की इस अवधि में एक तीसरी शक्ति का भी सामना हमें करना पड़ेगा—जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ममकते हैं, उसमें पूर्ण नागरिकता के लिए हमारे नीचो नागरिकों की तेजी से बढ़ती हुई माँगें ।

पाँड़ियों तक जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष की अगुआई गोरे अमरीकी लोग करते रहे, जिनकी अन्तरात्मा कहती थी कि किसी समूह के विरुद्ध भेदभाव उनके नैतिक मिडान्त के विरुद्ध था । अब नीचो अमरीकी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और अपने नीचो सह-नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि हमारे सविधान के अन्तर्गत अपने अधिकारों की माँग करें । नीचो लोग प्रतिमास बढ़ती हुई संख्या में इसका उत्तर दे रहे हैं ।

इसके प्रतिरिक्त, ये स्वर अब केवल हमारे देश में ही नहीं, वरन् सारी दुनिया में सुने जा रहे हैं । जब तक हम उन अमरीकियों को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखते हैं, जिनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे, तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक आस्था सम्बन्धी हमारे दावों को स्वीकार करेंगे ।

इस प्रकार, ये तीन चुनौतियाँ हैं, जो सातवें दशक में अमरीकी लोगों के सामने हैं—दुनिया के साथ हमारे सम्बन्ध, अपनी अर्थ-व्यवस्था की कार्य-क्षमता को सुधारने की हमारी योग्यता; और जाति, विश्वास, या धर्म के आधारों पर किसी अमरीकी के साथ भेदभाव को समाप्त करने के हमारे प्रयास ।

इन प्रश्नों के परस्पर विरोधी उत्तरों से सातवें दशक में लगभग निश्चित रूप में नए राजनीतिक सम्बन्धों का उदय होगा ।

चूँकि 'उदारवादी' 'दक्षियानुसी', 'उग्र', या 'प्रतिक्रियावादी' जैसे पुराने राजनीतिक विशेषणों की प्रासंगिकता तेजी से समाप्त हो रही है, अतः नए दृष्टिकोण जितनी जल्दी विकसित हो, उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा । जो नारे चौथे दशक में हमें प्रभावित करते थे, वे अब अधिकाधिक अमरीकियों को प्रेरित या प्रभावित नहीं कर पाते ।

मेरा यह मतलब नहीं कि जिस प्रकार के राजनीतिक तर्क और कार्य हमें सातवें दशक में प्रभावित करेंगे, उनका अतीत से कोई सम्बन्ध ही नहीं होगा । किसी भी युग में, उदारवाद कुछ माविक मूल्यों में विद्वाम की माँग करता है, जिन्हें हर पीढ़ी को, स्वयं अपने अनुभवों और लक्ष्यों के यथार्थ के दृष्टि में पुनः निरूपित करना पड़ता है ।

अतीत की भाँति, आने वाले दिनों में भी, दक्षियानुसी विचारकों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे अतीत से अधिक प्रेरणा ग्रहण करेंगे, और भविष्य को आशंका की दृष्टि से देखेंगे ।

उनमें से अधिक पराकाष्ठावादी यह माँग करेंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को, और अपने मित्रों के साथ की गई संधियों को छोड़कर निकल जाएँ, अपने नगरों का

रहती है। कुछ ग्रन्थ उद्योगों में मजदूर घान्दोलन कम काम करने के तरीके अपनाता है, जिससे उत्पादन कम होता है, और लागत तथा मूल्य उगी के अनुसार बढ़ जाते हैं।

व्यापक दृष्टि से, यह स्पष्ट है कि हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते रहे हैं जिसमें सशान्ति निहित स्वार्यों के लिए अपने हितों की रक्षा करना संभव होता है, जबकि लाखों लोग बेकार घूमते हैं, और हमारी आवादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से की पर्याप्त भोजन और मकान और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती।

यह पता लगाने के लिए गभीर पुनः निरीक्षण की आवश्यकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के बहुतेरे हिस्से गतिहीन क्यों पड़े रहते हैं, हमारे विकास की गति अधिर्गण्य औद्योगिक देशों की तुलना में पिछड़ क्यों गई है, बीम प्रतिशत अमरीकी परिवारों की आय अथ भी 2000 डालर प्रतिवर्ष से कम क्यों है, और जनसंख्या के कई हिस्सों में बेकारी अब भी दूर क्यों नहीं हो रही है, जबकि अधिकतम संभव उत्पादन की आवश्यकता है।

हमारी घरेलू अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में जिन प्रश्नों की पूछने और उनका उत्तर खोजने की आवश्यकता है, उनमें से कुछ ये हैं:

हम अपने आवास उद्योग को किस प्रकार पुनः संगठित कर सकते हैं, जिससे कम मूल्यों पर प्रतिवर्ष अधिक संख्या में और ज्यादा अच्छे मकान बनें ?

हम अपने नगरों में पुनःनिर्माण में तेजी कैसे ला सकते हैं, जिससे सातवें दशक के अन्दर गन्दी बर्तियाँ समाप्त हो जाएँ ?

हम सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उन लोगों को कैसे प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है ?

और सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम अपनी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को सबल कैसे बना सकते हैं, जिससे सभी प्रतिभाशाली अमरीकी लड़के-लड़कियों को कालेज में प्रवेश करने का अवसर मिले ?

ज्यादा अच्छे उत्तरों के लिए हमारी खोज स्थानीय, राज्य, और संघ शासनों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए हमें मजदूर संगठनों, विश्वविद्यालयों और हमारे व्यापार तथा कृषि संगठनों की सर्वोत्तम बुद्धियों की भी सहायता लेनी चाहिए।

हमारी अर्थ-व्यवस्था वह आवश्यक उपकरण है, जिसके द्वारा हमें अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक अवसरों और सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, पर्याप्त प्रतिरक्षा व्यवस्था निर्मित करनी है, और उन साधनों की व्यवस्था करनी है, जिनसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी गरीबी को मिटाने का प्रयास करने वाले नए राष्ट्रों की बढ़ती हुई दिक्कतों को हम कम कर सकें।

केवल एक आत्म-विश्वासपूर्ण, गतिशील अमरीका ही इस चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन उत्पादन वृद्धि में अड़चन डालने वाली पहले से ही मौजूद बाधाओं ने हमारी प्रगति को रोक रखा है।

राजनीतिक पुनःस्थापन की इस अवधि में एक तीसरी शक्ति का भी सामना हमें करना पड़ेगा—जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समझते हैं, उसमें पूर्ण नागरिकता के लिए हमारे नीग्रो नागरिकों की तेजी से बढ़ती हुई मांगें ।

पीढ़ियों तक जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष की अनुभूति गोरे अमरीकी लोग करते रहे, जिनकी अन्तरात्मा कहती थी कि किसी समूह के विरुद्ध भेदभाव उनके नैतिक सिद्धान्त के विरुद्ध था । अब नीग्रो अमरीकी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और अपने नीग्रो सह-नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत अपने अधिकारों की मांग करें । नीग्रो लोग प्रतिमास बढ़ती हुई संख्या में इसका उत्तर दे रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त, ये स्वर अब केवल हमारे देश में ही नहीं, बरन् सारी दुनिया में सुने जा रहे हैं । जब तक हम उन अमरीकियों को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखते हैं, जिनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे, तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक आस्था सम्बन्धी हमारे दावों को स्वीकार करेंगे ।

इस प्रकार, ये तीन चुनौतियाँ हैं, जो सातवें दशक में अमरीकी लोगों के सामने हैं—दुनिया के साथ हमारे सम्बन्ध, अपनी अर्थ-व्यवस्था की कार्य-क्षमता को सुधारने की हमारी योग्यता; और जाति, विश्वास, या धर्म के आधारों पर किसी अमरीकी के साथ भेदभाव को समाप्त करने के हमारे प्रयास ।

इन प्रश्नों के परस्पर विरोधी उत्तरों से सातवें दशक में लगभग निश्चित रूप में नए राजनीतिक सम्बन्धों का उदय होगा ।

चूँकि 'उदारवादी' 'दक्खानूसी', 'उग्र', या 'प्रतिक्रियावादी' जैसे पुराने राजनीतिक विशेषणों की प्रासंगिकता तेजी से समाप्त हो रही है, अतः नए दृष्टिकोण जितनी जल्दी विकसित हों, उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा । जो नारे चौथे दशक में हमें प्रभावित करते थे, वे अब अधिकाधिक अमरीकियों को प्रेरित या प्रभावित नहीं कर पाते ।

मेरा यह मतलब नहीं कि जिस प्रकार के राजनीतिक तर्क और कार्य हमें सातवें दशक में प्रभावित करेंगे, उनका अतीत से कोई सम्बन्ध ही नहीं होगा । किसी भी युग में, उदारवाद कुछ साविक मूल्यों में विश्वास की मांग करता है, जिन्हें हर पीढ़ी की, स्वयं अपने अनुभवों और तर्कों के यथार्थ के दृष्टि में पुनः निरूपित करना पड़ता है ।

अतीत की भाँति, आने वाले दिनों में भी, दक्खानूसी विचारकों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे अतीत से अधिक प्रेरणा ग्रहण करेंगे, और भविष्य की आगका की दृष्टि से देखेंगे ।

उनमें से अधिक पराकाष्ठावादी यह मांग करेंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को, और अपने मित्रों के साथ की गई संधियों को छोड़कर निकल आएँ, अपने नगरों का

पुनःनिर्माण करने और शिक्षा को सुधारने के प्रयत्नों की गति धीमी करें, और नीचो धमकीयों से बहे कि वे कुछ दिन और धीरज रखें ।

व्यवहार में वे कहेंगे—“दुनिया को रोको, हम उतरना चाहते हैं ।” लेकिन दुनिया रुकेगी नहीं, और हमसे सर्वाधिक भाग भी उतर नहीं सकते ।

हमारी तेजी से बदलती हुई दुनिया में जितने भयंकर खतरे हैं, उतने इतिहास के किसी अन्य काल में नहीं थे । और न किसी अन्य काल ने ऐसे उल्हासपूर्ण अवसर ही प्रदान किए थे कि व्यक्ति का विकास हो, वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा हो, और मानवी शक्तियाँ सामान्य कल्याण के लिए मुक्त हो ।

अतः हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में उदारमता व्यक्ति हमारे और अन्य अ-साम्यवादी राष्ट्रों के बीच अधिक सख्त विश्व सहयोग की, अन्य लोगों की स्वतंत्रता और कल्याण में अधिक रूचि लेने की, और अधिक दृढ़ता की माँग करेंगे, कि हम न केवल सोवियत धमकियों का सामना करें, बल्कि देस में भी ज्यादा अच्छा समाज निर्मित करें, जिसमें मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करने को स्वतंत्र हो, चाहे उनकी जाति, धर्म या रंग कुछ भी हो ।

नए सन्दर्भ में लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ की वृद्धि होने पर, नए मतभेदों के प्रकट होने और नए राजनीतिक दृष्टिकोणों के अपनाए जाने पर, हम आशा करते हैं कि उन्हीं का पक्ष सख्त रहेगा, जो मनुष्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखते हैं । आज के खतरनाक, उत्तेजक, और सभावनापूर्ण विश्व के सन्दर्भ में, लोक-तांत्रिक आस्था के संभाव्य फलों को पुनःपरिभाषित करना ऐसे लोगों का कर्तव्य है ।

दूसरा भाग

ज़िम्मेदार राज्य शासन— विकेन्द्रीकरण की कुंजी

अपने राज्य शासनों के संयन्त्र को अपने समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में हम पिछड़ गए हैं ।

फलस्वरूप, कई अवसरों पर जनमत ने सध शासन को मजबूर किया है कि वह ऐसी समस्याओं को अपने हाथ में ले, जिन पर राज्यों की राजधानियों में कार्यवाही करना ज्यादा अच्छा होता । वाशिंगटन में केन्द्रित शक्ति में वृद्धि होने का कारण बहुधा हमारी असफलता में देखा जा सकता है कि राज्यों की शासकीय पद्धतियों को हम अपने काल के अनुरूप नहीं बना सके ।

9 मार्च, 1950

गवर्नर का कार्य, एक गवर्नर की दृष्टि में

कॉनेक्टिकट के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों का मिहावलकन करते हुए श्री बील्स अपने नए कार्य की जिम्मेदारियों, खतरों, और अवसरों का निवेदन करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स मंगलवार, 24 जुलाई, 1949।

पिछले नवम्बर मास में कॉनेक्टिकट का गवर्नर बन गया, जो मेरे दल, मतदाताओं, और स्वयं मेरे लिए कुछ आश्चर्य की बात थी। मैं बहुत कम, 2,225 वोटों के बहुमत से जीता। कॉनेक्टिकट में चुनावों के आधुनिक इतिहास में इससे कम बहुमत का केवल यही दृष्टान्त है।

सारे देश की भाँति, कॉनेक्टिकट के रिपब्लिकनों को पूर्ण विश्वास था कि वे जीतेंगे। कॉनेक्टिकट 'स्थिर आदतों की भूमि' है, और पिछले एक सौ वर्षों में केवल स्पारह डेमोक्रेटिक गवर्नर हुए थे।

मैंने गवर्नर का चुनाव लड़ा, इसलिए नहीं कि मेरे विचार में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के 1948 में सफल होने की कोई उम्मीद थी—कॉनेक्टिकट में तो और भी नहीं—बल्कि अन्य कई कारणों से, जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे।

अधिकांश अन्य राज्यों की भाँति, कॉनेक्टिकट के सामने कुछ गंभीर समस्याएँ थीं। स्कूलों और अस्पतालों की बड़ी कमी थी, जिसे हमारे नगर बिना सहायता के पूरी नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ मकानों की कमी अन्य राज्यों से भी अधिक थी—और हमारे यहाँ गन्दी बस्तियाँ भी अनुपात से अधिक हैं। दो पीढ़ी पूर्व या और भी पहले बनाये गए, पुराने पिजडेनुमा मानसिक अस्पतालों की जगह आधुनिक मानसिक अस्पतालों की बड़ी आवश्यकता थी। बढ़ती हुई बेकारी का सामना करने के लिए व्यापक धर्म कानूनों की, और वृद्धावस्था की सहायता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता थी।

मैं अनुभव करता था कि ऐसी समस्याओं को राज्य द्वारा हल किया जा सकता है, और करना चाहिए। वाशिंगटन में शासन का अल्पधिक केन्द्रीकरण खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर कोई राज्य शासन करने लोगों के लिए मकानों की उचित

व्यवस्था नहीं कर पाता, या धरने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, या वृद्धों की देख-भाल नहीं कर पाता, तो संघ शासन को आतिरकार मजबूरी में, या राज्य कार्य-वाही के अभाव में कदम उठाना पड़ता है।

मेरे समझता हूँ कि वाशिंगटन में शासन के अत्यधिक केन्द्रीकरण को रोकने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय यह है कि सामान्यतः राज्य शासनों की कार्यक्षमता में सुधार किया जाय।

मुझे आशा थी कि अगर कॉनेक्टिकट में और अन्य राज्यों में, अपनी समस्याओं का सामना करने में जिम्मेदारी और कार्य कुशलता के काफी ऊँचे प्रतिमान स्थापित किये जाएँ, तो वाशिंगटन की और देखने की आवश्यकता कम पड़ेगी।

जब चुनाव में अपनी जीत का अचम्भा कम हुआ, और मैंने अपने काम पर नज़र डाली, तो मुझे दो तात्कालिक काम नज़र आए। पहला काम यह था कि जिस मंच के आधार पर मैं चुना गया था, उसे कार्यान्वित करने के लिए एक विधायक कार्यक्रम बनाऊँ। दूसरे, मुझे राज्य का बजट तैयार करना था।

मुझे उम्मीद थी कि दोनों ही कामों में बड़ी कठिनाइयाँ सामने आएँगी। कारण यह था कि कॉनेक्टिकट की सीनेट में तो डेमोक्रेटिक दल का अच्युत बहुमत था, लेकिन प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकनों का विद्याल बहुमत था।

इन दो जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, मैं केवल इतना जानता था कि मेरा काम यथाशक्ति सक्षम रीति से राज्य का शासन चलाना है, और विधानमंडल की अनुमति से, प्रशासकीय कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए, जो भी सगठनात्मक परिवर्तन हो सकें, करने थे। लेकिन पिछले छह महीनों के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि गवर्नर के काम में और भी बहुतेरे कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ, सिरदर्द और सन्तोष शामिल हैं।

गवर्नर की जिन्दगी के सर्वाधिक सतोपजनक पक्षों में से एक यह है कि सारे राज्य से लोग निरन्तर उससे मिलने आते हैं। वस्तुतः गवर्नर का दफ्तर देखने में, और बहुधा सुनने में भी, न्यू इंग्लैण्ड की किसी निरन्तर चल रही नगर-सभा जैसा लगता है।

गवर्नर के काम के इस अंग को देखकर मुझे और भी अधिक विश्वास हो गया है, कि वाशिंगटन की कोई एजेन्सी राज्य शासन का स्थान नहीं ले सकती। राज्य शासन में, विशेषतः कॉनेक्टिकट जैसे छोटे-से राज्य में, आप उन दृष्टिकोणों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहते और काम करते हैं, जो अन्ततः सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करते हैं।

जब वे समझने हैं कि आप सही हैं, और विशेष रूप में जब वे समझते हैं कि आप गलती पर हैं, तो वे सीधेना से अपनी राय आप तक पहुँचा देते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र है—सीधे बात, और कोई रोक-टोक नहीं।

इसके अलावा, हर गवर्नर की भाँति, मैं अपने दल के नेता के रूप में काम करता हूँ। यह जरूरी है कि मेरे दिल के विधायक, और मेरे दल के नगर अध्यक्ष तथा

राज्य और स्थानीय शाखाओं के अन्य पदाधिकारी किसी भी समय मुझ से मिल सकें, और राजनीतिक निर्णय लेने में मैं उनकी सहायता करूँ।

विधानमण्डल की बैठक के दिनों में रोज सुबह मैं उसके डेमाक्रैटिक नेताओं से मिलता, और विधानमण्डल में उनकी उस दिन की कार्यनीति के सम्बन्ध में चर्चा करता। (रिपब्लिकन नेता भी निमंत्रित किए जाते थे, लेकिन वे बहुत कम अवसरों पर आते।) सत्र के दिनों में किसी भी समय समितियों के अध्यक्ष अथवा, शिक्षा, आवास या अन्य विधेयको के सम्बन्ध में किसी नए विधायक सकट को लेकर मेरे पास आते, जिसमें उन्हें शीघ्र उत्तर की आवश्यकता होती।

गवर्नर के ये सभी अतिरिक्त, और विशेष कर्तव्य दिलचस्प, रोचक, और आवश्यक हैं। किन्तु गवर्नर के मूल कार्यों के साथ जुड़ जाने पर इनका बोझ अवश्य ही बहुत अधिक हो जाता है।

मैं शुरू से ही जानता था कि प्रशासन को सुधारने का काम आसान नहीं होगा। कॉन्विकट की 108 एजेन्सियों से ऐसा प्रशासकीय संयन्त्र बन गया है जिससे हबो गोल्डबर्ग को भी अचरज होगा। एजेन्सियों के आठ सौ अध्यक्ष या कमिश्नर हैं, जो कम से कम सिद्धान्त रूप में, सीधे मुझ को उत्तरदायी हैं। अगर मैं 'मन्त्रिपरिषद् की बैठक' बुलाने का साहस करूँ, तो सभ्यतः सारे ही आठ सौ को बुलाना होगा। इनमें से बहुतेरी एजेन्सियाँ तो कुकुरमुत्ते की तरह अपने-आप ही 'उग आईं' हैं। कुछ की रचना स्पष्टतः राजनीतिक कारणों से हुई है।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही दलों के मुशासन में रुचि रखने वाले कॉन्विकट के बहुतेरे नागरिकों ने राज्य के इस खर्चिले, तारतम्यहीन संयन्त्र को सुधारने की चेष्टा की है। गवर्नर विल्बर ब्रास ने चौथे दशक में इसकी कोशिश की थी, और कुछ प्रगति भी हुई थी। मैंने फिर कोशिश करने का निर्णय किया।

अपने सर्वप्रथम कार्यों में से एक में मैंने विधानमण्डल से अनुरोध किया कि राज्य की एक 'हूवर समिति' के द्वारा शासन को पुनः सगठित किया जाय। शासकीय मित-व्ययिता में रुचि रखने वाले कुछ करदाता समूहों को भी दबाव डालने पर, विधानमण्डल इसके लिए सहमत हो गया। समिति को अगले वर्ष के प्रारम्भ में अपनी सिफारिशें पेश करनी हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे, तो 1951 तक संभव है कि कॉन्विकट का शासन कुछ अधिक गतिशील दिखाई पड़े।

एक अन्य प्रशासकीय दिक्कत यह थी कि मेरे सोलहो मुख्य कमिश्नर रिपब्लिकनो द्वारा नियुक्त किये गए, और स्वयं भी रिपब्लिकन थे। उनमें से कुछ तो घोषित रूप में मेरे सामान्य कार्यक्रम और नीतियों के विरुद्ध थे। इनमें कई योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ क्या यह रीति बंसी ही नहीं है, जैसे क्रिसलर कम्पनी द्वारा नियुक्त विदेशक मण्डल को लेकर जनरल मोटर कम्पनी को चलाने की चेष्टा की जाय।

मेरा सबसे बड़ा, और निश्चय ही सबसे बठिन काम यह था कि मैं एक विधायक कार्यक्रम तैयार करूँ, और स्वीकृत कराऊँ। अपने प्रथम सन्देश में मैंने एक कार्यक्रम

निरूपित किया, जिसे तैयार करने के लिए मैं लगभग चुनाव के दिन से ही काम करता रहा था।

इस कार्यक्रम को डेमोक्रेटिक दल, श्रीर सीनेट का, तथा कोई सशक्त स्वतंत्र नागरिक समूहों का भी दृढ़ समर्थन प्राप्त था। सीनेट में डेमोक्रेटिक बहुमत होने के कारण, मैं सीनेट द्वारा कार्यक्रम के समर्थन पर भरोसा कर सकता था। लेकिन रिपब्लिकनों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि सभा का मामला भिन्न था, श्रीर उसे राह पर लाना असम्भव साबित हुआ।

इसका कारण वह है कि जिसे प्रगतिशील रिपब्लिकन श्रीर डेमोक्रेट दोनों ही 'सड़ी हुई नगर व्यवस्था' कहते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, 1850 के पूर्व स्थापित कोई भी कस्बा, चाहे जितना छोटा हूँ, प्रतिनिधि सभा में दो सदस्य भेज सकता है। चूँकि प्रह-युद्ध के समय से, कॉन्वेंटिकट के लगभग सभी छोटे कस्बों का विशाल बहुमत रिपब्लिकन रहा है, श्रीर चूँकि उनकी संख्या बड़े शहरों से बहुत अधिक है, अतः सदन में हमेशा एक पहले से ही मौजूद रिपब्लिकन बहुमत सुरक्षित रहता है।

यद्यपि प्रतिनिधि-सभा के दो-तिहाई सदस्य रिपब्लिकन हैं, लेकिन वे केवल एक तिहाई लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉन्वेंटिकट के पाँच सबसे बड़े शहरों में हमारी जन-संख्या का लगभग 35 प्रतिशत रहता है। लेकिन प्रतिनिधि सभा के 35 प्रतिशत सदस्य चुनने के बजाए, वे तीन प्रतिशत से भी कम सदस्य चुनते हैं।

मुझे स्वयं छोटे कस्बों से बड़ा प्यार है। वस्तुतः मैंने स्वयं एक छोटे से कस्बे एसेक्स में रहना पसन्द किया, जिसकी आवादी कुल 3,100 है। फिर भी, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता कि कुल 2,523 पुरुष, स्त्रियाँ श्रीर बच्चों की जनसंख्या वाले, यह सबसे छोटे कस्बों के बारह प्रतिनिधि कुल 6,56,000 आवादी के पाँच सबसे बड़े शहरों के दस प्रतिनिधियों को मतदान में हरा दें, जैसा कि ग्राम तौर पर होता है।

विधानमण्डल के सत्र में वह चाहे जो कुछ भी कहे या करें, कॉन्वेंटिकट की प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन विधायक दल के किसी नेता के सामने इसकी दूरस्थ सभावना पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं आती, कि चुनाव में उसकी हार हो सकती है। यह स्थिति कल्पनापूर्ण, जिम्मेदार लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है।

मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, कि इस व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकारें गंभीरता से विचार करें। अपनी शासकीय समस्याओं के हल के लिए वॉशिंगटन की ओर देखने की वर्तमान आवश्यकता का आगे चलकर यह परिणाम हो सकता है कि शासकीय शक्ति का खतरनाक अति केन्द्रीकरण हो जाय।

अगर हम यह मानकर चलते हैं कि सार्वजनिक समस्याओं को हल करना आवश्यक है, तो इसके पक्ष में प्रबल तर्क है कि उनमें से यथासंभव अधिक से अधिक को राज्यों के माध्यम से हल किया जाय। लेकिन राज्य उस समय तक प्रभावकारी और पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर सकेंगे, जब तक उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें इस योग्य नहीं बनाती कि उनके नागरिकों की इच्छा श्रीर संकल्प उनमें परिलक्षित हो।

कॉन्वेंटिकट में हम ऐसी व्यवस्था प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं।

हमारे स्कूलों की चुनौती

युद्धोत्तर काल में कॉनेक्टिकट में स्कूलों के गंभीर अभाव ने वित्त-व्यवस्था और राजनीति की बड़ी कठिन समस्याएँ प्रस्तुत कीं। गवर्नर यौल्स ने नवम्बर, 1949 में राज्य विधान-मंडल का एक विशेष 'स्कूल' सत्र बुला कर, उसमें यह सदेश प्रस्तुत किया। कॉनेक्टिकट के लगभग दो-तिहाई बच्चे अब ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो इसके कुछ सप्ताह बाद स्वीकृत कानून के अन्तर्गत बनाए गए।

हम यहाँ कॉनेक्टिकट की महासभा में इस विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं कि अपने राज्य में सार्वजनिक शिक्षा पर गंभीर प्रभाव वाले कदमों पर विचार करें।

न केवल कॉनेक्टिकट के लिए, बरन् सम्पूर्ण राष्ट्र और दुनिया के लिए, शायद इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई एक विषय नहीं है। अगर हम इस समय अपनी शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही नहीं करते, तो हम अपने लोकतांत्रिक शासन के भविष्य को खतरे में डाल देंगे।

पिछले तीस वर्षों से, बिना किसी बड़ी सफलता के, हम जिन समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, स्पष्टतः हमारे बच्चों को भी बहुसंख्यक उतनी ही उलझी हुई, बल्कि शायद और भी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अतः, जब हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, तो दरअसल हमारे सामने सवाल यह होता है कि भविष्य की समस्याओं का सामना करने के लिए, हम अपने बच्चों को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। कोई भी समुदाय, राज्य या राष्ट्र अपने भविष्य के कल्याण के लिए जो सर्वाधिक लाभकारी विनियोजन कर सकता है, हम उसकी चर्चा करके निर्णय करने को एकत्रित हुए हैं।

लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जिनका कहना है कि जो शिक्षा-व्यवस्था हमारी पीढ़ी के लिए काफी अच्छी थी, वह हमारे बच्चों के लिए भी अवश्य ही काफी अच्छी होगी। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण का कोई तार्किक आधार नहीं है। हमारे पितामहों को छोटे-छोटे स्कूलों में पुराने किस्म की जो शिक्षा मिली थी, आजके बच्चों को भी वही शिक्षा देकर हम यह आशा नहीं कर सकते कि उससे वे कल अगु-मुग की समस्याओं का सामना कर सकेंगे।

इसके प्रतिरिक्त, आज हमारे सामने हमारी सार्वजनिक शिक्षा के गुणात्मक ह्रास की भी आशंका है। हम न केवल भागे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बरन् हमका गंभीर मनना है कि हम पीछे हटने लगें।

जैसा मैंने बार-बार जोर दिया है, हमें अपने अध्यापक-प्रशिक्षण को, अध्यापकों की भर्ती को, और शिशु कक्षाओं से लेकर विद्विद्यालयों तक अपनी शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम को पुष्ट करना होगा।

इसके प्रतिरिक्त, हमें स्कूलों के लिए पर्याप्त इमारतों के बढ़ते हुए अभाव की समस्या का भी सामना करना होगा। बुरे स्कूल में अच्छी शिक्षा संभव है, और अच्छे स्कूल में बुरी शिक्षा भी हो सकती है। फिर भी, कनिक्टिकट में शिक्षा के स्तर को कायम रखने और सुधारने के लिए स्कूली इमास्तों के निर्माण की बहुत अधिक बढ़ाना एक तात्कालिक आवश्यक कदम है, और यही आज के इस विशेष संदेश का विषय है।

स्कूली इमारतों के लिए राजकीय सहायता की सामान्य समस्या निश्चय ही बड़ी उलझी हुई है। इसका अन्तिम हल प्राप्त करने के पहले कई प्रश्नों पर विचार करना होगा। मैं संक्षेप में इन प्रश्नों पर दृष्टि डालूंगा।

पहला प्रश्न है कि हमारी स्कूली इमारतों को बढ़ाने और प्राधुनिक बनाने की आवश्यकता कहाँ तक है। इसी प्रश्न पर असहमति का कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता।

स्थानीय स्कूल बोर्डों के पिछले प्रतिवेदन में हमारी स्कूलों सुविधाओं की अपर्याप्तता की ओर विशेष ध्यान खींचा गया है। उसमें कहा गया है कि हमारे वर्तमान स्कूलों में से लगभग एक चौथाई उन्नीसवीं सदी में बने थे। अब भी एक कमरे वाले पंचपन स्कूलों का उपयोग हो रहा है। चौथे दशक में हमने अपनी स्कूलों इमारतों की देख-रेख और उन्हें बढ़ाने के लिए बहुत कम काम किया, और पिछले दस सालों में और भी कम स्कूल बनाये गए हैं। इसके साथ ही, हमारे स्कूली बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस समय भी हमारे बच्चों को उचित शिक्षा-सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं, और हालत निरन्तर बिगड़ती जाएगी। हमारे बहुतेरे नगरो और कस्बों को नियमित कक्षा-भवनों के बाहर कक्षाएँ लगानी पड़ती हैं, और कई स्कूलों में कक्षाएँ तहखानों में, नगर-सभा-स्थलों में, जहाँ तक कि खतियों और गुमल-खानों में भी लगाई जाती हैं। ये ज्ञात तथ्य हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, प्रतिवेदन में संक्षेप में बताया गया है कि स्थानीय स्कूल बोर्डों के सदस्यों का राय में, अगले दो वर्षों में, और अगले दस वर्षों में, कितनी नई स्कूलों इमारतों की जरूरत होगी। ये संख्याएँ काफ़ी बड़ी हैं। उनसे पता चलता है कि स्कूली इमारतों के निर्माण के एक बड़े कार्यक्रम को, अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष नहीं, बल्कि अभी शुरू करने की जरूरत है।

दूसरा सवाल है कि इस उद्देश्य के लिए क्या राज्य की सहायता जरूरी है। यद्यपि ऐसे नगर कम ही हैं जो सचमुच ऋण की कानूनी सीमा तक पहुँच गए हैं, किन्तु ऐसे नगरों की संख्या कहीं अधिक है, जो ऋण लेने की व्यावहारिक आर्थिक सीमा तक पहुँच गए हैं या जल्दी ही पहुँच जाएँगे। इसके अलावा, हम यह भी जानते हैं कि कई स्थानीय शासनों को पहले ही सम्पत्ति कर को आर्थिक सीमा तक बढ़ाना पड़ा है।

अधिकांश मामलों में, हमारे नगरों और कस्बों के सामने न केवल स्कूली इमारतें बनाने के काफी बड़े कार्यक्रम हैं, बल्कि पूंजी की अन्य बड़ी आवश्यकताएँ भी हैं, जैसे पानी और सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार और विस्तार, दमकल और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक इमारतें आदि। स्थानीय स्कूल बोर्डों द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी से इन सामान्य स्थितियों का पता चलता है।

विशिष्ट रूप में, 116 नगरों और कस्बों के स्कूल बोर्डों का कहना है कि स्कूल निर्माण के आवश्यक कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्हें राज्य की सहायता मिलनी आवश्यक है। अन्य सत्रह कस्बों के कयनों से भी यह नतीजा निकाला जा सकता है कि उनके लिए राज्य की सहायता आवश्यक है। केवल सात का स्पष्ट रूप में कहना है कि सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः यह बात बिलकुल साफ है कि अगर कॉनेक्टिकट राज्य, अन्य कई राज्यों की भाँति स्कूल निर्माण कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की वित्तीय सहायता नहीं करता, तो इन स्कूलों का निर्माण नहीं हो सकेगा।

तीसरा प्रश्न है कि क्या हमारे सभी नगरों और कस्बों को सहायता की एक समान आवश्यकता है। उत्तर स्पष्ट है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में हमारे नगरों और कस्बों में बड़ी विभिन्नता है। हमारे कुछ नगर बहुत धनी हैं, और कुछ बहुत गरीब, और बहुतेरे इनके बीच में हैं। खर्च करने की हर समुदाय की योग्यता का निर्णय हमें मुख्यतः इस आधार पर करना होगा कि उसके आकार की तुलना में, उसका मूल कराधान योग्य धन कितना है।

हमारे लोकतांत्रिक समाज में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह धनी कस्बे में रहता हो, या निर्धन कस्बे में। अतः हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कॉनेक्टिकट के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें राज्य की सहायता का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति अपने आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति करने की वित्तीय क्षमता विभिन्न समुदायों में एक जैसी हो जाय।

अब हम चौथे सवाल को देखें। अगर स्कूलों का निर्माण करने के लिए नगरों को राजकीय सहायता की आवश्यकता है, तो क्या कॉनेक्टिकट राज्य वास्तव में इस समय सहायता देने की स्थिति में है?

इस प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ नीचे लिखे तथ्यों में मिल जाएगा। शिक्षा में धन

लगाने की हमारी योग्यता का हमारी धाय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। कनिष्ठक के लोगों की कुल धाय पिछले दश वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गई है। फिर भी, यद्यपि शिक्षा में एक स्पष्ट सकट हमारे सामने है, हम दश वर्ष पहले वही कम समृद्धि की अवस्था में शिक्षा पर अपनी धाय का जितना हिस्सा लगाते थे, आज शिक्षा के ग्रंथ का अनुपात उससे काफ़ी कम है।

इसमें संदेह की गुजाइश बहुत कम है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कनिष्ठक के लोग अधिक धन लगाने की स्थिति में हैं।

पाँचवा प्रश्न है—राज्य द्वारा कितनी सहायता दी जाय ? और इसके लिए धन कैसे प्राप्त किया जाय ? मेरा अपना विचार है कि समानता लाने वाली पद्धति के आधार पर, नगरो और बस्वों को राज्य की सहायता का प्रोत्साहन स्कूल निर्माण की लागत के एक-चौथाई से लेकर धाधे तक होना चाहिए। विनिष्ट मामलों में सहायता इस शीसत से कम या ज्यादा हो सकती है।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए अपने खर्चों में कटौती करके हम आवश्यक धन प्राप्त करें। धाय में से जिनकी राय ऐसी हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वे साफ-साफ बताएँ कि धाय राज्य की वर्तमान सेवाओं में कहाँ कटौती करेंगे और किस हद तक।

उदाहरण के लिए, क्या धाय राज्य की पुलिस के खर्चों में कमी करेंगे ? क्या धाय हमारे वृद्धों और दुर्भाग्यशाली लोगों के कल्याण के लिए किये जाने वाले भुगतानों के खर्च में कमी करेंगे ? अगर हाँ, तो कितनी ? क्या धाय राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कटौती करेंगे ? बेकारी के मुद्दों और मजदूरों के मुद्दों के कार्य-क्रमों में ? राष्ट्रीय रक्षा दल में ? पर-निर्भर बच्चों को दी जाने वाली सहायता में ? धाय में से कुछ लोग, जो जानते हैं कि हमारे बजट को सन्तुलित रखना कितना कठिन है, और यह भी कि महत्वपूर्ण राज्य सेवाओं को खतरे में डाले बिना खर्चों में कोई बड़ी कटौती करना संभव नहीं है, यह सुझाव रखते हैं कि कर वृद्धि के द्वारा स्कूल निर्माण की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय।

यह एक सच्चा-सीधा दृष्टिकोण है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि प्राथिक ढिलाई की इस अवधि में कर वृद्धि से सारे राज्य में व्यापार और रोजगार के सुधार में गभीर बाधा आएगी। इसके प्रतिरिक्त, मैं समझता हूँ कि कर वृद्धि अनावश्यक है। बजट निदेशक को इस समय जैसी आशा है, अगर हमारी राजस्व सम्बन्धी स्थिति उससे वही अधिक विगड़ नहीं जाती, तो मेरा विश्वास है कि सावधानी से प्रबन्ध करके, और समुचित विधायक कार्यवाही के द्वारा हम अपने धाय-व्यय को सन्तुलित रख सकते हैं।¹

1. गवर्नर बोल्ट के प्रशासन काल में कानिष्ठक उन तीन राज्यों में से एक था, जिन्होंने बिना कर वृद्धि के अपने बजट को सन्तुलित किया।

समस्या को हल करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। मेरा मतलब स्थानीय रूप में निर्मित स्कूलों के खर्च में राज्य के हिस्से की अदायगी किस्तों में करने की पद्धति से है।

जब कोई व्यापार-संस्था अपने कारखाने को बढ़ाती है, तो वह आमतौर पर कर्ज ले लेती है, और कारखाने के उपयोगी जीवन-काल में, कई वर्षों की अवधि में उस कर्ज को अदा करती है। जब कोई परिवार कोई घर खरीदता है, तो आमतौर पर उसे रेहन रखकर धन की व्यवस्था करता है, और कई वर्षों में उसे अदा कर देता है। कनेक्टिकट में हम इस समय इसी तरीके से अपने शिक्षक कॉलेजों, व्यवसायिक स्कूलों और कनेक्टिकट विश्वविद्यालय के नए हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं। स्कूल निर्माण के लिए हमें ढाई करोड़ डॉलर वार्षिक राज्य कोष की आवश्यकता पड़ेगी। यह धन भी हम इसी रीति से प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब व्यक्तिगत रूप में हर विधायक की, और हर राजनीतिक दल की निष्ठा की परीक्षा है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को पुष्ट करना चाहते हैं, तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं या नहीं ?

प्रश्न बिलकुल साफ और असन्दिग्ध है, और इसमें सचमुच गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। लगभग एक वर्ष से हम लोग स्कूलों के निर्माण की बात कर रहे हैं। हर कदम पर हम आग्रहपूर्वक कहते रहे हैं कि अब कार्यवाही होनी चाहिए। हम अब उस स्थिति पर आ गए हैं, जहाँ आम लोगों की भाषा में या तो काम होना चाहिए, या बहस बन्द होनी चाहिए।

इस सब के प्रारम्भ होने के समय, हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि मैं आपको साफ-साफ बताऊँ कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मेरी राय क्या है, और अधिक से अधिक तथ्य जो मैं प्राप्त कर सकूँ, आपके सामने प्रस्तुत करूँ।

यह मैंने कर दिया है। अब क्या होता है, यह आपके हाथ में है।

कानेक्टकट में मकानों के अभाव की पूर्ति

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा मकानों की माँग 1948-49 में एक तीव्र राजनीतिक प्रश्न था। इस लेख में बताया गया है कि कम कीमत पर मकान बनाने और स्वामित्व का एक प्रभावी कार्यक्रम कानेक्टकट शासन ने किम प्रकार विकसित किया। इस तरह का प्रयास किसी राज्य शासन द्वारा शायद ही कभी किया गया था। सत्तर हजार स्त्री पुरुष और बच्चे अब इस विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए गए मकानों में रह रहे हैं। नवम्बर, 1950 में प्रकाशित 'टू थर्ड्स ऑफ ए नेशन' शीर्षक परिचर्चा से।

सांजनिजक आवास कार्यक्रमों में क्या हमारे राज्य शासनों का कोई योग हो सकता है ? इस प्रश्न पर न केवल आवास की समस्या में रुचि रखने वालों को, वरन् उन सभी लोगों को सावधानी से विचार करना चाहिए, जो केन्द्रीय शासन पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता से चिन्तित हैं।

आम तौर पर, राज्य कार्यक्रमों द्वारा नहीं, वरन् सघ-नगरपालिका कार्यक्रमों के द्वारा गन्दी बस्तियों की सफाई की जा रही है, कम कीमत के मकान बनाए जा रहे हैं, निजी निर्माण कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और मध्य-वित्त वाले लोगों की कठिन आवास समस्या को हल करने की चेष्टा की जा रही है।

गन्दी बस्तियों की सफाई, पुनर्विकास, मकान सम्बन्धी खोज, मकान बनाने और खरीदने वालों के लिए रेहन ऋण कार्यक्रम आदि के लिए सघ शासन इतनी, इस प्रकार की, और ऐसे रूप में सहायता प्रदान करता है, जो हमारी वर्तमान कर व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकान्त राज्यों की क्षमता के बाहर है।

लेकिन कानेक्टकट के गवर्नर के रूप में अपने अनुभव से मुझे विश्वास हो गया है कि कोई जिम्मेदार मुचालित राज्य शासन काफी बड़ा आवास कार्यक्रम आरम्भ कर सकता है, और घन की व्यवस्था करके चला सकता है। ऐसा कार्यक्रम सघीय और स्थानीय कार्यक्रमों का एक आवश्यक और मूल्यवान पूरक होगा।

उदाहरण के लिए, कोई सश्रम और सक्रिय राज्य शासन, उधार लेने के अधिकार का उपयोग करके, बिना करदाताओं पर बोझ डाले, सामान्य आय वाले लोगों के

लिए प्रति उत्तम आवास कार्यक्रम चला सकता है। छोटे पैमाने पर वह नए कार्यक्रमों और वित्तीय पद्धतियों का परीक्षण कर सकता है, जिसका प्रयास करना संघ शासन के लिए अभ्यावहारिक होगा।

नित्य-प्रति के प्रत्यक्ष सम्पर्कों के द्वारा, जो दूरस्थ मध्य शासन के लिए असम्भव है, वह स्थानीय आवास अधिकरणों के काम के स्तर को उठा सकता है, और उनके कार्यों को समन्वित कर सकता है। और वह संघीय अनुदानों के साथ पूरक धन की व्यवस्था करके, तथा स्थानीय अधिकारियों को ऐड लगाकर, और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देकर गन्दी बस्तियों की सफाई, पुनर्विकास, और कम किराए वाले मकानों की व्यवस्था को और आगे बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न केवल आवास समस्या का ही नहीं है, वरन् लोअर-मिडिल क्लास शासन सम्बन्धी हमारी धारणा के मर्म तक, विशेषतः राज्य और संघीय शक्तियों के सम्बन्धों तक जाता है। संघ शासन से कहना कि वह नगर शासनों के साथ मिल कर सार्वजनिक आवास कार्यक्रम का पूरा बोझ उठाए, इसमें न केवल हम राज्य शासन के एक ऐसे पक्ष की अवहेलना करते हैं, जो भेरी राय में बड़ा महत्वपूर्ण है, वरन् इसके साथ ही वाशिंगटन के ऊपर और अधिक निर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं।

कॉन्वेक्टिकट में आवास सम्बन्धी बड़े ही तीव्र विधायक और राजनीतिक विवादों को दो वर्ष तक सुनने के बाद, मुझे अब कोई गलतफहमी नहीं है कि राज्य का आवास कार्यक्रम आसानी से चलाया जा सकता है। राज्य प्रशासनों में, और राज्य के राजनीतिक दलों में भी राज्य आवास कार्यक्रमों के विरोधी उतने ही दृढ़ और मुखर हैं, जितने वाशिंगटन में।

फिर भी, जब मैं दस हजार साफ, अच्छे, राज्य के धन से बने मकानों की पहली किश्त में 2500 उत्कृष्ट कॉन्वेक्टिकट परिवारों को प्रवेश करते देखता हूँ तो भावोद्वेग के साथ इतना ही कह सकता हूँ कि गतिशील लोकतांत्रिक समुदायों के निर्माण में राज्य के आवास कार्यक्रम का जो योग हो सकता है, उसे देखते हुए अगर कुछ विधायक और राजनीतिक सिरदर्द होते भी हैं तो कोई विशेष बात नहीं।

अमरीकी लोगों का यह दृढ़ और उचित विश्वास है कि उचित मूल्य या किराए पर अच्छे मकानों की व्यवस्था का हमारे स्वतन्त्र समाज के स्वास्थ्य में आधारभूत महत्व है। वे अनुभव करते हैं कि जब निजी साधनों से ऐसे मकानों के लिए वित्तीय व्यवस्था न हो सके, तो उनके शासन का कर्तव्य है कि हमारी निजी उद्यम व्यवस्था के अन्तर्गत ही काम करते हुए, इस कमी को पूरी करने के तरीके निकालें।

युद्ध के बाद कॉन्वेक्टिकट में आवास सम्बन्धी स्थिति राष्ट्र के अन्य औद्योगिक राज्यों जैसी ही थी। मुख्यतः कॉन्वेक्टिकट के विशेष युद्ध उद्योगों में काम करने के लिए बढ़ी मर्यादा में मजदूरों के आने के कारण, हमारी आवादी दस वर्षों में लगभग तीन लाख बढ़ गई। लैनहैम अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए पाँच हजार अस्थायी मकानों के अतिरिक्त, युद्ध-काल में मकानों का निर्माण लगभग पूरी तरह रुका रहा।

फलस्वरूप, हमारे छोटे-से राज्य में लगभग 37,000 परिवार मित्रों या सम्बन्धियों के यहाँ टिके हुए थे, और अन्य 42,000 ऐसे मकानों में रहते थे जिन्हें विशेषज्ञ लोग 'उचित से नीचे स्तर का' कहते थे, अर्थात् गन्दी बस्तियों में। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट हो गया कि कॉन्ट्रिक्ट में निजी उद्यम प्रति वर्ष केवल सात या आठ हजार मकानों के लिए धन की व्यवस्था कर सकता था। 1946 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सघीय सकटनालीन आवास कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद, निजी उद्यम द्वारा केवल अधिक प्राय वातों के लिए मकान बनाये गए, जिनका बिक्री मूल्य 15,000 डालर से अधिक होता था, और किराए 90 डालर मासिक से अधिक होते थे।

धुंध भूतपूर्व सैनिकों ने अपने सर्वाधिक निक्ट शासन सस्था से, अर्थात् राज्य विधान-मंडल से परियाद की। उनकी यह माँग 1948 में गर्वनर पद के लिए मेरे चुनाव अभियान का एक प्रमुख अंग बन गई, कि निजी ठेकेदारों के काम के पूरक रूप में, निम्न और मध्य-वित्त समूहों के लिए एक सचमुच पर्याप्त राज्य आवास कार्यक्रम पद-ग्रहण करने के बाद मैंने विधान-मंडल से एक राज्य ऋण-पत्र जारी करने का अधिकार माँगा, जिससे 13,000 मकान बनाये जाएँ। मेरा प्रस्ताव अन्ततः इस शर्त पर मान लिया गया कि उनमें से आधे मकान किराए पर दिए जाएँ, और आधे सामान्य प्राय वाले लोगों के हाथ बिक्री के लिए हों।

इस योजना का एक प्रमुख अंग यह था कि कार्यक्रम की वित्त-व्यवस्था अधिकांश राज्य द्वारा जारी किये गए एक वर्षीय पत्रों के द्वारा हो, जिनका प्रति वर्ष नवी-करण किया जाय। पचास वर्षीय पत्रों पर व्यज की सामान्य 2.6 प्रतिशत दर की तुलना में, इस समय इन पत्रों पर व्याज की दर 1 प्रतिशत से भी कम है। इस कम खर्च वाली, अल्प-कालीन वित्त व्यवस्था से हम मकानों के औसत किराए को 43 डालर पर ला सके। हर वर्ष व्याज की चालू दर के अनुसार यह रकम घटाई बढ़ाई जाएगी, और राज्य को कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा।

लेकिन बिक्री के लिए बनाये गए मकानों में नुकसान होने का कुछ खतरा है। अगर व्याज की दर काफी बढ़ जाय, तो एक घाटा पैदा हो जाएगा जो राज्य को भरना पड़ेगा। मकानों के अभाव की समस्या की तीव्रता के देखते हुए, यह मान लिया गया कि इसका खतरा उठाया जाय। (व्याज की दर सचमुच बढ़ी, और घाटा पैदा हुआ। लेकिन मकानों के व्यापक अभाव को कम करने के लिए यह मूल्य छोड़ा ही प्रतीत होता है।)

इस व्यापक कार्यक्रम को महासभा के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले मैंने सारे राज्य के वास्तुकारों, ठेकेदारों, इमारती सामान के वितरकों, और मजदूर नेताओं से इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ चर्चा की। उन सभी से मुझे आश्वासन मिला है। कि कम से कम लागत पर अच्छे क्रिस्म के मकान बनाने में राज्य को अधिकतम सहयोग

देने की पूरी कोशिश की जाएगी ।

सारे कॉन्विकट के इमारती मजदूर सगठनों के प्रतिनिधि नेताओं के आश्वासन से मुझे विधेय संतोष मिला कि कम काम करने या नकली काम करने के किसी भी प्रकार के तरीके सहन नहीं किये जाएंगे । यह वादा पूरा किया गया है ।

कॉन्विकट में अपने आवास-निर्माण के प्रयत्नों के द्वारा हमने राज्य और स्थानीय शासनो के बीच तथा शासन और निजी उद्यम के बीच एक प्रकार की मिली-जुली जिम्मेदारी कायम की है । मैं समझता हूँ कि हमने अधिकतम संकालु लोगों को भी यह विश्वास दिला दिया है कि राज्य के धन से चलाये गए, सुनियोजित आवास कार्यक्रम से न केवल निजी निर्माण कार्यों को, वरन् घरेलू सामान और फर्नीचर आदि की पूर्ति करने वालों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है ।

राज्य कार्यक्रम का लगभग हर अंग निजी उद्यम के हाथ में रहता है । स्थानीय आवास अधिकारी निजी वास्तुकारों की सेवाओं का उपयोग करते हैं । वे निर्माण का काम निजी इमारती ठेकेदारों को सौंप देते हैं, जो निजी क्षेत्रों से इमारती सामान खरीदते हैं, और निजी व्यापार की सामान्य स्थितियों में काम करने वाले मजदूरों को काम पर लगाते हैं ।

सारी वित्त-व्यवस्था, जिसमें कार्यक्रम के घर-स्वामित्व सम्बन्धी अंग के लिए रेहन-ऋणों की देख-रेख भी शामिल है, निजी बैंको, और निजी ऋण एजेंसियों के द्वारा की जाती है ।

हमारा अनुमान है कि 13,000 मकानों के पूरे कार्यक्रम से, कॉन्विकट में 1950 में बने मकानों की संख्या, इसके पूर्व किसी भी वर्ष में बने मकानों की अधिकतम संख्या से 75 प्रतिशत अधिक होगी । बिना राज्य शासन के प्रयत्नों के, ये मकान न बनते ।

हर अमरीकी परिवार के लिए एक अच्छा घर, आधुनिक लोकतन्त्र की चुनौती का एक अंग है । इस बोझ के उचित हिस्से को उठाकर, राज्य शासन केवल उस दिन को ज्यादा जल्दी लाने में सहायक होमे, जब मकान पूरी संख्या में उपलब्ध हों, बल्कि वे यह भी प्रदर्शित करेंगे कि हमारी परम्परागत सघ-राज्य व्यवस्था व्यवहार में भी उतनी ही सक्षम है जितनी सिद्धान्त में, और यह कि 'काम कराने के लिए' हमेशा वांशिंगटन जाना हमारे नागरिकों के लिए जरूरी नहीं है ।

एक प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

कोई राज्य शासन किस प्रकार 'ज़बरदस्त बीमारी' के खर्चों को पूरा करने में अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए एक बीमा कार्यक्रम बना और चला सकता है, इसे गवर्नर बोलस ने 28 अगस्त, 1950 को दिये गए एक रेडियो भाषण में बताया।

हम अमरीकी लोग प्रति वर्ष अधिक स्वस्थ होते जा रहे हैं। नवजात शिशु के अनेकित जीवन काल में, 1900 से अब तक हमने लगभग बीस वर्ष जोड़े हैं। क्षय रोग, निमोनिया, और डिप्थीरिया जैसे रोगों के विरुद्ध, जिनसे पहले लोग बड़ी संख्या में मरते थे, हमने प्रभावी कार्यवाही की है।

हम इस समय कैंसर, बच्चों के पक्षाघात, हृदय रोग, और अन्य ऐसे रोगों के सम्बन्ध में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।

कॉन्क्रिटकट में स्वास्थ्य सम्बन्धी हमारे कार्य विशेषतः अच्छे रहे हैं। हमारे पास प्रति उत्तम डाक्टर और अच्छे अस्पताल हैं। अमरीका के लगभग अन्य किसी भी हिस्से की अपेक्षा हमारे लोग अधिक स्वस्थ और दीर्घजीवी होते हैं।

फिर भी, मैं समझता हूँ कि चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में तीन प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए।

प्रथम, गंभीर बीमारियों के शुरू होने के पहले ही उनका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ?

दूसरे, यहाँ कॉन्क्रिटकट में हम डॉक्टरों के लिए अधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं ?

तीसरे, लम्बी और विपत्ति लाने वाली बीमारियों के बहुत बड़े खर्चों के सम्बन्ध में हम क्या कर सकते हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े परिवारों को हमेशा के लिए कष्टदायक बना रखा है ?

हम पहले प्रश्न से धारम्भ करें—गंभीर रोगों की शुरू में ही पक्का डाक्टर इस बात पर सहमत हैं कि अगर वे किसी गंभीर बीमारी को प्रारम्भिक अवस्था में ही पकड़ लें, तो वे हजारों ऐसे व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं जिनके लिए अन्यथा कोई खर्च नहीं रहता। इसी कारण हम सबसे धाप्रट किया जाता है कि पूरी जाँच के

लिए डॉक्टर के पास वर्ष में एक बार जरूर जाएँ।

निजी उदासीनता या आलस्य के कारण हममें से कुछ लोग इस सलाह पर ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे हमें इसके लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन हजारों अन्य लोग सोचते हैं कि वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

इस समस्या के हल करने के लिए, मैंने सुझाव दिया है कि हम सारे राज्य में बीस या तीस नैदानिक कक्ष स्थापित करें, जो स्वयं डॉक्टरों द्वारा ही नियंत्रित और संचालित किये जाएँ। इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में घूमते रहे। इन नैदानिक कक्षों द्वारा कॉन्सल्टेंट के सभी नागरिकों की, कम खर्च पर वर्ष में एक या दो बार पूरी स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।

इसका खर्च एक राज्य-व्यापी बीमा व्यवस्था के द्वारा चलाया जा सकता है, जिसमें कम आय वाले परिवारों के बोझ को कम करने के लिए राज्य शासन प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान दे सकता है।

कई डॉक्टरों ने मुझ से कहा है कि ऐसी किसी व्यवस्था के द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षा सगठित होने पर कॉन्सल्टेंट में शायद प्रति वर्ष हजारों जाने बचाई जा सकते हैं। व्यापक एक्स-रे परीक्षाओं के फलस्वरूप क्षय रोग के विरुद्ध जो प्रगति हुई है, उससे पता चलता है कि ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या कुछ किया जा सकता है।

दूसरी समस्या स्वास्थ्य सम्बन्धी हमारे वर्तमान साधनों को बढ़ाने की है, ताकि हमारे सभी लोगों को उस उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति प्रदान कर सकती है। आने वाले वर्षों में हमें ज्यादा अस्पताल बनाने होंगे, उन्हें अच्छी तरह सज्जित करना होना, और अधिक सहा में डॉक्टरों, नर्सों, और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना होगा।

अपने डॉक्टरों स्कूलों की सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं विशेषतः चिन्तित हूँ। यद्यपि येल विश्वविद्यालय का मेडिकल स्कूल अमरीका के सर्वोत्तम डॉक्टरों स्कूलों में से एक है, किन्तु उसकी भौतिक सीमाएँ इतनी हैं कि प्रति वर्ष केवल पैंसठ स्त्री-पुरुष ही प्रशिक्षण समाप्त करके निकल सकते हैं। यह संख्या पचीस वर्ष पहले भी इतनी ही थी।

हमारे अति उत्तम हार्टफ़ोर्ड अस्पताल पर आधारित, एक नया कॉन्सल्टेंट विश्व-विद्यालय मेडिकल स्कूल प्रति वर्ष कॉन्सल्टेंट के बहूतरे युवक-युवतियों को चिकित्सा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, जो इस समय डॉक्टर बनने के अवसर से वंचित रह जाते हैं।

तीसरा प्रश्न, जिसका उत्तर हमें खोजना होगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है—सम्बन्धी बीमारी पर होने वाला बहुत ही बड़ा खर्च, जो बहूतरे कॉन्सल्टेंट परिवारों की आय क्षमता के परे होता है।

उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा का मूल्य रतना अधिक होने के उचित कारण हैं। आधुनिक अस्पतालों को बनाने, सज्जित करने, और चलाने में बड़ा खर्च आता

है। डाक्टर के प्रशिक्षण में सात या आठ वर्ष लगते हैं। बहुतेरी आवश्यक नई दवाएँ बड़ी कीमती होती हैं।

इन बड़े खर्चों का हमारे हज़ारों नागरिकों पर बड़ा हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। कुछ ने मुझे मर्म-स्पर्शी पत्र लिखे हैं।

हम एक प्रतिनिधि उदाहरण को देखें, जिसकी जानकारी मुझे कुछ दिन पहले ही मिली। एक परिवार में पिता की उम्र सैंतालिस वर्ष है, और आमदनी 65 डालर प्रति सप्ताह है—जो अब कॉन्वेंटिकट के सभी परिवारों की औसत आय के लगभग है। कड़ी मेहनत से, और किरायेतशारी से उन्होंने कई वर्षों में 3,100 डालर बचाए थे। उन्हें यह सोचकर सन्तोष मिलता था कि इन धन से वे अपने बड़े ही प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्री को कालेज भेज सकेंगे।

लेकिन तीन वर्ष पहले माँ के पिता को, जो उनके साथ ही रहते थे, दिल की एक गंभीर बीमारी हो गई। बीमारी लम्बी थी, और उसमें चिकित्सा और अस्पताली देख-भाल के लिए 4,000 डालर की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप उनकी बचत के 3,100 डालर बड़ी तेज़ी से घटने लगे, और अब दोनों बच्चों के लिए कालेज जाना असंभव हो गया है।

यह मामला असामान्य नहीं है। निश्चय ही आप अपने नगर में और भी ऐसे दुःखद मामलों को जानते होंगे, जैसे मैं अपने नगर में जानता हूँ।

ब्लू क्रॉस जैसे वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समस्या की गंभीरता को कम करने में सहायक होते हैं। लेकिन वे किसी भी तरह सभी नागरिकों तक नहीं पहुँच सकते, और सभी तरह के मामलों को अपने हाथ में भी नहीं ले सकते।

इस स्थिति का सामना करने के लिए मैं एक विशेष कॉन्वेंटिकट बीमा योजना का सुझाव रखता हूँ, जो स्वेच्छा पर आधारित वर्तमान कार्यक्रमों की पूरक होगी।

इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए, हम अपने वार्षिक करों के माध्यम से छोटी-छोटी रकमें एक सामान्य निधि में जमा करेंगे। यह सामान्य निधि साधारण बीमारियों का खर्च देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल उन लम्बी, गंभीर, और खर्चीली बीमारियों में किया जाएगा, जिनका खर्च अपने सामान्य पारिवारिक खर्चों में निकालने की उम्मीद अधिकांश परिवार नहीं कर सकते।

मैं कुछ विस्तार से बताऊँ कि मेरे प्रस्ताव पर किसी तरह से काम होगा। हर परिवार के लिए, उसकी आय को देखते हुए, एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। चिकित्सा के जो खर्च इस सीमा से कम होंगे, उनकी अदायगी सामान्य रीति से सीधे की जाएगी, लेकिन उससे अधिक खर्च होने पर परिवार को केन्द्रीय बीमा निधि से सहायता मिलेगी।

उदाहरण के लिए, जिन बीमारी का खर्च किसी परिवार की वार्षिक आय के 10 प्रतिशत से कम हो उसका खर्च बीमार या उसके परिवार द्वारा सीधे दिया जाय। बीमा निधि का इस्तेमाल तभी किया जाय, जब किसी एक वर्ष में पारिवारिक बीमारी

का कुल खर्च प्रायः के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

जिस परिवार का मीने ऊपर जिक्र किया, यह योजना उसकी निम्न प्रकार से सहायता करती। आपकी याद होगा कि पिता की आय 65 डालर प्रति सप्ताह थी, अर्थात् 3,380 डालर वार्षिक। किमी साधारण बीमारी या बीमारियों का खर्च, जो 338 डालर तक हो—अर्थात् 3,380 डालर के 10 प्रतिशत तक—परिवार की आय, बचत, या अन्य साधनों से दिया जायगा।

लेकिन नाना की लम्बी दिल की बीमारी में अस्पताल और डाक्टरों के बिल 4,000 डालर से अधिक हो गए थे। इस अतिरिक्त भारी खर्च के लिए परिवार राज्य बीमा निधि से सहायता माँगता।

सावधानी से तथ्यों की जाँच करने के बाद, बीमारी के कुल खर्च 4,000 डालर, और परिवार की आय के 10 प्रतिशत, 338 डालर (जो परिवार द्वारा सीधे दिया जाना) के अन्तर की अदायगी बीमा निधि द्वारा कर दी जाती। इस मामले में यह रकम 3,362 डालर होती।

यह राज्य-व्यापी कार्यक्रम, हर एक की आय के आधार पर न्यूनतम मात्रा में सभी को उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार की वार्षिक आय 25,000 डालर है, तो उसके सदस्यों से अपेक्षित होगा कि किसी वर्ष में बीमारी या बीमारियों पर होने वाले खर्च में प्रथम 2,500 डालर, या पारिवारिक आय का दस प्रतिशत वे स्वयं देंगे।

इस प्रस्ताव के कई विभिन्न रूप हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पूरी बहस और व्यावसायिक विचार-विमर्श से, विशेषतः इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाली बैंकटिपक स्वास्थ्य बीमा एजेंसियों की सलाह से इस योजना को सुधारा जा सकता है।

लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि समस्या की उलझनों को अपने मार्ग में बाधक होने दें। चिकित्सा का खर्च बढ़ने के साथ, समस्या अधिकाधिक गंभीर होती जाएगी। जिसे कुछ डाक्टर 'विपत्ति लाने वाली' बीमारी कहते हैं, उससे अचानक पीड़ित होने वाले निम्न और सामान्य आय वाले परिवारों के भयंकर बोझ को कम करने का कोई तरीका हमें निकालना पड़ेगा।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस तरह की योजना में चिकित्सा का शासकीय नियंत्रण, या जिसे कुछ पराकाष्ठावादी 'चिकित्सा का समाजीकरण' कहते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत, यह कार्यक्रम एक ग्यास-मडल द्वारा संचालित होना चाहिए, जिसमें व्यावसायिक लोगों का—डाक्टरों, अस्पतालों के अध्यक्षों आदि का—बहुमत हो सकता है।

अपनी मर्जी से डाक्टर या रोगी चुनने में, या रोगी और डाक्टर के सम्बन्धों में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसमें चिकित्सा के उच्च स्तर कायम रखे और सुधारे जा सकेंगे। यह निजी स्वास्थ्य साधनों का डाक्टरों, नर्सों, अस्पतालों और दवाखानों

का—उपयोग करने वाला कानेक्टिकट का कार्यक्रम होगा, जिसका वाशिंगटन में संघ शासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

इससे न केवल कानेक्टिकट के हजारों परिवारों को बड़ा लाभ होगा, जिनके सामने चिकित्सा के भारी खर्चों की आशंका है, बल्कि डाक्टरों, नर्सों, दवाखानों, और अस्पतालों के अध्यक्षों को भी होगा, जो रोगियों को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य प्राप्त करना बहुधा कठिन पाते हैं।

जिन तीन समस्याओं का मैंने जिक्र किया है, वे मुझे बहुत दिनों से परेशान करती रही हैं। मैं जानता हूँ कि ये समस्याएँ आपसे भी बहुतो को परेशान करती रही हैं। मैंने जो उत्तर प्रस्तुत किए हैं, हो सकता है कि दूसरों के पास उससे ज्यादा अच्छे उत्तर हों। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि हम आवश्यकता का सामना करें, और उसकी पूर्ति के सबसे अधिक व्यावहारिक, सक्षम और कम खर्च वाले तरीके निकालने की चेष्टा मिलकर करें।

हमारे पास कनेक्टिकट में बड़ा धन है और स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में हमने अबतक अति उत्तम कार्य किया है। दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए हमारी स्थिति असाधारण रूप में अनुकूल है। अन्यत्र की भाँति यहाँ भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संघ शासन की सहायता लिए बिना, अपनी समस्याओं को प्रभावकारी रीति से राज्य के आधार पर हल करें।

हमारी सघ व्यवस्था अड़तालीस 'राज्य शासन की प्रयोगशालाएँ' प्रदान करती है, जिनमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के नए तरीके छोटे पैमाने पर निकाले, परखे, और सवारे जा सकते हैं।

इस परम्परा में हमारे दूर पश्चिम के कुछ राज्यों ने घेतन और काम के घटों सम्बन्धी हमारे वर्तमान कानूनों के बड़े हिस्से का निर्माण किया। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय वृद्धि विस्तार और शोच कार्यक्रम में कानेक्टिकट ने प्रमुख योग दिया।

अब मेरा सुझाव है कि एक राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास में भी कनेक्टिकट अग्रगण्य करे, जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, अधिक डाक्टरों और नर्सों, अधिक अस्पतालों और चिकित्सालयों सम्बन्धी हमारे नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वयं व्यावसायिक लोगों के निर्देशन में करे।

ऐसे किसी प्रयास में शासकीय हस्तक्षेप से डाक्टरों और रोगियों दोनों की ही स्वतंत्रता को हमें ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखना होगा। चिकित्सा के अपने ऊँचे स्तर की भी हमें सावधानी से रक्षा करनी होगी।

लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि शासन के सहयोगी प्रयासों के प्रति अपने परम्परागत भय के कारण हम चुप बैठ जाएँ, और कुछ न करें।

बीमारी को रोकने और उसका इलाज करने के लिए हमें अपने वर्तमान चिकित्सा साधनों को बढ़ाना होगा। हमें इसके साथ ही यह भी व्यवस्था करनी होगी कि अच्छी चिकित्सा की सुविधाएँ कनेक्टिकट के ही परिवार की आर्थिक क्षमता के अन्दर हों।

हमारा कर्तव्य है कि निजी चिकित्सक, शासन और अन्य सभी समूह मिलकर ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करें, जो व्यावहारिक हों, कम खर्च वाले हों, और हमारी अमरीकी कार्यपद्धति के अनुकूल हों।

वाशिंगटन में इस समय जिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसका तीव्र विरोध होने का एक कारण यह भी है कि उसे बनाने में चिकित्सा व्यवसाय का बहुत कम हाथ था।

इस कारण, मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि एक राष्ट्र-व्यापी समस्या के प्रति, एक विशिष्ट कॉन्फ़िडेंट ट्रिप्टिकोण सम्बन्धी अपने मुझाव पर मुझे कॉन्फ़िडेंट के डाक्टरों, नर्सों, चिकित्सा प्रशिक्षकों और व्यावसायिक संगठनों की राय मालूम हो।

मैं यह बता हूँ कि कॉन्फ़िडेंट के प्रमुख डाक्टरों और सर्जनों की एक अनौपचारिक समिति के साथ, जिसमें राज्य के कुछ चोटी के चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल हैं, कुछ निजी बैठकों में मैंने इस चुनौती के सम्बन्ध में चर्चा की थी। इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने स्वास्थ्य साधन सम्बन्धी गवर्नर की एक विशेष समिति नियुक्त की है।

कर्मचारियों और खोज कार्य सम्बन्धी मेरे आकस्मिक कोषों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी गई है। मेरा ह्याल है कि उनके प्रथम प्रतिवेदन और सिफ़ारिशों अगले कुछ सप्ताहों में तैयार हो जाएंगी।¹

¹ जनवरी, 1951 में श्री रौल्स के गवर्नर पद से हटने पर यह संभावनापूर्ण योजना खत्म हो गई

राज्य-शासन का आधुनिकीकरण

अप्रैल, 1950 में, गवर्नर वॉलस ने अनिच्छुक विधान-मंडल से आग्रह किया कि वह 'लिटिल ह्वर कमीशन' की सिफारिशों को स्वीकार करले, जिसे उन्होंने कॉनेक्टिकट राज्य की पुरानी और अकृशाल शासकीय पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। यद्यपि प्रतिनिधि सभा के अधिकांश आर्माए रिपब्लिकन बहुमत ने अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन दस वर्ष बाद, सौ वर्ष में पहली बार राज्य की प्रतिनिधि सभा में डेमाक्रैटिक बहुमत होने पर, उसकी सहायता से गवर्नर अब्राहम रिथिकाफ के कार्यकाल में ये सिफारिशें लगभग ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली गईं।

एक ही मत्तर वर्षों से, हमारे सभ और राज्य दोनों स्तरों के शासन में, संगम और संतुलन की व्यवस्था वह आधारशिला रही है, जिस पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। इसकी व्यावहारिक शक्ति कई ऐसे संकटों के समय प्रमाणित हुई है, जिसमें से कोई भी शासन के इससे दुर्बल रूप को नष्ट कर सकता था।

अगर परखे हुए मिद्धान्त से हमें श्रुति की भांति भविष्य में भी काम लेना है, तो हमें कार्यकारी, विधायक, और न्यायिक तीनों विभागों को सबल बनाने के लिए निरन्तर काम करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से हर एक जनता के निकट रहे, और उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति जिम्मेदार रहे। हमें इनमें से हर एक को आवश्यक उपकरण प्रदान करना चाहिए, जिससे की समस्याओं और सघर्षों का शीघ्रता से और लोकतांत्रिक रीति से निपटारा किया जा सके।

हमारे मध्य शासन की व्यवस्था को अच्छी काम चलाऊ हालत में रखने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। हमारी संघीय कांग्रेस और अदालतों की रीतियों और पद्धतियों में निरन्तर सुधार हुआ है, और संघ शासन की कार्यकारी शाखा का कई अवसरों पर पुनः सगठन किया गया है। अपने सभ शासन के कार्य-संचालन के इस निरन्तर पुनः परीक्षण के फलस्वरूप हम उसके तीनों महान् विभागों के बीच शक्ति के नाजुक सन्तुलन को कायम रख सके हैं।

लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारी शासन व्यवस्था में एक और भी आधारभूत सतुलन स्थापित किया था—केन्द्रीय शासन और राज्यों के बीच शक्ति और उत्तरदायित्व का विभाजन। ऐसा कहना मेरी राय में उचित होगा कि इस आवश्यक आधारभूत सतुलन को कायम रखने में हम उतने सफल नहीं रहे।

हम अपने राज्य शासनों के सपन्न को अपने समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में पिछड़ गए हैं।

फलस्वरूप, कई अवसरों पर जनमत ने संघ शासन को ऐसी समस्याएँ अपने हाथ में लेने पर मजबूर किया है, जिनका निपटारा राज्यों की राजधानियों में करना ज्यादा अच्छा होता। वाशिंगटन में केन्द्रित शक्ति में हुई वृद्धि का एक बड़ा कारण हमारी इस असफलता में देखा जा सकता है कि हम राज्यों की शासकीय पद्धतियों को समयानुसार विकसित नहीं कर सके।

हम स्वयं अपने कॉन्फिडकट राज्य की स्थिति पर नज़र डालें। हमारे राज्य का संविधान, और उस पर आधारित शासकीय ढांचा 130 वर्ष से भी पहले, 1818 में विकसित हुआ था। यह एक भिन्न और कहीं अधिक सरल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था, जब हमारे खेतों, गाँवों, और कस्बों तक औद्योगिकीकरण का प्रभाव नहीं पहुँचा था, जब न रेलें थी, न वायुमान, न रेडियो या मोटर्स, न विशाल औद्योगिक कारखाने या भीड़ भरे शहर, न व्यापक बेकारी का खतरा था, न भण्ड-युद्ध का।

हमारा प्रारम्भिक कॉन्फिडकट राज्य शासन एक सरल संगठन था, जिसमें केवल चार छोटे-छोटे विभाग थे। पचास वर्ष पहले भी, हमारे वर्तमान 202 विभागों और एजेन्सियों में से 80 प्रतिशत का कोई अस्तित्व नहीं था। 1930 तक भी, गवर्नर और राज्य के कई विभागों के अध्यक्ष पद को केवल आगिक समय वाले काम समझा जाता था। उस धीमे चलने वाली, घोडा-गाड़ी की अर्थ-व्यवस्था की पद्धतियों और आवश्यकताओं का स्थान धीरे-धीरे हमारे मशीन युग की पद्धतियों और आवश्यकताओं में ले लिया है।

इस बीच राज्यों शासन के काम अच्छे और बुरे कालों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों प्रशासनों के अन्तर्गत, और बहुधा खर्च या कार्य-कुशलता का कोई विशेष ध्यान रखे बिना ही निरन्तर बढ़ते रहे हैं।

कई पीढ़ियों से यह बात स्पष्ट रही है कि अन्य राज्यों की भाँति, कॉन्फिडकट में शासन की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाने से, प्रशासन में कसाव लाना जरूरी है, कि आंशिक समय वाला शासन अप्रव्ययपूर्ण और प्रभावहीन होता है, और यह है कि सुधारों की जरूरत काफी दिनों से है।

लोकतंत्र और कार्य-कुशलता में वृद्धि करने की दृष्टि से, हमारे राज्य-शासन के व्यापक पुनः संगठन के सुझाव कई बार दिये गए। 1902 में रिपब्लिकन गवर्नर ऊँ पी० मैन्लीन ने और 1936 में डेमोक्रेटिक गवर्नर विल्बर क्रॉम ने राज्य संवि

धान के प्राप्तिनीकरण के लिए साहसपूर्ण विन्मू निष्पन्न प्रयाग किए।

ये धीरे धीरे प्रयत्न अधिक सफल क्यों नहीं हुए, उनके कारण स्पष्ट रूप में से हैं—हमने ऐसे व्यक्तियों धीरे सगठनों की गरुण धीरे सक्ति को हमेशा प्राप्तिवत्ता से काम समझा है, जिनका कु-नाशन में भारी रवाम है। प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रभावित होने वाले निहित स्वार्थ बड़े सक्रिय थे, जबकि उनमें सामान्य होने वाली जनता सोई हुई थी।

पदग्रहण करने के बाद, 5 जनवरी, 1949, को अपने मदेश में मैंने गुमान रखा था कि अपने कनिष्ठकट शासन को सर्वथा प्राधुनिक बनाने के लिए धारा धीरे मैं—कार्यकारिणी धीरे विधान-मंडल—मिलकर पूरी सक्ति से प्रयाग करें। अपने राज्य के लोगों के लिए अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए, धारण्य को सम बनने के लिए, धीरे जहाँ भी सम्भव हो, अपने काम के खर्चों को कम करने के लिए, जो भी परिवर्तन आवश्यक हो, करें।

हम 31 मार्च, 1949 को इस बात पर सहमत हुए कि पाँच सदस्यों का राज्य संगठन कमीशन नियुक्त किया जाय, जो हमारे शासन की हर शाखा का अध्ययन करे, धन्य सुव्यवस्थित राज्यों के साथ हमारी सासकीय कार्यप्राप्ति की तुलना करे, और सभी मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। कमीशन की सिफारिशें प्रथम हमारे सामने हैं।

सरल रूप में, इन निष्कर्षों का सारांश यह है—कमीशन की राय में, 132 वर्ष पुराने संविधान पर आधारित हमारे राज्य शासन का संयंत्र बुरी तरह धीरे खतरनाक रूप में पुराना पड़ चुका है। एक प्रशासकीय जंगल उग गया है, जो विधान-मंडल, गवर्नर, अदालतों, या जनता के जिम्मेदार नियंत्रण की पहुँच के बाहर है, और जिसके फलस्वरूप व्यापक अपव्यय, अकुशलता, धीरे निराशा उत्पन्न होती है।

यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि अकुशल, धीरे गतिहीन नौकरशाही के दलदल में फँस जाने से हमारे राज्य-शासन को केवल हजारों राज्य कार्यचारियों और बीसियों स्वेच्छित सेवा बोंडों और कमीशनों के सदस्यों की लगन, योग्यता, धीरे जनसेवा की भावना ने ही रोका है।

कमीशन की सिफारिशों सीधे आधारभूत प्रश्नों को उठाती हैं। जो सुभाव दिये गए हैं, वे प्रासिक रूप में बड़े धीरे सफल व्यापारिक उद्यमों के प्रशासकीय अनुभवों से लिये गए हैं। धन्य सुभावों के आधार हैं, हूबर कमीशन द्वारा समर्पित सु-प्रबन्ध के सिद्धान्त, उन राज्यों के अनुभवों जो पुनः संगठन योजनाओं पर प्रमल कर चुके हैं, धीरे अन्त में, स्वयं कमीशन के सदस्यों के व्यावहारिक अनुभव, जो कनिष्ठकट उसकी परम्पराओं, धीरे विशिष्ट समस्याओं से परिचित हैं।

सिफारिशों को कई भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, यह सुभाव दिया गया है कि हमारे राज्य के वित्तीय ढाँचे का पूरी तरह पुनः संगठन किया जाय, ताकि हमें हर समय अपने राजस्व धीरे खर्चों की सही स्थिति

की जानकारी रहे। आज हमारे बजट सम्बन्धी और वित्तीय कार्यकलापों में पाँच भिन्न एजेन्सियों की विभाजित जिम्मेदारी है, जिनके लगभग उतने ही भिन्न विचार और दृष्टिकोण हैं।

दूसरे, प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे शासन की कार्यकारी शाखा की 202 एजेन्सियों और कमीशनो को कार्यात्मक आधार पर अठारह विभागों में समेकित कर दिया जाय।

तीसरे, सगठन कमीशन की सिफारिश है कि हमारी अपव्ययपूर्ण काउण्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय, जो कई पीढ़ियों से हमारे शासन का पाँचवाँ पहिया बनी रही है। दुहरावट, बड़े हुए खर्च, और अनावश्यक राजनीतिक पदों के रूप में करदाताओं ने इस पिसी-पिसी व्यवस्था की भारी कीमत भ्रदा की है।

चौथे, कमीशन ने हमारे नगरो और कस्बो के लिए सच्चे स्वशासन के एक कार्यक्रम की सिफारिश की है। हमारी वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय शासन संस्थाएँ वास्तव में राज्य शासन के ही क्षेत्र हैं, जो महासभा की अनुमति के बिना बहुतेरी समस्याओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सकते। सर्वोत्तम शासन वह होता है जो जनता के सर्वाधिक निकट हो। जैसा कमीशन ने कहा है, इसके लिए स्व-शासन और विकेन्द्रीकरण में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता है।

पाँचवें, कमीशन ने कहा है कि हमारी अदालती व्यवस्था को पुनः संगठित किया जाय, जिसमें छोटी अदालतों में पूरा समय देने वाले जज हों, और हमारे उच्च तथा सामान्य वाद न्यायलयों को समेकित किया जाय। इससे हमारी सम्पूर्ण अदालती व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा, और राजनीति के अन्तिम अवशेष भी, जहाँ कहीं होंगे, समाप्त हो जाएँगे।

छठे, कमीशन का प्रस्ताव है कि महासभा मुसंगठित हो, उसके लिए पर्याप्त कर्मचारी हों, और लम्बे समय तक लगन से किए जाने वाले उसके काम का उचित भुआवजा दिया जाय।

सातवें, कमीशन की सिफारिश है कि एक अधिक सरल और स्पष्ट राज्य संविधान स्वीकार किया जाय, जिसमें हमारी परम्परागत नागरिक स्वतंत्रता की पूर्ण सुरक्षा हो।

इन प्रस्तावों में निकट अतीत के इतिहास में पहली बार कनिविटकट को शासन की एक आधुनिक व्यवस्था प्राप्त होगी। हमारे शासन के तीन मौलिक विभाजनों में से हर एक को सबल बनाकर, ये प्रस्ताव हमारे लोकतंत्र को नई शक्ति प्रदान करेंगे। ये हमें इस योग्य बनाएँगे कि अपने लोगों के लिए हम जिन सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, उनमें काफी सुधार कर सकें। इसके अतिरिक्त, इनके द्वारा हम काफी बचत भी कर सकेंगे। कमीशन का अनुमान है कि दो वर्षों में कम से कम एक करोड़ बीस लाख डालर की बचत होगी।

कमीशन का प्रतिवेदन केवल एक ही मामले में निराशाजनक है। मैं जानता हूँ

कि भाष में से भी बहुता को मेरी भाँति संद होगा कि कमीशन के पाँच सदस्य इस प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके कि विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व की हमारी संस्था बेकार हो चुकी व्यवस्था को किस प्रकार संतोषित किया जाय।

जिन सिद्धान्तों के आधार पर हमारी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं, उन्हें 1818 के मूल विधान में निरूपित किया गया था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, सीनेट के सदस्य समान प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते थे। और कस्बों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते थे।

1818 में यह अनुचित नहीं था। उन प्रारम्भिक दिनों के कॉन्विक्ट के हमारे सबसे बड़े और सबसे छोटे नगरों के आधार का मामूली सा फर्क अपेक्षितया महत्वहीन था। आज अन्तर कहीं ज्यादा है, और स्थिति उतनी ही भिन्न है। फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा के चुनाव की यह पुरानी पद्धति हमारे दो-तिहाई लोगों के प्रति बड़ी भेद-भावपूर्ण हो गई है।

इस समय हमारे एक तिहाई लोग प्रतिनिधि सभा के दो तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। कॉन्विक्ट की इस स्थिति को सारे अमरीका में प्रतिनिधि शासन के एक धिसे-पिटे और अलोकतांत्रिक रूप के विविष्ट उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। कमीशन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने के लिए लगे के साथ बड़ी चेष्टा की, जिस पर पाँचों सदस्य सहमत हो सकें। दुर्भाग्यवश वे अपने मतभेद दूर नहीं कर सके, और उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रश्न को फिर किसी समय के लिए स्थगित कर दिया जाय। किन्तु कॉन्विक्ट में पूर्ण लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में नागरिकों के प्रतिनिधित्व की यह असमान व्यवस्था एक बाधा बनी रहती है। जल्दी या देर से इस बाधा को हटाना होगा।

अन्यत्र की भाँति कॉन्विक्ट में भी राजनीतिक उदासीनता समाप्त हो रही है। अणु-युग में, अपने शासन के कार्यकलाप में हमारी जनता की गंभीर रुचि है, और इतिहास के अन्य किसी भी काल से अधिक, उनका दृढ़ निश्चय है कि शासन उनके सन्धे हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं अपनी स्थिति बिलकुल साफ कर देना चाहूँगा। प्रतिनिधित्व के इस एक पक्ष को छोड़कर, मैं इस प्रतिवेदन को उत्साहपूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे, कॉन्विक्ट की महासभा से, अधिक से अधिक गंभीरता के साथ आप्रह करता हूँ कि इसे कानून का रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

तौसरा भाग

स्वतन्त्र व्यक्ति और स्वतन्त्र मन

आज व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सघर्ष हमारे काल का निर्णायक राजनीतिक संघर्ष है। अमरीका स्वतन्त्रता के बारे में क्या सोचता है, और इससे भी अधिक, अमरीका स्वतन्त्रता के बारे में क्या करता है, इसका प्रभाव हर राष्ट्र के लोगों पर, और हर शासन की नीतियों पर पड़ता है। अपने इतिहास के अन्य किसी भी काल से अधिक, अमरीका में हम लोग इस सम्बन्ध में विभ्रम को कोई स्थान नहीं दे सकते कि स्वतन्त्रता क्या है, बल्कि हमें स्वतन्त्रता के अर्थ और उसकी प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध में व्यापक, गंभीर सहमति प्राप्त करने की चेष्टा करनी होगी।

28 मई, 1950

स्वतन्त्रता की अन्तहीन खोज

इस लेख में (न्यूयार्क टाइम्स मंगलवार, 28 मई, 1950) गवर्नर वॉल्स इस बात पर जोर देते हैं कि इस बात को प्रमाणित करना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि 'मनुष्य के अधिकारों' को सफलतापूर्वक अठारहवीं सदी से बीसवीं सदी में लाया जा सकता है ।

लिकन ने 1864 में कहा था, "दुनिया को स्वतन्त्रता की कभी कोई अच्छी परिभाषा नहीं मिली, और इस समय अमरीकी लोगो को इसकी बड़ी जरूरत है । हम सब अपने को स्वतन्त्रता के पक्ष में घोषित करते हैं, लेकिन एक ही शब्द का प्रयोग करते हुए, हम सब का तात्पर्य एक ही नहीं होता ।"

हमारा तात्पर्य अब भी एक नहीं होता । फिर भी, आज व्यक्ति की स्वतन्त्रता का संघर्ष हमारे काम का निर्णायक राजनीतिक संघर्ष है । अमरीका स्वतन्त्रता के बारे में क्या सोचता है, और इससे भी अधिक अमरीका स्वतन्त्रता के बारे में क्या करता है, इसका प्रभाव हर राष्ट्र के लोगो और हर शासन की नीतियो पर पड़ता है । अपने इतिहास के अन्य किसी भी काल से अधिक, अमरीका में हम लोग इस सम्बन्ध में विभ्रम को कोई स्थान नहीं दे सकते, कि स्वतन्त्रता क्या है, बल्कि हमें स्वतन्त्रता के धर्म, और उसकी प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध में व्यापक, गंभीर सहमति प्राप्त करने की चेष्टा करनी होगी ।

"स्वतन्त्रता" स्वयं एक बहुमुखी शब्द है । स्वतन्त्रता के ही कई रूप हैं । स्वतन्त्रता को अविभाज्य कहने में न ईमानदारी है, न सचाई ।

प्रथम, और स्पष्ट रूप में, राजनीतिक स्वतन्त्रता है—अपने कांग्रेस सदस्यों, राष्ट्रपति, गवर्नरों, प्रधान मन्त्रियों और कर वसूल करने वालो का चुनाव करने की स्वतन्त्रता, शासकीय नीतियो की स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता ।

फिर, नागरिक स्वतन्त्रता है—अपने मन की बात सुलकर कहने की, शांति-पूर्ण समूहों में एकत्र होने की, सार्वजनिक सेवाओं की समान उपलब्धि की, और अपने देश में स्वतन्त्रतापूर्वक धूमने-फिरने की आजादी, उचित विचारण का अधिकार, अनुचित तलाशी, गिरफ्तारी और निर्वासन के विरुद्ध सुरक्षा ।

फिर, निजी स्वतन्त्रता है—अपना धर्म चुनने की, अपनी इच्छा से विवाह करने,

और अपनी धारणाओं के अनुसार अपने बच्चों को पालने की, और अगर हम चाहें तो शाकाहारी, गंध्यासी, या नाचने वाले बनने की स्वतन्त्रता ।

फिर कुछ मानवी स्वतन्त्रताएँ हैं— बिना जाति, धर्म, मूल राष्ट्रीयता या धार्मिक स्थिति सम्बन्धी किसी भेद भाव के, आजादी के साथ, मानवी गरिमा के धनुरूप, और अपनी पूरी क्षमता तक अपना विवास करने की स्वतन्त्रता । यह एक अपेक्षतया नई धारणा है, जिसकी चर्चा मैं बाद में अधिक विस्तार के साथ करूँगा ।

और तब धार्मिक स्वतन्त्रता आती है—जहाँ चाहें काम करने की, अपना काम या व्यापार चुनने की, कोई नई वस्तु बनाने या बेचने की, जो भी वेतन या भूतय मिल सके, उसे प्राप्त करने की, काम करने या छोड़ देने की, सम्पत्ति रखने या बेच देने की स्वतन्त्रता—जो सब काम करने की हमारी क्षमता, बुद्धि और तत्परता पर निर्भर है ।

अधिकांश सम्पत्ताओं ने इनमें से कुछ न कुछ स्वतन्त्रता प्रदान की है । हमारे युग के पहले, सभी तरह की स्वतन्त्रता प्रदान करने का दावा किसी ने नहीं किया । पुरानी सम्पत्ताओं में ऐसा अधिक होता रहा है कि ये सभी या अधिकांश स्वतन्त्रताएँ किसी एक विशिष्ट वर्ग को प्रदान की जाती थी, और अन्य सभी वर्ग अधिकांश उनसे वंचित रहते थे ।

आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कसौटी यह नहीं है कि वास्तविक व्यवहार में ये अलग-अलग स्वतन्त्रताएँ कितनी सख्या में मौजूद हैं । कसौटी यह है कि कितनी स्वतन्त्रता कितने लोगों को उपलब्ध है । इस कसौटी में अमरीका अपनी स्थापना के समय से ही, इतिहास में किसी भी देश या सम्पत्ता से आगे रहा है । इसके अलावा, दुनिया के अन्य किसी भी देश की तुलना में आज हम अधिक लोगों को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान कर रहे हैं ।

चूँकि सभी स्वतन्त्रताएँ राजनीतिक स्वतन्त्रता पर निर्भर हैं, मतः हम पहले उस पर विचार करें ।

हमारे देश का जन्म अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता के आधार-भूत सिद्धान्त को लेकर हुआ था । पिछले डेढ़ सौ वर्षों से हम इस मूल स्वतन्त्रता को सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार में भी प्रतिष्ठित करने के लिए कार्यरत रहे हैं । जब अमरीका की स्थापना हुई, उस समय हमारे बयस्क नागरिकों में एक अल्प-संख्या को ही मतदान करने या सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार था । नीग्रो, स्त्रियों और कुछ राज्यों में सम्पत्तिहीन लोग, इनका शासन संचालन में कोई हाथ नहीं था ।

आज, चुनावकर लगाने वाले बचे हुए राज्यों में कई लाख नीग्रो लोगों के दुखद भ्रष्टाचार को छोड़कर, इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के सभी अमरीकी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है ।

नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? यह भी स्वतन्त्रता के घोषणा-पत्र, हमारे संविधान और अधिकार-पत्र में प्रतिष्ठित एक आधार भूत स्वतन्त्रता थी ।

अधिकंश देशों की तुलना में, विशेषतः तानाशाही देशों की तुलना में, अमरीका का इतिहास स्पृहणीय है। लेकिन सच कहें तो हम जानते हैं कि हमारा इतिहास किन्नी तरह दोष-रहित नहीं रहा।

अमरीका में गीरे लोगों के लिए नागरिक स्वतंत्रता का जो रूप है, उस रूप में यह दक्षिण के नीग्रो लोगों को कभी उपलब्ध नहीं रही। और आज हम देखते हैं कि कांग्रेस के अन्दर और बाहर, कुछ आडम्बरपूर्ण लोग हर ऐसे व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता पर जहरीला हमला कर रहे हैं जिसके विचार उनके अपने विचारों से मेल नहीं खाते। यह सिद्धान्त कि हम विश्व साम्यवाद की सबसे बुरी विशेषताओं में से एक की—अर्थात् नागरिक स्वतंत्रता के दमन की—नकल करके उसे पराजित कर सकते हैं, और अपनी स्वतंत्रता को सबल बना सकते हैं, निश्चय ही बड़ा उत्तरनाक है।

लेकिन इन दुखद तथ्यों के सम्बन्ध में भी आशान्वित होने का काफी कारण है। कोई भी निष्पक्ष प्रेक्षक यह स्वीकार करेगा कि युद्ध के बाद नीग्रो नागरिकों को अधिक नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में जितनी प्रगति हुई है, उतनी हमारे इतिहास की अन्य किसी तुलनीय अवधि में नहीं। जहाँ तक चरित्र-दहन की मौजूदा बाढ़ का सम्बन्ध है, इस बात के संकेत अभी भी मिल रहे हैं कि न्याय और विवेक की परम्परागत अमरीकी भावना फिर से ऊपर आ रही है।

यद्यपि नागरिक स्वतन्त्रता के प्रश्न ने हमारे सारे इतिहास में बहुतेरे मतभेद उत्पन्न किए हैं, किन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता की समस्या और भी अधिक विवादपूर्ण है, और उसमें गलतफहमी की गुंजाइश ज्यादा है।

प्रारम्भिक अमरीका आर्थिक स्वतन्त्रता का एक आदर्श था, सम्यता के इतिहास में अनोखा। एक नए राष्ट्र, नए लोगों के रूप में हमने अपने आप को एक विशाल देश में पाया, जिसके साधन अप्रयुक्त पड़े थे, जिसमें अपार धन था, विशाल स्वामी-हीन भूमि थी, और कुल्हाड़ी, कुदाली, या हल लेकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए असंमित आर्थिक अवसर थे।

लेकिन इस पौष्ट्य-भरे युग की प्रिय स्मृतियों के प्रति अपने उत्साह में हमें यह तथ्य नहीं भूल जाना चाहिए कि इतिहास में अभूतपूर्व औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक स्वतन्त्रता की हमारी मूल धारणाओं की कठिन परीक्षा ली। इससे निस्सन्देह राष्ट्रीय धन में, धर्म की बचत करने वाले उपकरणों में, और मजदूरों की उत्पादन-शक्ति में विशाल वृद्धि हुई। लेकिन अधिकाधिक अमरीकियों के हमारे शहरों में इकट्ठा होकर मिलों और कारखानों में वेतन-भोगी मजदूर बनने से, हमारे बहुसंख्यक लोगों के लिए निजी आर्थिक स्वतन्त्रता का पुराना आदर्श लुप्त होने लगा।

अनिवार्य ही, औद्योगिक क्रान्ति ने जो आर्थिक स्वतन्त्रता हमसे छीन ली, उसके कुछ हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए हमने लोकतंत्र के महानतम उपकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया। हम 1929 के बहुत पहले से ही ऐसा करने लगे थे। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में 'पॉपुलिस्ट' आन्दोलन के समय, थियोडोर

रुजवेल्ट की 'सुमुचित' नीति और बुडरोवित्सन की 'नई स्वतंत्रता' के समय भी, हम बढ़ते हुए औद्योगिक संयंत्र और घटती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बीच पुनः सन्तुलन स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे ।

1929 की विशाल मन्दी के बाद, यह अनिवार्य था कि लोगों को फिर से काम पर लगाने, और बेकारी के बीमों की व्यवस्था करने के लिए, भविष्य में अनियंत्रित आर्थिक विपत्ति को रोकने के लिए, किसानों को प्राय में तेज गिरावट से बचाने के लिए, और अमरीकी परिवारों को समृद्धि के बीच भूखे रहने से बचाने के लिए, हम अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग करें ।

इसके साथ ही, एक और विशिष्ट विकास ऐसा हो रहा था, जिसका स्वतन्त्रता सम्बन्धी हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकता, कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों में मानवी अधिकारों और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में समाज के दृष्टिकोण में कितना जबरदस्त परिवर्तन हुआ है ।

मेरा तात्पर्य विशेषतः इस बात से है कि बिना उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की और ध्यान दिए, आज्ञादी से, आत्म-सम्मान के साथ, और अपनी क्षमता की पूर्ण सीमा तक अपना विकास करने के हर पुरुष, स्त्री और बच्चे के अधिकार पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है ।

आंशिक रूप में इस धारणा की जड़ें भी वही हैं जहाँ हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता की, और इसे भी हमारे स्वतन्त्रता के घोषणापत्र में प्रयुक्त शब्दों में व्यवहृत किया जा सकता है—“कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ स्वयं-मिद्व और अहरणीय अधिकार प्रदान किए हैं, और यह कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता, और सुख प्राप्ति के प्रयास भी हैं ।”

आंशिक रूप में यह धारणा हमारे महान् धर्मों की भी है—हममें सबसे छोटे, दुर्बल, गरीब, और बोझ से दबे व्यक्ति का भी ईश्वर की दृष्टि में मूल्य है ।

आंशिक रूप में, मानव मन और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में ज्यादा अच्छी जानकारी से, व्यक्ति के विकास में वातावरण के, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दक्षिणों के प्रभाव की ज्यादा अच्छी समझ से भी इसका विकास हुआ है ।

सभी अमरीकी बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करने का आन्दोलन मानवी अधिकारों में वृद्धि के सर्वप्रथम और सर्वाधिक निर्णायक संघर्षों में से एक था ।

अभी सौ वर्ष पहले तक ही, हमारे कुल सर्वाधिक सम्मानित नागरिकों की राय थी कि 'जनता' के लिए शिक्षा अनुचित, अनावश्यक, और निश्चित रूप में खतरनाक थी ।

अपने शासन को बहुमत की इच्छा के अनुसार चलाने की राजनीतिक स्वतन्त्रता के फलस्वरूप, सार्वजनिक शिक्षा को धीरे-धीरे सारे अमरीका में अपना लिया गया । आज सार्वजनिक शिक्षा सम्बन्धी हमारी धारणा और भी विस्तृत हो रही है, और

अन्ततः इसका यह परिणाम हो सकता है कि सभी योग्य छात्रों को कालेजों में प्रवेश मिले ।

अधिक व्यापक मानवी अधिकारों के लिए इस लम्बे संघर्ष का एक और पक्ष बीमारी के बोझ से अधिकाधिक लोगों को मुक्त करने से सम्बन्धित है । हमने यह निश्चय कर लिया कि मानसिक रोगी, अंधे विकलांग, क्षयग्रस्त, और अन्य रोगी तथा पंगु लोगों को अनुपयोगी और सहायता के परे मान कर नहीं छोड़ दिया जाएगा ।

अपने नगर, राज्य, और संघ शासन के द्वारा, इन लोगों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी खोज, पुनर्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और अस्पताल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए हमने अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया । मैं समझता हूँ कि अन्त में हम किसी व्यावहारिक पद्धति के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर सकेंगे जिससे रोगी की रोकथाम के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ हमारे सभी नागरिकों को प्राप्त हों, चाहे उनकी आय जो भी हो ।

हमारी सार्वजनिक अन्तरात्मा के विकास का एक और उदाहरण यह है कि हम अपने वृद्ध लोगों को, जिन्हे कठोर औद्योगिक समाज पहले दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकता था, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, और आराम का एक अच्छा न्यूनतम स्तर—संक्षेप में, अधिक मानवी स्वतन्त्रता—प्रदान करने का अधिकाधिक प्रयत्न कर रहे हैं । एक अन्य उदाहरण गन्दी वस्तियों की सफाई करने के कार्यक्रमों का है, ताकि हमारे अधिकाधिक नागरिकों को अच्छे आधुनिक घरों में रहने और अपने परिवारों का पालन-पोषण करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो ।

हम जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वह भौतिक धन की समानता नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता और रुचियों के अनुसार रहने, काम करने, और आगे बढ़ने के अवसरों की समानता है, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का हमारा और हमारे बच्चों का अधिकार है, मूल न्यूनतम सुरक्षा का अधिकार है । इनके अतिरिक्त, अधिकाधिक राजनीतिक और नागरिक स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य है, जो हमेशा अमरीकी उदारवादी परम्परा का आधार रही है ।

यह प्रमाणित करना हमारी पीढ़ी का कार्य है कि 'मनुष्य के अधिकारों' को सफलतापूर्वक अठारहवीं सदी से बीसवीं सदी में लाया जा सकता है ।

नई आप्रवास नीति की आवश्यकता

नम्बर, 1951 में सबे पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में हमारी अन्धी और भेदभावपूर्ण आप्रवास नीति की श्री वॉल्स आलोचना करते हैं, और एक ऐसे दृष्टि कोण का समर्थन करते हैं, जिसमें सभी योग्य आवेदकों को एक-सा अधिकार हो, चाहे उनकी मूल राष्ट्रीयता जो भी हो।

अमरीका को आप्रवास सम्बन्धी एक नई नीति की बड़ी आवश्यकता है। हमारी वर्तमान नीति की उत्पत्ति हार्डिंग और कूलिज के युग में हुई थी, जब हमने नासमन्ती के साथ यह निश्चय कर रखा था कि हम अपने को दुनिया, उसकी समस्याओं, और उसके लोगों से अलग रखेंगे। इसके सिद्धान्त पुराने पड़ चुके हैं, भेदभावपूर्ण हैं, और उन लोकतांत्रिक धारणाओं का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं, जिन पर हमारे देश का निर्माण हुआ है।

स्वतन्त्रता के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने के समय में 1921 तक, अमरीका ने सारी दुनिया से आए आप्रवासियों का उदारता से स्वागत किया। फलस्वरूप, लगभग चार करोड़ स्त्री-पुरुष और बच्चे अमरीका में स्वतन्त्रता और संभावनाओं के नए जीवन का निर्माण करने के लिए समुद्रों को पार करके आए।

अमरीका में नए आने वाले का यह प्रवाह, ज्ञात इतिहास के सबसे बड़े निष्क्रमणों में से एक है। बीसवीं सदी के पहले दस वर्षों में, आप्रवासियों का औसत दस लाख स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रतिवर्ष था—हमारी उस समय की जनसंख्या के एक प्रतिशत से अधिक। 1910 तक, अमरीका में रहने वाले सभी लोगों में से 40 प्रतिशत या तो स्वयं विदेश में पैदा हुए थे, या उनके माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक का जन्म विदेश में हुआ था।

आज अमरीका की शक्ति आंशिक रूप में इस कारण है कि अरसे तक हमने उदारतापूर्वक यूरोप के लोगों को अपने में शामिल किया। हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्वानों, वैज्ञानिकों, सार्वजनिक अधिकारियों, व्यापार और श्रम के नेताओं में से कई पचास वर्ष पूर्व के आप्रवासियों के पुत्र या पौत्र हैं।

1921 में सर्वप्रथम प्रतिबन्धात्मक कानून बनाये गए। इसके द्वारा, अमरीकी महाद्वीप के अन्ध भागों से नए आने वालों को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप में छूट दी गई, प्रति वर्ष 3, 50, 000 आप्रवासियों की अधिकतम सीमा बांध दी गई।

इन प्रतिबन्धों का यह असर पड़ा कि आप्रवासियों की वार्षिक संख्या, पहले महायुद्ध के पूर्व प्रति वर्ष आने वालों की औसत संख्या की एक तिहाई रह गई। इनमें अलग-अलग राष्ट्रों के लिए संख्या निर्धारण में पूर्वी और दक्षिणी यूरोप से आ सकने वाले के विरुद्ध गहरा भेदभाव बरता गया।

सेप्टिम्बर 1921 का कानून तो केवल एक शुद्धांत थी। 1924 में नया कानून बनाया गया, जिसमें आप्रवासियों की कुल संख्या आधी से भी कम कर दी गई, और दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के लोगों के विरुद्ध और भी कठोर भेदभाव बरता गया। यही कानून, जो 1929 में फिर संशोधित किया गया, अब भी हमारी आप्रवास नीति का आधार है।

इस तीस वर्षीय आप्रवास नीति का पहला लक्ष्य, स्पष्टतः, हमारे देश में आने वाले आप्रवासियों की संख्या को कम करना रहा है। यह लक्ष्य भलीभांति पूरा हुआ है। यद्यपि 1914 के बाद से हमारी जनसंख्या एक तिहाई बढ़ गई है, लेकिन पहले महायुद्ध के तत्काल पूर्व के चौदह वर्षों में, प्रतिवर्ष अमरीका आने वाले आप्रवासियों की औसत संख्या का छटा भाग ही 1924 के कानून द्वारा निर्धारित संख्याओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष आने पाता है।

आप्रवासियों की संख्या में इतनी बड़ी कटौती स्पष्टतः उस समय भी गलत थी, जब 1924 में हमारी वर्तमान नीति प्रतिष्ठित हुई। ऐसी कठोर नीति अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे एक विश्व संघर्ष के बीच और भी गलत है। इस संघर्ष में सफल होने की हमारी योग्यता, हमारे लोगों की शक्ति, विश्वास और योग्यता पर निर्भर है।

इस तथ्य से कौन इन्कार कर सकता है कि पिछले एक सौ वर्षों में जो लाखों व्यक्ति अमरीका आए, उन्होंने न केवल आर्थिक शक्ति के सन्दर्भ में, वरन् अध्यात्मिक मूल्यों में भी, हमें असीमित बल प्रदान किया है ?

हमारी वर्तमान अमपूर्ण आप्रवास नीति का दूसरा लक्ष्य कानून द्वारा यह तय करने की चेष्टा करना रहा है, कि किस प्रकार के लोग 'सर्वोत्तम' अमरीकी नागरिक बनते हैं। इस लक्ष्य के अनुरूप, हमारे आप्रवास सम्बन्धी कानूनों का आग्रह है कि अंग्रेज और जर्मन लोग, इटली और रूस के लोगों की अपेक्षा ज्यादा वांछनीय अमरीकी होते हैं।

राष्ट्रीयता के 'बर्गे' की यह धारणा लाखों अमरीकियों को निम्न कोटि के नागरिकों का स्थान देने का यह प्रयास, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है। यह अलोकतांत्रिक ही नहीं है, हास्यास्पद है।

इस बात का कोई भी प्रमाण कहाँ है, कि उन अमरीकियों की अपेक्षा, जो पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के लोगों के वंशज हैं, हमारे देश के निर्माण में उन अमरीकियों का योग कम रहा है, जो दक्षिणी या पूर्वी यूरोप के लोगों के वंशज हैं ?

यातुल्य, वे राज्य जिनमें पोलैंड, इटली, यूनान, घोर पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के अन्य देशों से घाटे आप्रवासी प्रवृत्तियाँ बने हैं—न्यूयार्क, मंगोलिया, रोड आइलैंड, कनिक्टिकट, न्यूजर्सी, पेन्सिलवेनिया, घोर मिगिगन—ने घब देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से हैं। प्रगतिशील विधि-निर्माण में वे घाटे हैं।

निम्नलिखित तुलनाओं से पता चलता है कि 1924 के कानून ने हमारी नीति के एक धंग के रूप में कितने बड़े भेदभाव की प्रतिष्ठित किया है।

पहले महायुद्ध के तत्काल पूर्व के वर्ष 1914 में इटली ने 2,96,000 आप्रवासी घाए थे। 1921 के अधिनियम ने इसे घटाकर 42, 000 प्रतिवर्ष कर दिया। घोर 1924 के कानून द्वारा निर्धारित, इटली के आप्रवासियों की वर्तमान सीमा केवल 5,000 प्रतिवर्ष रह गई है।

1914 में पोलैंड से 1, 74, 000 आप्रवासी अमरीका घाए। 1921 के कानून ने उनकी संख्या घटाकर 30, 000 कर दी, घोर 1925 के कानून ने कुल 6, 000। यूनान से 1907 में 46, 000 लोग हमारे देश में घाए थे, लेकिन अब केवल 207 व्यक्ति प्रति वर्ष ही आ सकते हैं।

इनके विपरीत, 1921 के कानून ने इजलिस्तान घोर उत्तरी आयरलैंड से घाने वालों की उच्चतम सीमा 77,000 निर्धारित की जो इन देशों से किसी एक वर्ष में आने वालों की अधिकतम संख्या से कुछ ही कम थी। 1924 के कानून में भी, जब कुल आप्रवासियों की मध्या आधी कर दी गई, तो इजलिस्तान के हिस्से को केवल 65,000 तक ही घटाया गया। इस कानून के अन्तर्गत, जर्मनी के आप्रवासियों की कुल वार्षिक संख्या, इटली, यूनान, घोर पोलैंड सहित दक्षिणी यूरोप के सभी देशों की कुल संख्या से काफी अधिक है।

यद्यपि युद्ध के प्रभाव के अन्तर्गत कांग्रेस द्वारा 1948 में स्वीकृत 'विस्थापित व्यक्तियों' से सम्बन्धित कानून ने विशेषतः कठिन परिस्थितियों में फँसे हुए बहुतेरे आरण्विधियों को तत्काल अमरीका आने की अनुमति दे दी, किन्तु इसने हमारी मूल नीति को असोधित नहीं किया। इन कानून के अन्तर्गत जिन 3, 30, 000 आप्रवासियों को आने दिया गया है, लगभग उन सभी की गिनती सम्बन्धित देशों से भविष्य में आ सकने वालों में कर ली जाएगी।

इसका अर्थ है कि अगर वर्तमान कानून को बदला नहीं जाता, तो भविष्य में कई वर्षों तक, कुछ ऐसे विशेष मामलों की अपेक्षतमा छोटी संख्या को छोड़कर, जो संख्या-निर्धारण के प्रतिबन्धों में नहीं आते, दक्षिणी घोर पूर्वी यूरोप के देशों से आप्रवासियों का आना वित्तकुल बन्द रहेगा।

हम इस कानून में से दक्षिण घोर पूर्वी यूरोप के विरुद्ध किये गए घुरे भेदभाव को भी समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय संख्या-निर्धारण को सतम कर देना चाहिए। जहाँ तक जाति, रंग, धर्म घोर मूल राष्ट्रीयता का प्रश्न है, सभी प्रायियों को एक ही स्तर पर रखना चाहिए।

नए आवास कानून के शुरू के वर्षों में अधिकांश राष्ट्रों की निर्धारित संख्या जल्दी ही भर जाती थी, और दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वालों की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन 1930 के बाद, मन्दी के फनस्वरूप, आवासियों की संख्या घट गई और 1940 और बाद, युद्ध के कारण और भी कमी आई। 1940 और 1946 के बीच अंग्रेजों ने अपनी काफी बड़ी वार्षिक संख्या के केवल पाँच प्रतिशत का उपयोग किया, और आवासियों ने केवल 3 प्रतिशत था। सभी देशों का कुल औसत केवल 23 प्रतिशत था। हमें चाहिए कि इस कमी को पूरी करने के लिए आवासियों को आने दें, और इसमें राष्ट्रीयता का कोई भेद न करें।

मेरा सुझाव है कि हम अपनी जनसंख्या के एक प्रतिशत के दो बटा पाँच हिस्से को आवासियों की अधिकतम वार्षिक सीमा निर्धारित करें, जिसमें अमरीकी महा-द्वीप के बाहर के सभी देश शामिल हों, और कोई राष्ट्रीय सीमाएँ न बाँधी जाएँ। अमरीका के अन्दर-अन्दर विकास के समर्थक लोग जितना पसन्द करेंगे, उससे यह संख्या अधिक हो सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अधिकांश अमरीकी इस अनुपात को काफ़ी कम मान कर स्वीकार कर लेंगे।

ऐसे किसी कानून के अन्तर्गत किस तरह के लोग अमरीका में आएँगे? क्या उनमें अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता होगी? क्या वे सबल, कानून का आदर करने वाले, और निष्ठावान होंगे? साम्यवादियों, फ़ासिस्टों, और अन्य अवांछनीय तत्वों के आने का खतरा कितना है?

पीढ़ियों से, यूरोप के हर कस्बे, गाँव, और शहर में, ऐसे बसियों, संकड़ों, और हजारों व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने अमरीका को एक स्वप्न देश समझा, जिसमें किसी दिन जाकर रहने की उन्हें आशा थी। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम थी जिनमें सचमुच इतना साहस और लगन थी कि वे हजारों मील समुद्र को पार करके अपने परिवारों को एक दूर देश में नए घरों में ले जाएँ, और ये आमतौर पर सबलतम, योग्यतम, और सर्वाधिक हृद-निश्चयी लोग थे।

आज लाखों ऐसे लोग, जो अपने पुराने देशों से एक, दो या तीन पीढ़ी से ही दूर रहे हैं, संकड़ों विभिन्न रीतियों से हमारी आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के स्वस्थ विकास में योग दे रहे हैं। जबके हमारे पुराने परिवारों में से कुछ में यह प्रवृत्ति रही है कि अपने अतीत की गरिमा में ही खोए रहे, और लोकतंत्र को पूर्व-स्थापित मानकर चलें, इन अपेक्षित नए आने वालों में से बहुतेरे हमारे सम्पूर्ण अमरीकी समाज में नया जीवन और नए प्राण फूँकते रहे हैं।

विदेशों से प्रति वर्ष कुछ हजार नए अमरीकियों के आ जाने से, जो स्वास्थ्य, चरित्र, और योग्यता के आधार पर चुने गए हों, हम कौशल, कल्पना और क्षमता के अपने राष्ट्रीय भंडार में और अधिक वृद्धि करेंगे। और चूँकि ये नए नागरिक बिना राष्ट्रीयता, जाति, या धर्म का ध्यान रखे चुने गए होंगे, अतः वे दुनिया के सामने यह

प्रमाणित करेंगे कि घमरीबा में पहले की भांति छात्र भी सोचने-बोचने एवं गारा ही नहीं है।

जहाँ तक साम्यवादियों, जागिरदों, और अन्य 'परादेशीय' तारों का सम्बन्ध है, हमारी घमरीबा छात्राग सेवा उन्हें छूटने में बड़ी सुगम हो गई है। विश्वानिध व्यक्त अधिनियम के अन्तर्गत जो द्वार्द साम्य स्त्री-पुरुष छात्र, उनमें से। जनवरी, 1951 तक केवल तीन रिगो कारखानेयता देस से निर्वाणित सिने गए।

सूयंततपूणं रीति से प्रतिबन्ध लगाने और भेदभाव करने वाले अपने छात्राग कानूनो की चुनौती को हम स्वीकार करें। इस सम्बन्ध में जायंयाही की उम्मत बट्टा दिने से है।

एक अमरीकी कस्बे का चित्र—एकसेस, कॉनेक्टिकट

समाज कल्याण से सम्बन्धित भारतीय श्रोताओं के समक्ष, 1952 के आरम्भ में, श्री थॉमस अमरीका के एक छोटे-से कस्बे का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह भाषण बाद में प्रकाशित हुआ, और सारे हिन्दुस्तान में कई भाषाओं में वितरित किया गया।

मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि एक देश के लोग सचमुच किसी अन्य देश के लोगों को उस समय तक नहीं समझ सकते, जब तक कि वे यह न जान लें कि दूसरे देश के लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके अनुभव और उनकी आशाएँ क्या हैं।

मेरे लिए, हिन्दुस्तान में सबसे रोचक और फलप्रसन्न समय वह रहा है, जब मैं गाँवों, छोटे कस्बों और बड़े शहरों की यात्रा करता रहा हूँ, मोहल्लों में जाता रहा हूँ, और यह देखने की कोशिश करता रहा हूँ, कि लोग कैसे रहते हैं, किन बातों के बारे में सोचते हैं, और कैसे अपने बच्चों को पालते हैं।

चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे देश को समझें, इसलिए मैं आपको कॉनेक्टिकट राज्य में एसेक्स के छोटे-से कस्बे के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ।

कॉनेक्टिकट अमरीका के उत्तर-पूर्वी भाग में एक छोटा-सा राज्य है, जिसकी आबादी केवल बीस लाख है। यह 1635 में बसा था, और हमारे सबसे पुराने राज्यों में से भी है। यह तारीख आपको तो कुछ ही समय पहले की प्रतीत होगी, लेकिन मेरे देश के लिए बहुत पुरानी है।

कॉनेक्टिकट को इंग्लिस्तान से आये हुए लोगों ने बसाया। वे अधिकांश किसान थे जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए आए थे, जिसके वे अपने देश में शिकार हुए थे। वे इसलिए आए थे कि निरंकुशता और तानाशाही से स्वतंत्र होकर, अपनी इच्छानुसार ईश्वर की उपासना कर सकें, और जिस तरह उचित समझें, अपना जीवन बिता सकें।

कॉनेक्टिकट की अधिकांश भूमि, जिसे वे जोतते थे, बजर और पथरीली थी, और सर्दी बड़ी कठोर होती थी। अतः उन्नीसवीं सदी के मध्य में, जब उन्होंने अमरीकी पश्चिमी की नई आश्चर्यजनक भूमि के बारे में सुना, जहाँ लगभग किसी भी

दिशा में, आप मौन भर तक हल चलाते चले जा सकते थे, जहाँ भूमि उपजाऊ और जलवायु अधिक अनुकूल थी, तो पूरे के पूरे गाँव और कस्बे उठ कर पश्चिमी की ओर चले गए।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में, यूरोपीय आप्रवासियों की नई लहर ने कॉनेक्टिकट को फिर से बसाया। आज राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर न्यू हैवेन, 65 प्रतिशत 'इटालवी' है—अर्थात्, वहाँ के 65 प्रतिशत लोगो का, या उनके माता-पिता अथवा नाना-दादा में से किसी का जन्म इटली में हुआ था। इसी तरह, न्यू ब्रिटेन में 60 प्रतिशत 'पोलैंडवासी' हैं, और राज्य की राजधानी हार्टफोर्ड में 40 से 50 प्रतिशत तक 'आयररी' लोग हैं।

सिवाय उसके लोगों के, कॉनेक्टिकट में प्राकृतिक साधन लगभग नहीं हैं। वहाँ न कोई खाने हैं, न तेल। फिर भी, कॉनेक्टिकट में प्रति व्यक्ति आय अमरीका में सबसे अधिक है, मुख्यतः इस कारण कि वहाँ के लोग बड़े ही कुशल हैं। हमारे सैकड़ों कारखानों में, हर प्रकार के विनिर्माण कार्य में, यह कौशल रचनात्मक कार्यों में लगता है, और बदले में लोगों को उच्च वेतन मिलता है।

सो वर्ष पहले कॉनेक्टिकट के केवल 15 प्रतिशत भाग में जंगल था। शेष पर खेती होती थी। यद्यपि राज्य की आबादी अब पहले से बहुत अधिक घनी हो गई है, और कई बड़े शहर हैं, लेकिन 70 प्रतिशत भूमि फिर से जंगल हो गई है, और पुराने खेतों में से अधिकांश जंगल में आ गए हैं।

राज्य में दो बड़े विश्वविद्यालय हैं—येल विश्वविद्यालय और कॉनेक्टिकट विश्वविद्यालय—जिनमें कुल लगभग बारह हजार छात्र-छात्राएँ हैं। सात छोटे कालेज और अध्यापकों के प्रतिक्षण के लिए चार विशेष कालेज भी हैं।

हमारी सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं, जितनी हमारी राय में होनी चाहिए। हम उसे सुधारने की निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं। हम इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉनेक्टिकट के हमारे बच्चे अधिक सख्या में कालेज जा सकें। हमारे कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक सभी लड़के-लड़कियों का स्कूल जाना आवश्यक है। उनमें से लगभग 30 प्रतिशत 'हार्ड स्कूलों' या माध्यमिक स्कूलों से उतीर्ण होने के बाद विश्व-विद्यालयों में जाते हैं।

हम अपनी आवास व्यवस्था और अपने अस्पतालों को भी सुधारने की निरन्तर चेष्टा कर रहे हैं, और यहाँ भी अच्छी प्रगति हो रही है। अपने सभी लोगों के लिए अधिक फायदेकर, और अधिक आत्म-सम्मानपूर्ण जीवन का आधार निर्मित करने के लिए, हम हर सभव प्रयत्न कर रहे हैं।

जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, ऐसे हैं, उसमें लगभग 3,500 लोग रहते हैं। यह अति सुन्दर नगर कॉनेक्टिकट नदी के किनारे बसा हुआ है। एमेक्स के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। पाँच छोटे-छोटे कारखाने हैं, जिनमें से सबसे बड़े बारताने में लगभग दो सौ व्यक्ति काम करते हैं। कुछ लोग वर्ष में दो से छह महीने

सक किसी कारखाने में काम करते हैं, अन्य चार-पांच महीनों तक खेती करते हैं, और एक महीना मछली पकड़ते हैं। हर साल वसन्त में नदी में बड़ी मछलियाँ होती हैं, और ग्राम तीर पर उनका अच्छा मूल्य मिलता है।

एसेक्स में बहुत धनी लोग नहीं हैं, और न सचमुच बहुत गरीब लोग हैं। वहाँ के सात सौ परिवारों में से, मैं केवल पन्द्रह-बीस को गिन सकता हूँ, जिनके पास कोई नौकर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, केवल एक परिवार के पास दो नौकर हैं।

वात यह है, कि भ्रमरीका में नौकरों को इतना अधिक वेतन मिलता है, कि हममें से अधिकांश नौकर नहीं रह सकते। यह भी एक कारण है कि हम इतने सारे द्विजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसे लेकर मेरे कुछ भारतीय मित्र हमारे साथ मजाक करते हैं। हमने ये उपकरण नौकरों का स्थान लेने के लिए बनाए हैं।

हमारे कस्बे के दासन को 'प्रत्यक्ष लोकतन्त्र' कहा जा सकता है। अगर ग्राम चुनाने के नए इजन, या किसी नई सड़क या स्कूल की जरूरत हो, तो नगरपालिका कार्यालय पर एक सूचना लगा दी जाती है कि अमुक तारीख की रात को उस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए नगर-सभा होगी।

कस्बे में मतदान योग्य आयु के वे सभी लोग सभा में आते हैं, जिनकी सम्बन्धित प्रश्न में रुचि होती है। वे एक सभा सचालक चुनते हैं, जो सभा की अध्यक्षता करता है, और सारा कस्बा किसी विधान-मंडल या विधान सभा की तरह काम करता है, जिनमें हर व्यक्ति का एक वोट होता है। उस रात हम सड़क, या दमकल, या स्कूल या और जो भी प्रश्न हो, उसके सम्बन्ध में एक लोकतांत्रिक निर्णय करके घर लौटते हैं।

अपना शासन चलाने के लिए एसेक्स में नगर सभा के प्रतिरिक्त तीन मुख्य नगर अधिवारी होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें 'सेलेक्टमेन' कहा जाता है। 'सेलेक्टमेन' बहुमत वाले दल के सदस्य होते हैं, और तीसरा अल्पमत वाले दल का सदस्य होता है। उसका काम है कि वह बहुमत दल के सदस्यों पर नज़र रहे ताकि हम सभी के हितों को ईमानदारी से और कुशलतापूर्वक ध्यान में रखा जाय।

मैं कह सकता हूँ कि हमारे कस्बे में अधिकांश लोगों की सर्वाधिक रुचि अपने परिवार और गिरजाघर के चारों ओर चलने वाली जिन्दगी में रहती है। कस्बे में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, और यहूदी मतों के लगभग बारह भिन्न गिरजाघर हैं। पर और गिरजा, अधिकांश लोगों के लिए यही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं।

विदेशों से आने वाले जो लोग हमारे छोटे भ्रमरीकी कस्बों में जाते हैं, वे यह गोच मारते हैं कि मेरे सह नागरिकों में से कुछ का दृष्टिकोण संबुद्धित है यह सच है कि हम बहुधा स्वयं अपनी समस्याओं में इतना फँस जाते हैं, कि हम में से कुछ लोग दुनिया की समस्याओं के बारे में पर्याप्त विचार नहीं करते। लेकिन यह स्थिति तेज़ी से बदल रही है। जिस उलझी हुई और परस्पर सम्बद्ध दुनिया में हम लोग हम समय रह रहे हैं, उसकी चुनौती के प्रति भ्रमरीका के अन्य स्थानों की भाँति एसेक्स के लोग

भी जागरूक हो रहे हैं। ये उन समस्याओं के ज्यादा अच्छे उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो हम सभी की समस्याएँ हैं, जैसे यही माग लोग कर रहे हैं।

जब भी मैं हिन्दुस्तान में घर बापन गया हूँ, मुझे घाघा दर्जन निमंत्रण मिलते हैं कि मैं हिन्दुस्तान के बारे में बोलूँ—हिन्दुस्तान के लोग बिग तरह सोचते हैं, आप किस तरह के लोग हैं, कैसे रहते हैं, यानी आपके बारे में सभी कुछ। अब हर सप्ताह हर प्रकार के ऐसे विषयों पर सभाएँ होती हैं, जिनमें दस या पन्द्रह वर्ष पहले भी लोगो में रचि ही नहीं थी।

अगर आप मुझसे पूछें कि एमेक्स में मेरे सह-नागरिक दुनिया में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, तो मैं बूढ़ेगा विश्व-शांति—एक ऐसे भविष्य की ओर देखने का भवगर जो घृणा और कटुता से मुक्त हो, उम सपर्य से मुक्त हो, जिसे अपने जीवनकाल में हमने इतना अधिक देखा है।

अगर आप रजिवार को एमेक्स के हमारे गिरजाघरों में जाएँ तो आप धर्मोपदेशों में बार-बार सभी जातियों और धर्मों के लोगो के बीच शांति और सद्भावना की प्रील सुनेंगे। आप लोगो को सिर झुकाकर विश्वशांति के लिए प्रार्थना करते सुनेंगे।

मेरे ये पडोसी तर्क-बुद्धि में विश्वास करने वाले लोग हैं, और सोचते हैं कि शांति की समस्या केवल इतनी ही है कि सभी लोग तर्क-बुद्धि से काम करें। एक धर्म में उनका सोचना ठीक है। अगर सभी लोग तर्क-बुद्धि से और समझदारी से काम लें, अगर सभी लोग दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कुछ अधिक चेष्टा करें, अगर एक देश को दूसरे से काटने वाले लौह-आवरण न हो, तो शांति की उपलब्धि कुछ ज्यादा आसान हो जाय।

अगर आप मेरे पडोसियों को मेरी तरह जानते, तो आप देखते कि उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें किसी के विषय सचमुच कोई बटुता है। आप उन्हें बहुत कुछ वही बातें सोचते और कहते पाएँगे, जो यहाँ हिन्दुस्तान में आप लोग सोचते और कहते हैं। सबसे अधिक उन्हें यह आशा है कि विश्व में सच्ची सद्भावना के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करने का कोई उपाय निकलेगा।

मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान से बहुतरे लोग अमरीका जाकर मेरे कस्बे की तरह सामान्य कस्बों को देख सकेंगे और एसेक्स में मेरे पडोसियों की तरह सामान्य लोगो से बातचीत कर सकेंगे।

मैं यह भी आशा करता हूँ की अमरीकी लोग और अधिक संख्या में हिन्दुस्तान आकर हिन्दुस्तान की जिन्दगी को—पारिवारिक जीवन को, मोहल्लों और गाँवों की जिन्दगी को—देख सकेंगे, और इस तरह हिन्दुस्तान के लोगो को, दुनिया को आप जो कुछ सिखा सकते हैं, उसे ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे, जैसे मैंने आपको जाना है।

नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख सकते हैं

मॉण्टगोमरी, अलाबामा में, 1957 के अंत में, मार्टिन लूथर किंग ने वसों के एक असाधारण बहिष्कार का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जो महात्मा गांधी के सिविल नाफरमानी के सिद्धान्तों पर आधारित था। 1 मार्च, 1958 के सेंटरडे इवनिंग पोस्ट में प्रकाशित इस लेख में श्री बौल्स महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली का, और अमरीका की जातीय समस्या के सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता का संक्षिप्त विवेचन करते हैं।

नीग्रो उपदेशक ने अपने गिरजा-क्षेत्र के लोगों से कहा, "आइए, हम फिर से अभ्यास करें। मैं एक गोरा आदमी हूँ, और मैं आपका अपमान करता हूँ, आपको धक्का देता हूँ। संभवतः आपको मार भी देता हूँ। आप क्या करेंगे?"

उनका उत्तर तैयार था — "मैं शांत रहूँगा। मैं हटूँगा नहीं। मैं मुड़कर माहूँगा नहीं। मैं दूसरा गाल भी मारने कर दूँगा।"

1956 में दिसम्बर की एक शाम थी। एक वर्ष तक पैदल काम पर जाकर और सामान्य भंडारों में संगठित की गई सैकड़ों मोटरों में सवारी करके, मॉण्टगोमरी, अलाबामा के 42,000 नीग्रो नगरिकों ने बिना भेदभाव के वसों में सवारी करने के अपने सवैधानिक अधिकार को मनवा लिया था।

अपने काम के दिन से वसों में नए नियम लागू होने वाले थे। अब वे अपने गिरजा-घरों में बैठने के स्थानों को वसों की सीटें मान कर धीरज के साथ अभ्यास कर रहे थे कि मानवीय सम्बन्धों की इस सर्वाधिक विस्फोटक समस्या में अपने ईसाई सिद्धान्तों पर किस प्रकार धावरण करें।

उनके पादरी ने उन्हें सलाह दी, "याद रखिए अहंकार मत कीजिए। गोरे मुनाफ़िरोँ पर रोव मत दिखाइए। धैर्य और आदर दिखाइए। आप उनके साथ वही व्यवहार करें, जो आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें।"

उनके बाद के सप्ताहों में गोरे कट्टर-बंधियों ने गोलियाँ चलाईं, बम फेंके, और नीग्रो लोगों व उनके नेताओं का बुरी तरह अपमान किया और धमकियाँ दीं। लेकिन वे बिना अहंकार या कटुता के अपनी जगह पर हड़ और सौम्य सड़े रहे।

जब धारितरकार उनकी जीत हुई, तो बहुतेरे गोरे नागरिकों को जो बसों में भेद-भाय की समाप्ति का प्रतिरोध मंगटित करने में सक्रिय रहे थे मजबूरन बहना पड़ा, "नीग्रो लोगो ने अभी जो कुछ किया है, उसकी दामता उनमें थी इतो हम नहीं जानते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उनका आदर करने लगे लेकिन ऐसा हो गया है।"

पहाडी पर (ईसा के) उपदेश का यह प्रागुनिक व्यावहारिक प्रदर्शन कौं सम्भव हुआ ? किन पद्धतियों ने इसे संभव बनाया ?

माण्टगोमरी के कार्यक्रम की गहरी अध्मारिमक जड़ें, न केवल ईसाइयत में, बरन् एशिया के प्राचीन धर्मों में भी थी। सत्ताइस वर्षोंय नीग्रो पादरी, माटिन लूथर, विंग जो कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्य किसी भी व्यक्ति ने ज्यादा जिम्मेदार थे साफनौर पर बहते हैं कि उन्होंने अपनी पद्धतियाँ सीधे गांधी जो से ली हैं, जिन्होंने करोड़ों हिन्दु-स्तानियों को आजादी दिलाने के लिए प्रतिभाशाली नीति से उनका प्रयोग किया था।

स्वयं गांधीजो को हसी लेखक टॉल्मटाय के अतिरिक्त, अमरीका के घोरोसे प्रेरणा मिली थी जिन्हें भगोडे नीग्रो लोगों से सम्बन्धित कानून का 'शांतिपूर्ण विरोध' करने के कारण मँसाचुनेट्स में बाराबास का दण्ड मिला था। घोरो के निबन्ध 'मिविल डिसग्रोबीडिएन्स' (मिविल नाकरमानी) ने ही गांधी जी ने यह शब्द लिया था जिमका प्रयोग उनके कार्यक्रम का अर्थान करने के लिए आमतौर पर किया जाता है।

अपने को कठोर-प्रकृति समझने वाले बहुतेरे अमरीकी, माँण्टगोमरी की घटनाओं को एक विशेष स्थिति कहकर टाल दे सकते हैं, और इस सुभाव की हँसी उड़ा सकते हैं कि इन पद्धतियों से सचमुच उन विस्फोटक जातीय विरोधों को कम किया जा सकता है, जिनमें बहुतेरी अमरीकी बरितियाँ बुरी तरह फँसी हुई हैं। लेकिन एक बात निश्चित है—गांधी जी की अंतिम सफलता के पहले उनके समकालीन लोग इस सम्बन्ध में जितने शकालु थे, इन अमरीकियों की सशयालुता उससे अधिक नहीं है।

गांधी जी के सवर्ष की शुष्प्रात, और माँण्टगोमरी के बहिष्कार के बीच कई महत्त्वपूर्ण समानताएँ हैं। माँण्टगोमरी का आन्दोलन एक घटना से आरम्भ हुआ, जो विकसित होकर एक धर्मयुद्ध बन गया।

एक शांत-स्वभाव नीग्रो दंजिन, श्रीमती रोजा पार्क्स को कई अघसरों पर बस में अपनी जगह गोरे लोगों को देनी पड़ी थी। लेकिन एक दिन, किसी ऐसे कारण से प्रेरित होकर, जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझती, उन्होंने अचानक अपनी जगह से न हटने का निरुण्य किया। जब बस के चालक ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो उन्होंने उत्तर दिया, "तो आप उन्हें बुला लीजिए।"

श्रीमती पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नीग्रो धार्मिक नेताओं ने एक दिन के लिए बसों के नगर-व्यापी बहिष्कार की अपील की। जब गोरे कट्टर पक्षियों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, तो विरोध-प्रदर्शन बढ़ा, यहाँ तक कि पूरे नगर की बस व्यवस्था, और माँण्टगोमरी का लगभग हर नीग्रो परिवार इससे प्रभावित हो गया।

गांधी जी का आन्दोलन, जिसने अन्ततः भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया,

नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख सकते हैं

बहुत कुछ इसी प्रकार आरम्भ हुआ था उनके साथ, आन्दोलन को आरम्भ करने वाली चिंगारी 1893 में, दूरस्थ, जातिभेद से ग्रस्त दक्षिण अफ्रीका में एक रेलगाड़ी में पंदा हुई थी।

गांधी उस समय तेइस वर्ष के एक युवा वकील थे, और एक मुकदमे में एक भारतीय नागरिक की ओर से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में पहली रेल यात्रा करते हुए रात के समय उन्हें आदेश दिया गया कि वे गोरे लोगों के लिए आरक्षित डिब्बे को छोड़ दें। जब उन्होंने इन्कार किया, तो अगले स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया।

उनका बड़ा कोट और सामान रेलगाड़ी में ही रह गया, जो तेजी के साथ दृष्टि से धोभल हो गई। सुबह की ठंड में कांपते हुए, उन्होंने अपने-प्राप से महानिष्ठा प्रदर्शन पूछा, "क्या मैं यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपने और अन्य तिरस्कृत लोगों के अधिकारों के लिए लड़ूँ, या हार मानकर हिन्दुस्तान वापस चला जाऊँ?"

उन्होंने लिखा है, "मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हिन्दुस्तान वापस चले जाना कायरता होगी।" उन्होंने तय किया कि, "यही काम को किसी भी मूल्य पर करने की हिम्मत करना ही सबसे श्रेष्ठ नियम है।"

बाद में जब वे प्रीटोरिया के लिए घोड़ागाड़ी पर रवाना हुए, तो उन्हें 'सैमी' कहकर बुलाया गया, बाहर एक गंदे बोरे पर बैठने को कहा गया, और एक भारी-भरकम गोरे ने उन्हें पीटा। प्रीटोरिया पहुँचने पर होटलो ने उन्हें कमरा देने में इन्कार कर दिया। आखिरकार एक अमरीकी नीग्रो ने उनकी सहायता की और किसी प्रकार उनके ठहरने का प्रबन्ध किया।

अगले दिन गांधी जी ने प्रीटोरिया के भारतीयों को एक सभा में बुलाया, जहाँ उन्होंने मुझाव दिया कि वे सहम करें, और अपने साथ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध लड़ें, और यह उड़ाई नए रचनात्मक तरीके से चलाई जाय।

गांधी जी ने कहा कि सच्चे पड़ोसियों का समाज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अतः हमारा तरीका हिंसा का न होकर समझाने-बुझाने का होना चाहिए। भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय को घृणा का परित्याग करना होगा। गोरों के अन्यायपूर्ण, भेदभाव करने वाले कानूनों का विरोध करते हुए भी, उन्हें अपने गोरे पड़ोसियों का, अपने जैसे मनुष्यों के रूप में आदर करना होगा।

उन्हें अविषस रहकर, और बिना उलट कर हाथ उठाए, या किसी का अपमान किए, चोटें सहने और जेल जाने के लिए अपने को तैयार करना होगा। उन्हें न केवल शब्दों से, बल्कि अपने जीवन के द्वारा दूसरों को समझाना होगा। अपने शब्दों को उन्हें जीवन में उतारना होगा।

उन्होंने कहा, "हम पहले इस पर विचार करें कि हमारे विरुद्ध गोरे लोगों को क्या शिकायतें हैं। हम देखें कि हमारे साथ भेदभाव करने के पक्ष में गोरे लोग जो कारण या तर्क देते हैं, क्या वे उचित हैं।"

उन्हें चुनने के लिए प्राये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो अपनी चालाकी और चतुर सौदागरी के लिए विख्यात थे। गांधी जी ने कहा कि वे कठोरता के साथ सचाई पर चलें, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की नई चेतना प्रदर्शित करें।

उन्होंने प्रागे कहा, "हम अपनी सारी कठिनाइयों के लिए गोरों को दोष नहीं दे सकते न हम अपने-आप सारी गरीबी को ही दूर कर सकते हैं, जिसमें हमारे लोग फँसे हुए हैं। लेकिन हम अपने घरों की सफाई करना, अधिधित प्रौढ़ों को पढ़ाना, और गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूलों की व्यवस्था करना प्रारम्भ कर सकते हैं।"

प्रयोगों और गतिधियों से होकर, गांधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक नया कार्यक्रम निकाला, जिसके नाटकीय नए रूप थे। केवल कानून के माध्यम से काम करने के बजाए—पार्लियेण्ट (संसद) से प्रतिबन्धात्मक कानूनों को खतम करने की अपीलें और अदालतों या चुनावों में विजय प्राप्त करने की चेष्टाएँ—गांधीजी ने हिन्दुस्तानियों को सिखाया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध के साथ समाज की रचनात्मक सेवा का मेल कैसे बिठाएँ।

उन्होंने हजारों भारतीयों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानबूझ कर भेदभाव वाले कानूनों को तोड़ता गया। सैकड़ों पुलिस की मार से गिर गए, और हजारों जेल गए।

अन्त में प्रधान मंत्री स्मट्स ने निश्चय किया कि गांधी जी के साथ उचित समझौता करने के अलावा और कोई व्यावहारिक उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, "बीस हजार हिन्दुस्तानियों को जेल में नहीं रखा जा सकता।"

×

×

×

स्वतंत्रता के सघर्ष में अपनी शक्तियों, और अहिंसात्मक कार्यवाही की अपनी पद्धतियों का उपयोग करने के लिए, 1915 में गांधीजी हिन्दुस्तान वापस लौट आए। अफ्रीका की भाँति हिन्दुस्तान में भी उनका कार्यक्रम अंग्रेजी प्रभुत्व के विरुद्ध सघर्ष करने तक सीमित न रहकर बहुत आगे तक गया। उनका लक्ष्य एक ऐसे हिन्दुस्तान का निर्माण करना था, जो अपना शासन स्वयं ऊँर सके। अतः उन्होंने जितना समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने में लगाया, उतना ही गाँवों में रचनात्मक कार्य के लिए अपने देशवासियों को प्रशिक्षित करने में।

भारतीय विकास के उनके तेरह-सूत्री कार्यक्रम में हिन्दुओं के अन्दर छुआछूत का अन्त, हिन्दू-मुस्लिम एकता और भाईचारे की स्थापना, और पाँच लाख गाँवों में जहाँ अधिकांश भारतवासी रहते थे, खेती, भोजन, शिक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना शामिल था।

अपनी राजनीतिक प्रतिभा के द्वारा गांधीजी ने ऐसे प्रश्नों को चुनकर नाटकीय रूप दिया, जिन्हें लोग समझते थे। 1930 में उनके नमक मार्च ने स्वतंत्रता की सारी सड़ाई को भारतीय शान्तिपूर्णों की एक सीधी-सी माँग पर केंद्रित कर दिया—घरेलू

नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख सकते हैं

नमक बनाने पर प्रतिबन्ध की, और नमक पर घुणित अंग्रेजी कर की समाप्ति ।

जब गांधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मील पैदल चल कर अरब सागर के तट पर जाएंगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की भ्रष्टाचार करके, ईश्वर के बनाए समुद्र से नमक बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में विजली दौड़ गई । जहाँ-जहाँ से चल कर वह गुजरे, लाखों किसान उनकी जयजयकार करते सड़कों के किनारे एकत्रित हो गए ।

5 अप्रैल की रात को वे समुद्र के किनारे पहुँचे । उन्होंने कहा, "ईश्वरेच्छा हुई, तो बल सुबह साढ़े छह बजे हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे ।" सूर्योदय के समय उन्होंने अपनी सामान्य प्रार्थना सभा की और नियत समय पर समुद्र तट से नमक की पहली मूट्टी उठाने के लिए पहुँचे ।

जब यह खबर सारे देश में फैली, तो बड़ी तीव्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दूर गाँव में भी पहुँची । नेहरू और लगभग एक लाख अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए ।

तब गांधीजी ने घोषणा की कि वे नजदीक के सरकारी नमक भंडार पर एक अहिंसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे । उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2,500 भारतीयों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज या हाथ न उठाने की शपथ ले रखी थी ।

यद्यपि सैकड़ों व्यक्ति (पुलिस की मार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिंसा नहीं हुई । जब गांधीजी ने जेल में सुना कि उत्तर-पूर्वी सीमाप्रान्त के जबर्दस्त पठान मुसलमानों ने भी अपना आत्मानुशासन कायम रखा, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई । हर जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, और पहली बार यह अनुभव करने लगे कि व्यक्तियों के रूप में उनके कुछ अधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और एक भविष्य है ।

तीस वर्ष तक गांधीजी ने प्रतिभापूर्ण राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ और अतिम विजय में बढ़ विश्वास के साथ, एक स्वतंत्र और सामाजिक चेतना युक्त भारत का निर्माण करने के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अपनी क्रांतिकारी नई पद्धतियों का प्रयोग किया ।

स्वतंत्रता आखिरकार 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त हुई । एक उपनिवेश-विरोधी क्रांति को कैसे विचित्र और शानदार परिणति थी । चालीस करोड़ लोगों ने अपना सामन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था । चमत्कार यह था कि उन्होंने यह विजय बिना किसी रक्तपात और घृणा के प्राप्त की थी । चूँकि अंग्रेजों ने बड़े अन्धे ढंग से हार मान ली, इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत समानता और पारस्परिक आदर के एक नए सम्बन्ध की नींव पड़ी ।

हिन्दुस्तान में, या माण्टगोमरी, अलाबामा में भी, गांधीवादी दृष्टिकोण की व्यावहारिक प्रभावकारिता से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता ।

लेकिन क्या यह लिटिल रॉक, शिकागो, लेविट टाउन, और न्यू ऑरलियन्स में भी काम कर सकता है ? तीन सौ वर्षों तक, घट्टव कुछ अनजाने में ही, ईसाई

उन्हे सुनने के लिए आये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो अपनी चालाकी और चतुर सौदागरी के लिए विख्यात थे। गांधी जी ने कहा कि वे कठोरता के साथ सचाई पर चलें, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की नई चेतना प्रदर्शित करें।

उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी सारी कठिनाइयों के लिए गोरों को दोष नहीं दे सकते न हम अपने-आप सारी गरीबी को ही दूर कर सकते हैं, जिसमें हमारे लोग फँसे हुए हैं। लेकिन हम अपने घरों की सफाई करना, अनिश्चित प्रौद्योगिकी पढ़ाना, और गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूलों की व्यवस्था करना आरम्भ कर सकते हैं।"

प्रयोगों और गलतियों से होकर, गांधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक नया कार्यक्रम निकाला, जिसके ताटकीय रूप थे। केवल कानून के माध्यम से काम करने के बजाए—पार्लियामेंट (संसद) से प्रतिबन्धात्मक कानूनों को खत्म करने की अपीलें और अदालतों या चुनावों में विजय प्राप्त करने की चेष्टाएँ—गांधीजी ने हिन्दुस्तानियों को सिखाया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध के साथ समाज की रचनात्मक सेवा का मेल कैसे बिटाएँ।

उन्होंने हजारों भारतीयों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानबूझ कर भेदभाव वाले कानूनों को तोड़ता गया। गैंगटो पुलिस की मार से गिर गए, और हजारों जेल गए।

अन्त में प्रधान मंत्री स्मट्स ने निश्चय किया कि गांधी जी के साथ उचित समझौता करने के बजाए और कोई व्यावहारिक उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, "बीस हजार हिन्दुस्तानियों को जेल में नहीं रखा जा सकता।"

×

×

×

स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी शक्तियों, और अहिंसात्मक कार्यवाही की अपनी पद्धतियों का उपयोग करने के लिए, 1915 में गांधीजी हिन्दुस्तान वापस लौट आए। अफ्रीका की भाँति हिन्दुस्तान में भी उनका कार्यक्रम अग्रणी प्रभुत्व के विरुद्ध सफल करने तक सीमित न रहकर बहुत आगे तक गया। उनका सध्य एक ऐसे हिन्दुस्तान का निर्माण करना था, जो अपना मायन स्वयं कर सके। अतः उन्होंने जितना समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने में लगाया, उतना ही गाँवों में रचनात्मक कार्य के लिए अपने देशवासियों को प्रशिक्षित करने में।

भारतीय विद्वानों के उनके तेरह-गुनी कार्यक्रम में हिन्दुओं के अन्दर छुपाए हुए या अज्ञान, हिन्दू-मुस्लिम एकता और भाईचारे की स्थापना, और पाँच लाख गाँवों में जहाँ अधिकांश भारतीयों रहते थे, गेहूँ, भोजन, शिक्षा, और आर्थिक स्वस्थता में सुधार करना शामिल था।

अपनी राजनीतिक प्रतिभा के द्वारा गांधीजी ने ऐसे प्रदर्शनों को चतुरर नाटकीय रूप दिया, जिन्हें लोग ममने थे। 1930 में उनके नमक मार्च ने स्वतंत्रता की सारी लड़ाई को भारतीय प्रामाण्य की एक गीली-गीली माँग पर संक्षिप्त कर दिया—खरेदू

नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख सकते हैं

नमक बनाने पर प्रतिबन्ध की, और नमक पर घृणित अंग्रेजी कर की समाप्ति ।

जब गांधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मील पैदल चल कर अरब सागर के तट पर जाएंगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की भ्रष्टता करके, ईश्वर के बनाए समुद्र से नमक बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में बिजली दौड़ गई । जहाँ-जहाँ से चल कर वह गुजरे, लाखों किसान उनकी जयजयकार करते सड़कों के किनारे एकत्रित हो गए ।

5 अप्रैल की रात को वे समुद्र के किनारे पहुँचे । उन्होंने कहा, "ईश्वरेच्छा हुई, तो बल सुबह साढ़े छह बजे हम सिविल नाकरमानी शुरू करेंगे ।" सूर्योदय के समय उन्होंने अपनी सामान्य प्रार्थना सभा की और नियत समय पर समुद्र तट से नमक की पहली मट्टी उठाने के लिए पहुँचे ।

जब यह खबर सारे देश में फैली, तो बड़ी तीव्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दूर गाँव में भी पहुँची । नेहरू और लगभग एक लाख अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए ।

तब गांधीजी ने घोषणा की कि वे नजदीक के सरकारी नमक भंडार पर एक अहिंसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे । उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2,500 भारतीयों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज या हाथ न उठाने की शपथ ले रखी थी ।

यद्यपि सैकड़ों व्यक्ति (पुलिस की मार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिंसा नहीं हुई । जब गांधीजी ने जेल में सुना कि उत्तर-पूर्वी सीमाप्रान्त के खबर्दस्त पठान मुसलमानों ने भी अपना आत्मानुशासन कायम रखा, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई । हर जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, और पहली बार यह अनुभव करने लगे कि व्यक्तियों के रूप में उनके कुछ अधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और एक भविष्य है ।

तीस वर्ष तक गांधीजी ने प्रतिभापूर्ण राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ और अंतिम विजय में दृढ़ विश्वास के साथ, एक स्वतंत्र और सामाजिक चेतना युक्त भारत का निर्माण करने के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अपनी क्रांतिकारी नई पद्धतियों का प्रयोग किया ।

स्वतंत्रता आखिरकार 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त हुई । एक उपनिवेश-विरोधी क्रांति को कौसी विविध और शानदार परिणति थी । चालीस करोड़ लोगों ने अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था । चमत्कार यह था कि उन्होंने यह विजय बिना किसी रक्तपात और घृणा के प्राप्त की थी । चूँकि अंग्रेजों ने बड़े अच्छे ढंग से हार मान ली, इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत समानता और पारस्परिक आदर के एक नए सम्बन्ध की नींव पड़ी ।

हिन्दुस्तान में, या माण्टगोमरी, दत्ताबामा में भी, गांधीवादी दृष्टिकोण की व्यावहारिक प्रभावकारिता से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता ।

लेकिन क्या यह लिटिल रॉक, शिकागो, लेविट टाउन, और न्यू आर्लियन्स में भी काम कर सकता है ? तीन सौ वर्षों तक, बहुत कुछ अनजाने में ही, ईसाई

उन्हें सुनने के लिए आये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो अपनी चालाकी और चतुर सौदागरी के लिए विख्यात थे। गांधी जी ने कहा कि वे कठोरता के साथ सचाई पर चले, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की नई चेतना प्रदर्शित करें।

उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी सारी कठिनाइयों के लिए गोगे को दोष नहीं दे सकते न हम अपने-आप सारी गरीबी को ही दूर कर सकते हैं, जिसमें हमारे लोग फँसे हुए हैं। लेकिन हम अपने घरों की सफाई करना, अशिक्षित प्रौढ़ों को पढ़ाना, और गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूलों की व्यवस्था करना आरम्भ कर सकते हैं।"

प्रयोगों और गलतियों से होकर, गांधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक नया कार्यक्रम निकाला, जिसके नाटकीय नए रूप थे। केवल कानून के माध्यम से काम करने के बजाए—पार्लियामेंट (संसद) से प्रतिवन्धनात्मक कानूनों को खत्म करने की अपीलें और अदालतों या चुनावों में विजय प्राप्त करने की चेष्टाएँ—गांधीजी ने हिन्दुस्तानियों को सिखाया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध के साथ समाज की रचनात्मक सेवा का मेल कैसे बिटाएँ।

उन्होंने हजारों भारतीयों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो राज्य के एक गिरे से दूसरे सिरे तक जातबुद्ध कर भेदभाव वाले कानूनों को तोड़ता गया। संबन्धी पुलिस की मार से गिर गए, और हजारों जेल गए।

अन्त में प्रधान मंत्री स्मट्स ने निश्चय किया कि गांधी जी के साथ उचित समझौता करने के बजाए और कोई व्यावहारिक उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, "बीस हजार हिन्दुस्तानियों को जेल में नहीं रखा जा सकता।"

X

X

X

स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी शक्तियों, और अहिंसात्मक कार्यवाही की अपनी पद्धतियों का उपयोग करने के लिए, 1915 में गांधीजी हिन्दुस्तान वापस लौट आए। अहिंसा की भाँति हिन्दुस्तान में भी उनका कार्यक्रम अप्रैतरी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करने तक सीमित न रहकर बहुत आगे तक गया। उनका लक्ष्य एक ऐसे हिन्दुस्तान का निर्माण करना था, जो अपना नामन स्वयं कर सके। अतः उन्होंने जिनना समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने में लगाया, उनका ही गाँवों में रचनात्मक कार्य के लिए करने देनाशक्तियों को प्रयत्न करने में।

भारतीय विभाग के उनके तेरह-सूत्री कार्यक्रम में हिन्दुओं के अन्दर सुपाठन का धर्म, हिन्दू-मुस्लिम एकरा और भाईचारे की स्थापना, और पाँच लाख गाँवों में जहाँ अधिकांश भारतीयों रहते थे, पानी, भोजन, शिक्षा, और मार्गदर्शक स्वास्थ्य में सुधार करना शामिल था।

अपनी राजनीतिक प्रतिभा के द्वारा गांधीजी ने ऐसे प्रश्नों को चुनकर नाटकीय रूप दिया, जिन्हें लोग समझते थे। 1930 में उनके नमक मार्च ने स्वतंत्रता की सारी शक्तों को भारतीयों की एक सीमा-सी सीमा पर केंद्रित कर दिया—परन्तु

नमक बनाने पर प्रतिबन्ध की, और नमक पर घृणित अंग्रेजी कर की समाप्ति ।

जब गांधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मील पैदल चल कर अरब सागर के तट पर जाएंगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की भ्रष्टता करके, ईश्वर के बनाए समुद्र से नमक बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में विजयी दौड़ गई । जहाँ-जहाँ से चल कर वह गुजरे, लाखों किसान उनकी जयजयकार करते सड़को के किनारे एकत्रित हो गए ।

5 अप्रैल की रात को वे समुद्र के किनारे पहुँचे । उन्होंने कहा, "ईश्वरेच्छा हुई, तो बल सुबह साढ़े छह बजे हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे ।" सूर्योदय के समय उन्होंने अपनी सामान्य प्रार्थना सभा की और नियत समय पर समुद्र तट से नमक की पहली मुट्टी उठाने के लिए पहुँचे ।

जब यह खबर सारे देश में फैली, तो बड़ी तीव्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दूर गाँव में भी पहुँची । नेहरू और लगभग एक लाख अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए ।

तब गांधीजी ने घोषणा की कि वे नजदीक के सरकारी नमक भंडार पर एक अहिंसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे । उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2,500 भारतीयों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज या हाथ न उठाने की शपथ ले रखी थी ।

यद्यपि सैकड़ों व्यक्ति (पुलिस की मार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिंसा नहीं हुई । जब गांधीजी ने जेल में सुना कि उत्तर-पूर्वी सीमाप्रान्त के जबरदस्त पठान मुसलमानों ने भी अपना आत्मानुशासन कायम रखा, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई । हर जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, और पहली बार यह अनुभव करने लगे कि व्यक्तियों के रूप में उनके कुछ अधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और एक भविष्य है ।

तीस वर्ष तक गांधीजी ने प्रतिभापूर्ण राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ और अंतिम विजय में दृढ़ विश्वास के साथ, एक स्वतंत्र और सामाजिक चेतना युक्त भारत का निर्माण करने के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अपनी क्रांतिकारी नई पद्धतियों का प्रयोग किया ।

स्वतंत्रता आखिरकार 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त हुई । एक उपनिवेश-विरोधी क्रांति को कैसे विचित्र और शानदार परिणति थी । चालीस करोड़ लोगों ने अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था । चमत्कार यह था कि उन्होंने यह विजय बिना किसी रक्तपात और घृणा के प्राप्त की थी । चूँकि अंग्रेजों ने बड़े अच्छे ढंग से हार मान ली, इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत समानता और पारस्परिक आदर के एक नए सम्बन्ध की नींव पड़ी ।

हिन्दुस्तान में, या माण्डगोमरी, अलाबामा में भी, गांधीवादी दृष्टिकोण की व्यावहारिक प्रभावकारिता से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता ।

लेकिन क्या यह लिटिल रॉक, शिकागो, लेविट टाउन, और न्यू ऑरलियन्स में भी काम कर सकता है ? तीन सौ वर्षों तक, बहुत कुछ अनजाने में ही

सिद्धान्तों के विरुद्ध चलते रहने के फलस्वरूप जो जातीय पूर्वाग्रह और भय संचित हो गए हैं, क्या यह उनसे अमरीकियों को—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में—मुक्ति दिला सकता है ?

अन्याय से लड़ने के गांधीजी के तरीके की सफलता की मुख्य शक्तें ये थी, कि यह सघर्ष ऐसी कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत हुआ, जिसका प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट करने वालों के हाथ में था, और जिसमें बड़ी हद तक समाचार पत्रों और बोली की आजादी थी।

इसके अतिरिक्त, एक प्रशिक्षित वकील के रूप में, गांधीजी हमेशा कानून की महत्ता का आदर करते रहे। उन्होंने कहा कि कानून बनाने और लागू करने के राज्य के अधिकार को स्वीकार किया जाय, और इसके साथ ही, जब तक लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वाले कानून बदले न जाएँ, तब तक उनका विरोध करने में अपने व्यक्तित्व और अपनी स्वतंत्रता को अर्पित कर दिया जाय। उनकी अपील मनुष्य के बनाये भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध एक उच्चतर प्राकृतिक नियम से, नैतिक नियम से थी।

ठीक यही तरीका था, जिससे मॉण्टगोमरी के सुसंगठित नीग्रो नागरिक, प्रतिभा-शाली नेतृत्व के अन्तर्गत, नगर की बसों में भेदभाव को खतम करा सके। रेवरेंड माटिन लूथर किंग और उनके सहयोगियों के नेतृत्व और प्रेरणा के फलस्वरूप, वे अपनी जन-सभाएँ “उन लोगों के लिए जो हमारा विरोध करते हैं” प्रार्थनाओं से आरम्भ करने लगे, और उन्होंने नियमित शपथ ली कि वे ‘केवल प्रेम और अहिंसा के हथियारों’ का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ‘ईश्वर के साथ चल रहे’ थे। अपने आन्दोलन का नाम उन्होंने ‘मॉण्टगोमरी सुधार सघ’ रखा।

गांधीजी की भाँति, डा० किंग ने भी इस बात पर जोर दिया कि वे और उनके सहयोगी रंगीन लोगों की ही नहीं, गोरे लोगों की भी प्रगति के लिए काम कर रहे थे।

डा० किंग ने कहा, “गोरे लोगों द्वारा भेदभाव के पक्ष में दिये गए तर्कों की हम परीक्षा करें। हम देखें कि क्या उनमें ऐसी भी स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और स्वयं कार्यवाही करें।”

और तब डा० किंग ने सफाई के साथ नीग्रो लोगों में अर्बुद बच्चों की सहायता, अपराधों की सहायता, साधनों के परे जाकर मोटरों की सरोद, और स्वास्थ्य के नीचे स्तरों की गिनाया। और गुलामी, भेदभाव, और बलात्कृत दूसरे दर्जे की नागरिकता के इन परिणामों को मिटाने के लिए मॉण्टगोमरी सुधार संघ दिन-रात काम करता है।

मॉण्टगोमरी नगर और कल्याण विभाग के रजिस्ट्रारों में अभी भी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है—नीग्रो लोगों में शराबखोरी, बाल अपराध, और तलाक़ घटे हैं।

जब भेदभाव के अहिंसात्मक विरोध और समाज-सेवा का यह मिला-जुला कार्यक्रम मॉण्टगोमरी के बाहर फैलेगा, तो मार्ग के दुगुंम होने की सम्भावना है। गांधीजी ने स्वयं यह प्रदर्शित किया कि सभी मनुष्यों की समान प्रतिष्ठा के ईसाई लक्ष्य की

प्राप्ति का कोई आमान, अनायास मार्ग नहीं है।

दूसरा गाल सामने करके हिन्दुस्तानियों ने पहले तो अंग्रेजों के गुस्से को और भी बढ़काया। नेहरू ने एक बार कहा कि जब वे अपनी रक्षा के लिए बिना एक उँगली भी उठाए चुपचाप खड़े थे, उस समय अपनी लोहे जड़ी लाठियों से उन्हें पीटने वाले सिपाहियों की आँखों में जैसी घृणा देखी थी, उससे अधिक घृणा अन्य किसी में नहीं देखी। अपनी अन्तरात्मा की ऐसी कठोर परीक्षा किसी को भी अच्छी नहीं लगती।

लेकिन महत्त्व अतिम परिणाम का था। जब हिन्दुस्तानियों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी, अन्ततः अंग्रेज भी उनका आदर करने लगे। इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वे स्वयं अपना आदर करने लगे। नेहरू ने कहा, "हम अपना भय त्याग कर मनुष्यों की तरह चलने लगे।"

यहाँ अमरीका में राष्ट्र-व्यापी स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में फ़ैसला करना कठिन है। गांधीजी न केवल एक शंभरी, निष्ठावान, और साहसी अध्यात्मिक नेता थे, वरन् उनकी राजनीतिक प्रतिभा भी असाधारण थी। अमरीका में, दबाव पड़ने पर ऐसा ही विश्वास और कौशल प्राप्त करने की नीग्रो नेताओं की योग्यता पर बहुत-कुछ निर्भर होगा। इससे भी अधिक निर्भर होगा उनके अनुयायियों की सख्या, साहस और निष्ठा पर।

केवल एक ही बात निश्चित है—अगर हमें अमरीका में जातीय मेलजोल प्राप्त करना है, तो किसी प्रकार की महान् नैतिक शक्ति का निर्माण करना होगा, जो हमारी राष्ट्रीय अन्तरात्मा को जगाए।

जल्दी या देर से, दक्षिण के साथ-साथ उत्तर, पूर्व और पश्चिम से भी एकमात्र संभव ईसाई उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि ईसा यह दिखाने आये थे कि ईश्वर सबका पिता है, और सभी मनुष्य भाई हैं, और ईसा की दृष्टि में यहूदी और ईसाई, यूनानी और बंजर, काले और गोरे में कोई भेद नहीं है।

सिद्धान्तों के विरुद्ध चलते रहने के फलस्वरूप जो जातीय पूर्वाग्रह और भय संचित हो गए हैं, क्या यह उनसे भ्रमरीकियों को—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में—भुक्ति दिला सकता है ?

अन्याय से लड़ने के गांधीजी के तरीके की सफलता की मुख्य शर्तें ये थी, कि यह संघर्ष ऐसी कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत हुआ, जिसका प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट करने वालों के हाथ में था, और जिसमें बड़ी हद तक समाचार पत्रों और बोली की आजादी थी।

इसके अतिरिक्त, एक प्रशिक्षित वकील के रूप में, गांधीजी हमेशा कानून की महत्ता का आदर करते रहे। उन्होंने कहा कि कानून बनाने और लागू करने के राज्य के अधिकार को स्वीकार किया जाय, और इसके साथ ही, जब तक सौकरतांत्रिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वाले कानून बदले न जाएँ, तब तक उनका विरोध करने में अपने व्यक्तित्व और अपनी स्वतंत्रता को अर्पित कर दिया जाय। उनको अपनी मनुष्य के बनाये भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध एक उच्चतर प्राकृतिक नियम से, नैतिक नियम से थी।

ठीक यही तरीका था, जिससे मॉण्टगोमरी के सुसंगठित नीग्रो नागरिक, प्रतिभाशाली नेतृत्व के अन्तर्गत, नगर की बसों में भेदभाव को खतम करा सके। रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग और उनके सहयोगियों के नेतृत्व और प्रेरणा के फलस्वरूप, वे अपनी जन-सभाएँ “उन लोगों के लिए जो हमारा विरोध करते हैं” प्रार्थनाओं से प्रारम्भ करने लगे, और उन्होंने नियमित रूप से ली कि वे ‘केवल प्रेम और अहिंसा के हथियारों’ का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ‘ईश्वर के साथ चल रहे’ थे। अपने आन्दोलन का नाम उन्होंने ‘मॉण्टगोमरी सुधार संघ’ रखा।

गांधीजी की भाँति, डा० किंग ने भी इस बात पर जोर दिया कि वे और उनके सहयोगी रंगीन लोगों की ही नहीं, गौरे लोगों की भी प्रगति के लिए काम कर रहे थे।

डा० किंग ने कहा, “गौरे लोगो द्वारा भेदभाव के पक्ष में दिये गए तर्कों की हम परीक्षा करें। हम देखें कि क्या उनमें ऐसी भी स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और स्वयं कार्यवाही करें।”

और तब डा० किंग ने सफाई के साथ नीग्रो लोगों में अर्बुध बच्चों की सहायता, अपराधों की सहायता, साधनों के परे जाकर मोटरो की सरोद, और स्वास्थ्य के नीचे स्तरों को गिनाया। और गुलामी, भेदभाव, और बलात् दूसरे दर्जे की नागरिकता के इन परिणामों को मिटाने के लिए मॉण्टगोमरी सुधार संघ दिन-रात काम करता है।

मॉण्टगोमरी नगर और कल्याण विभाग के रजिस्ट्रो में अभी भी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है—नीग्रो लोगों में शराबखोरी, बाल अपराध, और तलाक घटे हैं।

जब भेदभाव के अहिंसात्मक विरोध और समाज-सेवा का यह मिला-जुला कार्यक्रम मॉण्टगोमरी के बाहर फैलेगा, तो मार्ग के दुर्गम होने की सम्भावना है। गांधीजी ने स्वयं यह प्रदर्शित किया कि सभी मनुष्यों की समान प्रतिष्ठा के ईसाई सक्षय की

प्राप्ति का कोई आसान, अनायास मार्ग नहीं है।

दूसरा गाल सामने करके हिन्दुस्तानियों ने पहले तो अंग्रेजों के गुस्से को और भी भड़काया। नेहरू ने एक बार कहा कि जब वे अपनी रक्षा के लिए बिना एक उँगली भी उठाए चुपचाप खड़े थे, उस समय अपनी लोहे जड़ी लाठियों से उन्हें पीटने वाले सिपाहियों की आँखों में जैसी घृणा देखी थी, उससे अधिक घृणा अन्य किसी में नहीं देखी। अपनी अन्तरात्मा की ऐसी कठोर परीक्षा किसी को भी अच्छी नहीं लगती।

लेकिन महत्व अतिम परिणाम का था। जब हिन्दुस्तानियों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी, अन्ततः अंग्रेज भी उनका आदर करने लगे। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे स्वयं अपना आदर करने लगे। नेहरू ने कहा, "हम अपना भय त्याग कर मनुष्यों की तरह चलने लगे।"

यहाँ अमरीका में राष्ट्र-व्यापी स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम की संभावनाओं के बारे में फँसला करना कठिन है। गांधीजी न केवल एक गंभीर, निष्ठावान, और साहसी अध्यात्मिक नेता थे, वरन् उनकी राजनीतिक प्रतिभा भी असाधारण थी। अमरीका में, दबाव पड़ने पर ऐसा ही विश्वास और कौशल प्राप्त करने की नीग्रो नेताओं की योग्यता पर बहुत-कुछ निर्भर होगा। इससे भी अधिक निर्भर होगा उनके अनुयायियों की सख्या, साहस और निष्ठा पर।

केवल एक ही बात निश्चित है—अगर हमें अमरीका में जातीय मेलजोल प्राप्त करना है, तो किसी प्रकार की महान् नैतिक शक्ति का निर्माण करना होगा, जो हमारी राष्ट्रीय अन्तरात्मा को जगाए।

जल्दी या देर से, दक्षिण के साथ-साथ उत्तर, पूर्व और पश्चिम से भी एकमात्र संभव ईसाई उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि ईसा यह दिखाने आये थे कि ईश्वर सबका पिता है, और सभी मनुष्य भाई हैं, और ईसा की दृष्टि में यहूदी और ईसाई, यूनानी और ब्रंर, काले और गोरे में कोई भेद नहीं है।

नीग्रो अधिकार—कार्यवाही का समय अभी है

दक्षिण के साथ-साथ उत्तर की उप-नगरियों में उत्पन्न जातीय तनावों ने प्रेरणा दी कि हम अमरीका में सभी हिस्सों में इस 'नैतिक केंसर' पर फिर से नज़र डालें। न्यूयार्क टाइम्स, 17 जनवरी, 1960, और न्यू रिपब्लिक, 6 जुलाई, 1959 से।

अमरीका में जातीय भेदभाव को खतम करने का प्रमुख कारण साम्यवाद की चुनौती नहीं है। न विदेशों में मित्र प्राप्त करना और लोगों को प्रभावित करना ही इसका मुख्य कारण है। मुख्य कारण सरल और सीधा-सा यह है कि जातीय भेद-भाव गुलत है।

जातीय भेदभाव हमारे समाज में एक नैतिक केंसर है। यह हमारी धार्मिक और लोकतांत्रिक आस्था का जीवित, निरन्तर, और सदा-वर्तमान खडन है। यह हमारी राष्ट्रीय अन्तरात्मा को निरन्तर क्षय करता है।

प्रश्न मुख्यतः दोष मानव-जाति के साथ शांतिपूर्वक रहने का नहीं है। जब तक हम अपनी राष्ट्रीय अन्तरात्मा से इस दाग को नहीं मिटा देते, तब तक हम स्वयं अपने साथ शांतिपूर्वक रहने की आशा नहीं कर सकते।

हमारे देश में जातियों के बीच जो कुछ भी होता है—चाहे लिटिल रॉक में हो या माण्टगोमरी में, लेविट टाउन में हो या शिकागो में—वह हम सब के साथ होता है, और अमरीकियों के रूप में हम सब उसमें सहभागी हैं।

कौन अमरीकी समुदाय ऐसा है—चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में—जो अपनी आत्म-मरीक्षा करके अपने को निर्दोष कह सके?

हममें से कौन ऐसा है जो रोज आवास, स्कूल, और मनोरंजन के ऐसे क्षेत्रों से नहीं गुजरता जो रंगीन लोगों के लिए निषिद्ध हैं? हममें से कौन ऐसा है जो भेदभाव की धर्मनीति में, चाहे कितने ही अज्ञानों में, भाग नहीं लेता?

हम इस बात को न भूलें कि अमरीकी नीग्रो अब उत्तर में रहते हैं। डेट्रॉइट में नीग्रो लोगों की संख्या न्यू ब्रायनस की पाँच गुनी है, लॉस एंजेलिस में मियामी की छः गुनी।

फिर बड़े-बड़े उत्तरी लोग ऐसे हैं जो आत्म-नुष्टि की भावना के साथ जातीय भेद-

भाव को केवल एक हिस्से की समस्या समझते हैं। दक्षिण में जिसे वे एकीकरण की घीमी गति समझते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जबकि अपने चारों ओर व्याप्त भेदभाव के प्रति उदासीन या लगभग उदासीन रहते हैं।

दक्षिण के प्रतिरिक्त जो उन्तालीस राज्य हैं, उनमें केवल उन्नीस ने उचित रोजगार आचरण कमीशन नियुक्त किए हैं, और उनमें से भी तीन को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

बीस अन्य अ-दक्षिणी राज्यों में रोजगार सम्बन्धी भेदभाव के बारे में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। केवल नौ अ-दक्षिणी राज्यों ने मार्गजनि सहायता से बने मकानों में भेदभाव के विरुद्ध कानूनी कदम उठाए हैं। तीस अन्य अ-दक्षिणी राज्यों में प्राणा सम्बन्धी भेदभाव के विरुद्ध कोई सरकारी कार्यवाही नहीं की गई है।

न्यू हैवेन और पिट्सबर्ग जैसे कई शहर अपने पुन. निर्माण के लिए दूरगामी कदम उठा रहे हैं, जिनमें गंदी धस्तियों की सफाई, और मानवीय पुनर्वास भी शामिल है, जो जातीय तनावों को कम करने के लिए आवश्यक है। लेकिन बहुतेरे उत्तरी नगरों में शान्ति की कथित ममान सुरक्षा के पीछे व्यवहार में व्यापक भेदभाव छिपा है—

अ. स सम्बन्धी निपट्टियों और गरीबी के प्राकृतिक चयन द्वारा होने वाला भेदभाव।

के प्रमुख नगरों में बहुत कम ऐसे हैं जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक नीग्रो बच्चे गोरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं।

उत्तर की लगभग हर शहरी बस्ती अगर ईमानदारी से अपने जातीय सम्बन्धों पर विचार करे तो उसे पता चलेगा कि उसका जीवन उसके घोषित आदर्शों से कितनी दूर है। और एक बार यह देख लेने पर कि हमारे अपने नगरों और राज्यों में क्या कमी है, हमारे अन्दर यह भावना कम होगी कि मसन-डिनसन रेखा के दक्षिण के गोरे पराकाष्ठावादियों की निन्दा करना ही काफी है। दक्षिण पर किसी बात का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना इसका कि उत्तर के अति तत्पर आलोचक स्वयं क्यादा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें।

हम सभी के सौभाग्य से, संविधान में कोई रंग-भेद नहीं है। चौदहवें संशोधन के अनुसार यह अहम आवश्यक है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के सभी अंगों से जातीय भेदभाव को समाप्त किया जाय। मानवी अधिकारों का सार्विक घोषणा-पत्र, जिसे दुनिया के बहुत बड़े बहुमत ने स्वीकार कर लिया है, विश्व-व्यवस्था के प्रथम सिद्धान्तों में से एक के रूप में इसकी पुष्टि करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 'अधिकतम सुविचारित गति' के साथ जातीय अलगाव का अंत किया जाय। और नीग्रो लोग मुकदमे चलाकर इस आदेश का पालन कराएंगे। दक्षिण और अन्यत्र उठते हुए नीग्रो लोगों में ऐसे मुकदमे खाने वालों की प्रयत्नित सत्या निकल आएगी, चाहे उन्हें रोकने के लिए कितना भी दबाव क्यों न डाला जाय। चाहे जो भी दल सत्ताह्व हो, कानूनों का अन्ततः पालन होगा ही।

श्रीर, निस्सन्देह, कानून स्वयं एक प्रभायशाली शिक्षक है। मैग्य बस, राष्ट्र की राजधानी, श्रीर अन्तर्राज्य रेनगाष्टियों में भेदभाव की समाप्ति था, यदुनेरे शक.शुभों को यह विदवास दिलाने मे बडा प्रभाव पडा कि उन शोणो मे एकीकरण उचित था। कितनी श्रीर किसी भी तरह की बातचीत का मैग्य प्रभाव नहीं हो सरता था।

किन्तु इसकी आशका प्रतीत होती है कि हम यमीनो श्रीर जजो के भरोसे बैठ जाएं, श्रीर वहे कि अब यह केवल कानून श्रीर व्यवस्था का प्रश्न रह गया है। राष्ट्रपति आइजनह्वर के इस बचन मे यही दृष्टिरोग दिगाई देना प्रतीत होता था, कि उन्होने किसी से भी यह नहीं कहा, अपनी गती मे भी नहीं, कि वे सर्वोच्च न्यायालय के एकीकरण सम्बन्धी निर्णय को सही समझने हैं या गलत।

लेकिन केवल अदातती आदेशो से लोगो के दिल धीर दिमाग नहीं बदलेंगे। हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम कानून की अपरिष्ठापे शक्ति को अनिच्छापूर्वक मजबूरी मे स्वीकार करें। हमारी आशा है कि ऐतिहासिक आवश्यकता के समझे जाने से हर समुदाय से जातीय तत्वो मे मेल-जोल पैदा करने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिलेगा।

अगर स्कूलो के एकीकरण का प्रश्न, केवल कानून के पालन मे विश्वास करने वालो, श्रीर उसमे बनने की चेष्टा करने वालो के बीच एक कानूनी प्रश्न होता, तो 1954 मे सर्वोच्च न्यायालय की कायंबाही के पूर्य कोई प्रश्न रहा ही न होगा। लेकिन इससे तो समस्या ही उलट जाती है। अदालत ने इसलिए कायंबाही की, कि समानता की सर्वाधिक सुरक्षा इस राष्ट्र के गभीरतम राजनीतिक सिद्धान्तो से सम्बद्ध है, श्रीर इसलिए कि उसके समक्ष एक नैतिक प्रश्न था, जो हमारे अधिकार-पत्र श्रीर हमारी ईसाई सम्प्रदाय के मर्म तक जाता था।

कानून को अपनी शक्ति केवल इस कारण प्राप्त नहीं होती कि वह कानून है। उसे इसलिए समर्थन प्राप्त होता है कि उसमे समाज का नैतिक उद्देश्य निहित होता है, श्रीर राजनीतिक नेताओं का, व उन सभी लोगों का जो समान अधिकारो की स्थापना चाहते हैं, केवल इतना ही काम नहीं है कि वे अदालती फैसलो का सहारा लेकर उन पर अमल कराएँ, बल्कि लोगो को यह समझना भी है कि ये फैसले सही हैं।

अतः हमारी द्विविधा एक नैतिक श्रीर राष्ट्रीय द्विविधा है। इस परिप्रेक्ष्य मे, विश्व मत की चेतना उन कामो मे हमारी सहायक हो सकती है, जो हमें किसी भी सूरत मे करने चाहिए। लेकिन, कम से कम तीन रूपो मे, विश्व का अनुभव मेरी राय मे हमारे लिए श्रीर भी अधिक सहायक हो सकता है।

प्रथम, इस प्रश्न पर अत्यधिक दोषो होने की हमारी भावना इसमे कम होगी। जातीय भेदभाव के दोषो केवल हम ही अकेले नहीं हैं। यह एक सार्वभौमिक दोष है। यह दुनिया की सभी संस्कृतियों में व्याप्त है, सभी मनुष्य दससे प्रभावित हैं।

दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय के स्कूल एकीकरण निर्णय को कायन्वित कराने के लिए सफलतापूर्वक सड़ने वाले नीधी श्रीर भोरे वकीलो के कौशल श्रीर अनयक प्रयास

को अफ्रीका और एशिया वालों ने जिम सद्भावना और प्रशंसा की दृष्टि से देखा है, वह हमारे उत्साह को बढ़ाने वाली चीज है।

तोसरे, दुनिया के अनुभव से हम यह भी सीख सकते हैं कि प्रगति की कुंजी केवल कानूनों में ही नहीं है, बरन् लोगों के दिलों में भी है। अगर हम में अपनी सामियों को स्वीकार करने की, और दूसरों से सहायता लेने की विनम्रता हो, तो हम सब लोग—नीग्रो और गोरे दोनों ही—अन्य लोगों के व्यावहारिक अनुभव से सीख सकते हैं।

हमें रचनात्मक कार्य का सबसे बड़ा अवसर हमारे अपने पड़ोस में, अपने सह-नागरिकों के साथ अपने नित्य-प्रति के सम्बन्धों में मिलता है।

अगर भेदभाव के प्रति हमारी बढ़ती हुई चिन्ता को राष्ट्रीय पैमाने पर सामुदायिक कार्यक्रमों में ढाला जा सके, तो आगामी वर्षों में आश्चर्यजनक प्रगति हो सकती है।

मैसन-डिवसन रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर की वस्तियों के लिए एक नागरिक प्रदानावती में नीचे लिखे प्रश्न हो सकते हैं—

पुलिस विभाग में कितने नीग्रो हैं? दमकल में? नगरपालिका में? शिक्षा व्यवस्था में?

ऐसे कामों के लिए क्या नीग्रो लोगों को पूरा अवसर मिलता है? अगर हाँ, तो क्या उन्हें केवल योग्यता और सेवाओं के आधार पर तरक्की दी जा सकती है?

सार्वजनिक और निजी दोनों ही व्यवस्थाओं में किस प्रकार के मकान नीग्रो लोगों को उपलब्ध हैं? चिकित्सा और अस्पताल की सुविधाएँ कौसी हैं।

क्या सार्वजनिक आवास और मनोरंजन की सुविधाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का भेदभाव है?

निजी उद्यम के कामों में क्या स्थिति है? क्या नीग्रो मजदूरों को ऐसे काम मिलते हैं जिनमें उनके कौशल का पूरा उपयोग हो?

कार्य सम्बन्धी, व्यावसायिक प्रशिक्षण क्या नीग्रो लोगों को पूरी तरह उपलब्ध है?

क्या पुलिस और अदालतें उनके साथ आवादी के अन्य हिस्सों के समान ही उचित व्यवहार करती हैं?

हर शहर में, मेयर और प्रमुख नागरिकों के नेतृत्व में और सरकारी समूहों द्वारा निष्पक्ष अध्ययन से ऐसे प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में सामुदायिक सहमति प्राप्त की जा सकती है। और ये तथ्य फिर रचनात्मक लोकतांत्रिक कार्यवाही का आधार बन सकते हैं।

गुन्नार मिडेल द्वारा समस्या के अति उत्तम अध्ययन 'ऐन अमेरिकन डाइलेमा' (एक अमरीकी द्विविधा) में ऐसी कार्यवाही का एक महत्त्वपूर्ण संकेत मिलता है। यह संकेत इस अत्यधिक आत्माजनक तथ्य में है कि गोरे लोग जिन अधिकारों को

प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं—काम में अवसर की समानता, समान और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और भावात् व्यवस्था, और कानून की दृष्टि में समानता—उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नीचो लोग सबसे अधिक उत्सुक हैं ।

हमारे पास अब भी समय है, यह स्वयं हमारे नीचो मह-नागरिकों में सहनशक्ति और धैर्य के असाधारण गुणों के कारण ही है । इस बात को 185 वर्ष हो गए, जब हमने स्वतंत्रता के घोषणापत्र में ऐलान किया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र और समान हैं । इसके नब्बे वर्ष बाद हम गुलामों को मुक्त करने में सफल हुए । यह निर्णय करने में हमें और नब्बे वर्ष लगे कि हमारे स्कूलों में नीचो और गोरों बच्चों का अनिवार्य अलगाव अंतर्वैधानिक था ।

आज अधिकांश अमरीकी अपने दिलों में जानते हैं कि अब सफाई देने का समय नहीं रहा, अब कार्यवाही करने का समय आ गया है । हम जानते हैं कि सभी जातियों और मतों के लोगों के लिए अवसरों की वास्तविक समानता को अब रोक नहीं जा सकता । अतः अब हम अपनी अदानतों और अपनी अन्तरात्मा द्वारा आवश्यक बताई गई कार्यवाही की ओर बढ़ें ।

स्मिथ कालेज की स्नातकीय कक्षा के समक्ष, जिसकी एक सदस्य उनकी पुत्री भी थी, श्री वील्स खेद प्रकट करते हैं कि उनकी पीढ़ी आधुनिक अमरीकी समाज के लिए पर्याप्त नैतिक सन्दर्भ का निर्माण नहीं कर सकी। समाारम्भ भाषण, स्मिथ कालेज, 5 जून, 1960।

आप में से बहुतेरे लोग अपने माता-पिताओं की पीढ़ी के प्रति जितने सहिष्णु रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतिहास उससे अधिक सहिष्णु होगा। जिस प्रकार की दुनिया में हमें रहना पड़ा, और जिसकी व्यवस्था में भी हमें हाथ बँटाना पड़ा, यद्यपि हम लोग, आपके माता-पिता और मैं, उसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थे, फिर भी मैं समझता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वह कसौटी पर काफी खरा उतरेगा।

उदाहरण के लिए, मेरी पीढ़ी ने 130 वर्ष पुरानी परम्परा को तोड़कर अलगव की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। उसने आर्थिक और सामाजिक विपत्ति आने पर, राष्ट्रीय एकता को नई गम्भीरता और अर्थ प्रदान करने के लिए कार्यवाही की। उसने मुझे उत्तर काल में मासल योजना, उत्तरी अटलांटिक संधि, चतुःसूत्री कार्यक्रम, और पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम की सहासपूर्ण, रचनात्मक धारणाओं को लेकर नई दिशाओं में कदम उठाए।

हममें से जो अधिक भोरू हैं, उनमें से बहुतेरे हमारी प्राविधिक उपलब्धियों से काफ़ी आशकित हैं। वे कहते हैं कि हमारी मायें बहुत अधिक दूध देती हैं, और हमारी मशीनें बहुत अधिक इस्पात का उत्पादन करती हैं।

निस्सन्देह, जिन प्रश्नों की ओर ध्यान देना आवश्यक था, उनमें से बहुतों के सम्बन्ध में हम पर्याप्त कार्य नहीं कर सके। दुनिया के भूखे बच्चों तक फ़ालतू दूध को पहुँचाना भी स्पष्टतः ऐसा एक कार्य था।

फिर भी, आपके माता-पिताओं, और अपनी पीढ़ी के शेष लोगों की ओर से, मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रति आपका निर्णय बहुत अधिक कठोर नहीं होगा। यह सच है कि हमने अममान गति से और दृक्-दृक् कर ऐसा किया, फिर भी हमने ऐतिहासिक कर्तव्यों को पूरा किया। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में जो नए कर्तव्य हमारे सामने आएँगे, उन्हें पूरा करने की क्षमता और सकल्य भी हममें होगा।

लेकिन, यह स्पष्ट है और ईमानदारी से विश्लेषण करने का अवसर है। जो क्षेत्र

हैं, वहाँ देश के अन्दर हम अन्धी नकल करते हैं। राजनीतिज्ञ, पत्रकार, व्यापारी—यहाँ तक कि प्राध्यापक भी—अपने सर्वाधिक सिद्धान्तनिष्ठ कार्यों के लिए सर्वाधिक सिद्धान्तहीन कारण देने की प्रवृत्ति के अधिकाधिक शिकार हो रहे हैं।

ऐसा कहते हुए हम आत्म-तोष की भावना के साथ मुस्कराते हैं कि उच्च स्थानों में भ्रष्टाचार की घटनाओं से, और राष्ट्रीय विश्वास के पक्षों के दुरुपयोग से यही प्रमाणित होता है कि राजनीति आखिर राजनीति है।

उत्तर के पद-तोलुप लोग दक्षिण के अपने सहयोगियों को विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने इलाकों के राजनीतिक दवावों के कारण ही नीचो अधिकारों के पक्ष में वोट देते हैं।

सड़कों के ग्रीष्म-कालीन शिविरो और अस्पतालों के निर्माण के चन्दे देने वाले व्यापारी तत्काल ऐसा कह कर अपने भले उद्देश्यों पर परदा डालने लगते हैं कि इस तरह के कामों से उनके व्यापार का अर्थ्या प्रचार होता है, और फिर, इन रकमों पर टैक्स नहीं देना पड़ता।

इसी प्रसंग में वह बात उठती है, जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ—इतिहास की उस घड़ी में ही, जब विश्व के सघर्ष की वास्तविक प्रकृति सामने आ रही है, हमारे सामने मूल्यों का एक सकट उत्पन्न हो गया है। जिन नैतिक प्रतिमानों में विश्वास करना हम पसन्द करते हैं, उनमें करो की चोरी और छर्चों के गलत हिमात्र, झूठे विज्ञापन और ताप-तोल में बेईमानी, मिलावटी सामान, और मनोरंजन के नाम पर हिंसा के उपयोग को सहन करने की अनैतिकता सामिल है।

हम बुद्धू न प्रतीत हो, किसी भी ओर से होने वाली आलोचना से प्रभावित होने वाले न प्रतीत हों, विवाद से बचें, और यह प्रमाणित करें कि हम यथार्थवादी हैं, यही किसी बात को लेकर नहीं उड़ चलते, इसके राष्ट्रीय प्रयास में हमने अपने स्वीकृत विश्वासों और अपने वास्तविक नित्य-प्रति के आचरण में एक नैतिक खाई बना ली है। एक स्वतंत्र समाज के रूप में जीवित रहने के हमारे प्रयास में यह नैतिक खाई एक अधिकाधिक बढ़ता हुआ खतरा बन सकती है।

जो वास्तविक प्रश्न है, वह अधिक से अधिक यह है कि क्या बीसवीं सदी के आण्विक आतंक की सैनिक, प्राविधिक, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के सदर्भ में कोई खुला हुआ समाज अनिश्चित काल तक टिका रह सकता है।

अभी से ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो तनाव घटने की किसी संभावना की अपेक्षा, आण्विक गतिरोध के भयकर लेकिन परिचित खतरों के बीच अपने को अधिक सुरक्षित समझते हैं। उनके लिए किमी एक दिशा में सीधे चलना ज्यादा आसान है, चाहे उस रास्ते का अन्त स्पष्टतः सर्वनाश ही क्यों न हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने विलियम बटलर येट्स के वचन को फिर से सब साबित करने का निश्चय कर रखा है—“जो सबसे अच्छे हैं, उनमें विश्वास का अभाव है, जो सबसे बुरे हैं, उनमें तीव्रतम आवेग भरे हैं।” वे पेचीदगियों से, मध्यम

मागों से, कठिन चुनारों से, एक गाव भिन्न वैयक्तिक नीतियों पर चलने की प्रारम्भिकता से, धीरे धीरे प्राधुनिक विचार में मनुष्य, निरुत्पन्ना, धीरे धीरे की प्रारम्भिकता से परेशान हैं ।

ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इन दिनों, जब घटन दराने गेमुद हो गता है, विचार-बदलो से बाहर हो रगना मरणा है । मनीषी और मनीषमनी द्वारा होने वाले मीमिन् विनाश के समय भी ये लोग काफी गवरनाक थे । आज के प्राधुनिक जगत् में उनका स्थान प्रत्यक्ष ही गवता है ।

धमरीका के रचनात्मक नेतृत्व के सामने हम केवल शक्तियों का सामना करने की ही चुनौती नहीं है, परन्तु इसी भी है कि क्रान्तिकारी विचार की प्रवृत्ति को समझे, साम्यवादी समाज में काम कर रही शक्तियों को रोजे, और अन्य लोगों की प्राकाशाओं से भी सम्पर्क स्थापित करे—एनिया, धमरीका, और सामान्य धमरीका के पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे, जो हमारी धरती को केवल अधिकाधिक बेतगाम होने हुए इस-धमरीका संघर्ष का शराड़ा हो नहीं समझते ।

इस चुनौती का सामना करने के लिए चाहे बड़े समय हम बुद्धि विद्वान के शब्दों को याद कर सकते हैं, जिन्होंने एक बार धान्नापोलिस में एक स्नातकीय कक्षा से कहा था—

“हमारे समान धनी अन्य राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही सभितसाली राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही उत्साहपूर्ण राष्ट्र भी हुए हैं । लेकिन मैं प्राणा करता हूँ कि हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि इस राष्ट्र का निर्माण हमने अपनी सेवा करने के लिए नहीं, मनुष्य-जाति की सेवा के लिए किया था ।” दुनिया में अन्य किसी भी राष्ट्र का जन्म इस उद्देश्य से नहीं हुआ कि वह जितना अपने हित में काम करे, उतना ही दोष जगत के हित में भी ।”

धमरीकी समाज के सभी स्तरों पर इस दृष्टि को फिर से प्राप्त करके, हम उस प्राचीन प्रास्था की शांत बुद्धिमत्ता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो सुगों से वाइविल के द्वारा हम तक पहुँची है : “हम कष्टों में आनन्दित होते हैं, यह जानते हुए कि कष्टों से धैर्य प्राता है, और धैर्य से अनुभव, और अनुभव से प्राणा ।”

पुनश्च

थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, "लोकतंत्र शासन का एकमात्र ऐसा रूप है जो मनुष्य के अधिकारों के विरुद्ध निरन्तर खुले या गुप्त रूप में युद्ध-रत नहीं रहता।" किन्तु लोकतंत्र के सामने कभी ऐसी गंभीर चुनौती नहीं रही, जैसी इस घड़ी है।

यह चुनौती आंशिक रूप में लोकतन्त्र विरोधी सिद्धान्त के खतरे के कारण है, लेकिन उससे भी अधिक यह हमारी परम्परागत दृष्टि, आदर्शों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भावना में ह्रास होने के कारण है।

मूल सिद्धान्तों पर वापस जाकर ही हम अपने सामान्य उद्देश्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिन मत्तों को हमारे 'घोषणा-पत्र' ने कभी 'स्वयं सिद्ध' कहा था, वे अब भी सभी युगों के महान् सत्तों में से हैं—“कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि उनके सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ अठरणीय अधिकार प्रदान किए हैं, कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति के प्रयास भी हैं।”

यह हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों की पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ, नए विश्व सन्दर्भ में इन सार्विक सत्तों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि अन्तिम परिणाम की निजी जिम्मेदारी में हममें से हर एक का हिस्सा है।

देश और विदेश दोनों में ही हमें स्वार्थ के बजाए उदारता से, हिंसा के बजाए करुणा से, घृणा के बजाए प्रेम से काम करना सीखना होगा। अपने में, अपने भविष्य में, और अपनी सामान्य विरादरी में अपनी दृढ़ आस्था से हमें इन्कार न करके, दृढ़ता से उसे प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा करके ही हम उस अमरीका का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल सामान्य प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक भौतिक शक्ति में, वरन् सभी मनुष्यों के मूल अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता में भी सबल हो। स्थायी शांति का यही आधा रास्ता हो सकता है। मैं समझता हूँ कि परिणाम का फैसला अब होने वाला है।

- ९

वाशिंगटन, डी. सी., 17 अगस्त, 1962

मार्गों से, कठिन चुनावों से, एक साथ भिन्न वैकल्पिक नीतियों पर चलने की आवश्यकता से, और और आधुनिक विश्व में संतुलन, निपुणता, और धीरज की आवश्यकता से परेशान हैं।

ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इन दिनों, जब बटन दवाने में युद्ध हो सकता है, नियंत्रण-बन्धों से बाहर ही रखना अच्छा है। समीचीन और मशीनगनों द्वारा होने वाले सीमित विनाश के समय भी ये लोग काफी उत्तरदायक थे। आज के आण्विक जगत में उनका स्पर्श प्रलयकारी हो सकता है।

अमरीका के रचनात्मक नेतृत्व के पामने अब केवल रूसियों का सामना करने की ही चुनौती नहीं है, परन्तु इसकी भी है कि क्रांतिकारी विश्व की प्रकृति को समझे, साम्यवादी समाज में काम कर रही शक्तियों को खोजे, और अन्य लोगों की आकांक्षाओं से भी सम्पर्क स्थापित करे—एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरीका के पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे, जो हमारी धरती को केवल अधिकाधिक बेलगाम होते हुए रूस-अमरीका संघर्ष का अखाड़ा ही नहीं समझते।

इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ते समय हम बुड्रो विल्सन के शब्दों को याद कर सकते हैं, जिन्होंने एक बार आन्नापोलिस में एक स्नातकीय कक्षा से कहा था—

“हमारे समान धनी अन्य राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही शक्तिशाली राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही उत्साहपूर्ण राष्ट्र भी हुए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि इस राष्ट्र का निर्माण हमने अपनी सेवा करने के लिए नहीं, मनुष्य-जाति की सेवा के लिए किया था।” दुनिया में अन्य किसी भी राष्ट्र का जन्म इस उद्देश्य से नहीं हुआ कि वह जितना अपने हित में कार्य करे, उतना ही श्रेय जगत के हित में भी।”

अमरीकी समाज के सभी स्तरों पर इस दृष्टि को फिर से प्राप्त करके, हम उस प्राचीन आस्था की शांत बुद्धिमत्ता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो युगों से बाइबिल के द्वारा हम तक पहुँची है : “हम कष्टों में आनन्दित होते हैं, यह जानते हुए कि कष्टों से धर्म आता है, और धर्म से अनुभव, और अनुभव से आशा।”

पुनश्च

थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, “लोकतंत्र शासन का एकमात्र ऐसा रूप है जो मनुष्य के अधिकारों के विरुद्ध निरन्तर खुले या गुप्त रूप में युद्ध-रत नहीं रहता।” किन्तु लोकतंत्र के सामने कभी ऐसी गंभीर चुनौती नहीं रही, जैसी इस घड़ी है।

यह चुनौती आंशिक रूप में लोकतन्त्र विरोधी सिद्धान्त के खतरे के कारण है, लेकिन उससे भी अधिक यह हमारी परम्परागत दृष्टि, आदर्शों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भावना में ह्रास होने के कारण है।

मूल सिद्धान्तों पर वापस जाकर ही हम अपने सामान्य उद्देश्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिन सत्तों को हमारे ‘घोषणा-पत्र’ ने कभी ‘स्वयं सिद्ध’ कहा था, वे अब भी सभी युगों के महान् सत्यो में से हैं—“कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि उनके सृजनकर्त्ता ने उन्हें कुछ अहरणीय अधिकार प्रदान किए हैं, कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति के प्रयास भी हैं।”

यह हमारी पीढ़ी का कर्त्तव्य है कि अपने पूर्वजों की पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ, नए विश्व मन्दर्भ में इन सार्विक सत्त्वों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि अन्तिम परिणाम की निजी जिम्मेदारी में हमने से हर एक का हिस्सा है।

देश और विदेश दोनों में ही हमें स्वायं के बजाए उदारता से, हिंसा के बजाए करुणा से, धृष्टा के बजाए प्रेम से काम करना सीखना होगा। अपने में, अपने भविष्य में, और अपनी सामान्य बिरादरी में अपनी दृढ़ आस्था से हमें इन्कार न करके, दृढ़ता से उसे प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा करके ही हम उस अमरीका का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल सामान्य प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक भौतिक शक्ति में, बल्कि सभी मनुष्यों के मूल अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता में भी सबल हो। स्थायी शांति का यही आधार हो सकता है। मैं समझता हूँ कि परिणाम का फैसला अब होने वाला है।

शिगटन, डी. सी., 17 अगस्त, 1962